



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की प्रतिवेदन
- मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सामान्य
प्रयोजन वित्तीय रिपोर्ट**

संघ सरकार (वाणिज्यिक)

2025 की संख्या 06

(अनुपालन लेखापरीक्षा)

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की प्रतिवेदन
- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की
सामान्य प्रयोजन वित्तीय रिपोर्ट**

मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए

**संघ सरकार (वाणिज्यिक)
2025 की संख्या 06
(अनुपालन लेखापरीक्षा)**

विषय सूची

प्रस्तावना			
कार्यकारी सारांश			
प्रथम अध्याय	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश		
	1.1	परिचय	1
	1.2	सरकारी कंपनियों और निगमों में निवेश	6
	1.3	सीपीएसई से रिटर्न	20
	1.4	सरकारी कंपनियों और निगमों की परिचालन दक्षता	30
द्वितीय अध्याय	सीएजी की निगरानी भूमिका		
	2.1	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लेखापरीक्षा	38
	2.2.	सीएजी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वैधानिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति	38
	2.3	सीपीएसई द्वारा वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति	38
	2.4	सीएजी की निगरानी - वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा और पूरक लेखापरीक्षा	43
	2.5	सीएजी की निगरानी भूमिका के परिणाम	44
	2.6	लेखांकन मानकों इंड एण्ड के प्रावधानों का गैर-अनुपालन	86
	2.7	प्रबंधन पत्र	89

तृतीय	कॉर्पोरेट गवर्नेंस		
अध्याय	3.1	परिचय	91
भाग-अ: सीपीएसई जिनके शेयर/ शेयर और बॉड दोनों 31 मार्च, 2022 को स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध थे			
	3.2	निदेशक मंडल	95
	3.3	स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और कार्यप्रणाली	113
	3.4	निदेशक मंडल और समितियों की बैठकें	114
	3.5	स्वतंत्र निदेशकों का प्रशिक्षण	120
	3.6	रिक्तियों को भरने में अंतराल	121
	3.7	विविध	122
	3.8	लेखापरीक्षा समिति	125
	3.9	वार्षिक सामान्य बैठक में अध्यक्ष की उपस्थिति	137
	3.10	सतर्कता तंत्र	137
	3.11	संबंधित पार्टी लेनदेन	139
	3.12	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति	140
	3.13	हितधारक संबंध समिति	145
	3.14	सहायक कंपनियाँ	147
	3.15	जोखिम प्रबंधन समिति	148
	3.16	सचिवीय लेखापरीक्षा	151
	3.17	अनुपालन प्रमाणपत्र	152
	3.18	निष्कर्ष	153
भाग-ब: सीपीएसई/सांविधिक निगम जिनके बांड/डेबेंचर स्टॉक 31 मार्च, 2022 को एक्सचेंज में सूचीबद्ध थे			
	3.19	परिचय	157
	3.20	वित्तीय परिणाम	157
	3.21	स्टॉक एक्सचेंज को सूचनाएं/अन्य प्रस्तुतियां	159
	3.22	वेबसाइट	159
	3.23	अंदरूनी व्यापार की रोकथाम	160
	3.24	निदेशक मंडल	160

	3.25	रिक्तियों को भरने में अंतराल	163
	3.26	विविध	163
	3.27	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का कोरम	164
	3.28	वरिष्ठ प्रबंधन, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों, निदेशकों और प्रमोटरों सहित कर्मचारियों के संबंध में आचार संहिता और दायित्व	165
	3.29	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति	165
	3.30	हितधारक संबंध समिति	165
	3.31	अनुपालन प्रमाणपत्र	166
	3.32	निष्कर्ष	167
चौथा अध्याय	विनिवेश प्रक्रिया		
	4.1	भारत सरकार (जीओआई) की विनिवेश नीति	169
	4.2	विनिवेश के तरीके	170
	4.3	विनिवेश की प्रक्रिया	173
	4.4	पिछले पांच वर्षों के लिए सीपीएसई के विनिवेश का लक्ष्य और उपलब्धि	176
	4.5	पिछले पांच वर्षों के दौरान विनिवेश से मोड-वार प्राप्ति	179
	4.6	अल्पसंख्यक हिस्सेदारी बिक्री - आरंभिक सार्वजनिक पेशकश और बिक्री के लिए प्रस्ताव	182
	4.7	मॉयल लिमिटेड में शेयरों की पुनर्खरीद	189
	4.8	भारतीय पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की शेष हिस्सेदारी बिक्री के माध्यम से विनिवेश	190
	4.9	यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निर्दिष्ट उपक्रम द्वारा अर्जित ब्याज और लाभांश आय को शामिल करने के कारण विनिवेश प्राप्तियों को ₹1,107 करोड़ अधिक बताया गया	190
	4.10	रणनीतिक विनिवेश (सीपीएसई में भारत सरकार की बहुलांश हिस्सेदारी की बिक्री)	191
	4.11	विनिवेश से संबंधित अन्य मुद्दे	199

पाँचवाँ अध्याय	कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी		
	5.1	परिचय	201
	5.2	लेखापरीक्षा उद्देश्य	202
	5.3	लेखापरीक्षा का दायरा और कवरेज	203
	5.4	लेखापरीक्षा मानदंड	204
	5.5	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	204
	5.6	फोकस क्षेत्र	220
	5.7	प्रशासनिक व्यय	222
	5.8	परियोजना कार्यान्वयन	224
	5.9	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में शामिल न की गई गतिविधियों का सीएसआर वित्तपोषण	229
	5.10	निगरानी ढांचा	230
	5.11	प्रभाव आकलन	232
	5.12	रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण	232
	5.13	निष्कर्ष	237
छठवाँ अध्याय	घाटे में चल रहे चयनित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की समीक्षा		
	6.1	परिचय	240
	6.2	अशक्त/घाटे वाली सीपीएसई को समयबद्ध तरीके से बंद करने के लिए दिशानिर्देश	241
	6.3	घाटे में चल रहे चयनित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) की समीक्षा	241
	क) विनिवेश के लिए संदर्भित हानि उठाने वाली सीपीएसई		
	6.4	सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	242
	6.5	हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	246
	6.6	पीईसी लिमिटेड	257
	ब) घाटे में चल रहे सीपीएसई को अभी तक विनिवेश के लिए संदर्भित नहीं किया गया		

	6.7	नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	260
	6.8	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	276
	6.9	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, बेंगलुरु	289
अनुलग्नक	I	सरकारी कंपनियों/सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों/सांविधिक निगमों की सूची	309
	II	सीपीएसई जो 2021-22 के दौरान सीएजी ऑडिट के दायरे में आए/बाहर गए	330
	III क	बकाया लेखाओं या देय न होने वाले खातों या परिसमापनाधीन कंपनी का विवरण - सरकारी कंपनियां	332
	III ब	बकाया लेखाओं या परिसमापनाधीन कंपनी का विवरण - सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां	335
	IV	उन सरकारी कंपनियों की सूची जिनकी कुल परिसंपत्तियों का मूल्य 31.03.2022 तक बकाया दीर्घकालिक ऋणों से कम था	336
	V	65 सूचीबद्ध सीपीएसई के बाजार पूंजीकरण में वृद्धि और कमी	337
	VI	सरकारी कंपनियों और निगमों की सूची जिन्हें 2020-21 में घाटे की तुलना में 2021-22 के दौरान लाभ कमाने वाले सीपीएसई में जोड़ा गया	340
	VII	2021-22 में लाभ अर्जित करने वाली कंपनियों की सूची से बाहर रखी गई सरकारी कंपनियों की सूची	342
	VIII	31 मार्च 2022 तक शून्य या ऋणात्मक निवल संपत्ति वाली सरकारी कंपनियों की सूची	343
	IX	सरकारी कंपनियों द्वारा घोषित लाभांश में कमी	347
	X	सीपीएसई का विवरण जिन्हे लाभांश घोषित करना आवश्यक नहीं	352

XI	सरकारी कंपनियों और निगमों द्वारा नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	353
XII	सरकारी कंपनियों और निगमों की इक्विटी पर रिटर्न	423
XIII	उन सीपीएसई की सूची जिन्होंने अपने वित्तीय विवरण में संशोधन किया	485
XIV	उन सीपीएसई की सूची जहां सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट संशोधित की	486
XV	उन सीपीएसई की सूची जहां सीएजी द्वारा टिप्पणियां जारी की गईं	489
XVI	उन सीपीएसई का विवरण जहां सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखांकन मानक/इंड एस का अनुपालन न किए जाने की सूचना दी गई	492
XVII	उन सीपीएसई का विवरण जहां सीएजी द्वारा जारी प्रबंधन पत्रों के आधार पर महत्वपूर्ण सुधार किया गया	494
XVIII	उन सीपीएसई का विवरण जहां सीएजी द्वारा प्रबंधन पत्र जारी किए गए हैं	509
XIX	71 सीपीएसई की सूची जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थे और ऑडिट में शामिल हैं	517
XX	35 सीपीएसई/सांविधिक निगमों की सूची जिनके बांड/डिबेंचर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थे	520
XXI	उन 18 सीपीएसई की सूची जिनके शेयर और बांड दोनों स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थे	522
XXII	रणनीतिक विनिवेश की स्थिति	523
XXIII	लेखापरीक्षा के लिए चयनित सीपीएसई की सूची	525
XXIV	स्वतंत्र निदेशक वाले 38 सूचीबद्ध सीपीएसई की सूची	534
XXV	सीपीएसई वार कुल सीएसआर व्यय	536
XXVI	अधिनियम द्वारा सीपीएसई वार अनिवार्य सीएसआर व्यय बनाम वास्तविक आबंटन	544

XXVII	अतिरिक्त सीएसआर व्यय को समायोजित करने का दावा करने वाले सीपीएसई की सूची	550
XXVIII	सीपीएसई वार व्यय न की गई सीएसआर राशि	551
XXIX	सामान्य विषय-वस्तु पर सीएसआर व्यय	553
XXX	प्रभाव आकलन पर सीएसआर व्यय	555
XXXI	आधारभूत/आवश्यकता मूल्यांकन सर्वेक्षण आयोजित करने की स्थिति	556
XXXII	सीएसआर गतिविधियों की निगरानी की स्थिति	559
XXXIII	प्रभाव आकलन की स्थिति	562
XXXIV	सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से निर्मित/अर्जित पूंजीगत परिसंपत्तियों की स्थिति	567
XXXV	वर्ष 2016-17 से 2020-21 की अवधि के लिए हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचईसी) के लिए उत्पादन हेतु समझौता ज्ञापन लक्ष्य और उपलब्धियां	568
XXXVI	एचईसी के संयंत्रों और मशीनरी की स्थापित क्षमता और उपयोग	569
XXXVII	एचईसी के संबंध में आदेशों और निष्पादन की स्थिति	570
XXXVIII	वर्ष 2016-17 से 2021-22 की अवधि के दौरान एचईसी द्वारा निर्धारित समय में एवं निर्धारित समय से परे निष्पादित आदेशों का विवरण	571
XXXIX	2016-17 से 2021-22 के दौरान एचईसी की कार्यशील पूंजी	572
XL	अगस्त 2019 की बैठक में लिए गए निर्णय और पीईसी द्वारा उस पर की गई कार्रवाई	573
XLI	राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड (एनटीसी) की 23 संचालित मिलों की सूची	576
XLII	एनटीसी की 23 मिलों के आधुनिकीकरण की स्थिति और आधुनिकीकरण पर आने वाली लागत	577

	XLIII	2016-17 से 2019-20 के दौरान एनटीसी की 23 मिलों का क्षमता उपयोग	579
	XLIV	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) के परिचालन परिणाम	581
	XLV	एचओसीएल की वित्तीय स्थिति	582
	XLVI	सीसीईए अनुमोदन के अनुसार एचओसीएल की पुनर्गठन योजना	584
	XLVII	एचओसीएल की रसायनी इकाइयों में भूमि बिक्री की स्थिति	585
	XLVIII	एचओसीएल के क्यूमीन के भारी सिरों के अधिक उत्पादन के कारण उत्पादन में हानि	587

प्रस्तावना

1. कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्थापित सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के खातों की लेखापरीक्षा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के प्रावधानों के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। कंपनी अधिनियम के तहत सीएजी द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स) द्वारा प्रमाणित खाते सीएजी के अधिकारियों द्वारा पूरक लेखापरीक्षा के अधीन होते हैं और सीएजी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर अपनी टिप्पणियां देता है या उन्हें पूरक बनाता है। इसके अलावा, ये कंपनियां कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(7) के प्रावधानों के तहत सीएजी द्वारा नमूना लेखापरीक्षा के अधीन भी हैं।
2. कुछ निगमों और प्राधिकरणों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के अनुसार उनके खातों का लेखापरीक्षण सीएजी द्वारा किया जाना आवश्यक है। पाँच ऐसे निगमों के संबंध में, जैसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय खाद्य निगम और दामोदर घाटी निगम, प्रासंगिक कानून सीएजी को उनका एकमात्र लेखा-परीक्षक नामित करते हैं। एक निगम, जैसे केंद्रीय भंडारण निगम के संबंध में, केंद्रीय भंडारण निगम के खातों के लेखा-परीक्षण के लिए सीएजी की सलाह पर सरकार द्वारा लेखापरीक्षक नियुक्त किया जाता है। सीएजी को यह अधिकार है कि वह आवश्यकतानुसार लेखापरीक्षण कर सकता है।
3. किसी सरकारी कंपनी या निगम के खातों से संबंधित रिपोर्ट नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा

19-(क) के प्रावधानों के तहत संसद के समक्ष रखने के लिए सीएजी द्वारा सरकार को प्रस्तुत की जाती है।

4. यह 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सामान्य प्रयोजन वित्तीय रिपोर्ट है, जिसमें छह अध्याय हैं, अर्थात् केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय निष्पादन का सारांश, सीएजी की निगरानी भूमिका, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, विनिवेश प्रक्रिया, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और घाटे में चल रहे चयनित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की समीक्षा। सीपीएसई के संबंध में जहां किसी विशेष वर्ष के खाते 29 फरवरी, 2024 से पहले प्राप्त नहीं हुए थे, उस स्थिति में अंतिम बार ऑडिट किए गए खातों के आंकड़े लिए गए हैं। अध्याय-1 के कुछ सीपीएसई के संबंध में, पिछले वर्ष के आंकड़े लेखापरीक्षित /संशोधित आंकड़ों द्वारा अनंतिम आंकड़ों के प्रतिस्थापन के कारण 2022 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 27 में दिखाए गए संबंधित आंकड़ों से सहमत नहीं हो सकते हैं।

5. इस रिपोर्ट में 'कंपनियों/निगमों या सीपीएसईज़' के सभी संदर्भों को 'केन्द्र सरकार की कंपनियों/निगमों' के संदर्भ में समझा जा सकता है, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा न पता चले।

6. यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप आयोजित की गई है।

7. लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में सीपीएसई के प्रबंधन और उनके संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त सहयोग के लिए लेखापरीक्षा आभार व्यक्त करती है।

कार्यकारी सारांश

I. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश

परिचय

31 मार्च, 2022 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 698 केंद्रीय सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) थे। इनमें 490 सरकारी कंपनियाँ, 202 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ और छह वैधानिक निगम शामिल थे। यह रिपोर्ट 454 सरकारी कंपनियों और निगमों (छह वैधानिक निगमों सहित) और 188 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों से संबंधित हैं। इस रिपोर्ट में उन 56 सीपीएसई (जिनमें 14 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ शामिल हैं) को शामिल नहीं किया गया है, जिनके खाते तीन वर्ष या उससे अधिक समय से बकाया थे या परिसमापन के अधीन थे या जिनके पहले खाते बकाया नहीं थे।

(पैरा 1.1.3)

केन्द्र सरकार का निवेश

454 सरकारी कंपनियों और निगमों के खातों से पता चलता है कि 31 मार्च, 2022 तक केंद्र सरकार के पास शेयर पूंजी में ₹6,36,730 करोड़ की इक्विटी हिस्सेदारी थी। 31 मार्च 2022 तक इन सीपीएसई को केंद्र सरकार द्वारा दिए गए दीर्घकालिक ऋण की राशि ₹1,47,563 करोड़ थी। पिछले वर्ष की तुलना में, 2021-22 के दौरान सीपीएसई की इक्विटी में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी में ₹1,83,682 करोड़ की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई और दीर्घकालिक ऋण बकाया में ₹1,61,961 करोड़ की वृद्धि हुई।

(पैरा 1.2, 1.2.1 और 1.2.2.1)

बाजार पूंजीकरण

65 सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों (सात सहायक कंपनियों सहित) के शेयरों का कुल बाजार मूल्य, जिनके शेयरों में 2021-22 के दौरान कारोबार हुआ, 31 मार्च, 2022 तक ₹15,88,664 करोड़ था। 58 सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों (सात सहायक कंपनियों को छोड़कर) में केंद्र सरकार के पास मौजूद शेयरों का बाजार मूल्य 31 मार्च, 2022 तक ₹9,17,248 करोड़ था।

(पैरा 1.2.4)

सरकारी कंपनियों और निगमों से रिटर्न

258 सरकारी कंपनियों और निगमों ने 2021-22 के दौरान ₹2,69,307 करोड़ का लाभ कमाया, जिसमें से 69.18 प्रतिशत (₹1,86,317 करोड़) का योगदान तीन क्षेत्रों अर्थात् पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, बिजली और वित्तीय सेवाओं में 90 सीपीएसई द्वारा किया गया। इन 258 सीपीएसई का ऑन इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) 2021-22 में 15.50 प्रतिशत था, जबकि 2020-21 में 239 सीपीएसई का आरओई 13.11 प्रतिशत था।

(पैरा 1.3.1)

121 सरकारी कंपनियों और निगमों ने वर्ष 2021-22 के लिए ₹1,11,061 करोड़ के लाभांश की घोषणा की। इसमें से, केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त/प्राप्य लाभांश ₹54,381 करोड़ था, जो सभी 454 सरकारी कंपनियों और निगमों की इक्विटी पूंजी में केंद्र सरकार द्वारा किए गए कुल निवेश (₹6,36,730 करोड़) पर 8.54 प्रतिशत रिटर्न दर्शाता है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन नौ सरकारी कंपनियों ने 37,833 करोड़ रुपये का योगदान दिया, जो सभी सरकारी कंपनियों और निगमों द्वारा घोषित कुल लाभांश का 34.07 प्रतिशत है। 45 सीपीएसई द्वारा लाभांश की घोषणा पर भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन न करने पर, जिनके पास पर्याप्त निधि (प्रतिधारित आय और सामान्य रिजर्व) थी, के परिणामस्वरूप वर्ष 2021-22 के लिए लाभांश की घोषणा में ₹5,811 करोड़ की कमी हुई।

(पैरा 1.3.4)

हानि/संचित हानि

वर्ष 2021-22 के दौरान 170 सरकारी कंपनियों को ₹31,347 करोड़ का घाटा हुआ। 31 मार्च, 2022 तक 192 सरकारी कंपनियों का संचित घाटा ₹1,83,356 करोड़ था। इनमें से 79 कंपनियों की निवल मूल्य उनके संचित घाटे के कारण पूरी तरह खत्म हो गई थी। नतीजतन, 31 मार्च 2022 तक इन कंपनियों की कुल निवल मूल्य ₹75,186 करोड़ की सीमा तक नकारात्मक हो गई थी। इन 79 कंपनियों में से केवल 15 ने वर्ष 2021-22 के दौरान ₹1,111 करोड़ का लाभ कमाया।

(पैरा 1.3.2 और 1.3.3)

बिक्री और विपणन

454 सरकारी कंपनियों और निगमों की कुल बिक्री ₹31,18,281 करोड़ थी। इन सीपीएसई में से, 142 सीपीएसई ने सरकारी क्षेत्र को ₹3,92,660 करोड़ मूल्य के वस्तुएं बेचीं/सेवाएँ प्रदान कीं, जो उनकी कुल बिक्री का 25.22 प्रतिशत था।

(पैरा 1.4.3)

II. सीएजी की निगरानी भूमिका

सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के तहत 692 सीपीएसई में से (छह वैधानिक निगमों को छोड़कर), वर्ष 2021-2022 के लिए 592 सीपीएसई से वित्तीय विवरण 30 सितंबर, 2022 तक प्राप्त हुए। जबकि आठ सीपीएसई से वित्तीय विवरण देय नहीं थे, 92 सीपीएसई के वित्तीय विवरण 30 सितंबर, 2022 तक विभिन्न कारणों से लंबित थे।

(पैरा 2.3.2)

30 सितंबर, 2022 तक जिन 592 सीपीएसई से वित्तीय विवरण प्राप्त हुए, उनमें से 379 सीपीएसई में अनुपूरक लेखा परीक्षा की गई।

(पैरा 2.5.1)

सात सीपीएसई ने अपने वित्तीय विवरणों में संशोधन किया और 88 सीपीएसई के वैधानिक लेखा परीक्षकों ने वार्षिक आम बैठक में वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने से पहले अपनी

लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधन किया। इसके अलावा, 92 सीपीएसई के संबंध में वित्तीय विवरणों में अशुद्धियों को उजागर करने वाली विभिन्न टिप्पणियाँ भी जारी की गईं।

चयनित सीपीएसई के वित्तीय विवरणों पर जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियों का लाभप्रदता और परिसंपत्तियों/देनदारियों पर वित्तीय प्रभाव क्रमशः ₹4,498 करोड़ और ₹2,88,460 करोड़ था।

कुछ कम्पनियों अर्थात् उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, आईएफसीआई लिमिटेड, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने पूर्व में वित्तीय विवरणों पर जारी टिप्पणियों पर सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की।

(पैरा 2.5.1.1, 2.5.1.2 और 2.5.1.3)

सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा 19 सीपीएसई में वित्तीय विवरण तैयार करने में लेखा मानकों/ इंड एएस के प्रावधानों से विचलन पाया गया। सीएजी ने भी 12 सीपीएसई में ऐसे विचलनों की ओर इशारा किया।

(पैरा 2.6)

पूरक लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई वित्तीय रिपोर्टों या रिपोर्टिंग प्रक्रिया में अनियमितताएं और कमियां, जो महत्वपूर्ण नहीं थीं, उन्हें सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए 'प्रबंधन पत्र' के माध्यम से 240 सीपीएसई के प्रबंधन को सूचित किया गया था।

(पैरा 2.7)

III. कॉर्पोरेट गवर्नेंस

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की समीक्षा में 71 सूचीबद्ध सीपीएसई शामिल थे, जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध थे (जिनमें 18 सीपीएसई शामिल हैं जिनके शेयर और बॉन्ड/डिबेंचर दोनों सूचीबद्ध थे) और तीन वैधानिक निगमों (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और भारतीय खाद्य निगम) सहित 35 सीपीएसई, जिनके केवल बॉन्ड/डिबेंचर 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के दौरान मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण में स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध थे। यह देखा गया कि कुछ सीपीएसई/सांविधिक निगमों द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशा-निर्देशों और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के विनियमों का अनुपालन नहीं किया जा रहा था।

गैर-अनुपालन के मामलों का सारांश नीचे दिया गया है:

26 सीपीएसई (37 प्रतिशत) में गैर-कार्यकारी निदेशक बोर्ड की ताकत के 50 प्रतिशत से कम थे; 55 सीपीएसई (77 प्रतिशत) में बोर्ड में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

(पैरा 3.2.1 और 3.2.2.1)

20 सीपीएसई (28 प्रतिशत) के बोर्ड में कोई महिला निदेशक नहीं थी। इसके अलावा, 41 सूचीबद्ध सीपीएसई (शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं का हिस्सा) के बोर्ड में 2021-22 की पूरी/आंशिक अवधि के दौरान कोई महिला स्वतंत्र निदेशक नहीं थी।

(पैरा 3.2.3)

सात सीपीएसई (शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं का हिस्सा) में न्यूनतम छह निदेशकों का मानदंड पूरा नहीं किया गया था।

(पैरा 3.2.4)

सात सीपीएसईज (10 प्रतिशत) के स्वतंत्र निदेशकों ने बोर्ड और समितियों की कम से कम 80 प्रतिशत बैठकों में भाग नहीं लिया ।

(पैरा 3.4.1)

आठ सीपीएसई (11 प्रतिशत) में पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के रिक्त पदों को छह माह की अवधि के भीतर नहीं भरा गया।

(पैरा 3.6)

11 सीपीएसई (15 प्रतिशत) में लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया था; 28 सीपीएसई (39 प्रतिशत) में लेखापरीक्षा समिति के दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक नहीं थे; आठ सीपीएसई (11 प्रतिशत) में लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष एजीएम में शामिल नहीं हुए। आठ सीपीएसई (11 प्रतिशत) में लेखा परीक्षा समिति की कम से कम चार बैठकें आयोजित नहीं की गईं और 27 सीपीएसई (38 प्रतिशत) में लेखा परीक्षा समिति का कोरम अपर्याप्त था।

(पैरा 3.8.1.1, 3.8.1.2, 3.9, 3.8.3, और 3.8.4)

12 सीपीएसई (17 प्रतिशत) में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया गया था तथा 18 सीपीएसई (25 प्रतिशत) में इसकी संरचना अपर्याप्त थी।

(पैरा 3.12)

सात सीपीएसई (10 प्रतिशत) में हितधारक संबंध समिति का गठन नहीं किया गया था और आठ सीपीएसई (11 प्रतिशत) में इसकी संरचना अपर्याप्त थी।

(पैरा 3.13)

71 सीपीएसई में से, छह सीपीएसई (8 प्रतिशत) में जोखिम प्रबंधन समिति का गठन नहीं किया गया था; नौ सीपीएसई (13 प्रतिशत) में जोखिम प्रबंधन समिति की वर्ष के दौरान दो बार बैठक नहीं हुई और छह सीपीएसई (8 प्रतिशत) में जोखिम प्रबंधन समिति की दो बैठकों के बीच 180 दिनों से अधिक का अंतराल देखा गया।

(पैरा 3.15)

अनुशंसा:

प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग डीपीई निर्देशों/सेबी दिशा-निर्देशों/विनियमों में निर्धारित अनुसार सूचीबद्ध सीपीएसई सांविधिक निगमों द्वारा तिमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर सकते हैं। लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि सूचीबद्ध सीपीएसई सांविधिक निगमों के निदेशक मंडल को भी इन दिशा-निर्देशों/विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए ताकि सीपीएसई सांविधिक निगमों के कामकाज में बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जा सके।

(पैरा 3.15)

IV. विनिवेश प्रक्रिया

निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम) ने वर्ष 22-2021 के दौरान विनिवेश (रणनीतिक विनिवेश, बिक्री के लिए प्रस्ताव, शेयरों की पुनर्खरीद, अवशिष्ट स्टॉक बिक्री, शत्रु शेयर बिक्री और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निर्दिष्ट उपक्रम) के माध्यम से 13,534 ₹ करोड़ की राशि प्राप्त की। लेखापरीक्षा के दौरान, निम्नलिखित मुद्दे देखे गए:

सीपीएसई के विनिवेश का लक्ष्य और उपलब्धि

विनिवेश के माध्यम से प्राप्तियों के बजट अनुमानों में वर्ष 2021-22 को छोड़कर हर वर्ष वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई, जहां यह 2020-21 के बजट अनुमान ₹2,10,000 करोड़ से 16.67 प्रतिशत घटकर ₹1,75,000 करोड़ रह गया।

संशोधित अनुमान चरण में ₹1,75,000 करोड़ के बजट अनुमान को घटाकर ₹78,000 करोड़ कर दिया गया। हालाँकि, वास्तविक प्राप्ति संशोधित अनुमान का केवल 17 प्रतिशत थी।

(पैरा 4.4)

प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से विनिवेश से प्राप्ति की तुलना में अनुमानित प्राप्ति

भारतीय जीवन बीमा निगम और टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड को बजट अनुमान चरण में आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से विनिवेश के लिए चुना गया था, लेकिन वर्ष 2021-22 के दौरान इसे मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। हालाँकि, 2022-23 के दौरान एलआईसी में ₹20,516.12 करोड़ की राशि प्राप्त हुई, जो कि ₹50,000 करोड़ के अनुमानित अनुमान से कम थी।

(पैरा 4.6.1)

बिक्री प्रस्ताव के माध्यम से विनिवेश से प्राप्त राशि की तुलना में अनुमानित प्राप्ति

बजट अनुमान/संशोधित अनुमान चरण में बिक्री के लिए प्रस्ताव के माध्यम से विनिवेश के लिए 16 सीपीएसई की पहचान की गई थी। केवल तीन सीपीएसई अर्थात् राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में बिक्री के लिए प्रस्ताव 2021-22 के दौरान पूरा किया जा सका, जिसमें शुद्ध आय ₹5,116 करोड़ थी, जो संशोधित अनुमान चरण में अनुमानित राशि का 34.05 प्रतिशत थी।

(पैरा 4.6.2.1)

खुदरा और कर्मचारियों की बिक्री के लिए प्रस्ताव लक्ष्य की प्राप्ति

खुदरा निवेशकों और कर्मचारियों के लिए तीन सीपीएसई (हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड) में कर्मचारियों के लिए किए गए बिक्री प्रस्ताव में, खुदरा निवेशकों से प्राप्त अभिदान 18.39 और 75.56 प्रतिशत के बीच था और कर्मचारियों से अभिदान 0.05 प्रतिशत और 1.66 प्रतिशत के बीच था।

(पैरा 4.6.2.2)

मॉयल लिमिटेड में शेयरों की पुनर्खरीद

वर्ष 2021-22 के संशोधित अनुमान चरण में शेयरों की पुनर्खरीद (मॉयल लिमिटेड) के एक लेनदेन की पहचान की गई, जिसकी अनुमानित आय ₹400 करोड़ थी। मॉयल लिमिटेड द्वारा पुनर्खरीद प्रक्रिया के बाद सरकार को ₹393.77 करोड़ की आय प्राप्त हुई।

(पैरा 4.7)

विनिवेश प्राप्तियों को ₹1,107 करोड़ तक बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया

विनिवेश प्राप्तियों के तहत यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निर्दिष्ट उपक्रम द्वारा दीपम को प्रेषित ₹1,107 करोड़ की ब्याज और लाभांश आय को शामिल करने के परिणामस्वरूप वर्ष 2021-22 के दौरान विनिवेश प्राप्तियों को ₹1,107 करोड़ से अधिक बताया गया।

(पैरा 4.9)

एयर इंडिया के प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ-साथ रणनीतिक विनिवेश

एयर इंडिया लिमिटेड का रणनीतिक विनिवेश 2021-22 के दौरान ₹18,000 करोड़ में पूरा हुआ, जिसमें एयर इंडिया लिमिटेड में भारत सरकार की 100 प्रतिशत इक्विटी के साथ-साथ प्रबंधन नियंत्रण मेसर्स टैलेस प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित किया गया। वर्ष 2017 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा 'सैद्धांतिक' स्वीकृति दी गई थी। इस लेन-देन में ₹2,700 करोड़ का नकद प्रतिफल और मेसर्स टैलेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अधिग्रहित एयर इंडिया लिमिटेड के ₹15,300 करोड़ के ऋण शामिल थे। विनिवेश की प्रक्रिया के दौरान भारत सरकार को ₹88,036.17 करोड़ का शुद्ध वित्तीय भार वहन करना पड़ा।

{पैरा 4.10.1, 4.10.2 (iv)}

V. कॉर्पोरेट की सामाजिक उत्तरदायित्व

समीक्षा में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले 63 सीपीएसई (11 महारत्न, 09 नवरत्न, 29 मिनीरत्न और 14 अन्य) को शामिल किया गया। समीक्षा के दौरान 63 सीपीएसई के संबंध में मार्च 2022 को समाप्त एक वर्ष की अवधि को शामिल किया गया।

समीक्षा में निम्नलिखित महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ की गईं:

तीन सीपीएसई (एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनएलसी इंडिया लिमिटेड और एसजेवीएन लिमिटेड) की सीएसआर समिति ने वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के अनुसार समिति में तीन निदेशकों की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा नहीं किया।

(पैरा 5.5.1.1)

2021-22 में 63 सीपीएसई द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर कुल व्यय ₹4,005.30 करोड़ था। पेट्रोलियम और पावर क्षेत्र पर व्यय, कुल व्यय का 68.03 प्रतिशत था। रक्षा, रेलवे, पोत परिवहन, उर्वरक और अन्य क्षेत्रों में सीएसआर गतिविधियों के अनुसार न्यूनतम 2 प्रतिशत की आवश्यकता के मुकाबले व्यय में कमी थी। सीएसआर निधि के आवंटन के तहत, लेखापरीक्षा ने पाया कि 14 सीपीएसई ने 2 प्रतिशत से भी कम आवंटित किया। तीन सीपीएसई (डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और एमएसटीसी लिमिटेड) ने नकारात्मक लाभ के कारण धन आवंटित नहीं किया।

(पैरा 5.5.2.1 और 5.5.2.2)

छह सीपीएसई (भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) ने 2021-22 के दौरान सीएसआर गतिविधियों से अधिशेष उत्पन्न किया था।

(पैरा 5.5.2.7)

सीएसआर के अनुसार, सीपीएसई को इस अवधि के दौरान आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता देते हुए कोविड से संबंधित उपायों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य और पोषण से

संबंधित विषयों पर कम से कम 60 प्रतिशत खर्च करना आवश्यक था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 60 सीपीएसई में से केवल 39 सीपीएसई ही 2021-22 के दौरान सामान्य विषय पर खर्च किए जाने वाले 60 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त कर सके।

(पैरा 5.6.2)

पांच सीपीएसई (एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, राइट्स लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) ने वर्ष 2021-22 के दौरान 5 प्रतिशत की ओवरहेड व्यय सीमा को पार कर लिया। 63 सीपीएसई में से 25 ने सीएसआर परियोजना/गतिविधि की पहचान के लिए आधारभूत सर्वेक्षण/आवश्यकता मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और झारखंड सरकार के बीच समझौता ज्ञापन में परिकल्पित लक्ष्य की पूर्ति/उपलब्धि नहीं होना।

(पैरा 5.7 और 5.8.1)

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के तहत निर्धारित अयोग्य निधियों में ₹27.84 करोड़ का योगदान दिया।

(पैरा 5.9)

आठ सीपीएसई ने सीएसआर संशोधन नियम, 2021 के नियम 8 और नियम 9 के अनुपालन में वैधानिक प्रकटीकरण आवश्यकता का पूरी तरह से पालन नहीं किया था। दो सीपीएसई (आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनुयुफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और सेल रिफ्रेक्टरी कंपनी लिमिटेड) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में सीएसआर गतिविधियों पर रिपोर्टिंग करते समय प्रकटीकरण प्रारूप का अनुपालन नहीं किया। तीन सीपीएसई (चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, पावर ग्रिड सदरन इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इनकॉर्पोरेटेड) ने अपनी वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं का खुलासा नहीं किया था।

(पैरा 5.12)

VI. घाटे में चल रहे चयनित सीपीएसई की समीक्षा

घाटे में चल रहे सीपीएसई की समीक्षा से पता चला कि घाटे में चल रहे सीपीएसई की संख्या 143 से 177 के बीच थी और 2017-18 से 2021-22 के दौरान उन्हें ₹31,347 करोड़ से ₹56,294 करोड़ के बीच घाटा हुआ। इस प्रकार, 2017-22 के दौरान सीपीएसई को कुल ₹2,03,709 करोड़ का घाटा हुआ।

(पैरा सं. 6.1)

सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एससीएल) अपने अस्तित्व में आने के 19 साल (सितंबर 2024) बाद भी अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू नहीं कर सका। मंत्रालय ने कंपनी को बंद करने के लिए गतिविधियों को पूरा करने के लिए समयसीमा निर्धारित करने का (जून 2021 निर्देश दिया)। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में लंबित विभिन्न मुकदमों के कारण एससीएल का समापन अभी पूरा नहीं हुआ (सितंबर 2024)।

अनुशंसा संख्या 1:

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, एससीएल को बंद करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक कदम उठा सकता है।

(पैरा सं. 6.4.4)

हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचईसी) के मामले में, कार्यशील पूंजी की कमी और तरलता की समस्या, नियमित नकदी प्रवाह में कमी के कारण तीव्र निधि की कमी, पुराने संयंत्र और मशीनरी कम दक्षता के साथ काम कर रहे थे और बार-बार टूट रहे थे, प्रौद्योगिकी उन्नयन की कमी और कम जनशक्ति उत्पादकता आदि के कारण उत्पादन में कमी और कम क्षमता का उपयोग हुआ। खराब वित्तीय स्थिति के कारण, कंपनी अपने कुछ वैधानिक और कर्मचारियों के बकाये का समय पर भुगतान करने में असमर्थ थी। कंपनी ने एक आधुनिकीकरण योजना प्रस्तुत की थी जिसे अभी (जुलाई 2024) मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाना था।

(पैरा सं. 6.5)

अनुशंसा संख्या 2:

भारी उद्योग मंत्रालय एचईसी के परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन के मद्देनजर इसकी निरंतरता की स्थिरता की शीघ्र समीक्षा कर सकता है।

(पैरा सं. 6.5.2.8)

लेखापरीक्षा ने पाया कि पीईसी लिमिटेड को बंद करने के निर्णय के लगभग तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति से अनुमोदन प्राप्त होना नतीजतन, एक तरफ, कंपनी अपने परिचालन को बंद करने के कारण कोई राजस्व अर्जित नहीं कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ, उसे बकाया ऋणों पर भारी ब्याज बोझ के अलावा प्रशासनिक और स्थापना लागतों के लिए खर्च करना पड़ा।

अनुशंसा संख्या 3:

वाणिज्य विभाग को सार्वजनिक उद्यम विभाग के साथ समन्वय करके पीईसी लिमिटेड को बंद करने की प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए, क्योंकि देरी से कंपनी पर ब्याज का बोझ और प्रशासनिक लागत ही बढ़ेगी।

(पैरा सं. 6.6.3)

नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनटीसी) ने अप्रैल 2015 से मार्च 2022 के दौरान भारतीय कपास निगम से खुले बाजार की तुलना में महंगी कपास की खरीद पर ₹38.48 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

अनुशंसा संख्या 4:

एनटीसी उचित/प्रतिस्पर्धी दरों पर कच्चा माल खरीद सकता है जिससे उत्पादन लागत कम हो जाएगी।

{पैरा 6.7.4.1(i)}

एनटीसी ने मई 2020 से मार्च 2022 तक 6,140 श्रमिकों को मिलों के गैर-संचालन के कारण 50 प्रतिशत की दर से निष्क्रिय मजदूरी के लिए ₹112.75 करोड़ का भुगतान किया।

अनुशंसा संख्या 5:

एनटीसी को मिलों के अधिशेष/निष्क्रिय श्रमिकों को लाभकारी रोजगार प्रदान करने के लिए उनकी पुनर्नियुक्ति की आवश्यकता का आकलन करने की आवश्यकता है।

{पैरा 6.7.4.1(ii)}

एनटीसी द्वारा छत्तों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के तौर-तरीकों पर निर्णय लेने में देरी के परिणामस्वरूप ऊर्जा लागत में बचत प्राप्त करने के अवसर की अपरिहार्य हानि हुई।

अनुशंसा संख्या 6:

एनटीसी बिजली की लागत कम करने के लिए कदम उठा सकती है तथा छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने की दिशा में कार्रवाई में तेजी ला सकती है।

{पैरा 6.7.4.1(iii)}

वर्ष 2006-07 से 2008-09 के दौरान, भारत सरकार ने वेतन सहायता के लिए एनटीसी को ₹270 करोड़ का ऋण दिया। एनटीसी ने ऋण के पुनर्गठन के लिए मंत्रालय को कोई योजना प्रस्तुत नहीं की। परिणामस्वरूप, 31 मार्च, 2022 तक ₹270 करोड़ का मूल ऋण और उस पर ₹631.19 करोड़ का उपार्जित ब्याज बकाया था।

अनुशंसा संख्या 7:

एनटीसी, ऋण पर ब्याज के संचय से बचने के लिए यथाशीघ्र मंत्रालय को पुनर्गठन योजना प्रस्तुत करे।

{पैरा 6.7.4.2(i)}

एनटीसी ने बिना किसी सुरक्षा के ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन को ब्रिज लोन जारी कर दिया। 31 मार्च, 2022 तक, ₹66.10 करोड़ की मूल राशि और ₹125.35 करोड़ के ब्याज सहित ₹191.45 करोड़ की धनराशि एनटीसी द्वारा दिए गए ऋणों के कारण ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन के पास अवरुद्ध थी।

अनुशंसा संख्या 8:

एनटीसी किसी भी ऋण को जारी करने से पहले पर्याप्त संपार्श्विक सुरक्षा लेकर और ऋण देते समय उधारकर्ता की विश्वसनीयता पर उचित विचार करके अपने हितों की रक्षा कर सकती है।

{पैरा 6.7.4.2(ii)}

31 मार्च, 2022 तक एनटीसी के पास क्रमशः ₹8.28 करोड़ और ₹32.29 करोड़ मूल्य के धागे और कपड़े का स्टॉक एक साल से अधिक समय से पड़ा हुआ था। समय बीतने के साथ, इसके प्राप्ति योग्य मूल्य में कमी से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अनुशंसा संख्या 9:

एनटीसी को चाहिए कि वह शीघ्रातिशीघ्र माल (कच्चा माल और तैयार माल) के निपटान के लिए एक प्रणाली विकसित करे, ताकि धन की कमी को दूर किया जा सके तथा मिलों के सुचारु संचालन के लिए कार्यशील पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

{पैरा 6.7.4.3(i)}

वर्ष 2009 में निपटान की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से 15 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी एनटीसी मिलों में अप्रचलित मशीनरी का निपटान अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

अनुशंसा संख्या 10:

एनटीसी अप्रचलित वस्तुओं के निपटान के लिए एक व्यापक नीति तैयार कर सकता है ताकि ऐसी वस्तुओं का समय पर निपटान किया जा सके और उनका इष्टतम मूल्य प्राप्त किया जा सके।

{पैरा 6.7.4.3(ii)}

हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड की रसायनी इकाई में परिसंपत्तियों के निपटान की पूरी प्रक्रिया मई 2018 तक पूरी होनी थी, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों द्वारा भूमि क्षेत्र पर अतिक्रमण के कारण इस प्रक्रिया में बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ा। नतीजतन, आज तक केवल 40 प्रतिशत भूमि का ही मुद्रीकरण किया जा सका है और यहां तक कि बीपीसीएल को बेची गई भूमि भी उनके द्वारा अधिग्रहित नहीं की गई है।

अनुशंसा संख्या 11:

भूमि मुद्रीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता है ताकि कंपनी की वित्तीय देनदारियों को कम किया जा सके और इस प्रकार इसकी वित्तीय लागत में कमी लाई जा सके।

(पैरा 6.8.4.2)

भूमि बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग वीआरएस लागू करने, वेतन, वैधानिक/लेनदारों के बकाया का भुगतान करने तथा ऋणों के हिस्से का भुगतान करने के लिए किया गया। इससे कोच्चि इकाई तथा कंपनी के परिचालन प्रदर्शन में काफी सुधार हुआ। हालांकि, भूमि मुद्राकरण प्रक्रिया को पूरा करने में लगातार देरी के कारण, शेष सरकारी ऋणों पर ब्याज प्रतिबद्धताएं इसके वित्तीय स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही थी। बेंचमार्क ऋण दरों की तुलना में, सरकारी ऋणों की दर अधिक थी, जिसकी सरकार द्वारा समीक्षा की जा सकती है।

अनुशंसा संख्या 12:

सरकार ब्रिज लोन पर लगाए गए दरों की समीक्षा करें।

(पैरा 6.8.4.3)

कोच्चि इकाई को एक निजी निर्माता से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था, जिसका परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन कंपनी से कहीं बेहतर था। परिचालन का कम स्तर और इसके परिणामस्वरूप उच्च निश्चित लागत, तकनीकी अप्रचलन और उत्पाद विविधीकरण की कमी इसके परिचालन प्रदर्शन को प्रभावित करने वाली मुख्य बाधाएँ बनी हुई थी।

अनुशंसा संख्या 13:

सरकार तकनीकी-वाणिज्यिक अध्ययन और बाजार विश्लेषण के आलोक में कंपनी के परिचालन की स्थिरता की समीक्षा कर सकती है और गैर-रणनीतिक क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश हेतु अपनी वर्तमान नीति को लागू कर सकती है ताकि कंपनी के संचालन से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके ।

(पैरा सं.6.8.7)

एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड (एचएमटी एमटी) अपनी स्थापना (अप्रैल 2000) से ही घाटे में चल रही है और भारत सरकार और होल्डिंग कंपनी से ₹1,377.47 करोड़ (2007 से 2022 के दौरान) की वित्तीय सहायता प्राप्त होने के बावजूद, कंपनी अपने वित्तीय प्रदर्शन में सुधार नहीं कर सकी। 31 मार्च, 2022 तक, कंपनी को ₹1,932.26 करोड़ का घाटा हुआ था और निवल मूल्य घटकर (-) ₹1,684.74 करोड़ रह गई थी।

(पैरा 6.9.2.1)

कंपनी के पास दीर्घकालिक दृष्टि और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित कॉर्पोरेट/रणनीतिक योजना नहीं थी। हालाँकि जोखिम प्रबंधन नीति को मंजूरी दे दी गई थी (मई 2019), जोखिमों की जल्द पहचान के लिए जोखिम प्रबंधन समिति का गठन नहीं किया गया था, जिसमें प्रौद्योगिकी, बाजार की गतिशीलता, प्रतिस्पर्धा आदि के क्षेत्र में विविधीकरण से जुड़े जोखिम और उनका उचित शमन शामिल था।

अनुशंसा संख्या 14:

कंपनी दीर्घकालिक दृष्टि और लक्ष्यों के लिए कॉर्पोरेट रणनीतिक योजना तैयार कर सकती है और निदेशक मंडल से अनुमोदन प्राप्त कर सकती है। कंपनी को जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार जोखिम प्रबंधन समिति का गठन भी करना चाहिए और उसे क्रियान्वित करना चाहिए।

(पैरा 6.9.2.2)

कंपनी धन के विचलन तथा भारत सरकार से आगे धन प्राप्त न होने के कारण अपने उत्पादों को नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ उन्नत करने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप व्यापार के अवसरों का नुकसान हुआ तथा बेंगलुरु परिसर में सीएनसी सिस्टम प्रभाग को बंद करना पड़ा।

अनुशंसा संख्या 15:

यदि मंत्रालय एचएमटी एमटी का परिचालन जारी रखने का इरादा रखता है, तो कंपनी नवीनतम प्रौद्योगिकियों को उन्नत करने/अधिग्रहित करने की प्रक्रिया में तेजी ला सकती है, ताकि कंपनी का बाजार हिस्सा बढ़ सके और कंपनी का परिचालन व्यवहार्य हो सके।

(पैरा 6.9.2.3)

अप्रभावी विपणन प्रणाली और नवीनतम बाजार दरों के साथ मूल्य निर्धारण तंत्र की समीक्षा न करने तथा लंबी डिलीवरी अनुसूचियों के परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2022 को समाप्त पिछले छह वर्षों के दौरान ₹2,020.90 करोड़ के व्यावसायिक अवसरों का नुकसान हुआ। मशीनों की विलम्बित आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग के साथ-साथ प्रभावी अनुसरण और अनुवर्ती कार्रवाई के अभाव के परिणामस्वरूप ₹215.54 करोड़ की व्यापार प्राप्तियां एकत्रित हुईं, जिनमें से ₹73.86 करोड़ संदिग्ध थे।

अनुशंसा संख्या 16:

कंपनी को अपने मार्केटिंग डिवीज़न को मज़बूत करना चाहिए और बाज़ार की मांग और ग्राहक विनिर्देशों को जानने के लिए उद्योग विश्लेषण और आवधिक सर्वेक्षण करना चाहिए ताकि नवीनतम मूल्य निर्धारण/उत्पाद मिश्रण/उत्पाद डिज़ाइन को अपनाया जा सके और बाज़ार में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकें। कंपनी आपूर्तिकर्ताओं के साथ सख्ती से अनुवर्ती कार्रवाई भी कर सकती है और समय पर व्यापार प्राप्तियों को वसूल कर सकती है।

(पैरा 6.9.2.5)

पांच वर्षों से अधिक समय से ₹15.74 करोड़ मूल्य की भारी मात्रा में नॉन-मूविंग इन्वेंट्री पड़े रहने तथा कार्यशील पूंजी की भारी कमी के बावजूद, कंपनी ने नॉन-मूविंग इन्वेंट्री की उपयोगिता या निपटान का आकलन करने के लिए इसकी समीक्षा करने हेतु कोई तकनीकी समिति गठित नहीं की थी।

अनुशंसा संख्या 17:

कंपनी नॉन-मूविंग इन्वेंट्री की समीक्षा और उसके परिसमापन के लिए समय-समय पर तकनीकी समितियों का गठन कर सकती है।

(पैरा 6.9.2.6)

भूमि की सुरक्षा में विकलता के परिणामस्वरूप प्रागा टूल्स में 28.05 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण हो गया। समय पर कार्रवाई करने में एचएमटी एमटी की ओर से ढिलाई के कारण हैदराबाद इकाई द्वारा धारित भूमि के लिए स्पष्ट स्वामित्व प्राप्त करने में विफलता हुई। 31 मार्च, 2022 तक 23.450 एकड़ भूमि का वास्तविक स्वामित्व और मार्च 2001 में व्यवस्था योजना के अनुसार आवंटित भूमि के साथ मिलान नहीं किया जा सका। खाली भूमि और अप्रयुक्त बुनियादी ढांचे का मुद्राकरण न होने के कारण वैधानिक बकाया के भुगतान के अलावा लंबे समय से चले आ रहे ऋणों को चुकाने और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए धन जुटाने में विफलता हुई।

अनुशंसा संख्या 18:

कंपनी अपने पक्ष में टाइटल डीड को स्थानांतरित करवाने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ सख्ती से संपर्क कर सकती है और अतिक्रमण हटाने के लिए आवश्यक

कदम उठा सकती है। कंपनी गैर-परिचालन परिसंपत्तियों की पहचान करने और कार्यशील पूंजी के लिए धन जुटाने और वैधानिक बकाया के भुगतान के लिए जल्द से जल्द उनका मुद्रीकरण करने के अपने प्रयासों को तेज कर सकती है। कंपनी अपनी अजमेर, कलमस्सेरी और बंगलुरु इकाइयों में भूमि जोत में विसंगति को भी दूर कर सकती है।

(पैरा 6.9.2.7)

कंपनी के बोर्ड, होल्डिंग कंपनी और भारी उद्योग विभाग की ओर से निगरानी में चूक देखी गई। वरिष्ठ प्रबंधन में रिक्तियां थीं (मार्च 2014 से कोई पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक नहीं था और नवंबर 2017 से पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक की अनुपस्थिति थी) जिसने कंपनी के निर्णय लेने को गंभीर रूप से प्रभावित किया। भारी उद्योग विभाग की ओर से निर्णय लेने और अनुमोदन में देरी भी देखी गई।

अनुशंसा संख्या 19:

भारी उद्योग विभाग घाटे में चल रही इकाइयों के पुनर्गठन/पुनरुद्धार या बंद करने/विलय के लिए समय पर निर्णय ले सकता है, ताकि कंपनी पर और अधिक घाटे का बोझ न पड़े।

(पैरा 6.9.2.9)

प्रथम अध्याय

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश

1.1 परिचय

सरकारी कंपनी को कम्पनी अधिनियम, 2013 के धारा 2(45) में इस प्रकार परिभाषित किया गया है: कि एक ऐसी कंपनी जिसमें प्रदत्त शेयर पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत केंद्र सरकार, या किसी राज्य सरकार या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा, या आंशिक रूप से सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारण की जाती है, और इसमें एक ऐसी कंपनी भी शामिल है जो एक सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी है।

सरकारी कंपनी

कंपनी जिसमें प्रदत्त शेयर पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत केंद्र सरकार, या किसी राज्य सरकार या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा, या आंशिक रूप से सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारण की जाती है, और इसमें एक ऐसी कंपनी भी शामिल है जो एक सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी है।

इसके अलावा, कोई भी अन्य कंपनी¹ जो केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या एक से अधिक राज्य सरकारों के या आंशिक रूप से केंद्र सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में स्वामित्व में या उनसे नियंत्रित होती है, को इस रिपोर्ट में "सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ" के रूप में संदर्भित किया जाता है।

रिपोर्ट का यह अध्याय सरकारी कंपनियों, वैधानिक निगमों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश प्रस्तुत करता है। इस रिपोर्ट में "केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम" (सीपीएसई) शब्द का अर्थ उन सरकारी कंपनियों से है, जिनमें केंद्र सरकार की सीधी हिस्सेदारी 50 प्रतिशत या उससे अधिक होती है और ऐसी सरकारी

¹ कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 04 सितम्बर, 2014 के राजपत्र अधिसूचना के तहत कंपनी (कठिनाइयों को दूर करना) सातवां आदेश, 2014 जारी किया गया।

कंपनियों की सहायक कंपनियाँ भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों के तहत स्थापित वैधानिक निगमों और अन्य कंपनियाँ, जो केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व में हैं या उनसे नियंत्रित हैं, उन्हें भी सीपीएसई के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है।

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने दिसंबर 2022 में अपने सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2021-22 में उल्लेख किया कि सीपीएसई उन सरकारी कंपनियों को कहा जाता है, वैधानिक निगमों के अतिरिक्त, जिनमें केंद्र सरकार की 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी होती है। इन कंपनियों की सहायक कंपनियाँ, यदि भारत में पंजीकृत हैं, तो उन्हें भी सीपीएसई के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है। इसमें विभागीय रूप से चलाए जाने वाले सार्वजनिक उद्यमों, बैंकिंग संस्थानों और बीमा कंपनियों को शामिल नहीं किया जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) और डीपीई द्वारा अपनाई गई परिभाषाओं में अंतर के कारण सीएजी और डीपीई द्वारा सीपीएसई के रूप में मानी गई कंपनियों की संख्या में भी अंतर था। परिणामस्वरूप, डीपीई के सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सीपीएसई की संख्या 389 थी जबकि इस रिपोर्ट के अनुसार सीपीएसई की संख्या 698 थी (496 सरकारी कंपनियाँ और वैधानिक निगम और 202 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ)।

1.1.1 अधिदेश

सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों और सीएजी के (कर्तव्य, अधिकार और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के तहत किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत, सीएजी सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को वैधानिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त करता है और इन कंपनियों के खातों के लेखापरीक्षा के मामलों पर निर्देश देता है। इसके अतिरिक्त, सीएजी को पूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार भी है। कुछ वैधानिक निगमों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के अनुसार उनके खातों का लेखापरीक्षा केवल सीएजी द्वारा ही किए जाने का प्रावधान है।

भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा राष्ट्रीय आवास बैंक को नियंत्रित करने वाले अधिनियमों में ऐसे प्रावधान हैं जिनके अंतर्गत केंद्र सरकार किसी भी समय सीएजी को इन संस्थानों के खातों की जांच और रिपोर्ट के लिए लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त कर सकती है। वर्ष 2021-22 तक ऐसी कोई नियुक्ति नहीं की गई थी।

1.1.2 इस रिपोर्ट में क्या है

यह रिपोर्ट, सीपीएसई के खातों की वित्तीय प्रदर्शन की एक समग्र तस्वीर प्रस्तुत करती है जैसा की उनके खातों से पता चलता है।

इस रिपोर्ट में वर्ष 2021-22 (और पूर्ववर्ती वर्षों के जो इस वर्ष के दौरान अंतिम रूप में आए) के लिए सीपीएसई के वित्तीय विवरणों पर किए गए सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियों के साथ-साथ वित्तीय विवरणों में संशोधन के प्रभाव को शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट में उन वैधानिक निगमों के वित्तीय विवरणों पर सीएजी द्वारा जारी टिप्पणियों का प्रभाव भी शामिल है, जहाँ सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है।

यह रिपोर्ट सीपीएसई द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर अनुपालन, सीपीएसई में विनिवेश प्रक्रिया, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और घाटे में चल रही चयनित सीपीएसई की समीक्षा की स्थिति का समग्र चित्र भी प्रस्तुत करती है।

1.1.3 सीपीएसई की संख्या

31 मार्च 2022 तक सीएजी के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र में 698 सीपीएसई (परिशिष्ट-1) थे। इनमें 490 सरकारी कंपनियाँ², छह वैधानिक निगम³ और 202 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ शामिल हैं। इनमें से 642 सीपीएसई के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है और इन सीपीएसई का स्वरूप नीचे तालिका 1.1 में दर्शाया गया है।

सरकारी कंपनियाँ	490
वैधानिक निगम	6
सरकारी द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ	202
कुल सीपीएसई	698

तालिका 1.1: इस रिपोर्ट में शामिल सीपीएसई का कवरेज और प्रकृति

सीपीएसई की प्रकृति	सीपीएसई की कुल संख्या	रिपोर्ट में शामिल सीपीएसई की संख्या				रिपोर्ट में शामिल न किए गए सीपीएसई की संख्या
		तक के खाते			कुल	
		2021-22	2020-21	2019-20		
सरकारी कंपनियाँ	490	431	14	3	448*	42
वैधानिक निगम	6	6	0	0	6	0
कुल कंपनियां/निगम (ए)	496	437	14	3	454	42
सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियाँ (बी)	202	184	3	1	188	14
कुल (ए+बी)	698	621	17	4	642 ⁴	56

* 448 सरकारी कंपनियों में से 209 सीपीएसई में केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी है। शेष 239 सरकारी कंपनियाँ या तो सरकारी कंपनियों की सहायक कंपनियाँ/संयुक्त उद्यम (जेवी) हैं या गारंटी द्वारा सीमित कंपनियाँ⁵ हैं जिनके पास कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत शेयर पूंजी नहीं है।

² 490 सरकारी कंपनियों में 233 स्टैंडअलोन/होल्डिंग सरकारी कंपनियाँ और 257 सहायक कंपनियाँ/सरकारी कंपनियों के संयुक्त उद्यम शामिल हैं।

³ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, केंद्रीय भंडारण निगम, दामोदर घाटी निगम, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण।

⁴ इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में 21 सीपीएसई (17 सरकारी कंपनियाँ और 4 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ) के आंकड़े उनके अंतिम लेखों के अनुसार शामिल किए गए हैं क्योंकि प्रासंगिक वर्ष के लेखे कट-ऑफ तिथि (29 फरवरी, 2024) से पहले प्राप्त नहीं हुए थे।

⁵ क्रिएटिव म्यूज़ियम डिज़ाइनर्स, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन।

2021-22 के दौरान जिन सरकारी कंपनियों/ सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों का सीएजी के लेखापरीक्षा के दायरे में आना या बाहर जाना हुआ, उनकी विस्तृत जानकारी **परिशिष्ट-II** में दी गई है।

इस रिपोर्ट में 56 सीपीएसई (जिनमें 14 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ शामिल हैं) शामिल नहीं हैं, जिनके वित्तीय विवरणों में तीन साल या उससे अधिक का विलंब था, या जो परिसमापन की प्रक्रिया में थीं, या जिनके पहले खाते अभी तक देय नहीं हुए थे। इन सीपीएसई को **परिशिष्ट-III क** और **परिशिष्ट-III ख** में दो एस्टेरिक्स (**) का चिन्ह लगाया गया है।

इस रिपोर्ट में शामिल की गई सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश

सीपीएसई की संख्या	496
कवर किए गए सीपीएसई	454
प्रदत्त पूंजी (454 सीपीएसई)	₹8,30,531 करोड़
दीर्घकालिक ऋण (187 सीपीएसई)	₹25,33,850 करोड़
31 मार्च, 2022 तक बाजार पूंजीकरण (65 व्यापारित सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां)	₹15,88,664 करोड़
शुद्ध लाभ (258 सीपीएसई)	₹2,69,307 करोड़
शुद्ध घाटा (170 सीपीएसई)	₹31,347 करोड़
शून्य लाभ/हानि	26 सीपीएसई ⁶
लाभांश घोषित (121 सीपीएसई)	₹1,11,061 करोड़
निवल मूल्य (454 सीपीएसई)	₹21,79,355 करोड़

⁶ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को भी शून्य लाभ/हानि वाले सीपीएसई के रूप में माना गया है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का घाटा शुद्ध स्थापना व्यय के रूप में उसकी अचल परिसंपत्तियों में स्थानांतरित कर दिया गया था और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का घाटा उसके आईडब्ल्यूएआई फंड के साथ समायोजित किया गया था।

1.2 सरकारी कंपनियों और निगमों में निवेश

454 सरकारी कंपनियों और निगमों⁷ में 31 मार्च 2022 के अंत तक की प्रदत्त पूंजी और ऋण की राशि तालिका 1.2 में दी गई है:

तालिका 1.2: सरकारी कंपनियों और निगमों में प्रदत्त पूंजी और ऋण

(₹ करोड़ में)

निवेश के स्रोत	31.03.2022 तक			31.03.2021 तक		
	प्रदत्त ⁸ पूंजी	दीर्घकालिक ऋण	कुल	प्रदत्त पूंजी	दीर्घकालिक ऋण	कुल ⁹
केंद्र सरकार	6,36,730	1,47,563	7,84,293	4,75,000	1,41,000	6,16,000
केंद्र सरकार कंपनियाँ / निगम	1,15,594	51,418	1,67,012	99,494	54,990	1,54,484
राज्य सरकार / राज्य सरकार की कंपनियाँ / निगम	41,652	32,442	74,094	35,114	29,048	64,162
वित्तीय संस्थाएं और अन्य	36,555	23,02,427	23,38,982	37,241	21,46,851	21,84,092
कुल	8,30,531	25,33,850	33,64,381	6,46,849	23,71,889	30,18,738
केंद्र सरकार के निवेश का कुल निवेश में प्रतिशत	76.67	5.82	23.31	73.43	5.94	20.41

स्रोत: सीपीएसई के 2020-21 और 2021-22 वर्ष के लेखापरिष्कृत वित्तीय विवरण।

⁷ 496 सीपीएसई - 42 सीपीएसई जिनके खाते तीन साल या उससे अधिक समय से बकाया थे या परिसमापन की प्रक्रिया में थे या पहले खाते देय नहीं थे।

⁸ रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई 42 सरकारी कंपनियों में से 15 सीपीएसई की सूचना उपलब्ध थी जिनकी प्रदत्त पूंजी 1,423 करोड़ रुपये थी।

⁹ 25 सीपीएसई के संबंध में, पिछले वर्षों के अनंतिम आंकड़े 2021-22 के दौरान उस वर्ष के खातों के रूप में अपडेट किए गए हैं।

यह देखा गया कि 2021-22 में सरकारी कंपनियों और निगमों में कुल निवेश 2020-21 की तुलना में ₹3,45,643 करोड़ (11.45 प्रतिशत) बढ़ा, जिसमें ₹1,83,682 करोड़ की वृद्धि प्रदत्त पूंजी में और ₹1,61,961 करोड़ की वृद्धि दीर्घकालिक ऋणों में शामिल है।

1.2.1 इक्विटी होल्डिंग

2021-22 के दौरान, इस रिपोर्ट में शामिल 454 सीपीएसई में प्रदत्त पूंजी में ₹1,83,682 करोड़ की शुद्ध वृद्धि हुई। केंद्र सरकार की सीपीएसई में इक्विटी होल्डिंग 2021-22 के दौरान ₹1,61,730 करोड़¹⁰ बढ़ी। ₹1,61,730 करोड़ की वृद्धि 37 सीपीएसई में ₹1,62,059 करोड़ के शेयर जारी करने और छह सीपीएसई¹¹ में ₹329 करोड़ के शेयरों के विनिवेश/बाइबैक आदि का शुद्ध परिणाम था।

केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान ₹1,62,059 करोड़ की नई इक्विटी होल्डिंग में से, ₹1,59,323 करोड़ 34 सीपीएसई में ताजा इक्विटी के रूप में थी, जिससे संबंधित सीपीएसई में नकद प्रवाह हुआ और ₹2,736 करोड़ बोनस शेयर जारी करने/ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने के रूप में चार सीपीएसई¹² में था।

केंद्र सरकार और अन्य¹³ द्वारा सरकारी कंपनियों और निगमों में 2019-20 से 2021-22 तक के अंतिम तीन वर्षों में इक्विटी होल्डिंग को चार्ट 1.1 में दर्शाया गया है।

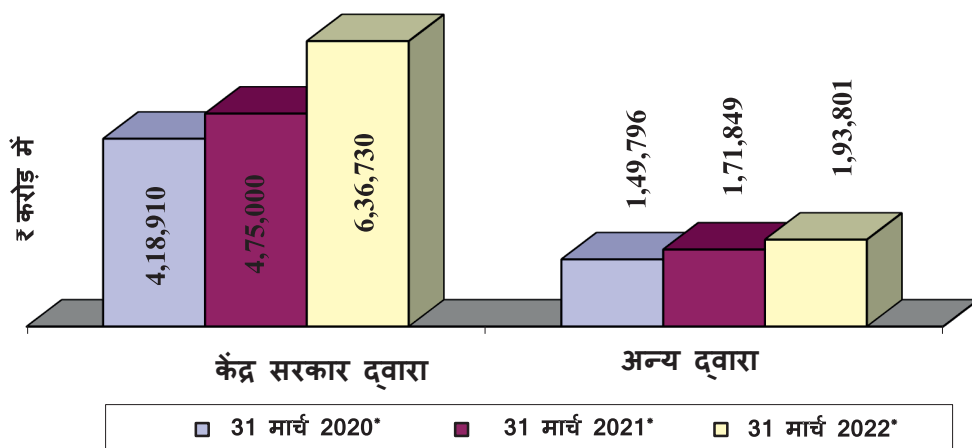
¹⁰ इस ऑडिट रिपोर्ट में 17 सरकारी कंपनियों के अनंतिम आंकड़ों को उनके पिछले ऑडिट किए गए खातों के आंकड़ों के आधार पर शामिल किया गया है क्योंकि रिपोर्ट तैयार करने के लिए कट-ऑफ डेट (29.02.2024) से पहले वर्ष 2021-22 के खाते प्राप्त नहीं हुए थे।

¹¹ जनवरी 2022 में पूरी तरह से विनिवेश की गई ₹32,665.22 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूंजी वाले एयर इंडिया लिमिटेड के आंकड़े रिपोर्ट में शामिल नहीं थे क्योंकि यह अब 31 मार्च, 2022 तक सरकारी कंपनी नहीं थी।

¹² पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, कोलकाता मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड।

¹³ अन्य में केन्द्र सरकार की कंपनियां/निगम, राज्य सरकारें, राज्य सरकार की कंपनियां/निगम और वित्तीय संस्थाएं आदि शामिल हैं।

चार्ट 1.1: सरकारी कंपनियों और निगमों में इक्विटी होल्डिंग



* पिछले वर्षों के अनंतिम आंकड़े 2021-22 के दौरान अद्यतन किए गए, क्योंकि उस वर्ष के खाते प्राप्त हुए थे।

केंद्र सरकार द्वारा 2021-22 में सीपीएसई की प्रदत्त पूंजी में ₹2,000 करोड़ से अधिक के निवेश की जानकारी नीचे तालिका 1.3 में दी गई है:

तालिका 1.3: 2021-22 के दौरान केंद्र सरकार का ₹2,000 करोड़ से अधिक का निवेश

(₹ करोड़ में)

सीपीएसई का नाम	मंत्रालय का नाम	राशि
वैधानिक निगम		
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	सड़क परिवहन और राजमार्ग	75,482 ¹⁴
भारतीय खाद्य निगम	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	2,505
सरकारी कंपनी		
एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	नागरिक उड्डयन	62,365 ¹⁵
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	वित्त	3,700
द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	वित्त	2,800

¹⁴ इसमें उपकर निधि, बजटीय सहायता (राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना और अन्य), इनविट परियोजनाओं से प्राप्ति, टोल प्रेषण का प्लाउ बेंक आदि शामिल हैं।

¹⁵ एअर इंडिया लिमिटेड के रणनीतिक विनिवेश को सुकर बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने एअर इंडिया लिमिटेड की गारंटीकृत/अन्य विगत देयताओं/अतिदेयों का निपटान करने के लिए एआई एसेट्स की होल्डिंग लिमिटेड में ₹62,365.40 करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी का निवेश किया था।

1.2.2 सरकारी कंपनियों और निगमों को दिए गए ऋण

1.2.2.1 31 मार्च 2022 तक के दीर्घकालिक ऋण की बकाया राशि की गणना

31 मार्च 2022 तक 454 सरकारी कंपनियों और निगमों में से 187 सीपीएसई में सभी स्रोतों से दीर्घकालिक ऋण का कुल बकाया ₹25,33,850 करोड़ था। 2021-22 के दौरान, सरकारी कंपनियों और निगमों के दीर्घकालिक ऋण में ₹1,61,961 करोड़ की वृद्धि हुई। 31 मार्च 2022 तक 187 सीपीएसई के कुल दीर्घकालिक ऋण में से, केंद्र सरकार से प्राप्त ऋण ₹1,47,563 करोड़¹⁶ था, जो 45 सीपीएसई में था। इन 45 सीपीएसई में से, 21 सीपीएसई में ₹12,773 करोड़ का ऋण 2021-22 से संबंधित था, जबकि आठ सीपीएसई¹⁷ ने 2021-22 के दौरान ऋण का भुगतान किया।

21 सीपीएसई में से 12 सीपीएसई¹⁸ को चल रहे परियोजनाओं/संचालन के कार्यान्वयन के लिए ऋण दिया गया, जबकि शेष नौ सीपीएसई में ऋण में वृद्धि या तो पूर्ववर्ती ऋण पर बकाया ब्याज के कारण थी या कर्मचारियों के बकाए का भुगतान करने के लिए ऋण दिया गया था।

केंद्र सरकार और अन्य¹⁹ द्वारा 2019-20 से 2021-22²⁰ तक के अंतिम तीन वर्षों में सरकारी कंपनियों और निगमों के दीर्घकालिक ऋणों का वार्षिक विवरण चार्ट 1.2 में दर्शाया गया है।

¹⁶ विश्व बैंक, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) आदि जैसी बाहरी एजेंसियों से ऋण शामिल हैं।

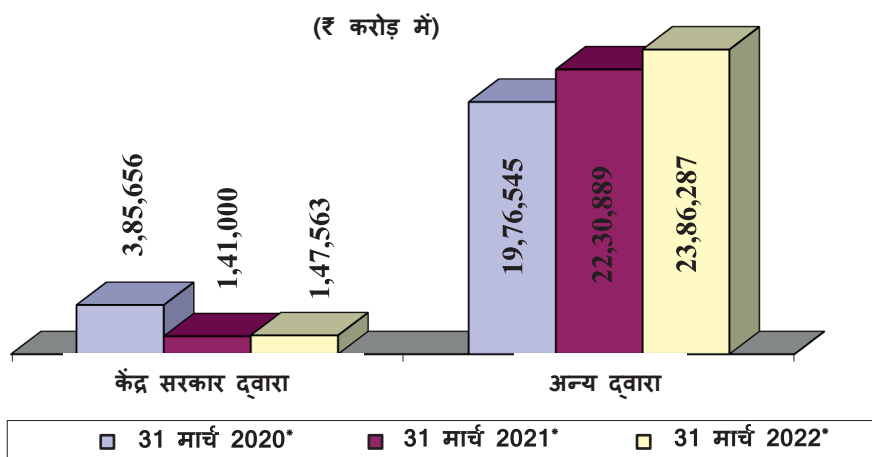
¹⁷ बेंगलूर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, दामोदर घाटी निगम, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड।

¹⁸ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, कॉकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड, राजस्थान इग्ज एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड।

¹⁹ अन्य में केंद्र सरकार की कंपनियां/निगम, राज्य सरकारें, राज्य सरकार की कंपनियां/निगम और वित्तीय संस्थान आदि शामिल हैं।

²⁰ भारतीय खाद्य निगम ने 2020-21 के दौरान ₹1,86,200 करोड़ के दीर्घकालिक ऋण चुकाए।

चार्ट 1.2: सरकारी कंपनियों और निगमों में दीर्घकालिक ऋण



*पिछले वर्षों के अग्रिम आंकड़े 2021-22 के दौरान अद्यतन किए गए, क्योंकि उस वर्ष के खाते प्राप्त हुए थे।

यह देखा जा सकता है कि 2021-22 के दौरान अन्य स्रोतों द्वारा सरकारी कंपनियों और निगमों को दीर्घकालिक ऋण में ₹1,55,398 करोड़ की वृद्धि हुई जबकि केंद्र सरकार द्वारा दीर्घकालिक ऋण में ₹6,563 करोड़ की वृद्धि हुई।

454 सरकारी कंपनियों और निगमों में से 267 सीपीएसई (जिसमें एक वैधानिक निगम, यानी केंद्रीय भंडारण निगम भी शामिल है) के पास 31 मार्च 2022 तक कोई दीर्घकालिक ऋण नहीं था।

1.2.2.2 ऋण दायित्वों को पूरा करने के लिए परिसंपत्तियों की पर्याप्तता

कोई कंपनी अपने ऋणों को चुकाने में सक्षम है यह जानने का एक तरीका उसके कुल ऋण का कुल परिसंपत्तियों से अनुपात जानना है। एक कंपनी को ऋण शोधनक्षम माना जाने के लिए, उसकी परिसंपत्तियों का मूल्य उसके ऋणों/बकायों के कुल योग से अधिक होना चाहिए। 31 मार्च 2022 तक ऋणों के बकाया रहने वाली 187 सीपीएसई में दीर्घकालिक ऋणों का कुल संपत्तियों के मूल्य द्वारा कवरेज तालिका 1.4 में नीचे दी गई है।

तालिका 1.4: कुल परिसंपत्तियों के साथ दीर्घकालिक के ऋण की कवरेज

	सकारात्मक कवरेज				नकारात्मक कवरेज			
	सीपीए-सई की संख्या	दीर्घकालिक ऋण	परिसंपत्तियों	ऋण से परिसंपत्तियों का प्रतिशत	सीपीए-सई की संख्या	दीर्घ कालिक के ऋण	परिसंपत्तियों	ऋण से परिसंपत्तियों का प्रतिशत
		(₹ करोड़ में)				(₹ करोड़ में)		
वैधानिक निगम	5	4,06,734	9,40,259	231.17				
सूचीबद्ध कंपनियां	38	16,04,734	35,03,126	218.30	2	16,803	9,884	58.82
गैर-सूचीबद्ध कंपनियां	116	4,75,782	11,98,719	251.95	26	29,797	12,246	41.10
कुल	159	24,87,250	56,42,104		28	46,600	22,130	

187 सीपीएसई में से 28 सीपीएसई के मामले में, कुल परिसंपत्तियों का मूल्य बकाया दीर्घकालिक ऋणों से कम था (परिशिष्ट-IV)।

1.2.2.3 ब्याज कवरेज अनुपात

ब्याज कवरेज अनुपात (आईसीआर) का उपयोग एक कंपनी की बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता को मापने के लिए किया जाता है और इसे कंपनी की ब्याज और करों से पहले की आय (ईबीआईटी) को उसी अवधि के ब्याज खर्चों से विभाजित करके गणना किया जाता है। जितना कम अनुपात होगा, उतनी ही कम कंपनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता होगी। एक आईसीआर जो एक से कम हो, यह दर्शाता है कि कंपनी ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही थी। 2019-20 से 2021-22 तक के अंतिम तीन वर्षों में जिन सीपीएसई के पास बकाया ऋण था, उनके सकारात्मक और नकारात्मक ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण तालिका 1.5 में नीचे दिया गया है।

तालिका 1.5: ब्याज कवरेज अनुपात

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज और कर से पूर्व आय (ईबीआईटी) (₹ करोड़ में)	सीपीएसई की संख्या	जिन सी- पीएसई में शून्य ब्याज है	जिन सी- पीएसई का आईसीआर ≥ 1 है	जिन सी- पीएसई का आईसीआर < 1 है
वैधानिक निगम						
2019-20	22,529.70	26,039.63	5	1	3	1
2020-21	31,704.04	28,623.17	5	1	2	2
2021-22	5,773.05	5,697.95	5	1	3	1
सूचीबद्ध सरकारी कंपनियां						
2019-20	98,815.03	1,87,716.51	42	5	24	13
2020-21	97,493.68	2,69,547.97	42	4	30	8
2021-22	89,229.12	3,15,693.72	40	2	32	6
गैर-सूचीबद्ध सरकारी कंपनियां						
2019-20	20,659.37	3,642.45	138	49	37	52
2020-21	21,237.12	23,578.14	137	46	49	42
2021-22	23,703.25	39,636.78	142	42	51	49

वैधानिक निगमों के मामले में, 2021-22 में ब्याज और ईबीआईटी में पिछले वर्ष की तुलना में कमी मुख्य रूप से एफसीआई में ऋण पर ब्याज में कमी के कारण हुई थी, जो 2020-21 में ₹29,068 करोड़ से घटकर 2021-22 में ₹3,715 करोड़ हो गया। यह देखा गया कि 2021-22 में पिछले वर्ष की तुलना में सभी सीपीएसई श्रेणियों में आईसीआर (ब्याज कवरेज अनुपात) एक या उससे अधिक वाले सीपीएसई की संख्या बढ़ी। इसके अलावा, कुल मिलाकर, 2021-22 में आईसीआर एक या उससे अधिक वाले सीपीएसई की संख्या बढ़कर 86 (3+32+51) हो गई, जो 2020-21 में 81 (2+30+49) थी। इसी तरह, आईसीआर एक से कम वाले सीपीएसई की संख्या भी 2021-22 में बढ़कर 56 (1+6+49) हो गई, जो 2020-21 में 52 (2+8+42) थी।

9 सीपीएसई²¹ के मामले में, 31 मार्च 2022 तक उनके ऋण/बकाया पर देय ब्याज उनके

²¹ पीईसी लिमिटेड, महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, नेशनल बाइसिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड, अंडमान फिशरीज लिमिटेड, टीसीआईएल एलटीआर लिमिटेड, इरकॉन शिव पुरी गुना लिमिटेड, मणिपुर स्टेट ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड।

कुल परिसंपत्तियों के मूल्य से अधिक था, जो इन कंपनियों में दिवालियापन के उच्च जोखिम को दर्शाता है।

1.2.2.4 केंद्र सरकारी ऋणों पर ब्याज की शेष राशि का अवधिवार विश्लेषण

31 मार्च 2022 तक, केंद्र सरकार द्वारा 25 सीपीएसई को प्रदान किए गए दीर्घकालिक ऋणों पर ₹4,184.16 करोड़ का ब्याज बकाया था। केंद्र सरकार के ऋणों पर सीपीएसई में बकाया ब्याज का अनुधिवार विश्लेषण तालिका 1.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.6: केंद्र सरकारी ऋणों पर ब्याज की शेष राशि

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	केंद्र सरकार ऋणों पर ब्याज की शेष राशि	केंद्र सरकार ऋणों पर ब्याज जो 1 वर्ष से कम समय के लिए शेष है	केंद्र सरकार ऋणों पर ब्याज जो 1-3 वर्षों के लिए शेष है	केंद्र सरकार ऋणों पर ब्याज जो 3 वर्षों से अधिक समय के लिए शेष है
1.	अंडमान फिशरीज लिमिटेड	7.19	2.31	1.42	3.46
2.	भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड	52.70	0.00	48.77	3.93
3.	बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	70.78	3.89	11.52	55.37
4.	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	123.85	0.00	0.00	123.85
5.	केंद्रीय कुटीर उद्योग निगम लिमिटेड	0.56	0.41	0.15	0.00
6.	केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	15.10	1.44	2.37	11.29
7.	दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड	400.19	400.19	0.00	0.00
8.	हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	69.66	10.77	31.27	27.62

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	केंद्र सरकार ऋणों पर ब्याज की शेष राशि	केंद्र सरकार ऋणों पर ब्याज जो 1 वर्ष से कम समय के लिए शेष है	केंद्र सरकार ऋणों पर ब्याज जो 1-3 वर्षों के लिए शेष है	केंद्र सरकार ऋणों पर ब्याज जो 3 वर्षों से अधिक समय के लिए शेष है
9.	हेमिस्फियर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड	1.64	0.34	1.10	0.20
10.	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड	55.00	11.00	44.00	0.00
11.	हिंदुस्तान इनसेक्टिसाइड्स लिमिटेड	43.72	4.70	9.39	29.63
12.	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	348.61	50.98	101.39	196.24
13.	हिंदुस्तान सॉल्ट्स लिमिटेड	26.95	2.71	6.64	17.60
14.	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	16.90	16.90	0.00	0.00
15.	आई टी आई लिमिटेड	22.56	3.00	19.56	0.00
16.	मद्रास उर्वरक लिमिटेड	766.40	54.58	163.74	548.08
17.	नेशनल बाइसिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	604.33	0.00	62.78	541.55
18.	नेपा लिमिटेड	198.66	1.29	18.41	178.96
19.	एनएचपीसी लिमिटेड	70.73	70.73	0.00	0.00
20.	उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हैंडलूम्स विकास निगम लिमिटेड	24.61	24.61	0.00	0.00
21.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड	1.77	0.00	1.77	0.00
22.	आरईसी लिमिटेड	3.25	3.25	0.00	0.00
23.	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	5.58	5.58	0.00	0.00
24.	द ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड	58.34	58.34	0.00	0.00

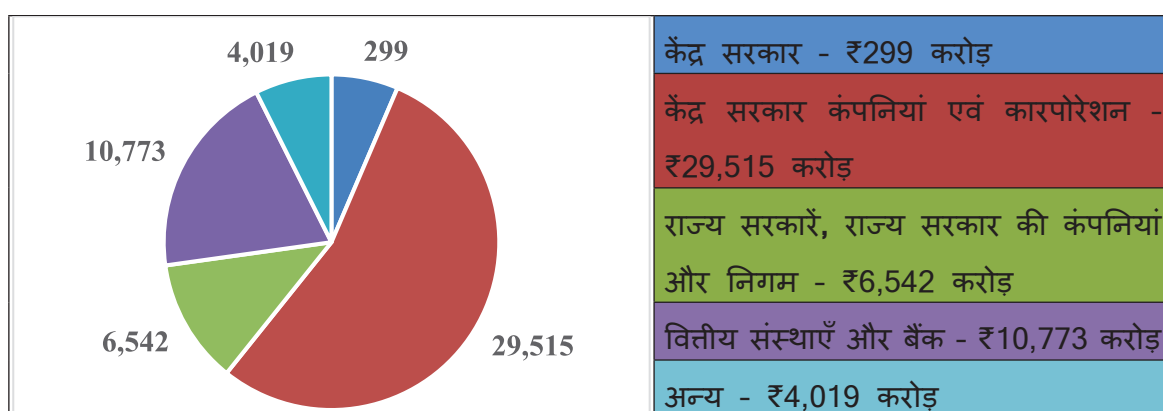
क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	केंद्र सरकार ऋणों पर ब्याज की शेष राशि	केंद्र सरकार ऋणों पर ब्याज जो 1 वर्ष से कम समय के लिए शेष है	केंद्र सरकार ऋणों पर ब्याज जो 1-3 वर्षों के लिए शेष है	केंद्र सरकार ऋणों पर ब्याज जो 3 वर्षों से अधिक समय के लिए शेष है
25.	द फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	1,195.08	239.02	717.05	239.01
	कुल	4,184.16	966.04	1,241.33	1,976.79

यह देखा गया कि केंद्र सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज 2021-22 में ₹4,184.16 करोड़ (25 सीपीएसई) हो गया जो 2020-21 में ₹5,805.34 करोड़ (17 सीपीएसई) था। इसके अलावा, यह पाया गया कि 47.24 प्रतिशत ब्याज तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया था।

1.2.3 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों में निवेश

केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र/राज्य सरकार की कंपनियों/निगमों द्वारा 188 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों²² में 2021-22 के दौरान किया गया निवेश चार्ट 1.3 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.3: सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों में शेयर पूंजी की संरचना



²² 188 = 202- 14 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ जिनके खाते तीन वर्ष या उससे अधिक समय से बकाया थे या परिसमापन के अधीन थे।

31 मार्च 2022 तक, 188 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों में प्रदत्त पूंजी ₹51,148 करोड़ थी। सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों में प्रदत्त पूंजी में 2021-22 में पिछले वर्ष की तुलना में ₹5,861 करोड़ की वृद्धि हुई।

1.2.4 सरकारी कंपनियों में इक्विटी निवेश का बाजार पूंजीकरण

बाजार पूंजीकरण उन कंपनियों के शेयरों का बाजार मूल्य दर्शाता है जिनके शेयर सूचीबद्ध हैं। 31 मार्च 2022 तक, 76 सीपीएसई के शेयर, जिसमें 59 सरकारी कंपनियां, सरकारी कंपनियों की नौ सहायक कंपनियां²³ और आठ सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां²⁴ शामिल हैं, भारत के विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध थे।

59 सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों के संदर्भ में, 58 कंपनियों के शेयरों का व्यापार हुआ और एक कंपनी²⁵ के शेयरों का व्यापार 2021-22 में नहीं हुआ। सरकारी कंपनियों की नौ सहायक कंपनियों के संदर्भ में, सात सहायक कंपनियों के शेयरों का व्यापार हुआ और दो सहायक कंपनियों²⁶ के शेयरों का व्यापार नहीं हुआ।

31 मार्च 2022 तक, 65 व्यापारित सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों (जिसमें सात सहायक कंपनियां शामिल हैं) के शेयरों का कुल बाजार मूल्य ₹15,88,664 करोड़ (इक्विटी निवेश ₹1,06,053 करोड़) था, जो 31 मार्च 2021 तक ₹12,86,882 करोड़ था। इस प्रकार, 31 मार्च 2022 तक व्यापारित सूचीबद्ध सीपीएसई के शेयरों का कुल बाजार मूल्य ₹3,01,782 करोड़ (23.45 प्रतिशत) बढ़ा।

एसईबीआई द्वारा निर्धारित लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की परिभाषा²⁷ और

²³ बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड, ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, द उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, द बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड।

²⁴ ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड, तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड, इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड, पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड।

²⁵ हिंदुस्तान फोटो फिल्मस (मैन्युफैक्चरिंग) कंपनी लिमिटेड।

²⁶ ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, द बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड।

²⁷ सेबी के 06 अक्टूबर, 2017 के परिपत्र के अनुसार, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है: लार्ज कैप: पूर्ण बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में पहली - 100वीं कंपनी मिड कैप: पूर्ण बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में 101वीं - 250वीं कंपनी, स्मॉल कैप: पूर्ण बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में 251वीं कंपनी से

बीएसई के अनुसार शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों के बाजार पूंजीकरण मान को ध्यान में रखते हुए, व्यापारित सूचीबद्ध सीपीएसई को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में वर्गीकृत किया गया है, जैसा कि तालिका 1.7 में दिया गया है।

तालिका 1.7: 65 सूचीबद्ध सीपीएसई की श्रेणीकरण

विवरण	2021-22	2020-21	समान सीपीएसई
लार्ज कैप सीपीएसई	10	08	7
मिड कैप सीपीएसई	13	14	11
स्मॉल कैप सीपीएसई	42	38	38
कुल	65	60	

यह देखा गया कि 2020-21 में 38 स्मॉल कैप सीपीएसई में से एक कंपनी²⁸ 2021-22 में मिड कैप कंपनी बन गई। 2020-21 में 14 मिड कैप सीपीएसई में से तीन कंपनियां²⁹ 2021-22 में लार्ज कैप कंपनियां बन गईं। 2020-21 में आठ लार्ज कैप सीपीएसई में से एक कंपनी 2021-22 में मिड कैप कंपनी³⁰ बन गई। इसके परिणामस्वरूप 2021-22 में 13 (14+1-3+1) मिड कैप सीपीएसई और 10 (8+3-1) लार्ज कैप सीपीएसई हो गए।

सबसे अधिक बाजार पूंजीकरण वाले शीर्ष तीन क्षेत्र थे: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (₹5,43,973 करोड़-34.24%), ऊर्जा (₹3,74,811 करोड़-23.59%) और रेलवे (₹1,50,540 करोड़-9.48%)। शेयरों के बाजार मूल्य में सबसे अधिक वृद्धि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में देखी गई (₹1,13,748 करोड़-26.44%) इसके बाद ऊर्जा क्षेत्र (₹68,048 करोड़-22.18%) और रक्षा क्षेत्र (₹44,422 करोड़-52.39%) में रही, जबकि शेयरों के बाजार मूल्य में सबसे अधिक गिरावट वित्तीय क्षेत्र (₹22,237 करोड़-34.87%) में देखी गई, इसके बाद हाउसिंग और शहरी मामलों के क्षेत्र (₹2,242 करोड़-25.51%) और संचार क्षेत्र (₹2,133 करोड़-13.47%) में रही। 31 मार्च, 2022 तक, 58 सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों (सात सहायक कंपनियों को छोड़कर) के शेयरों का बाजार मूल्य ₹15,13,333

²⁸ नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड।

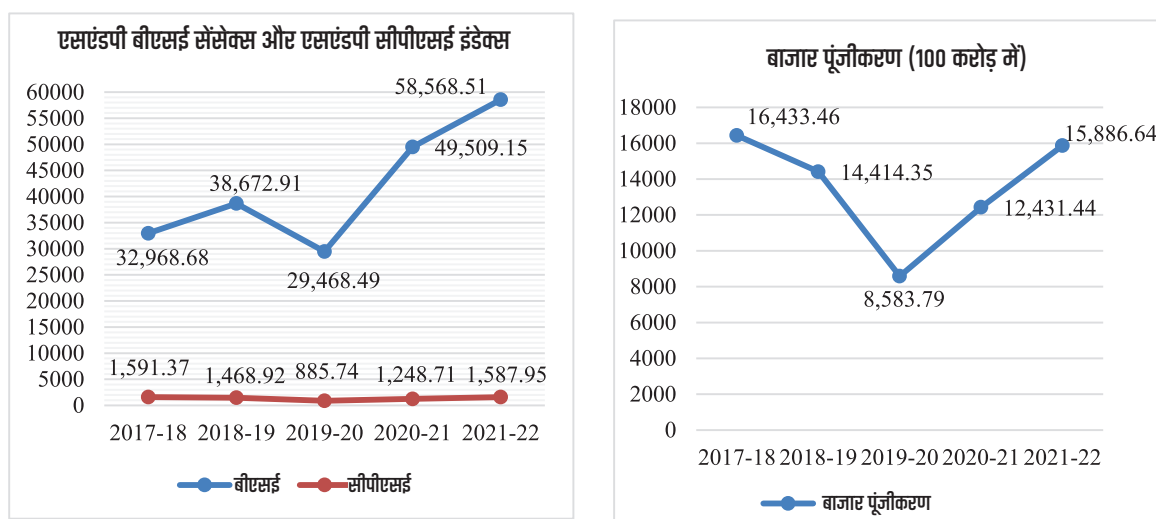
²⁹ इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड।

³⁰ एनएमडीसी लिमिटेड।

करोड़ था, जिसमें से केंद्र सरकार के पास रखे गए शेयरों का बाजार मूल्य ₹9,17,248 करोड़ (60.61%) था।

इस अवधि के दौरान, एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स³¹ 31 मार्च 2021 को 49,509.15 से 31 मार्च 2022 को 58,568.51 तक 18.30 प्रतिशत बढ़ा। इसकी तुलना में, एस एंड पी बीएसई -सीपीएसई इंडेक्स³² 31 मार्च 2021 को 1,248.71 से 31 मार्च 2022 को 1,587.95 तक 27.17 प्रतिशत बढ़ा। पिछले पांच वर्षों के दौरान व्यापारित सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों के बाजार पूंजीकरण का रुझान एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स और एस एंड पी बीएसई-सीपीएसई इंडेक्स के सापेक्ष चार्ट 1.4 में प्रदर्शित किया गया है।

**चार्ट 1.4: व्यापारित सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों के बाजार पूंजीकरण का रुझान
एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स और सीपीएसई इंडेक्स के सापेक्ष**



यह देखा गया कि 2018-19 से 2021-22 तक व्यापारित सूचीबद्ध सीपीएसई की बाजार पूंजीकरण का रुझान एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स और एसएंडपी बीएसई सीपीएसई इंडेक्स के साथ समान थी। 2017-18 से 2018-19 तक, इन सीपीएसई के शेयरों का बाजार मूल्य 12.29 प्रतिशत घटा (₹16,43,346 करोड़ से ₹14,41,435 करोड़) जबकि उसी अवधि में एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स में 17.30 प्रतिशत की वृद्धि हुई (32,968.68 से 38,672.91 तक), हालांकि एस एंड पी बीएसई-सीपीएसई इंडेक्स 7.69 प्रतिशत घटा (1,591.37 से

³¹ एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स एक बेंचमार्क इंडेक्स है जो 30 घटक शेयरों की एक टोकरी है जो बड़ी, तरल और प्रतिनिधि कंपनियों के नमूने का प्रतिनिधित्व करती है।

³² एसएंडपी बीएसई सीपीएसई इंडेक्स बीएसई में सूचीबद्ध सीपीएसई के प्रदर्शन को मापता है।

1,468.92 तक)। 2019-20 से, बाजार पूंजीकरण एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स और सीपीएसई इंडेक्स में एक बढ़ता रुझान देखा गया।

31 मार्च 2022 को सरकारी कंपनियों के सात सहायक कंपनियों के व्यापार किए गए शेयरों का कुल बाजार मूल्य ₹75,332 करोड़ था। 31 मार्च 2022 को इन सात सहायक सरकारी कंपनियों में शेयरों का कुल बाजार मूल्य, 31 मार्च 2021 की तुलना में ₹3,276 करोड़ बढ़ा है।

31 मार्च 2022 को शीर्ष 10 व्यापारित सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों की सूची, जिनका बाजार पूंजीकरण सबसे अधिक था, तालिका 1.8 में दी गई है।

तालिका 1.8: सबसे उच्च बाजार पूंजीकरण वाली सरकारी कंपनियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	बाजार पूंजीकरण	
		31 मार्च, 2022 की स्थिति अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार
1.	ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2,06,191	1,28,508
2.	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1,51,263	1,12,819
3.	एनटीपीसी लिमिटेड	1,30,857	1,03,221
4.	कोल इंडिया लिमिटेड	1,12,778	80,362
5.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,11,981	86,422
6.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	77,920	92,833
7.	गैल (इंडिया) लिमिटेड	69,137	60,189
8.	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड	61,968	28,099
9.	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	51,376	30,482
10.	हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड	49,727	33,267

65 व्यापारित सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों में से, 41 सीपीएसई के बाजार पूंजीकरण में वृद्धि हुई, जबकि 24 सीपीएसई के बाजार पूंजीकरण में कमी आई (परिशिष्ट-V)।

1.3 सीपीएसई से रिटर्न

1.3.1 सीपीएसई द्वारा अर्जित लाभ

यह देखा गया कि 2021-22 में 258 सरकारी कंपनियां और निगम लाभ में थीं, जबकि 2020-21 में यह संख्या 239 थी (45 सीपीएसई जुड़ी एवं 26 सीपीएसई घटी)। इन 45 सीपीएसई (*परिशिष्ट-VI*) में से छह सीपीएसई नई थी और अपने संचालन के पहले वर्ष में लाभ कमाया, 36 सीपीएसई ने पिछले वर्ष में नुकसान होने के बाद लाभ कमाया और तीन सीपीएसई का पिछले वर्ष में शून्य लाभ/हानि था। 36 सीपीएसई में से 21 ने परिचालन लाभ³³ की वजह से लाभ अर्जित किया। वहीं, 26 सीपीएसई (*परिशिष्ट-VII*), जिन्होंने पिछले वर्ष लाभ कमाने के बाद नुकसान उठाया, में से 16 सीपीएसई ने मुख्य रूप से परिचालन हानि के कारण हानि का सामना किया।

लाभ कमाने वाली सरकारी कंपनियों की श्रेणीबद्ध सूची पिछले दो वर्षों, यानी 2020-21 और 2021-22, में निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर तालिका 1.9 में दी गई है:

- ₹10,000 करोड़ से अधिक लाभ वाली सीपीएसई को उच्च लाभ कमाने वाली सीपीएसई के रूप में माना गया है।
- ₹1,000 करोड़ से ₹10,000 करोड़ के बीच लाभ वाली सीपीएसई को मध्यम लाभ कमाने वाली सीपीएसई के रूप में माना गया है।
- ₹1,000 करोड़ से कम लाभ वाली सीपीएसई को कम लाभ कमाने वाली सीपीएसई के रूप में माना गया है।

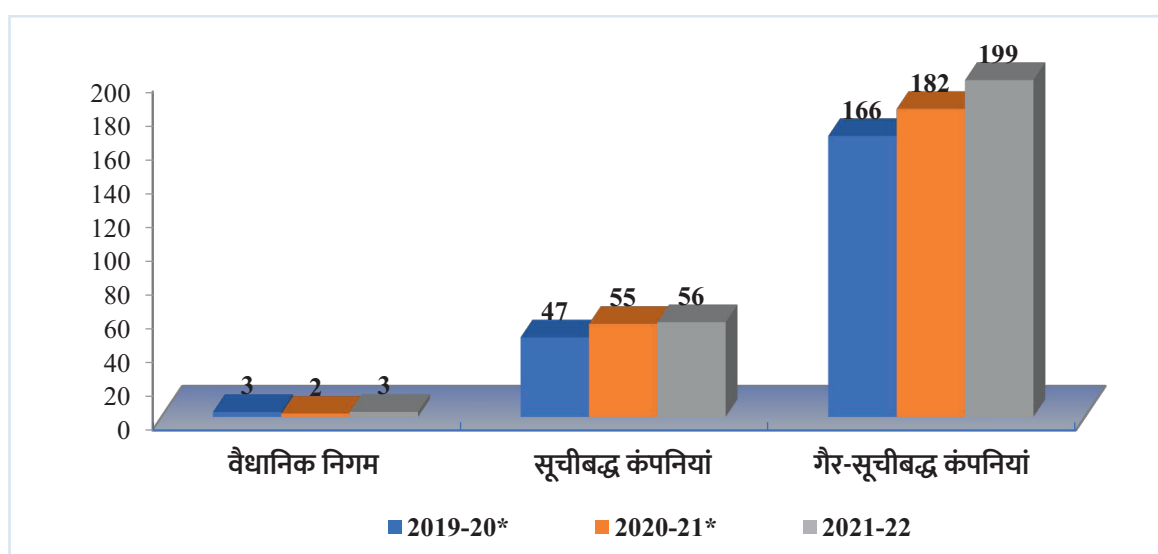
तालिका 1.9: लाभ अर्जित करने वाली सीपीएसई की श्रेणीकरण

सीपीएसई की श्रेणी	2021-22	2020-21	समान सीपीएसई
₹10,000 करोड़ से अधिक लाभ	9	6	4
₹1,000 करोड़ से ₹10,000 करोड़ के बीच लाभ	23	25	17
₹1,000 करोड़ से कम लाभ	226	208	179
कुल	258	239	200

³³ कुल परिचालन आय घटा व्यय।

सरकारी कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ 2020-21 में ₹1,94,092 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में ₹2,69,307 करोड़ हो गया और 2021-22 के दौरान ₹75,215 करोड़ (38.75 प्रतिशत) बढ़ा। तदनुसार, 258 सीपीएसई का रिटर्न ऑन इक्विटी (आरओई)³⁴ 2021-22 में 15.50 प्रतिशत था, जबकि 2020-21 में 239 सीपीएसई का 13.11 प्रतिशत था। 452 सरकारी कंपनियों और निगमों³⁵ जिसमें 170 घाटे में चलने वाली और 24 शून्य लाभ/हानि वाली कंपनियां शामिल हैं का कुल आरओई 2021-22 में 13.04 प्रतिशत था। 2019-20 से 2021-22 तक लाभ कमाने वाली सीपीएसई की संख्या को चार्ट 1.5 में दिखाया गया है। इस दौरान यह देखा जा सकता है कि लाभ कमाने वाली सीपीएसई की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही थी।

चार्ट 1.5: लाभ अर्जित करने वाली सीपीएसई की संख्या



*पिछले वर्षों के आंकड़े 2021-22 के दौरान अद्यतन किए गए जब उस वर्ष के खाते प्राप्त हुए।

2021-22 के दौरान अधिकतम लाभ का योगदान देने वाले शीर्ष तीन क्षेत्रों का विवरण सारांश रूप में तालिका 1.10 में दिया गया है।

³⁴ इक्विटी पर रिटर्न = (टैक्स और वरीयता लाभांश/इक्विटी के बाद शुद्ध लाभ)*100 जहां इक्विटी = प्रदत्त पूंजी + मुक्त रिजर्व - संचित हानि - आस्थगित राजस्व व्यय।

³⁵ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को छोड़कर जिन्हें शून्य लाभ/हानि सीपीएसई माना गया है क्योंकि उनके घाटे को फुटनोट 6 में दिए अनुसार समायोजित किया गया है।

तालिका 1.10: 2021-22 के दौरान अधिकतम लाभ का योगदान देने वाले शीर्ष 3 क्षेत्र

क्षेत्र	लाभ अर्जित करने वाली सीपीएसई की संख्या	शुद्ध अर्जित लाभ (₹ करोड़ में)	कुल लाभ के प्रतिशत के रूप में लाभ
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस			
सूचीबद्ध सरकारी कंपनियां	8	98,210	36.47
गैर-सूचीबद्ध सरकारी कंपनियां	7	8,139	3.02
उप-योग (क)	15	1,06,349	39.49
पावर			
सूचीबद्ध सरकारी कंपनियां	4	37,720	14.01
गैर-सूचीबद्ध सरकारी कंपनियां	38	10,023	3.72
वैधानिक निगम	1	635	0.24
उप-योग (ख)	43	48,378	17.96
वित्तीय सेवाएं			
सूचीबद्ध सरकारी कंपनियां	5	27,941	10.38
गैर-सूचीबद्ध सरकारी कंपनियां	27	3,649	1.36
उप-योग (ग)	32	31,590	11.73
कुल (क+ख+ग)	90	1,86,317	69.18

2021-22 में 90 सीपीएसई द्वारा ₹1,86,317 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया, जो सरकारी कंपनियों और निगमों के कुल लाभ का 69.18 प्रतिशत है, जबकि 2020-21 में 89 सीपीएसई द्वारा यह योगदान 71.40 प्रतिशत था।

सरकारी कंपनियों की सूची, जिन्होंने वर्ष 2021-22 के दौरान ₹10,000 करोड़ से अधिक का शुद्ध लाभ अर्जित किया, तालिका 1.11 में दी गई है।

तालिका 1.11: उन सीपीएसई की सूची जिन्होंने ₹10,000 करोड़ से अधिक शुद्ध लाभ अर्जित किया

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	कुल लाभ (₹ करोड़ में)	आर ओ ई (प्रतिशत)
1	ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	40,305	17.00
2	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	24,184	18.70
3	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	17,093	22.45
4	एनटीपीसी लिमिटेड	16,111	12.59
5	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	12,015	23.34
6	कोल इंडिया लिमिटेड	11,201	68.48
7	गैल (इंडिया) लिमिटेड	10,363	18.64
8	आरईसी लिमिटेड	10,045	19.92
9	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	10,021	16.89
	कुल	1,51,338	

यह देखा जा सकता है कि इन नौ सरकारी कंपनियों ने 2021-22 में 258 सरकारी कंपनियों और निगमों द्वारा अर्जित कुल लाभ का 56.20 प्रतिशत योगदान दिया। इन नौ सरकारी कंपनियों का आरओई 18.83 प्रतिशत था, जबकि शेष 249 सरकारी कंपनियों का आरओई 12.63 प्रतिशत था।

188 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों³⁶ में से, 129 सीपीएसई ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष में ₹15,011 करोड़ का लाभ अर्जित किया, जो कि 2020-21 में ऐसी 120 सीपीएसई द्वारा अर्जित ₹12,062 करोड़ के लाभ की तुलना में ₹2,948 करोड़ (24.44 प्रतिशत) की वृद्धि थी। इसके अतिरिक्त, 2021-22 में 129 सीपीएसई का आरओई 4.11 प्रतिशत था, जबकि 2020-21 में 120 सीपीएसई का आरओई 3.89 प्रतिशत था। 188 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों का आरओई 2021-22 में 3.01 प्रतिशत था, जबकि 2020-21 में ऐसी 182 कंपनियों का आरओई 3.02 प्रतिशत था।

³⁶ सरकार द्वारा नियंत्रित एक अन्य कंपनी अर्थात् नेशनल हाईवेज इन्विट प्रोजेक्ट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड ने न तो लाभ कमाया और न ही कोई हानि उठाई, क्योंकि उसका परिचालन अभी शुरू होना है।

1.3.2 सीपीएसई द्वारा हुई हानि

2021-22 के दौरान 170 सरकारी कंपनियों³⁷ हानि में रही। इन 170 हानि में रहने वाली सीपीएसई में से 84 ने पिछले पाँच वर्षों में दो से चार वर्षों तक नुकसान उठाया, जबकि 66 सीपीएसई ने पिछले पाँच वर्षों में लगातार नुकसान उठाया। सरकारी कंपनियों और निगमों द्वारा उठाए गए नुकसान 2021-22 में घट कर ₹31,347 करोड़ हो गये, जो कि 2020-21 में ₹34,555 करोड़ था, जैसा कि तालिका 1.12 में दिया गया है।

तालिका 1.12: 2019-20 से 2021-22 के दौरान हानि में रही सीपीएसई की संख्या

सूचीबद्ध / गैर-सूचीबद्ध वर्ष	सीपीएसई की संख्या जिन्होंने हानि उठाई	वार्षिक निवल हानि (₹ करोड़ में)	संचित हानि (₹ करोड़ में)	निवल मूल्य ³⁸ (₹ करोड़ में)
वैधानिक निगम				
2019-20	0	0	0	0
2020-21	1	1,962	0	12,850
2021-22	0	0	0	0
सूचीबद्ध सरकारी कंपनियाँ				
2019-20	21	12,042	39,483	1,17,699
2020-21	13	8,364	40,980	-2,686
2021-22	12	5,001	45,260	-41,108
गैर-सूचीबद्ध सरकारी कंपनियाँ				
2019-20	156	44,252	39,779	1,19,590
2020-21	154	24,229	45,429	1,00,370
2021-22	158	26,346	1,15,952	1,20,228

³⁷ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को छोड़कर, जिन्हें शून्य लाभ/हानि सीपीएसई माना गया है क्योंकि उनके घाटे को फुटनोट 6 में दिए अनुसार समायोजित किया गया है।

³⁸ निवल मूल्य का अर्थ है प्रदत्त शेयर पूंजी और मुक्त भंडार और अधिशेष घटा संचित हानि और आस्थगित राजस्व व्यय का कुल योग। मुक्त भंडार का अर्थ है मुनाफे और शेयर प्रीमियम खाते से बनाए गए सभी भंडार लेकिन इसमें परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन और मूल्यहास प्रावधान के राइट बैक से बनाए गए भंडार शामिल नहीं हैं।

सूचीबद्ध / गैर-सूचीबद्ध वर्ष	सीपीएसई की संख्या जिन्होंने हानि उठाई	वार्षिक निवल हानि (₹ करोड़ में)	संचित हानि (₹ करोड़ में)	निवल मूल्य ³⁸ (₹ करोड़ में)
कुल				
2019-20	177	56,294	79,262	2,37,288
2020-21	168	34,555	86,408	1,10,534
2021-22	170	31,347	1,61,211	79,121

तालिका 1.13 सूचीबद्ध सीपीएसई जिन्होंने वर्ष 2021-22 के दौरान ₹1,000 करोड़ से अधिक का नुकसान उठाया

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	कुल हानि
1	भारत संचार निगम लिमिटेड	6,982
2	दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड	3,815
3	द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	3,115
4	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	2,603
5	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2,136
6	आईएफसीआई लिमिटेड	1,991
7	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,675
8	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	1,061
9	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	1,057
कुल		24,435

यह देखा जा सकता है कि इन नौ सीपीएसई ने 2021-22 में 170 सीपीएसई द्वारा उठाए गए कुल नुकसान का 77.95 प्रतिशत योगदान दिया।

इसके अतिरिक्त, 188 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों में से 56 कंपनियों ने 2021-22 के दौरान ₹3,626 करोड़ का नुकसान उठाया, जबकि 2020-21 में ऐसी 182 कंपनियों में से 59 सीपीएसई ने ₹2,452 करोड़ का नुकसान उठाया था, जो ₹1,173 करोड़ (47.85 प्रतिशत) की वृद्धि दर्शाता है।

1.3.3 सरकारी कंपनियों में पूंजी का हास

31 मार्च 2022 तक, 192 सरकारी कंपनियों³⁹ के पास ₹1,83,356 करोड़ का संचयी नुकसान था। इन 192 सीपीएसई में से 131 सीपीएसई ने 2021-22 में ₹14,031 करोड़ का नुकसान उठाया, जबकि 61 सीपीएसई ने 2021-22 में कोई नुकसान नहीं उठाया (जिसमें शून्य लाभ/हानि वाली कंपनियां भी शामिल हैं), हालांकि उनके पास ₹22,144 करोड़ का संचयी नुकसान था। 192 सीपीएसई में से 15 कंपनियां 31 मार्च 2022 तक बंद/ परिसमापन के अंतर्गत थीं, जिनका संचयी नुकसान ₹38,009 करोड़ था।

कुल मिलाकर, 454 सरकारी कंपनियों और निगमों का निवल मूल्य ₹21,79,355 करोड़ था, जबकि उनकी प्रदत्त पूंजी ₹8,30,532 करोड़ थी। 192 सीपीएसई में से 79 कंपनियों का निवल मूल्य संचयी नुकसान से पूरी तरह से समाप्त हो चुका था, और उनका निवल मूल्य शून्य या नकारात्मक था। इन 79 सीपीएसई का निवल मूल्य 31 मार्च 2022 तक (-) ₹75,186 करोड़ था, जबकि इन कंपनियों में ₹66,682 करोड़ का शेयर पूंजी निवेश था (परिशिष्ट-VIII)। इसमें छह सूचीबद्ध कंपनियां भी शामिल थीं, जिनका निवल मूल्य (-) ₹43,318 करोड़ था, जबकि इन कंपनियों में ₹1,166 करोड़ का शेयर पूंजी निवेश था। उन 79 सीपीएसई में से, जिनकी पूंजी समाप्त हो चुकी थी (जिनका निवल मूल्य शून्य या नकारात्मक था), 15 सीपीएसई ने 2021-22 में ₹1,111 करोड़ का लाभ अर्जित किया। इसके अतिरिक्त, 79 सीपीएसई में से 32 ने पिछले पाँच वर्षों में लगातार नुकसान उठाया था, और 31 मार्च 2022 तक उनका संचयी नुकसान और नकारात्मक निवल मूल्य क्रमशः ₹55,974 करोड़ और ₹53,976 करोड़ था।

79 सीपीएसई में से 17 कंपनियों की पूंजी समाप्त हो चुकी थी, जिनमें 31 मार्च 2022 तक सरकारी ऋण ₹8,637 करोड़ था। इसमें एक सूचीबद्ध कंपनी (मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड) भी शामिल थी, जिसका सरकारी ऋण ₹554 करोड़ था।

31 मार्च 2022 तक, 372 सीपीएसई में से 33 कंपनियों का निवल मूल्य उनकी प्रदत्त पूंजी के आधे से कम था, जिनका निवल मूल्य धनात्मक था। इन 33 सीपीएसई में

³⁹ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को छोड़कर, जिन्हें शून्य लाभ/हानि सीपीएसई माना गया है क्योंकि उनके घाटे को फुटनोट 6 में दिए अनुसार समायोजित किया गया है।

से 14 कंपनियाँ, जिनका निवल मूल्य ₹8,695 करोड़ था, पिछले पाँच वर्षों से लगातार नुकसान में रही थी, और 12 कंपनियाँ, जिनका निवल मूल्य ₹3,687 करोड़ था, पिछले पाँच वर्षों में दो से चार वर्षों तक नुकसान में रही थी, जो उनके संभावित वित्तीय संकट को दर्शाता है।

1.3.4 सीपीएसई द्वारा लाभांश भुगतान

सरकारी कंपनियों और निगमों द्वारा अर्जित लाभ और घोषित लाभांश का विवरण तालिका 1.14 में दिया गया है।

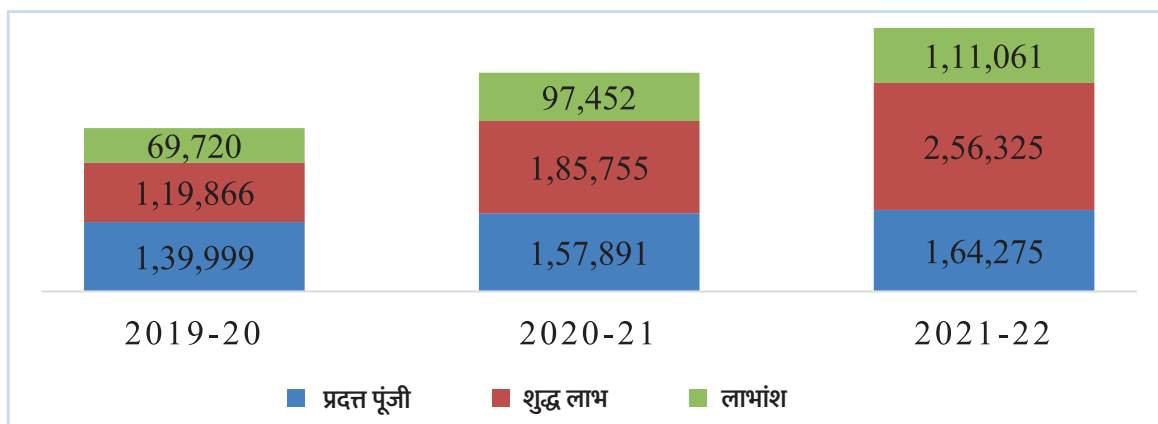
तालिका 1.14: अर्जित लाभ और घोषित लाभांश

श्रेणी	सीपीएसई की संख्या	प्रदत्त पूंजी (₹ करोड़ में)	शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	घोषित लाभांश (₹ करोड़ में)
वैधानिक निगम	1	68	451	141
सूचीबद्ध कंपनियाँ	47	98,089	2,17,385	91,648
गैर-सूचीबद्ध कंपनियाँ	73	66,118	38,489	19,272
कुल	121	1,64,275	2,56,325	1,11,061

454 सरकारी कंपनियों और निगमों में से, 121 सीपीएसई ने 2021-22 के लिए लाभांश घोषित किया। इन 121 लाभ अर्जित करने वाली सीपीएसई के निवल लाभ के प्रतिशत के रूप में घोषित लाभांश 2021-22 में घटकर 43.33 प्रतिशत हो गया, जो 2020-21 में 52.46 प्रतिशत था। हालांकि, निरपेक्ष रूप में, 2021-22 में सीपीएसई द्वारा घोषित लाभांश पिछले वर्ष की तुलना में ₹13,609 करोड़ बढ़ गया। चार्ट 1.6 में 2019-20 से 2021-22 तक के पिछले तीन वर्षों में लाभांश घोषित करने वाली सीपीएसई के निवल लाभ और प्रदत्त पूंजी के सापेक्ष घोषित लाभांश को दर्शाया गया है।

चार्ट 1.6: घोषित लाभांश का शुद्ध लाभ और प्रदत्त की गई पूंजी के सापेक्ष

(₹ करोड़ में)



121 सीपीएसई द्वारा 2021-22 के लिए घोषित कुल ₹1,11,061 करोड़ के लाभांश (जो उनके निवल मूल्य का 6.98 प्रतिशत है) में से, केंद्रीय सरकार को ₹54,381 करोड़ (जो उनके कुल घोषित लाभांश ₹90,362 करोड़ का 60.18 प्रतिशत है) प्राप्त/प्राप्ति योग्य हुआ जो कि 78 सीपीएसई⁴⁰ से था, जिनमें केंद्रीय सरकार का ₹84,133 करोड़ का शेयर निवेश था। 454 सीपीएसई में केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए ₹6,36,730 करोड़ के कुल शेयर पूंजी निवेश पर केंद्रीय सरकार को लाभांश के रूप में प्राप्ति योग्य रिटर्न 8.54 प्रतिशत था, जबकि 2020-21 में यह 9.68 प्रतिशत था। 54 सीपीएसई के मामले में, इन कंपनियों को अन्य सीपीएसई में ₹46,297 करोड़ के अपने शेयर पूंजी निवेश पर ₹23,461 करोड़ का लाभांश प्राप्त हुआ। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र के नौ सीपीएसई ने ₹37,833 करोड़ का लाभांश घोषित किया, जो 121 सीपीएसई द्वारा घोषित कुल ₹1,11,061 करोड़ के लाभांश का 34.07 प्रतिशत था। 47 सूचीबद्ध सीपीएसई द्वारा 2021-22 में घोषित ₹91,648 करोड़ का कुल लाभांश इन कंपनियों के बाजार पूंजीकरण (₹15,36,588 करोड़) का 5.96 प्रतिशत था।

निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम) द्वारा मई 2016 में जारी किए गए दिशानिर्देशों के अंतर्गत यह प्रावधान था कि प्रत्येक सीपीएसई को कर पश्चात लाभ का न्यूनतम 30 प्रतिशत या निवल मूल्य का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, का वार्षिक लाभांश देना होगा, बशर्ते कि यह अधिकतम लाभांश के अंतर्गत अनुमत वैधानिक

⁴⁰ 78 सीपीएसई वे सरकारी कंपनियां और सांविधिक निगम हैं जिनमें केन्द्र सरकार की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी होती है।

प्रावधानों के अनुसार हो। हालांकि, 45 सरकारी कंपनियों (जिसमें सात सूचीबद्ध सीपीएसई भी शामिल हैं) ने, जिनके पास पर्याप्त निधि (प्रतिधारित आय और सामान्य रिजर्व) था, सरकार द्वारा निर्धारित लाभांश घोषित नहीं किया, जैसा कि **परिशिष्ट-IX** में दिया गया है। इन 45 सरकारी कंपनियों द्वारा घोषित किए जाने वाले ₹10,945 करोड़ के न्यूनतम लाभांश के मुकाबले, ₹5,134 करोड़ का लाभांश भुगतान किया गया था, इससे 2021-22 में ₹5,811 करोड़ की कुल कमी आई (जबकि 2020-21 में 54 सरकारी कंपनियों द्वारा ₹11,532 करोड़ की कमी आई थी)।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 / पूर्व कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अनुसार, एक कंपनी अपने सदस्य को कोई लाभांश देने से मना कर सकती है यदि इसके उद्देश्य कला, विज्ञान, खेल, शिक्षा, अनुसंधान, सामाजिक कल्याण, धर्म, दान, पर्यावरण की रक्षा या किसी अन्य ऐसे उद्देश्य के संवर्द्धन से संबंधित हों। 31 मार्च 2022 तक, ऐसी 21 सीपीएसई थीं, जिनमें से 18 सीपीएसई ने ₹942 करोड़ का लाभ अर्जित किया, एक सीपीएसई को ₹53 करोड़ का नुकसान हुआ, एक सीपीएसई के पहले खाते देय नहीं थे और एक सीपीएसई को 2021-22 में शून्य लाभ/हानि थी, जैसा कि **परिशिष्ट-X** में विस्तृत रूप से दिया गया है।

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹15,011 करोड़ का लाभ अर्जित करने वाली 129 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों में से, 52 कंपनियों ने ₹4,567 करोड़ का लाभांश घोषित किया, जो उनकी ₹16,486 करोड़ की प्रदत्त पूंजी का 27.71 प्रतिशत था। इन 52 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के द्वारा 2021-22 में घोषित लाभांश का क्षेत्रवार वर्गीकरण तालिका 1.15 में दिया गया है।

तालिका 1.15: सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों द्वारा घोषित लाभांश

सेक्टर	कंपनियों की संख्या	प्रदत्त पूंजी (₹ करोड़ में)	शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	घोषित लाभांश (₹ करोड़ में)
कृषि आधारित उद्योग	1	20	14	3
वित्तीय सेवाएँ	28	5,147	4,665	1,052
औद्योगिक विकास और तकनीकी परामर्श	4	4	7	3
बीमा	2	1,259	1,529	201

सेक्टर	कम्पनियों की संख्या	प्रदत्त पूंजी (₹ करोड़ में)	शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	घोषित लाभांश (₹ करोड़ में)
पेट्रोलियम	6	954	1,956	606
ऊर्जा	6	7,709	2,173	2,296
दूरसंचार सेवाएँ	1	58	141	3
व्यापार और विपणन	1	41	32	18
परिवहन सेवाएँ	3	1,294	581	385
कुल	52	16,486	11,098	4,567

1.4 सरकारी कंपनियों और निगमों की परिचालन दक्षता

1.4.1 पूंजी पर रिटर्न (आरओसीई)

नियोजित पूंजी पर रिटर्न (आरओसीई) एक अनुपात है जो एक कंपनी की लाभप्रदता और उसकी पूंजी के उपयोग की दक्षता को मापता है। आरओसीई की गणना कंपनी की ब्याज और कर से पहले की आय (ईबीआईटी) को नियोजित पूंजी द्वारा विभाजित करके की जाती है⁴¹। सीपीएसई वार आरओसीई का विवरण **परिशिष्ट-XI** में दिया गया है। 2019-20 से 2021-22 तक के पिछले तीन वर्षों में सभी सीपीएसई⁴² का समेकित आरओसीई तालिका 1.16 में दिया गया है।

तालिका 1.16: नियोजित पूंजी पर रिटर्न (आरओसीई)

वर्ष	सीपीएसई की संख्या	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूंजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (प्रतिशत में)
2019-20	410	2,70,219	35,35,016	7.64
2020-21	432	3,63,927	36,62,024	9.94
2021-22	452	4,19,294	40,09,376	10.46

⁴¹ नियोजित पूंजी = प्रदत्त शेयर पूंजी + मुक्त भंडार और अधिशेष + दीर्घकालिक ऋण - संचित घाटा - आस्थगित राजस्व व्यय।

⁴² भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को छोड़कर, जिन्हें शून्य लाभ/हानि सीपीएसई माना गया है क्योंकि उनके घाटे को फुटनोट 6 में दिए गए अनुसार समायोजित किया गया है।

यह देखा गया कि 2019-20 (7.64 प्रतिशत) की तुलना में 2020-21 (9.94 प्रतिशत) और 2021-22 (10.46 प्रतिशत) में सीपीएसई का आरओसीई महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा, जिसका मुख्य कारण ईबीआईटी में वृद्धि थी।

1.4.2 सीपीएसई का इक्विटी पर रिटर्न (आरओई)

इक्विटी पर रिटर्न (आरओई)⁴³ कंपनियों की वित्तीय प्रदर्शन को मापने का एक तरीका है, जिसे शुद्ध आय को शेयरधारकों की इक्विटी से विभाजित करके गणना की जाती है। सीपीएसई वार आरओई का विवरण **परिशिष्ट-XII** में दिया गया है। 2019-20 से 2021-22 तक के पिछले तीन वर्षों में सभी सीपीएसई⁴⁴ का संकेंद्रित आरओई तालिका 1.17 में दिया गया है।

तालिका 1.17: इक्विटी पर लाभ (आरओई)

वर्ष	सीपीएसई की संख्या	कर और प्राथमिक लाभांश के बाद शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	इक्विटी (₹ करोड़ में)	आरओई (प्रतिशत में)
2019-20	410	82,747	14,22,646	5.82
2020-21	432	1,59,538	15,98,295	9.98
2021-22	452	2,37,961	18,25,434	13.04

यह देखा गया कि 2020-21 और 2021-22 में सीपीएसई का आरओई महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा, जिसका मुख्य कारण शुद्ध लाभ में वृद्धि थी।

2019-20 से 2021-22 तक उन सरकारी कंपनियों और निगमों का क्षेत्रवार आरओई, जिनके क्षेत्र की कुल इक्विटी ₹10,000 करोड़ से अधिक थी, तालिका 1.18 में प्रदर्शित किया गया है।

⁴³ इक्विटी पर रिटर्न = (कर और वरीयता लाभांश/इक्विटी के बाद शुद्ध लाभ) * 100 जहां इक्विटी = प्रदत्त पूंजी + मुक्त भंडार - संचित घाटा - आस्थगित राजस्व व्यय।

⁴⁴ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को छोड़कर जिन्हें शून्य लाभ/हानि सीपीएसई माना गया है क्योंकि उनके घाटे को फुटनोट 6 में दिए अनुसार समायोजित किया गया है।

तालिका 1.18: ₹10,000 करोड़ या उससे अधिक कुल इक्विटी वाले क्षेत्रों का आरओई

(प्रतिशत में)

क्रम संख्या	सेक्टर	2021-22	2020-21	2019-20
1.	कोयला और लिग्नाइट	41.31	33.81	50.86
2.	ठेके और निर्माण सेवाएं	14.85	12.40	11.87
3.	वित्तीय सेवाएं	13.23	11.76	9.95
4.	भारी उद्योग	0.85	-10.85	-6.24
5.	औद्योगिक विकास	7.80	17.63	21.45
6.	बीमा	-2.48	0.26	-4.37
7.	खनिज और धातु	25.66	18.60	9.34
8.	पेट्रोलियम	17.00	13.53	3.62
9.	विद्युत	13.48	11.31	10.10
10.	इस्पात	23.13	6.91	-3.91
11.	परिवहन उपकरण	23.96	18.30	19.90
12.	परिवहन सेवाएं	-2.60	-5.24	0.54

यह देखा जा सकता है कि औद्योगिक विकास और बीमा क्षेत्रों के अलावा 2021-22 में ₹10,000 करोड़ या अधिक की कुल इक्विटी वाले सभी क्षेत्रों का आरओई 2020-21 की तुलना में बढ़ा।

1.4.3 बिक्री और विपणन

2021-22 के दौरान, 454 सरकारी कंपनियों और निगमों की कुल बिक्री ₹31,18,281 करोड़ थी। इन 454 सीपीएसई में से, 142 सीपीएसई ने अपनी कुल बिक्री ₹15,56,969 करोड़ में से सरकारी क्षेत्र को ₹3,92,660 करोड़ मूल्य का सामान/सेवाएं बेचीं। इन 142 सीपीएसई की सरकारी क्षेत्र को बिक्री का समग्र प्रतिशत उनकी कुल बिक्री के संदर्भ में 25.22 प्रतिशत था। 454 सीपीएसई में से 60 सीपीएसई ने ₹1,35,658 करोड़ (उनकी कुल बिक्री ₹18,69,326 करोड़ का 7.26 प्रतिशत) मूल्य का सामान/सेवाएं निर्यात कीं, जबकि 50 सीपीएसई ने ₹5,54,167 करोड़ मूल्य का सामान/सेवाएं आयात कीं, जिससे सीपीएसई द्वारा ₹4,18,509 करोड़ का शुद्ध आयात हुआ।

एकाधिकार और गैर-एकाधिकार सीपीएसई के संदर्भ में कुल बिक्री, सरकारी क्षेत्र को की गई बिक्री और उस पर निर्यात का विवरण तालिका 1.19 में दिया गया है।

तालिका 1.19: एकाधिकार और गैर-एकाधिकार सीपीएसई की बिक्री विवरण

प्रकार/ वर्ष	सीपीएसई की संख्या	कुल बिक्री (₹ करोड़ में)	सरकारी क्षेत्र को बिक्री (₹ करोड़ में)	निर्यात बिक्री (₹ करोड़ में)
एकाधिकार सीपीएसई⁴⁵				
2019-20	50	13,64,847	47,919	21,960
2020-21	52	12,20,963	47,539	29,827
2021-22	61	17,43,531	65,886	48,348
गैर-एकाधिकार सीपीएसई				
2019-20	362	10,50,645	2,18,797	61,971
2020-21	382	10,94,054	2,63,458	58,168
2021-22	393	13,74,750	3,26,774	87,310
कुल				
2019-20	412	24,15,492	2,66,716	83,931
2020-21	434	23,15,017	3,10,997	87,995
2021-22	454	31,18,281	3,92,660	1,35,658

454 सीपीएसई द्वारा ₹31,18,281 करोड़ की कुल बिक्री के मुकाबले, 60 सीपीएसई द्वारा 2021-22 में निर्यात बिक्री 4.35 प्रतिशत (₹1,35,658 करोड़) रही। 2021-22 में ₹5,000 करोड़ से अधिक निर्यात बिक्री करने वाली सीपीएसई का विवरण तालिका 1.20 में दिया गया है।

⁴⁵ एकाधिकार का अर्थ है एक ऐसा बाजार संरचना, जिसमें एकल विक्रेता होता है, जो बाजार में एक अद्वितीय उत्पाद बेचता है। एकाधिकार बाजार में, विक्रेता को कोई प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह उत्पादों का एकमात्र विक्रेता होता है और उसके उत्पाद का कोई करीबी विकल्प नहीं होता। एक सीपीएसई को एकाधिकार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि जिस भौगोलिक क्षेत्र में यह संचालित होती है, वहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। पेट्रोलियम क्षेत्र के अंतर्गत सीपीएसई को एकाधिकार श्रेणी में शामिल किया गया है, क्योंकि पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य निर्धारण प्रणाली प्रभावी रूप से सरकार के नियंत्रण में होती है, और सरकार द्वारा स्वामित्व और नियंत्रित पेट्रोलियम उत्पाद कंपनियां वर्चुअल एकाधिकार के रूप में कार्य करती हैं।

तालिका 1.20: सीपीएसई जिनकी निर्यात बिक्री 2021-22 में ₹5,000 करोड़ से अधिक
(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	निर्यात बिक्री
1.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	33,219
2.	मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	31,351
3.	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	13,100
4.	गैल (इंडिया) लिमिटेड	8,960
5.	ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	7,662
6.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	7,245
7.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	6,924
8.	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	6,364
9.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	5,388
	कुल	1,20,213

इन नौ सीपीएसई द्वारा की गई निर्यात बिक्री सभी 60 सीपीएसई द्वारा किए गए कुल निर्यात का 88.61 प्रतिशत थी।

1.4.4 अनुसंधान और विकास

प्रौद्योगिकी, उत्पाद या अविष्कार का पेटेंट एक कंपनी को इसे बनाने, उपयोग करने या बेचने से दूसरों को रोकने का अधिकार प्रदान करता है। यह विकास लागत की वसूली में भी मदद करता है और पेटेंट की गई प्रौद्योगिकी के विकास में किए गए निवेश पर लाभ प्राप्त करने में सहायता करता है। पेटेंट का पंजीकरण यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि वही विचार आधारित प्रौद्योगिकी, उत्पाद या अविष्कार किसी अन्य कंपनी द्वारा प्राप्त नहीं किया जाएगा। तालिका 1.21 पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसंधान और विकास व्यय के मुकाबले पंजीकृत पेटेंट को दर्शाती है।

तालिका 1.21: अनुसंधान और विकास व्यय तथा पंजीकृत पेटेंट्स

2019-20		2020-21		2021-22	
अनुसंधान एवं विकास व्यय (करोड़ रुपए में)	पंजीकृत पेटेंटों की संख्या	अनुसंधान एवं विकास व्यय (करोड़ रुपए में)	पंजीकृत पेटेंटों की संख्या	अनुसंधान एवं विकास व्यय (करोड़ रुपए में)	पंजीकृत पेटेंटों की संख्या
4,932	1,385	5,319	1,457	6,802	1,605

यह देखा गया कि 2021-22 में अनुसंधान और विकास व्यय 2020-21 के ₹5,319 करोड़ से बढ़कर ₹6,802 करोड़ हो गया, जो ₹1,483 करोड़ की वृद्धि को दर्शाता है, और पेटेंट की संख्या भी 2020-21 में 1,457 से बढ़कर 2021-22 में 1,605 हो गई।

2021-22 में पंजीकृत 1,605 पेटेंट्स में से, 149 पेटेंट्स को नौ सीपीएसई द्वारा वाणिज्यिकृत किया गया और 2021-22 में ₹42.05 करोड़ की आय प्राप्त की गई, जैसा कि तालिका 1.22 में उल्लेखित है।

तालिका 1.22: व्यावसायीकरण किए गए पेटेंट्स की संख्या और अर्जित राजस्व

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	अनुसंधान और विकास पर कुल व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत पेटेंट्स की संख्या	व्यावसायीकरण किए गए पेटेंट्स की संख्या	पेटेंट्स के व्यावसायीकरण से अर्जित राजस्व (₹ करोड़ में)
1	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	1,069.38	11	3	34.91
2	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	576.55	225	4	0
3	ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	513.31	13	4	0
4	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	363.66	34	2	0
5	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	51.34	8	2	0

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	अनुसंधान और विकास पर कुल व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत पेटेंट्स की संख्या	व्यावसायीकरण किए गए पेटेंट्स की संख्या	पेटेंट्स के व्यावसायीकरण से अर्जित राजस्व (₹ करोड़ में)
6	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	23.26	6	1	0.45
7	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	20.94	33	18	1.3
8	मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	1.01	15	1	0.06
9	एग्रोनोवेटिव इंडिया लिमिटेड	0	582	114	5.33
	कुल	2,619.45	927	149	42.05

इसके अलावा, 2021-22 के दौरान जिन सीपीएसई ने ₹500 करोड़ से अधिक का अनुसंधान और विकास व्यय किया, उनका विवरण तालिका 1.23 में दिया गया है।

तालिका 1.23: सीपीएसई जिनका अनुसंधान और विकास व्यय ₹500 करोड़ से अधिक

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	कुल अनुसंधान और विकास व्यय (₹ करोड़ में)	शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	पंजीकृत पेटेंट की संख्या	शुद्ध लाभ पर अनुसन्धान एवं विकास व्यय का प्रतिशत
1	हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड	1,967	5,087	41	38.67
2	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	1,069	2,349	11	45.51
3	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	815	12,015	14	6.78
4	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	577	24,184	225	2.39
5	ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	513	40,306	13	1.27

यह देखा गया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2021-22 में अनुसंधान और विकास पर सबसे अधिक ₹1,967 करोड़ खर्च किए और कंपनी द्वारा पंजीकृत पेटेंट्स की संख्या 41 रही। इसी तरह, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 2021-22 में क्रमशः ₹1,069 करोड़ और ₹815 करोड़ का अनुसंधान और विकास व्यय किया, जबकि पेटेंट्स की संख्या केवल 11 और 14 थी।

डीपीई ने अपने जवाब (मई 2024) में बताया कि इस अध्याय पर उनकी कोई टिप्पणी नहीं है।

द्वितीय अध्याय

सीएजी की निगरानी भूमिका

2.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) सरकारी कंपनी और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के वैधानिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं, जो कि कंपनियों के अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) और (7) के अंतर्गत होती है। सीएजी को एक अनुपूरक लेखापरीक्षा करने और वैधानिक लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर टिप्पणी करने या उसे अनुपूरित करने का अधिकार होता है। कुछ निगमों के शासी अधिनियमों में यह प्रावधान है कि उनकी वित्तीय स्थिति की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाए और रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की जाए।

2.2. सीएजी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वैधानिक लेखापरीक्षकों की सीएजी द्वारा नियुक्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) के अंतर्गत यह प्रावधान है कि सरकारी कंपनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति सीएजी द्वारा वित्तीय वर्ष की शुरुआत से 180 दिनों के भीतर की जानी चाहिए। वर्ष 2021-2022 के लिए इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वैधानिक लेखापरीक्षक सीएजी द्वारा अगस्त 2021 में नियुक्त किए गए थे।

वर्ष 2021-2022 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वैधानिक लेखापरीक्षकों को अगस्त 2021 में नियुक्त किया गया था।

2.3 सीपीएसई द्वारा वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति

2.3.1 समय पर प्रस्तुति की आवश्यकता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अनुसार, सरकारी कंपनी के कार्यों और मामलों पर वार्षिक रिपोर्ट को उसकी वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के तीन महीने के भीतर

तैयार किया जाना चाहिए। इस तैयारी के बाद, जितनी जल्दी हो सके, वार्षिक रिपोर्ट को दोनों सदनों के संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए, इसके साथ-साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट और सीएजी की टिप्पणियां या लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर की गई टिप्पणियां भी प्रस्तुत की जानी चाहिए। समान प्रावधान संबंधित विधियों में भी हैं जो वैधानिक निगमों को नियंत्रित करती हैं। यह व्यवस्था सार्वजनिक धन के उपयोग पर आवश्यक संसदीय नियंत्रण प्रदान करती है, जो भारत के संचित कोष से कंपनियों में निवेश किया गया है।

कंपनियों के अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अनुसार, प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों की एजीएम आयोजित करनी होती है। इसमें यह भी कहा गया है कि एक एजीएम और अगली एजीएम के बीच 15 महीने से अधिक का समय नहीं गुजरना चाहिए। यह धारा यह भी प्रदान करती है कि यदि यह पहली वार्षिक सामान्य बैठक है, तो इसे कंपनी के पहले वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि से नौ महीने के भीतर आयोजित किया जाना चाहिए, और किसी अन्य मामले में, यह वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि से छह महीने के भीतर आयोजित किया जाना चाहिए। धारा में यह भी प्रावधान है कि रजिस्ट्रार किसी विशेष कारण से किसी भी वार्षिक सामान्य बैठक, पहली एजीएम को छोड़कर, के आयोजन के लिए समय सीमा को तीन महीने तक बढ़ा सकता है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में यह प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणों को संबंधित एजीएम में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस धारा में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति, जिसमें कंपनी के निदेशक भी शामिल हैं, धारा 129 के प्रावधानों का पालन नहीं करते हैं, तो उन पर जुर्माना और कारावास जैसी दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सीएजी को कंपनी के वित्तीय विवरणों का पूरक लेखापरीक्षण करने के लिए 60 दिनों की समय अवधि और एजीएम के लिए 21 दिनों की नोटिस अवधि प्रदान की गई है, तो आदर्श रूप से सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को वर्ष 2021-22 के लिए अपने वित्तीय विवरण सीएजी को 11 जुलाई, 2022 तक प्रस्तुत करने चाहिए थे। हालांकि, एक महत्वपूर्ण संख्या में सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों (सीपीएसई) ने अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों को सीएजी को 11 जुलाई, 2022 तक प्रस्तुत नहीं किया। कुछ सीपीएसई ने

अपने वित्तीय विवरण 30 सितंबर, 2022 तक सीएजी को प्रस्तुत नहीं किए, जो एजीएम आयोजित करने की अंतिम तिथि थी। इस संदर्भ में विवरण निम्नलिखित पैरा में दिए गए हैं।

2.3.2 सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों (सीपीएसई) द्वारा वित्तीय विवरणों की तैयारी में समयबद्धता

31 मार्च 2022 को, सीएजी के लेखापरीक्षण के अधीन कुल 490 सरकारी कंपनियां और 202 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां (सीपीएसई) थीं। इनमें से, आठ सरकारी कंपनियों से वित्तीय विवरण देय नहीं थे, क्योंकि ये कंपनियां नई थीं।

692 सीपीएसई में से 29 फरवरी, 2024 तक 69 सीपीएसई के वित्तीय विवरण लंबित थे।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 482 सरकारी कंपनियों और 202 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों से वित्तीय विवरण देय थे। इनमें से केवल 255 सरकारी कंपनियों (52.90 प्रतिशत) और 110 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों (54.45 प्रतिशत) ने 11 जुलाई, 2022 तक अपनी खाते सीएजी को अनुपूरक लेखापरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए। इसके अतिरिक्त, 30 सितंबर, 2022 तक केवल 418 सरकारी कंपनियों (86.72 प्रतिशत) और 174 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों (86.14 प्रतिशत) से वित्तीय विवरण प्राप्त हुए। 29 फरवरी, 2024 तक 431 सरकारी कंपनियों (89.42 प्रतिशत) और 184 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों (91.10 प्रतिशत) से वित्तीय विवरण प्राप्त हुए। इस प्रकार, 29 फरवरी, 2024 तक 51 सरकारी कंपनियों (10.58 प्रतिशत) और 18 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों (8.90 प्रतिशत) के वित्तीय विवरण विभिन्न कारणों से लंबित थे। सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के वित्तीय विवरण की लंबित स्थिति के विवरण तालिका 2.1 में दिए गए हैं।

तालिका 2.1: वित्तीय विवरणों के बकाया का विवरण

विवरण	सरकारी कंपनियाँ / सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ					
	सरकारी कंपनियाँ		सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ		कुल	
31 मार्च, 2022 को सीएजी के लेखापरीक्षा के अंतर्गत आने वाली सीपीएसई की कुल संख्या	490		202		692	
	सूचीबद्ध	असूचीबद्ध	सूचीबद्ध	असूचीबद्ध	सूचीबद्ध	असूचीबद्ध
सूचीबद्ध / असूचीबद्ध	68	422	8	194	76	616
घटा: नई सीपीएसई जिनसे 2021-22 के वित्तीय विवरण देय नहीं थे	0	8	0	0	0	8
उन सीपीएसई की संख्या जिनके लिए 2021-22 के वित्तीय विवरण देय थे	68	414	8	194	76	608
उन सीपीएसई की संख्या जिन्होंने 11 जुलाई, 2022 तक सीएजी की लेखापरीक्षा के लिए वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए	59	196	7	103	66	299
उन सीपीएसई की संख्या जिन्होंने 30 सितंबर, 2022 तक सीएजी की लेखापरीक्षा के लिए वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए।	68	350	8	166	76	516
उन सीपीएसई की संख्या जिन्होंने 29 फरवरी, 2024 तक सीएजी की लेखापरीक्षा के लिए वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए।	68	363	8	176	76	539
29 फरवरी, 2024 तक लंबित वित्तीय विवरणों की संख्या	0	51	0	18	0	69

विवरण		सरकारी कंपनियाँ / सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ					
		सरकारी कंपनियाँ		सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ		कुल	
लंबित वित्तीय विवरणों का वितरण	(i) परिसमापन प्रक्रियाधीन	0	26	0	11	0	37
	(ii) निष्क्रिय	0	0	0	0	0	0
	(iii) अन्य	0	25	0	7	0	32
अन्य श्रेणी के अंतर्गत लंबित वित्तीय विवरणों का आयु-आधारित विश्लेषण	एक वर्ष (2021-22)	0	14	0	3	0	17
	दो वर्ष (2020-21 एवं 2021-22)	0	3	0	1	0	4
	तीन वर्ष एवं अधिक	0	8	0	3	0	11

इन सीपीएसई के नाम **परिशिष्ट-III क** और **परिशिष्ट-III ख** में दिए गए हैं।

2.3.3 वैधानिक निगमों द्वारा वित्तीय विवरण तैयार करने में समयबद्धता

सीएजी द्वारा छह वैधानिक निगमों का लेखापरीक्षण किया जाता है। पांच वैधानिक निगमों में जहां सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वित्तीय विवरण 2021-22 के लिए 30 सितंबर, 2022 से पहले लेखापरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए थे। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के वर्ष 2021-22 के वित्तीय विवरण 30 सितंबर, 2022 तक प्राप्त नहीं हुए थे। केंद्रीय भंडारण निगम के मामले में, सीएजी अनुपूरक लेखापरीक्षा करता है और वित्तीय विवरण 30 सितंबर, 2022 से पहले प्राप्त हो गए थे।

2.4 सीएजी की निगरानी - वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा और पूरक लेखापरीक्षा

2.4.1 वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा

कंपनियों को वित्तीय विवरण कंपनियों अधिनियम, 2013 के अनुसूची तृतीय में निर्धारित प्रारूप में तैयार करना आवश्यक है और केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वित्तीय लेखा रिपोर्टिंग प्राधिकरण से परामर्श करके निर्धारित अनिवार्य लेखांकन मानकों का पालन करना होता है। वैधानिक निगमों को अपने वित्तीय विवरण उन नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में तैयार करना होता है, जो सीएजी से परामर्श करके बनाए गए हैं, और किसी अन्य विशिष्ट प्रावधान के अनुसार जो संबंधित अधिनियम में उन निगमों के खाते से संबंधित होते हैं।

2.4.2 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वित्तीय विवरणों का वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षक सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा करते हैं और इसके संबंध में अपनी रिपोर्ट कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत करते हैं।

सीएजी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की लेखापरीक्षा में वैधानिक लेखापरीक्षकों के प्रदर्शन की निगरानी करके एक निरीक्षण भूमिका निभाता है, जिसका समग्र उद्देश्य यह है की वैधानिक लेखापरीक्षक उन्हें सौंपे गए कार्यों को उचित और प्रभावी ढंग से पूरा करें। यह कार्य निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करके किया जाता है।

- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत वैधानिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना
- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर अनुपूरक टिप्पणी करना या उस पर टिप्पणी करना।

2.4.3 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 2013 या अन्य संबंधित अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की प्रमुख जिम्मेदारी एक संस्था के प्रबंधन की होती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त किए गए वैधानिक लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी होती है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करें, जो भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) के मानक लेखापरीक्षा पद्धतियों और सीएजी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार होती है। वैधानिक लेखापरीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत सीएजी को लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है।

चयनित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमाणित वित्तीय विवरणों और वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा की जाती है। इस समीक्षा के आधार पर, महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियां यदि कोई हों, तो उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत एजीएम के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए रिपोर्ट किया जाता है।

2.5 सीएजी की निगरानी भूमिका के परिणाम

2.5.1 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत सीपीएसई के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा

वित्तीय वर्ष 2021-22 के वित्तीय विवरण 30 सितंबर, 2022 तक 418 सरकारी कंपनियाँ (जिसमें 68 सूचीबद्ध कंपनियाँ शामिल हैं), 174 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ (जिसमें आठ सूचीबद्ध कंपनियाँ शामिल हैं) और पांच सांविधिक निगमों से

सीएजी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 379 सीपीएसई और पांच सांविधिक निगमों के वित्तीय विवरणों की समीक्षा की।

प्राप्त हुए थे। इनमें से 283 सरकारी कंपनियों, 96 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों और पांच सांविधिक निगमों के वित्तीय विवरणों की सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा की गई।

कुल मिलाकर, सीएजी ने 30 सितंबर, 2022 तक प्राप्त वित्तीय विवरणों में से 67.70 प्रतिशत सरकारी कंपनियों और 55.17 प्रतिशत सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के वित्तीय विवरणों की समीक्षा की। समीक्षा के परिणाम नीचे विस्तार से दिए गए हैं।

2.5.1.1 वित्तीय विवरणों में संशोधन

सीएजी द्वारा किए गए अनुपूरक लेखापरीक्षण के परिणामस्वरूप, पांच सरकारी कंपनियों और दो सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनियों ने अपने वित्तीय विवरणों को एजीएम में प्रस्तुत करने से पहले संशोधित किया जैसा कि **परिशिष्ट-XIII** में विस्तार से दिया गया है।

2.5.1.2 वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का संशोधन

सीएजी द्वारा किए गए अनुपूरक लेखापरीक्षण के परिणामस्वरूप, 66 सरकारी कंपनियों और 22 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के वैधानिक लेखापरीक्षकों ने अपनी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में जैसा कि **परिशिष्ट-XIV** में विस्तार से दिया गया है, कंपनियों के वित्तीय विवरणों को उनकी एजीएम में प्रस्तुत करने से पहले अपनी रिपोर्ट में संशोधन किया।

2.5.1.3 सीएजी द्वारा सीपीएसई पर वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुपूरक के रूप में जारी की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण के बाद, सीएजी ने चयनित सीपीएसई के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखापरीक्षण किया। उन 92 सीपीएसई की सूची जिन्हे टिप्पणियाँ जारी की गईं, **परिशिष्ट-XV** में दी गई है। सीपीएसई के वित्तीय विवरणों पर जारी की गई कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ, जिनका लाभप्रदता पर वित्तीय प्रभाव ₹4,498.04 करोड़ और परिसंपत्तियों/ देनदारियों पर ₹2,88,460.13 करोड़ था, नीचे दी गई हैं। पूर्व में इंगित किए जाने के बावजूद, कुछ सीपीएसई जैसे कि ओडिशा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ए.ii.6), आईएफसीआई लिमिटेड (ए.i.3), डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (बी.ii.6), ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (बी.ii.8), नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (बी.ii.13) ने सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की, जिसे नीचे इंगित किया गया है।

क. सूचीबद्ध सरकारी कंपनियां

क.ि. लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
1.	बाल्मर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	गैर चालू देनदारियों के अंतर्गत प्रावधान ₹12.02 करोड़ से कम दर्शाए गए थे, क्योंकि बाल्मर लॉरी स्टाफ प्रोविडेंट फंड के संदर्भ में मैसर्स डीएचएफएल, मैसर्स आईएल एंड एफएस, और मैसर्स रिलायंस कैपिटल में संदेहास्पद निवेश ₹11.65 करोड़ की देनदारी सहित ब्याज को शामिल नहीं किया गया था। इन सभी संस्थाओं के संबंध में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया का आदेश दिया, जिसके कारण मूलधन और ब्याज राशि की वसूली की संभावना बहुत कम प्रतीत होती है। इस प्रकार, इसके लिए प्रावधान न करने से प्रावधानों का कम आकलन और लाभ का अधिक आकलन हुआ, जो ₹12.02 करोड़ था। समाप्त पट्टाहोल्ड भूमि के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता को भुगतान करने योग्य किराया और मुआवजा शुल्क के लिए प्रावधान न करने से वर्तमान देनदारियों के अंतर्गत प्रावधानों का ₹1.93 करोड़ का कम आकलन, गैर चालू देनदारियों के अंतर्गत प्रावधानों का ₹11.36 करोड़ का कम आकलन और लाभ का ₹13.29 करोड़ का अधिक आकलन हुआ।
2.	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	कंपनी ने इंड एस 36 के पैरा 9 के अनुसार कॉनकोर एयर लिमिटेड (जो एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है) में अपनी निवेश की हानि परीक्षण नहीं किया और अपने निवेश को कम नहीं किया, क्योंकि कॉनकोर एयर लिमिटेड ने अपने रियायती अधिकारों और स्थिर संपत्तियों को मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड को बेचने का निर्णय लिया है। इसके परिणामस्वरूप, निवेश और कर से पूर्व लाभ का अधिक आकलन ₹12.41 करोड़ से हुआ।
3.	आईएफसीआई लिमिटेड	निम्नलिखित कारणों से ऋण को अधिक दिखाया गया और वर्ष के नुकसान को ₹344.60 करोड़ से कम दर्शाया गया: एनसीएलटी के निर्णय और समाधान योजना के अनुसार, कंपनी का वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (वीआईएल) से दावा ₹383.50 करोड़ की बकाया राशि के मुकाबले ₹70.31 करोड़ तक सीमित किया गया था। वीआईएल से अधिकतम वसूली राशि ₹74.71 करोड़ ही थी। ₹308.79 करोड़ की बाकी राशि को बट्टे खाते में न डाले जाने के कारण नुकसान का कम आकलन ₹101.56 करोड़ हुआ (जिसमें ₹207.23

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		करोड़ का हानि प्रावधान समायोजित किया गया) और लोन में उसी राशि तक का अधिक आकलन हुआ। कंपनी द्वारा पिछले वर्ष में इसे इंगित किए जाने के बावजूद कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया। • ग्रैन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए ₹135.81 करोड़ के लोन की बाकी राशि को बट्टे खाते में न डाले जाने के कारण, जो कि एनसीएलटी के आदेशों के अनुसार, परिसमापन की प्रक्रिया में है, नुकसान का कम आकलन ₹44.67 करोड़ हुआ (जिसमें ₹91.14 करोड़ का हानि प्रावधान समायोजित किया गया) और लोन में उसी राशि तक का अधिक आकलन हुआ। कंपनी द्वारा पिछले वर्ष भी इसे इंगित किए जाने के बावजूद कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया। • कंपनी ने मेसर्स कोस्टल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (सीईपीएल) को दिए गए ऋण के संबंध में ₹128.18 करोड़ की शेष राशि को बट्टे खाते में नहीं डाला, जिसे 30 जून 2018 को गैर निष्पादित संपत्ति घोषित किया गया था और एनसीएलटी के आदेशों के अनुसार परिसमापन प्रक्रिया शुरू की गई थी। कंपनी ने ₹584.17 करोड़ (₹285.45 करोड़ के बकाया ब्याज सहित) का दावा प्रस्तुत किया, हालाँकि, सीईपीएल की परिसंपत्तियों में कंपनी का हिस्सा ₹298.72 करोड़ की बकाया मूल ऋण राशि के मुकाबले केवल ₹170.54 करोड़ (लगभग) बनता है। इस प्रकार, ₹128.18 करोड़ की शेष राशि (₹298.72 करोड़ माइनस ₹170.54 करोड़) को बट्टे खाते में डाल दिया जाना चाहिए था। शेष 128.18 करोड़ रुपये की राशि को बट्टे खाते में न डालने के परिणामस्वरूप हानि को 42.16 करोड़ रुपये कम दर्शाया गया (86.02 करोड़ रुपये की हानि भत्ते के समायोजन के बाद) तथा ऋण को इतनी ही राशि अधिक दर्शाया गया। • रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड (आरएनवीएल) से ₹147 करोड़ की बकाया राशि की वसूली के लिए कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (15 जनवरी 2020) शुरू की गई थी। क्रेडिटर्स की समिति को बोलीदाताओं से दो समाधान योजनाएं प्राप्त हुईं। योजनाओं के अनुसार, यदि कंपनी योजना को स्वीकार करती है, तो अधिकतम वसूली ₹31.93 करोड़ होगी, और यदि असहमत होती है, तो ₹28.14 करोड़ की वसूली होगी। चूंकि कंपनी ने दिवालियापन को समाधान प्रक्रिया असहमती दी (14 मार्च 2022), अधिकतम संभव वसूली बकाया राशि ₹147 करोड़ में से ₹28.14 करोड़ ही है।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		बाकी ₹118.86 करोड़ को बट्टे खाते में न डाले जाने के कारण नुकसान का आकलन ₹39.09 करोड़ से कम हुआ (जिसमें ₹79.77 करोड़ का हानि प्रावधान समायोजित किया गया) और लोन में उसी राशि तक का अधिक आंकलन हुआ। • लोन में मधुकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमआईएल) के खिलाफ ₹151.50 करोड़ की बकाया राशि शामिल थी। कंपनी ने ₹31.43 करोड़ की अधिकतम वसूली राशि निकाली, जो इसके पास उपलब्ध संपत्तियों पर आधारित थी, और जनवरी 2020 में ₹70 करोड़ के एक बार निपटान (ओटीएस) पर सहमति दी, जिस पर एमआईएल ने सहमति नहीं दी। इसके बाद, कंपनी ने में ओटीएस को रद्द कर दिया (दिसंबर 2020)। एमआईएल ने 6 जून 2022 को ₹50 करोड़ का नया ओटीएस प्रस्ताव दिया। अतः अधिकतम संभव वसूली ₹50 करोड़ ही है, जबकि कुल बकाया ₹151.50 करोड़ है। बाकी ₹101.50 करोड़ को बट्टे खाते में न डाले जाने के कारण नुकसान का कम आकलन ₹33.38 करोड़ हुआ (जिसमें ₹68.12 करोड़ का हानि प्रावधान समायोजित किया गया) और लोन में उसी राशि तक का अधिक आंकलन हुआ। कंपनी द्वारा पिछले वर्ष भी इसे इंगित किए जाने के बावजूद कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया। • मेसर्स सी एंड सी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को ₹75.90 करोड़ का दिया गया लोन जिसमें ₹75.73 करोड़ की बाकी राशि को बट्टे खाते में नहीं डाला, जिसकी समाधान योजना के विफल होने के बाद परिसमापन प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई, परिसमापन मूल्य ₹234 करोड़ के रूप में कार्यान्वित किया गया और कंपनी का हिस्सा परिसमापन में ₹0.17 करोड़ ही था। बाकी राशि को बट्टे खाते में न डाले जाने के कारण नुकसान का कम आकलन ₹24.91 करोड़ हुआ (जिसमें ₹50.82 करोड़ का हानि प्रावधान समायोजित किया गया) और लोन में उसी राशि तक का अधिक आंकलन हुआ। कंपनी द्वारा पिछले वर्ष में इसे इंगित किए जाने के बावजूद कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया। • लोन में लिज़ ट्रेडर्स एंड एजेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (एलटीएपीएल) को दी गई ₹91.40 करोड़ की बकाया राशि शामिल थी। एलटीएपीएल द्वारा डिफॉल्ट करने के कारण, एक मामला रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) के सामने दायर किया गया। आरपी ने बताया कि कॉर्पोरेट डेब्टर के पास केवल सुरक्षा और वित्तीय परिसंपत्तियाँ हैं और पिछले

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		3-4 वर्षों से कोई व्यापार नहीं हुआ है। कंपनी के पास कोल्लम, केरल में एक संपत्ति है, जिसकी उचित मूल्य ₹32.69 करोड़ है। अन्य कोई सुरक्षा उपलब्ध न होने के कारण, बाकी ₹58.71 को बट्टे खाते में डाल दिया जाना चाहिये था। बाकी ₹58.71 करोड़ को बट्टे खाते में न डाले जाने के कारण नुकसान का कम आकलन ₹19.31 करोड़ हुआ (जिसमें ₹39.40 करोड़ का हानि प्रावधान समायोजित किया गया) और लोन में उसी राशि तक का अधिक आकलन हुआ। • ऋणों में 31 मार्च 2022 तक 78.21 करोड़ रुपये का बकाया मूलधन शामिल था, जो कि खेद सिन्नर एक्सप्रेसवे लिमिटेड (केएसईएल) पर था, जो कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई) परियोजना को लागू करने के लिए आईएल एंड एफएस समूह के तहत गठित एक एसपीवी है। एनएचआई द्वारा परियोजना को समाप्त कर दिया गया था। आईएल एंड एफएस समूह ने एनसीएलटी में समाधान योजना दायर की, जिसे मार्च 2020 में स्वीकृति प्राप्त हुई। स्वीकृत समाधान योजना के अनुसार, कंपनी का हिस्सा ₹63 करोड़ था। अधिकतम वसूली ₹63 करोड़ होने के कारण, बाकी ₹15.21 करोड़ का बट्टे खाते में डाल दिया जाना चाहिये था। बाकी ₹15.21 करोड़ को बट्टे खाते में न डाले जाने के कारण नुकसान का कम आकलन ₹5 करोड़ हुआ (जिसमें ₹10.21 करोड़ का हानि प्रावधान समायोजित किया गया) और लोन में उसी राशि का अधिक आकलन हुआ। कंपनी द्वारा पिछले वर्ष में इसे इंगित किए जाने के बावजूद कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया। • लोन में आईएल एंड एफएस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (आईडीसीएल) को दिए गए ₹100 करोड़ की बकाया राशि शामिल थी। ऋणदाता ने नवंबर 2019 से भुगतान में डिफॉल्ट किया था, और खाते को कंपनी द्वारा एनपीए घोषित किया गया। इसके बाद, आईएल एंड एफएस समूह द्वारा डिफॉल्ट करने पर, आईडीसीएल को “रेड कंपनी” के रूप में वर्गीकृत किया गया। फॉरेन्सिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर, अधिकांश ऋणदाता बैंकों ने दिसंबर 2020 से फरवरी 2022 के बीच खाते को धोखाधड़ी घोषित किया। हालांकि, कंपनी ने लोन को स्टेज 3 के रूप में दिखाया और 67.11 प्रतिशत का हानि प्रावधान किया, जबकि इसे धोखाधड़ी मानकर 100 प्रतिशत प्रावधान किया जाना चाहिए था। इस कारण से नुकसान का कम

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		आकलन ₹32.89 करोड़ हुआ (जिसमें ₹67.11 करोड़ का हानि प्रावधान समायोजित किया गया) और लोन में उसी राशि तक का अधिक आकलन हुआ। • लोन में कोस्टल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (सीपीएल) को दिए गए ₹4.96 करोड़ की बकाया राशि शामिल थी। केपीएमजी की फॉरेन्सिक रिपोर्ट (6 जनवरी 2020) के अनुसार, सीपीएल के लोन खाते को धोखाधड़ी घोषित किया गया था, और उसी आधार पर, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने सीपीएल के लोन खाते को धोखाधड़ी घोषित किया। हालांकि, कंपनी ने सीपीएल के लोन खाते को स्टेज 3 के रूप में दिखाया और 67.11 प्रतिशत का हानि प्रावधान किया, जबकि इसे धोखाधड़ी मानकर 100 प्रतिशत प्रावधान किया जाना चाहिए था। इसके कारण नुकसान का कम आकलन ₹1.63 करोड़ हुआ (जिसमें ₹3.33 करोड़ का हानि प्रावधान समायोजित किया गया) और लोन में उसी राशि तक का अधिक आकलन हुआ।
4.	आईटीआई लिमिटेड	अदालत के आदेशों के बाद भी खर्चों को ₹16.48 करोड़ कम दर्शाया गया है, क्योंकि 2016-17 से 2021-22 की अवधि के लिए बृहत बेंगलुरु महानगर पालिके (बीबीएमपी) को देय संपत्ति कर का प्रावधान नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप, लाभ का उस राशि तक अधिक आकलन हुआ है। इसके अलावा, उस पर देय ब्याज और जुर्माने की देनदारी का खुलासा भी नहीं किया गया।
5.	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	प्रावधानों में निम्नलिखित देनदारियों के कारण ₹552.66 करोड़ का प्रावधान शामिल नहीं किया गया: (i) ₹64.52 करोड़, जो हाइड्रोकार्बन के महानिदेशक द्वारा शेल गैस और तेल अन्वेषण एवं शोषण के लिए निर्धारित न्यूनतम कार्य कार्यक्रम को तय समय सीमा के भीतर पूरा न करने के कारण निर्णीत हर्जाने के रूप में मांगी गई है। (ii) ₹488.14 करोड़, जो भारत सरकार (जीओआई) को रॉयल्टी के अवैतनिक/कम भुगतान के रूप में देय है, जो हाइड्रोकार्बन के महानिदेशक द्वारा मांगी गई है (ब्लॉक्स केजी-ओएसएन -2001/3 और सीबी-ओएस /2 के लिए)। इन देनदारियों का प्रावधान न करने के कारण, प्रावधानों का कम आकलन और लाभ का अधिक आकलन से ₹552.66 करोड़ हुआ।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
6.	ऑयल इंडिया लिमिटेड	न्यूनतम कार्य कार्यक्रम के अधूरे रहने के संबंध में ₹144 करोड़ की देनदारी का प्रावधान न करने के कारण, जो कि फरवरी 2022 में ब्लॉक (एनईएलपी VI ब्लॉक एमजेड-ओएनएन-2004/1) की समाप्ति के बाद भारत सरकार को देय था, प्रावधान में कम आकलन और लाभ में ₹144 करोड़ का अधिक आकलन हुआ।
7.	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	• प्रॉपर्टी, प्लांट और उपकरण (एनई प्रोजेक्ट की परिसंपत्तियां) को ₹33.24 करोड़ से अधिक दर्शाया गया, क्योंकि परिसंपत्तियों के मूल्य का आकलन वैकल्पिक लागत विधि (प्रतिस्थापन लागत विधि) से किया गया था, जबकि 'उपयोग में परिसंपत्ति' का मूल्यांकन किया जाना चाहिए था, जो आई एंड एस 36 के पैरा 6 का उल्लंघन है। इसके परिणामस्वरूप, एनई प्रोजेक्ट के क्षति हानी का कम आकलन ₹33.24 करोड़ से कम हुआ और कर से पूर्व लाभ का अधिक आकलन उसी राशि तक हुआ। • अन्य आय में ₹50.18 करोड़ शामिल था, जो वर्ष 2021-22 में किए गए अधिक प्रावधान की वापसी का था। हालांकि, कंपनी ने इस प्रावधान वापसी को 'असाधारण वस्तु' के रूप में लाभ हानि पत्रक में घोषित नहीं किया, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III और इंड एस 1 के पैरा 96 का उल्लंघन है। इसके परिणामस्वरूप, अन्य आय का अधिक आकलन से ₹50.18 करोड़ हुआ और असाधारण वस्तु का उसी राशि तक का कम आकलन हुआ।
8.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	• दामोदर घाटी निगम को पेट्रोल और ऊर्जा प्रभार के बढ़े हुए खर्च के लिए प्रावधान न करने के कारण, जो कि पश्चिम बंगाल विद्युत नियामक आयोग के 05 मई 2022 के टैरिफ आदेशों के अनुसार देय था, ऊर्जा और फ्यूल चार्ज का कम आकलन और लाभ का अधिक आकलन ₹70.17 करोड़ से हुआ। • भारतीय रेलवे से प्राप्त अवशिष्ट अग्रिम पर देय ब्याज के लिए प्रावधान न करने के कारण, जो कि वित्त मंत्रालय के मुख्य सलाहकार (लागत) द्वारा 2019-20 के लिए तय ब्याज दर पर आधारित था, प्रावधानों से कम आकलन और लाभ का अधिक आकलन ₹30.79 करोड़ हुआ।

क.ii वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
1.	कोल इंडिया लिमिटेड	सीआईएल के गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते प्रत्येक पांच साल में राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते (एनसीडब्लूए) के अंतिमकरण के बाद निर्धारित किए जाते हैं। वेतन संशोधन 1 जुलाई 2021 से एनसीडब्लूए-XI के अनुसार देय था। कंपनी ने खातों में अपेक्षित वेतन संशोधन के लिए प्रावधान किया था। हालांकि, अपेक्षित वेतन संशोधन के लिए प्रावधान किए जाने के बावजूद, बीमांकिक ने पिछले वर्ष 2020-21 में उपयोग किए गए वही अनुमान लिया और 01 जुलाई 2021 से देय वेतन संशोधन को ध्यान में नहीं रखा। इसके परिणामस्वरूप, रिटायरमेंट लाभ के संदर्भ में प्रावधानों और वर्ष के लाभ का गलत चित्रण हुआ (राशि निर्दिष्ट नहीं की गई)।
2.	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	‘पट्टा प्राप्तियाँ’ रोलिंग स्टॉक और अन्य रेलवे परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए रेल मंत्रालय से प्राप्त होने वाली राशि को दर्शाता है। उपरोक्त को ‘ऋण’ के बजाय ‘प्राप्य’ के रूप में प्रकट करना कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III (डिवीजन III) का उल्लंघन था। इसके परिणामस्वरूप ‘प्राप्य’ को ₹2,00,692.50 करोड़ से अधिक दर्शाया गया है और ‘ऋण’ को भी उसी राशि से कम दर्शाया गया है। - प्राप्तियों में ₹20,898.72 करोड़ रुपये की राशि शामिल थी, जो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण के लिए वित्त पोषित रेलवे परियोजनाओं के लिए रेल मंत्रालय (एमओआर) से ‘पट्टा प्राप्तियों’ के रूप में दर्शाई गई राशि थी। (ईबीआर-आईएफ के लिए ₹15,161.20 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए ₹5,737.52 करोड़ रुपये)। भारतीय लेखा मानक 116 के पैरा 9 के अनुसार, ‘यदि अनुबंध किसी विचार के बदले में एक निश्चित अवधि के लिए पहचानी गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, तो अनुबंध एक पट्टा है, या इसमें पट्टा शामिल है।’ कंपनी ने रेल मंत्रालय के साथ उपरोक्त ‘पट्टा प्राप्तियों’ के लिए पट्टा समझौता किया (मार्च 2022)। हालांकि, कंपनी द्वारा प्रदान की गई धनराशि से बनाई गई विशिष्ट रेलवे संपत्ति को समझौते में दी गई परियोजनाओं की सूची से पहचाना नहीं जा सकता है। इस प्रकार, इसे भारतीय लेखा मानक 116 के पैरा 9 के अनुसार ‘पट्टा’

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, कंपनी अपने मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन के अनुसार केवल पट्टा फाइनेंस के माध्यम से रेलवे परिसंपत्तियों का वित्तपोषण कर सकती है। इस प्रकार, उपरोक्त को 'ऋण' नहीं कहा जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप पट्टा प्राप्तियों को ₹20,898.72 करोड़ से अधिक दर्शाया गया था।
3.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	विलंबित टैक्स देनदारी ₹24.52 करोड़ से कम दर्शाई गई, जो कि निवेश की खरीद मूल्य के संदर्भ में निवेश के बाजार मूल्य में परिवर्तन के कारण होने वाले कर प्रभाव पर आधारित विलंबित टैक्स देनदारी थी। इसके परिणामस्वरूप, अन्य समग्र आय से अधिक आकलन ₹24.52 करोड़ हुआ।
4.	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	ट्रेड रसीवेबल्स में ₹1,063.47 करोड़ की राशि शामिल थी, जो डिस्कॉम से जल और सुरक्षा खर्चों तथा ऊर्जा सरेंडर लागत के रूप में लंबित थी, जिसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई बिल्स में अप्रैल 2019 से दिसंबर 2020 की अवधि के लिए बिल किया गया था। ये खर्च कंपनी की आंतरिक दिशा-निर्देशों के आधार पर बिल किए गए थे, जो न तो कोयला मंत्रालय के दिशा-निर्देशों (जनवरी 2015) के अनुरूप थे, और न ही केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा मार्च 2019 में अपनी नियमावली में अनुमोदित थे। इसके अलावा, ये खर्च डिस्कॉम द्वारा न तो स्वीकार किए गए थे और न ही भुगतान किए गए थे, क्योंकि ये बिना डिस्कॉम की सहमति के बिल किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप, व्यापार प्राप्त आय एवं प्रतिधारित आय का अधिक आकलन से ₹1,063.47 करोड़ हुआ।
5.	फर्टिलाइज़र एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	प्रावधानों में ₹47.90 करोड़ की राशि सम्मिलित नहीं थी, जो कंपनी के कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए थी, जैसा कि सार्वजनिक उद्यम विभाग के 03 अगस्त, 2017 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा वेतन संशोधन की स्वीकृति और एंड एस 37 के पैरा 10 के अनुसार, कंपनी पर वेतन संशोधन के लिए एक रचनात्मक दायित्व था और इसलिए कंपनी को इसे इंड एस 37 के पैरा 14 के अनुसार वित्तीय विवरणों में प्रावधान करना चाहिए था। इसके लिए प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप वेतन संशोधन के लिए प्रावधान का कम आकलन और लाभ का ₹47.90 करोड़ से अधिक आकलन हुआ।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
6.	ओडिशा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	(क) ₹27.15 करोड़ का प्रावधान, जो ओडिशा सरकार को माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, 1957 के अंतर्गत मुआवजा भुगतान के रूप में दिसंबर 2017 और नवंबर 2018 में जमा किया गया था, नहीं बनाया गया, हालांकि इसे ओडिशा सरकार द्वारा आंशिक भुगतान के रूप में स्वीकृत किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, अन्य वर्तमान संपत्तियों का अधिक आकलन और वर्ष के घाटे का ₹27.15 करोड़ कम आकलन हुआ। यह मुद्दा 2019-20 और 2020-21 के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण के दौरान भी उठाया गया था, हालांकि कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। (ख) कंपनी ने बेलकुंडी और भद्रसाही खनन पट्टों के पूरक पट्टा दस्तावेजों के निष्पादन के लिए ₹79.48 करोड़ का स्टॉप शुल्क और पंजीकरण शुल्क का प्रावधान नहीं किया, जो फरवरी 2020 में ओडिशा सरकार द्वारा नवीनीकरण किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप, वर्तमान देनदारियों का कम आकलन ₹79.48 करोड़ से हुआ। हालांकि, कंपनी ने बागियाबुरु खदान के लिए ₹6.10 करोड़ के स्टॉप शुल्क और पंजीकरण शुल्क के लिए देनदारी का प्रावधान किया और इसके अनुरूप अमूर्त परिसंपत्तियां बनाई, लेकिन उसका ऋण परिशोधन नहीं किया। संबंधित पट्टों के जीवनकाल को ध्यान में रखते हुए, ऋण परिशोधन खर्चों का लेखांकन न करने के कारण घाटे का कम आकलन से ₹50.32 करोड़, इस वर्ष के ऋण परिशोधन खर्च का कम आकलन ₹4.13 करोड़ और अमूर्त संपत्तियां (ऋण परिशोधन खर्चों के बाद) का कम आकलन से ₹31.13 करोड़ हुआ। यह मुद्दा पिछले वर्षों में भी लेखापरीक्षा द्वारा उठाया गया था, लेकिन कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

ए.III. नकद प्रवाह विवरण पर टिप्पणियाँ

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
1.	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	कंपनी ने निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह के अंतर्गत ₹19.98 करोड़ के रूप में प्राप्त ब्याज आय का प्रकटीकरण किया, जबकि यह ₹33.07 करोड़ होनी चाहिए थी। इसके परिणामस्वरूप, निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह का कम आकलन और संचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह का अधिक आकलन से ₹13.09 करोड़ हुआ।

ए.iv. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
1.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	संभावित देनदारियाँ ₹245.89 करोड़ से कम दर्शाई गई, जो निम्नलिखित कारणों से हुई: i. प्र. सीसीए मुंबई द्वारा 24 अक्टूबर 2019 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप ₹144.66 करोड़ की मांग उठाई गई। ii. दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा लंबित संपत्ति कर के रूप में ₹101.23 करोड़ की मांग।
2.	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी ने फ्रीहोल्ड माइनिंग लैंड और माइन डेवलपमेंट कॉस्ट के संबंध में मूल्यहास / ऋण परिशोधन पर अपनी लेखा नीति में परिवर्तन किया। हालांकि, इंड एस 8 की आवश्यकताओं के अनुसार, इन परिवर्तनों के लिए आवश्यक प्रकटीकरण नहीं किए गए।
3.	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (समेकित वित्तीय विवरण)	- कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची III के अंतर्गत निम्नलिखित जानकारी का प्रकटीकरण नहीं किया: क. समेकित कुल परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में शुद्ध परिसंपत्तियों और शुद्ध परिसंपत्तियों की राशि। ख. समेकित लाभ या हानि के प्रतिशत के रूप में लाभ या हानि में हिस्सेदारी और उसकी राशि। ग. अन्य समग्र आय (ओसीआई) की राशि और समेकित ओसीआई प्रतिशत के रूप में ओसीआई का प्रतिशत। - कंपनी ने इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात का प्रकटीकरण नहीं किया और चार रेशियोज (इक्विटी पर रिटर्न अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात, नियोजित पूंजी पर रिटर्न और निवेश पर रिटर्न) के संदर्भ में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, जिनमें 25 प्रतिशत से अधिक अंतर था, जैसा कि कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय के 24 मार्च 2021 के अधिसूचना और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची III के अंतर्गत आवश्यक था।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
4.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	कंपनी ने इक्विटी पर रिटर्न, शुद्ध लाभ अनुपात, नियोजित पूंजी पर रिटर्न और निवेश पर रिटर्न 31 मार्च, 2021 और 31 मार्च, 2022 के आंकड़ों के बीच अंतर के रूप में की, जबकि इसको पिछले वर्ष के मुकाबले प्रतिशत में बदलाव के रूप में गणना करनी चाहिए थी। इसके अलावा, चूंकि पिछले वर्ष के मुकाबले तीन अनुपात (इक्विटी पर रिटर्न, शुद्ध लाभ अनुपात और नियोजित पूंजी पर रिटर्न) में बदलाव 25 प्रतिशत से अधिक था, इसलिए इसके लिए स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता थी, जो कि कंपनी द्वारा नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची III में संशोधनों के अनुपालन में कमी हुई। • संभावित देनदारी में ₹31.06 करोड़ की राशि शामिल नहीं की गई, जो एक्साइज ड्यूटी पर अंतर के रूप में ब्याज की राशि थी। • संभावित देनदारी में ₹23.63 करोड़ की राशि शामिल नहीं की गई, जो विक्री कर के लिए 2009-10 से 2013-14 तक के अंतर संबंधी दावे थे, जिन्हें 31 मार्च, 2022 तक ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था। • संभावित देनदारी ₹21.52 करोड़ से अधिक दर्शाई गई, जो मेसर्स जी एस अटवाल (इंजीनियरिंग) प्राइवेट लिमिटेड के दावे के संबंध में थी, जिसके लिए अरबिट्रेटर ने कंपनी के खिलाफ निर्णय दिया था और कंपनी द्वारा फरवरी 2022 में ₹4.69 करोड़ की राशि पार्टी को भुगतान की गई थी।

ए.व. स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
1.	आईएफसीआई लिमिटेड (समेकित वित्तीय विवरण)	वैधानिक लेखापरीक्षक ने कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 के पैरा 3 के उपधारा (xxi) पर अपनी टिप्पणियाँ नहीं दीं। लेखापरीक्षक की रिपोर्ट इस संदर्भ में अधूरी रही।

बी. असूचीबद्ध सरकारी कंपनियाँ

बी.1. लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
1.	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	उपरिभार और कोयले की निकासी का वास्तविक निकासी के मुकाबले शॉर्ट बुकिंग के लाभ को अधिक बताया और देनदारी को कम बताया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹21.39 करोड़ का अंतर हुआ।
2.	भारत संचार निगम लिमिटेड	- पेंशन के लिए योगदान (व्यय-कर्मचारी लाभ व्यय) ₹105.35 करोड़ कम दिखाया गया, क्योंकि 01 दिसंबर, 2011 से 30 सितंबर, 2014 तक अधिकतम वेतन स्केल पर पेंशन योगदान के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप घाटे का भी कम आकलन हुआ। - मूल्यहास और ऋण परिशोधन व्यय ₹1,398.40 करोड़ से कम दिखाए गए, क्योंकि कंपनी ने पट्टे की ज़मीनों का ऋण परिशोधन शामिल नहीं किया, जिन्हें उसने फ्रीहोल्ड ज़मीन के रूप में दिखाया था। इसके परिणामस्वरूप घाटे का कम आकलन और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अधिक आकलन हुआ। - अन्य व्यय ₹201.45 करोड़ कम दिखाए गए, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशंस विभाग के टीईआरएम सेल द्वारा कस्टमर एप्लिकेशन फॉर्म पेनल्टी और ईएमएफ पेनल्टी के लिए लगाए गए जुर्माने का समावेश नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप घाटे का भी उस राशि तक कम आकलन हुआ।
3.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड-23 ओवरबर्डन रिमूवल (ओबीआर) लागत निर्धारित करने और उसे उचित रूप से आवंटित करने के सिद्धांतों और विधियों को निर्दिष्ट करता है। मार्गदर्शन नोट (जे. एन. बोस समिति द्वारा ओबीआर लेखांकन पर) के अनुसार, स्ट्रिपिंग एक्टिविटी समायोजन की गणना में री-हैंडलिंग ओबीआर के लिए मात्रा और कार्य घंटों को नहीं माना जाना चाहिए। हालाँकि, इसके विपरीत, कंपनी ने राजमहल परियोजना में री-हैंडलिंग ओबीआर के लिए मात्रा और कार्य घंटों दोनों को

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		ध्यान में रखा, सोनपुर बाज़ारी ओपन कास्ट परियोजना (ओसीपी) में री-हैंडलिंग के लिए कार्य घंटों को ध्यान में रखा और मोहनपुर ओसीपी में ओवरहेड खर्चों का गलत आवंटन किया। इसके परिणामस्वरूप खर्चों (स्ट्रिपिंग एक्टिविटी समायोजन) का अधिक आकलन ₹51.73 करोड़ हुआ। इसने वर्ष के घाटे को भी समान राशि से कम किया।
4.	भारत इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	• एक संदर्भ 2020-21 के वित्तीय वर्ष के लिए संशोधित स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का है, जिसमें यह बताया गया था कि टैक्स से पहले का लाभ ₹459.15 करोड़ कम दिखाया गया था और विविध देनदारियाँ उसी राशि से अधिक दिखाई गई थीं, जो कि टर्म लोन पर मोरेटोरियम अवधि के दौरान अर्जित ब्याज आय की वापसी के कारण हुआ था। कंपनी ने 2021-22 के वित्तीय वर्ष में ₹60.46 करोड़ की राशि प्राप्त की, जो उपर्युक्त ब्याज आय में से थी, और इसे नकद आधार पर आय माना, लेकिन शेष ब्याज आय ₹398.69 करोड़ को वर्तमान वर्ष में मान्यता नहीं दी। इसने लेखांकन के प्रोद्भूत पद्धति के अनुपालन में कमी की। इसके परिणामस्वरूप, पूर्व अवधि की आय ₹60.46 करोड़ कम, ब्याज आय ₹398.69 करोड़ कम और विविध देनदारियाँ (ब्याज पूंजीकरण) खाता ₹398.69 करोड़ अधिक दिखाई गई। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए लाभ भी ₹398.69 करोड़ कम दिखाया गया। • रायबरेली इलाहाबाद हाइवे प्राइवेट लिमिटेड (आरएएचपीएल) का लोन खाता सितंबर 2016 से बकाया था और 31 मार्च 2017 को इसे एनपीए घोषित किया गया था। 31 मार्च 2022 को आरएएचपीएल से ₹49.08 करोड़ का मूलधन बकाया था, जिसके लिए ₹24.54 करोड़ का प्रावधान किया गया था। हालांकि, लोन संपत्ति की वसूली के लिए कोई ठोस प्रस्ताव उपलब्ध नहीं था, लेकिन इसे अमान्य नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप, लोन का अधिक मूल्यांकन और वित्तीय उपकरणों पर मूल्यहास का कम आकलन हुआ, जो ₹24.54 करोड़ (₹49.08 करोड़ घटा ₹24.54 करोड़) था। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए लाभ भी उसी सीमा तक अधिक दिखाया गया।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
5.	नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड	• बकाया दावों (आईबीएनआर/आईबीएनईआर सहित) में ₹40.98 करोड़ का दावा शामिल नहीं किया गया था, जो 31 मार्च, 2022 से पहले कार्यकारी कार्यालयों को सूचित किए गए थे, लेकिन वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान इसका हिसाब नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹40.98 करोड़ का कम प्रावधान हुआ। इससे किए गए दावे (निवल) और वर्ष के नुकसान को उसी राशि तक कम दिखाया गया। • एक अग्नि दावा बीमा के संदर्भ में, जो मैर्सस भिलोसा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को जारी की गई थी, संकाय/पुनर्बीमा रिकवरी ₹105.06 करोड़ की दो बार लेखा जोखा करने के कारण पुनर्बीमाकर्ता से अधिक वसूली की प्रविष्टि हुई। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के अंत में बकाया दावे (अग्नि), वर्तमान देनदारियों और वर्ष के नुकसान को ₹105.06 करोड़ कम दिखाया गया। • जो पॉलिसियां पहले ही समाप्त हो चुकी थी, उनके लिए अनुपार्जित प्रीमियम आरक्षित (निधि) का निर्माण करने के कारण प्रावधानों के अंतर्गत अनुपार्जित प्रीमियम आरक्षित (निधि) और वर्ष के नुकसान को ₹32.95 करोड़ अधिक दर्शाया गया। • क्लेम आउटस्टैंडिंग (मरीन) के अंतर्गत रिइंश्योरेंस रिकवरी की बुकिंग करते समय, कंपनी ने गलत बुकिंग पैटर्न प्रतिशत माना, जिसके कारण रिइंश्योरेंस रिकवरी में ₹16.07 करोड़ की कमी हुई। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के अंत में क्लेम आउटस्टैंडिंग (मरीन) के लिए देनदारी अधिक और साथ ही वर्तमान देनदारियों और टैक्स के बाद नुकसान में ₹16.07 करोड़ की अधिकता हो गई।
6.	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	• पहले से समाप्त हो चुकी पॉलिसियों पर अनअर्न्ड प्रीमियम रिजर्व का निर्माण करने के कारण अनअर्न्ड प्रीमियम रिजर्व ₹809.28 करोड़ से अधिक दर्ज किया गया, जबकि प्रीमियम अपूर्ण आरक्षित निधि ₹670.51 करोड़ कम दर्ज की गई, जिससे 2021-22 के वर्ष के लिए प्रावधानों और हानि का ₹138.77 करोड़ अधिक आकलन हुआ।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		- आईआरडीए विनियमों और कंपनी की अपनी नीति के विपरीत, कंपनी ने ₹95.08 करोड़ के दावों के लिए प्रावधान नहीं किया, जो 31 मार्च, 2022 से पहले संचालन कार्यालयों को सूचित किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्वों, दावों और हानि का ₹95.08 करोड़ से कम का आकलन हुआ - कंपनी की लेखांकन नीति संख्या 6 (डी) के अनुसार, शुद्ध आईबीएनआर/आईवीएनईआर को सकल आईबीएनआर/आईवीएनईआर से सकल दावे रिजर्व का प्रतिशत मानकर निर्धारित किया जाता है। हालांकि, - कंपनी ने मोटर टीपी (नॉन-पूल) व्यापार में ₹7,117.97 करोड़ का सकल आईबीएनआर/आईबीएनईआर, अभियांत्रिक प्रमाणन के अनुसार, दर्ज किया और इसे घटाव आईबीएनआर/आईबीएनईआर और शुद्ध आईबीएनआर/आईबीएनईआर में बदल दिया, जो क्रमशः ₹498.26 करोड़ और ₹6,619.71 करोड़ था, जबकि लेखांकन नीति संख्या 6 (d) के अनुसार यह ₹709.90 करोड़ और ₹6,408.07 करोड़ होना चाहिए था। - कंपनी ने फसल व्यापार में ₹32.45 करोड़ का सकल आईबीएनआर/आईबीएनईआर, अभियांत्रिक प्रमाणन के अनुसार, दर्ज किया और इसे घटाव आईबीएनआर/आईबीएनईआर और शुद्ध आईबीएनआर/आईबीएनईआर में बदल दिया, जो क्रमशः ₹1.62 करोड़ और ₹30.83 करोड़ था, जबकि लेखांकन नीति संख्या 6 (d) के अनुसार यह ₹19.94 करोड़ और ₹12.51 करोड़ होना चाहिए था। उपरोक्त के परिणामस्वरूप, वर्तमान दायित्वों, दावों (शुद्ध) और वर्ष की हानि का ₹229.96 करोड़ (₹211.64 करोड़⁴⁶ जमा ₹18.32 करोड़⁴⁷) से अधिक आकलन हुआ।

⁴⁶ ₹6,619.71 करोड़ घटा ₹6,408.07 करोड़

⁴⁷ ₹30.83 करोड़ घटा ₹12.51 करोड़

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		- लंबित दावों में ₹112.52 करोड़ को शामिल नहीं किया गया, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में रबी-2021-22 सीजन के लिए सह-बीमा हिस्सेदारी का लंबित दायित्व था, जो लेखांकन नीति संख्या 6 का उल्लंघन था। इसके परिणामस्वरूप, वर्तमान दायित्वों और वर्ष की हानि का आकलन से ₹112.52 करोड़ कम हुआ। - आंतरिक संधि और आंतरिक विकल्पी के तहत भुगतान किए गए दावों के लिए प्रावधान न करने के साथ-साथ संबंधित पुनः बीमाकर्ता कंपनियों द्वारा सूचित सह-बीमा पॉलिसियों के लिए पुनः बीमा कमीशन (₹76.69 करोड़) और दायित्व (₹35.51 करोड़) के लिए प्रावधान न करने के कारण, जो कंपनी के खाता समापन से पहले सूचना दी गई थीं, अपने लेखांकन नीति संख्या 6 के उल्लंघन में, इसके परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्वों और वर्ष की हानि का आकलन ₹112.20 करोड़ से कम हुआ। - यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने (फरवरी 2022 में) 31 दिसंबर, 2021 तक कंपनी के सह-बीमा हिस्से के लिए ₹28.90 करोड़ का दायित्व सूचित किया। इसमें से कंपनी ने ₹9.44 करोड़ का भुगतान किया, लेकिन शेष ₹19.46 करोड़ का दायित्व नहीं दर्ज किया। इसके परिणामस्वरूप, वर्तमान दायित्वों, विविध राजस्व खाते के तहत दावों और वर्ष की हानि का आकलन ₹19.46 करोड़ से कम हुआ।
7.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण)	केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के कर्मचारियों को देय जोखिम और कठिनाई भत्ते के लिए प्रावधान न करने तथा देर से भुगतान पर ब्याज की गणना न करने के कारण अन्य खर्चों और अन्य वित्तीय दायित्वों में ₹48.87 करोड़ कम तथा लाभ को उतना ही ज्यादा बताया गया।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
8.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	- अन्य आय में ₹64.15 करोड़ की राशि शामिल थी, जो मैसर्स जाइफर-वीईपीएल-केसीएल (जेवी) से कंपनी द्वारा अनुबंध समाप्ति पर लगाए गए जुर्माने के कारण प्राप्त की जानी थी। अनुबंध समाप्ति का नोटिस कंपनी द्वारा अगस्त 2021 में जारी किया गया था, जिसके खिलाफ ठेकेदार ने 03 सितंबर, 2021 को माननीय बिलासपुर उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी। मामला अभी भी लंबित है। मामले के न्यायालय में होने के बावजूद, कंपनी ने इस राशि को "अन्य आय" के रूप में दर्ज किया। इसके परिणामस्वरूप अन्य आय और लाभ का ₹64.15 करोड़ से अधिक आंकलन हुआ। - मूल्यहास/ शमन/ हानि में ₹50.76 करोड़ का अतिरिक्त मूल्यहास प्रावधान शामिल था, जो 240 टन डंपरों के उपयोगी जीवन को सात साल के बजाय 15 साल मानने के कारण हुआ। इसके परिणामस्वरूप गैर-चालू संपत्तियों और लाभ का ₹50.76 करोड़ से कम आंकलन हुआ।
9.	टुस्को लिमिटेड	वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बेसिक कमाई प्रति शेयर (ईपीएस) और तनुकृत कमाई प्रति शेयर (ईपीएस) ₹(-) 89.89 थे, जबकि इन्हें गलत तरीके से क्रमशः ₹(-)89.91 और ₹(-)84.55 के रूप में प्रदर्शित किया गया था।

बी.ii. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
1.	बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2019-20 से करों और शुल्कों की प्रतिपूर्ति को मौद्रिक अनुदान के रूप में मानने के लिए लेखांकन नीति में बदलाव, मूल समझौता ज्ञापन की शर्तों का उल्लंघन था। इसके परिणामस्वरूप दायित्वों और पूंजीगत कार्य में प्रगति का ₹507.17 करोड़ से अधिक आंकलन हुआ।
2.	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	कंपनी के गैर-कार्यकारी कर्मचारियों की वेतन और मजदूरी राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते (एनसीडब्लूए) के अंतिम रूप देने के बाद हर पाँच साल में तय की जाती है। वेतन संशोधन 01 जुलाई, 2021 से एनसीडब्लूए-XI के

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी																
		अनुसार होना था। कंपनी ने खाता पुस्तकों में अपेक्षित वेतन संशोधन के लिए प्रावधान किया था। अपेक्षित वेतन संशोधन के लिए प्रावधान किए जाने के बावजूद, बीमांकिक ने बिना 01 जुलाई, 2021 से अपेक्षित वेतन संशोधन को ध्यान में रखे पिछले वर्ष 2020-21 में जो मान्यताएँ अपनाई थीं, उन्हीं के आधार पर दायित्व का आकलन किया। इसके परिणामस्वरूप सेवानिवृत्ति लाभों और वर्ष के लाभ के संदर्भ में प्रावधानों का गलत चित्रण हुआ (राशि का आंकलन नहीं किया गया)।																
3.	भारत संचार निगम लिमिटेड	• व्यापारिक प्राप्तियाँ ₹738.69 करोड़ की राशि से अधिक दर्शाई गईं और नुकसान कम दर्शाया गया, क्योंकि निम्नलिखित के लिए प्रावधान नहीं किया गया: (₹ करोड़ में) <table><tr><th>विवरण</th><th>राशि</th></tr><tr><td>तीन वर्षों से अधिक समय से लंबित लीज़ सर्किट्स के अंतर्गत पुरानी प्राप्तियाँ</td><td>131.05</td></tr><tr><td>तीन वर्षों से अधिक समय से लंबित इंटरकनेक्ट उपयोग शुल्क के अंतर्गत पुरानी प्राप्तियाँ</td><td>607.64</td></tr><tr><td>कुल</td><td>738.69</td></tr></table> • संपत्ति, संयंत्र और उपकरण ₹2,046.98 करोड़ की राशि से अधिक दर्शाए गए हैं, क्योंकि निम्नलिखित को शामिल किया गया है: (₹ करोड़ में) <table><tr><th>विवरण</th><th>राशि</th></tr><tr><td>बेचने के लिए रखी गई परिसंपत्तियाँ। इसके परिणामस्वरूप 'बेचने के लिए रखी गई परिसंपत्तियाँ' का आंकलन उसी राशि से कम हुआ है।</td><td>2,046.57</td></tr><tr><td>परिसंपत्तियाँ जो भूमि और विकास कार्यालय, दूरसंचार विभाग और भारत सरकार द्वारा हस्तांतरित/स्वीकार की गईं। इसके परिणामस्वरूप नुकसान का आंकलन उसी राशि से कम हुआ है।</td><td>0.41</td></tr><tr><td>कुल</td><td>2,046.98</td></tr></table>	विवरण	राशि	तीन वर्षों से अधिक समय से लंबित लीज़ सर्किट्स के अंतर्गत पुरानी प्राप्तियाँ	131.05	तीन वर्षों से अधिक समय से लंबित इंटरकनेक्ट उपयोग शुल्क के अंतर्गत पुरानी प्राप्तियाँ	607.64	कुल	738.69	विवरण	राशि	बेचने के लिए रखी गई परिसंपत्तियाँ। इसके परिणामस्वरूप 'बेचने के लिए रखी गई परिसंपत्तियाँ' का आंकलन उसी राशि से कम हुआ है।	2,046.57	परिसंपत्तियाँ जो भूमि और विकास कार्यालय, दूरसंचार विभाग और भारत सरकार द्वारा हस्तांतरित/स्वीकार की गईं। इसके परिणामस्वरूप नुकसान का आंकलन उसी राशि से कम हुआ है।	0.41	कुल	2,046.98
विवरण	राशि																	
तीन वर्षों से अधिक समय से लंबित लीज़ सर्किट्स के अंतर्गत पुरानी प्राप्तियाँ	131.05																	
तीन वर्षों से अधिक समय से लंबित इंटरकनेक्ट उपयोग शुल्क के अंतर्गत पुरानी प्राप्तियाँ	607.64																	
कुल	738.69																	
विवरण	राशि																	
बेचने के लिए रखी गई परिसंपत्तियाँ। इसके परिणामस्वरूप 'बेचने के लिए रखी गई परिसंपत्तियाँ' का आंकलन उसी राशि से कम हुआ है।	2,046.57																	
परिसंपत्तियाँ जो भूमि और विकास कार्यालय, दूरसंचार विभाग और भारत सरकार द्वारा हस्तांतरित/स्वीकार की गईं। इसके परिणामस्वरूप नुकसान का आंकलन उसी राशि से कम हुआ है।	0.41																	
कुल	2,046.98																	

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी										
		- व्यापारिक प्राप्तियाँ ₹183.82 करोड़ से अधिक दर्शाई गई, क्योंकि निम्नलिखित सेवाओं के दावों को शामिल किया गया था: टेलीफोन, ब्रॉडबैंड, प्राइवेट डेटा नेटवर्क और कोर नेटवर्क टीएक्स-उत्तर सर्किल के संबंध में विलंब शुल्क जिनकी प्राप्ति की संभावना बहुत कम है। ये दावे पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं। इसके परिणामस्वरूप हानि का आंकलन उसी राशि तक कम हुआ है। - अन्य प्राप्तियाँ (अन्य वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ) ₹97.94 करोड़ से अधिक दर्शाई गई, क्योंकि दूरसंचार विभाग से यूएसओएफ-एलडब्ल्यूई परियोजनाओं के अंतर्गत अधिक राशि प्राप्ति योग्य दिखाई गई। इसके परिणामस्वरूप नुकसान का आंकलन उसी राशि से कम हुआ है। - अन्य वर्तमान दायित्व और नुकसान ₹11.44 करोड़ तक कम दर्शाए गए, क्योंकि निम्नलिखित के लिए प्रावधान नहीं किया गया: (₹ में करोड़) <table><tr><th>विवरण</th><th>राशि</th></tr><tr><td>बकाया अविवादित वैधानिक देयताओं पर ब्याज/जुर्माना</td><td>2.64</td></tr><tr><td>मैसर्स टीसीआईएल और मेसर्स क्वाडजेन को 01.10.2021 से 31.03.2022 तक वाई-फाई हॉटस्पॉट्स की रख-रखाव के लिए देय वार्षिक रख-रखाव प्रभार शुल्क का दायित्व</td><td>3.42</td></tr><tr><td>मेसर्स स्टरलाइट और मेसर्स विंध्य टेलीलिंक्स लिमिटेड को एनएफएस ओएफसी लिंक की रख-रखाव के लिए देय एएमसी शुल्क का दायित्व</td><td>5.38</td></tr><tr><td>कुल</td><td>11.44</td></tr></table>	विवरण	राशि	बकाया अविवादित वैधानिक देयताओं पर ब्याज/जुर्माना	2.64	मैसर्स टीसीआईएल और मेसर्स क्वाडजेन को 01.10.2021 से 31.03.2022 तक वाई-फाई हॉटस्पॉट्स की रख-रखाव के लिए देय वार्षिक रख-रखाव प्रभार शुल्क का दायित्व	3.42	मेसर्स स्टरलाइट और मेसर्स विंध्य टेलीलिंक्स लिमिटेड को एनएफएस ओएफसी लिंक की रख-रखाव के लिए देय एएमसी शुल्क का दायित्व	5.38	कुल	11.44
विवरण	राशि											
बकाया अविवादित वैधानिक देयताओं पर ब्याज/जुर्माना	2.64											
मैसर्स टीसीआईएल और मेसर्स क्वाडजेन को 01.10.2021 से 31.03.2022 तक वाई-फाई हॉटस्पॉट्स की रख-रखाव के लिए देय वार्षिक रख-रखाव प्रभार शुल्क का दायित्व	3.42											
मेसर्स स्टरलाइट और मेसर्स विंध्य टेलीलिंक्स लिमिटेड को एनएफएस ओएफसी लिंक की रख-रखाव के लिए देय एएमसी शुल्क का दायित्व	5.38											
कुल	11.44											

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
4.	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	- अन्य वर्तमान दायित्वों में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जेएसपीसीबी) द्वारा कंपनी की पाँच खदानों के संबंध में लगाए गए पर्यावरणीय मुआवजे के लिए प्रावधान शामिल नहीं किया गया। जेएसपीसीबी ने ₹32.45 करोड़ का मुआवजा लगाया, जिसमें से कंपनी ने एक खदान के लिए ₹1.35 करोड़ का भुगतान किया। शेष ₹31.10 करोड़ का भुगतान न करने के बावजूद, खाता पुस्तकों में कोई प्रावधान नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप अन्य वर्तमान दायित्वों का आंकलन कम और लाभ का आंकलन ₹31.10 करोड़ से अधिक हुआ। - राष्ट्रीय कोयला वेतन करार (एनसीडब्ल्यू) को अंतिम रूप दिए जाने के बाद प्रत्येक पाँच वर्ष में कंपनी के गैर-कार्यपालकों के वेतन और मजदूरी को अंतिम रूप दिया जाता है। एनसीडब्ल्यू-xi के अनुसार वेतन संशोधन 01 जुलाई, 2021 से होना था। कंपनी ने लेखा बहियों में अपेक्षित वेतन संशोधन का प्रावधान किया। अपेक्षित वेतन संशोधन के लिए प्रावधान करने के बावजूद, एक्चुअरी ने उसी धारणा के साथ देयता का आकलन किया, जिस पर पिछले वर्ष 2020-21 में 01 जुलाई, 2021 से अपेक्षित वेतन संशोधन पर विचार किए बिना विचार किया गया था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों और लाभ (राशि की मात्रा निर्धारित नहीं की गई) के संबंध में प्रावधानों का दोषपूर्ण चित्रण हुआ।
5.	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड	कंपनी के गैर-कार्यकारी कर्मचारियों की वेतन और मजदूरी प्रत्येक पाँच वर्षों में राष्ट्रीय कोल वेतन समझौते (एनसीडब्ल्यू) के अंतिम रूप दिए जाने के बाद तय की जाती है। वेतन संशोधन 01 जुलाई, 2021 से एनसीडब्ल्यू-XI के अनुसार होना था। कंपनी ने खाता पुस्तकों में अपेक्षित वेतन संशोधन के लिए प्रावधान किया था। अपेक्षित वेतन संशोधन के लिए प्रावधान किए जाने के बावजूद, बीमांकिक ने पिछले वर्ष 2020-21 में जो मान्यताएँ अपनाई थीं, उन्हीं के आधार पर दायित्व का आकलन किया, बिना 01 जुलाई, 2021 से अपेक्षित वेतन संशोधन को ध्यान में रखे। इसके

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		परिणामस्वरूप सेवानिवृत्ति लाभों और वर्ष के लाभ के संदर्भ में प्रावधानों का गलत चित्रण हुआ (राशि का आंकलन नहीं किया गया)।
6.	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	कंपनी ने रेलवे मंत्रालय के साथ एक अनुदान समझौता किया है, ताकि एक परियोजना को लागू किया जा सके और नए रेलवे गलियारे को 30 वर्षों की अवधि के लिए संचालित और बनाए रखा जा सके। समझौते के अनुसार, रेलवे मंत्रालय नेटवर्क का उपयोग करेगा और कंपनी को ट्रेक एक्सेस शुल्क अदा करेगा। इंड एस 115 के पैराग्राफ 11 के अनुसार, सेवा अनुदान समझौते के अंतर्गत निर्मित अवसंरचना को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती। हालांकि, कंपनी ने अनुदान समझौते के अंतर्गत निर्मित अवसंरचना को 'संपत्ति, संयंत्र और उपकरण/पूंजीगत कार्य में प्रगति' के रूप में मान्यता दी, जो इंड एस 115 का उल्लंघन है। इसके परिणामस्वरूप 'संपत्ति, संयंत्र और उपकरण' और 'पूंजीगत कार्य में प्रगति' का क्रमशः ₹22,759.57 करोड़ और ₹41,676.68 करोड़ से अधिक आंकलन हुआ और 'अमूर्त परिसंपत्तियाँ/वित्तीय परिसंपत्तियाँ (विकासशील)' का आंकलन ₹64,436.25 करोड़ से कम हुआ। यह मुद्दा 2020-21 के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के दौरान भी उठाया गया था, लेकिन कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।
7.	डीएमई डेवलपमेंट लिमिटेड (2020-21)	दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के संबंध में पूंजीगत कार्य में प्रगति- अमूर्त परिसंपत्तियाँ ₹9,890.74 करोड़ की राशि से अधिक दर्शाई गईं। चूंकि कंपनी को उपयोगकर्ताओं से टोल शुल्क लेने का अधिकार नहीं है और वह केवल राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से आवधिक वार्षिकी भुगतान प्राप्त करेगी, इंड एस 115 और इंड एस 38 के प्रावधानों के अनुसार, खर्च को पूंजीगत कार्य में प्रगति-अमूर्त संपत्तियाँ के रूप में श्रेणीबद्ध करना अनुचित है। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय परिसंपत्तियों का आंकलन ₹9,890.74 करोड़ से कम हुआ।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
8.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	- व्यापारिक प्राप्तियाँ ₹132.30 करोड़ की राशि को शामिल करती हैं, जो एनटीपीसी लिमिटेड से 2017 से 2020 के बीच 0-3 किलोमीटर की दूरी के लिए कोयले की आपूर्ति पर सतही परिवहन शुल्क (एसटीसी) के रूप में प्राप्त की जानी थी। चूंकि कोयले की आपूर्ति के लिए 0-3 किलोमीटर की दूरी पर एसटीसी लगाने के लिए कोई समझौता नहीं है, ₹132.30 करोड़ की प्राप्ति की संभावना बहुत कम है और उपयुक्त प्रावधान बनाना चाहिए था। प्रावधान न बनाने के कारण व्यापारिक प्राप्तियाँ (खराब और संदिग्ध ऋण के लिए अलाउंस सहित) का आंकलन अधिक और हानि का आंकलन कम हुआ। यह मुद्दा 2020-21 के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के दौरान भी उठाया गया था, लेकिन कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। - कंपनी के गैर-कार्यकारी कर्मचारियों की वेतन और मजदूरी राष्ट्रीय कोल वेतन समझौते (एनसीडब्लूए) के अंतिम रूप दिए जाने के बाद हर पाँच साल में तय की जाती है। वेतन संशोधन 01 जुलाई, 2021 से एनसीडब्लूए-XI के अनुसार होना था। कंपनी ने खाता पुस्तकों में अपेक्षित वेतन संशोधन के लिए प्रावधान किया था। अपेक्षित वेतन संशोधन के लिए प्रावधान किए जाने के बावजूद, बीमांकिक ने पिछले वर्ष 2020-21 में जो मान्यताएँ अपनाई थीं, उन्हीं के आधार पर दायित्व का आकलन किया, बिना 01 जुलाई, 2021 से अपेक्षित वेतन संशोधन को ध्यान में रखे। इसके परिणामस्वरूप सेवानिवृत्ति लाभों और वर्ष के लाभ के संदर्भ में प्रावधानों का गलत चित्रण हुआ (राशि का आंकलन नहीं किया गया)।
9.	कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	पूँजीगत कार्य में प्रगति - प्रारंभिक व्यय में ₹219.46 करोड़ की कमी शामिल की गई, जो कि वर्ष के विनिमय अंतराल लाभ के कारण हुई और इसे पूँजीगत कार्य में प्रगति के अंतर्गत प्रारंभिक व्यय के रूप में पूँजीकृत किया गया। विनिमय अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता नहीं देने के कारण इंड एस-21 का पालन नहीं हुआ।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में ₹160.91 करोड़ की राशि शामिल थी, जो पश्चिम बंगाल सरकार से एसजीएसटी के रूप में प्राप्त की जानी थी, जो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दावा की प्रक्रिया के लिए लंबित था, जैसा कि 2008 में साइन किए गए समझौते (एमओयू) के धारा 10.4 के अनुसार था। चूंकि पश्चिम बंगाल सरकार 2012 में परियोजना से बाहर निकल गई और इसके बाद इस संबंध में कोई नया/संशोधित एमओयू साइन नहीं किया गया, एसजीएसटी के पुनर्भरण में अनिश्चितता थी। इसलिए, उपरोक्त राशि को अन्य वित्तीय संपत्तियों के रूप में दिखाना और सीडब्ल्यूआईपी के रूप में नहीं दिखाना, यह सही नहीं था। इसके परिणामस्वरूप अन्य वित्तीय संपत्तियों का आंकलन ₹160.91 करोड़ से अधिक हुआ और सीडब्ल्यूआईपी का आंकलन उसी राशि तक कम हुआ। - पूंजीगत कार्य में प्रगति - प्रारंभिक व्यय - व्यय में ₹89.47 करोड़ की राशि शामिल थी, जो विनिमय अंतर लागत थी, जिसे वित्तीय विवरणों में उधारी लागत के रूप में वर्गीकृत किया गया था, बजाय कि विनिमय अंतर लागत के। इसके परिणामस्वरूप उधारी लागत का आंकलन अधिक और विनिमय अंतर लागत का आंकलन ₹89.47 करोड़ कम हुआ। - पूंजीगत कार्य में प्रगति में ₹10.11 करोड़ की राशि शामिल नहीं की गई, जो मार्च 2022 महीने के अंतर्गत भूमिगत सुरंग निर्माण कार्यों का व्यय था, जिसे ठेकेदार ने रिपोर्टिंग तिथि के बाद, लेकिन वित्तीय विवरणों के तैयार होने से पहले दावा किया था। इसके परिणामस्वरूप पूंजीगत कार्य में प्रगति और ठेकेदार दायित्व का आंकलन ₹10.11 करोड़ से कम हुआ।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
10.	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	कंपनी के गैर-कार्यकारी कर्मचारियों की वेतन और मजदूरी राष्ट्रीय कोल वेतन समझौते (एनसीडब्ल्यू) के अंतिम रूप दिए जाने के बाद हर पाँच साल में तय की जाती है। वेतन संशोधन 01 जुलाई, 2021 से एनसीडब्ल्यू-XI के अनुसार होना था। कंपनी ने खाता पुस्तकों में अपेक्षित वेतन संशोधन के लिए प्रावधान किया था। अपेक्षित वेतन संशोधन के लिए प्रावधान किए जाने के बावजूद, अभियांत्रिक ने पिछले वर्ष 2020-21 में जो मान्यताएँ अपनाई थीं, उन्हीं के आधार पर दायित्व का आकलन किया, बिना 01 जुलाई, 2021 से अपेक्षित वेतन संशोधन को ध्यान में रखे। इसके परिणामस्वरूप सेवानिवृत्ति लाभों और वर्ष के लाभ के संदर्भ में प्रावधानों का गलत चित्रण हुआ (राशि का आंकलन नहीं किया गया)।
11.	नबीनगर ऊर्जा जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड	वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान कंपनी द्वारा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को भुगतान किए गए ₹85.35 करोड़ के ट्रांसमिशन शुल्क को निर्धारित समय के भीतर परियोजना पूरी न होने के कारण पूंजी -कार्य प्रगति पर के रूप में बुक किया गया था। चूँकि कंपनी निर्धारित समय के भीतर अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर सकी, इसलिए इन ट्रांसमिशन शुल्कों को पूंजीगत कार्य-प्रगति के रूप में मानने के बजाय सीधे लाभ और हानि के विवरण पर लगाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप पूंजीगत कार्य-प्रगति और लाभ को ₹85.35 करोड़ से अधिक बताया गया है।
12.	नेशनल हाईवे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (2020-21)	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों में पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा किए बिना, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ किए गए पांच रियायत समझौतों के संदर्भ में कंपनी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले टोल संग्रह अधिकारों से संबंधित ₹7,350.40 करोड़ की राशि शामिल है। चूँकि पूर्ववर्ती शर्तें पूरी नहीं की गईं, इसलिए इसकी बुकिंग के परिणामस्वरूप अमूर्त परिसंपत्ति और अन्य वित्तीय देनदारी को अधिक बताया गया।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
13.	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	- व्यापार प्राप्तियों में एनटीपीसी लिमिटेड से सितंबर 2017 से अगस्त 2020 की अवधि के लिए 0-3 किमी की लीड दूरी के लिए कोयले की आपूर्ति के लिए भूतल परिवहन शुल्क (एसटीसी) के कारण प्राप्त होने वाली ₹221.79 करोड़ की राशि शामिल थी। 0-3 किमी की लीड दूरी के लिए कोयले की आपूर्ति के लिए एसटीसी चार्ज करने के लिए किसी भी समझौते के अभाव में, ₹221.79 करोड़ की वसूली की संभावना बहुत कम है और उपयुक्त प्रावधान बनाया जाना चाहिए था। इस प्रकार, प्रावधानों का बनाने न करने के परिणामस्वरूप उस सीमा तक व्यापार प्राप्तियों (खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए भते का शुद्ध) और वर्ष के लिए लाभ को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया। वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट भी उस सीमा तक अपर्याप्त है। यह मुद्दा 2020-21 के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के दौरान भी उठाया गया था। हालांकि, कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। - अम्लोहरी कोल हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी) की उपयोगी आयु 7.5 वर्ष के बजाय 15 वर्ष मानी जाने के कारण संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को ₹118.81 करोड़ तक अधिक मूल्यांकन किया गया और मूल्यहास कम दर्शाया गया। इसके परिणामस्वरूप लाभ भी इसी सीमा तक बढ़ा हुआ दिखाया गया। - कंपनी के गैर-कार्यकारी कर्मचारियों का वेतन और मजदूरी हर पांच वर्ष में नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट (एनसीडब्ल्यू) के अंतिमकरण के बाद तय किए जाते हैं। एनसीडब्ल्यू-XI के अनुसार, वेतन पुनरीक्षण 01 जुलाई 2021 से लंबित था। कंपनी ने खातों में अपेक्षित वेतन पुनरीक्षण का प्रावधान किया। हालांकि, अनुमानकर्ता ने 2020-21 में किए गए पूर्वानुमान के आधार पर देयता का आकलन किया, जिसमें 01 जुलाई 2021 से अपेक्षित वेतन पुनरीक्षण को शामिल नहीं किया गया। इससे सेवानिवृत्ति लाभों और वर्ष के मुनाफे के प्रावधानों में गलत चित्रण हुआ (राशि का माप नहीं किया गया)।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
14.	एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण पर भी टिप्पणी जारी की गई)	नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएसआईसी) द्वारा 100 प्रतिशत इक्विटी के साथ एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड का गठन 28 अगस्त 2020 को आत्मनिर्भर भारत फंड (एसआरआई फंड) के प्रवर्तक के रूप में किया गया। भारत सरकार ने कंपनी को एसआरआई फंड में योगदान के लिए ₹180.34 करोड़ (₹155.34 करोड़ 31 मार्च 2022 तक और ₹25 करोड़ 2 अप्रैल 2022 को) जारी किए। एनएसआईसी, एसआरआई फंड के प्रायोजक के रूप में, ने भी वर्ष के दौरान ₹0.02 करोड़ का योगदान किया। कंपनी ने भारत सरकार और एनएसआईसी द्वारा किए गए योगदान के लिए उन्हें यूनिट्स जारी किए। एसआरआई फंड के लिए कंपनी एक अलग बैंक खाता बनाए हुए है। इसके अलावा, अन्य लेन-देन के लिए एक और बैंक खाता रखा जा रहा है जिसमें 31 मार्च 2022 तक ₹3.28 करोड़ शेष था। वित्तीय स्थिति विवरण में नकद और नकद समकक्ष को प्रकट करते समय, दोनों खातों के बैंक शेष को दिखाया जाना चाहिए था, जबकि कंपनी ने भारत सरकार/एनएसआईसी से प्राप्त फंड को कुल बैंक बैलेंस से समायोजित कर दिया और एसआरआई फंड के अलावा अन्य लेन-देन के बैंक खाते का शेष ही दिखाया। भारत सरकार और एनएसआईसी द्वारा जारी फंड का गलत समायोजन होने से बैंक बैलेंस ₹152.34 करोड़⁴⁸, पारगमन में प्रेषण ₹25 करोड़ और देनदारियां - एसआरआई फंड के लिए यूनिट कैपिटल ₹177.34 करोड़ से कम दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप, फाइनेंसिंग गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकदी और नकद प्रवाह विवरण में नकद और नकद समकक्ष में ₹152.34 करोड़ की कमी आई है।
15.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	व्यापार प्राप्तियों में ₹63.33 करोड़ की राशि भी शामिल है, जो एनटीपीसी लिमिटेड से सितंबर 2017 से जुलाई 2020 की अवधि के लिए सतह परिवहन शुल्क (एसटीसी) के अंतर्गत 0-3 किमी की दूरी पर कोयला आपूर्ति के लिए प्राप्त की जानी है। 0-3 किमी की दूरी पर कोयला आपूर्ति

⁴⁸ एसआरआई फंड के संबंध में किए गए व्यय में कटौती के बाद।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
		के लिए एसटीसी शुल्क लगाने के संबंध में कोई समझौता नहीं होने के कारण, ₹63.33 करोड़ की वसूली की संभावना बहुत कम है, और इसके लिए उपयुक्त प्रावधान बनाया जाना चाहिए था। प्रावधान न बनाने के कारण, व्यापार प्राप्तियों (खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए भत्तों के शुद्ध) और वर्ष के मुनाफे को इसी सीमा तक बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया गया है। वैधानिक लेखापरीक्षारों की रिपोर्ट भी इसी सीमा तक अधूरी है। कंपनी के 2020-21 के वित्तीय विवरण में भी इस मुद्दे पर टिप्पणी की गई थी। हालांकि, कुल ₹117.89 करोड़ की प्राप्य राशि के विरुद्ध, एसईसीएल ने केवल ₹54.56 करोड़ का ही प्रावधान बनाया, जिससे अपर्याप्त प्रावधान की स्थिति बनी। • कंपनी के गैर-कार्यकारी कर्मचारियों का वेतन और मजदूरी हर पांच वर्ष में नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट (एनसीडब्ल्यू) के अंतिमकरण के बाद तय किए जाते हैं। एनसीडब्ल्यू-XI के अनुसार, वेतन पुनरीक्षण 01 जुलाई 2021 से लंबित था। कंपनी ने खातों में अपेक्षित वेतन पुनरीक्षण का प्रावधान किया। हालांकि, अनुमानकर्ता ने 2020-21 में किए गए पूर्वानुमान के आधार पर देयता का आकलन किया, जिसमें 01 जुलाई 2021 से अपेक्षित वेतन पुनरीक्षण को शामिल नहीं किया गया। इससे सेवानिवृत्ति लाभों और वर्ष के मुनाफे के प्रावधानों में गलत चित्रण हुआ (राशि का माप नहीं किया गया)।
16.	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	₹19.53 करोड़ की देयता को अग्रिम राशि के रूप में मान्यता न देने के कारण, अन्य चालू देनदारियों और पूंजीगत कार्य-प्रगति ₹19.53 करोड़ से कम दर्शाई गई। यह राशि कंपनी को कोयला मंत्रालय से खदान खोलने की अनुमति मिलने की तारीख, 15 फरवरी 2022, से 15 कार्य दिवसों के भीतर जमा करनी थी।
17.	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	उन नीतियों पर अर्जित प्रीमियम आरक्षित (निधि) का निर्माण, जो पहले ही समाप्त हो चुकी थीं, ने प्रावधानों के अंतर्गत अर्जित प्रीमियम आरक्षित (निधि) और वर्ष की हानि को ₹80.52 करोड़ तक अधिक दिखाया।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
18.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	कंपनी के गैर-कार्यकारी कर्मचारियों का वेतन और मजदूरी हर पांच वर्ष में नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट (एनसीडब्लूए) के अंतिमकरण के बाद तय किए जाते हैं। एनसीडब्लूए-XI के अनुसार, वेतन पुनरीक्षण 01 जुलाई 2021 से लंबित था। कंपनी ने खातों में प्रस्तावित वेतन पुनरीक्षण का प्रावधान किया। हालांकि, अनुमानकर्ता ने 2020-21 में किए गए पूर्वानुमान के आधार पर देयता का आकलन किया, जिसमें 01 जुलाई 2021 से अपेक्षित वेतन पुनरीक्षण को शामिल नहीं किया गया। इससे सेवानिवृत्ति लाभों और वर्ष के मुनाफे के प्रावधानों में गलत चित्रण हुआ (राशि का माप नहीं किया गया)।

बी.iii. नकदी प्रवाह विवरण पर टिप्पणी

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
1.	भारत संचार निगम लिमिटेड	गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ और दायित्व में बदलाव को कार्यशील पूंजी परिवर्तन की गणना में शामिल करना, जबकि इसे निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए था, यह इंड एस-7 प्रावधानों के अनुरूप नहीं था।
2.	एनआरटीयू फाउंडेशन	सावधि जमा में ₹6.12 करोड़ की वृद्धि को 'परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह' के अंतर्गत दिखाया गया है, जबकि इसे 'निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह' के अंतर्गत दिखाया जाना चाहिए था, जो कि एस - 3 (नकद प्रवाह विवरण) के पैरा 5.5 का उल्लंघन है।

बी.िव. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ:

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
1.	भारत संचार निगम लिमिटेड	- संभावित देनदारियों को ₹600 करोड़ की राशि से कम दर्शाया गया, क्योंकि कंपनी द्वारा अग्रिम खरीद आदेश वापसी के कारण मैसर्स विहान नेटवर्क्स लिमिटेड द्वारा भेजे गए वैधानिक नोटिस के रूप में माँग को शामिल नहीं किया गया। - बिक्री के लिए रखे गए परिसंपत्तियों में टेलीकॉम फैक्ट्री गोपालपुर (पश्चिम बंगाल) को शामिल किया गया, जिसका मूल्य ₹223.86 करोड़ था, जो अवैध रूप से अतिक्रमण में था और बिक्री के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं था। इस तथ्य को न तो कंपनी ने खातों की टिप्पणियों में उजागर किया, न ही वैधानिक लेखापरीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया।
2.	एफएसीटी आरसीएफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड	- कंपनियों के अधिनियम, 2013 के अनुसूची III के प्रावधानों के विपरीत, कंपनी ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों और सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा संबंधित 'व्यापारिक देनदारियाँ' का खुलासा नहीं किया। 'प्रावधान न की गई संभावित देनदारियाँ' को ₹20.06 करोड़ की राशि से कम दिखाया गया, जो आयकर विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए उठाई गई माँग थी। कंपनी ने इस माँग के खिलाफ अपील की है, जो लंबित है। - भारत सरकार ने 16 नवंबर, 2018 को फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीटी) को कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी में ₹29.25 करोड़ की अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। इस मंजूरी के अंतर्गत, कंपनी ने 2010 से 2013 के बीच एफएसीटी द्वारा आपूर्ति किए गए जिप्सम और अन्य सेवाओं के बदले ₹15.18 करोड़ के इक्विटी शेयर जारी किए। ₹11.68 करोड़ के इक्विटी शेयर, जिनके बदले 2014 से 2020 तक एफएसीटी द्वारा प्रदान की गई जिप्सम/अन्य सेवाएँ हैं, अभी तक कंपनी द्वारा आवंटित नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त, एफएसीटी द्वारा ₹2.39 करोड़ के जिप्सम की आपूर्ति अभी भी अतिरिक्त निवेश को पूरा करने के लिए लंबित थी। ये महत्वपूर्ण तथ्य वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में उजागर नहीं किए गए थे।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
3.	नेशनल हाई स्पीड रेलवे कंपनी लिमिटेड	कंपनी के पास सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना और पेंशन योजना के लिए नीति है। हालांकि, कंपनी ने सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना को परिभाषित नहीं किया है और इस पर लेखांकन नीति भी तैयार नहीं की है, जो इंड एस 19 के पैरा 135 का उल्लंघन है। नोट 2.13 (सी) (I) भी इस सीमा तक अधूरा है कि परिभाषित योगदान योजना के अंतर्गत पेंशन योजना के बारे में खुलासा नहीं किया गया है।
4.	नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज़ इंक	पूँजीगत प्रतिबद्धताएँ ₹23.16 करोड़ की राशि से कम दिखाई गईं क्योंकि शास्त्री पार्क, दिल्ली में मिनी डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए बढ़ी हुई लागत को शामिल नहीं किया गया था।
5.	ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	कंपनी ने भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं के संदर्भ में प्रीमियम आय 2020-21 तक खातों के अंतिमकरण तक प्राप्त रिटर्न के आधार पर मान्यता दी। कंपनी ने 2021-22 में अपनी लेखांकन नीति में बदलाव किया और संशोधित नीति के अनुसार, भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं के संदर्भ में प्रीमियम आय को अगले वित्तीय वर्ष के 30 अप्रैल तक प्राप्त रिटर्न के आधार पर मान्यता दी जाती है। कंपनी ने लेखांकन नीति में इस बदलाव के प्रभाव, यानी ₹90.10 करोड़ से प्रीमियम में कमी, को वित्तीय विवरणों में प्रकट नहीं किया, जैसा कि लेखांकन मानक -1 के पैरा संख्या 22 और पैरा 26 के अंतर्गत आवश्यक था।
6.	पंजाब लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	नोट 24 में यह उल्लेख किया गया है कि कंपनी ने उत्तरी रेलवे से वार्षिक लाइसेंस शुल्क के आधार पर 12,056.46 वर्ग मीटर भूमि प्राप्त की है। कंपनी ने उपरोक्त को इंड एस 116 के पैरा 6 के अंतर्गत शॉर्ट-टर्म पट्टा के रूप में दर्ज किया है। हालांकि, कंपनी ने इंड एस 116 के पैरा 60 के अनुसार इस तथ्य का खुलासा नहीं किया, जैसा कि आवश्यक था।
7.	रेलटेल एंटरप्राइजेज लिमिटेड	कंपनी ने चार अनुपातों (इक्विटी पर रिटर्न अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात, नियोजित पूँजी पर रिटर्न और निवेश पर रिटर्न) के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया, जहां विचलन 25 प्रतिशत से अधिक था, जैसा कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की 24 मार्च, 2021 की अधिसूचना और कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अंतर्गत आवश्यक था।

बी.व. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
1.	धालभूमगढ़ एयरपोर्ट लिमिटेड (2020-21)	वैधानिक लेखापरीक्षक ने अपनी संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों की 'टिप्पणियों' पर एसए-700 (संशोधित) के अनुसार अपनी राय व्यक्त नहीं की।
2.	नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज़ इंक	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत सीएजी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के संदर्भ में वैधानिक लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया बिंदु संख्या 3 (विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्तियाँ) के बारे में तथ्यात्मक रूप से गलत है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से विशिष्ट योजनाओं के लिए ₹556.04 करोड़ प्राप्त किए, जबकि वैधानिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से ऐसी कोई राशि न तो प्राप्त की और न ही प्राप्त करनी थी।
3.	पॉडिचेरी अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	- वैधानिक लेखापरीक्षक ने मूल रिपोर्ट में कंपनियाँ (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) संशोधन नियम, 2021 के अनुसार सूचीबद्ध विषयों पर रिपोर्ट करने से चूक की और इन्हें 30 जुलाई, 2022 को संशोधित स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल किया। हालांकि, इस संशोधन के कारण लेखापरीक्षक की राय पर प्रभाव और यह तथ्य कि यह 18 मई, 2022 को जारी की गई स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट को प्रतिस्थापित करेगा, संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट में खुलासा नहीं किया गया। - संशोधित स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट नियत परिसंपत्तियाँ और इन्वेंट्री की भौतिक सत्यापन की नियमितता और सत्यापन रिपोर्ट में पाए गए भेदों पर टिप्पणी करने में विफल रही, जैसा कि कंपनियाँ (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 द्वारा आवश्यक है। - वैधानिक लेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत सीएजी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को पूरी तरह से शामिल करने में विफलता दिखाई।

बी.vi. अन्य टिप्पणियाँ

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
1.	देवगढ़ एयरपोर्ट लिमिटेड (2020-21)	कंपनी के वित्तीय विवरणों को 31 मार्च, 2020 और 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्षों के लिए संबंधित वार्षिक सामान्य बैठक में सीएजी के लेखा प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना और प्रस्तुत किए बिना मंजूरी दी गई थी। यह कंपनी अधिनियम, 2013 और लेखा और लेखापरीक्षा पर नियमों, 2020 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था।
2.	हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी	कंपनी ने 21 सितंबर, 2021 को आयोजित वार्षिक सामान्य बैठक में 2020-21 के लिए अपने वित्तीय विवरणों को सीएजी की टिप्पणियों के बिना अपनाया, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) और धारा 143(6)(ख) के प्रावधानों का पालन न करने के समान है।

सी. सूचीबद्ध सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ**सी.i. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ**

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
1.	पीएनबी गिल्ड्स लिमिटेड	कंपनी ने मैसर्स टीसीएस कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड को आपूर्ति, एकीकरण, कार्यान्वयन, रख-रखाव और एकीकृत ट्रेजरी प्रबंधन समाधान के प्रबंधन के लिए पुरस्कारित कार्यों के संबंध में ₹15.45 करोड़ की शेष संविदात्मक प्रतिबद्धताओं का खुलासा नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप, लेखा टिप्पणियों में इस सीमा तक कमी हुई है, इसके अलावा इंड एस 38 के पैरा 122 (e) का पालन भी नहीं किया गया।

डी. गैर-सूचीबद्ध सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ

डी.ि. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
1.	क्रॉस बॉर्डर ऊर्जा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	31 मार्च, 2022 तक का ₹22.53 करोड़ का संचित एमएटी क्रेडिट अधिकार वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों के अंतर्गत ऋण और अग्रिम के रूप में दर्ज किया गया था, जबकि इसे गैर-चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत एक अलग लाइन आइटम के रूप में खाता-बद्ध किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप, वर्तमान परिसंपत्तियाँ - वित्तीय परिसंपत्तियाँ (ऋण और अग्रिम) का अधिक आंकलन और गैर-चालू परिसंपत्तियाँ अस्थगित कर परिसंपत्तियों का ₹22.53 करोड़ से कम आंकलन हुआ।
2.	कन्याकुमारी पोर्ट लिमिटेड	वी. ओ. चिदंबरनार पोर्ट अथॉरिटी, जो कंपनी का एक प्रमोटर है, द्वारा किए गए खर्चों का लेखांकन न करने और पोर्ट्स, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा की गई पुनर्भुगतान के परिणामस्वरूप, पिछले अवधि के खर्चों का ₹5.08 करोड़ से कम आंकलन, पूंजीगत कार्य-प्रगति का ₹25.11 करोड़ से कम आंकलन और वर्तमान देनदारियों का ₹30.19 करोड़ से कम आंकलन हुआ।
3.	नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	‘नकद और नकद समकक्ष’ में ₹18.40 करोड़ की टर्म डिपॉजिट खाता शामिल था, जिसकी परिपक्वता अधिग्रहण की तारीख 3 महीने से अधिक थी, इसके परिणामस्वरूप ‘नकद और नकद समकक्ष’ का अधिक आंकलन और ‘अन्य बैंक शेष’ का कम आंकलन हुआ। महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 2.8 भी इस सीमा तक गलत थी कि उसने ‘अन्य बैंक शेष’ को ‘नकद और नकद समकक्ष’ का हिस्सा बना दिया था।

डी.ii. प्रकटीकरण पर टिप्पणियां

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	टिप्पणी
1.	कन्याकुमारी पोर्ट लिमिटेड	कन्याकुमारी में सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोड के माध्यम से ट्रांसशिपमेंट हब पोर्ट के विकास के लिए जारी की गई रुचि की अभिव्यक्ति मार्च 2021 के दौरान पोर्ट्स, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार रद्द कर दी गई। हालांकि इस घटना का कंपनी के अस्तित्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव है, न तो कंपनी ने इसे वित्तीय विवरणों में खुलासा किया, और न ही वैधानिक लेखापरीक्षक ने इसे अपने लेखापरीक्षा रिपोर्ट में मुख्य लेखा परीक्षीय मामलों के अंतर्गत शामिल किया।
2.	कृष्णपट्टनम रेलवे कंपनी लिमिटेड	नोट-19(i) के संदर्भ में, कंपनी ने इस तथ्य का खुलासा नहीं किया कि उसने रेलवे मंत्रालय (एमओआर) के खिलाफ ₹3,227.74 करोड़ की कुल दावा दायर किया है और एमओआर ने ₹5,556.53 करोड़ के काउंटर दावे दायर किए हैं।

2.5.2 वैधानिक निगम जहाँ सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक हैं

वह महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ जो सीएजी ने उन वैधानिक निगमों के वित्तीय विवरणों पर दी हैं जहाँ सीएजी केवल लेखापरीक्षक हैं, नीचे विस्तृत की गई हैं:

एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) (वित्तीय वर्ष 2020-21 के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ)

- पूंजीगत कार्य-प्रगति ₹17.97 करोड़ से कम दिखाया गया था, जो एएआई द्वारा पाकयौंग एयरपोर्ट, सिक्किम में निर्माण कार्य के संदर्भ में (फरवरी 2021 में) घोषित मध्यस्थता पुरस्कार पर देय था। इसके परिणामस्वरूप अन्य देनदारियों का भी कम दिखाया जाना हुआ।
- पूंजीगत कार्य-प्रगति ₹19.88 करोड़ से कम दिखाई गई थी, जो सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली पर संयुक्त परिचालन कार्यालय के निर्माण से संबंधित थी। इसके परिणामस्वरूप जमा कार्य में समान मात्रा में अधिक दिखाया गया।

- पूंजीगत कार्य-प्रगति ₹20.15 करोड़ की राशि से अधिक दिखाया गया था क्योंकि निम्नलिखित कार्यों का पूंजीकरण नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, स्थायी संपत्तियाँ ₹20.15 करोड़ से, मूल्यहास ₹3.10 करोड़ से और वर्ष की हानि ₹3.10 करोड़ से कम दिखायी गया।

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	राशि	मूल्यहास
1	महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट, अगरतला में सीआईएसएफ बैरक, कुत्ते का बाड़ा, कोटे और अन्य विकास कार्यों का निर्माण	15.08	2.41
2	जोरहाट एयरपोर्ट के एयर साइड पर वाहन लेन का चौड़ीकरण और विभिन्न नागरिक कार्य	0.46	0.02
3	आईएलएस इंद्र का एफएफएम भाग (संख्या 72559)	0.16	0.10
4	लखनऊ एयरपोर्ट पर 16 डीवीआर सिस्टम	0.53	0.01
5	उत्तर क्षेत्र के हवाई अड्डों की विभिन्न संपत्तियों का पूंजीकरण न करना	3.60	0.53
6	अमृतसर एयरपोर्ट पर एससीसीटीवी का पूंजीकरण न करना	0.32	0.03
कुल		20.15	3.10

- ₹42.81 करोड़ की राशि जो विभिन्न एजेंसियों से सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली पर संयुक्त संचालन कार्यालय के निर्माण से संबंधित काम के संबंध में वसूली योग्य है। हालांकि, यह राशि खाता पुस्तकों में डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत दिखाई गई है। इससे डिपॉजिट वर्क का अधिक प्रदर्शन और वसूली योग्य राशि का कम प्रदर्शन हुआ है।
- व्यापार प्राप्य राशियाँ ₹40.40 करोड़ से कम दर्शायी गयी, जो कि मेसर्स अडानी लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स लिमिटेड से रियायत समझौता के अनुच्छेद 6.4.5 के अनुसार वसूली योग्य राशि है। हालांकि, इस वसूली योग्य राशि को दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम के अंतर्गत दिखाया गया, जिससे उस खाते का अधिक प्रदर्शन हुआ है।

दामोदर वैली कॉर्पोरेशन (डीवीसी) (वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ)

- नकद और नकदी समकक्ष ₹36.28 करोड़ से कम दर्शाए गए, जो कि उपभोक्ताओं से फरवरी 2020 से मार्च 2022 के बीच प्राप्त ऊर्जा शुल्क का खाता न करने के कारण हुआ, जो सीधे डीवीसी के एंटरप्राइज बिजनेस एप्लिकेशन (ईबीए) बैंक खाता में प्राप्त हुए थे। इसके परिणामस्वरूप व्यापार प्राप्य का भी उतनी ही मात्रा में अधिक प्रदर्शन हुआ है।
- नकद और नकदी समकक्ष ₹49.67 करोड़ से अधिक दर्शाए गए, जो कि ऊर्जा प्लांट्स के लिए एफजीडी उपकरणों की आपूर्ति के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) के माध्यम से किए गए भुगतान का खाता न करने के कारण हुआ। हालांकि, चालानों/बिलों और एसआरआईएनएस के विवरणों की अनुपस्थिति के कारण, इसके परिसंपत्तियों और देनदारियों पर प्रभाव का लेखापरीक्षण में सत्यापन नहीं किया जा सका।
- ऊर्जा की आपूर्ति (परिचालन से राजस्व) में ₹24.63 करोड़ की राशि शामिल थी, जो कि "अनबिल्ड राजस्व" के रूप में बुक की गई थी, जो अप्रैल 2012 से दिसंबर 2021 (₹21.72 करोड़) और जनवरी से मार्च 2022 (₹2.91 करोड़) तक मैथॉन ऊर्जा लिमिटेड से खरीदी गई ऊर्जा की लागत के खिलाफ थी। नियामक आयोगों के किसी भी टैरिफ आदेश की अनुपस्थिति में पूरी राशि को राजस्व के रूप में मान्यता देने से परिचालन से राजस्व, लाभ और अन्य चालू परिसंपत्तियों (अनबिल्ड राजस्व) का ₹24.63 करोड़ से अधिक प्रदर्शन हुआ है।
- विलंब भुगतान अधिभार (डीपीएस) में ₹66.39 करोड़ की राशि शामिल थी, जो डीवीसी द्वारा जनवरी 2021 से जून 2021 के बीच 10 औद्योगिक उपभोक्ताओं पर 2006-2013 की अवधि के लिए डब्ल्यूबीईआरसी द्वारा पारित टैरिफ आदेश (मार्च/जून 2020) के आधार पर उठाए गए बिलों की थी। डीपीएस की मान्यता, माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा (जनवरी 2022) जारी रद्दीकरण आदेशों के बावजूद, डीपीएस (अन्य आय) को अधिक और संबंधित चालू परिसंपत्तियों (ट्रेड रिसीवेबल) का ₹66.39 करोड़ तक अधिक बताया गया है।
- ऊर्जा एक्सचेंज के माध्यम से ऊर्जा की खरीद (ऊर्जा खरीदने की लागत) ₹23.24 करोड़ से कम दर्शाई गई, जो कि अगस्त 2021 महीने में ऊर्जा एक्सचेंज-आईईएक्स

से खरीदी गई ऊर्जा की लागत का हिसाब न करने के कारण हुआ, जिसके लिए उसी महीने आईईएक्स सेटलमेंट अकाउंट के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप नकद और नकदी समकक्ष को भी उतनी ही मात्रा में अधिक बताया गया है।

- कार्बन निकासी और उपयोग खर्च ₹20 करोड़ से कम दर्शाए गए, जो कि मेजिया थर्मल ऊर्जा स्टेशन में सितंबर 2021 में ऐश डाइक के टूटने के कारण फसलों और कृषि भूमि को हुए नुकसान के लिए देनदारी का प्रावधान न करने के कारण हुआ। राशि को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश के अनुसार ₹36.88 करोड़ के रूप में अस्थायी रूप से आंका गया था। दावा के अंतिम आकलन की प्रतीक्षा करते हुए, डीवीसी ने एनजीटी के आदेशों के अनुसार बैकुरा के डीएम के पास ₹20 करोड़ अस्थायी मुआवजे के रूप में जमा किए थे। इसलिए, खाता पुस्तकों में जमा राशि के समानान्तर देनदारी की प्रावधान की जानी चाहिए थी। इसके परिणामस्वरूप लाभ ₹20 करोड़ को अधिक बताया गया है।

भारत की अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूआई) (2020-21 के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ)

आईडब्ल्यूआई कालाडन परियोजना के लिए परियोजना विकास सलाहकार (पीडीसी) के रूप में कार्य कर रहा है। प्राप्त पीडीसी शुल्क और उससे संबंधित खर्च आईडब्ल्यूआई से संबंधित थे और इसलिए इन्हें आईडब्ल्यूआई के खातों में शामिल किया जाना चाहिए था। हालांकि, खाता नोट्स के बिंदु संख्या 14 के अनुसार, प्राधिकरण ने 31 मार्च, 2020 तक ₹33.87 करोड़ प्राप्त किए, जिसमें पीडीसी शुल्क ₹29.05 करोड़, सेवा कर ₹2.11 करोड़, जीएसटी ₹1.72 करोड़ और हाइड्रोग्राफिक सर्वे खर्च की वापसी ₹0.99 करोड़ शामिल थी। परियोजना में 31 मार्च, 2021 तक ₹2.72 करोड़ की आंतरिक प्राप्तियां भी हुईं, जिसमें बैंक ब्याज भी शामिल था। उपरोक्त राशि में से ₹31.28 करोड़ खर्च किया गया था। इन आंकड़ों की पुष्टि लेखापरीक्षा द्वारा नहीं की जा सकती, क्योंकि आईडब्ल्यूआई ने 2020-21 के लिए कालाडन परियोजना के लिए अलग से खाता पुस्तिका तैयार की थी और इस परियोजना के लेन-देन का कोई प्रभाव आईडब्ल्यूआई के 2020-21 के वित्तीय विवरणों में नहीं शामिल किया गया था। यह मुद्दा पहले भी लेखापरीक्षा द्वारा उठाया गया था, लेकिन आईडब्ल्यूआई द्वारा कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया था।

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) (2020-21 के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ)

- नियंत्रण निधि और राजस्व से संबंधित खर्च को लाभ हानि खाते की बजाय पूंजी खाता के खिलाफ समायोजित करने के कारण, वर्ष के घाटे और शेयरधारक निधि-पूंजी ₹3,320.34 करोड़ से कम दर्शाई गई। यह मुद्दा पहले भी लेखापरीक्षा द्वारा उठाया गया था; हालांकि, एनएचएआई द्वारा कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया।
- 31 मार्च 2021 तक, एनएचएआई पर विभिन्न ऋणों के रूप में ₹3,07,162.61 करोड़ की देनदारी थी। हालांकि, एनएचएआई ने इन ऋणों की चुकौती के लिए एक आरक्षित (निधि) फंड नहीं बनाया, जो कि इसके अपने नियमों के खिलाफ था, जबकि पिछले वर्षों में इसी पर टिप्पणी की गई थी।
- भारत सरकार की ओर से रखे गए संपत्तियाँ में ₹136.60 करोड़ का अधिक मूल्यांकन किया गया था, जो दूसरे कार्यालय बिल्डिंग पर खर्च की गई राशि के कारण था, जो कि एनएचएआई की संपत्ति थी और इसे पूंजीकरण किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप स्थिर परिसंपत्तियों (निवल ब्लॉक) का ₹129.77 करोड़ से कम मूल्यांकन हुआ और हानि ₹6.83 करोड़ से कम दिखाई गई ।
- ₹3,469.89 करोड़ की राशि, जो कि पूंजी आरक्षित (निधि) के रूप में थी, को 'स्थिर परिसंपत्तियाँ और भारत सरकार की ओर से रखे गए संपत्तियाँ' के खिलाफ स्थानांतरित किया गया और समायोजित/घटित किया गया। इसके परिणामस्वरूप 'आरक्षित (निधि) और अधिशेष' और 'स्थिर परिसंपत्तियाँ और भारत सरकार की ओर से रखे गए परिसंपत्तियाँ' का कम मूल्यांकन हुआ।
- एनएचएआई ने 2020-21 के वित्तीय वर्ष में ₹1,976.38 करोड़ की अप्रयुक्त पूंजी पर ब्याज अर्जित किया। हालांकि, एनएचएआई को जारी किए गए अनुदान या अग्रिम (वापसी के अलावा) पर अर्जित ब्याज को भारत की समेकित निधि में नहीं भेजा गया, जो कि जीएफआर 2017 के खिलाफ था। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों (भारत सरकार को भुगतान - भारत की समेकित निधि) का कम मूल्यांकन हुआ और स्थिर परिसंपत्तियों वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान पर अर्जित ब्याज की राशि का कम मूल्यांकन हुआ।

- 'वर्तमान संपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम' में ₹11,207.86 करोड़ का अधिक मूल्यांकन किया गया था, जो मंत्रालय द्वारा निर्देशित विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए एनएचएआई द्वारा की गई भुगतान के कारण एमओआरटीएच से वसूल किए जाने की राशि थी। हालांकि, एमओआरटीएच ने (जून 2018) इन वसूलियों को पूरा करने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया था और यह स्पष्ट किया था कि इस प्रकार की वसूलियों के लिए एनएचएआई को अलग से कोई निधि जारी नहीं की जाएगी और इसे एनएचएआई को अपने संसाधनों से पूरा करना होगा। इसके बावजूद ये वसूलियाँ एनएचएआई के खातों में दिखाई दे रही थीं, जबकि एमओआरटीएच से कोई और आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ था। यह मुद्दा पहले भी लेखापरीक्षा द्वारा उठाया गया था, हालांकि, एनएचएआई द्वारा कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया।
- 'वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम' में ₹312.40 करोड़ का अधिक मूल्यांकन किया गया था, जो तीन विशेष उद्देश्य वाहनों (एसपीवी) को दिए गए ऋण की राशि थी, जिन्हें समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। एनएचएआई ने पहले ही इन तीन एसपीवी में ₹403.11 करोड़ के पूरे निवेश में गिरावट के लिए प्रावधान किया था, इसलिए ₹312.40 करोड़ के ऋण के लिए भी प्रावधान किया जाना चाहिए था। इसका प्रावधान न करने से वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋण और अग्रिम का अधिक मूल्यांकन और घाटे का कम मूल्यांकन हुआ। यह मुद्दा पहले भी लेखापरीक्षा द्वारा उठाया गया था, हालांकि, एनएचएआई द्वारा कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया।
- वर्तमान देनदारियाँ और प्रावधान ₹40.54 करोड़ से कम मूल्यांकित की गईं, जो कि भारतीय हाईवे प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (आईएचएमसीएल) को विभिन्न सेवाओं के लिए भुगतान करने के कारण था, जो आईएचएमसीएल ने एनएचएआई को प्रदान की थीं। इसके परिणामस्वरूप टोल संग्रह गतिविधियों के खर्च का भी समान रूप से कम मूल्यांकन हुआ।
- ₹353.22 करोड़ का समायोजन नहीं किया गया, जो कि कलेवा यारगी रोड परियोजना पर खर्च की गई राशि थी, और ₹401.25 करोड़ की राशि जो मंत्रालय से प्राप्त की गई थी, इससे वर्तमान देनदारियाँ और प्रावधान का अधिक मूल्यांकन और वर्तमान संपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम का ₹353.22 करोड़ से अधिक मूल्यांकन हुआ।

- निम्नलिखित खाता शीर्षों में ₹1,198.83 करोड़ का कम मूल्यांकन किया गया था, जो कि देनदारियों के लिए गैर/कम प्रावधान के कारण था।

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	राशि
1	सीएएलए अधिनिर्णय द्वारा 3जी अवॉर्ड / 3डी अधिनिर्णय जारी होने के बावजूद भूमि अधिग्रहण के लिए देय मुआवजा,	622.34
2	ठेकेदार/संविदाकार द्वारा टोल/ब्याज के कम भुगतान के संबंध में भारत सरकार को देय राशि	29.25
3	निर्माण कार्य के लिए ठेकेदार/संविदाकार को देय राशि	330.55
4	प्रयुक्ति स्थानांतरण के लिए ठेकेदार/संविदाकार/प्रयुक्ति विभाग को देय राशि	68.84
5	किए गए कार्य के रख-रखाव के लिए ठेकेदार/संविदाकार को देय राशि	9.62
6	बोनस / वार्षिकी भुगतान के कारण ठेकेदार/संविदाकार को देय राशि	104.30
7	पर्यवेक्षण कार्य और डीपीआर तैयारी के लिए सलाहकारों को देय राशि	9.03
8	अन्य देनदारियाँ	24.90
कुल		1,198.83

इससे परिसंपत्तियों का मूल्यांकन ₹1,189.21 करोड़ कम और राजमार्गों के रखरखाव पर व्यय ₹9.62 करोड़ कम हुआ है।

- एजेंसी शुल्कों को खाता पुस्तकों में न जोड़े जाने के कारण आय का मूल्यांकन कम हुआ, हानि का मूल्यांकन अधिक हुआ और चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का मूल्यांकन ₹1,136.06 से करोड़ कम हुआ।
- पूर्व अवधि की मदों में ₹3,741.57 करोड़ की राशि शामिल नहीं की गई, जो कि एजेंसी शुल्क था और जिसके लिए एनएचएआई द्वारा एमओआरटीएच पर चालान जारी नहीं किए गए थे और 31 मार्च 2020 से पहले की अवधि के लिए खाता पुस्तकों में इसे शामिल नहीं किया गया था। इससे पूर्व अवधि की मदों का मूल्यांकन कम हुआ, संचित हानि का मूल्यांकन अधिक हुआ और चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का मूल्यांकन ₹3,741.57 करोड़ से कम हुआ।

- भूसंपत्ति मुआवजे और विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित दावों के कारण आकस्मिक देनदारी ₹1,705.10 करोड़ कम आंकी गई। अतः आकस्मिक देनदारी के प्रकटीकरण संबंधी नोट क्रमांक 26 में इस सीमा तक कमी थी।
- वित्तीय विवरणों के भाग में शामिल नोट्स में करों, ग्रेच्युटी, छुट्टी वेतन और अन्य के लिए किए गए प्रावधानों के संबंध में ऐएस-29 के पैरा 66 की आवश्यकता के अनुसार कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कोविड-19 महामारी और किसान आंदोलन के कारण एनएचएआई को क्रमशः ₹3,512.62 करोड़ और ₹814.13 करोड़ का टोल राजस्व का अनुमानित नुकसान हुआ। हालांकि, खातों में इसके बारे में किसी प्रकार का प्रकटीकरण नहीं किया गया।
- मार्ग एवं सेतु परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार की ओर से 12 परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों (नमूनों के आधार पर) में से 14,006.9738 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध केवल 7,349.9628 हेक्टेयर भूमि (यानी 52.48 प्रतिशत) को भारत सरकार/एनएचएआई के नाम पर 31 मार्च 2021 तक दाखिल खारिज किया गया। वित्तीय विवरण में भूमि अधिग्रहण और दाखिल खारिज से संबंधित इन तथ्यों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।
- 31 मार्च 2010 तक टोल संग्रह, नकारात्मक अनुदान आदि के बाद शुद्ध पूंजी की ₹6,183.56 करोड़ राशि को वित्त मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त किए बिना एनएचएआई के पूंजी खाते में स्थानांतरित कर दिया गया। वित्तीय विवरणों में इस तथ्य का उपयुक्त प्रकटीकरण किया जाना आवश्यक था।

2.6 लेखांकन मानकों / इंड एस के प्रावधानों का गैर-अनुपालन

कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 469 के अंतर्गत, धारा 129 (1), धारा 132 और धारा 133 के साथ पढ़े जाने पर केंद्र सरकार ने लेखांकन मानक 1 से 5, 7 और 9 से 29 निर्धारित किए हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने कंपनियों (भारतीय लेखांकन मानक) नियमों के माध्यम से 39 भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एस) को अधिसूचित किया है, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

वैधानिक लेखापरीक्षकों ने बताया कि **परिशिष्ट-XVI** में दर्शाई गई 19 सीपीएसई ने अनिवार्य लेखांकन मानकों/आई एंड एस का पालन नहीं किया।

पूरक लेखापरीक्षा के दौरान, सीएजी ने भी देखा कि कुछ सीपीएसई ने लेखांकन मानकों/आई एंड एस का पालन नहीं किया था, जिसका उल्लेख उनके वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा नहीं किया गया था, जैसा कि तालिका 2.2 में दिया गया है।

तालिका 2.2: लेखा मानकों/ आई एंड एस का पालन न करना

लेखांकन मानक/ आई एंड एस	सीपीएसई का नाम	विचलन
एस - 3	नकदी प्रवाह विवरण	गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस
	एनआरटीयू फाउंडेशन	नकद और नकद समकक्ष में ₹144.96 करोड़ की बंधक राशि शामिल की गई थी, जिसे विक्रेताओं ने जीईएम पोर्टल पर व्यवसाय करने के लिए जमा किया था। यह राशि जीईएम के साथ व्यवसाय को समाप्त करने पर उन्हें वापस की जाएगी। अतः, यह राशि कंपनी के उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं थी। हालांकि, इस तथ्य का खुलासा कंपनी ने अपनी नकद प्रवाह विवरणिका में नहीं किया, जो एस-3 के पैरा 45 के अनुपालन में नहीं था।
एस - 5	अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि की वस्तुएं और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन	कैनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड
इंड एस - 1	वित्तीय विवरण की प्रस्तुति	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

लेखांकन मानक/ आई एंड एस	सीपीएसई का नाम	विचलन
इंड एस -7	नकद प्रवाह विवरण	नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
		इंड एस 7 के पैरा 7 के उल्लंघन में, 'वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष' में ₹18.40 करोड़ की राशि शामिल थी, जो कि अधिग्रहण की तारीख से 3 महीने से अधिक की परिपक्वता वाले सावधि जमा खाते होने चाहिए थे। 'अन्य बैंक शेष' के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उसका समायोजन 'परिचालन गतिविधियों से नकदी' के अंतर्गत 'वर्तमान और अस्तित्वहीन परिसंपत्तियों में वृद्धि/कमी' के रूप में किया जाना चाहिए था।
		रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
		कंपनी ने ₹11.79 करोड़ की सावधि जमा राशि को 'अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों' के बजाय 'अन्य बैंक बैलेंस' के अंतर्गत गलत तरीके से प्रकट किया।
		रेलटेल एंटरप्राइजेज लिमिटेड
		कंपनी ने ₹11.79 करोड़ की सावधि जमा राशि को 'अन्य चालू वित्तीय संपत्तियों' के बजाय 'अन्य बैंक बैलेंस' के अंतर्गत गलत तरीके से प्रकट किया।
इंड एस - 16	सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
		- मूल्यहास की गणना व्यक्तिगत संपत्तियों के बजाय संपत्तियों के असमरूप समूह पर की गई। - अवशिष्ट मूल्य परिसंपत्ति लागत के 5% से अधिक आंका गया।
		भाग्यनगर गैस लिमिटेड
		परिसंपत्ति का भिन्न आर्थिक अवधि तकनीकी मूल्यांकन द्वारा समर्थित नहीं है।
		केआईओसीएल लिमिटेड
		घटकीकरण पर गलत लेखांकन नीति।

लेखांकन मानक/ आई एंड एस	सीपीएसई का नाम	विचलन
इंड एस - 36	परिसंपत्तियों की क्षति	भाग्यनगर गैस लिमिटेड
		एनएमडीसी लिमिटेड
		सूचना के बाहरी स्रोत की उपस्थिति में भी परिसंपत्तियों के मूल्य वहन करने में हानि का आकलन न करना।
		- कोकिंग कोयले पर क्षति की पहचान न होना। 5 वर्ष से अधिक पुरानी गैर-चलित वस्तुओं का मूल्यांकन नहीं किया गया।
इंड एस - 105	बिक्री के लिए रखी गई अस्तित्वहीन परिसंपत्तियां और बंद परिचालन	कॉनकोर एयर लिमिटेड
		‘गैर-चालू परिसंपत्तियों’ को शामिल करने के कारण संपत्ति संयंत्र और उपकरण को ₹15.62 करोड़ से अधिक बताया गया था, जिनके 12 महीने की अवधि के भीतर बेचे जाने की उम्मीद है। इसे इंड एस 105 के पैरा 6 के अनुसार ‘वर्तमान संपत्ति’ के अंतर्गत ‘बिक्री के लिए धारित’ के रूप में दिखाया जाना चाहिए था।

2.7 प्रबंधन पत्र

वित्तीय लेखापरीक्षा का एक उद्देश्य यह है कि वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा से उत्पन्न होने वाले लेखापरीक्षा मामलों पर लेखापरीक्षकों और कॉर्पोरेट इकाई की शासन संबंधी जिम्मेदारी संभालने वालों के बीच संवाद स्थापित किया जाए।

सीपीएसई के वित्तीय विवरणों पर मुख्य टिप्पणियों को सीएजी द्वारा कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत टिप्पणियों के रूप में रिपोर्ट किया गया। इन टिप्पणियों के अलावा, सीएजी द्वारा वित्तीय रिपोर्टों या रिपोर्टिंग प्रक्रिया में देखी गई अनियमितताओं या कमियों को भी ‘प्रबंधन पत्र’ के माध्यम से प्रबंधन को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए सूचित किया गया। ये कमियां सामान्यतः निम्नलिखित से संबंधित थीं:

- लेखांकन नीतियों और प्रथाओं का अनुप्रयोग और व्याख्या;
- लेखापरीक्षा से उत्पन्न समायोजन जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं; और

- कुछ जानकारी का अपर्याप्त या गैर-प्रकटीकरण, जिस पर संबंधित सीपीएसई के प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि अगली वर्ष में सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

वर्ष 2020-21 के लिए जारी किए गए प्रबंधन पत्रों के आधार पर, सीपीएसई के प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सुधारों को **परिशिष्ट-XVII** में उजागर किया गया है।

वर्ष के दौरान, सीएजी ने 240 सीपीएसई को 'प्रबंधन पत्र' जारी किए (**परिशिष्ट-XVIII**)

तृतीय अध्याय

कॉर्पोरेट गवर्नेंस

3.1 परिचय

कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन प्रथाओं का अनुप्रयोग है, जो कानूनों का सही अर्थ और भावना में पालन करने, प्रभावी प्रबंधन और संपत्ति के वितरण के लिए नैतिक मानकों का पालन करने और सभी हितधारकों के सतत विकास के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने पर आधारित है।

कई सीपीएसई और सांविधानिक निगम सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, जिनके शेयर और बांड/डेबेंचर स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हैं। सीपीएसई को अधिक स्वायत्तता देने की सरकारी नीति के संदर्भ में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का महत्व बढ़ गया है। महारत्न योजना के अंतर्गत, सीपीएसई से अपनी गतिविधियों का विस्तार करने और वैश्विक दिग्गज बनने की अपेक्षा की जाती है, जिसके लिए प्रभावी कॉर्पोरेट गवर्नेंस अनिवार्य हो गया है।

3.1.1 कॉर्पोरेट गवर्नेंस को नियंत्रित करने वाले प्रावधान

कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पहल के लिए भारत में कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय (एमसीए) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) प्रमुख नियामक संस्थाएँ हैं। सेबी भारत में सूचीबद्ध कंपनियों/सांविधिक निगमों के कॉर्पोरेट गवर्नेंस की निगरानी और नियमन करता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित नियामक प्रावधान मुख्य रूप से कम्पनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीकरण प्रतिबद्धताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015, सेबी(गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों की जारी और सूचीबद्ध करने) विनियम, 2021 और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी मार्गदर्शन से कवर होते हैं, जिन्हें नीचे समझाया गया है:

3.1.1.1 कम्पनी अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधान

कम्पनी अधिनियम, 2013 को 29 अगस्त, 2013 को लागू किया गया, जिसने कम्पनी अधिनियम, 1956 को प्रतिस्थापित किया। इसके अतिरिक्त, एमसीए ने (31 मार्च, 2014) को कंपनियों के प्रबंधन और प्रशासन, निदेशकों की नियुक्ति और योग्यताएँ, और बोर्ड की बैठकों और उसकी शक्तियों के नियमों की अधिसूचना भी की। कम्पनी अधिनियम, 2013 और कंपनियों के नियम मिलकर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करते हैं। उपरोक्त के साथ इन नियमों में, विशेष रूप से निम्नलिखित आवश्यकताओं का प्रावधान है।

- स्वतंत्र निदेशकों के लिए योग्यताएँ, उनके कर्तव्य और पेशेवर आचरण के लिए दिशा-निर्देश (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और (8) तथा अनुसूची IV को कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यताएँ) नियम, 2014 की धारा 5 के साथ पढ़ें)।
- सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक मंडल में एक महिला निदेशक की अनिवार्य नियुक्ति {कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1)}।
- कुछ समितियों की अनिवार्य स्थापना जैसे कि लेखापरीक्षा कमिटी {कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(1)}, नामांकन और पारिश्रमिक कमिटी {कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(1)} और हितधारक संबंध कमिटी {कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(5)}।
- निदेशक मंडल की न्यूनतम चार बैठकें हर साल आयोजित करना, इस प्रकार से कि दो लगातार बैठकों के बीच 120 दिन से अधिक का अंतर न हो {कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173(1)}।

3.1.1.2 सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) नियम, 2015

सेबी ने 02 सितंबर, 2015 को सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) नियम, 2015 को अधिसूचित किया, जो 01 दिसंबर, 2015 से प्रभावी हुआ। मार्च 2022 तक, सेबी(सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (पाँचवां संशोधन) नियम, 2021 को 07 सितंबर, 2021 को अधिसूचित किया गया, जिसको इस रिपोर्ट में ध्यान में रखा गया है।

सेबी दिशा-निर्देश सीपीएसई में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अच्छी प्रथाओं को संस्थागत बनाने में मदद करते हैं, जैसा कि नियम 16 से 27 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत शेयरों और गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों⁴⁹ के लिए और अन्य प्रासंगिक एवं संशोधित प्रावधानों में नियम 50 से 62 में केवल गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के लिए लागू होते हैं।

3.1.1.3 सेबी (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गमन और सूचीकरण) नियम, 2021

यह नियम 16 अगस्त, 2021 से प्रभावी हुआ और सीपीएसई में गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के लिए निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अच्छी प्रथाओं को स्थापित करने के लिए संस्थान को सक्षम बनाता है।

3.1.1.4 कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई के दिशा-निर्देश

डीपीई ने नवंबर 1992 में सीपीएसई के निदेशक मंडल में गैर-आधिकारिक निदेशकों को शामिल करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे, इसके बाद नवंबर 2001 में सीपीएसई के निदेशक मंडल के स्वतंत्र निदेशकों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। सीपीएसई के कार्यों में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए, डीपीई ने जून 2007 में सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशा-निर्देशों को आरंभ किया। शुरू में, ये दिशा-निर्देश स्वैच्छिक थे और एक साल की परीक्षण अवधि के लिए लागू किए गए थे। इस अवधि के दौरान प्राप्त अनुभव के आधार पर, इन दिशा-निर्देशों को संशोधित किया गया और मई 2010 में फिर से जारी किया गया, जिन्हें अनिवार्य बना दिया गया और सभी सीपीएसई पर लागू किया गया। डीपीई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में निदेशक मंडल की संरचना, बोर्ड समितियों जैसे लेखापरीक्षा समिति, पारिश्रमिक समिति की संरचना और कार्य, सहायक कंपनियों का विवरण, प्रकटीकरण, रिपोर्ट और कार्यान्वयन के लिए अनुसूचियां जैसे क्षेत्र शामिल हैं। डीपीई ने 'कॉर्पोरेट गवर्नेंस' को सभी सीपीएसई के समझौता ज्ञापन (एमओयू) में एक निष्पादन मापदंड के रूप में भी शामिल किया।

⁴⁹ गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का अर्थ है ऋण प्रतिभूतियाँ, गैर-परिवर्तनीय प्रतिदेय वरीयता शेयर, सतत गैर-संचयी वरीयता शेयर, सतत ऋण उपकरण और बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य प्रतिभूतियाँ। इसके अलावा, विनियम 16 से 27, 31 मार्च, 2023 तक 'अनुपालन करें या स्पष्टीकरण दें' के आधार पर हैं और उसके बाद उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध इकाई के लिए अनिवार्य आधार पर हैं। इस प्रकार, चूंकि विनियम 16 से 27 उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध इकाई के लिए अनिवार्य नहीं हैं, इसलिए गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के लिए विनियम 16 से 27 के अनुपालन पर विचार नहीं किया गया है।

इस प्रकार, कंपनी अधिनियम, 2013, सेबीनियम और डीपीई दिशा-निर्देश 2010 मिलकर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए एक सक्षम ढांचा प्रदान करते हैं।

3.1.2 सूचीबद्ध सीपीएसई और सांविधिक निगमों जिनके शेयर, बांड और डेबेंचर विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध थे द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा

31 मार्च, 2022 तक, 698 सीपीएसई (जिसमें छह सांविधिक निगम शामिल हैं) थे, जो विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण में थे और जो भारत के सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में थे। इनमें से, 71 सीपीएसई⁵⁰, जिनके शेयर/बांड सूचीबद्ध हैं, और 35 सीपीएसई/ सांविधिक निगम⁵¹, जिनके बांड/डेबेंचर सूचीबद्ध हैं, 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 के बीच लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए थे। 71 सूचीबद्ध सीपीएसई, जिनके शेयर/बांड सूचीबद्ध हैं, की सूची *अनुलग्नक-XIX* में दी गई है और 35 सीपीएसई/ सांविधिक निगम, जिनके बांड/डेबेंचर सूचीबद्ध हैं, की सूची *अनुलग्नक-XX* में दी गई है।

इसके अतिरिक्त, उपरोक्त में से 18 सीपीएसई हैं जिनके दोनों शेयर और बांड/डेबेंचर सूचीबद्ध हैं, जैसा कि *अनुलग्नक-XXI* में दिया गया है।

2021-22 के दौरान सीपीएसई जिनके शेयर / शेयर और बांड दोनों विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध थे, सीपीएसई द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रावधानों के अनुपालन में देखे गए मुद्दे अध्याय के भाग अ तथा सीपीएसई/ सांविधिक निगम जिनके बांड/डेबेंचर विभिन्न स्टॉक एक्सचेंज सूचीबद्ध थे, के मुद्दे अध्याय के भाग ब में दर्शाये गए हैं।

⁵⁰ कुल 76 सूचीबद्ध सीपीएसई में से पांच कंपनियों को बाहर रखा गया है, जैसे स्कूटर इंडिया लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड (परिसमापन के अंतर्गत) और हिंदुस्तान फोटोफिल्म्स (मैन्युफैक्चरिंग) कंपनी लिमिटेड (समापन प्रक्रिया के अंतर्गत)।

⁵¹ इसमें तीन वैधानिक निगम शामिल हैं, जैसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और भारतीय खाद्य निगम, जिनके बांड 31 मार्च, 2022 तक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थे।

भाग-अ

सीपीएसई जिनके शेयर/ शेयर और बॉन्ड दोनों 31 मार्च, 2022 को स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध थे

3.2 निदेशक मंडल

3.2.1 निदेशक मंडल में गैर-कार्यकारी निदेशक

निदेशक मंडल कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) नियम, 2015 की धारा 17(1)(ए) में कहा गया है कि सूचीबद्ध संस्थाओं के निदेशक मंडल में कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशकों का एक उचित संयोजन होना चाहिए, जिसमें निदेशक मंडल के कम से कम 50 प्रतिशत निदेशक गैर-कार्यकारी निदेशक होने चाहिए। निदेशक मंडल की संरचना की समीक्षा से यह पता चला कि तालिका 3.1 में सूचीबद्ध सीपीएसई के पास गैर-कार्यकारी निदेशकों की आवश्यक संख्या (कुल बोर्ड सदस्यों का कम से कम 50 प्रतिशत) नहीं थी।

तालिका 3.1: सीपीएसई जिनमें गैर-कार्यकारी निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	निदेशक मंडल में कुल निदेशकों की संख्या	निदेशक मंडल में कार्यकारी निदेशकों की संख्या	निदेशक मंडल में आवश्यक गैर-कार्यकारी निदेशकों की संख्या	निदेशक मंडल में वास्तविक गैर-कार्यकारी निदेशकों की संख्या	कमी (प्रतिशत में)	वर्ष 2021-22 के दौरान गैर अनुपालन की अवधि
1.	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	4	2	2	1	1(50)	अप्रैल से नवम्बर
2.	मझगाँव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड	8	4	4	1	3(75)	अप्रैल से नवम्बर
3.	गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	6	3	3	2	1(33)	अप्रैल से अगस्त
		6	3	3	1	2 (67)	सितम्बर से मार्च

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	निदेशक मंडल में कुल निदेशकों की संख्या	निदेशक मंडल में कार्यकारी निदेशकों की संख्या	निदेशक मंडल में आवश्यक गैर-कार्यकारी निदेशकों की संख्या	निदेशक मंडल में वास्तविक गैर-कार्यकारी निदेशकों की संख्या	कमी (प्रतिशत में)	वर्ष 2021-22 के दौरान गैर अनुपालन की अवधि
4.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8	4	4	2	2(50)	अप्रैल से जून
5.	राईट्स लिमिटेड	8	4	4	1	3(75)	अप्रैल से जून
		6	3	3	1	2(67)	जुलाई से सितम्बर
		8	4	4	0	4(100)	अक्टूबर
6.	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4	2	2	1	1(50)	सितम्बर से अक्टूबर
7.	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	6	3	3	2	1(33)	अप्रैल से नवम्बर
8.	ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	14	7	7	3	4 (57)	अप्रैल से अक्टूबर
9.	गेल (इंडिया) लिमिटेड	8	4	4	3	1 (25)	अप्रैल से मई
		8	4	4	2	2 (50)	जून से अगस्त,
		8	4	4	1	3 (75)	सितम्बर से अक्टूबर
10.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	10	5	5	4	1(20)	अप्रैल से जून
		10	5	5	3	2 (40)	जुलाई से अगस्त
		8	4	4	3	1 (25)	सितम्बर
		8	4	4	2	2 (50)	अक्टूबर
		10	5	5	2	3 (60)	नवंबर
11.	एनएचपीसी लिमिटेड	8	4	4	1	3 (75)	अप्रैल से अक्टूबर

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	निदेशक मंडल में कुल निदेशकों की संख्या	निदेशक मंडल में कार्यकारी निदेशकों की संख्या	निदेशक मंडल में आवश्यक गैर-कार्यकारी निदेशकों की संख्या	निदेशक मंडल में वास्तविक गैर-कार्यकारी निदेशकों की संख्या	कमी (प्रतिशत में)	वर्ष 2021-22 के दौरान गैर अनुपालन की अवधि
12.	सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड	10	5	5	4	1 (20)	अप्रैल से मई और जुलाई से अक्टूबर
13.	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	12	6	6	5	1 (17)	अप्रैल से मई
14.	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	10	5	5	3	2 (40)	अप्रैल से जून
		8	4	4	3	1 (25)	जुलाई से अक्टूबर
15.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	6	3	3	1	2 (67)	अप्रैल से जुलाई
		6	3	3	2	1 (33)	अगस्त से अक्टूबर
16.	भारत डाइनेमिक्स लिमिटेड	8	4	4	2	2 (50)	अप्रैल से नवम्बर
17.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	10	5	5	4	1 (20)	अप्रैल से अक्टूबर
18.	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	12	6	6	3	3 (50)	अप्रैल से जून
		10	5	5	3	2 (40)	जुलाई से अगस्त
		8	4	4	3	1 (25)	सितम्बर से नवम्बर
19.	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	8	4	4	2	2 (50)	अप्रैल से अक्टूबर
20.	स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	6	3	3	2	1 (33)	अप्रैल से नवम्बर
21.	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	8	4	4	2	2 (50)	अप्रैल
		6	3	3	2	1 (33)	मई से अक्टूबर

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	निदेशक मंडल में कुल निदेशकों की संख्या	निदेशक मंडल में कार्यकारी निदेशकों की संख्या	निदेशक मंडल में आवश्यक गैर-कार्यकारी निदेशकों की संख्या	निदेशक मंडल में वास्तविक गैर-कार्यकारी निदेशकों की संख्या	कमी (प्रतिशत में)	वर्ष 2021-22 के दौरान गैर अनुपालन की अवधि
22.	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	8	4	4	3	1 (25)	अगस्त से अक्टूबर
23.	हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड	10	5	5	4	1 (20)	अप्रैल से जुलाई
		10	5	5	2	3 (60)	अगस्त से नवम्बर
		10	5	5	3	2 (40)	दिसम्बर से मार्च
24.	कोल इंडिया लिमिटेड	8	4	4	3	1 (25)	अप्रैल से जून
		10	5	5	2	3 (60)	जुलाई से अक्टूबर
25.	आरईसी लिमिटेड	6	3	3	1	2 (67)	अप्रैल से अगस्त
		6	3	3	2	1 (33)	सितम्बर से अक्टूबर
26.	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ऑफ त्रावणकोर लिमिटेड	8	4	4	3	1 (25)	अप्रैल से मार्च

जैसा कि उपर्युक्त दी गई तालिका में देखा गया है, 71 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 26 (37 प्रतिशत) में वर्ष 2021-22 की पूरी/आंशिक अवधि के दौरान आवश्यक संख्या में गैर-कार्यकारी निदेशक बोर्ड में नहीं थे। कमी का प्रतिशत 17 से 100 प्रतिशत के बीच था।

3.2.2 स्वतंत्र निदेशक

3.2.2.1 प्रबंधन के निर्णय पर स्वतंत्र दृष्टिकोण रखने में सक्षम बोर्ड में स्वतंत्र प्रतिनिधियों की उपस्थिति को शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा के साधन के रूप में माना जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4), सेबी (सूचीबद्धता

बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 17(1)(बी) और डीपीई दिशानिर्देश 2010 के पैरा 3.1.4 के अनुसार, जहां बोर्ड का अध्यक्ष एक गैर-कार्यकारी निदेशक है, बोर्ड का कम से कम एक तिहाई हिस्सा स्वतंत्र निदेशकों से युक्त होना चाहिए और यदि अध्यक्ष एक कार्यकारी निदेशक है, तो बोर्ड का कम से कम आधा हिस्सा स्वतंत्र निदेशकों से युक्त होना चाहिए। सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015 के विनियमन 16(1)(बी) के अनुसार, 'स्वतंत्र निदेशक' का अर्थ सूचीबद्ध इकाई के नामित निदेशक के अलावा एक गैर-कार्यकारी निदेशक होगा। निदेशक मंडल की संरचना की समीक्षा से पता चला कि तालिका 3.2 में सूचीबद्ध सीपीएसई के पास अपने बोर्ड में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

तालिका 3.2: सीपीएसई जिनमें स्वतंत्र निदेशक की अपेक्षित संख्या नहीं थी

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम ⁵²	बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के अलावा निदेशकों की संख्या	अध्यक्ष की स्थिति	आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या	कमी (प्रतिशत में)	वर्ष 2021-22 के दौरान कमी का समय
1.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4 3 5	कार्यकारी	4 3 5	1 0 0	3 (75) 3 (100) 5 (100)	अप्रैल से जुलाई अगस्त सितंबर से अक्टूबर
2	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5 5	कार्यकारी	5 5	0 4	5 (100) 1 (20)	अप्रैल से नवंबर दिसंबर से मार्च
3	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	9	कार्यकारी	9	1	8 (89)	अप्रैल से अक्टूबर

⁵² 4 क्रमांक 1 से 16 तक उल्लिखित सीपीएसई के लिए, शेयर और बॉन्ड / डिबेंचर दोनों 31 मार्च 2022 पर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थे।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम ⁵²	बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के अलावा निदेशकों की संख्या	अध्यक्ष की स्थिति	आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या	कमी (प्रतिशत में)	वर्ष 2021-22 के दौरान कमी का समय
4	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	6 6 7	कार्यकारी	6 6 7	3 1 3	3 (50) 5 (83) 4 (57)	अप्रैल से जुलाई अगस्त से नवंबर दिसंबर से मार्च
5	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	7 7 6 8	कार्यकारी	7 7 6 8	2 1 1 7	5 (71) 6 (86) 5 (83) 1 (13)	अप्रैल से जून जुलाई से अगस्त सितंबर से नवंबर फरवरी से मार्च
6	एनएचपीसी लिमिटेड	5 5	कार्यकारी	5 5	0 4	5 (100) 1 (20)	अप्रैल से अक्टूबर नवंबर से मार्च
7	सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड	7 7	कार्यकारी	7 7	2 5	5 (71) 2 (29)	अप्रैल से अक्टूबर नवंबर से मार्च
8	एनटीपीसी लिमिटेड	8 8 8	कार्यकारी	8 8 8	2 0 4	6 (75) 8 (100) 4 (50)	अप्रैल से जुलाई अगस्त से अक्टूबर दिसंबर से मार्च
9	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	4	कार्यकारी	4	0	4 (100)	अप्रैल से अक्टूबर

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम ⁵²	बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के अलावा निदेशकों की संख्या	अध्यक्ष की स्थिति	आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या	कमी (प्रतिशत में)	वर्ष 2021-22 के दौरान कमी का समय
10	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	7	कार्यकारी	7	2	5 (71)	अप्रैल से अक्टूबर जनवरी से मार्च
		8		8	6	2 (25)	
11	मंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल लिमिटेड	7	गैर-कार्यकारी	4	1	3 (75)	अप्रैल से अक्टूबर
12	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	4	कार्यकारी	4	1	3 (75)	अप्रैल से जुलाई अगस्त से अक्टूबर नवंबर से मार्च
		4		4	0	4 (100)	
		4		4	2	2 (50)	
13	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4	कार्यकारी	4	3	1 (25)	अप्रैल से जुलाई अगस्त से अक्टूबर नवंबर से मार्च
		7		7	3	4 (57)	
		9		9	5	4 (44)	
14	एनएमडीसी लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	0	6 (100)	अप्रैल से अक्टूबर नवंबर से मार्च
		6		6	4	2 (33)	
15	आरईसी लिमिटेड	4	कार्यकारी	4	0	4 (100)	अप्रैल से अक्टूबर नवंबर से मार्च
		4		4	3	1 (25)	
16	आईएफसीआई लिमिटेड	7	कार्यकारी	7	0	7 (100)	अप्रैल से मार्च

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम ⁵²	बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के अलावा निदेशकों की संख्या	अध्यक्ष की स्थिति	आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या	कमी (प्रतिशत में)	वर्ष 2021-22 के दौरान कमी का समय
17	बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड	4 4	गैर-कार्यकारी	2 2	0 1	2(100) 1(50)	अप्रैल से अक्टूबर नवंबर से मार्च
18	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	4 4	कार्यकारी	4 4	1 0	3(75) 4 (100)	अप्रैल से अगस्त सितंबर से मार्च
19	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	5 5	कार्यकारी	5 5	0 3	5(100) 2 (40)	अप्रैल से नवंबर दिसंबर से मार्च
20	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	6 6 6	कार्यकारी	6 6 6	0 1 5	6 (100) 5 (83) 1 (17)	अप्रैल से जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर से दिसंबर
21	राइट्स लिमिटेड	5 4 5 5	कार्यकारी	5 4 5 5	0 3 3 4	5(100) 1 (25) 2(40) 1 (20)	अप्रैल से अक्टूबर नवंबर दिसंबर से जनवरी फरवरी से मार्च
22	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	6 6 6	कार्यकारी	6 6 6	2 1 4	4 (67) 5 (83) 2 (33)	अप्रैल से जुलाई अगस्त से अक्टूबर नवंबर से मार्च

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम ⁵²	बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के अलावा निदेशकों की संख्या	अध्यक्ष की स्थिति	आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या	कमी (प्रतिशत में)	वर्ष 2021-22 के दौरान कमी का समय
23	इंडियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टुरिज़म कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4	कार्यकारी	4	0	4 (100)	अप्रैल से अक्टूबर नवंबर से दिसंबर जनवरी से मार्च
		3		3	2	1 (33)	
		5		5	2	3 (60)	
24	भारत हवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	7	कार्यकारी	7	3	4 (57)	अप्रैल से जुलाई अगस्त से अक्टूबर
		6		6	3	3 (50)	
25	तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड	6	गैर-कार्यकारी	3	0	3 (100)	अप्रैल से मार्च
26	रेल विकास निगम लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	2	4 (67)	अप्रैल से मई जून से जुलाई अगस्त से अक्टूबर नवंबर से मार्च
		6		6	1	5(83)	
		7		7	0	7(100)	
		7		7	2	5(71)	
27	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	5	कार्यकारी	5	0	5 (100)	अप्रैल से अक्टूबर नवंबर से मार्च
		5		5	4	1(20)	
28	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	2	4 (67)	अप्रैल से जुलाई अगस्त से अक्टूबर नवंबर से मार्च
		6		6	1	5 (83)	
		6		6	5	1 (17)	

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम ⁵²	बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के अलावा निदेशकों की संख्या	अध्यक्ष की स्थिति	आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या	कमी (प्रतिशत में)	वर्ष 2021-22 के दौरान कमी का समय
29	गेल(इंडिया) लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	1	5 (83)	अप्रैल से मई
		5		5	1	4 (80)	जून से अगस्त
		5		5	0	5 (100)	सितंबर से अक्टूबर
30	मैंगनीज ऑर इंडिया लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	2	4 (67)	अप्रैल से अक्टूबर
31	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	5	कार्यकारी	5	0	5 (100)	अप्रैल से अक्टूबर
		5		5	1	4 (80)	नवंबर से दिसंबर
		6		6	3	3 (50)	जनवरी से मार्च
32	राष्ट्रीय केमिकलस एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	5	कार्यकारी	5	4	1 (20)	अप्रैल से अक्टूबर
33	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	3	3 (50)	अप्रैल से अक्टूबर
34	एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड	4	कार्यकारी	4	1	3 (75)	अप्रैल से मई
		3		3	1	2 (67)	जून से अक्टूबर
35	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	7	कार्यकारी	7	1	6 (86)	अप्रैल से जून
		6		6	1	5 (83)	जुलाई से अक्टूबर
36	आईटीआई लिमिटेड	4	कार्यकारी	4	3	1 (25)	अप्रैल से जून
		3		3	0	3 (100)	सितम्बर से अक्टूबर

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम ⁵²	बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के अलावा निदेशकों की संख्या	अध्यक्ष की स्थिति	आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या	कमी (प्रतिशत में)	वर्ष 2021-22 के दौरान कमी का समय
37	नैशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड	5	कार्यकारी	5	1	4 (80)	अप्रैल से अक्टूबर
38	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	1	5 (83)	अप्रैल से नवम्बर
39	नैशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	0	6 (100)	अप्रैल से अक्टूबर
40	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	5	कार्यकारी	5	3	2 (40)	जुलाई से अक्टूबर
41	एचएमटी लिमिटेड	4	कार्यकारी	4	2	2 (50)	मार्च
42	बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड	5	कार्यकारी	5	4	1 (20)	सितम्बर से नवम्बर
43	मेटल स्क्रेप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5	कार्यकारी	5	1	4 (80)	अप्रैल से अक्टूबर
		5		5	3	2 (40)	नवम्बर से दिसम्बर
		4		4	2	2 (50)	जनवरी से मार्च
44	स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	5	कार्यकारी	5	0	5 (100)	अप्रैल से नवम्बर
45	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	3	कार्यकारी	3	0	3 (100)	अप्रैल से नवम्बर
		3		3	2	1 (33)	दिसम्बर से मार्च
46	न्यू इंडिया एश्योरेस कंपनी लिमिटेड	3	कार्यकारी	3	2	1 (33)	अप्रैल से अगस्त
47	कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड	5	कार्यकारी	5	0	5(100)	अप्रैल से अक्टूबर

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम ⁵²	बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के अलावा निदेशकों की संख्या	अध्यक्ष की स्थिति	आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या	कमी (प्रतिशत में)	वर्ष 2021-22 के दौरान कमी का समय
48	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	6 6	कार्यकारी	6 6	0 4	6 (100) 2 (33)	अप्रैल से नवम्बर दिसम्बर से मार्च
49	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	3 3	कार्यकारी	3 3	0 1	3 (100) 2 (67)	अप्रैल से नवम्बर दिसम्बर से मार्च
50	हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड	7 7 7	कार्यकारी	7 7 7	2 0 1	5 (71) 7 (100) 6 (86)	अप्रैल से जुलाई अगस्त से नवम्बर दिसम्बर से मार्च
51	कोल इंडिया लिमिटेड	7 7	कार्यकारी	7 7	0 6	7 (100) 1 (14)	अप्रैल से अक्टूबर नवम्बर से दिसम्बर
52	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	4	गैर-कार्यकारी	2	1	1(50)	अप्रैल से अक्टूबर
53	ऑयल इंडिया लिमिटेड	4	कार्यकारी	4	3	1 (25)	अप्रैल से अक्टूबर
54	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	3	गैर-कार्यकारी	2	0	2 (100)	अगस्त से जनवरी
55	फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकलस त्रावनकोट लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	1	5 (83)	अप्रैल से मार्च

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा गया है, 71 सूचीबद्ध सीपीएसईमें से 55 (77 प्रतिशत) में 2021-22 के वर्ष के पूरे आंशिक अवधि के दौरान बोर्ड पर आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। कमी का प्रतिशत 13 से 100 प्रतिशत के बीच था।

भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने जवाब (जुलाई 2024) में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (क्रम संख्या 24) और एचएमटी लिमिटेड (क्रम संख्या 41) से संबंधित टिप्पणियों के लिए बताया कि स्वतंत्र निदेशक (जिसमें महिला स्वतंत्र निदेशक भी शामिल हैं) रिक्त पदों को भरने का मामला लगातार डीपीई के साथ उठाया गया।

हालांकि, तथ्य यह है कि दोनों सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशकों (महिला स्वतंत्र निदेशक सहित) का पद उपरोक्त तालिका 3.2 में उल्लिखित अवधि के दौरान रिक्त रहा।

3.2.2.2 सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (5) (बी) में यह निर्धारित किया गया है कि निदेशक मंडल को स्वतंत्र निदेशकों के कर्तव्यों को कम्पनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित आचार संहिता में शामिल करना चाहिए। हालांकि, तालिका 3.3 में सूचीबद्ध सीपीएसई के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित आचार संहिता में कम्पनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित स्वतंत्र निदेशकों के कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था।

तालिका 3.3: सीपीएसई जहां आचार संहिता में स्वतंत्र निदेशकों के कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम
1.	रेल विकास निगम लिमिटेड
2.	बामरलॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
3	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
4.	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
5.	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ऑफ ट्रावनकोर लिमिटेड

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा गया है, 71 सूचीबद्ध सीपीएसई में से पांच (7 प्रतिशत) ने अपने निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित आचार संहिता में कंपनियों के अधिनियम, 2013 में निर्धारित स्वतंत्र निदेशकों के कर्तव्यों को शामिल नहीं किया है।

3.2.3 महिला निदेशक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1), कंपनियों (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 का नियम 3 और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ)

विनियम, 2015 का विनियम 17(1)(क) यह निर्धारित करते हैं कि सूचीबद्ध संस्था के निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक होना चाहिए। सेबी विनियम, 2015 यह भी निर्धारित करते हैं कि शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं के निदेशक मंडल में कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक होनी चाहिए। निदेशक मंडल की संरचना की समीक्षा से यह पता चला कि तालिका 3.4 और 3.5 में सूचीबद्ध सीपीएसई के निदेशक मंडल में 2021-22 के दौरान महिला निदेशक और स्वतंत्र महिला निदेशक की कमी थी।

तालिका 3.4: सीपीएसई जिनके निदेशक मंडल में महिला निदेशक नहीं थी

क्रम सं.	सीपीएसई ⁵³ का नाम	वर्ष 2021-22 के दौरान अनुपालन न होने की अवधि
1.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	अप्रैल से नवंबर
2.	एनएचपीसी लिमिटेड	अप्रैल से नवंबर
3.	एनटीपीसी लिमिटेड	अप्रैल से नवंबर
4.	मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	अप्रैल से अक्टूबर
5.	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	अप्रैल से नवंबर
6.	गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	अप्रैल से मार्च
7.	मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड	अप्रैल से दिसंबर
8.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	अप्रैल से जून
9.	राइट्स लिमिटेड	अप्रैल से नवंबर
10.	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	अगस्त से मार्च
11.	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	जून से सितम्बर और दिसंबर से मार्च
12.	ऑयल इंडिया लिमिटेड	अप्रैल से नवंबर
13.	रेल विकास निगम लिमिटेड	अप्रैल से मार्च
14.	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	अप्रैल से अक्टूबर
15.	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	अप्रैल से नवंबर

⁵³ क्रमांक 1 से 5 तक उल्लिखित सीपीएसई के लिए, शेयर और बांड/डिबेंचर दोनों को 31 मार्च, 2022 तक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया था।

क्रम सं.	सीपीएसई ⁵³ का नाम	वर्ष 2021-22 के दौरान अनुपालन न होने की अवधि
16.	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	अप्रैल से अक्टूबर
17.	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	अप्रैल से अक्टूबर
18.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	अप्रैल से अक्टूबर
19.	मिश्रधातु निगम लिमिटेड	अप्रैल से मार्च
20.	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	अप्रैल से दिसंबर

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा गया है, 71 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 20 (28 प्रतिशत) में 2021-22 पूरी/आंशिक अवधि के दौरान निदेशक मंडल में कोई महिला निदेशक नहीं थी।

तालिका 3.5: शीर्ष 1,000 संस्थाओं के भीतर सूचीबद्ध सीपीएसई जिनके निदेशक मंडल में महिला स्वतंत्र निदेशक नहीं थी

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	वर्ष 2021-22 के दौरान अनुपालन न होने की अवधि
1.	गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	अप्रैल से मार्च
2.	मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड	अप्रैल से दिसंबर
3.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	अप्रैल से नवंबर
4.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	अप्रैल से नवंबर
5.	राइट्स लिमिटेड	अप्रैल से नवंबर
6.	रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	अप्रैल से मार्च
7.	इंडियन रेल्वे कैटरिंग एण्ड टुरिज़म कॉर्पोरेशन लिमिटेड	अप्रैल से मार्च
8.	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	अप्रैल से अक्टूबर
9.	ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	अप्रैल से अक्टूबर
10.	हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड	अप्रैल से नवंबर
11.	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	अगस्त से मार्च
12.	रेल विकास निगम लिमिटेड	अप्रैल से मार्च

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	वर्ष 2021-22 के दौरान अनुपालन न होने की अवधि
13.	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	अप्रैल से अक्टूबर
14.	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	अप्रैल से नवंबर
15.	गेल (इंडिया) लिमिटेड	अगस्त से नवंबर
16.	एनएचपीसी लिमिटेड	अप्रैल से नवंबर
17.	केआईओसीएल लिमिटेड	अप्रैल से अक्टूबर
18.	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	अप्रैल से अक्टूबर
19.	एनटीपीसी लिमिटेड	अप्रैल से नवंबर
20.	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	अप्रैल से अक्टूबर
21.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	अप्रैल से अक्टूबर
22.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	अप्रैल से अक्टूबर
23.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	अप्रैल से अक्टूबर
24.	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	अप्रैल से जनवरी
25.	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	अप्रैल से अक्टूबर
26.	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	अप्रैल से फरवरी
27.	एचएमटी लिमिटेड	मार्च
28.	बामरलॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	अप्रैल से नवंबर
29.	एंड्रयूयूल एंड कंपनी लिमिटेड	अप्रैल से अक्टूबर
30.	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	अप्रैल से नवंबर
31.	मेटलस्क्रेप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड	दिसंबर से मार्च
32.	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	अप्रैल से मार्च
33.	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	अप्रैल से मार्च
34.	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	अप्रैल से अक्टूबर
35.	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	अप्रैल से दिसंबर
36.	कोल इंडिया लिमिटेड	अप्रैल से मार्च
37.	आईएफसीआई लिमिटेड	अप्रैल से मार्च

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	वर्ष 2021-22 के दौरान अनुपालन न होने की अवधि
38.	ऑयल इंडिया लिमिटेड	अप्रैल से नवंबर
39.	एनएमडीसी लिमिटेड	अप्रैल से मार्च
40.	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	अप्रैल से जनवरी
41.	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ऑफ त्रावणकोर लिमिटेड	अप्रैल से मार्च

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा गया है, 71 में से 41 सीपीएसई (58 प्रतिशत), जो शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध संस्थाओं में शामिल हैं, उनके बोर्ड में 2021-22 के पूरी/आंशिक अवधितक कोई महिला स्वतंत्र निदेशक नहीं थी।

3.2.4 बोर्ड में निदेशकों की न्यूनतम संख्या

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1)(ग) में यह निर्दिष्ट किया गया है कि शीर्ष 2,000 सूचीबद्ध संस्थाओं के बोर्ड में कम से कम छह निदेशक होने चाहिए। बोर्ड के निदेशकों की संरचना की समीक्षा से यह सामने आया कि तालिका 3.6 में सूचीबद्ध सीपीएसई के बोर्ड में आवश्यक संख्या में निदेशक नहीं थे।

तालिका 3.6: शीर्ष 2,000 संस्थाओं में शामिल सीपीएसई जिनके बोर्ड में छह से कम निदेशक थे

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	वर्ष 2021-22 के दौरान अनुपालन न होने की अवधि
1.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	अप्रैल से अक्टूबर
2.	मझगांव डॉकशिप बिल्डर्स लिमिटेड	अप्रैल से दिसंबर
3.	इंडियन रेलवे कैटरिंग टुरिज़म कॉर्पोरेशन लिमिटेड	अप्रैल से नवंबर
4.	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	अप्रैल से मार्च
5.	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	अप्रैल से मार्च
6.	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	अप्रैल से मार्च
7.	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	अगस्त से जनवरी

जैसा कि उपर्युक्ततालिका में देखा गया है, 71 में से सात सीपीएसई (10 प्रतिशत), जो शीर्ष 2,000 सूचीबद्ध संस्थाओं में शामिल हैं, के बोर्ड में 2021-22 के पूरे/आंशिक अवधि के दौरान छह से कम निदेशक थे।

3.2.5 बोर्ड निदेशक की बैठकों में कोरम

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के नियम 17 (2A) के अनुसार, शीर्ष 2,000 सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए बोर्ड की प्रत्येक बैठक में कोरम की आवश्यकता उसकी कुल सदस्यों की संख्याका एक तिहाई या तीन निदेशक, जो भी अधिक हो, जिसमें कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक शामिल हो, होनी चाहिए। हालांकि, सीपीएसई के संबंध में जो तालिका 3.7 में उल्लिखित हैं, बोर्ड बैठकों में अपर्याप्त कोरम था।

तालिका 3.7: बोर्ड बैठकों में अपर्याप्त कोरम वाली सीपीएसई

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिसमें स्वतंत्र निदेशक अनुपस्थित थे	कमी प्रतिशत में)
1.	गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	7	3	43
2.	मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड	9	6	67
3.	राइट्स लिमिटेड	8	4	50
4.	इंडियन रेलवे कैटरिंग टुरिज़म कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8	5	63
5.	हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड	7	6	86
6.	तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड	5	5	100
7.	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	9	5	56
8.	एनएचपीसी लिमिटेड	10	5	50
9.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	6	4	67
10.	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	12	7	58
11।	एनटीपीसी लिमिटेड	15	5	33
12.	आईटीआई लिमिटेड	7	1	14
13.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	5	3	60

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिसमें स्वतंत्र निदेशक अनुपस्थित थे	कमी प्रतिशत में)
14.	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	5	4	80
15.	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	8	2	25
16.	स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	7	6	86
17.	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	8	5	63
18.	कोचीन शिप यार्ड लिमिटेड	5	3	60
19.	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	5	4	80
20.	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	5	3	60
21.	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	12	6	50
22.	कोल इंडिया लिमिटेड	18	12	67
23.	एनएमडीसी लिमिटेड	9	6	67
24.	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	7	4	57
25.	आरईसी लिमिटेड	11	8	73

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा गया है, 71 में से 25 सीपीएसई (35 प्रतिशत), के बोर्ड बैठक के लिए आवश्यक कोरम 2021-22 के दौरान पूरा नहीं किया गया। कमी का प्रतिशत 14 से 100 प्रतिशत के बीच था।

3.3 स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और कार्यप्रणाली

3.3.1 स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति, पुनः नियुक्ति और अवधि

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के नियम 25(8) के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों से स्वतंत्र स्थिति का घोषणा पत्र लिया जाना चाहिए। हालांकि, एक सीपीएसई (ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड) के मामले में, इसका पालन नहीं किया गया था।

3.3.2 स्वतंत्र निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के नियम 17(10) के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किया जाएगा, जिसमें (क) निदेशकों का निष्पादन, (ख) स्वतंत्रता मानदंडों को पूरा करना और उनके प्रबंधन से स्वतंत्रता शामिल हैं, बशर्ते कि मूल्यांकन में वे निदेशक भाग न लें जिनका मूल्यांकन किया जा रहा है। हालांकि, तालिका 3.8 में सूचीबद्ध सीपीएसई के मामले में, स्वतंत्र निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा नहीं किया गया था।

तालिका 3.8: सीपीएसई जहाँ स्वतंत्र निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा नहीं किया गया

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1	एनटीपीसी लिमिटेड
2	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
3	आरईसी लिमिटेड

71 में से तीन सीपीएसई (4 प्रतिशत) के मामले में, स्वतंत्र निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा 2021-22 के दौरान नहीं किया गया था।

3.4 निदेशक मंडल और समितियों की बैठकें

3.4.1 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड समितियों की बैठकें जिनमें स्वतंत्र निदेशकों को भाग लेना चाहिए

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची IV (III) (3) में कहा गया है कि स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड समिति की सभी बैठकों में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए, जिनके वे सदस्य हैं। हालांकि, कुछ स्वतंत्र निदेशकों ने इन बैठकों में से कुछ में भाग नहीं लिया। तालिका 3.9 में उन स्वतंत्र निदेशकों की संख्या दर्शाई गई है जिन्होंने बोर्ड और समिति की बैठकों में से कम से कम 80 प्रतिशत बैठकों में भाग नहीं लिया।

तालिका 3.9: सीपीएसई जहाँ स्वतंत्र निदेशकों ने बोर्ड/ समिति की बैठकों में से कम से कम 80 प्रतिशत बैठकों में भाग नहीं लिया

क्रम सं.	सीपीएसई ⁵⁴ का नाम	स्वतंत्र निदेशकों की संख्या
1.	एनएमडीसी लिमिटेड	1
2.	सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड	1
3.	राष्ट्रीय केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	1
4.	रेल विकास निगम लिमिटेड	1
5.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	1
6.	जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1
7.	एचएमटी लिमिटेड	1

जैसा कि उपर्युक्ततालिका में देखा गया है, 71 सूचीबद्ध सीपीएसई में से सात (10 प्रतिशत) में स्वतंत्र निदेशकों ने 2021-22 के दौरान बोर्ड और समितियों की बैठकों में से कम से कम 80 प्रतिशत बैठकों में भाग नहीं लिया।

3.4.2 कंपनी की सामान्य बैठकों में भाग लेना

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची IV (III) (5) में कहा गया है कि स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी की सभी सामान्य बैठकों में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए। तालिका 3.10 में उन सूचीबद्ध सीपीएसई का उल्लेख है जिनमें से एक या एक से अधिक स्वतंत्र निदेशकों ने सामान्य बैठकों में भाग नहीं लिया।

तालिका 3.10: सीपीएसई जहाँ स्वतंत्र निदेशकों ने सामान्य बैठकों में भाग नहीं लिया

क्रम सं.	सीपीएसई ⁵⁵ का नाम
1.	राष्ट्रीय केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
2.	भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
3.	एचएमटी लिमिटेड

⁵⁴ क्रमांक 1 और 2 में उल्लिखित सीपीएसई के लिए, शेयर और बांड/डिबेंचर दोनों को 31 मार्च, 2022 तक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थे।

⁵⁵ क्रम संख्या 1 और 2 में उल्लिखित सीपीएसई के लिए, शेयर और बांड/डिबेंचर दोनों को 31 मार्च, 2022 तक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थे।

क्रम सं.	सीपीएसई ⁵⁵ का नाम
4.	जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
5.	इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड

जैसा कि उपर्युक्ततालिका से यह देखा गया है, 71 सूचीबद्ध सीपीएसई में से पांच (7 प्रतिशत) में एक या एक से अधिक स्वतंत्र निदेशक सामान्य बैठक में उपस्थित नहीं थे।

3.4.3 कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की बैठकें

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन 25 (3) के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों को वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बैठक आयोजित करनी चाहिए, जिसमें गैर-स्वतंत्र निदेशक और प्रबंधन के सदस्य उपस्थित न हों, और सभी स्वतंत्र निदेशकों को ऐसी बैठक में उपस्थित होने का प्रयास करना चाहिए। तालिका 3.11 में उन सीपीएसईका उल्लेख है जिनके स्वतंत्र निदेशकों ने कम से कम एक बैठक आयोजित नहीं की, और तालिका 3.12 में उन सीपीएसईका उल्लेख है जहां सभी स्वतंत्र निदेशक 2021-22 के दौरान ऐसी बैठक में उपस्थित नहीं थे।

तालिका 3.11: सीपीएसई जहाँ स्वतंत्र निदेशकों ने कम से कम एक बैठक आयोजित नहीं की

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1	गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड
2.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
3.	भारत इम्यूनो लॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
4.	आईएफसीआई लिमिटेड
5.	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ऑफ त्रावण कोर लिमिटेड

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा गया है, 71 सीपीएसई में से पांच (7 प्रतिशत) में स्वतंत्र निदेशकों ने गैर-स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति के बिना कम से कम एक बैठक आयोजित नहीं की।

तालिका 3.12: सीपीएसई जहां सभी स्वतंत्र निदेशक बैठकों में उपस्थित नहीं थे

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम सितम्बर से अक्टूबर
1.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
2.	इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 71 सूचीबद्ध सीपीएसई में से दो सीपीएसई (3 प्रतिशत) में जहां सभी स्वतंत्र निदेशक, गैर-स्वतंत्र निदेशक की मौजूदगी के बिना स्वतंत्र निदेशकों की बैठकों में उपस्थित नहीं थे,

3.4.4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठकें

3.4.4.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173(3) के अनुसार, बोर्ड की बैठकें कम से कम सात दिन पहले लिखित नोटिस देकर बुलानी चाहिए। इसके अलावा, बोर्ड की बैठक को आपातकालीन व्यापार निपटाने के लिए कम नोटिस पर बुलाया जा सकता है, बशर्ते कि कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक, यदि कोई हो, बैठक में उपस्थित हो। आगे यह प्रावधान है कि यदि स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में ऐसी बैठक होती है, तो उस बैठक में लिए गए निर्णय सभी निदेशकों को भेजे जाएंगे और केवल तब ही अंतिम होंगे जब कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा उन्हें स्वीकृति दी जाएगी। तालिका 3.13 में यह दर्शाया गया है कि बोर्ड की बैठकें सात दिन पहले नोटिस दिए बिना बुलाई गई थीं और बोर्ड की बैठकें कम समय के नोटिस पर आयोजित की गईं, जिसमें कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक की उपस्थिति नहीं थी और ऐसी बैठक में लिए गए निर्णयों को कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया था।

तालिका 3.13: सीपीएसई जहाँ बोर्ड की बैठकें सात दिन पहले नोटिस दिए बिना बुलाई गईं

क्रम सं.	सीपीएसई 56का नाम	बोर्ड बैठकों की कुल संख्या	सात दिन का नोटिस दिए बिना बुलाई गई बैठकों की संख्या	सात दिन से कम समय में नोटिस देने में कमी का प्रतिशत
1.	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	12	2	17
2.	आईएफसीआई लिमिटेड	9	1	11
3	कोल इंडिया लिमिटेड	18	5	28

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से यह देखा गया है कि 2021-22 के दौरान 71 में से तीन सीपीएसई (4 प्रतिशत) में बोर्ड की बैठकें सात दिन पहले नोटिस दिए बिना बुलाई गईं, कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक उपस्थित नहीं था और ऐसी बैठकों में लिए गए निर्णयों को कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया था।

3.4.4.2 विनियमन 17(7) और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015 के अनुसूची II के भाग A में यह निर्धारित किया गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को संस्थान के संचालन की समीक्षा के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। उपर्युक्त विनियम के अनुसार जानकारी, सीपीएसई के संबंध में, जो तालिका 3.14 में दर्शाए गए हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रदान नहीं की गई थी।

तालिका 3.14: सीपीएसई जहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को विस्तृत जानकारी प्रदान नहीं की गई

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	जानकारी उपलब्ध नहीं
1.	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	i. वार्षिक परिचालन योजनाएँ ii. पूंजी और राजस्व बजट
2.	बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड	i. वार्षिक परिचालन योजनाएँ ii. पूंजी और राजस्व बजट

⁵⁶ क्रम संख्या 1 और 2 में उल्लिखित सीपीएसई के लिए, शेयर और बांड/डिबेंचर दोनों को 31 मार्च, 2022 तक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थे।

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	जानकारी उपलब्ध नहीं
3.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	समितियों की बैठकों का विवरण
4.	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	विदेशी मुद्रा जोखिम का त्रैमासिक विवरण
5.	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	लेखापरीक्षा समिति की बैठक का विवरण
6.	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ऑफ त्रावण कोर लिमिटेड	i. पूंजीगत बजट ii. विदेशी मुद्रा जोखिम का त्रैमासिक विवरण

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से यह देखा गया है कि 71 में से छह सीपीएसई (8 प्रतिशत) में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 2021-22 के दौरान विस्तृत जानकारी प्रदान नहीं की गई थी।

3.4.4.3 सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015 के विनियमन 46 (2) (क, छ और च) में यह निर्धारित किया गया है कि अपने व्यवसाय, संबंधित पार्टी लेन-देन से निपटने की नीति और गैर-कार्यकारी निदेशकों को भुगतान करने के मानदंडों की जानकारी, यदि वह वार्षिक रिपोर्ट में नहीं दी गई हो, तो कंपनी की वेबसाइट पर घोषित की जानी चाहिए। इसके अलावा, विनियमन 46 (2)(ग) में यह निर्धारित किया गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संरचना को उसकी वेबसाइट पर घोषित किया जाना चाहिए। हालांकि, यह जानकारी 2021-22 के दौरान दो सीपीएसई की वेबसाइट पर नहीं दी गई, जैसा कि तालिका 3.15 में उल्लेखित है।

तालिका 3.15: सीपीएसई जहाँ जानकारी वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं की गई

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	जानकारी का खुलासा नहीं किया गया
1.	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	i. संबंधित पक्ष लेन देन से निपटने की नीति। ii. निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों की संरचना।
2.	बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड	i. संबंधित पक्ष लेनदेन से निपटने की नीति। ii. निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों की संरचना।

3.5 स्वतंत्र निदेशकों का प्रशिक्षण

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) 2015 के विनियमन 25 (7) और अनुसूची (ड) के (ग) (2) (छ) में यह निर्धारित किया गया है कि कंपनी को स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी/उद्योग गतिविधियों, उनके भूमिकाओं, अधिकारों और जिम्मेदारियों तथा अन्य प्रासंगिक जानकारी से परिचित कराना चाहिए। स्वतंत्र निदेशकों को दिए गए प्रशिक्षण की जानकारी कंपनी की वेबसाइट पर प्रकाशित की जानी चाहिए, इसके अतिरिक्त वार्षिक रिपोर्ट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस खंड में वेब लिंक का उल्लेख किया जाना चाहिए। हालांकि, तालिका 3.16 में उल्लिखित सीपीएसई के संदर्भ में स्वतंत्र निदेशकों का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था और तालिका 3.17 में उल्लिखित सीपीएसई के संदर्भ में स्वतंत्र निदेशकों को दिए गए प्रशिक्षण के विवरण को उनकी वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं किया गया था।

तालिका 3.16: सीपीएसई जहाँ स्वतंत्र निदेशकों को प्रशिक्षण नहीं दिया गया

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1.	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
2.	इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड
3.	भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
4.	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
5.	आईएफसीआई लिमिटेड
6.	इंड बैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा गया है कि 71 में से छह सीपीएसई (8 प्रतिशत) में 2021-22 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।

तालिका 3.17: सीपीएसई जहाँ स्वतंत्र निदेशकों को दिए गए प्रशिक्षण के विवरण को उनकी वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं किया गया

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
2.	भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
3.	बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड
4.	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड
5.	मिश्र धातु निगम लिमिटेड

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा गया है कि 71 में से पांच सीपीएसई (7 प्रतिशत) में 2021-22 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को दिए गए प्रशिक्षण के विवरण को उनकी वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं किया गया था।

3.6 रिक्तियों को भरने में अंतराल

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 203(4) के अनुसार, यदि किसी पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कर्मों का पद रिक्त होता है, तो उस रिक्ति को छह महीने के भीतर बोर्ड की बैठक में भर लिया जाना चाहिए। हालांकि, सीपीएसई जो तालिका 3.18 में सूचीबद्ध हैं, में पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कर्मों की रिक्ति को बोर्ड द्वारा छह महीने के भीतर नहीं भरा गया था।

तालिका 3.18: सीपीएसई जहाँ पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंध कीयकर्मों की रिक्ति को छह महीने के भीतर बोर्ड द्वारा नहीं भरा गया

क्रम सं.	सीपीएसई ⁵⁷ का नाम
1.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
2.	आरईसी लिमिटेड
3.	राष्ट्रीय केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
4.	एनएलसी इंडिया लिमिटेड
5.	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
6.	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
7.	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड
8.	ऑयल इंडिया लिमिटेड

⁵⁷ क्रम संख्या 1 और 2 में उल्लिखित सीपीएसई के लिए, शेयर और बांड/डिबेंचर दोनों को 31 मार्च, 2022 तक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थे।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा गया है कि 71 मेंसे आठ सीपीएसई (11 प्रतिशत) में 2021-22 के दौरान पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कर्मों की रिक्ति छह महीने के भीतर नहीं भरी गई थी।

3.7 विविध

3.7.1 सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) नियम 2015 के अनुसूची V के भाग ग (6) और नियम 34 (3) के अनुसार, कंपनी के वार्षिक रिपोर्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में निदेशकों को दी गई वेतन और अन्य लाभों के संबंध में निम्नलिखित खुलासे होने चाहिए: (i) गैर-कार्यकारी निदेशकों के कंपनी के साथ सभी वित्तीय लेन-देन, (ii) गैर-कार्यकारी निदेशकों को भुगतान करने का मानदंड, (iii) प्रत्येक निदेशक के वेतन, लाभ, बोनस, स्टॉक विकल्प, पेंशन आदि के मुख्य समूहों के अंतर्गत वेतन पैकेज का सारांश, (iv) निश्चित घटक और निष्पादन लिंक प्रोत्साहन के विवरण के साथ निष्पादन मापदंड, (v) सेवा अनुबंध, नोटिस अवधि, सेवरेंस शुल्क, और (vi) स्टॉक विकल्प विवरण, छूट अवधि आदि। हालांकि, यह दो सीपीएसई (रेल विकास निगम लिमिटेड और मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड) के संदर्भ में 2021-22 में अनुपालन नहीं किया गया।

3.7.2 डीपीई दिशा-निर्देश 2010 के पैरा 8.3 के अनुसार, कंपनी को प्रत्येक तिमाही के समापन के 15 दिनों के भीतर निर्धारित प्रारूप में अपनी प्रगति रिपोर्ट संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को भेजनी चाहिए। हालांकि, यह अनुपालन सीपीएसई के संदर्भ में नहीं किया गया, जैसा कि तालिका 3.19 में विस्तार से बताया गया है।

तालिका 3.19: सीपीएसई जहाँ तिमाही प्रगतिरिपोर्ट 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत नहीं की गई

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1.	कोल इंडिया लिमिटेड
2.	हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड
3.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
4.	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
5.	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ऑफ त्रावण कोर लिमिटेड

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा गया है कि 71 में से पाँच सीपीएसई (7 प्रतिशत) ने प्रत्येक तिमाही के समापन के 15 दिनों के भीतर प्रशासनिक मंत्रालय को तिमाही प्रगति रिपोर्ट 2021-22 के दौरान नहीं प्रस्तुत की।

3.7.3 सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) नियम 2015 के अनुसूची (V) के भाग (C)(2) (ज) के अनुसार, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में एक चार्ट या मैट्रिक्स होना चाहिए, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता की सूची दी गई हो, जिसमें बोर्ड द्वारा पहचान की गई मुख्य कौशल/विशेषज्ञता/क्षमताओं की सूची शामिल हो, जो उसके व्यवसाय(ओं) और क्षेत्र(ओं) के संदर्भ में प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक हैं, और जो वास्तव में बोर्ड में उपलब्ध हैं, साथ ही उन निदेशकों के नाम जिन के पास ऐसे कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता हैं। हालांकि, यह अनुपालन सीपीएसई के संदर्भ में नहीं किया गया, जैसा कि तालिका 3.20 में विस्तार से बताया गया है।

तालिका 3.20: सीपीएसई जहाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में मुख्य कौशल/विशेषज्ञता/क्षमताओं की सूची को निर्दिष्ट करने वाला चार्ट/मैट्रिक्स नहीं था

क्रम सं.	सीपीएसई ⁵⁸ का नाम
1.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
2.	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
3.	सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड
4.	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
5.	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
6.	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
7.	आरईसी लिमिटेड
8.	बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड
9.	हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड
10.	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
11.	गेल (इंडिया) लिमिटेड
12.	बामरलॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड

⁵⁸ क्रम संख्या 1 और 7 में उल्लिखित सीपीएसई के लिए, शेयर और बांड/डिबेंचर दोनों को 31 मार्च, 2022 तक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थे।

क्रम सं.	सीपीएसई ⁵⁸ का नाम
13.	केआईओसीएल लिमिटेड
14.	एनएलसी इंडिया लिमिटेड
15.	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
16.	ट्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
17.	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
18.	एचएमटी लिमिटेड
19.	बामरलॉरी एंड कंपनी लिमिटेड
20.	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड
21.	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा गया है कि 71 में से 21 सीपीएसई (30 प्रतिशत) में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता का चार्ट या मैट्रिक्स 2021-22 के दौरान शामिल नहीं था।

3.7.4 सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) (नियम 2015 के अनुसूची(V) के भाग (ग) (2) (i) के अनुसार, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में यह पुष्टि होनी चाहिए कि बोर्ड के अनुसार, स्वतंत्र निदेशक इन नियमों में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं और वे प्रबंधन से स्वतंत्र हैं। हालांकि, यह अनुपालन सीपीएसई के संदर्भ में नहीं किया गया, जैसा कि तालिका 3.21 में विस्तार से बताया गया है।

तालिका 3.21: सीपीएसई जहाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में स्वतंत्र निदेशकों के बारे में बोर्ड की पुष्टि शामिल नहीं थी

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1.	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
2.	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड
3.	मेटल स्ट्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा गया है कि 71 में से तीन सीपीएसई (4 प्रतिशत) में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में बोर्ड से यह पुष्टि नहीं थी कि स्वतंत्र निदेशक बोर्ड से स्वतंत्र हैं और 2021-22 के दौरान आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं।

3.8 लेखापरीक्षा समिति

3.8.1 लेखा परीक्षा समिति की संरचना:

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015 की विनियमन 18 में निम्नलिखित निर्धारित किया गया है:

3.8.1.1 प्रत्येक सूचीबद्ध संस्था को एक योग्य और स्वतंत्र लेखापरीक्षा समिति का गठन करना चाहिए। हालांकि, 71 में से 11 सीपीएसई (15 प्रतिशत) के संदर्भ में वर्ष 2021-22 की पूरी/आंशिक अवधि के दौरान यह अनुपालन नहीं किया गया था, जैसा कि तालिका 3.22 में विस्तार से दिया गया है।

तालिका 3.22: सीपीएसई जहाँ लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया

क्र. म. सं.	सीपीएसई ⁵⁹ का नाम	वर्ष 2021-22 के दौरान कमी की अवधि
1.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	अप्रैल से नवंबर
2.	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	अप्रैल से अक्टूबर
3.	बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड	अप्रैल से मार्च
4.	गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	अप्रैल से मार्च
5.	मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड	अप्रैल से दिसंबर
6.	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	अप्रैल से अक्टूबर
7.	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	अप्रैल से नवंबर
8.	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	अप्रैल से दिसंबर
9.	कोल इंडिया लिमिटेड	अप्रैल से अक्टूबर
10.	ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	अप्रैल से अक्टूबर
11.	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	अप्रैल से दिसंबर

3.8.1.2 लेखापरीक्षा समिति के दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे। हालांकि यह अनुपालन सीपीएसई के संदर्भ में नहीं किया गया जैसा कि तालिका 3.23 में विस्तार से बताया गया है

⁵⁹ क्रमांक 1 और 10 में उल्लिखित सीपीएसई के लिए, शेयर और बांड/डिबेंचर दोनों को 31 मार्च, 2022 तक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थे।

**तालिका 3.23: सीपीएसई जहां लेखापरीक्षा समिति के दो तिहाई सदस्य
स्वतंत्र निदेशक नहीं थे**

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	लेखापरीक्षा समिति में निदेशकों की कुल संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यक संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या	कमी (प्रतिशत में)	कमी की अवधि वर्ष 2021-22 के दौरान कमी
1.	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	3	2	1	1 (50)	अगस्त से दिसंबर
2.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3	2	1	1 (50)	अप्रैल से नवंबर
3.	राइट्स लिमिटेड	3	2	0	2 (100)	अप्रैल से अक्टूबर
4.	इंडियन रेलवे कैटरिंग टुरिज़्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3	2	0	2 (100)	अप्रैल से अक्टूबर
5.	ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2	2	1	1 (50)	अप्रैल से अक्टूबर
6.	हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड	3	2	0	2 (100)	अप्रैल से फरवरी
7.	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	3	2	1	1 (50)	अगस्त से दिसंबर
8.	तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड	3	2	0	2 (100)	अप्रैल से मार्च
9.	रेल विकास निगम लिमिटेड	3	2	1	1 (50)	अप्रैल से अक्टूबर
10.	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	3	2	0	2 (100)	अप्रैल से नवंबर
11.	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	3	2	1	1 (50)	अगस्त से नवंबर

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	लेखापरीक्षा समिति में निदेशकों की कुल संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यक संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या	कमी (प्रतिशत में)	कमी की अवधि वर्ष 2021-22 के दौरान कमी
12.	गेल(इंडिया) लिमिटेड	3 3	2 2	1 0	1 (50) 2 (100)	अप्रैल से जुलाई अगस्त से नवंबर
13.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3	2	1	1 (50)	जुलाई से नवंबर
14.	बामरलॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	3	2	1	1 (50)	अप्रैल से मार्च
15.	एनएचपीसी लिमिटेड	3	2	0	2 (100)	अप्रैल से नवंबर
16.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	3	2	0	2 (100)	अप्रैल से दिसंबर
17.	एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड	3	2	1	1 (50)	अप्रैल से दिसंबर
18.	एनटीपीसी लिमिटेड	3	2	0	2 (100)	जुलाई से दिसंबर
19.	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	3	2	1	1 (50)	अप्रैल से जनवरी
20.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	3	2	0	2 (100)	अप्रैल से अक्टूबर
21.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	3	2	1	1 (50)	अप्रैल से अक्टूबर
22.	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	3	2	1	1 (50)	अप्रैल से दिसंबर
23.	मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	4	3	1	2 (67)	अप्रैल से दिसंबर
24.	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	3 3	2 2	1 0	1 (50) 2 (100)	अप्रैल से जुलाई अगस्त से नवंबर

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	लेखापरीक्षा समिति में निदेशकों की कुल संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यक संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या	कमी (प्रतिशत में)	कमी की अवधिवर्ष 2021-22 के दौरान कमी
25.	मेटलस्क्रेपट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3	2	1	1 (50)	अप्रैल से अक्टूबर
26.	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	3	2	0	2 (100)	अप्रैल से जुलाई
27.	आरईसी लिमिटेड	3	2	0	2 (100)	अप्रैल से नवंबर
28.	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ऑफ त्रावण कोर लिमिटेड	3	2	1	1 (50)	अप्रैल से मार्च

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा गया है, 71 में से 28 सीपीएसई (39 प्रतिशत) में 2021-22 के वर्ष के पूरे/आंशिक अवधि के दौरान लेखापरीक्षा समिति के दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक नहीं थे, कमी का प्रतिशत 50 से 100 प्रतिशत के बीच रहा था।

3.8.1.3 लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को एक स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए। हालांकि, यह अनुपालन नहीं किया गया था, जैसा कि तालिका 3.24 में विवरणित सीपीएसई के संदर्भ में देखा गया है।

तालिका 3.24: सीपीएसई जहाँ लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक नहीं थे

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	वर्ष 2021-22 के दौरान कमी की अवधि
1.	राइट्स लिमिटेड	अप्रैल से अक्टूबर
2.	इंडियन रेलवे कैटरिंग टुरिज़्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड	अप्रैल से अक्टूबर
3.	हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड	अप्रैल से फरवरी
4.	तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड	अप्रैल से मार्च
5.	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	अप्रैल से नवंबर
6.	एनटीपीसी लिमिटेड	जुलाई से दिसंबर
7.	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	अगस्त से जनवरी

जैसा कि उपर्युक्त की तालिका में देखा गया है, 71 में से सात सीपीएसई (10 प्रतिशत) में 2021-22 के वर्ष के पूरे/आंशिक अवधि के दौरान लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक नहीं थे,

3.8.2 लेखापरीक्षा समिति के सदस्य की वित्तीय साक्षरता

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 18 (1) (ग) के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति के सभी सदस्य वित्तीय रूप से साक्षर होने चाहिए और कम से कम एक सदस्य को लेखांकन या संबंधित वित्तीय प्रबंधन का विशेषज्ञता होना चाहिए। हालांकि, यह अनुपालन नहीं किया गया था, जैसा कि तालिका 3.25 में विवरणित सीपीएसई के संदर्भ में देखा गया है:

तालिका 3.25: सीपीएसई जहाँ लेखापरीक्षा समिति की वित्तीय साक्षरता से संबंधित विनियमन का पालन नहीं किया गया

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1.	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
2.	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
3.	मेटलस्क्रेपट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड
4.	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड

जैसा कि उपर्युक्त दी गई तालिका से देखा गया है, 2021-22 के दौरान 71 सीपीएसई में से चार (6 प्रतिशत) सीपीएसई में, लेखापरीक्षा समिति से संबंधित वित्तीय साक्षरता के नियमों का पालन नहीं किया गया था।

3.8.3 लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 18(2) (क) के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति को हर साल कम से कम चार बार बैठक करनी चाहिए, और किसी भी दो बैठकों के बीच अधिकतम 120 दिनों का अंतराल होना चाहिए। हालांकि, तालिका 3.26 में उल्लिखित सीपीएसई में कम से कम चार लेखापरीक्षा समिति की बैठकें आयोजित नहीं की गईं।

तालिका 3.26: सीपीएसई जहाँ कम से कम चार लेखापरीक्षा समिति की बैठकें नहीं आयोजित की गईं

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	आयोजित बैठकों की संख्या
1.	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	0
2.	मझगांव डॉकशिप बिल्डर्स लिमिटेड	2
3.	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	1
4.	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	2
5.	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	2
6.	मिश्रधातु निगम लिमिटेड	0
7.	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	2
8.	एनएमडीसी लिमिटेड	3

जैसा कि उपर्युक्त दी गई तालिका से देखा गया है, 71 सीपीएसई में से आठ (11 प्रतिशत) सीपीएसई में, लेखापरीक्षा समिति की कम से कम चार बैठकें 2021-22 के दौरान आयोजित नहीं की गईं।

इसके अलावा, तालिका 3.27 में उल्लिखित सीपीएसई के संबंध में, दो लेखापरीक्षा समिति बैठकों के बीच का अंतराल 120 दिनों से अधिक था।

तालिका 3.27: सीपीएसई जिनके लेखापरीक्षा समिति बैठकों के बीच 120 दिनों से अधिक का अंतराल था

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	ऐसे मामलों की संख्या जब अंतराल 120 दिनों से अधिक था	अन्तराल (दिनों में)
1.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1	157
2.	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	1	145
3.	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	1	456
4.	कोल इंडिया लिमिटेड	1	453
5.	एनएमडीसी लिमिटेड	1	365

जैसा कि उपर्युक्त की तालिका में दिखाया गया है, 71 सीपीएसई में से पांच (7 प्रतिशत) सीपीएसई में वर्ष 2021-22 के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की दो बैठकों के बीच 120 दिनों से अधिक का अंतराल था।

3.8.4 लेखापरीक्षा समिति बैठकों का कोरम

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) नियम 2015 के विनियमन 18(2) (ख) और डीपीई दिशा निर्देश 2010 के पैरा 4.4 के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति बैठकों के कोरम की आवश्यकता (अर्थात्, दो सदस्य या लेखापरीक्षा समिति के एक तिहाई सदस्य, जो भी अधिक हो, जिसमें कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक हों) है। तालिका 3.28 में दिखाए गए सीपीएसई के संबंध में लेखापरीक्षा समिति बैठकों में कोरम अपर्याप्त था।

तालिका 3.28: लेखापरीक्षा समिति बैठकों के लिए अपूर्ण कोरम वाले सीपीएसई

क्रम सं.	सीपीएसई ⁶⁰ का नाम	आयोजित बैठकों की संख्या	अपूर्ण कोरम वाली बैठकों की संख्या (प्रतिशत में)	अपूर्ण कोरम वाली बैठकों का प्रतिशत
1.	मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	12	9	75
2.	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5	4	80
3.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	7	2	29
4.	एनएचपीसी लिमिटेड	10	6	60
5.	सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड	4	3	75
6.	एनटीपीसी लिमिटेड	8	4	50
7.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	4	2	50
8.	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5	3	60
9.	आरईसी लिमिटेड	6	3	50
10.	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	5	2	40
11.	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	13	11	85

⁶⁰ क्रमांक 1 से 9 तक उल्लिखित सीपीएसई के लिए, शेयर और बांड/डिबेंचर दोनों को 31 मार्च, 2022 तक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थे।

क्रम सं.	सीपीएसई ⁶⁰ का नाम	आयोजित बैठकों की संख्या	अपूर्ण कोरम वाली बैठकों की संख्या (प्रतिशत में)	अपूर्ण कोरम वाली बैठकों का प्रतिशत
12.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8	6	75
13.	रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	5	4	80
14.	इंडियन रेलवे कैटरिंग टुरिज़म कॉर्पोरेशन लिमिटेड	6	3	50
15.	हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड	5	5	100
16.	तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड	5	5	100
17.	रेलविकास निगम लिमिटेड	4	3	75
18.	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	10	6	60
19.	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	4	2	50
20.	गेल (इंडिया) लिमिटेड	11	6	55
21.	बामरलॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	4	3	75
22.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	6	4	67
23.	एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड	8	6	75
24.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	4	3	75
25.	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	6	3	50
26.	मेटल स्कैपट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड	6	4	67
27.	स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	6	5	83

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा गया है कि 71 सीपीएसई में से 27 (38 प्रतिशत) में लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए आवश्यक कोरम अपर्याप्त था।

3.8.5 लेखापरीक्षा समिति द्वारा सूचना/दस्तावेजों की समीक्षा:

3.8.5.1 सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 18(3) और अनुसूची II के भाग (ग) (क) के अंतर्गत यह निर्धारित किया गया है कि लेखापरीक्षा समिति को इन विनियमों में उल्लिखित कुछ मामलों की समीक्षा करनी चाहिए। हालांकि, लेखापरीक्षा समिति ने तालिका 3.29 में दर्शाए गए सीपीएसई के संदर्भ में इन मामलों में से एक या अधिक की समीक्षा नहीं की।

तालिका 3.29: सीपीएसई जहां अपेक्षित सूचना की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा नहीं की गई

क्रम सं.	सेबी विनियमन	समीक्षा की जाने वाली जानकारी	सीपीएसई का नाम
1.	विनियमन 18(3) और विनियमनों की अनुसूची II के भाग (ग) (क) (4)	अनुमोदन हेतु बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करें।	1. ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
2.	विनियमन 18(3) और विनियमनों की अनुसूची II के भाग (ग) (क) (7)	लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता और लेखापरीक्षा का निष्पादन और प्रभावशीलता।	1. मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
3.	विनियमन 18(3) और विनियमनों की अनुसूची II के भाग (ग) (क) (11)	आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन करें।	1. ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2. मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड 3. नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड 4. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड 5. फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ऑफ त्रावणकोर लिमिटेड
4.	विनियमन 18(3) और विनियमनों की अनुसूची II के भाग (ग) (क) (12)	प्रबंधन के साथ मिलकर वैधानिक, आंतरिक लेखापरीक्षकों के कार्य निष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना।	1. राइट्स लिमिटेड 2. मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड 3. नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड

क्रम सं.	सेबी विनियमन	समीक्षा की जाने वाली जानकारी	सीपीएसई का नाम
5.	विनियमन 18(3) और विनियमनों की अनुसूची II के भाग (ग) (क) (13)	आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की स्टाफिंग और वरिष्ठता, आंतरिक लेखापरीक्षा में रिपोर्टिंग संरचना कवरेज और आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करें।	1. हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड 2. बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड 3. मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड 4. नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड 5. बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड 6. मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड. 7. स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
6.	विनियमन 18(3) और विनियमनों की अनुसूची II के भाग(C) (A) (14)	आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर चर्चा करें और उसके आधार पर अनुवर्ती कार्यवाही करें।	1. मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड 2. नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड 3. बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड 4. स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
7.	विनियमन 18(3) और विनियमनों की अनुसूची II के भाग(C) (A) (16)	लेखापरीक्षा शुरू होने से पहले वैधानिक लेखापरीक्षकों के साथ लेखापरीक्षा की प्रकृति और दायरे के बारे में चर्चा करें तथा लेखापरीक्षा के बाद चर्चा करके चिंता के किसी भी क्षेत्र का पता लगाएं।	1. राइट्स लिमिटेड 2. ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड 3. रेलविकास निगम लिमिटेड 4. कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 5. बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड 6. मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

क्रम सं.	सेबी विनियमन	समीक्षा की जाने वाली जानकारी	सीपीएसई का नाम
			7. नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड 8. इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड 9. बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड 10. एंड्रयूयूल एंड कंपनी लिमिटेड 11. मेटल स्क्रेप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड 12. स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 13. हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड 14. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड 15. भारत डायनेमिक्स लिमिटेड 16. फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ऑफ त्रावणकोर लिमिटेड

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा गया है कि 2021-22 के दौरान, सीपीएसई में एक से लेकर 16 तक की संख्या में लेखापरीक्षा समिति द्वारा आवश्यक जानकारी की समीक्षा नहीं की गई।

3.8.5.2 सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 18(3) और अनुसूची II के भाग (ग) (ख) के अंतर्गत यह निर्धारित किया गया है कि लेखापरीक्षा समिति को इन विनियमों में उल्लिखित कुछ मामलों की अनिवार्य रूप से समीक्षा करनी चाहिए। हालांकि, सीपीएसई की लेखापरीक्षा समिति ने 2021-22 के दौरान इन मामलों में से एक या अधिक की समीक्षा नहीं की, जैसा कि तालिका 3.30 में दर्शाया गया है:

**तालिका 3.30: सीपीएसई जहां आवश्यक जानकारी की लेखापरीक्षा समिति द्वारा
समीक्षा नहीं की गई**

क्रम सं.	सेबी विनियमन	समीक्षा की जाने वाली जानकारी	सीपीएसई का नाम
1.	विनियमन 18(3) और विनियमनों की अनुसूची II के भाग (ग) (ख) (2)	प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण (जैसा कि लेखापरीक्षा समिति द्वारा परिभाषित किया गया है)	1. हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड 2. नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड 3. भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड 4. फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ऑफ त्रावणकोर लिमिटेड
2.	विनियमन 18(3) और विनियमन 18(3) की अनुसूची II का भाग (ग) (ख) (3) और विनियमन 18(3) की अनुसूची II का भाग (ग) (ख) (1)	वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी प्रबंधन पत्र/आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के पत्र	1. नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
3	विनियमन 18(3) और विनियमनों की अनुसूची II के भाग (ग) (ख) (4)	आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट	1. हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड 2. नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
4	विनियमन 18(3) और विनियमनों की अनुसूची II के भाग (ग) (ख) (5)	मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति, निष्कासन, पारिश्रमिक की शर्तें	1. हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड 2. हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड

3.8.5.3 सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची II के भाग (ग) (क) (19) में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा कमेटी उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव और पृष्ठभूमि आदि का आकलन करने के बाद मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति को मंजूरी देगी। हालाँकि, एक सीपीएसई (इंड बैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड) के मामले में मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति के लिए लेखापरीक्षा कमेटी की मंजूरी नहीं ली गई थी।

3.9 वार्षिक सामान्य बैठक में अध्यक्ष की उपस्थिति

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 18 (1) (घ) में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होगा और वह शेयर धारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित रहेगा। हालाँकि, तालिका 3.31 में दर्शाए गए सीपीएसई के संबंध में, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित नहीं हुए।

तालिका 3.31: सीपीएसई जहां लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष वार्षिक सामान्य बैठक में शामिल नहीं हुए

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2.	गार्डनरीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड
3.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
4.	भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
5.	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
6.	कोचीन शिप यार्ड लिमिटेड
7.	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड
8.	कोल इंडिया लिमिटेड

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा गया है, 71 में से आठ सीपीएसई (11 प्रतिशत) में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष 2021-22 के दौरान वार्षिक सामान्य बैठक में शामिल नहीं हुए।

3.10 सतर्कता तंत्र

3.10.1 सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 का विनियमन 22(1) यह निर्धारित करता है कि सूची बद्ध इकाई निदेशकों और कर्मचारियों के लिए वास्तविक चिंताओं की रिपोर्ट करने के लिए सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी तैयार करेगी। हालाँकि, एक सीपीएसई (तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड) के संबंध में, इकाई ने 2021-22 के दौरान निदेशकों और कर्मचारियों के लिए वास्तविक चिंताओं की रिपोर्ट करने के लिए सतर्कता तंत्र तैयार नहीं किया।

3.10.2 सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 18(3) और विनियम की अनुसूची II के भाग ग (क) (18) में यह प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति की भूमिका में अन्य बातों के साथ-साथ व्हिसल ब्लोअर विधि के कामकाज की समीक्षा करना भी शामिल होगा। हालाँकि, तालिका 3.32 में दर्शाए गए सीपीएसई के संबंध में, लेखापरीक्षा समिति ने व्हिसल ब्लोअर विधि के कामकाज की समीक्षा नहीं की:

तालिका 3.32: सीपीएसई जहां लेखापरीक्षा समिति द्वारा व्हिसल ब्लोअर विधि की समीक्षा नहीं की गई

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1.	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2.	हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड
3.	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
4.	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
5.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
6.	एनटीपीसी लिमिटेड
7.	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड
8.	इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड
9.	मिश्र धातु निगम लिमिटेड
10.	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
11.	इंड बैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड
12.	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ऑफ त्रावणकोर लिमिटेड
13.	तमिलनाडु टेली कम्युनिकेशन लिमिटेड

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा गया है, 71 में से 13 सीपीएसई (18 प्रतिशत) में वर्ष 2021-22 के दौरान लेखापरीक्षा समिति द्वारा व्हिसल ब्लोअर विधि की समीक्षा नहीं की गई।

3.10.3 सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची V के भाग ग (10) (ग) में यह प्रावधान है कि वार्षिक रिपोर्ट में सतर्कता (क्रिया विधि) की स्थापना, व्हिसल ब्लोअर (पॉलिसी) के विवरण के बारे में प्रकटीकरण और

यह पुष्टि शामिल होगी कि किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति तक पहुँचने से मना नहीं किया गया है। हालाँकि, 71 सीपीएसई में से दो सीपीएसई (3 प्रतिशत) (मद्रास फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड और तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड) के संबंध में, वार्षिक रिपोर्ट में सतर्कता तंत्र के बारे में विवरण और यह पुष्टि शामिल नहीं थी कि किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति तक पहुँचने से मना नहीं किया गया था।

3.11 संबंधित पार्टी लेनदेन

3.11.1 सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 का विनियमन 23 (1) यह निर्धारित करता है कि सूचीबद्ध इकाई संबंधित पार्टी लेन देन की भौतिकता और संबंधित पक्ष लेन देन से निपटने के बारे में निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित स्पष्ट सीमा सहित एक नीति तैयार करेगी और ऐसी नीति की निदेशक मंडल द्वारा हर तीन साल में कम से कम एक बार समीक्षा की जाएगी और तदनुसार अद्यतन किया जाएगा। हालाँकि, 71 सीपीएसई में से दो सीपीएसई (3 प्रतिशत) (मद्रास फर्टिलजर्स लिमिटेड और इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड) के संबंध में, संस्थाओं ने 2021-22 के दौरान संबंधित पार्टी लेन देन की भौतिकता और संबंधित पार्टी लेन देन से निपटने के बारे में कोई नीति तैयार/समीक्षा/अद्यतन नहीं की।

3.11.2 सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 23 (9) में प्रावधान है कि सूची बद्ध इकाई अपने अर्ध वर्ष के एकल और समेकित वित्तीय परिणामों के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर, संबंधित पार्टी लेन-देन का प्रकटीकरण समेकित आधार पर, वार्षिक परिणामों के लिए प्रासंगिक लेखांकन मानकों में निर्दिष्ट प्रारूप में स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत करेगी और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगी। हालाँकि, एक सीपीएसई (बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड) के संबंध में, विनियमन के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज को प्रकटीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया था, जबकि तालिका 3.33 में विस्तृत सीपीएसई के संबंध में, स्टॉक एक्सचेंज को प्रकटीकरण किया गया था, हालाँकि, इसे वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं किया गया था।

तालिका 3.33: सीपीएसई जहांस्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत प्रकटीकरण वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं किया गया

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1.	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
2.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
3.	बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा गया है, 71 सीपीएसई में से तीन सीपीएसई (4 प्रतिशत) द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत किया गया खुलासा वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं किया गया।

3.12 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

3.12.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(1), कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के नियम 6 और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 19(1) और (2) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक मंडल को कम से कम तीन निदेशकों वाली एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन करना होगा, जिनमें से सभी गैर-कार्यकारी निदेशक होने चाहिए और कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए और समिति का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होगा। हालाँकि, तालिका 3.34 में दर्शाए गए सीपीएसई के संबंध में, 2021-22 के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया गया था।

तालिका 3.34: सीपीएसई जो नामांकन और पारिश्रमिक समिति गठित करने में विफल रहे

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम ⁶¹	वर्ष 2021-22 के दौरान कमी की अवधि
1.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	अप्रैल से नवंबर
2.	बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड	अप्रैल से मार्च
3.	गार्डनरीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	अप्रैल से मार्च

⁶¹ क्रम संख्या 1 और 12 में उल्लिखित सीपीएसई के लिए, शेयर और बांड/डिबेंचर दोनों को 31 मार्च, 2022 तक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थे /

4.	मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड	अप्रैल से दिसंबर
5.	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	अप्रैल से अक्टूबर
6.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	अप्रैल से जनवरी
7.	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	अप्रैल से अक्टूबर
8.	कोचीन शिप यार्ड लिमिटेड	अप्रैल से नवंबर
9.	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	अप्रैल से दिसंबर
10.	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	अप्रैल से मार्च
11.	कोल इंडिया लिमिटेड	अप्रैल से अक्टूबर
12.	ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	अप्रैल से अक्टूबर

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा गया है, 71 में से 12 सीपीएसई (17 प्रतिशत) में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया गया था।

इसके अलावा, यद्यपि नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया था, लेकिन सीपीएसई में तीन गैर-कार्यकारी निदेशकों और उन में से आधे स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता पूरी नहीं हुई थी, जैसा कि तालिका 3.35 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.35: नामांकन और पारिश्रमिक की अपर्याप्त संरचना वाले सीपीएसई समिति

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम ⁶²	वर्ष 2021-22 के दौरान गैर-अनुपालन की अवधि
1.	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	अप्रैल से नवंबर
2.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	अप्रैल से नवंबर
3.	एनटीपीसी लिमिटेड	जुलाई से दिसंबर
4.	मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	अप्रैल से दिसंबर
5.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	अप्रैल से मार्च
6.	रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	अगस्त से दिसंबर
7.	इंडियन रेलवे कैटरिंग टुरिज़्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड	अप्रैल से अक्टूबर
8.	हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड	अप्रैल से जनवरी

⁶² क्रमांक 1 से 4 और क्रमांक 18 में उल्लिखित सीपीएसई के लिए, शेयर और बांड/डिबेंचर दोनों को 31 मार्च, 2022 तक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थे।

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम ⁶²	वर्ष 2021-22 के दौरान गैर-अनुपालन की अवधि
9.	तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड	अप्रैल से मार्च
10.	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	अप्रैल से नवंबर
11.	गेल (इंडिया) लिमिटेड	अगस्त से नवंबर
12.	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ऑफ त्रावण कोर लिमिटेड	अप्रैल से मार्च
13.	राइट्स लिमिटेड	अप्रैल से नवंबर
14.	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	अप्रैल से मार्च
15.	एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड	अप्रैल से दिसंबर
16.	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	अप्रैल से जनवरी
17.	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	अप्रैल से दिसंबर
18.	आईएफसीआई लिमिटेड	अप्रैल से मार्च

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा गया है, 71 में से 18 सीपीएसई (25 प्रतिशत) में नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना पर्याप्त नहीं थी।

3.12.2 सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 19(2) और डीपीई दिशा निर्देश 2010 के पैरा 5.1 में यह प्रावधान है कि नामांकन और पारिश्रमिक समिति का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होगा। हालाँकि, तालिका 3.36 में वर्णित सीपीएसई के संबंध में, अध्यक्ष 2021-22 के दौरान एक स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

तालिका 3.36: सीपीएसई जहां नामांकन और पारिश्रमिक समिति का अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक नहीं था

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	वर्ष 2021-22 के दौरान गैर-अनुपालन की अवधि
1.	इंडियन रेलवे कैटरिंग टुरिज़म कॉर्पोरेशन लिमिटेड	अप्रैल से अक्टूबर
2.	हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड	नवंबर से जनवरी
3.	तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड	अप्रैल से मार्च
4.	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	अप्रैल से नवंबर

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	वर्ष 2021-22 के दौरान गैर-अनुपालन की अवधि
5.	गेल (इंडिया) लिमिटेड	अगस्त से नवंबर
6.	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	अगस्त से जनवरी
7.	आईएफसीआई लिमिटेड	अप्रैल से मार्च

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा गया है, 71 में से सात सीपीएसई (10 प्रतिशत) में नामांकन और पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

3.12.3 सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 19 (3) में प्रावधान है कि नामांकन और पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित रहेंगे। हालाँकि, तालिका 3.37 में दर्शाए गए सीपीएसई के संबंध में अध्यक्ष वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित नहीं थे।

तालिका 3.37: सीपीएसई जहां नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित नहीं थे

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1.	राइट्स लिमिटेड
2.	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
3.	जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
4.	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड
5.	कोल इंडिया लिमिटेड

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा गया है, 71 में से पांच सीपीएसई (7 प्रतिशत) में नामांकन और पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष एजीएम में उपस्थित नहीं थे।

3.12.4 सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 19 (3 क) में प्रावधान है कि नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी। हालाँकि, वर्ष 2021-22 के दौरान 71 सीपीएसई में से दो सीपीएसई (3 प्रतिशत) (ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड और हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड) के संबंध में नामांकन और पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक नहीं हुई

3.12.5. सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के विनियमन 19 (2A) में यह प्रावधान है कि नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठक का कोरम या तो दो सदस्यों या समिति के एक तिहाई सदस्यों से मिलकर बनेगा, जो भी अधिक हो, जिसमें कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक की उपस्थिति शामिल होगी। हालाँकि, 71 सीपीएसई में से दो सीपीएसई (3 प्रतिशत) (राइट्स लिमिटेड और आईएफसीआई लिमिटेड) के संबंध में, 2021-22 के दौरान विनियमन का अनुपालन नहीं किया गया।

3.12.6 सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची II के भाग (क) (2) में यह प्रावधान है कि स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए मानदंड नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा तैयार किए जाएंगे। हालाँकि, तालिका 3.38 में उल्लेखित 2021-22 के दौरान सीपीएसई के संबंध में स्वतंत्र निदेशकों और निदेशक मंडल के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए मानदंड में सूचीबद्ध नहीं किए गए थे।

तालिका 3.38: सीपीएसई जहां स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार नहीं किए गए हैं

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1.	पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
2.	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
3.	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
4.	बामरलॉरी एंड कंपनी लिमिटेड

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा गया है, 71 सीपीएसई में से चार (6 प्रतिशत) में स्वतंत्र निदेशकों के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन हेतु मानदंड तैयार नहीं किये गये थे।

3.12.7 सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के अनुसूची II के भाग घ (क)(3) में यह प्रावधान है कि निदेशक मंडल की विविधता सुनिश्चित करने के लिए नीति नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा तैयार की जाएगी। हालाँकि, 2021-22 के दौरान तालिका 3.39 में सूचीबद्ध सीपीएसई के संबंध में निदेशक मंडल की विविधता सुनिश्चित करने के लिए नीति तैयार नहीं की गई थी।

तालिका 3.39: सीपीएसई जहां निदेशक मंडल की विविधता सुनिश्चित करने की नीति तैयार नहीं

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1.	हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड
2.	रेल विकास निगम लिमिटेड
3.	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
4.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
5.	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
6.	एनटीपीसी लिमिटेड
7.	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
8.	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा गया है, 71 में से आठ सीपीएसई (11 प्रतिशत) में निदेशक मंडल की विविधता सुनिश्चित करने के लिए नीति तैयार नहीं की गई थी।

3.13 हितधारक संबंध समिति

3.13.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(5) और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 20(1) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी को एकहित धारक संबंध समिति का गठन करना होगा। हालाँकि, निम्नलिखित सीपीएसई में इसका अनुपालन नहीं किया गया, जैसा कि तालिका 3.40 में विस्तृत रूप से बताया गया है:

तालिका 3.40: सीपीएसई जहां हितधारक संबंध समिति का गठन नहीं किया गया

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	वर्ष 2021-22 के दौरान गैर-अनुपालन की अवधि
1.	बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड	अप्रैल से मार्च
2.	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	अप्रैल से अक्टूबर
3.	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	अप्रैल से अक्टूबर
4.	कोचीन शिप यार्ड लिमिटेड	अप्रैल से नवंबर
5.	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	अप्रैल से दिसंबर

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	वर्ष 2021-22 के दौरान गैर-अनुपालन की अवधि
6.	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	अप्रैल से मार्च
7.	कोल इंडिया लिमिटेड	अप्रैल से अक्टूबर

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा गया है, 71 सीपीएसई में से सात (10 प्रतिशत) में वर्ष 2021-22 की पूरी/आंशिक अवधि के दौरान हित धारक संबंध समिति का गठन नहीं किया गया था।

3.13.2 सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के विनियमन 20(2A) में प्रावधान है कि हित धारक संबंध समिति में कम से कम तीन निदेश कहोंगे, जिनमें से कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होगा। हालाँकि, निम्नलिखित सीपीएसई में इसका अनुपालन नहीं किया गया, जैसा कि तालिका 3.41 में विस्तृत रूप से बताया गया है:

तालिका 3.41: सीपीएसई जहां हित धारक संबंध की संरचना समिति विनियमन के अनुरूप नहीं है

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	वर्ष 2021-22 के दौरान गैर-अनुपालन की अवधि
1.	इंडियन रेलवे कैटरिंग टुरिज़म कॉर्पोरेशन लिमिटेड	अप्रैल से अक्टूबर
2.	हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड	अप्रैल से जनवरी
3.	पॉवरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	अप्रैल से जुलाई
4.	तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड	अप्रैल से मार्च
5.	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	अप्रैल से नवंबर
6.	भारत लेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	अप्रैल से दिसंबर
7.	इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड	अप्रैल से मार्च
8.	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	अगस्त से जनवरी

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा गया है, 71 सीपीएसई में से आठ (11 प्रतिशत) में, वर्ष 2021-22 की पूरी/आंशिक अवधि के दौरान हितधारक संबंध समिति की संरचना विनियमन के अनुसार नहीं थी।

3.13.3 सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 20(3) में प्रावधान है कि हितधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित रहेंगे। हालाँकि, निम्नलिखित सीपीएसई में इसका अनुपालन नहीं किया गया, जैसा कि तालिका 3.42 में विस्तृत रूप से बताया गया है:

तालिका 3.42: सीपीएसई जहां हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित नहीं थे

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
2.	भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
3.	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
4.	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड
5.	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
6.	कोल इंडिया लिमिटेड
7.	एनएमडीसी लिमिटेड

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा गया है, 71 में से सात सीपीएसई (10 प्रतिशत) में हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष एजीएम में उपस्थित नहीं थे।

3.13.4 सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 20(3क) में प्रावधान है कि हितधारक संबंध समिति की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी। हालाँकि, 71 सीपीएसई में से दो (3 प्रतिशत) (ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड और हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड) की हितधारक संबंध समिति की 2021-22 के दौरान एक बार भी बैठक नहीं हुई।

3.14 सहायक कंपनियाँ

3.14.1 सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 24(1) में यह प्रावधान है कि सूचीबद्ध इकाई के निदेशक मंडल में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक अ-सूचीबद्ध महत्वपूर्ण सहायक कंपनी के बोर्ड में निदेशक होगा। हालाँकि, 2021-22 के दौरान 71 सीपीएसई में से तीन सीपीएसई (4 प्रतिशत) (एनएलसी इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड और एचएमटी लिमिटेड) के संबंध में इसका अनुपालन नहीं किया गया।

कोल इंडिया लिमिटेड के संबंध में, कोयला मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2024) में कहा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं किए जाने के कारण अनुपालन नहीं किया जा सका, हालांकि उसने नियमित रूप से इस मामले को आगे बढ़ाया।

हालांकि, तथ्य यह है कि 2021-22 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड के संबंध में सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015 के विनियमन 24(1) का अनुपालन नहीं किया गया।

3.14.2 सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 24(2) में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति को वित्तीय विवरणों, विशेष रूप से अ-सूचीबद्ध सहायक कंपनी द्वारा किए गए निवेशों की समीक्षा करनी चाहिए। हालांकि, 71 सीपीएसई में से एक सीपीएसई (1 प्रतिशत) (कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड) के मामले में इसका अनुपालन नहीं किया गया।

3.15 जोखिम प्रबंधन समिति

3.15.1 सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 21(1) और 21(5) में प्रावधान है कि शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध संस्थाओं को एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन करना होगा। हालांकि, सीपीएसई के संबंध में इसका अनुपालन नहीं किया गया, जैसा कि तालिका 3.43 में विस्तृत रूप से बताया गया है:

तालिका 3.43: सीपीएसई जहां जोखिम प्रबंधन समिति का गठन नहीं किया गया

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	वर्ष 2021-22 के दौरान कमी की अवधि
1.	गार्डनरीचशिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	अगस्त से फरवरी
2.	बामरलॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	अप्रैल से फरवरी
3.	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	अप्रैल से अक्टूबर
4.	स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	अप्रैल से मार्च
5.	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	मई से दिसंबर
6.	मिश्रधातु निगम लिमिटेड	अप्रैल से दिसंबर

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा गया है, 71 सीपीएसई में से छह (8 प्रतिशत) में वर्ष 2021-22 की पूरी/आंशिक अवधि के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति का गठन नहीं किया गया था।

3.15.2 सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 21(2) में प्रावधान है कि जोखिम प्रबंधन समिति में कम से कम तीन सदस्य होने चाहिए, जिनमें से अधिकांश निदेशक मंडल के सदस्य होंगे, जिसमें कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक शामिल होगा। हालाँकि, सीपीएसई के मामले में इसका अनुपालन नहीं किया गया, जैसा कि तालिका 3.44 में विस्तृत रूप से बताया गया है:

तालिका 3.44: जोखिम प्रबंधन समिति की अपर्याप्त संरचना वाले सीपीएसई

क्रमसं.	सीपीएसई का नाम	वर्ष 2021-22 के दौरान गैर-अनुपालन की अवधि
1.	इंडियन रेलवे कैटरिंग टुरिज़म कॉर्पोरेशन लिमिटेड	अप्रैल से अक्टूबर
2.	गेल (इंडिया) लिमिटेड	अगस्त से दिसंबर
3.	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	अगस्त से जनवरी

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा गया है, 71 सीपीएसई में से तीन (4 प्रतिशत) में वर्ष 2021-22 की आंशिक अवधि के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना पर्याप्त नहीं थी।

3.15.3 सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 21 (3 क) और (3 ग) में प्रावधान है कि जोखिम प्रबंधन समिति को वर्ष में कम से कम दो बार मिलना चाहिए। इसके अलावा, जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकें इस तरह से आयोजित की जाएँगी कि लगातार आधार पर किसी भी दो लगातार बैठकों के बीच एक सौ अस्सी दिन से अधिक का अंतराल न हो। हालाँकि, तालिका 3.45 में उल्लिखित सीपीएसई के संबंध में, जोखिम प्रबंधन समिति ने वर्ष में दो बार बैठक नहीं की और तालिका 3.46 में उल्लिखित सीपीएसई के संबंध में, दो बैठकों के बीच का अंतराल 180 दिनों से अधिक था।

तालिका 3.45: सीपीएसई जहां जोखिम प्रबंधन समिति की वर्ष के दौरान दो बार बैठक नहीं हुई

क्रमसं.	सीपीएसई का नाम	आयोजित बैठकों की संख्या
1.	हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड	1
2.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	0
3.	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1
4.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	0
5.	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	1
6.	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	1
7.	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	1
8.	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	1
9.	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा गया है, 71 में से नौ सीपीएसई (13 प्रतिशत) में जोखिम प्रबंधन समिति ने 2021-22 के दौरान कम से कम दो बैठकें आयोजित नहीं कीं।

तालिका 3.46: जोखिम प्रबंधन समिति की दो बैठकों के बीच 180 दिनों से अधिक का अंतराल रखने वाले सीपीएसई

क्रमसं.	सीपीएसई का नाम	अन्तराल (दिनों में)
1.	गार्डनरीचशिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	215
2.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	278
3.	ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	285
4.	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	217
5.	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	364
6.	एनएमडीसी लिमिटेड	234

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा गया है, 71 में से छह सीपीएसई (8 प्रतिशत) में, वर्ष 2021-22 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की दो बैठकों के बीच अंतराल 180 दिनों से अधिक था।

3.15.4 सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 21(4) में प्रावधान है कि जोखिम प्रबंधन समिति की भूमिका और जिम्मेदारी निदेशक मंडल द्वारा परिभाषित की जानी चाहिए। निदेशक मंडल जोखिम प्रबंधन योजना की निगरानी और समीक्षा करने तथा ऐसे अन्य कार्य जो वह उचित समझे, समिति को सौंप सकता है। ऐसे कार्यों में विशेष रूप से साइबर सुरक्षा शामिल होगी। हालाँकि, 2021-22 के दौरान एक सीपीएसई (फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ऑफ़ त्रावणकोर लिमिटेड) में इसका अनुपालन नहीं किया गया।

3.15.5 सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (9) (क) और (ख) में यह प्रावधान है कि सूचीबद्ध इकाई जोखिम मूल्यांकन और न्यूनतमकरण प्रक्रियाओं के बारे में निदेशकमंडल के सदस्यों को सूचित करने के लिए प्रक्रियाएँ निर्धारित करेगी और निदेशक मंडल सूचीबद्ध इकाई के लिए जोखिम प्रबंधन योजना तैयार करने, उसे लागू करने और उसकी निगरानी करने के लिए जिम्मेदार होगा। हालाँकि, सीपीएसई के संबंध में इसका अनुपालन नहीं किया गया जैसा कि तालिका 3.47 में विस्तृत रूप से बताया गया है।

तालिका 3.47: सीपीएसई जहां जोखिम मूल्यांकन और न्यूनीकरण प्रक्रियाएं और जोखिम प्रबंधन योजना निर्धारित नहीं की गई है

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1.	हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड
2.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
3.	स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा गया है, 71 में से तीन सीपीएसई (4 प्रतिशत) में 2021-22 के दौरान जोखिम मूल्यांकन और न्यूनीकरण प्रक्रियाएं और जोखिम प्रबंधन योजना निर्धारित नहीं की गई थी।

3.16 सचिवीय लेखापरीक्षा

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के विनियमन 24(क) (2) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक सूचीबद्ध इकाई को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत

से साठ दिनों के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को निर्दिष्ट प्रारूप में सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। हालाँकि, 71 सीपीएसई में से दो सीपीएसई (3 प्रतिशत) (ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड और बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड) के संबंध में, 2021-22 के दौरान निर्धारित समय के भीतर सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत नहीं की गई।

3.17 अनुपालन प्रमाणपत्र

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 अनुसूची V(ग) (10) (ट) में प्रावधान है कि सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा समेकित आधार पर सांविधिक लेखापरीक्षक को दी जाने वाली सभी सेवाओं के लिए कुल शुल्क का विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में प्रकट किया जाना चाहिए। हालाँकि, सीपीएसई के संबंध में इसका अनुपालन नहीं किया गया, जैसा कि तालिका 3.48 में विस्तृत रूप से बताया गया है:

तालिका 3.48: सीपीएसई जहां सांविधिक लेखापरीक्षक को भुगतान की गई फीस का विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में प्रकट नहीं किया गया

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1.	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
2.	हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड
3.	तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड
4.	एंड्रयूयूल एंड कंपनी लिमिटेड
5.	कोल इंडिया लिमिटेड

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा गया है, 71 में से पांच सीपीएसई (7 प्रतिशत) में, सांविधिक लेखापरीक्षक को भुगतान की गई फीस से संबंधित विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में प्रकट नहीं किया गया था।

3.17.2 सेबी (सूची बद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची V (ग) (10) (ठ) में प्रावधान है कि कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 बंध में वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की

गई शिकायतों की संख्या, वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या और वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या का खुलासा कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में किया जाना चाहिए। हालाँकि, एक सीपीएसई (ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड) द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया।

3.18 निष्कर्ष

अध्याय के भाग (अ) में शामिल 71 सूचीबद्ध सीपीएसई के संबंध में, यह पाया गया कि 71 सूचीबद्ध सीपीएसई में से केवल तीन सीपीएसई (3 प्रतिशत) अर्थात् एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बीईएमएल लिमिटेड और एमएमटीसी लिमिटेड ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशा-निर्देशों, सेबी विनियमों और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों में निर्धारित सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया था, जिनका लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषण किया गया था। प्रमुख गैर-अनुपालन के मामलों का सारांश नीचे दिया गया है:

- i. 71 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 26 सीपीएसई (37 प्रतिशत) में गैर-कार्यकारी निदेशक बोर्ड की क्षमता के 50 प्रतिशत से कम थे और यह कमी 17 से 100 प्रतिशत के बीच थी; 55 सीपीएसई (77 प्रतिशत) में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशक बोर्ड में नहीं थे और यह कमी 13 से 100 प्रतिशत के बीच थी; (पैरा 3.2.1 और 3.2.2.1)
- ii. 71 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 20 सीपीएसई (28 प्रतिशत) के बोर्ड में कोई महिला निदेशक नहीं थी। इसके अलावा, 41 सूचीबद्ध सीपीएसई (58 प्रतिशत) जो शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध संस्थाओं में से हैं, के बोर्ड में 2021-22 की पूरी/आंशिक अवधि के दौरान कोई महिला स्वतंत्र निदेशक नहीं थी; (पैरा 3.2.3)
- iii. शीर्ष 2,000 सूचीबद्ध संस्थाओं में शामिल 71 सीपीएसई में से सात (10 प्रतिशत) में बोर्ड में न्यूनतम छह निदेशकों का मानदंड पूरा नहीं किया गया; (पैरा 3.2.4)
- iv. 71 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 25 सीपीएसई (35 प्रतिशत) के निदेशक मंडल की बैठकों में निदेशकों की संख्या अपर्याप्त थी और यह कमी 14 से 100 प्रतिशत के बीच थी; (पैरा 3.2.5)
- v. 71 सूचीबद्ध सीपीएसई में से, तीन सीपीएसई (4 प्रतिशत) के संबंध में, स्वतंत्र

निदेशक का निष्पादन मूल्यांकन पूरे निदेशक मंडल द्वारा नहीं किया गया था; (पैरा 3.3.2)

- vi. 71 सीपीएसई में से, सात सीपीएसई (10 प्रतिशत) में स्वतंत्र निदेशकों ने बोर्ड और समितियों की कम से कम 80 प्रतिशत बैठकों में भाग नहीं लिया, जिन में वे सदस्य थे। (पाँच) सीपीएसई (7 प्रतिशत) में, एक या उससे अधिक स्वतंत्र निदेशक सामान्य बैठक में उपस्थित नहीं थे। पांच सीपीएसई (7 प्रतिशत) में, स्वतंत्र निदेशकों ने गैर-स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति के बिना कम से कम एक बैठक आयोजित नहीं की। इसके अलावा, दो सीपीएसई (3 प्रतिशत) में गैर-स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति के बिना सभी स्वतंत्र निदेशक स्वतंत्र निदेशकों की बैठक में उपस्थित नहीं थे; (पैरा 3.4.1 से 3.4.3)
- vii. 71 सीपीएसई में से तीन सीपीएसई (4 प्रतिशत) में बोर्ड की बैठकें सात दिन से कम समय की सूचना देकर बुलाई गईं; (पैरा 3.4.4.1)
- viii. 71 सीपीएसई में से, छह सीपीएसई (8 प्रतिशत) निदेशक मंडल को विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई; (पैरा 3.4.4.2)
- ix. 71 सीपीएसई में से, छह सीपीएसई (8 प्रतिशत) में स्वतंत्र निदेशकों को प्रशिक्षण नहीं दिया गया था और पांच सीपीएसई (7 प्रतिशत) के संबंध में, स्वतंत्र निदेशकों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण वेबसाइट पर प्रकट नहीं किया गया था; (पैरा 3.5)
- x. 71 सीपीएसई में से आठ सीपीएसई (11 प्रतिशत) में पूर्ण कालिक प्रमुख प्रबंध कीयकार्मिकों की रिक्ति ऐसी रिक्ति की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर नहीं भरी गई; (पैरा 3.6)
- xi. 71 सीपीएसई में से पांच सीपीएसई (7 प्रतिशत) द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही के अंत से 15 दिनों के भीतर प्रशासनिक मंत्रालय को प्रस्तुत नहीं की गई; (पैरा 3.7.2)
- xii. 71 सीपीएसई में से, 21 सीपीएसई (30 प्रतिशत) में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता को दर्शाने वाला चार्ट या मैट्रिक्स शामिल नहीं था, (पैरा 3.7.3)
- xiii. 71 सीपीएसई में से 11 सीपीएसई (15 प्रतिशत) में लेखापरीक्षा समिति का गठन

- नहीं किया गया था; 28 सीपीएसई (39 प्रतिशत) में लेखापरीक्षा समिति के दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक नहीं थे और यह कमी 50 से 100 प्रतिशत तक थी; सात सीपीएसई (10 प्रतिशत) में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक नहीं थे ; चार सीपीएसई (6 प्रतिशत) में लेखापरीक्षा समिति की वित्तीय साक्षरता से संबंधित विनियमन का अनुपालन नहीं किया गया था; (पैरा 3.8.1 और 3.8.2)
- xiv. आठ सीपीएसई (11 प्रतिशत) के मामले में लेखापरीक्षा समिति की कम से कम चार बैठकें आयोजित नहीं की गईं 15 सीपीएसई (7 प्रतिशत) में लेखापरीक्षा समिति की दो बैठकों के बीच का अंतराल 120 दिनों से अधिक था और 27 सीपीएसई (38 प्रतिशत) में लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए कोरम अपर्याप्त था; (पैरा 3.8.3 और 3.8.4)
- xv. 71 सीपीएसई में से, लेखापरीक्षा समिति ने एक से लेकर 16 सीपीएसई के संबंध में अपेक्षित सूचना की समीक्षा नहीं की; (पैरा 3.8.5.1)
- xvi. 71 सीपीएसई में से, लेखापरीक्षा समिति ने 1 से 4 तक के सीपीएसई में सूचना की अनिवार्य समीक्षा नहीं की; आठ सीपीएसई (11 प्रतिशत) में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष एजीएम में शामिल नहीं हुए; 13 सीपीएसई (18 प्रतिशत) में लेखापरीक्षा समिति द्वारा व्हिसलब्लोअर तंत्र की समीक्षा नहीं की गई; (पैरा 3.8.5.2, 3.9 और 3.10.2)
- xvii. 71 सीपीएसई में से, दो सीपीएसई (3 प्रतिशत) में संबंधित पक्ष लेन देन की महत्ता पर नीति तैयार/समीक्षा/अद्यतन नहीं की गई थी; तीन सीपीएसई (4 प्रतिशत) के संबंध में स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत प्रकटीकरण वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं किया गया था; (पैरा 3.11.1 और 3.11.2)
- xviii. 71 सीपीएसई में से 12 सीपीएसई (17 प्रतिशत) में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया गया था; 18 सीपीएसई (25 प्रतिशत) में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना पर्याप्त नहीं थी; सात सीपीएसई (10 प्रतिशत) में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक नहीं थे; पांच सीपीएसई (7 प्रतिशत) में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष एजीएम में उपस्थित नहीं थे तथा दो सीपीएसई (3 प्रतिशत) में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठक आयोजित नहीं की गई थी; (पैरा 3.12.1 से 3.12.4)
- xix. 71 सीपीएसई में से चार सीपीएसई (6 प्रतिशत) में स्वतंत्र निदेशकों और निदेशक

मंडल के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार नहीं किए गए थे; (पैरा 3.12.6)

- xx. 71 सीपीएसई में से आठ सीपीएसई (11 प्रतिशत) में निदेशक मंडल की विविधता सुनिश्चित करने के लिए नीति तैयार नहीं की गई थी; (पैरा 3.12.7)
- xxi. 71 सीपीएसई में से, सात सीपीएसई में हित धारक संबंध समिति का गठन नहीं किया गया था (10 प्रतिशत); आठ सीपीएसई में हित धारक संबंध समिति की संरचना विनियमन के अनुसार नहीं थी (11 प्रतिशत); सात सीपीएसई में हित धारक संबंध समिति के अध्यक्ष वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित नहीं थे (10 प्रतिशत); दो सीपीएसई में हित धारक संबंध समिति की एक बार भी बैठक नहीं हुई (3 प्रतिशत); (पैरा 3.13.1 से 3.13.4)
- xxii. 71 सीपीएसई में से तीन सीपीएसई में स्वतंत्र निदेशक सहायक कंपनी के बोर्ड में निदेशक नहीं थे (4 प्रतिशत); लेखापरीक्षा समिति ने एक सीपीएसई में सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की समीक्षा नहीं की (1 प्रतिशत); (पैरा 3.14)
- xxiii. 71 सीपीएसई में से, छह सीपीएसई में (8 प्रतिशत) जोखिम प्रबंधन समिति का गठन नहीं किया गया था; तीन सीपीएसई (4 प्रतिशत) में जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना पर्याप्त नहीं थी; नौ सीपीएसई (13 प्रतिशत) में जोखिम प्रबंधन समिति की वर्ष के दौरान दोबार बैठक नहीं हुई; छह सीपीएसई (8 प्रतिशत) में जोखिम प्रबंधन समिति की दो बैठकों के बीच का अंतराल 180 दिनों से अधिकथा; एक सीपीएसई (1 प्रतिशत) में जोखिम प्रबंधन समिति की भूमिका और जिम्मेदारी परिभाषित नहीं की गई थी; तीन सीपीएसई (4 प्रतिशत) में जोखिम मूल्यांकन और न्यूनीकरण प्रक्रियाओं और जोखिम प्रबंधन योजना के बारे में निदेशक मंडल को सूचित करने की प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई थी; (पैरा 3.15.1 से 3.15.5)
- xxiv. 71 सीपीएसई में से दो सीपीएसई (3 प्रतिशत) में सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत नहीं की गई थी; पांच सीपीएसई (7 प्रतिशत) में कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में सांविधिक लेखापरीक्षक को भुगतान की गई फीस से संबंधित विवरण का खुलासा नहीं किया गया था; (पैरा 3.16 और 3.17.1)

भाग - ब

सीपीएसई/सांविधिक निगम जिनके बांड/डेबेंचर स्टॉक 31 मार्च, 2022 को एक्सचेंज में सूचीबद्ध थे

3.19 परिचय

31 मार्च, 2022 तक, सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 35 सीपीएसई और सांविधिक निगम हैं, जिनके बांड/डेबेंचर भारत में स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। सीपीएसई/सांविधिक निगमों में कॉर्पोरेट गवर्नेन्स को नियंत्रित करने वाले प्रावधान, जिनके बांड/डेबेंचर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं, मुख्य रूप से कंपनी अधिनियम, 2013, डीपीई दिशा निर्देश 2010, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 और सेबी (अ-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) विनियम, 2021 के अंतर्गत आते हैं।

31 मार्च, 2022 तक जिनके बांड/डेबेंचर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थे, सीपीएसई और सांविधिक निगमों द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेन्स प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा के दौरान निम्नलिखित गैर-अनुपालन पाए गए।

3.20 वित्तीय परिणाम

3.20.1 सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के विनियमन 52(2)(घ) में प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणाम लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ वित्तीय वर्ष की समाप्ति से साठ दिनों के भीतर स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत किए जाने चाहिए। बशर्ते कि जारीकर्ता, जिनका सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा किया जा रहा है, वार्षिक लेखापरीक्षा वित्तीय परिणामों के प्रकटीकरण के लिए निम्नलिखित दो चरणीय प्रक्रिया अपनाएं:

- (i) प्रथम स्तर की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी, जो सूचीबद्ध इकाई के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा करेगा और ऐसे वित्तीय परिणाम वित्तीय वर्ष की समाप्ति से साठ दिनों के भीतर स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत किए जाएंगे।

- (ii) सीपीएजी द्वारा लेखापरीक्षा पूरी होने के बाद, वित्तीय परिणाम वित्तीय वर्ष की समाप्ति से नौ महीने के भीतर स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत किए जाएंगे।

तालिका 3.49 में सूचीबद्ध तीन सीपीएसई ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 60 दिनों के भीतर स्टॉक एक्सचेंज को लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखापरीक्षित एकल और समेकित वित्तीय परिणाम प्रस्तुत नहीं किए।

तालिका 3.49: सीपीएसई जिन्होंने 60 दिनों के भीतर स्टॉक एक्सचेंज को वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम प्रस्तुत नहीं किए

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1	डीएमई डेवलपमेंट लिमिटेड
2	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
3	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड

35 सीपीएसई/सांविधिक निगमों में से तीन सीपीएसई (9 प्रतिशत) ने निर्धारित समय के भीतर स्टॉक एक्सचेंज को वार्षिक लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणाम प्रस्तुत नहीं किए। इसके अलावा, 35 सीपीएसई/सांविधिक निगम में से एक सांविधिक निगम (भारतीय खाद्य निगम) ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति से नौ महीने के भीतर स्टॉक एक्सचेंज को वित्तीय परिणाम प्रस्तुत नहीं किए।

3.20.2 सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 का विनियमन 52(4) यह निर्धारित करता है कि सूचीबद्ध इकाई तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करते समय वित्तीय परिणामों के साथ कुछ निर्दिष्ट लाइन आइटम का खुलासा करेगी। इसके अलावा, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015 के विनियमन 52(5) में यह निर्धारित किया गया है कि सूचीबद्ध इकाई उप-विनियमन (4) के तहत आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने की तारीख से सात कार्य दिवसों के भीतर स्टॉक एक्सचेंज को डेबेंचर ट्रस्टी द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी कि उसने सामग्री पर ध्यान दिया है।

35 सीपीएसई/सांविधिक निगमों में से एक सीपीएसई (एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड (एआईएचएल) (3 प्रतिशत) ने 2021-22 के दौरान सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 52(4) और 52(5) का अनुपालन नहीं किया।

3.21 स्टॉक एक्सचेंज को सूचनाएं/अन्य प्रस्तुतियां

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ)(पांचवां संशोधन) विनियम, 2021 के विनियमन 57(4) में प्रावधान है कि सूचीबद्ध इकाई तिमाही की शुरुआत से पहले पांच कार्य दिवसों के भीतर उन सभी अ-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का विवरण प्रदान करेगी, जिनके लिए तिमाही के दौरान ब्याज/लाभांश/मूल दायित्व देय होंगे।

35 सीपीएसई/सांविधिक निगमों में से एक सांविधिक निगम (भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण) (3 प्रतिशत) ने 2021-22 के दौरान तिमाही की शुरुआत से पहले पांच कार्य दिवसों के भीतर सभी अ-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का विवरण प्रदान नहीं किया।

3.22 वेबसाइट

3.22.1 सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 62(1) में प्रावधान है कि सूचीबद्ध इकाई एक कार्यात्मक वेबसाइट बनाए रखेगी जिसमें सूचीबद्ध इकाई के बारे में कुछ प्रासंगिक जानकारी होगी जैसे उसके व्यवसाय का विवरण; बोर्ड की संरचना; वित्तीय जानकारी; सूचीबद्ध इकाई के नामित अधिकारियों की संपर्क जानकारी जो निवेशक शिकायतों की सहायता और निपटान के लिए जिम्मेदार हैं; पूर्ण संपर्क विवरण के साथ डेबेंचर ट्रस्टियों का नाम; सूचीबद्ध इकाई द्वारा दायर अनुपालन रिपोर्ट सहित सभी जानकारी और रिपोर्ट; इन विनियमों के विनियम 52 के उप-विनियम (7) और उप-विनियम (7 क) में निर्दिष्ट विचलन या भिन्नता के विवरण; कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत प्रदान की गई वार्षिक रिटर्न।

35 सीपीएसई/सांविधिक निगमों में से एक सीपीएसई (एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड) (3 प्रतिशत) ने 2021-22 के दौरान अपनी कार्यात्मक वेबसाइट पर कुछ जानकारी का खुलासा नहीं किया, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमन 62(1) सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के तहत आवश्यक है।

3.22.2 सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 का विनियमन 62 (क) (i) यह निर्धारित करता है कि सूचीबद्ध संस्थाएं, जिन पर विनियम 15 से विनियम 27 लागू हैं, उन्हें स्वतंत्र निदेशकों को प्रदान किए गए परिचय कार्यक्रमों

के विवरण का अपनी वेबसाइट पर अतिरिक्त प्रकटीकरण भी करना होगा, जिसमें (i) स्वतंत्र निदेशकों द्वारा भाग लिए गए कार्यक्रमों की संख्या (वर्ष के दौरान और आज तक संचयी आधार पर), (ii) ऐसे कार्यक्रमों में स्वतंत्र निदेशकों द्वारा बिताए गए घंटों की संख्या (वर्ष के दौरान और आज तक संचयी आधार पर), और (iii) अन्य प्रासंगिक विवरण शामिल हैं।

35 में से एक सीपीएसई (यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) (3 प्रतिशत) ने 2021-22 के दौरान अपनी वेबसाइट पर कुछ अतिरिक्त खुलासे नहीं किए, जैसे कि सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 62 (1 क) (i) के तहत उल्लिखित है।

3.23 अंदरूनी व्यापार की रोकथाम

डीपीई दिशा निर्देश 2010 के पैरा 6.11 में प्रावधान है कि बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कंपनी की प्रतिभूतियों के लेनदेन में अंदरूनी व्यापार की रोकथाम के लिए आंतरिक प्रक्रिया संहिता और आचरण का अनुपालन करेंगे।

35 सीपीएसई/सांविधिक निगमों में से एक सीपीएसई (एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड) 2021-22 के दौरान उपरोक्त प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया क्योंकि कंपनी ने आंतरिक प्रक्रिया संहिता नहीं बनाई थी।

3.24 निदेशक मंडल

3.24.1 स्वतंत्र निदेशक

बोर्ड में स्वतंत्र प्रतिनिधियों की मौजूदगी, जो प्रबंधन के निर्णय पर स्वतंत्र दृष्टिकोण रख सकें, को व्यापक रूप से शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा के साधन के रूप में माना जाता है। कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 और डीपीई दिशानिर्देश 2010 के पैरा 3.1.4 के अनुसार, जहां बोर्ड का अध्यक्ष एक गैर-कार्यकारी निदेशक है, बोर्ड का कम से कम एक तिहाई हिस्सा स्वतंत्र निदेशकों से बना होना चाहिए और यदि वह एक कार्यकारी निदेशक है, तो बोर्ड का कम से कम आधा हिस्सा स्वतंत्र निदेशकों से बना होना चाहिए। निदेशक मंडल की संरचना की समीक्षा

से पता चला कि तालिका 3.50 में सूचीबद्ध सीपीएसई में उनके बोर्ड में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

तालिका 3.50: सूचीबद्ध बांड वाले सीपीएसई/सांविधिक निगम जिनके पास स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थे

क्रम सं.	सीपीएसई/सांविधिक निगम का नाम	स्वतंत्र निदेशकों के अलावा बोर्ड में निदेशकों की संख्या	अध्यक्ष का दर्जा	आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या	कमी (प्रतिशत में)	वर्ष 2021-22 के दौरान कमी की अवधि
1	एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड	6	कार्यकारिणी	6	0	6 (100)	अप्रैल से मार्च
2	भारत संचार निगम लिमिटेड	5	कार्यकारिणी	5 5	0 4	5 (100) 1 (20)	अप्रैल से अक्टूबर नवंबर से मार्च
3	एनटीपीसी-सेल (जेवी)	6	गैर-कार्यकारी	3	0	3 (100)	अप्रैल से मार्च
4	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	3	कार्यकारिणी	3	1	2 (67)	अप्रैल से मार्च
5	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	6	गैर-कार्यकारी	3	0	3(100)	अप्रैल से मार्च
6	टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5	कार्यकारिणी	5	3	2 (40)	अप्रैल से मार्च

क्रम सं.	सीपीएसई/सांविधिक निगम का नाम	स्वतंत्र निदेशकों के अलावा बोर्ड में निदेशकों की संख्या	अध्यक्ष का दर्जा	आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या	कमी (प्रतिशत में)	वर्ष 2021-22 के दौरान कमी की अवधि
7	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	4	कार्यकारिणी	4	0 1 2	4 (100) 3 (75) 2(50)	अप्रैल से नवंबर दिसंबर से जनवरी फरवरी से मार्च
8	इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फिन कंपनी लिमिटेड	7	कार्यकारिणी	7	0	7 (100)	अप्रैल से मार्च
9	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड	6	कार्यकारिणी	6	0 1	6 (100) 5 (83)	अप्रैल से दिसंबर जनवरी से मार्च

35 में से नौ सीपीएसई/सांविधिक निगमों (26 प्रतिशत) के बोर्ड में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। कमी का प्रतिशत 20 से 100 प्रतिशत के बीच था।

3.24.2 महिला निदेशक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) और कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 3 में प्रावधान है कि सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक होनी चाहिए। निदेशक मंडल की संरचना की समीक्षा से पता चला कि तालिका 3.51 में सूचीबद्ध सीपीएसई के बोर्ड में कोई महिला निदेशक नहीं थी।

तालिका 3.51: सूचीबद्धबांड वाले सीपीएसई जिनके बोर्ड में महिला निदेशक नहीं थे

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	वर्ष 2021-22 के दौरान गैर-अनुपालन की अवधि
1.	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड	अप्रैल से मार्च
2.	डीएमई डेवलपमेंट लिमिटेड	अप्रैल से मार्च
3.	न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	अप्रैल से मार्च

32 सूचीबद्ध सीपीएसई में से तीन में⁶³ (9 प्रतिशत), 2021-22 के दौरान बोर्ड में कोई महिला निदेशक नहीं थी।

न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के संबंध में, परमाणु ऊर्जा विभाग ने अपने उत्तर (जून 2024) में कहा है कि महिला निदेशक की नियुक्ति का मामला मूर्तरूप नहीं ले सका, हालांकि उसने इस मामले को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के समक्ष उठाया है।

हालांकि, तथ्य यह है कि 2021-22 के दौरान न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक मण्डल में कोई महिला निदेशक नहीं थी।

3.25 रिक्तियों को भरने में अंतराल

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203(4) के अनुसार, यदि किसी पूर्ण कालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) का पद रिक्त है, तो उस रिक्ति को बोर्ड की बैठक में रिक्ति की तिथि से छह माह की अवधि तक भरना अनिवार्य है। हालांकि, 2021-22 के दौरान 32 सीपीएसई में से एक, सीपीएसई (भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड) में, बोर्ड द्वारा इस अवधि के भीतर प्रमुख प्रबंधकीय एजेंसी की रिक्तियाँ नहीं भरी गईं।

3.26 विविध

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची V के भाग ग(2) (ज) में यह प्रावधान है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में निदेशक मंडल के

⁶³ ये प्रावधान कंपनियों के लिए लागू हैं, हालांकि, 35 सीपीएसई के नमूना चयन में तीन सांविधिक निगम शामिल हैं, अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय खाद्य निगम और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। इसलिए, इन सांविधिक निगमों पर यहां विचार नहीं किया गया है।

कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता को दर्शाने वाला एक चार्ट या मैट्रिक्स शामिल होगा, जिसमें निदेशक मंडल द्वारा पहचाने गए मुख्य कौशल/विशेषज्ञता/क्षमताओं की सूची निर्दिष्ट की जाएगी, जो इसके व्यवसाय और क्षेत्र के संदर्भ में प्रभावी ढंग से काम करने के लिए आवश्यक हैं और जो वास्तव में बोर्ड के पास उपलब्ध हैं, साथ ही ऐसे निदेशकों के नाम भी होंगे जिनके पास ऐसे कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता है। हालाँकि, 2021-22 के दौरान एक सीपीएसई (एनटीपीसी-सेल (जेवी)) द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया।

3.27 लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का कोरम

डीपीई दिशानिर्देश 2010 के पैरा 4.4 में लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए कोरम की आवश्यकता निर्धारित की गई है (अर्थात्, दो सदस्य या लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों का एक तिहाई, जो भी अधिक हो, कम से कम दो स्वतंत्र निदेशकों के साथ)। सीपीएसई के संबंध में लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में अपर्याप्त कोरम था, जैसा कि तालिका 3.52 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.52: लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए अपर्याप्त कोरम वाले सीपीएसई

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें कोरम अपर्याप्त था	टिप्पणी
1	एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड	2	2	बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था। इसलिए, कोरम पूरा नहीं था।
2	भारत संचार निगम लिमिटेड	5	5	बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था। इसलिए, कोरम पूरा नहीं हुआ
3	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	7	7	बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था। इसलिए, कोरम पूरा नहीं हुआ
4	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	7	7	बोर्ड में केवल 1 स्वतंत्र निदेशक था। इसलिए, कोरम पूरा नहीं था।

32 सीपीएसई में से चार (13 प्रतिशत) में वर्ष 2021-22 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठकों के लिए कोरम अपर्याप्त था।

3.28 वरिष्ठ प्रबंधन, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों, निदेशकों और प्रमोटरों सहित कर्मचारियों के संबंध में आचार संहिता और दायित्व

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 46 (2) (घ) में यह प्रावधान है कि सूचीबद्ध इकाई को निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों की आचार संहिता को अपनी वेबसाइट पर प्रसारित और पोस्ट करना होगा। हालाँकि, एक सीपीएसई {एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड (एआईएचएल)} के संबंध में, 2021-22 के दौरान उपरोक्त विनियमन का अनुपालन नहीं किया गया था।

3.29 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(1) और कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के नियम 6 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी का निदेशक मंडल तीन या अधिक गैर-कार्यकारी निदेशकों से मिलकर नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन करेगा, जिसमें से कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे। हालाँकि, एक सीपीएसई (यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) के संबंध में, 2021-22 के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया गया था।

इसके अलावा, हालाँकि नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया था, लेकिन 2021-22 के दौरान एक सीपीएसई {एनटीपीसी-सेल (जेवी)} में तीन गैर-कार्यकारी निदेशकों और उनमें से आधे स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता पूरी नहीं हुई।

3.30 हितधारक संबंध समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(5) के अनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय एक हजार से अधिक शेयरधारक, डेबेंचर धारक, जमा धारक और किसी अन्य सुरक्षा धारक वाली कंपनी के निदेशक मंडल को एक हितधारक संबंध समिति का गठन करना होगा। हालाँकि, सीपीएसई के मामले में इसका अनुपालन नहीं किया गया, जैसा कि तालिका 3.53 में विस्तृत रूप से बताया गया है।

तालिका 3.53: सीपीएसई जहां हितधारक संबंध समिति का गठन नहीं किया गया

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1	एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड
2	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड

32 में से दो सीपीएसई (6 प्रतिशत) में वर्ष 2021-22 के दौरान हितधारक संबंध समिति का गठन नहीं किया गया।

3.31 अनुपालन प्रमाणपत्र

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची V(ग) (10) में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

क्रम सं.	सेबी विनियमन	विशिष्ट
1	अनुसूची (V)(ग) (10) (झ)	कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में किसी कार्यरत कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाण पत्र का खुलासा किया जाना चाहिए कि कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक को बोर्ड/कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या किसी ऐसे वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।
2	अनुसूची (V) (ग) (10) (ट)	सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षक को समेकित आधार पर भुगतान की गई सभी सेवाओं के लिए कुल फीस का ब्यौरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में प्रकट किया जाना आवश्यक है।
3	अनुसूची (V) (ग) (10) (ठ)	कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या, वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या और वित्तीय वर्ष के अंततकलंबित शिकायतों की संख्या का खुलासा कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में किया जाना आवश्यक है।

35 सीपीएसई/सांविधिक निगमों में से एक सीपीएसई {ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ओआईसीएल)} (3 प्रतिशत) में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में उपरोक्त विनियमों का अनुपालन नहीं किया गया था।

3.32 निष्कर्ष

भाग ब के संबंध में प्रमुख गैर-अनुपालन के मामलों का सारांश नीचे दिया गया है:

- i. 35 सीपीएसई/सांविधिक निगमों में से तीन सीपीएसई (9 प्रतिशत) ने 60 दिनों के भीतर स्टॉक एक्सचेंज को वार्षिक लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणाम प्रस्तुत नहीं किए। इसके अलावा, एक सांविधिक निगम ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति से नौ महीने के भीतर स्टॉक एक्सचेंज को वित्तीय परिणाम प्रस्तुत नहीं किए थे। (पैरा 3.20.1)
- ii. 35 सीपीएसई/सांविधिक निगमों में से एक सीपीएसई (3 प्रतिशत) ने अपनी कार्यात्मक वेबसाइट पर अपेक्षित कुछ जानकारी का खुलासा नहीं किया। (पैरा 3.22.1)
- iii. 35 सीपीएसई/सांविधिक निगमों में से एक सीपीएसई (3 प्रतिशत) ने स्वतंत्र निदेशकों को प्रदान किए गए सुविधाकरण कार्यक्रमों से संबंधित कुछ अतिरिक्त खुलासे अपनी वेबसाइट पर नहीं किए। (पैरा 3.22.2)
- iv. 35 सीपीएसई/सांविधिक निगमों में से नौ सीपीएसई/सांविधिक निगमों (26 प्रतिशत) में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशक बोर्ड में नहीं थे। कमी का प्रतिशत 20 से 100 प्रतिशत के बीच था। (पैरा 3.24.1)
- v. 32 सीपीएसई में से तीन सीपीएसई (9 प्रतिशत) के बोर्ड में कोई महिला निदेशक नहीं थी। (पैरा 3.24.2)
- vi. 32 में से एक सीपीएसई (3 प्रतिशत) में पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की रिक्ति ऐसी रिक्ति की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर नहीं भरी गई। (पैरा 3.25)
- vii. 32 में से चार सीपीएसई (13 प्रतिशत) में लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए कोरम अपर्याप्त था। (पैरा 3.27)
- viii. 32 में से एक सीपीएसई (3 प्रतिशत) में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया गया। (पैरा 3.29)
- ix. 32 में से दो सीपीएसई (6 प्रतिशत) में हितधारक संबंध समिति का गठन नहीं किया गया था। (पैरा 3.30)

डीपीई ने अपने उत्तर (जनवरी 2024) में कहा कि डीपीई सीपीएसई के नियमित प्रशासनिक मामलों की निगरानी नहीं करता है और दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सीपीएसई और संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों पर है। तदनुसार, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को अध्याय जारी किया गया (मई 2024)। हालांकि, सितंबर, 2024 तक, 21 सीपीएसई के संबंध में केवल नौ मंत्रालयों/विभागों से प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुईं और अध्याय में उन पर विचार किया गया है।

अनुशंसा

प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग डीपीई दिशा-निर्देशों/सेसेबी विनियमों में निर्धारित अनुसार सूचीबद्ध सीपीएसई/सांविधिक निगमों द्वारा तिमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर सकते हैं। लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि सूचीबद्ध सीपीएसई/सांविधिक निगमों के निदेशक मंडल को भी इन दिशा-निर्देशों/विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए ताकि सीपीएसई/सांविधिक निगमों के कामकाज में बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जा सके।

चौथा अध्याय

विनिवेश प्रक्रिया

4.1 भारत सरकार (जीओआई) की विनिवेश नीति

वित्त मंत्रालय के अंतर्गत निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में इक्विटी के विनिवेश सहित इक्विटी में केंद्र सरकार के निवेश के प्रबंधन से संबंधित सभी मामलों को देखता है। इसके कार्य के प्रमुख क्षेत्र निजीकरण और अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री सहित रणनीतिक विनिवेश से संबंधित हैं।

दीपम सीपीएसई के पूंजी पुनर्गठन के लिए सामान्य सिद्धांतों और तंत्र पर दिशा-निर्देश जारी करता है और सीपीएसई के वित्तीय पुनर्गठन और पूंजी बाजार के माध्यम से उक्त उद्यमों में निवेश आकर्षित करने के मामलों में सरकार को सलाह देता है। दीपम की पूंजी पुनर्गठन भूमिका सीपीएसई के प्रबंधन में एक अलग भूमिका है और शेयरों की पुनर्खरीद के संबंध में छोड़कर यह सरकार की विनिवेश नीति का हिस्सा नहीं है।

सरकार ने 04 फरवरी, 2021 को सीपीएसई के लिए नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति अधिसूचित की। नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) में सरकार की उपस्थिति को न्यूनतम करना है। नई पीएसई नीति राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, वित्तीय सेवाओं के प्रावधान और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता के मानदंडों के आधार पर चार⁶⁴ रणनीतिक क्षेत्रों को वर्णित करती है। रणनीतिक क्षेत्रों में सरकारी नियंत्रण में होल्डिंग कंपनी स्तर पर मौजूदा सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक उद्यमों की न्यूनतम उपस्थिति बरकरार रखी जाएगी। शेष को निजीकरण या किसी अन्य पीएसई के साथ विलय या सहायक बनाने या बंद करने पर विचार किया जाएगा। गैर-रणनीतिक क्षेत्रों के सभी पीएसई का निजीकरण, जहां

⁶⁴ (i) परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा ; (ii) परिवहन और दूरसंचार; (iii) विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनिज और (iv) बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएँ।

संभव हो, पर विचार किया जाएगा, अन्यथा ऐसे उद्यमों को बंद करने पर विचार किया जाएगा। हालाँकि, यह नीति सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के कुछ वर्गों जैसे गैर-लाभकारी कंपनियों, या कमजोर समूहों को सहायता प्रदान करने वाले सीपीएसई, या विकासात्मक/प्रचारक भूमिकाएँ आदि पर लागू नहीं होती है।

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति को लागू करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं (13 दिसंबर, 2021), जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों, नीति आयोग, व्यय विभाग और दीपम के परामर्श से गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में बंद करने या निजीकरण के लिए सीपीएसई की पहचान करने का प्रावधान है।

मंत्रिमंडल ने 18 मई, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) के निदेशक मंडल को विनिवेश (रणनीतिक विनिवेश और अल्पांश हिस्सेदारी बिक्री दोनों) या उनकी किसी सहायक कंपनी या इकाई को बंद करने या संयुक्त उद्यम में हिस्सेदारी की बिक्री के लिए लेनदेन की सिफारिश करने और उसे शुरू करने के लिए सशक्त बनाने को मंजूरी दी थी। यह भी मंजूरी दी गई कि सीपीएसई के बोर्ड और प्रशासनिक मंत्रालय के प्रस्ताव के आधार पर, दीपम वैकल्पिक तंत्र⁶⁵ की "सैद्धांतिक" मंजूरी प्राप्त करेगा। इसके बाद, सीपीएसई का बोर्ड दीपम या डीपीई दिशानिर्देशों के आधार पर सहायक कंपनियों/इकाइयों/संयुक्त उद्यमों के विनिवेश या बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।

दीपम ने 14 सितंबर, 2022 को होल्डिंग/मूल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा रणनीतिक विनिवेश/सहायक कंपनियों/इकाइयों की अल्पमत हिस्सेदारी बिक्री/संयुक्त उद्यमों में हिस्सेदारी की बिक्री के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए और डीपीई ने 31 अक्टूबर 2022 को बंद करने हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए।

4.2 विनिवेश के तरीके

सरकार विनिवेश के लिए अलग-अलग रास्ते अपनाती है, जो इस प्रकार हैं:

⁶⁵ वैकल्पिक तंत्र में वित्त मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा संबंधित सीपीएसई के प्रशासनिक मंत्रालय के मंत्री शामिल होते हैं।

(i) **रणनीतिक विनिवेश:** इसका तात्पर्य किसी सीपीएसई में सरकार की पूरी या पर्याप्त हिस्सेदारी की बिक्री के साथ-साथ प्रबंधन नियंत्रण का हस्तांतरण है। निजीकरण के मामले में, जो रणनीतिक विनिवेश का एक उप-समूह है, सीपीएसई में सरकारी इक्विटी और इसका प्रबंधन नियंत्रण एक निजी रणनीतिक खरीदार (खरीदारों) को हस्तांतरित कर दिया जाता है और रणनीतिक विनिवेश के अन्य मामलों में, सरकारी इक्विटी को नियंत्रण के साथ दूसरे सीपीएसई को हस्तांतरित कर दिया जाता है।

(ii) **अल्पसंख्यक हिस्सेदारी की बिक्री:** यह भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा अनुमोदित विभिन्न तरीकों जैसे आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ), बिक्री के लिए प्रस्ताव (ओएफएस), शेयरों की पुनर्खरीद आदि के माध्यम से प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के बिना कुछ सीपीएसई में किया जाता है। ये तरीके पूंजी बाजार को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं (क) अच्छा प्रदर्शन करने वाले सीपीएसई के फ्लोट में वृद्धि (ख) खुदरा निवेशकों को स्टॉक की विस्तारित रेंज में भाग लेने का अवसर प्रदान करना और (ग) पूंजी बाजार की लिक्विडिटी और डेप्थ बढ़ाना।

विनिवेश के इन तरीकों को संक्षेप में नीचे समझाया गया है:

(क) आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव / आगे सार्वजनिक प्रस्ताव

आरंभिक सार्वजनिक पेशकश: जब कोई गैर-सूचीबद्ध कंपनी या तो शेयरों या परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का नया निर्गम जारी करती है या अपने मौजूदा शेयरों या परिवर्तनीय प्रतिभूतियों को बिक्री के लिए या दोनों को पहली बार जनता के सामने पेश करती है, तो उसे आईपीओ कहा जाता है। यह जारीकर्ता के शेयरों या परिवर्तनीय प्रतिभूतियों को शेयर बाजार पर सूचीबद्ध करने और व्यापार करने का मार्ग प्रशस्त करता है।

आगे की सार्वजनिक पेशकश: जब पहले से सूचीबद्ध कंपनी जनता के लिए शेयरों या परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का नया निर्गम लाती है या जनता के लिए बिक्री की पेशकश करती है, तो उसे एफपीओ कहा जाता है।

(ख) बिक्री के लिए प्रस्ताव: यह सूचीबद्ध कंपनियों के लिए एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयरों की बिक्री का एक सरल तरीका है। इस प्रणाली को पहली बार 2012 में सेबी द्वारा पेश किया गया था, ताकि सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों

के प्रमोटरों के लिए अपनी हिस्सेदारी कम करना और न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) मानदंडों का पालन करना आसान हो सके। इस पद्धति को बड़े पैमाने पर सूचीबद्ध कंपनियों, सरकारी और निजी दोनों द्वारा, न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता के सेबी मानदंडों का पालन करने के लिए अपनाया गया था। सरकार ने प्रायः सीपीएसई में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए इस मार्ग का उपयोग किया है।

(ग) शेयरों की पुनर्खरीद: पुनर्खरीद किसी कंपनी द्वारा मौजूदा शेयरधारकों से अपने शेयरों की पुनर्खरीद है, जिससे खुले बाजार में उसके शेयरों की संख्या कम हो जाती है।

कंपनियां कई कारणों से अपने शेयर वापस खरीदती हैं: (i) प्रमोटरों द्वारा रखे गए शेयरों के मूल्य में वृद्धि करने के लिए । (ii) अल्पसंख्यक शेयरधारकों द्वारा किसी भी खतरे को खत्म करने के लिए जो नियंत्रण हिस्सेदारी की तलाश कर रहे हों। (iii) सीपीएसई के लिए, पुनर्खरीद भारत सरकार (जीओआई) के लिए सीपीएसई में भारत सरकार द्वारा रखी गई इक्विटी का विनिवेश करने और सीपीएसई के पास पड़ी निष्क्रिय नकदी का उचित उपयोग करने का एक उपकरण है।

(घ) भारत सरकार की शेयरधारिता की शेष बिक्री: शेष बिक्री सरकार द्वारा विनिवेश का वह तरीका है जिसे उन मामलों में चुना जाता है जहाँ सरकार कंपनी में अल्पमत शेयरधारक है और सेबी द्वारा निर्धारित बिक्री के लिए प्रस्ताव की विधि उपलब्ध नहीं थी। विनिवेश के इस तरीके में, सरकार किसी भी सामान्य शेयरधारक की तरह शेयर बाजार पर अपने शेयर बेचती है।

(ड) एक्सचेंज ट्रेडेड फंड: एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्टॉक की एक टोकरी है जो निफ्टी 50 की तरह एक सूचकांक की संरचना को दर्शाती है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ट्रेडिंग मूल्य अंतर्निहित स्टॉक के शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य पर आधारित है जिसका यह प्रतिनिधित्व करता है और इसे किसी भी स्टॉक की तरह पूरे कारोबारी दिन में खरीदा और बेचा जा सकता है।

विनिवेश के उपर्युक्त तरीकों के अलावा, भारत सरकार ने शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 की धारा 8ए (1) के अनुसार भारत के शत्रु संपत्ति संरक्षक के अधीन रखी गई विभिन्न कंपनियों में शत्रु शेयरों को बेचने के लिए दीपम को अधिकृत किया है। इसके बाद, कैबिनेट नोट (26 फरवरी, 2019) ने अचल शत्रु संपत्तियों के मुद्रीकरण सहित सीपीएसई/पीएसयू/अन्य सरकारी संगठनों की परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए प्रक्रिया और तंत्र निर्धारित किया।

4.3 विनिवेश की प्रक्रिया

4.3.1 सीपीएसई के रणनीतिक विनिवेश में निम्नलिखित चरण शामिल हैं:

क. रणनीतिक क्षेत्रों के अंतर्गत सीपीएसई के लिए:

- नीति आयोग सिफारिश करता है कि सीपीएसई को सरकारी नियंत्रण में रखा जाए या निजीकरण या किसी अन्य पीएसई के साथ विलय या सहायक बनाने या बंद करने पर विचार किया जाए।
- नीति आयोग की सिफारिशें विनिवेश पर सचिवों के कोर ग्रुप⁶⁶ (सीजीडी) के समक्ष रखी जाती हैं।
- सीजीडी अनुशंसाएं वैकल्पिक तंत्र (एएम) के समक्ष रखी जाती हैं।
- एएम सीपीएसई को सरकारी नियंत्रण में बनाए रखने या निजीकरण या किसी अन्य पीएसई के साथ विलय या सहायक बनाने या बंद करने पर विचार करने की मंजूरी देता है।
- दीपम सीपीएसई के रणनीतिक विनिवेश के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त करता है।
- दीपम अंतर मंत्रालयी समूह (आईएमजी) के अनुमोदन से निविदा के माध्यम से लेनदेन सलाहकार/कानूनी सलाहकार/परिसंपत्ति मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति करता है।
- इसके अलावा, दो-चरणीय बोली प्रक्रिया (ईओआई /आरएफपी) का पालन किया जाता है। प्रत्येक चरण में, प्रक्रिया स्वीकृत प्रक्रिया के अनुसार बहु-स्तरीय निर्णय लेने की प्रणाली से गुजरती है।

ख. गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में सीपीएसई के लिए

- डीपीई संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों, नीति आयोग, व्यय विभाग और

⁶⁶ विनिवेश पर सचिवों के कोर समूह का नेतृत्व कैबिनेट सचिव करते हैं और इसमें सचिव (आर्थिक मामलों का विभाग), सचिव (राजस्व), सचिव (व्यय), सचिव (दीपम), सचिव (कॉर्पोरेट मामले), सचिव (कानूनी मामले) और प्रशासनिक विभाग के सचिव शामिल होते हैं।

दीपम के परामर्श से बंद करने या निजीकरण के लिए सीपीएसई की पहचान करेगा।

- डीपीई बंद करने और/या विनिवेश के लिए पहचाने गए सीपीएसई के संबंध में सीसीईए से सैद्धांतिक मंजूरी लेगा।
- डीपीई सीसीईए के निजीकरण/विनिवेश के लिए दीपम को सीसीईए की सैद्धांतिक मंजूरी के बारे में सूचित करता है। हालांकि, समापन में, प्रक्रिया प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा शुरू की जाती है।
- दीपम मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगा।

4.3.2 आईपीओ/एफपीओ के माध्यम से अल्पमत हिस्सेदारी की बिक्री में निम्नलिखित चरण शामिल हैं

- संबंधित सीपीएसई के प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा सैद्धांतिक सहमति।
- सीसीईए ने आईपीओ/एफपीओ के माध्यम से सीपीएसई में अल्पसंख्यक हिस्सेदारी के विनिवेश को मंजूरी देती है।
- विनिवेश प्रक्रिया का मार्गदर्शन और निगरानी करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति⁶⁷ (एचएलसी) का गठन।
- प्रस्तावित लेनदेन के लिए आईएमजी द्वारा सलाहकारों (मर्चेट बैंकर्स/बुक रनिंग लीड मैनेजर्स और कानूनी सलाहकार) की नियुक्ति ।
- एचएलसी बुक रनिंग लीड मैनेजर (बीआरएलएम) की सलाह पर विचार करने के बाद वैकल्पिक तंत्र (एएम) को मूल्य बैंड/फ्लोर मूल्य की सिफारिश करता है।
- वैकल्पिक तंत्र मूल्य बैंड/न्यूनतम मूल्य, विनिवेश की विधि और खुदरा निवेशकों और कर्मचारियों के लिए मूल्य छूट पर निर्णय लेता है।

⁶⁷ उच्च स्तरीय समिति में दीपम के सचिव, संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार तथा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव, संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार शामिल हैं।

4.3.3 ओएफएस के माध्यम से अल्पमत हिस्सेदारी की बिक्री में निम्नलिखित चरण शामिल हैं:

- दीपम विभिन्न विभागों के अधिकारियों से मिलकर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करता है।
- एचएलसी ने एएम को यह सिफारिश की कि कितनी अल्पसंख्यक हिस्सेदारी बेची जाए।
- एएम एचएलसी की सिफारिशों पर विचार करता है और सैद्धांतिक मंजूरी देता है।
- मर्चेट बैंकर-सह-सेलिंग ब्रोकर/कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति अंतर-मंत्रालयी समूह⁶⁸ (आईएमजी) की सिफारिश से की जाती है।
- दीपम, प्रशासनिक मंत्रालय और सीपीएसई के साथ मिलकर नॉन-डील रोड शो आयोजित करता है ।
- मर्चेट बैंकर समय, शेयरों की मात्रा और दी जाने वाली छूट की सिफारिश करते हैं।
- एचएलसी मर्चेट बैंकरों की सिफारिशों पर विचार करता है और एएम को समय और मूल्य निर्धारण की सिफारिश करता है।
- वैकल्पिक तंत्र मूल्य बैंड/न्यूनतम मूल्य, विनिवेश की विधि और खुदरा निवेशकों और कर्मचारियों के लिए मूल्य छूट पर निर्णय लेता है।

4.3.4 सीपीएसई द्वारा सरकारी शेयरधारिता की पुनर्खरीद में निम्नलिखित चरण शामिल हैं:

- सीपीएसई का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम में निहित प्रावधानों और दीपम द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार अपने निवल मूल्य और नकदी शेष के आधार पर पुनर्खरीद पर विचार करता है, जब तक कि सीपीएसई में

⁶⁸ अंतर मंत्रालय समूह की अध्यक्षता दीपम तथा प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के सचिव द्वारा होती है व इसमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से नौ सचिव या उनके प्रतिनिधि (भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे नहीं) शामिल होते हैं।

पूंजी प्रबंधन और लाभांश की निगरानी के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा छूट नहीं दी जाती है।

- एचएलसी सीपीएसई के पुनर्खरीद प्रस्ताव में सरकार की भागीदारी के संबंध में एएम को सिफारिश करती है।
- एएम पुनर्खरीद में सरकार की भागीदारी और पुनर्खरीद में सरकार की इक्विटी की पेशकश को मंजूरी देता है।

4.3.5 होल्डिंग/मूल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा रणनीतिक विनिवेश/सहायक कंपनियों/इकाइयों की अल्पमत हिस्सेदारी की बिक्री/संयुक्त उद्यमों में हिस्सेदारी की बिक्री के लिए।

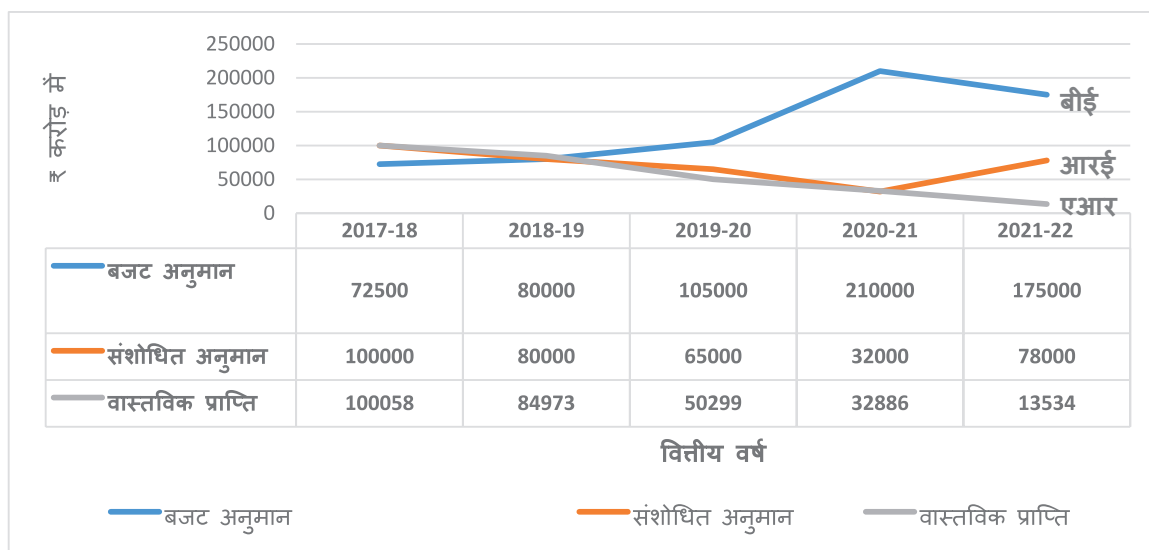
18 मई, 2022 को हुई अपनी बैठक में कैबिनेट ने होल्डिंग/मूल (पीएसई) के निदेशक मंडल को अपनी सहायक कंपनियों/यूनिटों/जेवी में हिस्सेदारी के विनिवेश (रणनीतिक विनिवेश और अल्पांश हिस्सेदारी बिक्री/बंद दोनों) की प्रक्रिया की सिफारिश करने और उसे शुरू करने का अधिकार दिया। इस संबंध में, एएम को उपरोक्त विनिवेश प्रस्ताव के सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए सीसीईए की शक्ति सौंपी गई है जिसे एएम सचिवालय के रूप में दीपम द्वारा संसाधित किया जा रहा है।

4.4 पिछले पांच वर्षों के लिए सीपीएसई के विनिवेश का लक्ष्य और उपलब्धि

किसी वित्तीय वर्ष में विनिवेश के माध्यम से प्राप्तियों के लिए बजट अनुमान आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) द्वारा तय किए जाते हैं। ये दीपम द्वारा प्रदान किए गए इनपुट पर आधारित होते हैं। वर्ष के दौरान हुई प्रगति और संभावित लेन-देन के आधार पर, दीपम डीईए को संशोधित अनुमान बताता है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के लिए बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और विनिवेश प्रक्रिया के माध्यम से की गई वास्तविक प्राप्ति नीचे चार्ट 4.1 में दी गई है:

चार्ट 4.1: लक्षित विनिवेश की तुलना में वास्तविक प्राप्ति



उपर्युक्त चार्ट 4.1 से निम्नलिखित को देखा जा सकता है:

- विनिवेश के माध्यम से प्राप्तियों के लिए बजट अनुमान हर साल लगातार बढ़ रहा है, चालू वर्ष 2021-22 को छोड़कर जहां यह 2020-21 के ₹2,10,000 करोड़ के बजट अनुमानों की तुलना में 16.67 प्रतिशत घटकर ₹1,75,000 करोड़ रह गया।
- वर्ष 2021-22 के लिए ₹ 1,75,000 करोड़ के बजट अनुमान को संशोधित अनुमान चरण में घटाकर ₹78,000 करोड़ कर दिया गया, जो 55 प्रतिशत की कमी दर्शाता है। यहां तक कि इन संशोधित लक्ष्यों को भी हासिल नहीं किया जा सका क्योंकि वास्तविक प्राप्ति केवल ₹13,534 करोड़ थी जो संशोधित अनुमान ₹78,000 करोड़ से काफी कम (82.64 प्रतिशत कम) थी।
- लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि 2021-22 में दीपम के आंतरिक प्रक्षेपण की तुलना में डीईए द्वारा बजट अनुमान और संशोधित अनुमान चरण में प्राप्ति लक्ष्यों में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया था। वर्ष 2021-22 के लिए दीपम द्वारा किए गए बजट अनुमान और संशोधित अनुमानों के लिए विनिवेश प्राप्तियों का आंतरिक प्रक्षेपण ₹1,41,710 करोड़ और ₹1,27,016 करोड़ था, जिसके विरुद्ध डीईए द्वारा अंतिम रूप दिए गए आंकड़े क्रमशः ₹1,75,000 करोड़ और ₹78,000 करोड़ थे। हालाँकि, दीपम द्वारा अनुमानित और डीईए द्वारा अंतिम रूप दिए गए बजट अनुमान और संशोधित अनुमान प्राप्तियों का ब्योरा लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किया गया था।

इस प्रकार, लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि दीपम द्वारा बजट अनुमान और संशोधित अनुमानों के लिए विनिवेश प्राप्तियों का आंतरिक प्रक्षेपण और डीईए द्वारा अंतिम रूप देना वैध इनपुट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों पर आधारित था या नहीं।

दीपम ने उत्तर दिया (जनवरी 2024) कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए संशोधित अनुमान लक्ष्य विभिन्न कारणों से हासिल नहीं किया जा सका, जिसमें लगातार कोविड लहरें, यूक्रेन संकट के बाद भू-राजनीतिक उथल-पुथल, बाजार की स्थिति और आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी और यूएस फेडरल रिजर्व सहित कई केंद्रीय बैंकों द्वारा शेयर बाजार पर व्यापक प्रभाव शामिल हैं। परिणामस्वरूप, भारत के एलआईसी का आईपीओ वर्ष के दौरान अमल में नहीं आ सका और बीपीसीएल के रणनीतिक विनिवेश के लिए रुचि की अभिव्यक्ति को रद्द करना पड़ा। दीपम ने कहा कि विनिवेश एक सतत प्रक्रिया है और महामारी ने वैश्विक स्तर पर भारी आर्थिक अव्यवस्था और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान पैदा किया है। इसने विभाग के लिए विनिवेश लेनदेन, विशेष रूप से बोलीदाताओं की बोली लगाने/निवेश करने की क्षमता में कमी के मद्देनजर रणनीतिक विनिवेश लेनदेन को आगे बढ़ाने में गंभीर बाधाएं पैदा कीं। यह भी बताया कि एलआईसी के आरपीओ का आकार मौजूदा बाजार स्थिति को ध्यान में रखते हुए मूल इंटेंडेड 5 प्रतिशत के कुल शेयर की बजाए 3.5 प्रतिशत कम किया गया। दीपम ने यह भी बताया कि 2021-22 के दौरान विनिवेश प्राप्तियों के लिए बजट अनुमान ₹1,75,000 करोड़ रखा गया था, जिसमें से सीपीएसई से विनिवेश प्राप्तियां ₹75,000 करोड़ थीं और शेष सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों में सरकारी हिस्सेदारी के विनिवेश से थीं। 2014-15 से, सरकार ने अल्पसंख्यक हिस्सेदारी बिक्री मार्ग के माध्यम से ₹3.17 लाख करोड़ का विनिवेश किया है। अल्पसंख्यक हिस्सेदारी बिक्री के माध्यम से इतने बड़े विनिवेश के कारण, अब बिक्री के लिए प्रस्ताव/एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मार्ग के माध्यम से विनिवेश की सीमित गुंजाइश है।

इसके अलावा, दीपम ने कहा कि लेन-देन की बाजार पर निर्भर प्रकृति को देखते हुए और सीपीएसई शेयरों की कीमत में उछाल से बचने के लिए भी विनिवेश के लिए यथार्थवादी लक्ष्य तय करने की आवश्यकता है। इसलिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 और उसके बाद के दौरान लक्ष्यों को उत्तरोत्तर कम करके अधिक व्यावहारिक स्तर पर लाया गया है।

सीपीएसई के अनुसार संशोधित एवं बजट अनुमान प्राप्तियों का ब्यौरा लेखापरीक्षा को

उपलब्ध नहीं कराए जाने के संबंध में, यह कहा गया कि सीपीएसई वार अपेक्षित विनिवेश प्राप्तियां दीपम के लिए आंतरिक हैं और केवल समेकित अनुमान ही डीईए के साथ साझा किए गए थे। संशोधित अनुमान/बजट अनुमान केवल मौजूदा बाजार स्थितियों और लेनदेन की व्यवहार्यता के आधार पर तय किए गए अनुमान हैं। हालांकि, प्राप्तियों की अंतिम प्राप्ति मौजूदा बाजार स्थितियों, घरेलू और वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण और निवेशकों की रुचि पर निर्भर करती है।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि यूक्रेन संकट फरवरी 2022 में शुरू हुआ था। इसके अलावा, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के विनिवेश की प्रक्रिया फरवरी 2022 में ही ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखिल करने के साथ शुरू हुई थी। इसके अलावा, चूंकि वित्तीय बाजार गतिशील है और बदलता रहता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि बजट अनुमान और संशोधित अनुमान लक्ष्य तय करने से पहले बाजार के रुझानों का विश्लेषण करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन किया जाए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2021-22 के दौरान बजट अनुमान और संशोधित अनुमान लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक प्राप्ति क्रमशः मात्र 8 प्रतिशत और 17 प्रतिशत थी।

संघ सरकार (वाणिज्यिक) - केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सामान्य प्रयोजन वित्तीय रिपोर्ट पर सीएजीकी 2022 की रिपोर्ट संख्या 27 (सिफारिश संख्या 1) में दीपम से इनपुट लेने के बाद डीईए द्वारा यथार्थवादी बजट अनुमानों के निर्धारण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक कुशल और प्रभावी बजट प्रक्रिया को सक्षम करने के लिए वर्ष के दौरान निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति योग्य हों। हालांकि, इसका अनुपालन नहीं किया गया जैसा कि उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है।

लेखापरीक्षा का मानना है कि दीपम द्वारा बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों का प्रक्षेपण तथा आर्थिक कार्य विभाग द्वारा आगे अंतिम रूप दिया जाना यथार्थवादी होना चाहिए, क्योंकि बजट में व्यय की योजना अनुमानित प्राप्तियों के अनुरूप बनाई जाती है।

4.5 पिछले पांच वर्षों के दौरान विनिवेश से मोड-वार प्राप्ति

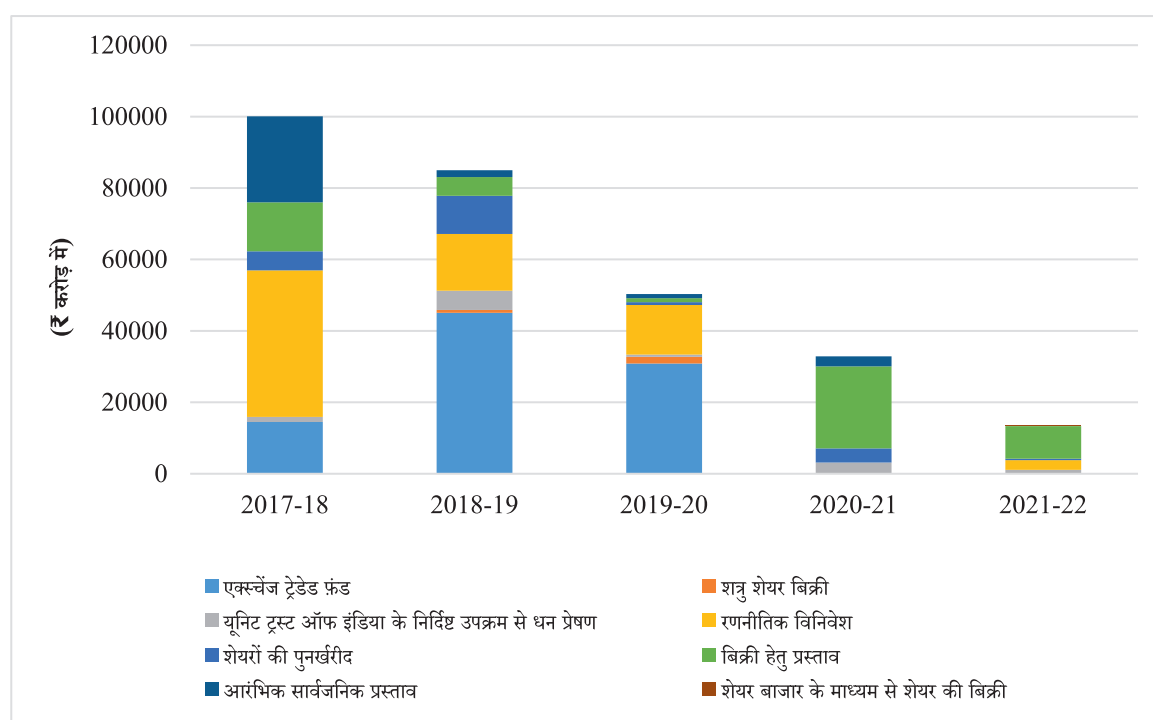
2017-18 से 2021-22 के दौरान विनिवेश से वास्तविक प्राप्तियों का मोड-वार विवरण तालिका 4.1 और चार्ट 4.2 में दिया गया है:

तालिका 4.1: पिछले पांच वर्षों के दौरान मोड-वार प्राप्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
एक्सचेंज ट्रेडेड फंड	14,500	45,080	30,869	0	0
शत्रु शेयर बिक्री	0	779	1,881	41	4
यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निर्दिष्ट उपक्रम से धन प्रेषण	1,400	5,379	600	3,125	1,107
रणनीतिक विनिवेश	41,069	15,914	13,883	0	2,700
शेयरों की पुनर्खरीद	5,338	10,671	822	3,936	394
बिक्री हेतु प्रस्ताव	13,711	5,236	1,130	22,983	9,110
आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव	24,040	1,914	1,114	2,801	0
शेयर बाजार के माध्यम से शेयर की बिक्री	0	0	0	0	219
कुल	1,00,058	84,973	50,299	32,886	13,534

चार्ट 4.2: पिछले पांच वर्षों के दौरान मोड-वार प्राप्ति



तालिका 4.1 और चार्ट 4.2 से स्पष्ट है कि पिछले पाँच वर्षों के दौरान कुल विनिवेश आय में लगातार गिरावट देखी गई, जो वर्ष 2017-18 में ₹1,00,058 करोड़ से घटकर वर्ष 2021-22 में ₹13,534 करोड़ हो गई, यानी 85 प्रतिशत से अधिक की गिरावट। वर्ष 2021-22 के दौरान विनिवेश का मोड-वार विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 4.2: 2021-22 के दौरान विनिवेश प्राप्तियों का मोड-वार विवरण

क्रम. सं.	विनिवेश का तरीका	लेन-देन की संख्या	प्राप्तियां (₹ करोड़ में)
1.	रणनीतिक विनिवेश	1	2,700
2	बिक्री हेतु प्रस्ताव*	4	9,110
3.	पुनर्खरीद	1	394
4.	शेयर बाजार के माध्यम से शेयरों की बिक्री	1	219
5.	यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निर्दिष्ट उपक्रम से ब्याज और लाभांश आय सहित शेयरों की बिक्री आय से प्राप्त धन	1	1,107
6.	शत्रु शेयरों की बिक्री	1	4
कुल		9	13,534

* इसमें एसयूटीआई की एक्सिस बैंक रणनीतिक होल्डिंग के विनिवेश से प्राप्त ₹3,994 करोड़ रुपये की आय भी शामिल है।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका 4.2 में दर्शाया गया है, दीपम ने 2021-22 के दौरान नौ लेनदेन के माध्यम से ₹13,534 करोड़ की राशि प्राप्त की।

विनिवेश के विभिन्न मामलों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

4.6 अल्पसंख्यक हिस्सेदारी बिक्री - आरंभिक सार्वजनिक पेशकश और बिक्री के लिए प्रस्ताव

4.6.1 आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव

4.6.1.1 आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से विनिवेश से प्राप्ति की तुलना में अनुमानित प्राप्तियां

दीपम ने 2021-22 के दौरान बजट अनुमान चरण में आरंभिक सार्वजनिक पेशकश मोड के माध्यम से क्रमशः ₹50,000 करोड़ और ₹200 करोड़ के लिए एलआईसी और टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) के विनिवेश की पहचान की, हालांकि, संशोधित अनुमान चरण में केवल एलआईसी के विनिवेश का अनुमान लगाया गया था। एलआईसी और टीसीआईएल के आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव 31 मार्च, 2022 तक पूरे नहीं हुए, जिसके परिणामस्वरूप आरंभिक सार्वजनिक पेशकश मोड के माध्यम से आय की 'शून्य' प्राप्ति हुई। वर्ष के दौरान एलआईसी और टीसीआईएल दोनों के विनिवेश में हुई प्रगति इस प्रकार है:

(i) एलआईसी

वित्त मंत्री ने 2020-21 के बजट भाषण में घोषणा की थी कि सरकार ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी का एक हिस्सा बेचने का प्रस्ताव रखा है। वर्ष 2021-22 के दौरान, दीपम ने बजट अनुमान और संशोधित अनुमान दोनों चरणों में एलआईसी में विनिवेश का अनुमान लगाया था, जिसमें प्रत्येक चरण में ₹50,000 करोड़ की अनुमानित राशि थी। आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से वैकल्पिक तंत्र को शक्तियों के प्रत्यायोजन के साथ एलआईसी के विनिवेश पर सीसीईए की मंजूरी 08 जुलाई, 2021 को ली गई थी। लेखापरीक्षा ने नोट किया कि वैकल्पिक तंत्र ने एलआईसी के कुल मूल्यांकन ₹6,00,000 करोड़ (लगभग) में से 3.5 प्रतिशत विनिवेश को मंजूरी दी थी। हालांकि, प्रस्ताव का आकार, जारी करने की तिथियां, मूल्य बैंड, बोली लॉट और अन्य प्रस्ताव संबंधी मामलों को वित्तीय वर्ष 2021-22 के बाद ही अंतिम रूप दिया गया। वर्ष 2022-23 में विनिवेश के माध्यम से की गई वास्तविक प्राप्ति ₹20,516.12 करोड़ थी जो कि ₹50,000 करोड़ के अनुमानित अनुमान से कम थी। दीपम ने जवाब दिया (जनवरी 2024) कि बजट अनुमान और संशोधित अनुमान दोनों

चरणों में एलआईसी के विनिवेश के अनुमान भारतीय एम्बेडेड मूल्य (आईईवी) की गणना होने तक और बाजार की प्रतिक्रिया मिलने तक ₹50,000 करोड़ की अनुमानित राशि के साथ किए गए थे। ₹50,000 करोड़ के अनुमानित अनुमान और ₹20,516.12 करोड़ की वास्तविक प्राप्ति के बीच का अंतर हिस्सेदारी कमजोर पड़ने के प्रतिशत में 5 प्रतिशत से 3.5 प्रतिशत तक की गिरावट के कारण था, क्योंकि निवेशकों के साथ विचार-विमर्श के बाद यह महसूस किया गया था कि बाजार की क्षमता केवल छोटे आकार के आईपीओ के लिए थी। इसके अलावा, यह कहा गया कि प्रस्ताव का आकार, जारी करने की तारीखें, मूल्य बैंड, बोली लॉट और अन्य प्रस्ताव संबंधी मामलों को एलआईसी के एम्बेडेड मूल्य (ईवी) को अंतिम रूप देने और उस समय निवेशकों की मांग का आकलन करने, जो कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बाद हुए, के बाद अंतिम प्रॉस्पेक्टस दाखिल करने के चरण में ही अंतिम रूप दिया जा सकता है दीपम ने दोहराया कि कोविड महामारी के कारण बड़े पैमाने पर व्यवधानों के बीच एलआईसी-आईपीओ के लिए कई तरह की गतिविधियाँ की जानी थीं। यूक्रेन संकट और फेड नीतियों के परिणामस्वरूप, पूंजी बाजार में भारी अस्थिरता थी और ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखिल करने के बाद निवेशकों की रुचि कम हो गई, जिसके परिणामस्वरूप एलआईसी आईपीओ को स्थगित कर दिया गया और इसे छोटा कर दिया गया।

(ii) टीसीआईएल

दीपम ने बजट अनुमान चरण में टीसीआईएल में 200 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि के विनिवेश का अनुमान लगाया था। हालांकि, संशोधित अनुमान चरण में, टीसीआईएल को विनिवेश के लिए प्रस्तावित नहीं किया गया।

दीपम ने जवाब दिया (जनवरी 2024) कि टीसीआईएल पिछले तीन वित्तीय वर्षों में समेकित आधार पर निरंतर शुद्ध घाटा उठा रही है, स्टैंडअलोन आधार पर लाभप्रदता में गिरावट और वर्ष 2021-22 के दौरान महामारी के प्रभाव के कारण उम्मीदें कम रहीं, वित्तीय वर्ष 2020-21 में ऑर्डर बुक की वृद्धि स्थिर रही, जो कि टीसीआईएल और भारती एयरटेल (30:70) के बीच संयुक्त उद्यम भारती हेक्साकॉम लिमिटेड को हुए नुकसान से और अधिक प्रभावित हुई। इसलिए, सीसीईए द्वारा तत्काल तीन पूर्ववर्ती वित्त वर्षों में से किसी में शुद्ध लाभ पर सीपीएसई की सूचीबद्धता के लिए संशोधित पात्रता मानदंड को मंजूरी देने और समेकित स्तर पर टीसीआईएल के लगातार घाटे के कारण, टीसीआईएल

आईपीओ के लॉन्च पर निर्णय लेने के लिए आईपीओ को बाद में रोक दिया गया क्योंकि यह निवेशकों से कोई ट्रेक्शन आकर्षित नहीं करेगा। दीपम ने आगे बताया कि 05 अप्रैल, 2021 को नीति आयोग में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भारती हेक्साकॉम लिमिटेड में टीसीआईएल के शेयरों के विनिवेश के बाद टीसीआईएल के विनिवेश पर विचार किया जाएगा।

4.6.1.2 वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान नियोजित आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव/अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव के प्रसंस्करण में देरी

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, दीपम ने संशोधित अनुमान चरण में वैपकोस लिमिटेड और केआईओसीएल लिमिटेड के विनिवेश की पहचान की। हालाँकि, 31 मार्च, 2021 तक दोनों सीपीएसई असूचीबद्ध रहे। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि दोनों सीपीएसई को वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बजट अनुमान और संशोधित अनुमान चरण में विनिवेश के लिए प्रोजेक्टेड नहीं किया गया था। स्थिति इस प्रकार है:

- **वैपकोस:** सीसीईए ने 27 दिसंबर, 2018 को वैपकोस के आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव को मंजूरी दी। बुक रनिंग लीड मैनेजर और कानूनी सलाहकार की नियुक्ति क्रमशः 18 नवंबर, 2019 और 14 फरवरी, 2020 को की गई। रजिस्ट्रार और विज्ञापन एजेंसी की नियुक्ति 25 जून, 2021 को की गई। आगे, उच्च स्तरीय समिति ने 8 अगस्त, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसे 26 सितंबर, 2022 को दाखिल किया गया।

दीपम ने जवाब दिया (जनवरी 2024) कि उच्च स्तरीय समिति ने 05 सितंबर, 2023 को बुक रनिंग लीड मैनेजर्स (बीआरएलएम) और लेखापरीक्षक की टिप्पणियों पर ध्यान दिया कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 2023 के लिए परिचालन घाटा दर्ज किया है और कंपनी का औसत परिचालन लाभ भी नकारात्मक था और इसलिए, कंपनी सेबी (पूँजी जारी करने और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन के खंड 6(1) के तहत सार्वजनिक प्रस्ताव के लिए अयोग्य थी। चूंकि कंपनी सार्वजनिक प्रस्ताव के लिए अयोग्य हो गई, इसलिए उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुसार कंपनी का डीआरएचपी सेबी से वापस ले लिया गया।

- **केआईओसीएल लिमिटेड:** सीसीईए ने 27 दिसंबर, 2018 को केआईओसीएल लिमिटेड के सार्वजनिक पेशकश पर अनुपालन की मंजूरी दे दी। 18 जुलाई, 2019 को मर्चेंट बैंकर और कानूनी सलाहकार नियुक्त किए गए। दिसंबर, 2020 में उच्च स्तरीय समिति की बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन केआईओसीएल लिमिटेड द्वारा देवदरी खदानों के लिए प्रथम चरण की वन मंजूरी प्राप्त होने तक इसे स्थगित कर दिया गया था। रिकॉर्ड के अनुसार, एक उप-समिति ने मार्च 2021 में खदानों का दौरा किया और इस प्रकार, अगली उच्च स्तरीय समिति की बैठक अप्रैल 2021 में प्रस्तावित की गई क्योंकि समर्पित लौह अयस्क खदानों के लिए वन मंजूरी के संबंध में कुछ समस्या थी।

दीपम ने जवाब दिया (जनवरी 2024) कि वन मंजूरी न मिलने के कारण पहले रुकी हुई विनिवेश प्रक्रिया का समाधान हो गया है। इसके अलावा, कंपनी की शेयरधारिता का बहुत छोटा हिस्सा जनता के पास होने के कारण, बाजार में इस शेयर का बहुत कम कारोबार होता है, जिसके कारण एक्सचेंज में कंपनी के शेयर की कीमत निवेशकों के दृष्टिकोण से उचित मूल्य का संकेत नहीं देती है। साथ ही, कंपनी का व्यवसाय और वित्तीय प्रदर्शन फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर के लॉन्च के लिए अनुकूल नहीं है। इसलिए, सेबी के परामर्श से इस मामले के बारे में उचित निर्णय लिया जाएगा।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि केआईओसीएल ने दिसंबर 2018 में सीसीईए द्वारा विनिवेश को मंजूरी देने से पहले कंपनी के वित्त वर्ष 2017-18 के अंतिम उपलब्ध वार्षिक वित्तीय विवरणों के अनुसार कर पूर्व लाभ (लाभ) ₹86.08 करोड़ बताया था। इसके अलावा, कंपनी का लाभ वित्त वर्ष 2018-19 में बढ़कर ₹184.12 करोड़ हो गया, यानी उस वर्ष के दौरान, जिसमें प्रारंभिक विनिवेश प्रस्तावित किया गया था; और बाद में कंपनी ने वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान ₹410.23 करोड़ और ₹411.03 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया। इस प्रकार, कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन संतोषजनक प्रतीत हुआ। इसके अलावा, कंपनी की शेयरधारिता का बहुत छोटा हिस्सा जनता के पास होने का दीपम द्वारा बताया गया कारण दीपम द्वारा विनिवेश की योजना बनाने और दिसंबर 2018 में सीसीईए द्वारा कंपनी के फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर को मंजूरी देने के समय पहले से मौजूद था। सीसीईए की मंजूरी के पांच साल बीत जाने के बाद भी सार्वजनिक ऑफर लॉन्च करने का निर्णय अभी (जनवरी 2024) लिया जाना था।

4.6.2 बिक्री प्रस्ताव

4.6.2.1 बिक्री प्रस्ताव के माध्यम से विनिवेश से प्राप्ति की तुलना में अनुमानित प्राप्तियां

बजट अनुमान चरण में आठ सीपीएसई से बिक्री प्रस्ताव के माध्यम से ₹19,710 करोड़ प्राप्त करने का अनुमान लगाया गया था। हालाँकि, इन आठ सीपीएसई में से, केवल दो सीपीएसई को संशोधित अनुमान में बनाए रखा गया था, जिसमें ₹4,400 करोड़ की अपेक्षित विनिवेश प्राप्तियाँ थी। इसके अलावा, संशोधित अनुमान चरण में आठ अन्य सीपीएसई की पहचान की गई थी, जिसमें ₹10,627 करोड़ की अपेक्षित प्राप्ति थी, जबकि 10 सीपीएसई से कुल प्राप्तियाँ ₹15,027 करोड़ होने का अनुमान था।

हालाँकि, 2021-22 के दौरान केवल तीन सीपीएसई यानी एनएमडीसी लिमिटेड, आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में विनिवेश हुआ, जिसमें ₹5,116 करोड़ की शुद्ध आय हुई, जो संशोधित अनुमान चरण की अनुमानित राशि का 34.05 प्रतिशत था। इसके अलावा, 2022-23 में दो और सीपीएसई में विनिवेश हुआ, जिन्हें 2021-22 में संशोधित अनुमान चरण में पहचाना गया था यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड, और ₹3,530.28 करोड़ की राशि प्राप्त हुई।

इसलिए, जैसा कि ऊपर से देखा जा सकता है, बजट अनुमान चरण में ओएफएस के लिए पहचाने गए छह सीपीएसई को बाद में संशोधित अनुमान चरण में छोड़ दिया गया, बजट अनुमान चरण के साथ-साथ संशोधित अनुमान चरण में बिक्री प्रस्ताव के लिए पहचाने गए दो सीपीएसई और संशोधित अनुमान चरण में बिक्री के लिए प्रस्ताव के लिए पहचाने गए पांच सीपीएसई को वर्ष 2021-22 के दौरान मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि 2019-20 में स्वीकृत और 2020-21 के संशोधित अनुमान चरण में योजनाबद्ध अन्य दो सीपीएसई में बिक्री के लिए प्रस्ताव आज तक नहीं किया गया है। यह भी देखा गया कि हालाँकि इनमें से कुछ सीपीएसई में विनिवेश के लिए सीसीईए/वैकल्पिक तंत्र की मंजूरी वर्ष 2015 से 2018 के बीच दी गई थी, लेकिन वर्ष 2021-22 तक विनिवेश नहीं हो सका।

दीपम ने जवाब दिया (जनवरी 2024) कि यह निकट से मध्यम अवधि के बाजार की स्थितियों के बारे में मौजूदा अपेक्षाओं के आधार पर प्रत्येक चरण (बीई और आरई चरणों)

में अस्थायी अनुमान लगाता है। हालांकि, बाजार की स्थिति, कंपनी का प्रदर्शन और आर्थिक हित बदलते रहते हैं। वास्तविक लेन-देन इन कारकों के आधार पर किए जाते हैं। दीपम ने यह भी कहा कि कैबिनेट समिति से मंजूरी का लेन-देन के समय से कोई संबंध नहीं है।

यह भी कहा गया कि विभाग ने अनुभव किया है कि बहुत अधिक विनिवेश लक्ष्य से पीएसयू शेयरों में नए निर्गमों की अपेक्षित अधिक आपूर्ति के कारण मूल्य वृद्धि होती है। इसलिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान उत्तरोत्तर लक्ष्यों को अधिक व्यावहारिक स्तरों तक घटा दिया गया है। दीपम की सुविचारित विनिवेश रणनीति ने पीएसयू शेयरों के बेहतर मूल्य के रूप में लाभ दिया है क्योंकि पिछले दो वर्षों से पीएसई सूचकांक ने निफ्टी और सेंसेक्स से बेहतर प्रदर्शन किया है।

4.6.2.2 खुदरा एवं कर्मचारियों के लिए बिक्री प्रस्ताव के लक्ष्यों की उपलब्धियाँ

2021-22 के दौरान पूर्ण किए गए गैर-खुदरा निवेशकों/खुदरा निवेशकों और कर्मचारी ऑफर फॉर सेल लेनदेन के लिए प्राप्त सब्सक्रिप्शन का विवरण नीचे तालिका 4.3 में दिया गया है:

तालिका 4.3: गैर-खुदरा निवेशकों/खुदरा निवेशकों और कर्मचारी बिक्री प्रस्ताव के लिए प्राप्त सब्सक्रिप्शन

(प्रतिशत में)

सीपीएसई का नाम	प्रस्तावित विनिवेश	ग्रीन शू ऑप्शन ⁶⁹	कुल प्रस्तावित विनिवेश	वास्तविक विनिवेश	गैर-खुदरा निवेशकों के लिए सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुई	खुदरा निवेशकों के लिए सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुई	कर्मचारी बिक्री प्रस्ताव के लिए सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुई
हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	5.00	5.00	10.00	6.61	141.25	36.87	0.05
आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड	5.50	2.50	8.00	8.00	195.86	18.39	0.15
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	4.00	3.49	7.49	7.49	213.75	75.56	1.66

⁶⁹ ग्रीन शू विकल्प एक अंडरराइटिंग समझौते में एक प्रावधान है जो अंडरराइटर को निवेशकों को जारीकर्ता द्वारा शुरू की गई योजना से अधिक शेयर बेचने का अधिकार देता है।

तालिका 4.3 से यह स्पष्ट है कि 2021-22 के दौरान खुदरा निवेशकों और कर्मचारियों के लिए किए गए सभी बिक्री प्रस्ताव लेनदेन कम सब्सक्राइब हुए। खुदरा निवेशकों के लिए बिक्री प्रस्ताव के मामले में, सब्सक्रिप्शन 18.39 प्रतिशत और 75.56 प्रतिशत के बीच था, जबकि कर्मचारियों के लिए बिक्री प्रस्ताव के मामले में, सब्सक्रिप्शन 0.05 प्रतिशत और 1.66 प्रतिशत के बीच था।

दीपम ने जवाब दिया (जनवरी 2024) कि सेबी के मानदंडों के अनुसार, ओएफएस के आकार का न्यूनतम 10 प्रतिशत खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित किया जाना है। यह आरक्षण उनके बीच स्टॉक की मांग से इतर है, जिससे खुदरा श्रेणी में कम सब्सक्रिप्शन हो सकता है। खुदरा निवेशक ओएफएस विंडो के माध्यम से द्वितीयक बाजार से समान स्टॉक खरीदने में अधिक सहज महसूस कर सकते हैं क्योंकि उनकी वांछित मात्रा कम होती है और आमतौर पर ओएफएस लॉन्च के बाद स्टॉक की कीमत भी द्वितीयक बाजार में कम हो जाती है। इसलिए, खुदरा निवेशकों के साथ-साथ, सेबी के मानदंड गैर-खुदरा निवेशकों को भी टी + 1 दिन पर खुदरा बकेट भरने की अनुमति देते हैं यदि यह कम सब्सक्राइब रहता है।

इसके अलावा, दीपम ने यह भी उत्तर दिया कि मुख्य लेनदेन के बाद दो सप्ताह के भीतर कर्मचारी ओएफएस पूरा करना आवश्यक है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि कर्मचारियों को दिए जाने वाले मूल्य की तुलना में द्वितीयक बाजार में स्टॉक किस मूल्य पर कारोबार कर रहा है। आम तौर पर ओएफएस के 2-3 दिनों के बाद, ओएफएस शेयरों की अतिरिक्त आपूर्ति के कारण शेयर की कीमत में ओर कमी आ सकती है। कर्मचारियों के हिस्से के लिए ओएफएस के आकार का 5 प्रतिशत आरक्षित करना भी कम सब्सक्रिप्शन का एक कारण है क्योंकि कर्मचारियों के बीच उनकी कंपनी के शेयर की मांग के बावजूद आरक्षण किया जाता है। इस आरक्षण पद्धति की समीक्षा की गई है और हाल के ओएफएस लेनदेन में, दीपम पहले कंपनी के माध्यम से कर्मचारियों से शेयरों की संख्या के लिए रुचि मांगता है और केवल उतने ही शेयर आरक्षित किए जाते हैं। ओएफएस में भागीदारी के लिए कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त छूट नहीं दी जा रही है।

जबकि लेखापरीक्षा इस बात की सराहना करता है कि ओएफएस का समग्र लक्ष्य पूरा हो गया था, हालांकि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि उस समय वैकल्पिक तंत्र द्वारा अनुमोदित प्रासंगिक पद्धति के आधार पर 0.05 प्रतिशत और 1.66 प्रतिशत के बीच

कर्मचारी सब्सक्रिप्शन कम रही। यह तथ्य नोट किया गया है कि कर्मचारियों के लिए बिक्री की पेशकश के मामले में आरक्षण पद्धति की दीपम द्वारा समीक्षा की गई है।

4.7 मॉयल लिमिटेड में शेयरों की पुनर्खरीद

सीपीएसई के पूंजी पुनर्गठन पर दिशानिर्देश (मई 2016) में कहा गया है कि जिन मामलों में सीपीएसई व्यवहार्य व्यावसायिक विस्तार के लिए नकदी/बैंक बैलेंस का उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं, शेयरों की पुनर्खरीद से कंपनी में निवेशकों का विश्वास बढ़ता है और इससे कंपनी को भविष्य में पूंजी जुटाने में मदद मिलने की संभावना है, जब उसे विस्तार के लिए धन की आवश्यकता होगी। इन दिशानिर्देशों में आगे कहा गया है कि प्रत्येक सीपीएसई को अपने नकदी और बैंक बैलेंस, पूंजीगत व्यय और व्यावसायिक विस्तार, निवल मूल्य, दीर्घकालिक उधार, किसी भी अन्य वित्तीय प्रतिबद्धताओं, अन्य प्राप्तियों और आकस्मिक देनदारियों और शेयर के बाजार मूल्य का विश्लेषण करना था। इस विश्लेषण के आधार पर, यह स्पष्ट रूप से सामने आना चाहिए कि सीपीएसई के पास अधिशेष नकदी और बैंक बैलेंस को पुनर्खरीद के माध्यम से पूंजी के पुनर्गठन के लिए विचार किया जाना था। हालांकि, कम से कम ₹2,000 करोड़ के निवल मूल्य और ₹1,000 करोड़ से अधिक के नकद शेष वाले प्रत्येक सीपीएसई को अपने शेयरों को वापस खरीदने के विकल्प का उपयोग करना था।

दीपम के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, 54 सूचीबद्ध सीपीएसई में से कुल 27 सीपीएसई शेयरों की पुनर्खरीद के लिए पात्र थे। वर्ष 2021-22 के संशोधित अनुमान चरण में केवल एक पुनर्खरीद लेनदेन यानी मॉयल लिमिटेड की पहचान की गई थी, जिसकी अनुमानित आय ₹400 करोड़ थी।

मॉयल बोर्ड ने (10 नवंबर, 2021) ₹205 प्रति इक्विटी शेयर के पुनर्खरीद मूल्य पर मॉयल लिमिटेड की निवल मूल्य के 25 प्रतिशत के पुनर्खरीद पर विचार किया और उसे मंजूरी दी। उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों (10 नवंबर, 2021) के आधार पर, वैकल्पिक तंत्र ने मॉयल में इक्विटी शेयरों के पुनर्खरीद में सरकार की भागीदारी को इस शर्त के अधीन मंजूरी दी कि भारत सरकार की शेयरधारिता 51 प्रतिशत से कम नहीं होगी। इसके अलावा, पुनर्खरीद के लिए उपलब्ध कुल 3,38,42,668 शेयरों में से, भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने प्रमोटर होने के नाते पुनर्खरीद के लिए उपलब्ध 62.36 प्रतिशत

शेयरों को बेच दिया और शेष 37.64 प्रतिशत शेयर जनता द्वारा बेचे गए। मॉयल द्वारा पुनर्खरीद प्रक्रिया के बाद भारत सरकार को ₹393.77 करोड़ की आय प्राप्त हुई।

दीपम ने उत्तर दिया (जनवरी 2024) कि जहां सीपीएसई ओएफएस, कैपेक्स योजना, निवल मूल्य पुनर्गठन, उधार क्षमता/ पूंजी उत्तोलन अनुपात, बाजार मूल्य आदि जैसे पूंजी प्रबंधन और पुनर्गठन के लिए कुछ अन्य प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ने की योजना बना रहा था, वहां बायबैक संभव नहीं था। इसलिए, समय समय पर सीपीएसई में पूंजी प्रबंधन और लाभांश (सीएमसीडीसी) की निगरानी के लिए अंतरमंत्रालयी समिति द्वारा उपर्युक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए, मामले के आधार पर सीपीएसई को छूट देने के लिए निर्णय लिया गया था।

4.8 भारतीय पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की शेष हिस्सेदारी बिक्री के माध्यम से विनिवेश

भारतीय पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो सरकार का एक पूर्ववर्ती सीपीएसई था, का वर्ष 2002 में निजीकरण कर दिया गया था और बाद में वर्ष 2007 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ विलय कर दिया गया था। सीसीईए ने किसी अन्य निवेशक की तरह शेयर बाजार पर 8,32,480 इक्विटी शेयरों की बिक्री को मंजूरी दी (28 अप्रैल, 2021) क्योंकि सरकार प्रमोटर के रूप में बिक्री के लिए प्रस्ताव के माध्यम से शेयरधारिता बेचने के लिए पात्र नहीं थी। भारत सरकार के निर्णय के अनुसार मर्चेट बैंकर द्वारा 07 अक्टूबर, 2021 और 25 अक्टूबर, 2021 के बीच छह किस्तों में लेन-देन किया गया, जिससे ₹219.34 करोड़ की विनिवेश प्राप्तियां हुईं।

4.9 यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निर्दिष्ट उपक्रम द्वारा अर्जित ब्याज और लाभांश आय को शामिल करने के कारण विनिवेश प्राप्तियों को ₹1,107 करोड़ अधिक बताया गया

यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का गठन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अधिनियम, 1963 के तहत किया गया था और इसे 18 दिसंबर, 2002 को यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (उपक्रम का हस्तांतरण और निरसन) अधिनियम 2002 (निरसन अधिनियम, 2002) के माध्यम से निरस्त कर दिया गया और इसे दो नई संस्थाओं में पुनर्गठित किया गया, जिनका नाम

यूटीआई ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड⁷⁰ और स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। दोनों संस्थाओं को यूटीआई (निरसन) अधिनियम, 2002 के तहत संसद द्वारा आवंटित विभिन्न योजनाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निर्दिष्ट उपक्रम ने ₹1,107 करोड़ की ब्याज और लाभांश आय दीपम को प्रेषित की, जिसे विनिवेश प्राप्तियों के अंतर्गत शामिल किया गया था। चूंकि यह आय सरकारी शेयरधारिता से प्राप्त धन का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसे विनिवेश प्राप्तियों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2021-22 के दौरान विनिवेश प्राप्तियों को ₹1,107 करोड़ तक बढ़ाकर बताया गया है।

दीपम ने जवाब दिया (जनवरी 2024) कि उसने सही वर्गीकरण के लिए इस मामले को लेखा महानियंत्रक (सीजीए) के वेतन एवं लेखा कार्यालय के समक्ष उठाया है। इस मामले में कोई भी बदलाव सीजीए से परामर्श के बाद उनकी सलाह पर किया जाएगा।

4.10 रणनीतिक विनिवेश (सीपीएसई में भारत सरकार की बहुलांश हिस्सेदारी की बिक्री)

रणनीतिक विनिवेश का मतलब है पहचाने गए सीपीएसई में सरकार की पूरी या पर्याप्त हिस्सेदारी की बिक्री और साथ ही प्रबंधन नियंत्रण का हस्तांतरण। सीसीईए ने 31 मार्च, 2022 तक 36 सीपीएसई में रणनीतिक विनिवेश के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी दे दी है। रणनीतिक विनिवेश लेनदेन की स्थिति जिसके लिए सीसीईए ने अप्रैल 2022 तक 'सैद्धांतिक' मंजूरी दी है, नीचे तालिका 4.4 में दी गई है। प्रत्येक चरण के तहत कंपनियों के नाम नीचे *अनुलग्नक-XXII* में दिए गए हैं।

तालिका 4.4: रणनीतिक विनिवेश लेनदेन की स्थिति

अवस्था	संख्या
दीपम द्वारा संसाधित किए जा रहे चालू लेनदेन जिनमें ईओआई जारी किया गया है	8
ऐसे लेन-देन जिनमें ईओआई जारी नहीं किया गया है या ईओआई/आरएफपी जारी करने के बाद लेनदेन रद्द कर दिया गया है	6
संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा संसाधित किए जा रहे लेनदेन	3

⁷⁰ सेबी के माध्यम से पंजीकृत यूटीआई म्यूचुअल फंड, यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड - को निवेश प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है।

अवस्था	संख्या
मुकदमेबाजी के कारण लेन-देन रुका	2
सीपीएसई द्वारा बंद करने की सिफारिश/अनुमोदन के कारण लेनदेन रुका; कोई अन्य कारण	5
लेन-देन संभव नहीं	2
लेन-देन पूरा हुआ*	10
अब तक कुल रणनीतिक विनिवेश पर विचार किया गया	36

* नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड का लेन-देन वर्ष 2022-23 में पूरा किया गया।

वर्ष 2021-22 के लिए दीपम द्वारा किए गए बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों के लिए रणनीतिक विनिवेश प्राप्तियों का समग्र अनुमान क्रमशः ₹66,900 करोड़ और ₹56,715 करोड़ था। हालाँकि, वर्ष 2021-22 के दौरान केवल एक सीपीएसई अर्थात्, एयर इंडिया लिमिटेड, इसकी एक सहायक कंपनी, एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड (एआईएक्सएल) और इसकी संयुक्त उद्यम कंपनी, एयर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एआईएसएटीएस) का कुल ₹18,000 करोड़ में विनिवेश किया गया था, जिसमें सरकार को स्ट्रैटेजिक पार्टनर (मैसर्स टैलेस प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) से ₹2,700 करोड़ का नकद प्रतिफल प्राप्त हुआ था। रणनीतिक साझेदार ने एयर इंडिया के शेयरों (एयर इंडिया और इसकी सहायक कंपनी एआईएक्सएल के 100% शेयर और एआईएसएटीएस के 50% शेयर) के साथ-साथ एयर इंडिया और एआईएक्सएल में ₹15,300 करोड़ का कर्ज टेकओवर किया। इस प्रकार, दीपम ने संशोधित अनुमान चरण में अनुमानित अपने रणनीतिक विनिवेश लक्ष्य का 32 प्रतिशत से भी कम हासिल किया है।

दीपम ने जवाब दिया (जनवरी 2024) कि 2021-22 में रणनीतिक विनिवेश लक्ष्य में कमी मुख्य रूप से भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के विभिन्न कारणों से विनिवेश से हटने से संबंधित है, जैसे कि कई कोविड-19 लहरों और भू-राजनीतिक स्थितियां, अधिकांश क्यूआईपी ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में मौजूदा स्थितियों के कारण बीपीसीएल के विनिवेश की वर्तमान प्रक्रिया को जारी रखने में असमर्थता व्यक्त की है आदि। इन कारणों को देखते हुए, भारत सरकार ने बीपीसीएल के रणनीतिक विनिवेश के लिए वर्तमान ईओआई प्रक्रिया को बंद करने का फैसला किया है और स्थिति की समीक्षा के आधार पर फिर से

शुरू करने पर निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और बीईएमएल लिमिटेड की विनिवेश समय सीमा में गैर-कोर अधिशेष भूमि संपत्ति को अलग करने के लिए राज्य सरकार से अविलयन प्रक्रिया और भूमि संबंधी मंजूरी के कारण देरी हुई। रेलवे द्वारा भूमि पट्टा नीति को अंतिम रूप देने में लगने वाले समय के कारण कॉनकोर के स्ट्रैटेजिक विनिवेश की प्रक्रिया में देरी हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के लिए वित्तीय सेवा विभाग द्वारा संबंधित कानून में आवश्यक संशोधन पारित करने की आवश्यकता होगी। प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड और फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड के संबंध में पीआईएम/ईओआई जारी किए गए और 2021-22 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के लिए मध्यस्थ नियुक्त किए गए। इसके अलावा, 2021-22 की अवधि के दौरान, कोविड और भू-राजनीतिक संकट के कारण लेन-देन की गति धीमी हो गई, जिससे बोली लगाने वालों की रुचि प्रभावित हुई। साथ ही, चल रहे अदालती मामलों ने भी लेन-देन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

4.10.1 एयर इंडिया के प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ-साथ रणनीतिक विनिवेश

सीसीईए ने जून 2017 में एयर इंडिया लिमिटेड और इसकी पांच सहायक कंपनियों⁷¹ के रणनीतिक विनिवेश पर विचार करने के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी दी थी। एयर इंडिया लिमिटेड के साथ-साथ इसकी एक सहायक कंपनी, एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड और इसकी संयुक्त उद्यम कंपनी, एयर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का विनिवेश जनवरी 2022 में पूरा हुआ। विनिवेश के बाद, प्रबंधन नियंत्रण के साथ एयर इंडिया लिमिटेड में भारत सरकार की 100 प्रतिशत इक्विटी को मेसर्स टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मेसर्स टैलेस प्राइवेट लिमिटेड को ₹18,000 करोड़ में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसमें ₹2,700 करोड़ का नकद प्रतिफल और एयर इंडिया लिमिटेड के ₹15,300 करोड़ के ऋण शामिल थे।

एयर इंडिया लिमिटेड के निजीकरण की प्रक्रिया के दौरान प्रमुख घटनाक्रमों/घटनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

⁷¹ एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज़ लिमिटेड, एलाइड एयर सर्विसेज़ लिमिटेड, एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड (पहले एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज़ लिमिटेड और होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया।

4.10.1.1 जून 2017 में सीसीईए अनुमोदन के बाद पहला प्रयास

नीति आयोग ने एयर इंडिया लिमिटेड और इसकी पांच सहायक कंपनियों के रणनीतिक विनिवेश की सिफारिश की (12 मई, 2017)। रणनीतिक विनिवेश के लिए तीन विकल्पों पर विचार करने के बाद, अर्थात (i) विकल्प I - अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री, (ii) विकल्प II - 51 प्रतिशत से 74 प्रतिशत के बीच हिस्सेदारी की बिक्री और (iii) विकल्प III - 100 प्रतिशत विनिवेश, इसने विकल्प III की सिफारिश की क्योंकि इससे अधिकतम बिक्री मूल्य प्राप्त होगा और सरकार द्वारा पूर्ण निकास से सौदे पर कुछ प्रीमियम मिलेगा। विनिवेश पर सचिवों के कोर ग्रुप ने नीति आयोग की सिफारिश से सहमति व्यक्त की (02 जून, 2017) और सीसीईए को इसकी सिफारिश की।

सीसीईए ने सीसीईए के निर्णय की तारीख से एक वर्ष की समय-सीमा के भीतर एयर इंडिया लिमिटेड और इसकी पांच सहायक कंपनियों के रणनीतिक विनिवेश को 'सैद्धांतिक' मंजूरी दे दी (28 जून, 2017) और विनिवेश के लिए अनुशंसित तीन विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प के चयन सहित रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने के लिए एयर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक तंत्र⁷² (एआईएसएएम) का गठन किया।

एयर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक तंत्र ने मंजूरी दी (अक्टूबर 2017) कि एयर इंडिया लिमिटेड की पांच सहायक कंपनियों और एक संयुक्त उद्यम कंपनी⁷³ में से, एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड, जो लाभ कमाने वाली सहायक कंपनी है और एयर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो लाभ कमाने वाली संयुक्त उद्यम कंपनी है, का एयर इंडिया लिमिटेड के साथ विनिवेश किया जाएगा। साथ ही, एयर इंडिया लिमिटेड की चार सहायक कंपनियों (एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, एलाइड एयर सर्विसेज लिमिटेड, एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड और होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) और अन्य गैर-परिचालन परिसंपत्तियों के साथ-साथ किसी भी परिसंपत्ति द्वारा समर्थित नहीं संचित कार्यशील पूंजी ऋण के भंडारण के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन बनाया

⁷² एयर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक तंत्र का गठन 03 जुलाई, 2017 को किया गया था और इसमें वित्त मंत्री अध्यक्ष के रूप में तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, रेल मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री और विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री शामिल थे।

⁷³ एयर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड।

जाएगा। इस इकाई का नाम 'एआई एसेट्स होल्डिंग कंपनी'⁷⁴ होगा। एयर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक तंत्र ने यह भी निर्णय लिया कि एयर इंडिया लिमिटेड के ऋण को दो भागों अर्थात्, 'अंतर्निहित परिसंपत्तियों द्वारा समर्थित ऋण' और 'संचित कार्यशील पूंजी ऋण किसी भी संपत्ति द्वारा समर्थित नहीं', में विभाजित किया जाएगा यह भी निर्णय लिया गया कि सरकार एयर इंडिया लिमिटेड में 51 प्रतिशत से 76 प्रतिशत तक हिस्सेदारी तथा प्रबंधन नियंत्रण भी बेच सकती है ।

दिसंबर 2017 में मेसर्स अन्स्ट एंड यंग एलएलपी को लेनदेन सलाहकार नियुक्त किया गया और जनवरी 2018 में मेसर्स आरबीएसए एडवाइजर्स एलएलपी को परिसंपत्ति मूल्यांकनकर्ता नियुक्त किया गया।

ट्रांजैक्शन एडवाइजर ने सिफारिश की कि सरकार 74 प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री का विकल्प चुन सकती है, हालांकि, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विनिवेश पर सचिवों के कोर ग्रुप को 76 प्रतिशत हिस्सेदारी के विनिवेश की सिफारिश की। विनिवेश पर सचिवों के कोर ग्रुप ने एयर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक तंत्र को इसकी सिफारिश (05 मार्च, 2018) की, जिसे अंततः उनके द्वारा अनुमोदित (मार्च 2018) किया गया।

28 मार्च, 2018⁷⁵ को अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए प्रारंभिक सूचना जापन जारी किया गया था, जिसमें ₹33,392 करोड़ का ऋण था, जिसमें ₹5,038 करोड़ की मौजूदा देनदारियाँ शामिल थीं, जो किसी भी परिसंपत्ति द्वारा समर्थित नहीं थीं, जिन्हें एयर इंडिया लिमिटेड में रखा जाना था। हालाँकि, सरकार को कोई अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त नहीं हुई। एयर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक तंत्र ने बाद में (18 जून, 2018) पाया कि सरकार द्वारा 24 प्रतिशत इक्विटी को बनाए रखना अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त न होने के मुख्य कारणों में से एक था। इस प्रकार, विनिवेश का यह प्रयास विफल हो गया।

4.10.1.2 विनिवेश का दूसरा प्रयास

विनिवेश पर सचिवों के कोर समूह ने एयर इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों के रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया को एयर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक तंत्र के तहत फिर

⁷⁴ भारत सरकार द्वारा गठित एक विशेष प्रयोजन वाहन है, जिसका उद्देश्य एयर इंडिया लिमिटेड से एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, एलाइड एयर सर्विसेज लिमिटेड, एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड और होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में उसके शेयरों का अधिग्रहण करना है; तथा एयर इंडिया लिमिटेड द्वारा तय किए गए गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करना है।

⁷⁵ बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 14 मई, 2018 थी जिसे बढ़ाकर 31 मई, 2018 कर दिया गया था।

से शुरू करने की सिफारिश की (अगस्त 2019) जिसे सितंबर 2019 में एआईएसएएम ने मंजूरी दे दी थी। लेन-देन सलाहकार ने दूसरे प्रयास के शुरुआती चरण में किसी भी परिसंपत्ति द्वारा समर्थित नहीं ऋण और वर्तमान देनदारियों के साथ चार विकल्पों की सिफारिश की (सितंबर 2019)। हालांकि, 'सचिवों की उप-समिति' ने सिफारिश की (अक्टूबर 2019) कि एयर इंडिया लिमिटेड में ₹23,771 करोड़ की कुल ऋण राशि बरकरार रखी जाए और किसी भी परिसंपत्ति द्वारा समर्थित नहीं वर्तमान देनदारियों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, एआईएसएएम ने एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड के साथ एयर इंडिया के 100 प्रतिशत और एयर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के 50 प्रतिशत विनिवेश को मंजूरी दी (जनवरी 2020)। इसके बाद 27 जनवरी, 2020 को प्रारंभिक सूचना ज्ञापन जारी किया गया, जिसमें एयर इंडिया लिमिटेड में ₹23,287 करोड़ का ऋण बरकरार रखने की बात कही गई।

बाद में, विनिवेश पर सचिवों के कोर समूह ने (अक्टूबर 2020) एयर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक तंत्र को बोली मानदंड में उद्यम मूल्य पद्धति में बदलाव के लिए सिफारिश की, जिसमें कोई पूर्व-निर्धारित ऋण स्तर नहीं होगा और बोलीदाता संयुक्त ऋण और इक्विटी मूल्य उद्धृत करने में सक्षम होंगे, जिसे एयर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक तंत्र द्वारा (26 अक्टूबर, 2020) अनुमोदित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 14 दिसंबर, 2020 तक कुल सात अभिरुचि पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से पांच को लेनदेन सलाहकार की तकनीकी मूल्यांकन रिपोर्ट (फरवरी 2021) के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया।

लेन-देन सलाहकार ने आरक्षित मूल्य ₹12,077 करोड़ प्रस्तावित किया जबकि परिसंपत्ति मूल्यांकनकर्ता ने इसे ₹16,224.63 करोड़ प्रस्तावित किया। अंतर-मंत्रालयी समूह ने विनिवेश पर सचिवों के कोर समूह (सीजीडी) को ₹12,906 करोड़ के आरक्षित मूल्य की सिफारिश की⁷⁶ जिसे सीजीडी ने (29 सितंबर, 2021) मंजूरी दे दी।

⁷⁶ लेनदेन सलाहकार व मूल्यांकनकर्ता द्वारा उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणालियों पर विचार करते हुए, विनिवेश पर सचिवों के कोर समूह ने परिसंपत्ति मूल्यांकनकर्ता द्वारा दिए गए मूल्यांकन को 20 प्रतिशत का भार और आरक्षित मूल्य निर्धारण के प्रयोजन के लिए लेनदेन सलाहकार द्वारा दिए गए मूल्यांकन को 80 प्रतिशत का भार स्वीकृत किया।

आरक्षित मूल्य को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, अंतर-मंत्रालयी समूह की बैठक (29 सितंबर, 2021) में दोनों योग्य संस्थागत बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियाँ खोली गईं, जिसमें मेसर्स टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मेसर्स टैलेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसने ₹18,000 करोड़ की राशि उद्धृत की थी, योग्य पाई गई। तदनुसार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, एयर इंडिया लिमिटेड और मेसर्स टैलेस प्राइवेट लिमिटेड के बीच शेयर खरीद समझौता (25 अक्टूबर, 2021) निष्पादित किया गया और विनिवेश की प्रक्रिया पूरी हुई (27 जनवरी, 2022)।

4.10.2 एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां

रणनीतिक विनिवेश को पूरा होने में चार साल से अधिक का समय लगा, यानी जून 2017 में एयर इंडिया लिमिटेड के विनिवेश पर सीसीईए की मंजूरी से लेकर जनवरी 2022 में लेनदेन के समापन तक की अवधि। विनिवेश लेनदेन की पूरी प्रक्रिया के दौरान लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित बातें देखीं:

i. बोली मानदंड के रूप में उद्यम मूल्य पद्धति को अपनाना

मार्च 2018 में शुरू हुई पहली विनिवेश प्रक्रिया के दौरान, एयर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक तंत्र ने बोली मानदंड के रूप में परिसंपत्ति मूल्य पद्धति को मंजूरी दी थी जिसमें बोलीदाताओं को अपनी संपत्तियों द्वारा समर्थित एयर इंडिया के ऋणों के आधार पर आरक्षित राशि से कम नहीं बोली लगाने की अनुमति दी गई थी। उपरोक्त बोली मानदंड को जनवरी 2020 में दूसरी विनिवेश प्रक्रिया के दौरान भी अपनाया गया था। हालांकि, विनिवेश प्रक्रिया के दूसरे प्रयास में कोई ईओआई प्राप्त नहीं हुई थी, जब तक कि विनिवेश पर सचिवों के कोर समूह ने एंटरप्राइज वैल्यू पद्धति में बोली मानदंड में बदलाव के लिए एयर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक तंत्र को सिफारिश (अक्टूबर 2020) नहीं की, जिसमें कोई पूर्व-निर्धारित ऋण स्तर नहीं होगा और बोली लगाने वाले संयुक्त ऋण प्लस इक्विटी मूल्य उद्धृत करने में सक्षम होंगे। यह भी सिफारिश की गई थी कि ऋण और नकद प्रतिफल को 85:15 के अनुपात में विभाजित किया जा सकता है जिसे एयर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक तंत्र द्वारा अनुमोदित (26 अक्टूबर, 2020) किया गया था।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि बोलियाँ एंटरप्राइज वैल्यू पद्धति में बोली मानदंड में बदलाव के बाद प्राप्त हुई थीं, जहां कोई पूर्व-निर्धारित ऋण स्तर नहीं था और बोली

लगाने वाले संयुक्त ऋण प्लस इक्विटी मूल्य उद्धृत करने में सक्षम थे। हालाँकि, पिछले असफल प्रयासों के कारण विनिवेश प्रक्रिया में दो साल से अधिक की देरी हुई।

ii. एयर इंडिया लिमिटेड के रणनीतिक विनिवेश के पूरा होने पर भारत सरकार द्वारा वहन किए गए ऋण और देयताएं

2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान इक्विटी पूंजी, एयर इंडिया लिमिटेड के लिए वित्तीय बाजार से जुटाए गए गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर और एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड के माध्यम से अतिरिक्त सहायता और भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में कुल ₹91,051.17 करोड़ की राशि प्रदान की गई, जिसका विवरण नीचे तालिका 4.5 में दिया गया है।:

तालिका 4.5: विनिवेश प्रक्रिया के दौरान एयर इंडिया में सरकार का पूंजी निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	मात्रा
वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान एयर इंडिया में इक्विटी पूंजी	1,937.21
वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान एयर इंडिया में इक्विटी पूंजी	3,975.00
एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड द्वारा अ-परिवर्तनीय ऋणपत्र की आय ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए एयर इंडिया को हस्तांतरित की गई	22,064.00
सरकार द्वारा एयर इंडिया को अतिरिक्त सहायता ⁷⁷ प्रदान की गई	61,178.00
भारत सरकार से अनुदान	1,944.00
एआईएचएल को हस्तांतरित अधिशेष (वर्तमान परिसंपत्तियों और वर्तमान देनदारियों का अंतर)	(47.04)
विनिवेश प्रक्रिया के दौरान सरकार द्वारा भुगतान की गई कुल राशि	91,051.17

इसके अलावा, विनिवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी भारत सरकार को बकाया अ-परिवर्तनीय ऋणपत्र के कारण⁷⁸ ₹14,985.00 करोड़ की देनदारी वहन करनी है। इसके अलावा, सरकार

⁷⁷ भारत सरकार ने विनिवेश की अवधि के दौरान एयर इंडिया लिमिटेड की गारंटी/अन्य पिछले बकाये/अतिदेय के निपटान के लिए एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड के माध्यम से एयर इंडिया लिमिटेड को अतिरिक्त सहायता प्रदान की।

⁷⁸ ₹21,985 करोड़ (31 मार्च, 2022 को) की राशि वाले एनसीडी में से ₹14,985 करोड़ के बकाया एनसीडी अभी परिपक्व होने बाकी हैं।

पूर्ववर्ती एयर इंडिया लिमिटेड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों (रणनीतिक विनिवेश की अंतिम तिथि तक) और पात्र मौजूदा कर्मचारियों (जो 55 वर्ष या उससे अधिक आयु के हो चुके हैं या 20 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं) और उनके जीवनसाथी के लिए सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधाओं के लिए भी जिम्मेदार है। हालाँकि, लेखापरीक्षा द्वारा राशि का आकलन नहीं किया जा सका।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि विनिवेश की प्रक्रिया पूरी होने पर भारत सरकार ने ₹88,036.17 करोड़ का शुद्ध वित्तीय भार वहन किया था, अर्थात् ₹1,06,036.17 करोड़ (पूँजी निवेश, ऋणपत्र आय, अतिरिक्त वित्तीय सहायता और भारत सरकार द्वारा वहन की जाने वाली देनदारियों सहित) घटा ₹18,000 करोड़ (एयर इंडिया लिमिटेड के विनिवेश से प्राप्त आय)।

दीपम ने स्पष्ट किया (जनवरी 2024) कि नीति आयोग ने 12 मई, 2017 की अपनी चौथी रिपोर्ट में एयर इंडिया लिमिटेड के रणनीतिक विनिवेश के लिए एक रोडमैप की सिफारिश की। नीति आयोग के अनुसार, बैलेंस शीट की सफाई के बिना, एयर इंडिया लिमिटेड के रणनीतिक विनिवेश का कोई भी प्रयास किसी भी बोलीदाता को आकर्षित करने में विफल हो सकता है। दीपम ने आगे कहा कि, किसी भी पूँजी निवेश के अभाव में विनिवेश प्राप्तियां, पूँजी निवेश की राशि के समान स्तर से कम होतीं। केवल एयर इंडिया लिमिटेड को बंद/विनिवेश करने से एयर इंडिया का पिछला कर्ज और देनदारियां खत्म नहीं होंगी, क्योंकि सरकार ने कर्ज के बड़े हिस्से की गारंटी पहले ही दे दी थी।

4.11 विनिवेश से संबंधित अन्य मुद्दे

4.11.1 शत्रु शेयरों, शत्रु संपत्तियों की बिक्री और परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण

वर्ष 2021-22 के दौरान, दीपम ने कुल ₹3.75 करोड़ मूल्य के 1,27,622 शेयर बेचे हैं और 31 मार्च, 2022 तक 15,847 शेयर बिना बिके रह गए हैं।

शत्रु शेयरों की बिक्री में लंबितता से संबंधित मुद्दा, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संघ सरकार (वाणिज्यिक) - सामान्य प्रयोजन वित्तीय रिपोर्ट पर सीएजीकी 2022 की रिपोर्ट संख्या 27 में भी उठाया गया था; तथापि, संपूर्ण शत्रु शेयरों की बिक्री पर अनुपालन आज की तिथि तक लंबित है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अक्टूबर 2020 में वैकल्पिक तंत्र ने निर्णय लिया कि ₹100 करोड़ और उससे अधिक मूल्य वाली संपत्तियों का मुद्रीकरण दीपम द्वारा किया जाएगा और ₹100 करोड़ से कम मूल्य वाली संपत्तियों का मुद्रीकरण संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/शत्रु संपत्ति के संरक्षक/सीपीएसई द्वारा उनकी मौजूदा बिक्री प्रक्रिया के बाद किया जाएगा। हालाँकि, दीपम ने शत्रु संपत्तियों और संपत्ति मुद्रीकरण से संबंधित कोई बिक्री लेनदेन नहीं किया है। इसके बाद, दोनों कार्यों को 21 मार्च, 2022 को डीपीई को हस्तांतरित कर दिया गया।

दीपम ने यह भी कहा कि निपटान के लिए लंबित अनबिके शेयरों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों का है। सूचीबद्ध कंपनियों के लंबित शेयरों की बिक्री न होने के कारणों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कंपनियाँ या तो निलंबित श्रेणी में हैं, या तरल नहीं हैं या क्षेत्रीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं जहाँ व्यापार बंद हो गया है, एक अलग कार्यप्रणाली को मंजूरी दी गई थी। तदनुसार, इन शेयरों की बिक्री के लिए इच्छुक बोलीदाताओं से बोलियाँ आमंत्रित करने के लिए जनवरी 2024 में समाचार पत्रों में एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया है।

इसके अलावा दीपम ने उत्तर दिया कि उसने डीपीई को परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्य हस्तांतरित करने से पहले विभिन्न गतिविधियाँ शुरू की हैं, जैसे कि गैर-प्रमुख परिसंपत्ति मुद्रीकरण के संबंध में विश्व बैंक के साथ तकनीकी सहायता व्यवस्था में प्रवेश करना, गैर-प्रमुख परिसंपत्ति मुद्रीकरण पाइपलाइन बनाने के लिए गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों की पहचान करना, विशेष रूप से परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए ई-बोली मंच डिजाइन करना आदि।

पाँचवाँ अध्याय

कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी

5.1 परिचय

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यवसाय द्वारा नैतिक रूप से व्यवहार करने और स्थानीय समुदाय के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हुए आर्थिक विकास में योगदान देने की निरंतर प्रतिबद्धता है। यह स्थिरता, सामाजिक प्रभाव और नैतिकता को शामिल करके अपने हितधारकों और बड़े पैमाने पर सामान्य समुदाय के हितों को मान्यता देता है। सीएसआर की अवधारणा देने और लेने की विचारधारा पर आधारित है। कंपनियां समाज से कच्चे माल, मानव संसाधन आदि के रूप में संसाधन लेती हैं। सीएसआर गतिविधियों का कार्य करके, कंपनियां समाज को कुछ वापस दे रही हैं।

कानूनी ढांचा: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के माध्यम से भारत में सीएसआर फंडिंग को अनिवार्य बना दिया गया है। इसमें प्रावधान है कि हर कंपनी जिसका निवल मूल्य पांच सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक है, या एक हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक का कारोबार है, या तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान पांच करोड़ रुपये या उससे अधिक का शुद्ध लाभ है, वह सीएसआर गतिविधियां करने के लिए पात्र होगी। कंपनी अधिनियम, 2013 ऐसी किसी भी कंपनी के लिए अनिवार्य बनाता है कि वह सीएसआर गतिविधियों पर तीन तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार गणना) का कम से कम 2 प्रतिशत सालाना खर्च करे। कंपनियां अपनी सीएसआर नीतियों में जिन गतिविधियों को शामिल कर सकती हैं, उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में सूचीबद्ध किया गया है। अधिनियम के तहत सीएसआर के प्रावधानों का अनुपालन यानी सीएसआर समिति का गठन, सीएसआर नीति तैयार करना और सीएसआर गतिविधियों पर निर्धारित राशि खर्च करना अप्रैल 2014 से लागू हुआ।

फरवरी 2014 में, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनियां (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 (समय-समय पर संशोधित) जारी किए। सीएसआर नीति नियम 01 अप्रैल, 2014 से सीपीएसई सहित सभी कंपनियों पर लागू किए गए थे। सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने भी अगस्त 2016 में सीपीएसई द्वारा सीएसआर के तहत गतिविधियों के चयन और कार्यान्वयन में पारदर्शिता और उचित परिश्रम के पालन पर अधिसूचना जारी की थी। दिसंबर 2018 में, डीपीई ने हर साल थीम-आधारित दृष्टिकोण अपनाकर राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति केंद्रित तरीके से सीएसआर फंड के उपयोग से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए। दिशानिर्देशों में यह भी निर्देश दिया गया कि नीति आयोग द्वारा पहचाने गए आकांक्षी जिलों को वरीयता दी जा सकती है। 'स्वास्थ्य और पोषण, अस्थायी अस्पतालों और अस्थायी कोविड देखभाल सुविधाओं की स्थापना सहित कोविड से संबंधित उपायों पर विशेष ध्यान देने का वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रित हस्तक्षेप के लिए एक विषय के रूप में लिया गया था।

5.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

सीपीएसई की सीएसआर गतिविधियों की समीक्षा के लिए लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम 2014 (जनवरी 2021 में संशोधित) और समय-समय पर जारी डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों का 2021-22 के दौरान अनुपालन किया गया था। सीपीएसई के प्रयासों का आंकलन करने के लिए, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित मुद्दों को समावेश किया:

- क्या सीएसआर समिति के गठन, सीएसआर नीति के निर्माण और अनुपालन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया गया है;
- क्या कार्यान्वयन के लिए चयनित सीएसआर गतिविधियां कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के तहत दी गई गतिविधियों की सूची के अंतर्गत आती हैं;
- क्या सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली निर्धारित राशि से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया गया है;
- क्या सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत गतिविधियों/परियोजनाओं के चयन को प्राथमिकता देते समय लोगों की स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है;

- क्या गतिविधियों के चयन और कार्यान्वयन में पारदर्शिता और यथोचित परिश्रम है; और
- क्या सीएसआर कार्यान्वयन के लिए सीपीएसई द्वारा निगरानी, रिपोर्टिंग और मूल्यांकन हेतु संस्थागत तंत्र शुरू किया गया है।

5.3 लेखापरीक्षा का दायरा और कवरेज

लेखापरीक्षा ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत 177 सीपीएसई में से 65 सीपीएसई का चयन किया, जिन्होंने वित्त वर्ष 2020-21 में लाभ कमाया था (डीपीई सार्वजनिक उद्यम (पीई) सर्वेक्षण के अनुसार) जैसा कि नीचे दी गई तालिका में संक्षेप में बताया गया है। पीई सर्वेक्षण में प्रकाशित वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान लाभ कमाने वाले सभी सीपीएसई का विवरण, जिसमें लेखापरीक्षा के लिए चयनित नमूना सीपीएसई की सूची भी शामिल है, *अनुलग्नक-XXIII* में दिया गया है।

2021-22 के दौरान सीएसआर गतिविधियों की समीक्षा के लिए सीपीएसई का चयन

सीपीएसई का शुद्ध लाभ	सीपीएसई की संख्या	चयनित सीपीएसई की संख्या	चयनित सीपीएसई का प्रतिशत
₹500 करोड़ से अधिक	35	35*	100
₹100 करोड़ से अधिक - ₹500 करोड़	46	23#	50
₹50 करोड़ से अधिक - ₹100 करोड़	12	3	25
₹10 करोड़ - ₹50 करोड़	43	4	10
₹10 करोड़ से कम	41	0	0
कुल	177	65	

*ओएनजीसी विदेश लिमिटेड शामिल है

नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड शामिल है

65 सीपीएसई में से एक सीपीएसई यानी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड अपना परिचालन विदेश में करता है और इसलिए वह सीएसआर के लिए योग्य नहीं है। एक सीपीएसई (एनपीजीसीएल)⁷⁹ के संबंध में सीएसआर खर्च की जानकारी उपलब्ध नहीं थी। इसलिए 2021-22 के दौरान लेखापरीक्षा समीक्षा 63 सीपीएसई तक सीमित थी।

⁷⁹ नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड का अगस्त 2022 में एनटीपीसी में विलय हो गया।

5.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा विश्लेषण निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया गया:

- i. कंपनी अधिनियम, 2013 (समय-समय पर संशोधित) की धारा 135 और अनुसूची VII में निहित प्रावधान;
- ii. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के प्रावधान (समय-समय पर संशोधित);
- iii. डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देश और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाएं/स्पष्टीकरण।

5.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

सीएसआर समिति के गठन, सीएसआर नीति के निर्माण और अनुपालन, सीएसआर गतिविधियों की योजना और निष्पादन तथा सीपीएसई द्वारा इसकी निगरानी और रिपोर्टिंग के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की सीमा पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित पैराग्राफों में प्रस्तुत किए गए हैं।

5.5.1 योजना

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) में प्रावधान है कि प्रत्येक कंपनी जिसकी शुद्ध संपत्ति पांच सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक हो या कारोबार एक हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक हो या तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ पांच करोड़ रुपये या उससे अधिक हो, वह सीएसआर गतिविधियां करने के लिए पात्र होगी ।

63 सीपीएसई में से तीन सीपीएसई ने⁸⁰ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के तहत शुद्ध लाभ के आधार पर सीएसआर व्यय करने के मानदंडों को पूरा नहीं किया। हालांकि, इन सीपीएसई ने क्रमशः ₹85.75 लाख, ₹79.60 लाख और ₹17.83 लाख खर्च किए, जो सीएसआर के प्रति उनकी सक्रिय और स्वैच्छिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

⁸⁰ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, एमएसटीसी लिमिटेड।

5.5.1.1 सीएसआर समिति का गठन

किसी कंपनी में सीएसआर गतिविधि को औपचारिक रूप देने की दिशा में पहला कदम कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्दिष्ट सीएसआर समिति का गठन है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (1) में प्रावधान है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में शर्तों को पूरा करने वाली प्रत्येक कंपनी को बोर्ड की एक सीएसआर समिति का गठन करना होगा जिसमें तीन या अधिक निदेशक शामिल होंगे, जिनमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होगा। इसके अलावा, सीएसआर नियम, 2014 के नियम 5(1) (i) के अनुसार, धारा 135(1) के अंतर्गत आने वाली एक गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के अनुसार स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है और इसकी सीएसआर समिति ऐसे निदेशक के बिना होगी।

31 मार्च, 2022 तक, 63 सीपीएसई में से तीन सीपीएसई⁸¹ के मामले में अधिनियम की धारा 135(1) के अनुसार समिति में न्यूनतम तीन निदेशकों का अनुपालन नहीं किया गया था। इसके अलावा, जैसा कि अधिसूचना में बताया गया है *अनुलग्नक-XXIV*, समिति में सूचीबद्ध 63 सीपीएसई में से सभी 38 सीपीएसई के पास एक स्वतंत्र निदेशक था।

5.5.1.2 सीएसआर नीति का निर्माण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (3) के अनुसार सीएसआर समिति को सीएसआर नीति तैयार करनी होगी और बोर्ड को इसकी सिफारिश करनी होगी, जो धारा 135 (4) के अनुसार समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए इसे मंजूरी देगी। साथ ही, सीएसआर नियमों के पैरा 6 (2) के अनुसार, कंपनी की सीएसआर नीति में यह निर्दिष्ट किया जाना चाहिए कि सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष कंपनी के व्यावसायिक लाभ का हिस्सा नहीं होना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी 63 सीपीएसई ने सीएसआर नीति तैयार की थी और संबंधित बोर्ड ने उसे मंजूरी भी दी थी। हालांकि, एक सीपीएसई यानी राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड ने अपनी नीति में यह निर्दिष्ट नहीं किया था कि सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष सीएसआर नियम, 2014 के अनुसार कंपनी

⁸¹ एंटिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड।

के व्यावसायिक लाभ का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इसलिए एनएसआईसी की सीएसआर नीति उस सीमा तक अपर्याप्त थी।

5.5.1.3 वार्षिक सीएसआर योजना और बजट

जनवरी 2021 के संशोधित सीएसआर नियमों के अनुसार, सीएसआर समिति एक वार्षिक कार्य योजना तैयार करेगी और बोर्ड को सिफारिश करेगी, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों में किए जाने के लिए अनुमोदित सीएसआर गतिविधियों और कार्यक्रमों की सूची, निष्पादन का तरीका और धन के उपयोग के तौर-तरीके शामिल होंगे और सीएसआर समिति की सिफारिश पर वर्ष के दौरान किसी भी समय ऐसी योजना में बदलाव किया जा सकता है।

63 सीपीएसई में से, लेखापरीक्षा ने एक सीपीएसई अर्थात कोल इंडिया लिमिटेड के संबंध में विचलन देखा। वार्षिक कार्य योजना के भाग के रूप में, कंपनी ने सीएसआर बजट का 51.59 प्रतिशत एक अलग निधि के रूप में अलग रखा, बिना विशिष्ट परियोजनाओं की पहचान किए जिन पर यह राशि खर्च की जाएगी। परिणामस्वरूप, ₹77.64 करोड़ के कुल सीएसआर व्यय में से, ₹54.62 करोड़ (यानी, 70 प्रतिशत) उन परियोजनाओं पर खर्च किए गए जिन्हें वार्षिक कार्य योजना की तैयारी/अनुमोदन के बाद पहचाना और अनुमोदित किया गया था।

कंपनी ने कहा (नवंबर 2022) कि चूंकि पूरे साल प्रोजेक्ट प्रस्ताव प्राप्त होते रहे, इसलिए फंड उसी हिसाब से जारी किया गया और इसलिए पूरे साल के लिए योजना शुरू में तैयार नहीं की जा सकी। यह भी ध्यान में लाया गया कि कंपनी के बोर्ड ने वार्षिक कार्य योजना को इस शर्त के साथ मंजूरी दी थी कि वार्षिक कार्य योजना के विषयों को फिर से संगठित किया जा सकता है।

कंपनी को उत्तर को कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 के संदर्भ में देखा जा सकता है, जहां सीएसआर समिति को उस वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित व्यक्तिगत गतिविधियों की बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाने वाली अन्य आवश्यकताओं के साथ एक सूची तैयार करने की आवश्यकता होती है। यह सूची स्वरूप में अस्थायी हो सकती है और बाद में सीएसआर समिति द्वारा अनुशंसित बोर्ड की मंजूरी के साथ, जैसा कि उचित समझा जाता है, संशोधन के लिए लिया जा सकता है। हालाँकि, कंपनी

ने इसके बजाय योजना में विभिन्न शीर्ष बनाए और उन्हें धन आवंटित किया, जिससे संशोधित सीएसआर नियमों में अनिवार्य वार्षिक कार्य योजना का उद्देश्य विफल हो गया।

डीपीई ने जवाब में कहा (अप्रैल 2024) कि वार्षिक सीएसआर योजना को संशोधित सीएसआर नियमों के नियम 5 के प्रावधान के अनुसार बोर्ड द्वारा उचित औचित्य के साथ संशोधित किया जा सकता है। कंपनी ने वार्षिक कार्य योजना में बदलाव के लिए उचित औचित्य प्रदान किया है, जो जरूरी नहीं कि वार्षिक कार्य योजना के उद्देश्य को विफल कर रहा हो।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि कोल इंडिया लिमिटेड ने केवल औसत 2 प्रतिशत और खर्च की जाने वाली धनराशि का विवरण दिया था, न कि खर्च के क्षेत्रों और शीर्षकों का।

5.5.2 वित्तीय घटक

5.5.2.1 चयनित सीपीएसई के लिए कुल सीएसआर व्यय का विवरण

(i) कुल सीएसआर व्यय

चयनित 63 सीपीएसई में 11 महारत्न, नौ नवरत्न, 29 मिनीरत्न और 14 अन्य सीपीएसई शामिल हैं। 2021-22 के दौरान इन 63 सीपीएसई द्वारा श्रेणीवार कुल सीएसआर व्यय नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

तालिका 5.2: कुल सीएसआर व्यय

वर्ग	सीपीएसई की संख्या	सीएसआर व्यय (करोड़ रुपए में)	कुल सीएसआर व्यय का प्रतिशत
महारत्न कंपनियाँ	11	2,268.63	56.64
नवरत्न कंपनियाँ	9	659.49	16.47
मिनीरत्न कंपनियाँ	29	927.41	23.15
अन्य कंपनियाँ	14	149.77	3.74
कुल	63	4,005.30	100.00

सीपीएसईवार कुल सीएसआर व्यय *अनुलग्नक-XXV* में दिया गया है ।

(ii) क्षेत्रवार सीएसआर व्यय

63 सीपीएसई द्वारा क्षेत्रवार व्यय नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

तालिका 5.3: क्षेत्रवार व्यय

क्रम सं.	क्षेत्र	सीपीएसई की संख्या	2 प्रतिशत व्यय किया जाना है (करोड़ रुपये में)	वास्तविक व्यय (करोड़ रुपये में)
1	विमानन	1	0.63	0.63
2	खनन	10	708.36	979.74
3	रक्षा	6	166.33	146.81
4	उर्वरक	3	4.47	3.69
5	पेट्रोलियम	10	1,350.60	1,489.48
6	शक्ति	14	1,192.56	1,235.27
7	रेलवे	5	129.01	84.03
8	शिपिंग	2	22.22	20.17
9	अन्य	12	81.66	45.48
	कुल	63	3,655.84	4,005.30

- पेट्रोलियम और बिजली क्षेत्र के अंतर्गत सीपीएसई द्वारा सबसे अधिक व्यय किया गया, जो कुल सीएसआर व्यय का 68.03 प्रतिशत रहा। इन दो क्षेत्रों में सबसे अधिक सीएसआर व्यय करने वाले सीपीएसई तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (₹458.00 करोड़), एनटीपीसी लिमिटेड (₹356.72 करोड़) और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹298.29 करोड़) थे।
- रक्षा, रेलवे, शिपिंग, उर्वरक और अन्य क्षेत्रों में न्यूनतम 2 प्रतिशत के सापेक्ष व्यय में कमी रही, जबकि खनन, पेट्रोलियम और बिजली क्षेत्र में व्यय आवश्यक 2 प्रतिशत से अधिक रहा। सबसे कम सीएसआर व्यय वाले सीपीएसई सेल रिफ़्रेक्टरी कंपनी लिमिटेड (₹13.25 लाख), इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनैस कंपनी लिमिटेड (₹15.93 लाख) और एमएसटीसी लिमिटेड (₹17.83 लाख) थे।
- सभी 63 सीपीएसई का समग्र सीएसआर व्यय पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत से अधिक था।

5.5.2.2 निधि का आवंटन

अधिनियम की धारा 135 (5) के अनुसार किसी भी कंपनी के लिए पिछले तीन वित्तीय वर्षों (अधिनियम की धारा 198 के तहत गणना) के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत वार्षिक रूप से सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करना अनिवार्य है। 63 सीपीएसई के लिए इस प्रकार गणना किए गए औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत ₹3,655.84 करोड़ था, जिसकी तुलना में सीपीएसई ने ₹4,049.35 करोड़ आवंटित किए थे।

(i) अधिनियम द्वारा अधिदेशित कुल व्यय का 2 प्रतिशत और (ii) वित्त 2021-22 के दौरान 2 प्रतिशत राशि के विरुद्ध वास्तविक आवंटन के संबंध में सभी सीपीएसईसी की विस्तृत तस्वीर *अनुलग्नक-XXVI* में विस्तृत रूप से दी गई है। इसे नीचे दी गयी तालिका में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 5.4: सीएसआर के लिए वास्तविक आवंटन की तुलना में अनिवार्य

63 सीपीएसई के पिछले तीन वर्षों का औसत शुद्ध लाभ (अधिनियम की धारा 198 के अनुसार)	2 प्रतिशत आवंटन किया जाएगा	वास्तविक आवंटित राशि
₹1,82,791.40 करोड़	₹3,655.84 करोड़	₹4,049.35 करोड़ ⁸²
	शुद्ध अतिरिक्त आवंटन ₹409.61 करोड़ तक था।	

लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि:

- 25 सीपीएसई ने न्यूनतम 2 प्रतिशत से अधिक आवंटन किया था, अतिरिक्त आवंटन ₹436.56 करोड़ तक था।
- 15 सीपीएसई⁸³ को 2 प्रतिशत से भी कम आवंटन किया गया, आवंटन में कमी ₹64.48 करोड़ तक थी।
- 21 सीपीएसई ने ठीक 2 प्रतिशत आवंटित किए गए थे।

⁸² दो सीपीएसई अर्थात् भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, बामर लारी एण्ड कॉपने लिमिटेड के संबंध में डेटा उपलब्ध नहीं था।

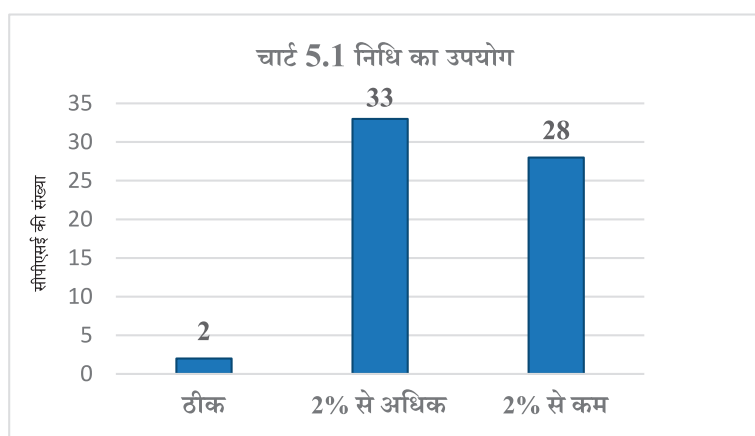
⁸³ इसमें भारत डायनेमिक्स लिमिटेड भी शामिल है। अनिवार्य 2 प्रतिशत के विरुद्ध आवंटन के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए।

- तीन सीपीएसई⁸⁴ ने नकारात्मक लाभ के कारण धन आवंटित नहीं किया। हालांकि, इन सीपीएसई ने सीएसआर पर खर्च किया, जबकि उन्हें वैधानिक रूप से खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी।

डीपीई ने जवाब में कहा (अप्रैल 2024) कि औसत शुद्ध लाभ का न्यूनतम 2 प्रतिशत आवंटित करने का अनुपालन अनिवार्य है। जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, यदि सीपीएसई ने 2 प्रतिशत से कम आवंटित किया है, तो इस तथ्य से इसकी पुष्टि करने की आवश्यकता है कि क्या उपर्युक्त परिदृश्य के लिए कोई सेट-ऑफ था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कोई सेट ऑफ नहीं था और इसलिए, सीपीएसई द्वारा खर्च में कमी थी जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 135 (5) का अनुपालन नहीं हुआ।

5.5.2.3 निधियों का उपयोग



कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (5) में कहा गया है कि बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत खर्च करे। डीपीई ने यह भी सलाह दी (अगस्त 2016) कि सीपीएसई

को वर्ष के लिए आवंटित सीएसआर फंड का पूरा उपयोग करने के लिए सभी प्रयास करने चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 63 सीपीएसई में से:

- दो सीपीएसई ने⁸⁵ ठीक 2 प्रतिशत खर्च किया था ।
- 33 सीपीएसई ने 2 प्रतिशत से अधिक व्यय किया, जो ₹695.24 करोड़ था और 28 सीपीएसई⁸⁶ ने 2 प्रतिशत से कम व्यय किया (सीएसआर व्यय में ₹345.78

⁸⁴ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, एमएसटीसी लिमिटेड।

⁸⁵ एनएलसी इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड साउदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड।

⁸⁶ भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलीमर लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड्स

करोड़ की कमी)।

i) वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सीएसआर पर किए गए वास्तविक व्यय और (ii) क्या किया गया व्यय आवश्यक अधिनियम द्वारा निर्धारित 2 प्रतिशत से अधिक था या कम था, के संबंध में सभी सीपीएसई की तुलनात्मक तस्वीर का विवरण *अनुलग्नक-XXVI* में दिया गया है।

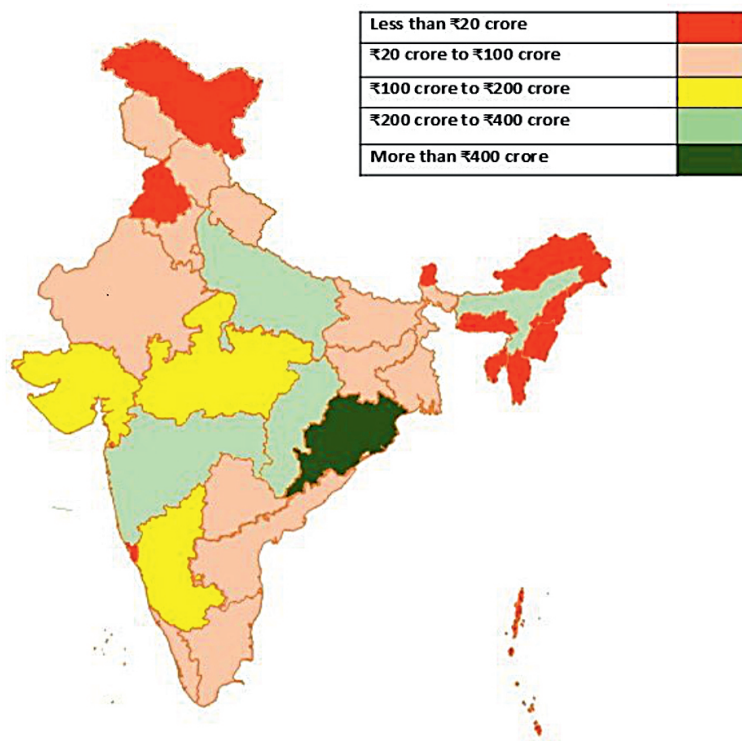
डीपीई ने अपने उत्तर में कहा (अप्रैल 2024) कि वार्षिक सीएसआर व्यय को सेट-ऑफ (यदि लागू हो) के अनुरूप देखा जाना चाहिए और अनुपालन को उक्त वर्ष में सीएसआर व्यय पर विचार करते हुए देखा जाना चाहिए और क्या अगले वर्ष के छह महीने के भीतर अनुसूची VII में उल्लिखित किसी भी निधि में योगदान दिया गया था। 28 सीपीएसई द्वारा व्यय में कमी के संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि कोई सेट ऑफ लागू नहीं था। इसलिए सीएसआर गतिविधियों के व्यय में कमी थी।

5.5.2.4 राज्यों में सीएसआर खर्च में व्यापक भिन्नता

विभिन्न राज्यों में चयनित सीपीएसई द्वारा सीएसआर खर्च में व्यापक भिन्नता देखी गई। वर्ष 2021-22 के दौरान 63 चयनित सीपीएसई द्वारा राज्यवार सीएसआर खर्च को चित्र 5.2 में दर्शाया गया है।

लिमिटेड, गेल गैस लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईटीआई लिमिटेड, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज लिमिटेड, एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड, राइट्स लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सिक्वोरिटी प्रिंटिंग मिटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, सेल रिफ्रैक्टरी कम्पनी लिमिटेड।

चित्र 5.2 : 2021-22 के दौरान सीपीएसई 63 द्वारा सीएसआर व्यय

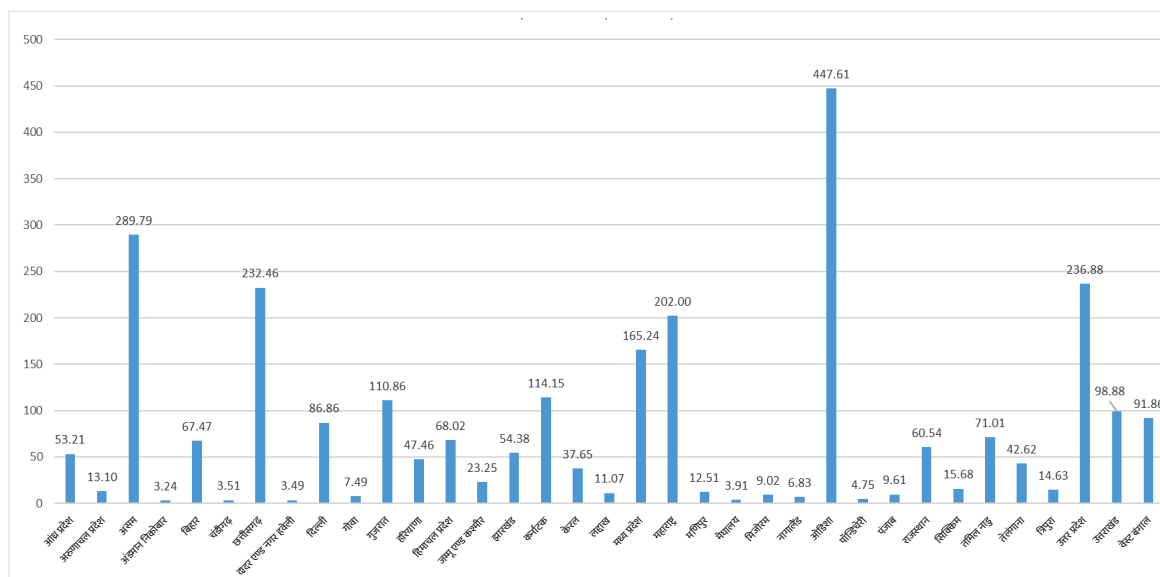


एक राज्य ने ₹400 करोड़ से अधिक (स्तर ए) खर्च किए, चार राज्यों ने ₹200 करोड़ और ₹400 करोड़ के बीच खर्च किए (स्तर बी), तीन राज्यों ने ₹100 करोड़ और ₹200 करोड़ के बीच खर्च किए (स्तर सी), 13 राज्यों ने ₹20 करोड़ और ₹100 करोड़ के बीच खर्च किए (स्तर डी), और 14 राज्यों ने ₹20 करोड़ से कम खर्च किए (स्तर ई)⁸⁷।

राज्यवार सीएसआर व्यय नीचे दिए गए चार्ट में दिया गया है:

⁸⁷ स्तर ए-ओडिशा, स्तर बी-असम, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, स्तर सी-गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, स्तर डी- उत्तराखंड , आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, स्तर ई - अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, गोवा, लद्दाख , मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पांडिचेरी, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा।

चार्ट 5.2: 2021-22 के दौरान चयनित 63 सीपीएसई द्वारा राज्यवार सीएसआर खर्च
(₹ करोड़ में)



तालिका 5.5: राज्यवार उच्चतम और न्यूनतम व्यय

सबसे अधिक व्यय	सबसे कम खर्च
ओडिशा - ₹447.61 करोड़	लक्षद्वीप एवं दमन और दीव (शून्य)
असम - ₹289.79 करोड़	अंडमान और निकोबार - ₹3.24 करोड़
उत्तर प्रदेश - ₹236.88 करोड़	दादरा और नगर हवेली - ₹3.49 करोड़
छत्तीसगढ़ - ₹232.46 करोड़	चंडीगढ़ - ₹3.51 करोड़
महाराष्ट्र - ₹202.00 करोड़	मेघालय - ₹3.91 करोड़

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- जिन राज्यों पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया, वे थे- ओडिशा (16.45 प्रतिशत), असम (10.65 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (8.71 प्रतिशत)। इन तीन राज्यों ने कुल सीएसआर व्यय का 35.81 प्रतिशत हिस्सा लिया, जबकि कुछ अन्य तुलनीय राज्यों में सीएसआर व्यय इस प्रकार था- पश्चिम बंगाल (3.38 प्रतिशत), बिहार (2.48 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (1.96 प्रतिशत), झारखंड (2 प्रतिशत) और तमिलनाडु (2.61 प्रतिशत)।

- अकेले ओडिशा में सीएसआर खर्च (₹447.61 करोड़) सबसे कम सीएसआर खर्च वाले 21 राज्यों (₹437.95 करोड़) से अधिक था, जो राज्यों में सीएसआर खर्च में व्यापक असमानता को दर्शाता है। ओडिशा में अधिकतम सीएसआर खर्च महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (₹251.76 करोड़) द्वारा किया गया, जिसके बाद ओएनजीसी (₹40.17 करोड़) का स्थान रहा।
- अंडमान और निकोबार में सीएसआर व्यय सबसे कम था (₹3.24 करोड़) के बाद दादरा और नगर हवेली (₹3.49 करोड़), चंडीगढ़ (₹3.51 करोड़), और मेघालय (₹3.91 करोड़) हैं।
- पूर्वोत्तर राज्यों (आठ राज्य) के संबंध में कुल ₹365.45 करोड़ के व्यय में से, अधिकतम सीएसआर व्यय असम (₹289.79 करोड़) में हुआ, जो पूर्वोत्तर राज्यों में कुल व्यय का लगभग 80 प्रतिशत था। सबसे कम व्यय मेघालय (₹3.91 करोड़) में हुआ।

डीपीई ने जवाब में कहा (अप्रैल 2024) कि हालांकि, स्थानीय क्षेत्रों में सीएसआर खर्च बोर्ड का विशेषाधिकार है या किसी कंपनी की नीति द्वारा संचालित है, वे राष्ट्रीय प्राथमिकता के साथ-साथ कल्याणकारी राज्य की बड़ी ज़रूरतों के अनुसार अपने सीएसआर व्यय को गैर-स्थानीय क्षेत्रों में मोड़ सकते हैं क्योंकि किसी भौगोलिक क्षेत्र को प्राथमिकता देने के लिए कोई प्रतिबंध या बाध्यता नहीं है। आकांक्षी जिलों में खर्च अधिमानतः सीपीएसई द्वारा किया जाना है। चूंकि राज्यों के बीच आकांक्षी जिलों की संख्या अत्यधिक परिवर्तनशील है, इसलिए व्यय पूरे राज्य/देश में समान रूप से वितरित नहीं हो सकता है।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि 63 सीपीएसई में से 47 सीपीएसई ने 112 आकांक्षी जिलों में से 94 में कुल ₹360.95 करोड़ खर्च किए थे, जो कुल सीएसआर का 9 प्रतिशत था। स्थानीय क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों का चयन करते समय, सीपीएसई को सीएसआर गतिविधियों के संचालन के लिए सबसे अधिक उपेक्षित क्षेत्र की पहचान करनी चाहिए, जिससे संबंधित राज्यों और राष्ट्र का समग्र विकास हो सके।

5.5.2.5 पिछले वर्ष में खर्च की गई अतिरिक्त राशि का समायोजन

सीएसआर नियमों (नियम 7 {3}) में संशोधन (जनवरी 2021) के अनुसार, "जहां कोई कंपनी धारा 135 की उप-धारा (5) के तहत प्रदान की गई आवश्यकता से अधिक राशि

खर्च करती है, ऐसी अतिरिक्त राशि को धारा 135 की उप-धारा (5) के तहत खर्च करने की आवश्यकता के विरुद्ध तत्काल बाद के तीन वित्तीय वर्षों तक इन शर्तों के अधीन सेट किया जा सकता है कि - (i) सेट ऑफ के लिए उपलब्ध अतिरिक्त राशि में सीएसआर गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो, शामिल नहीं होगा और (ii) बोर्ड उस आशय का प्रस्ताव पारित करेगा।

63 सीपीएसई में से 19 सीपीएसई ने पिछले वर्ष यानी 2020-21 में 2 प्रतिशत से अधिक खर्च किया था। तदनुसार, सभी 19 सीपीएसई ने पिछले वर्ष के दौरान खर्च की गई अतिरिक्त राशि को 2021-22 में खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि के विरुद्ध सेट ऑफ कर दिया था। हालाँकि, तीन सीपीएसई⁸⁸ ने इस संबंध में बोर्ड का प्रस्ताव पारित नहीं किया था। दो सीपीएसई के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं थी⁸⁹। इन 19 सीपीएसई की सूची, जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए अतिरिक्त सीएसआर व्यय से संबंधित वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान इस तरह के सेट ऑफ का दावा किया है, *अनुलग्नक-XXVII* में दी गई है।

डीपीई ने जवाब में कहा (अप्रैल 2024) कि पैरा का शीर्षक और उसके अंतर्गत मामला एक दूसरे से मेल नहीं खाता। इसलिए, इसमें संशोधन की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा ने बताया है कि अतिरिक्त राशि का समायोजन करते समय सीपीएसई ने संशोधित सीएसआर नियमों में निर्दिष्ट उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया था, जो इस संबंध में बोर्ड का प्रस्ताव पारित करने के संबंध में था।

5.5.2.6 अप्रयुक्त सीएसआर खाते में अप्रयुक्त राशि का स्थानांतरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (6) के अनुसार, किसी कंपनी की सीएसआर नीति के अनुसरण में किसी चल रही परियोजना के संबंध में उप-धारा (5) के तहत खर्च न की गई कोई भी राशि कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीस दिनों की अवधि के भीतर किसी भी अनुसूचित बैंक में उस वित्तीय वर्ष के लिए खोले गए 'अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व खाता' नामक एक विशेष खाते में स्थानांतरित की जाएगी। कंपनी द्वारा ऐसी राशि को ऐसे हस्तांतरण की तिथि से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर

⁸⁸ एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गैल गैस लिमिटेड

⁸⁹ एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड।

सीएसआर गतिविधियों के लिए खर्च किया जाएगा, ऐसा न करने पर, कंपनी को तीसरे वित्तीय वर्ष के पूरा होने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में इसे स्थानांतरित करना होगा।

इसके अतिरिक्त, चालू परियोजना के अलावा अन्य से संबंधित अप्रयुक्त राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह माह के भीतर अनुसूची VII में शामिल किसी भी निधि में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक 63 सीपीएसई में से 26 सीपीएसई के पास ₹259.69 करोड़ की अप्रयुक्त राशि थी। जिसका विवरण *अनुलग्नक-XXVIII* में दिया गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- 23 सीपीएसई ने चालू परियोजनाओं के संबंध में 30 दिनों के निर्धारित समय के भीतर 255.09 करोड़ रुपये की अव्ययित राशि को अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित कर दिया था।
- नौ सीपीएसई ने⁹⁰ चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य अप्रयुक्त राशि के मामले में 30 सितंबर 2022 के भीतर अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट निधि में ₹131.25 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की थी।
- एक सीपीएसई (आर्टिफिकल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) ने 2021-22 के दौरान सीएसआर के लिए ₹142.05 लाख की राशि आवंटित की थी। हालाँकि, कंपनी ने कोविड से संबंधित बुनियादी ढाँचे आदि में केवल ₹113.21 लाख खर्च किए और शेष ₹28.84 लाख की राशि को अप्रयुक्त सीएसआर खाते में स्थानांतरित कर दिया, जबकि उस तिथि तक कंपनी के पास कोई “चालू परियोजना” नहीं थी, जहां इस राशि का उपयोग किया जाना था क्योंकि शुरू की गई गतिविधियों के लिए परिव्यय राशि कुल व्यय से मेल खाती थी। इस प्रकार, इस अप्रयुक्त राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह महीने के भीतर अधिनियम की अनुसूची VII में

⁹⁰ नौ सीपीएसई यानी चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, गोल गैस लिमिटेड, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईटीआई लिमिटेड, एनएचडीसी लिमिटेड, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर सर्विसेज इंकॉर्पोरेटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड ने पीएम केयर्स फंड में धनराशि स्थानांतरित की है और एक सीपीएसई यानी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने फंड का नाम नहीं बताया है।

शामिल किसी भी निधि में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था।

इस पर कंपनी ने जवाब दिया (जनवरी 2023) कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(6) के अनुपालन में, यदि चल रही परियोजना की अव्ययित राशि शेष है, तो उसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीस दिनों की अवधि के भीतर विशेष खाते में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। हालांकि, परियोजना को निर्दिष्ट करना आवश्यक नहीं है। चूंकि राशि चल रही परियोजना के लिए अलग रखी गई थी, इसलिए, कोई अव्ययित राशि नहीं थी जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

प्रतिक्रिया को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 को 'अव्ययित सीएसआर राशि के उपचार' पर एमसीए स्पष्टीकरण (अगस्त 2021) के साथ पढ़ा जाए तो यह अनिवार्य है कि किसी विशेष वित्तीय वर्ष की चल रही परियोजना के संबंध में अव्ययित शेष राशि को 'अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व खाते' (यूसीएसआरए) में स्थानांतरित कर दिया जाए। आगे यह भी प्रावधान है कि यदि कंपनी ऐसी राशि खर्च करने में विफल रहती है, तो बोर्ड अपनी रिपोर्ट में राशि खर्च न करने के कारणों को निर्दिष्ट करेगा और जब तक कि अव्ययित राशि किसी चल रही परियोजना से संबंधित न हो, राशि को एक निर्दिष्ट कोष में स्थानांतरित कर देगा। कंपनी द्वारा इनमें से किसी का भी पालन नहीं किया गया; और इसलिए, ₹28.84 लाख की सीमा तक अव्ययित सीएसआर फंड को अनियमित रूप से रोके रखा गया और साथ ही बोर्ड की रिपोर्ट में प्रकटीकरण आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया गया।

- इसी प्रकार, इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने चल रही परियोजनाओं को निर्दिष्ट किए बिना यूसीएसआरए को 269.86 लाख रुपये हस्तांतरित कर दिए।
- ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने वर्ष 2021-22 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट में 30 अप्रैल, 2022 को अप्रयुक्त सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि के रूप में ₹13.07 करोड़ की सूचना दी थी। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि बैंक स्टेटमेंट के अनुसार, अप्रयुक्त सीएसआर खाते में ₹14.53 करोड़ जमा किए गए थे (₹13.07 करोड़ 30 अप्रैल, 2022 (देय तिथि) तक हस्तांतरित किए गए थे और

शेष ₹1.46 करोड़ की अप्रयुक्त राशि 02 मई, 2022 को विलंब से जमा की गई थी। इसके परिणामस्वरूप जमा करने में देरी हुई और अप्रयुक्त खाते में जमा राशि की गलत रिपोर्टिंग हुई।

तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ने बताया (फरवरी 2023) कि खामियों को नोट कर लिया गया है और तदनुसार सभी कार्य केंद्रों को 2022-23 की अव्ययित राशि को 25 अप्रैल, 2023 तक जमा करने की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश जारी किए जाएंगे।

5.5.2.7 सीएसआर गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष

सीएसआर नियम 2014 के नियम 6 (2) के अनुसार, किसी सीएसआर परियोजना या कार्यक्रम से उत्पन्न अधिशेष व्यवसाय लाभ का हिस्सा नहीं होगा। इसके अलावा, संशोधित सीएसआर नियम, 2021 के नियम 7 (2) में कहा गया है कि सीएसआर गतिविधियों से उत्पन्न कोई भी अधिशेष किसी कंपनी के व्यावसायिक लाभ का हिस्सा नहीं होगा और इसे उसी परियोजना में वापस लगाया जाएगा या इसे अप्रयुक्त सीएसआर खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और कंपनी की सीएसआर नीति और वार्षिक कार्य योजना के अनुसरण में खर्च किया जाएगा या ऐसी अधिशेष राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह महीने की अवधि के भीतर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

इसके अलावा, जनवरी 2021 में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार, सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष का विवरण, यदि कोई हो, तो सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट में खुलासा किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 63 सीपीएसई में से छह सीपीएसई ने⁹¹ सीएसआर गतिविधियों से ₹14.69 करोड़ की राशि का अधिशेष अर्जित किया था। इनमें से तीन सीपीएसई ने⁹² ₹9.03 करोड़ की राशि पुनर्निवेश की थी और तीन सीपीएसई ने⁹³ सीएसआर पर वार्षिक

⁹¹ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

⁹² पावर फाइनंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड।

⁹³ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड।

रिपोर्ट में ₹5.66 करोड़ की राशि के अधिशेष की रिपोर्ट नहीं की थी, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

- i. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कार्यान्वयन एजेंसियों ने लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा की गई 38 परियोजनाओं में से नौ में ₹22.52 लाख का ब्याज अर्जित किया था। हालांकि, कंपनी ने सीएसआर फंड पर अर्जित ब्याज को अधिशेष के रूप में रिपोर्ट नहीं किया।

कंपनी ने जवाब दिया (जनवरी 2023) कि सीएसआर परियोजना से अर्जित आय का उपयोग अन्य सीएसआर परियोजनाओं को आवंटन के माध्यम से सीएसआर गतिविधियों के लिए किया गया था। तथ्य यह है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 2 प्रतिशत सीएसआर दायित्व से अधिक ब्याज आय को अधिशेष के रूप में खुलासा नहीं किया था।

- ii. स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थान-स्वर्ण मंदिर के लिए स्वच्छता कार्य योजना परियोजना को लागू करने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने नगर निगम अमृतसर, पंजाब को ₹4.90 करोड़ (जुलाई 2017 में ₹1.65 करोड़ और नवंबर 2017 में ₹3.25 करोड़) जारी किए थे। यह परियोजना 31 मार्च, 2018 तक पूरी होनी थी, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि नगर निगम अमृतसर ने अपने फंड उपयोग विवरण में (अगस्त 2021) शेष राशि पर अर्जित ब्याज के रूप में ₹53.00 लाख का अधिशेष बताया था। यह राशि कंपनी द्वारा नगर निगम अमृतसर को किए गए अगले भुगतान के विरुद्ध सेट ऑफ कर दी गई थी। हालांकि, कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में अधिशेष का खुलासा नहीं किया था।

कंपनी ने स्वीकार किया (जनवरी 2023) कि परियोजना के तहत उसके द्वारा वितरित धनराशि पर ₹53.00 लाख की ब्याज राशि उत्पन्न हुई, जिसका उपयोग नगर निगम अमृतसर द्वारा समझौता ज्ञापनों के अनुरूप परियोजना के लिए किया गया, जो कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी द्वारा किए गए ₹1.93 करोड़ के योगदान से अतिरिक्त था। तथ्य यह है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने वर्ष 2021-22 के वित्तीय विवरणों में ₹53.00 लाख की अधिशेष आय की सूचना नहीं दी थी।

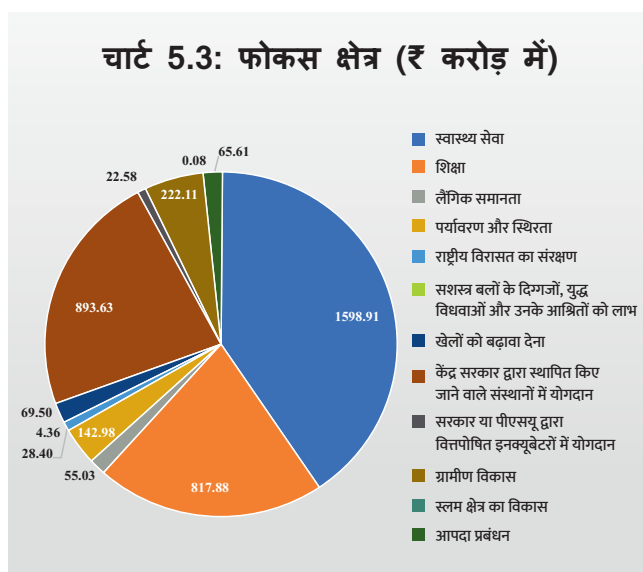
- iii. ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 2009 से 2022 के दौरान राजीव

गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी), असम के कॉर्पस फंड में ₹108.70 करोड़ का योगदान दिया था। आरजीआईपीटी ने इस राशि को सावधि जमा में निवेश किया और 2021-22 में उस पर अर्जित ब्याज (₹4.36 करोड़) का उपयोग आरजीआईपीटी के नियमित/परिचालन व्यय को पूरा करने के लिए किया जा रहा था। हालाँकि, कंपनी ने सीएसआर पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट में अधिशेष आय की सूचना नहीं दी थी।

कंपनी ने कहा (फरवरी 2023) कि आरजीआईपीटी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में उत्पन्न अधिशेष की रिपोर्ट कर रही थी जिसे अभी आरजीआईपीटी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाना बाकी था और इसलिए यह आरजीआईपीटी की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। हालाँकि तथ्य यह है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को आरजीआईपीटी से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए थी।

5.6 फोकस क्षेत्र

5.6.1 फोकस क्षेत्र का विश्लेषण



कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में 12 व्यापक क्षेत्र सूचीबद्ध हैं जिनके तहत एक कंपनी द्वारा सीएसआर फंड खर्च किया जा सकता है। जैसे कि (i) स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल, (ii) शिक्षा, कौशल विकास, (iii) लैंगिक समानता, सामाजिक समानता महिला सशक्तीकरण, वृद्धाश्रम आदि की स्थापना, (iv) पर्यावरण और स्थिरता (v) राष्ट्रीय विरासत,

कला और संस्कृति का संरक्षण, (vi) सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों को लाभ, (vii) खेलों को बढ़ावा देना, (viii) केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निधि, (ix) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वित्त पोषित इनक्यूबेटर्स में योगदान, (x) ग्रामीण विकास, (xi) स्लम क्षेत्र विकास और (xii) आपदा प्रबंधन।

63 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों (सीपीएसई) 2021-22 के लिए सीएसआर व्यय के मुख्य क्षेत्र के विश्लेषण से पता चला कि कुल ₹3,921.07 करोड़ (प्रशासनिक खर्चों को निकाल कर) के सीएसआर फंड में सीपीएसई ने मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा, अनुसूची VII कोष में योगदान और शिक्षा पर खर्च।

जबकि, सबसे कम व्यय झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों, युद्ध दिग्गजों और सशस्त्र बलों तथा प्रौद्योगिकी के विकास पर किया गया, जैसा कि तालिका 5.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.6: अधिकतम और न्यूनतम सीएसआर खर्च वाले फोकस क्षेत्र

प्रमुख व्यय वाले फोकस क्षेत्र		सबसे कम व्यय वाले फोकस क्षेत्र	
स्वास्थ्य देखभाल	₹1,598.91 करोड़ (40.78 प्रतिशत)	ग्रामीण विकास	₹7.78 लाख (0.001 %)
विभिन्न निधियों में योगदान	₹893.63 करोड़ (22.79 प्रतिशत)	सशस्त्र सेना के दिग्गज	₹4.36 करोड़ (0.11 %)
शिक्षा	₹817.88 करोड़ (20.86 प्रतिशत)	केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वित्तपोषित इनक्यूबेटरों में योगदान	₹22.58 करोड़ (0.58 %)

5.6.2 सामान्य विषय पर डीपीई दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन

दिसंबर 2018 से डीपीई स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पोषण जैसे सामान्य विषयों को अधिसूचित कर रहा है, जिन पर सभी सीपीएसई द्वारा संबंधित वर्षों के लिए सीएसआर व्यय किया जाना था। सीपीएसई को आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता देते हुए इन विषयों पर कम से कम 60 प्रतिशत खर्च करना आवश्यक था। डीपीई ने 12 मई, 2021 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रित हस्तक्षेप के लिए विषय के रूप में 'स्वास्थ्य और पोषण, जिसमें अस्थायी अस्पताल और अस्थायी कोविड देखभाल सुविधाएं स्थापित करने सहित कोविड से संबंधित उपायों पर विशेष ध्यान दिया गया है' को अधिसूचित किया था।

60 सीपीएसई द्वारा सूचित सामान्य विषय पर व्यय का प्रतिशत⁹⁴ नीचे दर्शाया गया है:

⁹⁴ तीन सीपीएसई अर्थात एमएसटीसी लिमिटेड, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड के लिए डेटा उपलब्ध नहीं है।

तालिका 5.7: सामान्य विषय पर व्यय का प्रतिशत

व्यय (प्रतिशत में)	सीपीएसई की संख्या	कुल व्यय (करोड़ रुपये में)
60 प्रतिशत से अधिक	40	1,932.85
60 प्रतिशत से कम	20	613.21
कुल	60	2,546.06

लेखापरीक्षा ने पाया कि उपरोक्त 40 सीपीएसई में से, एनटीपीसी लिमिटेड ने पर्यावरण और सौंदर्यीकरण गतिविधियों पर खर्च की गई ₹31.30 करोड़ की राशि को सामान्य थीम के अंतर्गत शामिल किया था, जिसके कारण सामान्य थीम पर लक्ष्य व्यय पूरा हुआ दिखाया गया था (66.54 प्रतिशत)। अन्य 39 सीपीएसई जिन्होंने सामान्य थीम पर 60 प्रतिशत व्यय हासिल किया था का विवरण *अनुलग्नक-XXIX* में है ।

डीपीई ने जवाब में कहा (अप्रैल 2024) कि फोकस क्षेत्रों की पहचान और उसके परिणामस्वरूप सीएसआर व्यय बोर्ड का विवेकाधिकार है। विभिन्न विषयों पर व्यय के अनुपात को डीपीई द्वारा घोषित सामान्य विषय के प्रकाश में देखा जाना चाहिए और इस प्रकार स्वास्थ्य और शिक्षा में सीएसआर व्यय का बड़ा हिस्सा इस तथ्य के कारण है कि ये सामान्य विषय का हिस्सा बने हुए हैं। सामान्य विषय पर 60 प्रतिशत व्यय के लक्ष्य को पूरा नहीं करने वाले सीपीएसई डीपीई दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हैं।

5.7 प्रशासनिक व्यय

प्रशासनिक ओवरहेड/व्यय का अर्थ है कंपनी द्वारा कंपनी में सीएसआर कार्यों के सामान्य प्रबंधन और प्रशासन के लिए किए गए व्यय, लेकिन इसमें किसी विशेष सीएसआर परियोजना के डिजाइन, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए सीधे किए गए व्यय शामिल नहीं होंगे। सीएसआर नियमों के अनुसार, प्रशासनिक व्यय को समग्र सीएसआर व्यय के 5 प्रतिशत के भीतर रखा जाना चाहिए। 2020-21 से उस वित्त वर्ष के लिए कुल सीएसआर व्यय का अतिरिक्त 5 प्रतिशत व्यय या ₹50 लाख जो भी कम हो, प्रभाव आकलन अध्ययनों के लिए अनुमति दी गई थी। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रशासनिक ओवरहेड के अंतर्गत आने वाले लागत तत्व सीएसआर प्रभाग में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए वेतन और प्रशिक्षण, स्टेशनरी लागत और यात्रा व्यय हैं।

63 सीपीएसई में से केवल 36 सीपीएसई ने ₹104.52 करोड़ का प्रशासनिक ओवरहेड खर्च किया था। 27 सीपीएसई ने कोई प्रशासनिक व्यय नहीं किया। 36 सीपीएसई के लिए कुल प्रशासनिक व्यय नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए हैं।

तालिका 5.8: 36 सीपीएसई के प्रशासनिक व्यय

क्रम सं.	प्रशासनिक व्यय के तत्व	राशि (करोड़ रुपये में)
1	आधारभूत सर्वेक्षण/आवश्यकता मूल्यांकन अध्ययन	0.13
2	क्षमता निर्माण कार्यक्रम जैसे प्रशिक्षण, कार्यशालाएं, सेमिनार, सम्मेलन आदि।	1.08
3	नियमित सीएसआर कर्मचारियों के साथ-साथ सीएसआर के लिए अपनी सेवाएं देने वाले कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन	100.30
4	अधिनियम, विनियमों आदि की पूर्ति पर किए गए व्यय।	0.04
5	कोई अन्य व्यय	2.97
	कुल ओवरहेड	104.52
	कुल सीएसआर	4,005.30
	कुल सीएसआर का प्रतिशत	2.61 %

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- प्रशासनिक/ओवरहेड व्यय का प्रमुख तत्व (95.96 प्रतिशत) वेतन था।
- पाँच सीपीएसई के संबंध में ओवरहेड व्यय 5 प्रतिशत की सीमा से अधिक हो गया, अर्थात् एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड (15.01 प्रतिशत - ₹40.43 लाख), एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड (11.35 प्रतिशत - ₹ 29 लाख), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (8.26 प्रतिशत - ₹2.54 करोड़), राइट्स लिमिटेड (6.73 प्रतिशत - ₹66.18 लाख) और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (5.79 प्रतिशत - ₹4.41 करोड़)।

सीपीएसई वार ओवरहेड्स **अनुलग्नक-XXV** में दिए गए हैं।

जहां तक प्रभाव आकलन पर किए गए व्यय का सवाल है, 63 सीपीएसई में से केवल 16 सीपीएसई ने प्रभाव आकलन पर ₹1.72 करोड़ की राशि खर्च की है और उनमें से

सभी ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (*अनुलग्नक-XXX*) द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा का अनुपालन किया है।

5.8 परियोजना कार्यान्वयन

5.8.1 आवश्यकता मूल्यांकन का संचालन

अगस्त 2016 की डीपीई अधिसूचना के अनुसार, सीपीएसई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने और सीएसआर के तहत गतिविधियों/परियोजनाओं के चयन के लिए हितधारकों के चयन और उनके साथ सहभागिता के मानदंड स्पष्ट रूप से रेखांकित किए गए हैं।

लेखापरीक्षा के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 63 सीपीएसई में से केवल 33 सीपीएसई ने 3,055 परियोजनाओं के संबंध में आधारभूत सर्वेक्षण और आवश्यकता मूल्यांकन अध्ययन कराया था। 33 सीपीएसई द्वारा आवश्यकता आकलन पर व्यय ₹12.95 लाख तक था। 25 सीपीएसई ने सीएसआर परियोजना/गतिविधि की पहचान के लिए आधारभूत सर्वेक्षण/आवश्यकता आकलन अध्ययन नहीं किया (*अनुलग्नक-XXXI*)। पाँच सीपीएसई के संबंध में डेटा⁹⁵ उपलब्ध नहीं था।

डीपीई ने जवाब में कहा (अप्रैल 2024) कि सभी स्थितियों में बेसलाइन सर्वेक्षण और आवश्यकता मूल्यांकन अध्ययन करना अनिवार्य नहीं है। ऐसी ज़रूरतें जिला प्रशासन/राज्य सरकार और अन्य हितधारकों द्वारा सुझाई जा सकती हैं।

उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जा सकता है कि डीपीई की अगस्त 2016 की अपनी अधिसूचना के अनुसार, सीपीएसई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों की जरूरतों को प्राथमिकता देने और सीएसआर के तहत गतिविधियों/परियोजनाओं के चयन के लिए हितधारकों के चयन और उनके साथ जुड़ाव के मानदंडों को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है।

⁹⁵ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल रिफ़्रेक्टरी कंपनी लिमिटेड, बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एमएसटीसी लिमिटेड।

5.8.2 सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन के तरीके के बारे में आंकड़े

कंपनी (सीएसआर) नियम, 2014 और 2021 का नियम 4 विशेष रूप से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के तहत सीएसआर गतिविधि करने के तरीके से संबंधित है। बोर्ड स्वयं या किसी पंजीकृत ट्रस्ट/सोसाइटी या कंपनी द्वारा स्थापित किसी कंपनी या अधिनियम की धारा 8 के तहत उसकी होल्डिंग या सहायक या सहयोगी कंपनी या अन्यथा के माध्यम से सीएसआर समिति द्वारा अनुमोदित अपनी सीएसआर गतिविधियों को करने का निर्णय ले सकता है।

कार्यान्वयन का तरीका इस प्रकार था:

- ✓ चार सीपीएसई ने सभी परियोजनाओं को आंतरिक स्तर पर क्रियान्वित किया था।
- ✓ आठ सीपीएसई ने सभी सीएसआर परियोजनाओं को बाहरी एजेंसियों को आउटसोर्स कर दिया था।
- ✓ 44 सीपीएसई ने परियोजनाओं को आंतरिक रूप से तथा बाह्य एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित किया।
- ✓ सात सीपीएसई ने⁹⁶ आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये।

बाह्य एजेंसियों के माध्यम से क्रियान्वित कुल 3,907 परियोजनाओं में से 3,844 परियोजनाओं के लिए उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि:

- 1,025 परियोजनाओं के संबंध में एजेंसियों का चयन निविदा के माध्यम से किया गया
- 751 परियोजनाओं के संबंध में एजेंसियों का चयन नामांकन के आधार पर किया गया।
- 2,068 परियोजनाएं या तो राज्य प्राधिकरण, जिला प्रशासन, ग्राम पंचायत के माध्यम से या गैर सरकारी संगठनों/कार्यान्वयन एजेंसियों आदि से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर शुरू की गईं।

⁹⁶ एनएमडीसी लिमिटेड, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इनकॉर्पोरेटेड, आईटीआई लिमिटेड, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड।

5.8.3 परियोजना के कार्यान्वयन में कमियाँ

(क) परिकल्पित उद्देश्यों की पूर्ति न होना

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने झारखंड सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया (जून 2015) जिसका उद्देश्य झारखंड राज्य में खेलों को बढ़ावा देना और सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत गठित सोसाइटी के तत्वावधान में खेलों के विकास को संयुक्त रूप से आगे बढ़ाना है ताकि प्रतिभाशाली खेल कर्मियों/खिलाड़ियों के विकास और पोषण पर अधिक से अधिक और केंद्रित ध्यान दिया जा सके और होटवार , रांची में एकीकृत खेल परिसर में 15 खेल अकादमियों और एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा सके।

समझौता ज्ञापन की शर्तें और उनकी उपलब्धियां इस प्रकार थीं:

तालिका 5.9: एमओयू की शर्तें

समझौता ज्ञापन की शर्तें	समय	मार्च 2022 तक वास्तविक
सात खेल अकादमियाँ स्थापित करना	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की तिथि से 12 महीने के भीतर अर्थात् जून 2016 तक	अब तक केवल 10 खेल अकादमियाँ स्थापित की गई हैं।
आठ खेल अकादमियाँ स्थापित करना	अगले 12 महीनों में- जून 2017	
खेल विश्वविद्यालय की स्थापना	एमओयू की तिथि से 36 महीने के भीतर - जून 2018	कोई खेल विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किया गया
सोसायटी द्वारा विभिन्न खेल अकादमियों में 700 छात्रों (न्यूनतम) और 1,400 छात्रों (अधिकतम) का चयन		2019-20 तक कुल 452 छात्रों को शामिल किया गया और खेल परिसर में दिसंबर 2022 तक 438 छात्र बने रहे।

कंपनी ने खेल अकादमी/खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मौजूदा सुविधाओं के उन्नयन, पुनर्वास और मरम्मत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी प्रारंभिक लागतों को वहन किया था। संचालन और रखरखाव की लागत दोनों पक्षों द्वारा समान अनुपात में वहन की जानी थी। कंपनी ने ₹39.33 करोड़ (2016-17 से 2021-22) की वित्तीय सहायता प्रदान की।

लेखापरीक्षा ने पाया कि समझौता जापन पर हस्ताक्षर करने के आठ साल बीत जाने के बाद भी उपरोक्त में से कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया गया, फिर भी कंपनी ने वित्तीय सहायता वितरित करना जारी रखा। समझौता जापन में परिकल्पित लक्ष्यों को हासिल न करने के बावजूद, कंपनी ने नई समयसीमा या संशोधित लक्ष्य पर विचार करते हुए इसे संशोधित नहीं किया। यह भी पाया गया कि 2021-22 में स्पोर्ट्स सोसाइटी के कुल व्यय ₹11.52 करोड़ में से, ₹4.35 करोड़ (यानी, 38 प्रतिशत) केवल खेल संबंधी गतिविधियों पर खर्च किए गए और शेष ₹7.17 करोड़ (यानी, 62 प्रतिशत) प्रशासनिक/स्थापना/मरम्मत संबंधी गतिविधियों पर खर्च किए गए।

कंपनी ने बताया (जनवरी 2023) कि कोविड महामारी के कारण मार्च 2020 से मार्च 2022 तक खेल कैडेटों के प्रवेश के साथ-साथ अकादमी के कामकाज और संचालन में बाधा आई। सीमित छात्रावास क्षमता के कारण आवास क्षमता बढ़ाने के बाद जल्द ही नए प्रवेश शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा, खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में, 2017 में राज्य विधानसभा में एक प्रस्तावित मसौदा विधेयक पारित किया गया था और राज्यपाल को स्वीकृति के लिए भेजा गया था और यह झारखंड सरकार के विचाराधीन है। विशिष्ट प्रतिबद्धताओं के लिए समझौता जापन में समयसीमा में संशोधन को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विचार के लिए रखा जाएगा।

जवाब को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि एमओयू में परिकल्पित लक्ष्य हासिल करने की समयसीमा कोविड महामारी से पहले की थी और लक्ष्य आज तक हासिल नहीं किए गए थे। लक्ष्य को पूरा न करने के बावजूद, एमओयू को संशोधित नहीं किया गया और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने अपने सीएसआर फंड से अनुदान वितरित करना जारी रखा। इसके अलावा, अधिकांश अनुदानों का उपयोग मरम्मत और रखरखाव और स्थापना संबंधी गतिविधियों के लिए किया गया।

(ख) बिलों की प्रामाणिकता का सत्यापन न किया जाना

जुलाई 2021 में गेल गैस लिमिटेड को समन्वित शिक्षा संस्थान, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत गैर सरकारी संगठन से रायसेन जिले, मध्य प्रदेश के ग्रामीण समुदाय के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए में एक सीएसआर प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस परियोजना को “डिजिटल साक्षरता पर सामुदायिक सशक्तिकरण

के माध्यम से सतत आजीविका” कहा गया। ₹15.01 लाख के अनुमानित लागत में मानव संसाधन व्यय और 10 ऑल-इन-वन कंप्यूटर, एक लैपटॉप, दो टैबलेट और प्रिंटर, प्रोजेक्टर आदि जैसी अन्य आवश्यकताओं की खरीद शामिल थी। कंपनी की सीएसआर समिति ने सितंबर 2021 में कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रस्तावित समान बजट आवंटन के साथ परियोजना को मंजूरी दी। अक्टूबर 2021 में एजेंसी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

एजेंसी ने समय-समय पर परियोजना के लिए खरीदे 20 ऑल-इन-वन कंप्यूटरों और बाह्य उपकरणों के लिए निधि उपयोग रिपोर्ट और चालान के साथ-साथ उन विद्यालयों के प्रधानाचार्यों से प्राप्त पत्रों की प्रतियां प्रस्तुत किए जिन्हें ये कंप्यूटर और बाह्य उपकरण उपलब्ध कराए गए थे।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि स्कूलों को दान किए गए कंप्यूटर, प्रिंटर और बाह्य उपकरणों के मेक, मॉडल, निर्माण की तिथि और विन्यास का विवरण कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रस्तुत संबंधित चालान में उल्लेखित नहीं था। साथ ही, ये चालान न तो जीएसटी चालान थे और न ही जीएसटी से छूट के बारे में कोई दस्तावेज प्रदान किया गया था। इसलिए, लेखापरीक्षा दान किए गए दस्तावेजों और उपकरणों की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं कर सकी।

कंपनी ने बताया (जनवरी 2023) कि एजेंसी ने ट्रांस प्रिविलेज्ड ग्लोबल वेलफेयर फाउंडेशन नामक एक एनजीओ से कंप्यूटर खरीदे थे, इसलिए कोई जीएसटी चालान नहीं दिया गया। इसके अलावा, खरीदे गए कंप्यूटर नए और बेसिक मॉडल के थे, जिसकी वजह से कंप्यूटर की कीमत कम है। डिजिटल साक्षरता परियोजना पूरी होने के बाद कंप्यूटर सरकारी स्कूलों को सौंप दिए गए।

उत्तर को निम्नलिखित दृष्टि से देखा जाना चाहिए:

- गेल गैस लिमिटेड ने कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से दान किए गए कंप्यूटरों और बाह्य उपकरणों का विवरण और विन्यास प्राप्त नहीं किया, जिसके कारण उपकरणों की विश्वसनीयता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।
- प्रस्तुत किए गए चालान गैर-जीएसटी चालान थे और कंपनी जीएसटी से छूट के लिए कोई सहायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकी।

(ग) व्यय की अधिक बुकिंग

ओएनजीसी फाउंडेशन ने अपनी एक सीएसआर परियोजना के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे थे। विदेशी विक्रेता से प्राप्त ऑक्सीजन कंसंट्रेटर (संख्या में 5,000) को अंतिम गंतव्य पर ले जाने से पहले अस्थायी रूप से नई दिल्ली के गोदाम में रखा गया था। ओएनजीसी फाउंडेशन ने भंडारण और बीमा शुल्क के लिए ₹11.11 लाख खर्च किए। ये शुल्क ओएनजीसी फाउंडेशन और तेल पीएसयू के बीच समान रूप से (₹1.59 लाख प्रत्येक) साझा किए जाने थे⁹⁷ क्योंकि सभी एक ही सुविधा का उपयोग कर रहे थे। तेल पीएसयू ने तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड को अपना हिस्सा वापस कर दिया था। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ने अपनी पुस्तकों में संपूर्ण वेयरहाउसिंग लागत दर्ज की थी, जिसके परिणामस्वरूप सीएसआर परियोजना लागत (₹9.52 लाख) अधिक दर्ज हुई।

5.9 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में शामिल न की गई गतिविधियों का सीएसआर वित्तपोषण

जैसा कि पैरा 5.6 में बताया गया है, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में 12 व्यापक क्षेत्र सूचीबद्ध हैं, जिनके अंतर्गत कोई कंपनी सीएसआर निधि खर्च कर सकती है। इसके अलावा संशोधित सीएसआर नियमों और एमसीए (अगस्त 2021) द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार 22 जनवरी 2021 से किसी भी इकाई के कोष में योगदान स्वीकार्य सीएसआर व्यय नहीं है।

लेखापरीक्षा ने एक सीपीएसई यानी तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड के मामले में अयोग्य निधि में योगदान के संबंध में विचलन देखा, जिसने आरजीआईपीटी - असम ऊर्जा केंद्र (इस अध्याय के पैरा 5.5.2.7 में उल्लिखित) को एंडोमेंट फंड (कॉर्पस फंड) के लिए ₹27.84 करोड़ का योगदान दिया था (मार्च 2022)। यह योगदान सीएसआर गतिविधि के अंतर्गत नहीं आता है।

कंपनी ने बताया (फरवरी 2023) कि ₹80.86 करोड़ की बंदोबस्ती राशि केवल 2012

⁹⁷ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, गेल (इंडिया) लिमिटेड, बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड।

तक ही प्रदान की गई थी। उसके बाद कंपनी द्वारा आरजीआईपीटी को उनके बंदोबस्ती कोष में योगदान के उद्देश्य से कोई राशि जारी नहीं की गई है। प्रबंधन ने कहा कि कंपनी ने 25 मार्च, 2022 को पूंजीगत व्यय के लिए आरजीआईपीटी को ₹32.93 करोड़ की धनराशि जारी की थी, जिसके लिए आरजीआईपीटी ने निधि उपयोग प्रमाणपत्र प्रदान किया है, जिसमें किसी बंदोबस्ती निधि का उल्लेख नहीं था।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 29 सितंबर, 2021 के पत्र के माध्यम से कंपनी को सूचित किया कि कंपनी से ₹32.93 करोड़ (कैपेक्स के लिए ₹5.09 करोड़ और एंडोमेंट फंड के लिए ₹27.84 करोड़) अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके अलावा, आरजीआईपीटी ने 27 जनवरी, 2023 के अपने पत्र में यह भी कहा कि कंपनी से एंडोमेंट फंड के रूप में उन्हें ₹108.7 करोड़ (2020 तक ₹80.86 करोड़ और 2022 में ₹27.84 करोड़) प्राप्त हुए हैं। इसलिए, 22 जनवरी, 2021 से आरजीआईपीटी के कॉर्पस फंड में ₹27.84 करोड़ का योगदान सीएसआर व्यय के रूप में अयोग्य है।

डीपीई ने अपने जवाब में (अप्रैल 2024) ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संबंध में तथ्यों को स्वीकार किया।

5.10 निगरानी ढांचा

सीएसआर नियम, 2014 के नियम 5(2) के अनुसार, सीएसआर समिति सीपीएसई द्वारा किए गए सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी निगरानी तंत्र स्थापित करेगी। डीपीई ने 01 अगस्त, 2016 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सीपीएसई को सीएसआर की निगरानी, रिपोर्टिंग और मूल्यांकन के लिए एक संस्थागत तंत्र बनाने का निर्देश दिया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 63 सीपीएसई में से,

- 14 सीपीएसई ने मासिक समीक्षा की,
- 17 सीपीएसई ने त्रैमासिक/द्वैमासिक, चार सीपीएसई ने⁹⁸ अर्धवार्षिक और दो सीपीएसई

⁹⁸ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड, एनएमडीसी लिमिटेड, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड।

ने⁹⁹ वार्षिक निगरानी की।

- 8 सीपीएसई ने एमओयू/परियोजना/आवश्यकता के आधार पर समीक्षा की,
- 10 सीपीएसई ने नियमित/लगातार समीक्षा की,
- 4 सीपीएसई ने¹⁰⁰ निगरानी की आवश्यकता निर्दिष्ट नहीं की,
- 4 सीपीएसई ने¹⁰¹ कोई जानकारी नहीं दी।

उपरोक्त सीपीएसई का विवरण *अनुलग्नक-XXXII* में दिया गया है।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि एक सीपीएसई यानी एनटीपीसी लिमिटेड ने ₹66.08 लाख की लागत से सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एसआईई) करने के लिए तैनात एजेंसी के लिए निगरानी और मूल्यांकन प्रक्रिया नहीं की थी, जैसा कि संदर्भ की शर्तों (टीओआर) के तहत निर्धारित किया गया था। 2021-22 के दौरान तैनात एजेंसियों के लिए कंपनी के पास न तो साप्ताहिक और न ही मासिक निगरानी रिपोर्ट उपलब्ध थी। इस प्रकार, कंपनी ने अपनी सीएसआर नीति से विचलन किया है और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के लिए टीओआर के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है।

कंपनी ने जवाब दिया (फरवरी 2023) कि एसआईई प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक तीन साल में टीओआर के अनुरूप आयोजित किया जाता है। एनटीपीसी कार्यों और खरीद नीति में परिभाषित प्रक्रिया के अनुसार एसआईई को सूचीबद्ध एजेंसियों/संस्थानों के माध्यम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त, एसआईई की प्रगति की निगरानी समय पर पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए एक अनुबंध की शर्त है। इस संबंध में, एजेंसियों को कंपनी अधिनियम के अनुसार अनिवार्य आवश्यकता के अलावा सीएसआर पहलों के प्रभाव का आकलन करने के लिए समीक्षा और टिप्पणियों के लिए सभी निष्कर्षों के साथ एक समेकित मसौदा रिपोर्ट कंपनी को प्रस्तुत करना आवश्यक था। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि कंपनी में एसटीई का संचालन प्रसिद्ध कंपनियों द्वारा किया गया था जो ज्यादातर

⁹⁹ चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स (त्रावणकोर) लिमिटेड।

¹⁰⁰ एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलिमर लिमिटेड, एन बी सी सी (इंडिया) लिमिटेड, पावर ग्रिड सदरन इन्टरकनेक्टर ट्रेन्ज़िमेशन लिमिटेड।

¹⁰¹ एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स (इंडिया) लिमिटेड, बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, सिक्युरिटी, प्रिंटिंग मिनिटंग बुंगरही ऑफ इंडिया लिमिटेड, नैशनल समाल इंडस्ट्रीज़ बुंगरही लिमिटेड।

तय समय के अनुसार काम पूरा करने में सक्षम थीं। हालांकि, साप्ताहिक/मासिक निगरानी रिपोर्टों के अभाव में, लेखापरीक्षा यह सत्यापित नहीं कर सका कि टीओआर के अनुसार सूचीबद्ध एजेंसियों के लिए एसआईई प्रगति की निगरानी की गई है और क्या काम पूरा होने को सुनिश्चित किया गया था।

5.11 प्रभाव आकलन

संशोधित सीएसआर नियम, 2021 के नियम 8 (3) (ए) के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसरण में पिछले तीन वित्तीय वर्षों में 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक की औसत सीएसआर बाध्यता वाली प्रत्येक कंपनी को एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से एक करोड़ रुपये या उससे अधिक के परिव्यय वाली अपनी सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव आकलन करना होगा, जो प्रभाव आकलन करने से कम से कम एक वर्ष पहले पूरी हो गई हों।

63 सीपीएसई में से 37 सीपीएसई की औसत सीएसआर देनदारी ₹10 करोड़ से अधिक थी। इनमें से 22 सीपीएसई की सीएसआर परियोजनाएं ₹1 करोड़ से अधिक की थीं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सभी 22 सीपीएसई ने एक स्वतंत्र एजेंसी (अनुलग्नक-XXXIII) के माध्यम से प्रभाव मूल्यांकन कराया था ।

5.12 रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण

सीएसआर संशोधन नियम, 2021 के नियम 8 के अनुसार, कंपनियों को सीएसआर पर एक वार्षिक रिपोर्ट शामिल करनी होगी जिसमें सीएसआर नीति और उसके वेब लिंक, औसत शुद्ध लाभ, सीएसआर समिति की संरचना, प्रशासनिक ओवरहेड्स, निर्धारित राशि, अप्रयुक्त राशि, अप्रयुक्त राशि के कारण आदि का खुलासा करते हुए निर्धारित प्रारूप में निर्दिष्ट विवरण शामिल होंगे।

नियम 9 के अनुसार, कंपनी को अपनी वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना और सीएसआर नीति तथा बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं का अनिवार्य रूप से खुलासा करना चाहिए।

नियम 10 के अनुसार, किसी कंपनी द्वारा सीएसआर परियोजनाओं के अंतर्गत परिसंपत्तियों के सृजन या अधिग्रहण के मामले में, कंपनी द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक

रिपोर्ट में मद 10 के अंतर्गत निम्नलिखित परिसंपत्ति-वार विवरण भी प्रदान किया जाना चाहिए:

- पूंजीगत परिसंपत्ति(ओं) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि
- पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर राशि
- उस संस्था या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि।
- निर्मित या अर्जित पूंजीगत परिसंपत्तियों का विवरण (पूंजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित)

इस संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियां निम्नानुसार थीं:

(क) लेखापरीक्षा ने पाया कि 63 सीपीएसई में से आठ सीपीएसई ने¹⁰² निम्नानुसार वैधानिक प्रकटीकरण आवश्यकता का पूर्णतः पालन नहीं किया है:

- दो सीपीएसई (आर्टिफिकल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में सीएसआर गतिविधियों की रिपोर्टिंग करते समय प्रकटीकरण प्रारूप का अनुपालन नहीं किया।

सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड ने उत्तर दिया (फरवरी 2023) कि यदि सीएसआर प्रावधान कंपनी पर 01 अप्रैल, 2020 को या उससे पहले लागू होते हैं, तो अनुलग्नक-1 प्रारूप के अनुसार रिपोर्ट तैयार करने की आवश्यकता है और यदि सीएसआर प्रावधान कंपनी पर 01 अप्रैल, 2020 को या उसके बाद लागू होते हैं, तो अनुलग्नक-2 प्रारूप के अनुसार रिपोर्ट तैयार करने की आवश्यकता है। इसलिए, कंपनी ने अनुलग्नक-1 के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट सही ढंग से रिपोर्ट की थी। एसआरसीएल का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुलग्नक-1 01 अप्रैल, 2020 से पहले शुरू हुए वित्तीय वर्ष के लिए लागू है जबकि अनुलग्नक-2 01 अप्रैल, 2020 को या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लागू है। चूंकि रिपोर्टिंग 2021-

¹⁰² आर्टिफिकल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स (त्रावणकोर) लिमिटेड, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड, पावर ग्रिड सदरन इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इनकॉर्पोरेटेड, सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड।

22 की अवधि के लिए है, इसलिए इस मामले में अनुलग्नक-2 लागू है जिसका कंपनी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया था।

- तीन सीपीएसई (चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, पावर ग्रिड सदरन इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इनकॉर्पोरेटेड) ने अपनी वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का खुलासा नहीं किया था। जबकि चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और पावर ग्रिड सदरन इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड की कोई वेबसाइट नहीं है, वहीं नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इनकॉर्पोरेटेड की वेबसाइट में सुधार की बात कही गई है।

चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने जवाब दिया (जनवरी 2023) कि कंपनी (सीएसआर नीति) संशोधन नियम, 2021 के नियम 9 के अनुसार, यह उल्लेख किया गया है कि सीएसआर नीति को सार्वजनिक पहुंच के लिए वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना है, यदि कोई हो। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की वेबसाइट बनाने की प्रक्रिया चल रही है और जब वेबसाइट चालू हो जाएगी तो सीएसआर नीति प्रदर्शित की जाएगी।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा निगमित ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार कर लिया गया (दिसंबर 2022) और कंपनी की वेबसाइट को अपडेट करने का आश्वासन दिया गया।

- एक सीपीएसई (इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड) ने अपनी वेबसाइट पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं का आंशिक रूप से खुलासा किया था और एक सीपीएसई (उर्वरक एवं रसायन (त्रावणकोर) लिमिटेड) ने अपनी वेबसाइट पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं का खुलासा नहीं किया था।

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने जवाब दिया (नवंबर 2022) कि अवलोकन को नोट कर लिया गया है और जल्द से जल्द इसका अनुपालन किया जाएगा।

फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स (त्रावणकोर) लिमिटेड ने जवाब दिया (जनवरी 2023) कि उसने अपनी वेबसाइट पर सीएसआर समिति और सीएसआर नीति की संरचना

प्रकाशित कर दी है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर नीति में कंपनी द्वारा परिकल्पित परियोजनाओं की प्रकृति शामिल है और यह कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। हालांकि, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स (त्रावणकोर) लिमिटेड ने उनकी वेबसाइट पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं का खुलासा न करने के संबंध में टिप्पणी पर कोई जवाब नहीं दिया।

(ख) दो सीपीएसई (एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में अव्ययित राशि की सूचना नहीं दी थी।

- वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तावित सीएसआर गतिविधियों के अनुसार, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए अव्ययित राशि ₹4.33 करोड़ थी, फिर भी कंपनी ने इसे शून्य बताया। इसलिए रिपोर्ट में अव्ययित राशि के कारणों का भी खुलासा नहीं किया गया।

एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जवाब दिया (दिसंबर 2022) कि कंपनी ने सीएसआर को लागू करने के लिए लाभार्थी/सार्वजनिक प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और इसकी प्रगति के लिए नियमित आधार पर इसकी निगरानी की। कंपनी ने वर्ष के अंत में अपनी पुस्तकों में शेष आवंटित राशि के लिए देयता का प्रावधान किया, भले ही उस वर्ष के दौरान इसका भुगतान नहीं किया गया था, जो आईसीएआई द्वारा 'सीएसआर गतिविधियों के व्यय के लिए लेखांकन' पर तकनीकी गाइड के पैरा-18 के अनुरूप था। कंपनी पहले से ही अलग बैंक खाता बनाए हुए थी, जिसमें हर साल आवंटित कुल राशि स्थानांतरित की जाती थी और सीएसआर परियोजनाओं के लिए सभी भुगतान इस अलग बैंक खाते से किए जाते थे। इसलिए, इस अलग बैंक खाते में शेष राशि चल रही परियोजनाओं के लिए देय शेष राशि थी।

उत्तर को तकनीकी गाइड के पैरा-18 के संदर्भ में देखा जा सकता है जिसमें कहा गया है कि “... वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधि किस सीमा तक पूरी हुई, इसकी राशि के लिए देयता का प्रावधान वित्तीय विवरण में मान्य होना चाहिए...”। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सीएसआर गतिविधि पूरी नहीं की तथा देयता को स्वीकार कर लिया तथा बोर्ड रिपोर्ट में इसे व्यय के रूप में दर्शाया, जो उचित नहीं है। अप्रयुक्त राशि को अलग बैंक खाते में रखा जाना था तथा बोर्ड रिपोर्ट में कंपनी अधिनियम,

2013 की धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार निर्धारित समय के भीतर खर्च न कर पाने का कारण/औचित्य बताया जाना चाहिए था।

- 2021-22 के दौरान, इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने ₹2.69 करोड़ की अव्ययित राशि को अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित कर दिया था। हालाँकि, वार्षिक रिपोर्ट में अव्ययित राशि को गलत तरीके से 'शून्य' दिखाया गया था। कंपनी ने स्वीकार किया (नवंबर 2022) कि रिपोर्ट में दी गई जानकारी तथ्यात्मक रूप से गलत थी।
- (ग) लेखापरीक्षा में पाया गया कि 63 सीपीएसई में से 21 सीपीएसई ने वर्ष 2021-22 के दौरान सीएसआर गतिविधियों (*अनुलग्नक-XXXIV*) के माध्यम से पूंजीगत संपत्तियां बनाई/अर्जित की थीं, जिनमें से तीन सीपीएसई (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) ने वार्षिक रिपोर्ट में इसका खुलासा नहीं किया था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:
- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अनुसार, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने वर्ष 2021-22 के दौरान संपत्ति के निर्माण/अधिग्रहण पर ₹7.95 करोड़ की राशि खर्च की। हालांकि, कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट में इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी। कंपनी का उत्तर (मार्च 2023) वार्षिक रिपोर्ट में अन्य पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण/अधिग्रहण का खुलासा न करने पर नगण्य है।
- भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सीएसआर गतिविधियों पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट में न तो किसी पूंजीगत संपत्ति के बारे में रिपोर्ट की और न ही पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण/अधिग्रहण के लिए किसी सीएसआर व्यय का खुलासा किया। कंपनी ने वर्ष 2022-23 के दौरान सीएसआर के माध्यम से बनाई गई या अधिग्रहित पूंजीगत संपत्तियों की सूची प्रकाशित करने का आश्वासन दिया (फरवरी 2023)।
- ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 'मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन प्लांट्स' की संपत्ति बनाई थी, हालांकि कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट में न तो किसी पूंजीगत संपत्ति के बारे में रिपोर्ट की है और न ही पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण/अधिग्रहण के लिए किसी सीएसआर व्यय का खुलासा किया है।

कंपनी ने कहा (फरवरी 2023) कि पीएसए प्लांट के चालू होने/स्थापना के बाद, सरकारी अस्पताल के पास संपत्ति/प्लांट के अधिकार, शीर्षक और हित होंगे। साथ ही, संबंधित सरकार पर ओएनजीसी फाउंडेशन की वित्तीय सहायता से अगले पांच वर्षों के लिए प्लांट के उचित रख-रखाव/कार्य और रखरखाव के लिए बाध्यता थी। चूंकि कंपनी या ओएनजीसी फाउंडेशन के साथ कोई पूंजीगत संपत्ति नहीं बनाई गई है, इसलिए यह माना गया कि बोर्ड की रिपोर्ट में आवश्यक प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

प्रबंधन की प्रतिक्रिया को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जा सकता है कि संशोधित सीएसआर नियम, 2021 के अनुसार किसी विशेष वर्ष के लिए सीएसआर के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण और अधिग्रहण के संबंध में विवरण घोषित करने के लिए अधिकार और शीर्षक का कोई मानदंड नहीं है और ऐसी सभी पूंजीगत परिसंपत्तियों की जानकारी वर्तमान मालिक की परवाह किए बिना प्रस्तुत की जानी चाहिए। इसलिए, इसे सीएसआर रिपोर्ट के आइटम 10 के तहत रिपोर्ट किया जाना चाहिए था।

5.13 निष्कर्ष

सभी चयनित 63 सीपीएसई ने सीएसआर नीति तैयार की थी और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसरण में सीएसआर समिति का गठन किया था। 63 में से 60 सीपीएसई को अपने शुद्ध लाभ के आधार पर सीएसआर व्यय करना आवश्यक था। 60 पात्र सीपीएसई में से 21 सीपीएसई ने सीएसआर गतिविधियों के लिए ठीक 2 प्रतिशत निधि आवंटित की, 25 सीपीएसई ने 2 प्रतिशत से अधिक आवंटित किया, 14 सीपीएसई ने 2 प्रतिशत से कम आवंटित किया था और दो सीपीएसई के संबंध में डेटा उपलब्ध नहीं था। लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹3,655.84 करोड़ के औसत शुद्ध लाभ के निर्धारित 2 प्रतिशत के मुकाबले, कुल आवंटन ₹4,049.35 करोड़ था यानी अतिरिक्त आवंटन ₹409.61 करोड़ तक था। 63 सीपीएसई द्वारा किया गया वास्तविक सीएसआर व्यय 4,005.30 करोड़ रुपये था, जिसमें से दो सीपीएसई ने ठीक 2 प्रतिशत खर्च किया, 33 सीपीएसई ने 2 प्रतिशत से अधिक खर्च किया और 28 सीपीएसई ने 2 प्रतिशत से कम खर्च किया ।

छह सीपीएसई ने सीएसआर गतिविधियों से ₹14.69 करोड़ का अधिशेष अर्जित किया था, जिसमें से तीन सीपीएसई ने धनराशि पुनर्निवेश कर दी थी तथा तीन सीपीएसई ने अधिशेष धनराशि की सूचना नहीं दी थी।

पांच सीपीएसई के मामले में प्रशासनिक ओवरहेड 5 प्रतिशत की सीमा को पार कर गए थे। कुल 40 सीपीएसई ने कॉमन थीम 'स्वास्थ्य और पोषण, जिसमें अस्थायी अस्पताल और अस्थायी कोविड देखभाल सुविधाएं स्थापित करने सहित कोविड से संबंधित उपायों पर विशेष ध्यान दिया गया है पर 60 प्रतिशत सीएसआर खर्च का निर्धारित लक्ष्य हासिल किया था। एक सीपीएसई (एनटीपीसी लिमिटेड) ने कॉमन थीम के तहत ₹31.30 करोड़ की गलत राशि शामिल की थी, इस प्रकार 60 प्रतिशत से अधिक की रिपोर्ट की गई थी। आकांक्षी जिलों में सीएसआर खर्च कुल सीएसआर व्यय का 9 प्रतिशत ही था जो काफी कम था।

63 सीपीएसई में से 25 सीपीएसई ने सीएसआर परियोजनाओं की पहचान के लिए आधारभूत सर्वेक्षण और आवश्यकता मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया।

63 सीपीएसई ने 5,822 सीएसआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के तरीके की रिपोर्ट की थी, जिसमें 1,915 परियोजनाएं सीधे/इन-हाउस कार्यान्वित की गईं, और 3,907 परियोजनाएं सरकारी/बाहरी एजेंसियों, एनजीओ, सोसाइटी के माध्यम से निष्पादित की गईं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 1025 परियोजनाओं में एजेंसियों का चयन निविदा के माध्यम से किया गया, 751 परियोजनाओं में एजेंसियों का चयन नामांकन के माध्यम से किया गया और 2,068 परियोजनाएं या तो राज्य प्राधिकरण, जिला प्रशासन, ग्राम पंचायत के माध्यम से या एनजीओ/कार्यान्वयन एजेंसियों आदि से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर शुरू की गईं।

लेखापरीक्षा में सीएसआर नियमों और एमसीए के निर्देशों/दिशानिर्देशों का गैर-अनुपालन के उदाहरण भी पाए गए, जैसे अनुसूची सात के अंतर्गत शामिल न की गई गतिविधियों को वित्त पोषण, अयोग्य निधियों को वित्त पोषण, मुख्य रूप से कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाओं को वित्त पोषण, एकबारगी आयोजन आदि।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 63 सीपीएसई में से नौ सीपीएसई ने¹⁰³ वैधानिक प्रकटीकरण

¹⁰³ भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड, उर्वरक और रसायन (त्रावणकोर) लिमिटेड, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, राष्ट्रीय

आवश्यकता का पूर्णतः पालन नहीं किया था। 63 सीपीएसई में से 21 सीपीएसई ने वर्ष 2021-22 के दौरान सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन/अर्जन किया था, जिनमें से तीन सीपीएसई ने वार्षिक रिपोर्ट में इसका खुलासा नहीं किया था।

यह अध्याय डीपीई को जारी किया गया (दिसंबर 2023) और डीपीई से प्राप्त उत्तर (अप्रैल 2024) पर अध्याय में विचार किया गया है।

छठवाँ अध्याय

घाटे में चल रहे चयनित
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की समीक्षा

6.1 परिचय

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना के मुख्य उद्देश्यों में से एक¹⁰⁴ देश के तीव्र आर्थिक विकास और औद्योगीकरण में मदद करना और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा तैयार करना था।

हालाँकि, समय के साथ, कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम या तो रुग्ण/अव्यवहार्य हो गए या फिर व्यवहार्य बने रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

नीचे दी गई तालिका से पता चलता है कि हानि में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) की संख्या 143 से 177 के बीच थी एवं 2017-18 से 2021-22 के दौरान उन्हें ₹31,347 करोड़ से ₹56,294 करोड़ के बीच घाटा हुआ। इस प्रकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) ने 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान ₹2,03,709 करोड़ की हानि उठाई।

तालिका 6.1: घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई)

वर्ष	घाटे में चल रहे सीपीएसई की कुल संख्या	हुई हानियाँ (₹ करोड़ में)	निवल संपत्ति (₹ करोड़ में)
2017-18	143	40,769	1,54,807
2018-19	145	40,744	1,04,876
2019-20	177	56,294	2,37,288
2020-21	168	34,555	1,10,534
2021-22	170	31,347	79,121

¹⁰⁴ जैसा कि औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 में कहा गया है।

6.2 अशक्त/घाटे वाली सीपीएसई को समयबद्ध तरीके से बंद करने के लिए दिशानिर्देश

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने अशक्त/घाटे में चल रहे सीपीएसई को समयबद्ध तरीके से बंद करने तथा चल और अचल संपत्तियों के निपटान के लिए संशोधित दिशानिर्देश (जून 2018) जारी किए। ये दिशानिर्देश सभी बीमार/घाटे में चल रहे सीपीएसई पर लागू थे, जहां (ए) प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए)/कैबिनेट से बंद करने के लिए अनुमोदन/सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त किया गया है; या (बी) प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा सीपीएसई को बंद करने का निर्णय लेने के बाद सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है।

जून 2018 के संशोधित दिशानिर्देश निम्नलिखित हैं:

- सीपीएसई को बंद करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के निर्णय की तारीख से तीन महीने का समय, सांविधिक बकाए का आकलन, कर्मचारियों के बकाए का आकलन, अचल संपत्ति/भूमि से संबंधित जानकारी को भूमि प्रबंधन पोर्टल वेबसाइट पर डालने आदि जैसी गतिविधियों के लिए दिया गया है।
- मंत्रिमंडल/सीसीईए द्वारा रुग्ण/घाटे में चल रहे सीपीएसई को बंद करने के अनुमोदन के विवरण जारी होने की तारीख से 13 महीने का समय, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों को बंद करने के बारे में सूचित करने के लिए सामान्य नोटिस, सीपीएसई का नाम हटाने के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन आदि जैसी गतिविधियों के लिए दिया जाता है।

6.3 घाटे में चल रहे चयनित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) की समीक्षा

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए, लेखापरीक्षा ने छह सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) की स्थिति की समीक्षा की है, अर्थात् सेतुसमुद्रम निगम लिमिटेड (बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय), राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड (वस्त्र मंत्रालय), हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (रसायन और उर्वरक मंत्रालय), पीईसी लिमिटेड (पूर्व में- प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड¹⁰⁵) (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय), हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (भारी उद्योग मंत्रालय) और एचएमटी मशीन टूल्स

¹⁰⁵ वर्ष 1997 में कंपनी का नाम बदलकर पीईसी लिमिटेड कर दिया गया।

लिमिटेड, बेंगलुरु (भारी उद्योग मंत्रालय)। समीक्षाधीन छह सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में से तीन सीपीएसई को अभी तक विनिवेश के लिए संदर्भित किया जाना है तथा अन्य तीन को विनिवेश के लिए संबंधित मंत्रालय को संदर्भित किया गया है। इसलिए, घाटे में चल रहे चयनित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) पर यह अध्याय दो भागों में विभाजित है।

क) विनिवेश के लिए संदर्भित हानि उठाने वाली सीपीएसई

6.4 सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

6.4.1 परिचय

सेतुसमुद्रम शिपिंग चैनल परियोजना में भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों और अन्य देशों के बीच चलने वाले जहाजों के लिए यात्रा समय और परिचालन लागत में कमी की परिकल्पना की गई थी क्योंकि पाक जलडमरूमध्य क्षेत्र में उथले पानी की मौजूदगी के कारण जहाज श्रीलंकाई तट का चक्कर लगाते हैं। भारत सरकार (जीओआई) ने सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एससीएल) नामक एक विशेष प्रयोजन माध्यम संस्था के गठन को मंजूरी दी (सितंबर 2004) तथा इसे एक कंपनी के रूप में निगमित किया गया (दिसंबर 2004)। परियोजना स्थल के सबसे निकटतम प्रमुख बंदरगाह होने के कारण वीओ चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी (पूर्ववर्ती वीओ चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट) को परियोजना-पूर्व गतिविधियों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया था।

भारत सरकार ने ₹2,427.40 करोड़ की लागत से परियोजना को मंजूरी दी थी, जिसे 1.5:1 के ऋण इक्विटी अनुपात पर संरचित किया जाना था। इक्विटी हिस्सा ₹970.96 करोड़ का था और ₹1,456.44 करोड़ के लिए घरेलू और विदेशी ऋण जुटाए जाने थे। घरेलू और विदेशी ऋण के माध्यम से परियोजना वित्त पोषण को पूरा करने के एससीएल के प्रयास परियोजना निष्पादन अर्थात् निविदा करना, परियोजना के अनुबंधों का प्रदान किया जाना एवं सरकारी गारंटी प्राप्त करना, में विलंब के कारण सफल नहीं हुए। 31 मार्च 2022 तक शेयरधारिता का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

तालिका 6.2: 31 मार्च 202 तक शेयरधारिता

शेयरधारक का नाम	धारित शेयर पूंजी (₹ करोड़ में)	धारिता का प्रतिशत
भारत सरकार	495.00	66.43
वीओ चिदंबरनार बंदरगाह प्राधिकरण	50.00	6.71
शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	50.00	6.71
अन्य : ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी, कामराजर पोर्ट लिमिटेड (पूर्ववर्ती एन्नोर पोर्ट लिमिटेड), विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी	150.00 (प्रत्येक को ₹30 करोड़)	20.15
कुल	745.00	100.00

6.4.2 निकर्षण गतिविधि

मंत्रालय ने नामांकन के आधार पर परियोजना के लिए आवश्यक संपूर्ण निकर्षण कार्य ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को सौंप दिया। जुलाई 2005 में पाक जलडमरूमध्य क्षेत्र में निकर्षण कार्य प्रारम्भ हुआ।

सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के कारण सितंबर 2007 से निकर्षण कार्य को रोक दिया गया था। केंद्र सरकार के विरुद्ध दायर पर्यावरण मंजूरी, प्राचीन स्मारकों और पुरातत्व स्थल से संबंधित कुछ कानूनी मामलों में एससीएल प्रतिवादी भी था। सभी कानूनी मामलों की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में एक ही मामले के रूप में की जा रही थी। इस मामले की आखिरी सुनवाई दिसंबर 2023 में हुई थी और यह अब तक (सितंबर 2024) लंबित है।

6.4.3 कंपनी की वित्तीय स्थिति

एससीएल का 31 मार्च, 2022 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय आंकड़ा नीचे दी गई तालिका में दिया गया है :

तालिका 6.3: 2017-18 से 2021-22 तक का वित्तीय आंकड़ा

(₹ करोड़ में)

विवरण/वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
इक्विटी शेयर पूंजी	745.00	745.00	745.00	745.00	745.00
पूंजीगत निकर्षण के लिए प्रावधान	47.69	133.89	95.34	85.72	65.72
प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	708.58	868.25	868.25	868.25	868.25
व्यापार प्राप्तियां	8.42	8.03	7.90	7.90	7.89
नकद और नकदी समकक्ष	66.68	70.45	31.74	23.20	3.68
परिचालन से राजस्व	-	-	-	-	-
अन्य आय	5.26	4.56	3.27	1.79	0.65
कर्मचारी हितलाभ व्यय	0.25	0.27	0.28	0.25	0.24
अन्य व्यय (किराया)	0.21	0.25	0.22	0.21	0.41
कर पश्चात लाभ/(हानि)	1.88	2.41	1.65	0.81	(0.10)

उपरोक्त तालिका में निम्नलिखित को दर्शाया गया है:

- एससीएल ने 31 मार्च, 2022 तक अपने खातों में पूंजीगत निकर्षण¹⁰⁶ और अन्य प्रगतिरत पूंजीगत कार्य के लिए 868.25 करोड़ रुपये की राशि को पूंजीगत प्रगतिरत कार्य के रूप में लेखांकित किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और अदालत में लंबित मामलों के कारण निकर्षण का काम नहीं किया जा सका इसलिए निकर्षित क्षेत्र गाद¹⁰⁷ के अधीन था जिससे संपत्ति की काफी क्षति हुई। एससीएल ने गाद के कारण होने वाले नुकसान का आकलन नहीं किया (मार्च 2022)।
- वेतन, प्रशासनिक व्यय और किराये जैसे अनुत्पादक व्यय होने के बावजूद अप्रयुक्त निधि की सावधि जमा से अर्जित ब्याज के रूप में अन्य आय के कारण एससीएल को 2017-21 के दौरान कोई हानि नहीं हुई।

¹⁰⁶ पूंजीगत निकर्षण से तात्पर्य है रखरखाव निकर्षण के विपरीत नई निकर्षण।

¹⁰⁷ पानी के नीचे की धाराओं और लहरों की गति के कारण ड्रेज किए गए क्षेत्र में रेत और गाद का रिसाव।

मंत्रालय द्वारा अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, संयुक्त सचिव (बंदरगाह) और विकास सलाहकार (बंदरगाह) की एक समिति गठित की गई जिसने ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को देय एससीएल की बकाया देनदारियों को अंतिम रूप दिया (फरवरी 2019) जो ₹136.72 करोड़ थी। जिसमें से, एससीएल ने उपलब्ध निधियों से ₹71 करोड़ की राशि का भुगतान (2019-2022) किया। एससीएल ने ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को अपने लंबित बकाये का भुगतान करने के लिए मंत्रालय से ₹115.72 करोड़ का अनुदान मांगा (मई 2019)।

6.4.4 परियोजना की वर्तमान स्थिति

एससीएल अपने अस्तित्व में आने के 19 साल बाद (सितंबर 2024) भी वाणिज्यिक परिचालन शुरू नहीं कर सका। विभिन्न मुकदमों के कारण सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर (सितंबर 2007) पूंजीगत निकर्षण का कार्य निलंबित कर दिया गया था। एससीएल ने 2009 से 2022 तक स्थापना और प्रशासनिक व्यय के लिए ₹21.55 करोड़ खर्च किए। एससीएल ने 2010 से 2019 के बीच परिचालन गतिविधियों की समाप्ति के कारण विभिन्न परिचालन परिसंपत्तियों जैसे कि लान्चस, बायस को ₹28.91 करोड़ में बेचा और ₹21.02 करोड़ प्राप्त किए/वसूली की। एससीएल ने परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए अन्य बंदरगाह प्राधिकरणों से प्राप्त होने वाली शेष राशि ₹7.89 करोड़ को लेखांकित किया।

मंत्रालय ने एससीएल को समापन प्रक्रिया के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न कदमों पर कानूनी राय/सलाह प्राप्त करने का निर्देश दिया (जून 2019)। एससीएल के बोर्ड ने मंत्रालय को एससीएल के समापन का प्रस्ताव भेजने के लिए अनुमोदन प्रदान किया (जून 2019)। एससीएल के बोर्ड द्वारा यह भी निर्णय लिया गया (जून 2019) कि कॉर्पोरेट कार्यालय चेन्नई और परियोजना कार्यालय रामेश्वरम में चल संपत्तियों को क्रमशः चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट और वीओ चिदंबरनार पोर्ट प्राधिकरण को उनके उपयोग या निपटान के लिए पुस्तक मूल्य पर हस्तांतरित किया जाए और परियोजना कार्यालय रामेश्वरम को बंद कर दिया जाए। समापन का प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा गया (अगस्त 2019)। अपर सॉलिसिटर जनरल ने भी अन्य शर्तों के अधीन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा¹⁰⁸ 272 के अंतर्गत

¹⁰⁸ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 272 में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण द्वारा किसी कंपनी के समापन के लिए याचिका प्रस्तुत करने के प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।

एससीएल को समापन करने से पहले अपनाए जाने वाले कदम/प्रक्रिया पर अपनी राय दी (दिसंबर 2019)।

इसके बाद, मंत्रालय ने एससीएल को छह महीने के भीतर कंपनी को बंद करने के लिए गतिविधियों को पूरा करने के लिए एक समयसीमा तैयार करने का निर्देश दिया (जून 2021) जिस पर एससीएल ने अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत की (जुलाई 2021)। एससीएल का समापन अभी पूरा होना बाकी है (सितंबर 2024)। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित विभिन्न मुकदमे एससीएल को बंद करने में बाधा थे। मंत्रालय ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2024) में कहा कि एससीएल को बंद करने पर कैबिनेट नोट अगस्त 2022 में विचार के लिए कैबिनेट सचिवालय को भेजा गया था, जिस पर कैबिनेट सचिवालय ने सूचित किया (अक्टूबर 2024) कि कैबिनेट नोट अब कैबिनेट सचिवालय के विचाराधीन नहीं है। मंत्रालय की ओर से यह भी बताया गया कि रामेश्वरम में एससीएल परियोजना कार्यालय 12 अप्रैल, 2024 को बंद कर दिया गया था।

अनुशंसा संख्या 1:

पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय एससीएल को बंद करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

6.5 हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड

6.5.1 परिचय

हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचईसी), रांची की स्थापना दिसंबर 1958 में भारी उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में की गई थी, जिसका प्राथमिक उद्देश्य इस्पात, खनन, रेलवे, बिजली, रक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान, परमाणु और रणनीतिक क्षेत्रों के लिए उपकरणों और मशीनरी के डिजाइन और निर्माण में स्वपर्याप्तता और आत्मनिर्भरता हासिल करना था। कंपनी की तीन परिचालन इकाइयाँ थीं, अर्थात् हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, हैवी मशीन टूल्स प्लांट और फाउंड्री फोर्ज प्लांट। बिहार सरकार ने 1958-59 के दौरान फैक्ट्री, टाउनशिप और अन्य संबद्ध उद्देश्यों के लिए एचईसी को 7,199.51 एकड़ भूमि आवंटित की थी। कंपनी ने केवल 35.69 प्रतिशत भूमि (फैक्ट्री के लिए 729.27 एकड़ और टाउनशिप के लिए 1,839.88 एकड़) का उपयोग किया। 31 मार्च 2022 तक

48.19 प्रतिशत भूमि (3,469.61 एकड़) अन्य एजेंसियों¹⁰⁹ को हस्तांतरित की गई थी और 16.12 प्रतिशत भूमि (1,160.75 एकड़) खाली थी, जिसमें अतिक्रमण¹¹⁰ के अंतर्गत 73.05 एकड़ भूमि शामिल थी।

6.5.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

6.5.2.1 सरकार से प्राप्त पुनरुद्धार पैकेज और वित्तीय सहायता

लंबे समय तक घाटे में रहने और भारी ऋणात्मक निवल संपत्ति के कारण, एचईसी को अशक्त घोषित कर दिया गया और फरवरी 1992 में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) को संदर्भित किया गया, जिसने अगस्त 1996 में पुनर्वास पैकेज को मंजूरी प्रदान की। हालांकि पैकेज विफल रहा और औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) ने कंपनी को बंद करने का कार्यादेश दिया (06 जुलाई, 2004)। झारखंड उच्च न्यायालय ने बंद करने की कार्यवाही को रद्द कर दिया और भारत सरकार, झारखंड सरकार, एचईसी और अन्य संबंधित पक्षों को पुनरुद्धार पैकेज के अनुसार कार्य करने का निर्देश दिया (नवंबर 2009)।

भारत सरकार ने 1995-96 से 2002-03 के दौरान कंपनी को वित्तीय सहायता प्रदान की। इसके पश्चात 2005 और 2008 में पुनरुद्धार पैकेज प्रदान किए गए। लेखापरीक्षा ने पाया कि पुनरुद्धार पैकेज मुख्य रूप से वित्तीय पुनर्गठन जैसे ऋण और ब्याज की छूट, ऋणों को इक्विटी में परिवर्तित करना और बकाया राशि का निपटान करने के लिए थे और संयंत्र सुविधाओं के आधुनिकीकरण की ओर ध्यान नहीं दिया गया। निधि का बड़ा हिस्सा ऋणों के पुनर्भुगतान और कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं में उपयोग किया गया और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) के लिए निधि को चिन्हित नहीं किया गया। परिणामस्वरूप,

¹⁰⁹ भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पुनरुद्धार पैकेज (सितंबर 2008) और कैबिनेट की मंजूरी (मार्च 2017) के अनुसार 984.82 करोड़ रुपये की नकदी के एवज में 2,998.30 एकड़ भूमि झारखंड सरकार को हस्तांतरित की गई थी। बकाया राशि के परिसमापन के लिए 158 एकड़ जमीन सीआईएसएफ को हस्तांतरित की गई। संसाधन जुटाने के लिए 313.31 एकड़ भूमि सेल / लौह एवं इस्पात अनुसंधान एवं विकास केंद्र, राष्ट्रीय फाउंड्री एवं फोर्ज प्रौद्योगिकी संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, झारखंड राज्य क्रिकेट संघ, पेट्रोल पंप, बीएसएनएल, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को पट्टे पर दी गई/ प्रदान की गई।

¹¹⁰ 'एचईसी में टाउनशिप और भूमि प्रबंधन' पर एक ऑडिट पैरा को सीएजी ऑडिट रिपोर्ट-संघ सरकार (वाणिज्यिक) संख्या 18/ वर्ष 2020 में शामिल किया गया था और इसलिए भूमि प्रबंधन इस लेखापरीक्षा के दायरे में नहीं था।

पैकेज का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग किया जा सका। लेखापरीक्षा ने पाया कि पूंजीगत व्यय के लिए केवल ₹82.48 करोड़ का उपयोग किया गया, जिसमें से कंपनी ने ₹31.54 करोड़ मूल्य का केवल एक नया उपकरण खरीदा।

फलस्वरूप, पिछले 25 वर्षों से कई मौकों पर भारत सरकार से प्राप्त राहत और सहायता के बावजूद, कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन में पिछले वर्षों के दौरान में गिरावट आई है। एचईसी को पिछले पांच वर्षों से लगातार घाटा हो रहा है, सिवाय 2017-18 के, जब लाभ मुख्य रूप से झारखंड सरकार को अप्रयुक्त भूमि के हस्तांतरण पर प्राप्त निधि और पूंजीगत लाभ कर के लिए भारत सरकार से अनुदान प्राप्त करने के कारण हुआ था। 31 मार्च, 2022 को कंपनी का संचित घाटा (-) ₹1,528.54 करोड़ था और इसकी इक्विटी पूरी तरह खत्म हो गई थी। बार-बार घाटे के कारण कार्यशील पूंजी का संकट पैदा हो गया। इस प्रकार, ऐसे पुनरुद्धार पैकेजों का कोई दीर्घकालिक प्रभाव नहीं था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा (जुलाई 2024) कि कम्पनी ने मेकॉन द्वारा तैयार आधुनिकीकरण योजना प्रस्तुत की है।

मंत्रालय का उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि आधुनिकीकरण योजना को मंत्रालय द्वारा अभी तक मंजूरी प्रदान नहीं की गई है (जुलाई 2024)।

कंपनी के वित्तीय, उत्पादन और परिचालन निष्पादन पर अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

6.5.2.2 वित्तीय प्रदर्शन

2016-17 से 2020-21 के दौरान एचईसी का वित्तीय प्रदर्शन नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

तालिका 6.4: 2017-18 से 2021-22 तक का वित्तीय आंकड़े

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल राजस्व	कुल व्यय	लाभ/हानि (कर से पहले)	संचित हानि	निवल मूल्य	आकस्मिक देयता
2017-18	1,059.77	536.43	509.09	(597.65)	109.80	354.26
2018-19	562.42	654.80	(93.67)	(691.32)	10.38	381.28

वर्ष	कुल राजस्व	कुल व्यय	लाभ/हानि (कर से पहले)	संचित हानि	निवल मूल्य	आकस्मिक देयता
2019-20	170.85	566.33	(405.37)	(1,096.69)	(400.73)	541.68
2020-21	296.99	475.29	(175.78)	(1,272.47)	(582.25)	653.69
2021-22	283.47	539.47	(256.07)	(1,528.54)	(844.07)	677.46

- एचईसी को 2016-17 से 2021-22 के दौरान लगातार घाटा हुआ, सिवाय 2017-18 के, जब लाभ मुख्य रूप से झारखंड सरकार को अप्रयुक्त भूमि के हस्तांतरण पर प्राप्त निधि (₹559 करोड़) और पूंजीगत लाभ कर के लिए भारत सरकार से अनुदान (₹62 करोड़) प्राप्त करने के कारण हुआ था।
- 31 मार्च 2022 को कंपनी का संचित घाटा (-) ₹1,528.54 करोड़ था। 31 मार्च, 2022 को कंपनी का निवल मूल्य (-) ₹844.07 करोड़ थी। कंपनी की इक्विटी (₹606.08 करोड़) पूरी तरह खत्म हो गई थी।
- मंत्रालय ने उत्तर दिया (जुलाई 2024) कि उक्त अवधि के दौरान कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन मुख्यतः पुराने संयंत्र और मशीनरी गंभीर वित्तीय संकट तथा वर्ष 2020-21 में कोविड के प्रभाव के कारण कंपनी का प्रदर्शन खराब होता गया। हालांकि तथ्य यह है कि कोविड के बाद भी कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन में सुधार नहीं हुआ और इस अवधि के दौरान कंपनी लाभ अर्जित नहीं कर पाई। जिसके परिणामस्वरूप संचित घाटे में वृद्धि हुई और इस तरह इक्विटी पूरी तरह खत्म हो गई।

6.5.2.3 उत्पादन प्रदर्शन

- कंपनी ने भारी उद्योग मंत्रालय के साथ हर साल समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 2016-17 से 2020-21 की अवधि के लिए एचईसी का उत्पादन प्रदर्शन **अनुलग्नक-XXXV** में दिया गया है। 2016-17 से 2020-21¹¹¹ के दौरान कंपनी का उत्पादन समझौता ज्ञापन लक्ष्य का 28.30 प्रतिशत से 59.81 प्रतिशत तक रहा।
- 2016-17 से 2021-22 की अवधि के दौरान कंपनी के तीन संयंत्रों (फाउंड्री फोर्ज प्लांट, हवी मशीन टूल्स प्लांट और हवी मशीन बिल्डिंग प्लांट) से कुल उत्पादन

¹¹¹ एमओयू के प्रारूप में संशोधन के कारण 2021-22 की जानकारी उपलब्ध नहीं थी

स्थापित क्षमता का केवल 3.98 प्रतिशत और 20.06 प्रतिशत के बीच था (*अनुलग्नक-XXXVI*)।

उत्पादन में कमी और कम क्षमता उपयोग का कारण कंपनी में कार्यशील पूंजी और तरलता का अभाव, नियमित नकदी प्रवाह में कमी के कारण निधि की अत्यधिक कमी, कम दक्षता के साथ काम करने और बार बार खराब होने वाले पुराने संयंत्र और मशीनरी, प्रौद्योगिकी उन्नयन की कमी और निम्न कार्यबल उत्पादकता आदि, जैसा कि आगे के कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा (जुलाई 2024) कि डीपीई द्वारा अक्टूबर 2022 में आयोजित अंतर-मंत्रालयी समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि एचईसी का परिचालन उप-इष्टतम है/इसे बंद करने/विनिवेश के लिए समीक्षा की जा रही है, इसलिए इसे एमओयू प्रक्रिया से छूट दी जानी चाहिए। हालांकि, उत्तर में कंपनी के उत्पादन प्रदर्शन में सुधार के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में कुछ नहीं कहा गया है।

6.5.2.4 परिचालन प्रदर्शन

(i) कार्यादेशों की प्राप्ति और निष्पादन

एचईसी को मुख्य रूप से स्टील, कोयला और खनन क्षेत्र, भारतीय रेलवे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, आयुध फैक्ट्री, भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड आदि से कार्यादेशों की प्राप्ति हुई। 2016-17 से 2021-22 के दौरान, एचईसी ने अपने द्वारा पेश की गयी 1990 बोलियों में से 623 कार्यादेश (₹2,836 करोड़ मूल्य के) प्राप्त किए। लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी ने मुख्य रूप से अपनी मूल्य बोली; तकनीकी अप्रचलन; पिछले कार्यादेशों को पूरा न करने आदि के कार्यादेश खो दिए। प्राप्त कार्यादेशों में से, कंपनी इस अवधि के दौरान केवल ₹1,665 करोड़ का टर्नओवर हासिल कर सकी।

वित्तीय वर्ष के अंत में प्राप्त, निष्पादित तथा लंबित कार्यादेशों का मूल्य *अनुलग्नक-XXXVII* में दर्शाया गया है। 2016-17 से 2021-22 की अवधि के दौरान निर्धारित समय के भीतर तथा निर्धारित समय से परे प्राप्त, निष्पादित कार्यादेशों का विवरण *अनुलग्नक-XXXVIII* में दिया गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2016-17 से 2021-22 की अवधि के दौरान 12.51 प्रतिशत और 81.44 प्रतिशत मामलों में कंपनी समय के भीतर कार्यादेशों को पूरा कर सकी।

2021-22 में ग्राहकों द्वारा ₹694.47 करोड़ मूल्य के कार्यादेश रद्द/वापस ले लिए गए और 31 मार्च 2022 तक बकाया कार्यादेश बुकिंग ₹1,451.40 करोड़ थी।

कार्यादेशों के निष्पादन में विलंब के कारण ग्राहकों द्वारा परिसमाप्त हर्जाना लगाया गया और इस पर 2016-17 से 2021-22 के दौरान लाभ और हानि खाते में ₹107.94 करोड़ का भार डाला गया।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा (जुलाई 2024) कि अपने बहुमूल्य योगदान के बावजूद, कम क्षमता उपयोग और कार्यशील पूंजी की कमी के कारण कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था। इसने आगे कहा कि कम्पनी द्वारा कार्यादेश बुकिंग की बढ़ोतरी के लिए भरसक प्रयास किये जा रहे हैं तथा वर्तमान व्यावसायिक क्षेत्र के अलावा नए क्षेत्रों में भी व्यवसाय को देखा जा रहा है। हालाँकि, कार्यशील पूंजी की कमी के कारण कार्यादेशों को बिक्री में बदलना बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान लंबित कार्यादेशों का संचयी मूल्य उच्च स्तर पर था।

(ii) ऋणात्मक मार्जिन¹¹² पर बेची गई सामग्री

लेखापरीक्षा ने पाया कि एचईसी के पास कोई दस्तावेजी मूल्य निर्धारण नीति नहीं थी। ग्राहकों को दिए जाने वाले उत्पादों/सेवाओं का मूल्य अनुमान कच्चे माल की लागत, प्रसंस्करण लागत, खरीदी गई वस्तुओं, निर्माण, कमीशनिंग, लाभ मार्जिन और ऐसे उत्पाद के लिए परिकल्पित अन्य प्रासंगिक लागतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता था।

2016-17 से 2019-20 की अवधि के लिए (वर्ष 2020-21 के लिए लागत लेखापरीक्षा नहीं की गई थी), शुद्ध बिक्री प्राप्ति¹¹³ के आँकड़ों और उत्पादन लागत के विश्लेषण से निम्नलिखित बातें सामने आईं:

- 2016-17 से 2018-19 के दौरान हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट के मामले में उत्पादन लागत पर शुद्ध बिक्री प्राप्ति का मार्जिन धनात्मक था; हालाँकि, 2019-20 में यह ऋणात्मक हो गया। 2016-17 से 2020-21 के दौरान ₹1,035.81 करोड़ मूल्य के

¹¹² मार्जिन उत्पादन लागत पर शुद्ध बिक्री प्राप्ति का आधिक्य है।

¹¹³ शुद्ध बिक्री प्राप्ति, करों और शुल्कों को घटाकर प्राप्त बिक्री आय है।

निष्पादित की गयी 584 कार्यादेशों में से 82 विक्रय कार्यादेशों के मामले में कम्पनी ₹31.32 करोड़ (14.04 प्रतिशत) का मूल लागत¹¹⁴ भी वसूल नहीं कर सकी। इसके अलावा, कंपनी 29 कार्यादेशों (4.97 प्रतिशत) के मामले में इनपुट सामग्री लागत भी वसूल नहीं कर सकी।

- फाउंड्री फोर्ज प्लांट में उत्पादन लागत पर शुद्ध बिक्री प्राप्ति का मार्जिन 2016-17 से 2019-20 तक सभी चार वर्षों के दौरान ऋणात्मक रहा। 2017-18 से 2020-21 (2016-17 के लिए लागत डेटा उपलब्ध नहीं था) की अवधि के दौरान फाउंड्री फोर्ज प्लांट द्वारा निष्पादित ₹116.74 करोड़ मूल्य के 64 विक्रय कार्यादेशों में से कंपनी 49 बिक्री कार्यादेशों (76.56 प्रतिशत) में ₹45.49 करोड़ की मूल लागत वसूल नहीं कर सकी।
- हेवी मशीन टूल्स प्लांट में उत्पादन लागत पर शुद्ध बिक्री प्राप्ति का मार्जिन 2016-17 और 2018-19 में धनात्मक था और 2017-18 और 2019-20 में ऋणात्मक था। 2016-2021 के दौरान हेवी मशीन टूल्स प्लांट द्वारा निष्पादित ₹36.69 करोड़ मूल्य के 85 कार्यादेशों में से, कंपनी 10 ऑर्डर (11.76 प्रतिशत) में ₹2.15 करोड़ की मूल लागत भी वसूल नहीं कर सकी।
- परियोजना प्रभाग के मामले में, वर्ष 2016-17, 2018-19 और 2019-20 के दौरान उत्पादन लागत पर शुद्ध बिक्री प्राप्ति का मार्जिन ऋणात्मक था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्य निष्पादन के बाद ऋणात्मक मार्जिन के कारणों का विश्लेषण नहीं किया गया था और अभिलेखों में औचित्य भी नहीं पाया गया था। त्रुटिपूर्ण मूल्य आकलन के कारण ऋणात्मक मार्जिन वाले कार्यों के निष्पादन ने कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

उत्तर में, प्रबंधन ने उत्पादन की उच्च लागत के लिए स्थापित क्षमता का कम उपयोग, फाउंड्री फोर्ज प्लांट में कम उत्पादकता, मशीनों की उपलब्धता और दक्षता में कमी, मशीनों में निम्न सटीकता और हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट में निष्पादन चक्र में वृद्धि के कारण ओवरहेड लागत में वृद्धि जैसे कारणों का हवाला दिया (मार्च 2022)।

¹¹⁴ मूल लागत उत्पादन की कुल प्रत्यक्ष लागत है, जिसमें कच्चा माल और श्रम शामिल है।

प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि कई मामलों में प्रबंधन मूल लागत या सामग्री लागत भी वसूल नहीं कर पाया, जिससे उत्पादों के लागत अनुमान में विसंगतियां उजागर हुईं। इसके अलावा, प्रबंधन के उत्तर में ऋणात्मक मार्जिन के कारणों का विश्लेषण नहीं किये जाने के विषय में कुछ नहीं कहा गया।

मंत्रालय ने उत्तर (जुलाई 2024) में कहा कि लंबे समय से लंबित कार्यादेशों के निष्पादन में विलंब, निधि की कमी के कारण इनपुट सामग्री की खरीद में विलंब, संशोधित दर के कारण इनपुट सामग्री की खरीद में विलंब, संशोधित दर के कारण बिजली की कीमत में वृद्धि तथा भुगतान नहीं किये जाने पर विलंबित भुगतान अधिभार ऋणात्मक योगदान के कारण थे। इसने आगे कहा कि कोविड महामारी लॉकडाउन की स्थिति के कारण उत्पादन और उत्पादकता बुरी तरह से बाधित हुई।

मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि एचईसी कोविड से पूर्व अर्थात् 2016-17 से 2019-20 की अवधि के दौरान मूल लागत या सामग्री लागत भी वसूल नहीं कर पाया था।

6.5.2.5 कार्यशील पूंजी, संयंत्र और मशीनरी की पर्याप्तता

(i) कार्यशील पूंजी

एचईसी में 2016-17 से 2021-22 के दौरान कार्यशील पूंजी¹¹⁵ आवश्यकता से कम थी (अनुलग्नक-XXXIX)। 2016-2022 के दौरान कार्यशील पूंजी 2017-18 में (-) ₹67.40 करोड़ और 2021-22 में (-) ₹937.69 करोड़ के बीच थी। ऋणात्मक कार्यशील पूंजी के कारण इनपुट की खरीद में विलंब, महत्वपूर्ण व्यय में कटौती, कर्मचारियों को वेतन और मजदूरी के भुगतान में विलंब और विविध लेनदारों की बढ़ोतरी हो गयी। अपने अल्पकालिक दायित्वों का भुगतान करने के लिए फर्म के पास पर्याप्त तरल संपत्ति न होने के कारण, यह स्थिति ऋणदाताओं और लेनदारों के लिए चिंता का कारण हो सकती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, मधुबंद कोल वाशरी (भारत कोकिंग कोल लिमिटेड) और आकांक्षा (न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाएं विक्रेता भुगतान में विलंब के कारण प्रभावित हुईं।

¹¹⁵ कार्यशील पूंजी = चालू परिसंपत्तियां - चालू देयताएं।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2024) कि कंपनी की भूमि के मुद्रीकरण के माध्यम से कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के अंतर को पाटने के प्रयास किए गए थे।

मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि निगम की भूमि के मुद्रीकरण के बावजूद विक्रेताओं और लेनदारों की बड़ी देनदारियां लंबित थीं और साथ ही एचईसी अपने नियमित वेतन/मजदूरी और वैधानिक बकाया का भुगतान करने में भी सक्षम नहीं था।

(ii) संयंत्र और मशीनरी का निष्पादन

एचईसी में प्लांट और मशीनरी 50 साल से भी पहले स्थापित की गई थी और आज तक (सितंबर 2024) कुछ प्लांट और मशीनरी (2,650 टी हाइड्रोलिक प्रेस, इंडक्शन फर्नेस, पैकेज बॉयलर, फाउंड्री फोर्ज प्लांट में कंप्रेसर) को छोड़कर संसाधनों की कमी के कारण कोई महत्वपूर्ण वृद्धि/नवीनीकरण नहीं किया गया था। टूट-फूट के कारण उपकरण और मशीनरी में सटीकता की हानि, अधिक उम्र के कारण मशीनरी की मूल क्षमता में कमी, उपकरणों का निरंतर खराब होना, पुराने और अप्रचलित उपकरण/मशीनरी जो वर्तमान समय के उत्पादों की आवश्यकताओं यथा सहनशीलता, सतह की फिनिश गुणवत्ता मानदंड इत्यादि को पूरा करने में असमर्थता, इनपुट सामग्री की उपलब्धता की कमी प्लांट और मशीनरी के खराब उपयोग के मुख्य कारण थे। एचईसी ने उपकरण और मशीनरी के उपयोग के लिए कोई मानदंड तय नहीं किए थे।

मंत्रालय ने उत्तर में बताया (जुलाई 2024) कि निवारक मरम्मत और रखरखाव के लिए कार्यक्रम व्यवहार में था और कार्यबल की कमी के बावजूद जहाँ तक संभव हो इसका पालन किया जा रहा था। मंत्रालय ने यह ध्यान दिलाया कि संयंत्र और मशीनरी के प्रदर्शन के संबंध में इष्टतम स्थिति बनाए रखने में कंपनी की वित्तीय तंगी एक बड़ी बाधा है।

6.5.2.6 ग्रेच्युटी से संबंधित सरकारी ऋण की वापसी न करना

भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) ने 31 मार्च, 2011 से 31 मार्च, 2014 के दौरान सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को बकाया ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए एचईसी को ₹47.89 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया (01 अक्टूबर, 2014)। ऋण को 2015 से 2019 तक ब्याज सहित पांच बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि

वित्तीय संकट के कारण, कंपनी ने किसी भी किस्त एवं ब्याज का समय पर भुगतान नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹69.66 करोड़ (मार्च 2022) का ब्याज और दंडात्मक ब्याज का अतिरिक्त बोझ पड़ा।

मंत्रालय ने स्वीकार किया (जुलाई 2024) कि एचईसी का वित्तीय संकट जारी है और इसलिए ग्रेच्युटी के लिए ऋण की वापसी नहीं की जा सकी।

6.5.2.7 कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए सरकारी गारंटी

भारत सरकार ने मई 2007 में एचईसी को 2008-09 तक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के लिए ₹150 करोड़ की सरकारी गारंटी प्रदान की थी। मार्च 2009 में 2009-10 के लिए गारंटी को बढ़ाकर ₹253 करोड़ कर दिया गया और बाद में वैधता को 2016-17 तक बढ़ा दिया गया। एचईसी ने भारी उद्योग मंत्रालय से गारंटी की वैधता अवधि को तीन और वर्षों के लिए बढ़ाने और गारंटी को ₹253 करोड़ से बढ़ाकर ₹388 करोड़ करने का बार-बार अनुरोध किया। एचईसी ने भारतीय स्टेट बैंक से ₹388 करोड़ तक की ऋण सुविधा के लिए कार्यशील पूंजी व्यवस्था के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति जमा करने के लिए मंत्रालय के अनुमोदन का अनुरोध किया (जून 2021)। लेखापरीक्षा ने पाया कि गारंटी के विस्तार से संबंधित अनुमोदन प्राप्त होना बाकी है (मार्च 2023)।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मार्च 2022) कि बैंक ने लेटर ऑफ क्रेडिट/बैंक गारंटी शुल्क पर 50 प्रतिशत की छूट सहित सभी राहत वापस ले ली है, जिसका लाभ कंपनी सरकारी गारंटी जमा करने के बाद उठा रही थी। एसबीआई ने नकद ऋण पर ब्याज दर में भी 5 प्रतिशत की वृद्धि की है।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2024) कि उसने एचईसी को कार्यशील पूंजी व्यवस्था के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति प्रदान करके अल्पावधि वित्तपोषण की व्यवस्था करने के लिए समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सलाह दी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि भारतीय स्टेट बैंक ने ऋण सुविधाओं को ₹388 करोड़ से बढ़ाकर ₹720 करोड़ करने के एचईसी के अनुरोध पर विचार करने में असमर्थता व्यक्त की तथा एचईसी द्वारा समेकित प्रस्ताव अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया था। गारंटी अवधि की वैधता के विस्तार में विलंब तथा गारंटी राशि में वृद्धि न किया जाना प्रतिकूल कार्यशील पूंजी की स्थिति के कारणों में से एक था।

6.5.2.8 वैधानिक और कर्मचारी देयताएँ

खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए, कंपनी निम्नलिखित वैधानिक और कर्मचारी देयताओं का समय पर भुगतान करने में सक्षम नहीं थी (मार्च 2022 तक) जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है:

तालिका 6.5: भुगतान नहीं की गयी वैधानिक और कर्मचारी देय राशि

(₹ करोड़ में)

शीर्ष का विवरण	राशि
बकाया बिजली शुल्क	153.56
बकाया जल शुल्क	52.34
सीआईएसएफ बकाया	121.79
भविष्य निधि ट्रस्ट	15.80
भविष्य निधि ऋण/स्वैच्छिक भविष्य निधि सदस्यता	43.17
ग्रेच्युटी बकाया	41.48

इसके अलावा, नियमित कर्मचारियों का वेतन 14 महीने से बकाया है, जबकि गैर-नियमित कर्मचारियों को 10 महीने (मार्च 2023 तक) से भुगतान नहीं किया गया है।

मंत्रालय ने बताया (जुलाई 2024) कि कंपनी नकदी संकट से गुजर रही है; हालाँकि, पुराने देनदारों से वसूली करके धीरे-धीरे वैधानिक और कर्मचारी बकाया चुकाने के प्रयास किए जा रहे हैं। एचईसी को कार्यशील पूंजी व्यवस्था के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति प्रदान करके निधि की व्यवस्था करने की भी सलाह दी गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जैसा कि ऊपर पैरा में कहा गया है, भारतीय स्टेट बैंक ने ऋण सुविधाओं को 388 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 720 करोड़ रुपये करने के एचईसी के अनुरोध पर विचार करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी (अगस्त 2023) और एचईसी द्वारा अभी तक निधि की व्यवस्था नहीं की गई थी।

अनुशंसा संख्या 2:

भारी उद्योग मंत्रालय परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन को दृष्टिगत रखते हुए एचईसी को चालू रखने की संभावना की शीघ्र समीक्षा करे ।

6.6 पीईसी लिमिटेड

6.6.1 परिचय

पीईसी लिमिटेड (पूर्व में प्रोजेक्ट एंड इन्क्विपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड¹¹⁶) को 1971-72 में स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसटीसी) से अलग किया गया था ताकि एसटीसी के रेलवे उपकरण डिवीजन के सारिणीबद्ध व्यवसाय को संभाला जा सके, शुरू से लेकर अंत तक की (टर्न-की) परियोजनाओं में विविधता लाई जा सके, विशेष रूप से भारत के बाहर और भारतीय इंजीनियरिंग उपकरणों के निर्यात को बढ़ावा देने में सहायता की जा सके। 23 मई 1990 से पीईसी लिमिटेड तत्कालीन नवगठित होल्डिंग कंपनी अर्थात् भारत बिजनेस इंटरनेशनल लिमिटेड की सहायक कंपनी बन गई। 27 मार्च, 1991 से पीईसी लिमिटेड भारत सरकार के सीधे स्वामित्व वाली एक स्वतंत्र कंपनी बन गई। पीईसी लिमिटेड के मुख्य कार्यों में परियोजनाओं, इंजीनियरिंग उपकरणों और निर्मित वस्तुओं, रक्षा उपकरणों और स्टोर्स का निर्यात, औद्योगिक कच्चे माल, सर्राफा (बुलियन) और कृषि वस्तुओं का आयात, मौजूदा व्यापार लाइनों का समेकन और साथ ही साथ नए उत्पादों और नए बाजारों का विकास करना; गैर-इंजीनियरिंग वस्तुओं जैसे कोयला और कोक, लौह अयस्क, खाद्य तेल, स्टील स्क्रेप आदि के निर्यात में विविधीकरण; और आगे के निर्यात के लिए काउंटर ट्रेड/विशेष व्यापार व्यवस्था की संरचना करना शामिल था।

चित्र 6.1: पीईसी लिमिटेड की गतिविधियाँ



¹¹⁶ वर्ष 1997 में कंपनी का नाम बदलकर पीईसी लिमिटेड कर दिया गया।

6.6.2 वित्तीय स्थिति और कार्य परिणाम

अपने प्रशासनिक विभाग अर्थात वाणिज्य विभाग के निर्देशों के आधार पर, कंपनी ने सितंबर 2019 से अपनी व्यावसायिक गतिविधियों को बंद कर दिया। 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले पिछले छह वर्षों के लिए कंपनी के कार्य परिणाम तालिका 6.6 में दिए गए हैं।

**तालिका 6.6: 2017-18 से 2021-22 तक पीईसी लिमिटेड की
वित्तीय स्थिति और कार्य परिणाम**

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
बिक्री	4,451.92	617.87	8.03	-	-
अन्य कमाई	28.56	11.89	4.37	2.76	1.94
कुल राजस्व	4,480.48	629.76	12.40	2.76	1.94
उपभोग की गई सामग्री की लागत	4,290.01	607.75	6.45	-	-
वित्तीय लागत	73.18	143.75	116.70	114.34	309.02
अन्य व्यय	184.46	39.20	18.30	15.99	12.37
कुल व्यय	4,547.65	790.70	141.45	130.33	321.39
असाधारण वस्तुएं	10.21	(338.71)	(18.22)	(2.05)	5.16
कर पूर्व लाभ	(56.96)	(499.65)	(147.27)	(129.62)	(314.29)
कर के बाद लाभ	(56.96)	(499.65)	(147.27)	(129.62)	(314.29)
निवल मूल्य	(1,133.91)	(1,633.10)	(1,780.12)	(1,909.21)	(2,223.98)
लिया गया ऋण	944.35	1,477.70	1,594.43	1,705.34	1915.49

बैंक द्वारा ऋण सुविधाओं को वापस लेने के कारण वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी की बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में 86 प्रतिशत की गिरावट आई, जिसका कंपनी द्वारा कार्य कार्यादेशों के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। सितंबर 2019 से कंपनी द्वारा परिचालन बंद करने के कारण 2019-20 के दौरान बिक्री में लगभग 99 प्रतिशत की गिरावट आई और 2020-21 और 2021-22 के दौरान बिक्री शून्य हो गई। कंपनी के निरंतर घाटे का मुख्य कारण उच्च वित्त लागत, देनदारों से बकाया राशि की वसूली न होना और परिचालन बंद करना था।

6.6.3 कंपनी को बंद करने का निर्णय

वाणिज्य विभाग के अंतर्गत तीन लोक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसई) अर्थात एमएमटीसी लिमिटेड, एसटीसी लिमिटेड और पीईसी लिमिटेड की समीक्षा के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में 29 अगस्त, 2019 को एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान विचार-विमर्श किया गया कि पीईसी लिमिटेड की अनिश्चित वित्तीय स्थिति को देखते हुए, जिसे 2018 में ऋणदाता बैंकों द्वारा गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित किया गया था और फरवरी 2019 में इसे राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण में भी ले जाया गया था, इसके जारी रहने का कोई वैध कारण प्रतीत नहीं होता था। तदनुसार, पीईसी लिमिटेड को बंद करने के लिए कई निर्णय लिए गए। बैठक के दौरान लिए गए प्रमुख निर्णय और उन पर वाणिज्य विभाग और पीईसी लिमिटेड द्वारा की गई कार्रवाई **अनुबंध-XL** में दी गई है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वाणिज्य विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर पीईसी लिमिटेड ने सितंबर 2019 से अपना परिचालन बंद कर दिया था, लेकिन कंपनी को बंद करने के निर्णय के कार्यान्वयन की प्रगति काफी धीमी थी।

यद्यपि वाणिज्य विभाग द्वारा कंपनी को बंद करने का निर्णय अगस्त 2019 में लिया गया था, लेकिन विभाग ने कंपनी से प्रारंभिक कार्रवाई के लिए आवश्यक जानकारी नवंबर 2021 में ही मांगी। पीईसी ने प्रारंभिक कार्रवाई के अंतर्गत धन की आवश्यकता का अनुमान लगाया और बैंकों के बकाए और अन्य बकाया के निपटान के लिए ₹1,705.34 करोड़ की बजटीय सहायता मांगी (नवंबर 2021)।

इस बीच, वाणिज्य विभाग ने पीईसी को बंद करने के लिए एक कैबिनेट नोट तैयार किया और इसे 26 अक्टूबर, 2021 को कैबिनेट सचिवालय को भेज दिया। हालांकि, कैबिनेट सचिवालय ने इसे डीपीई द्वारा 13 दिसंबर, 2021 के कार्यालय ज्ञापन के अंतर्गत जारी नए दिशानिर्देशों के अनुसार संसाधित करने की सलाह के साथ वापस कर दिया।

इस संबंध में हुई प्रगति पर, वाणिज्य विभाग ने सूचित किया (अप्रैल 2022/जून 2022) कि उसने पीईसी लिमिटेड के मामले में निर्णय लेने के लिए डीपीई से संपर्क किया था। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में अधिकारियों के समूह की एक समिति गठित की गई थी और निजीकरण या बंद करने के लिए वाणिज्य विभाग

के अंतर्गत सीपीएसई की पहचान करने के लिए 04 अप्रैल, 2022 को समिति की एक बैठक हुई थी और अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया गया था कि पीईसी को ऋण शोधन क्षमता एवं दिवालियापन संहिता, 2016 के अंतर्गत बंद किया जाए। वाणिज्य विभाग ने डीपीई द्वारा मंत्रालयों/विभागों को टिप्पणियों के लिए प्रसारित सीसीईए के मसौदा नोट को अपनी मंजूरी दे दी थी (मई 2022)। सीसीईए की सैद्धांतिक मंजूरी लेने के लिए आगे की कार्यवाई डीपीई द्वारा की जानी थी।

इस प्रकार, वाणिज्य विभाग द्वारा पीईसी लिमिटेड को बंद करने के निर्णय के लगभग तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी, सीसीईए से अनुमोदन प्राप्त होना बाकी था (जून 2022)। नतीजतन, एक तरफ, सितंबर 2019 से परिचालन बंद होने के कारण कंपनी कोई राजस्व अर्जित नहीं कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ, उसे बकाया ऋणों पर भारी ब्याज बोझ के अलावा, प्रशासनिक और स्थापना लागतों के लिए खर्च करना पड़ा।

वाणिज्य विभाग ने अपने उत्तर (जून 2024) में बताया कि पीईसी लिमिटेड को शीघ्र बंद करने के मामले पर डीपीई के साथ नियमित अनुव्रती कार्यवाई की जा रही है।

अनुशंसा संख्या 3:

वाणिज्य विभाग को सार्वजनिक उद्यम विभाग के साथ समन्वय करके पीईसी लिमिटेड को बंद करने की प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए, क्योंकि विलंब से कंपनी पर ब्याज का बोझ और प्रशासनिक लागत ही बढ़ेगी।

ब) घाटे में चल रहे सीपीएसई को अभी तक विनिवेश के लिए संदर्भित नहीं किया गया

6.7 नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

6.7.1 परिचय

नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनटीसी) की स्थापना अप्रैल 1968 में तीन राष्ट्रीयकरण अधिनियमों 1974, 1986 और 1995 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित रुग्ण वस्त्र उपक्रमों के मामलों का प्रबंधन करने के लिए की गई थी। कंपनी अपनी नौ सहायक कंपनियों के माध्यम से 119 वस्त्र मिलों का प्रबंधन कर रही थी। अप्रचलित प्रौद्योगिकी, अतिरिक्त कार्यबल, खराब उत्पादकता आदि के कारण, एनटीसी की सभी नौ सहायक कंपनियों को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर)

के पास भेजा गया, जिसने 2002 से 2008 के बीच उनके लिए पुनरुद्धार योजनाओं को मंजूरी¹¹⁷ दी।

एनटीसी की 119 मिलों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

तालिका 6.7: बीआईएफआर को भेजी गई 119 मिलों की स्थिति

विवरण	मिलों की संख्या
चालू मिलें*	22
बंद मिलें	77
संयुक्त उद्यम के माध्यम से पुनरुद्धार के लिए तैयार मिलें : (5 मिलें पुनर्जीवित और 11 मिलें मध्यस्थता के अधीन)	16
पुडुचेरी सरकार को हस्तांतरित की गईं मिलें	2
मिलें, जो परिचालित नहीं हैं	2
कुल	119

* 22 प्रचालनरत मिलों के अतिरिक्त, न्यू मिनर्वा मिल, हासन, कर्नाटक (जो 01 जनवरी, 2011 को स्थापित एक नई इकाई थी) भी प्रचालनरत थी।

एनटीसी अपनी 23 चालू मिलों (*अनुलग्नक-XLI*) के माध्यम से यार्न और फैब्रिक के उत्पादन के व्यवसाय में थी, जिसमें 7.68 लाख स्पिंडल और 408 करघे थे। एनटीसी ने अपनी पांच संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनियों के माध्यम से परिधानों का निर्माण भी किया। एनटीसी के पास अपने 85 खुदरा स्टोरों के साथ पूरे देश में एक खुदरा नेटवर्क भी था। हालाँकि, कार्यशील पूंजी की कमी के कारण एनटीसी की सभी मिलों में परिचालन निलंबित कर दिया गया था (मार्च 2022)।

¹¹⁷ आठ सहायक कंपनियों के लिए पुनरुद्धार योजना 2002-03 में स्वीकृत की गई थी तथा शेष एक सहायक कंपनी के लिए पुनरुद्धार योजना 2005-06 में स्वीकृत की गई थी।

चित्र 6.2: नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड



6.7.2 परिचालन एवं वित्तीय परिणाम

2016-17 से 2021-22 की अवधि के दौरान, एनटीसी के परिचालन और वित्तीय परिणाम निम्नानुसार थे:

तालिका 6.8: 2016-17 से 2021-22 तक एनटीसी लिमिटेड के परिचालन और वित्तीय परिणाम

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22*
बिक्री (करोड़ रुपए)	1,168.49	1,066.27	1,081.85	850.42	148.15	101.40
कर पश्चात लाभ (करोड़ रुपये)	969.38	(-) 307.95	(-) 310.22	(-) 350.11	(-) 343.87	(-) 311.86
निवल संपत्ति (₹ करोड़)	2,268.11	2,041.09	1,730.87	1,380.76	1,036.89	725.03
धागे / सूत का उत्पादन (लाख किलोग्राम में)	520.02	526.18	504.09	409.41	17.83	23.81
कपड़े का उत्पादन (लाख मीटर में)	201.81	191.58	190.06	88.88	0.82	2.53

6.7.3 रणनीतिक विनिवेश के लिए एनटीसी की पहचान

वस्त्र मंत्रालय ने एनटीसी को सूचित किया (अप्रैल 2018) कि नीति आयोग ने 27 मार्च, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में रणनीतिक विनिवेश के लिए एनटीसी की अनंतिम रूप से पहचान की थी। मंत्रालय ने एनटीसी को आगे सूचित किया (दिसंबर 2018) कि विनिवेश के लिए सचिवों के कोर समूह ने 11 अक्टूबर, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में एनटीसी मिलों को दो/तीन समूहों में बांटने और सभी भूमि को एक विशेष प्रयोजन वाहन को अलग करने के लिए एक खाका तैयार करने की अनुशंसा की थी, जिसके बाद एनटीसी के रणनीतिक विनिवेश पर एक विचार किया जाएगा। एनटीसी द्वारा सितंबर 2019 में मंत्रालय को खाका प्रस्तुत किया गया था। इसके अलावा, एनटीसी ने एनटीसी की सभी अचल और चल संपत्तियों के व्यापक लेखापरीक्षा के लिए एनबीसीसी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए (दिसंबर 2019)। एनबीसीसी द्वारा प्रस्तुत मसौदा रिपोर्ट नवंबर 2022 तक एनटीसी द्वारा जांच के अधीन थी। एनटीसी द्वारा प्रदान की गई जानकारी (नवंबर 2024) के अनुसार, एनटीसी के रणनीतिक विनिवेश के संबंध में आगे कोई प्रगति नहीं हुई।

6.7.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

6.7.4.1 लाभप्रदता

2016-17 से 2021-22 तक पिछले छह वर्षों के दौरान, एनटीसी को लगातार परिचालन घाटे का सामना करना पड़ा। 2016-17 से 2019-20 की अवधि¹¹⁸ के दौरान यार्न की उत्पादन लागत और बिक्री मूल्य का वर्ष-वार विवरण नीचे दिया गया है:

¹¹⁸ वर्ष 2020-21 और 2021-22 पर विचार नहीं किया गया क्योंकि कोविड-19 महामारी और कच्चे माल की खरीद के लिए कार्यशील पूंजी की कमी के कारण सभी मिलें चालू नहीं थीं।

तालिका 6.9: यार्न की उत्पादन की औसत लागत और औसत बिक्री मूल्य

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
उत्पादन की औसत लागत (₹/किग्रा)	252.45	247.32	252.14	260.49
औसत बिक्री मूल्य (₹/किग्रा)	195.01	194.32	202.80	195.35

लेखापरीक्षा ने पाया कि यार्न की उत्पादन लागत हमेशा बिक्री मूल्य से अधिक थी। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि 2016-17 से 2019-20 तक 23 में से कम से कम 17 ऑपरेटिंग मिलों की उत्पादन लागत¹¹⁹ बजटीय उत्पादन लागत से अधिक थी।

दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान संघ (एसआईटीआरए) ने 40s काउंट¹²⁰ के धागे के लिए उत्पादन लागत के मानदंड निर्धारित किए हैं। तदनुसार, 2018-19 तक उत्पादन की कुल लागत बिक्री कारोबार का 97.5 प्रतिशत होनी चाहिए थी जिसे 2019-20 से संशोधित कर 99.7 प्रतिशत कर दिया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2016-17 से 2019-20 तक लगातार 23 में से 21 चालू मिलों के संबंध में बिक्री कारोबार के प्रतिशत के रूप में उत्पादन की लागत हमेशा एसआईटीआरए मानदंडों से अधिक थी। इन 21 चालू मिलों में उत्पादन की लागत 2016-17 से 2019-20 के दौरान एसआईटीआरए मानदंडों से 14 प्रतिशत से अधिक थी।

प्रबंधन ने कहा (जून 2022) कि एसआईटीआरए केवल गुणवत्ता, उत्पादकता और लागत विश्लेषण के लिए एक बाजार संकेतक था और यार्न के निर्माण या बिक्री में शामिल नहीं था।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि यद्यपि एसआईटीआरए यार्न के निर्माण या बिक्री में शामिल नहीं था, लेकिन यह वस्त्र उद्योग के लिए उत्पादकता और लागत विश्लेषण के लिए एक बाजार संकेतक था और इस तरह, एनटीसी को इनपुट लागत को कम करने और अपनी मिलों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए एसआईटीआरए द्वारा निर्धारित मानदंडों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा, एनटीसी

¹¹⁹ उत्पादन लागत के घटक में कच्चा माल, बिजली, वेतन एवं मजदूरी, भंडार एवं पैकिंग सामग्री, प्रशासनिक उपरिव्यय तथा ब्याज एवं मूल्यहास शामिल हैं।

¹²⁰ यार्न काउंट यार्न की मोटाई को संदर्भित करता है और प्रति इकाई लंबाई में इसके द्रव्यमान द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह एक संख्यात्मक अभिव्यक्ति है जो यार्न की सुंदरता या खुरदरापन को परिभाषित करती है।

की 23 में से कम से कम 17 ऑपरेटिंग मिलों में उत्पादन की लागत भी एनटीसी द्वारा निर्धारित उत्पादन की बजटीय लागत से अधिक थी।

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित कारकों की पहचान की जो मुख्य रूप से एनटीसी की परिचालन हानि के लिए जिम्मेदार थे।

(i) उच्च मूल्य पर कपास की खरीद

अप्रैल 2015 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) से ₹1,275.42 करोड़ मूल्य की कपास खरीदी गई। जुलाई 2016 में एनटीसी ने कच्चे माल की खरीद लागत को प्रमुख समस्या क्षेत्रों में से एक के रूप में पहचाना, जो उत्पादन लागत का 58.25 प्रतिशत था और 2018-19 तक कच्चे माल की लागत को 51 प्रतिशत तक कम करने का निर्णय लिया। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, एनटीसी ने एक कार्य योजना तैयार की, जिसमें कपास की ई-खरीद या कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (निजी पार्टियां) से कपास की खरीद शामिल थी, जो बेहतर दरों की पेशकश कर रहे थे। दिसंबर 2016 की संशोधित खरीद नीति के अनुसार केवल सीसीआई से कपास खरीदने का निर्णय लिया गया था, भले ही सीसीआई की दरें एल-1 बोलीदाता की तुलना में ₹500 अधिक हों। ऑडिट ने कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वेब पोर्टल से कपास की ऐतिहासिक कीमत की जांच की और पाया कि खुले बाजार में कपास कम कीमत पर उपलब्ध थी। इस प्रकार, एनटीसी को खुले बाजार की तुलना में सीसीआई से महंगे कपास की खरीद पर 38.48 करोड़ रुपये¹²¹ का अनावश्यक व्यय करना पड़ा।

प्रबंधन ने कहा (जून 2022) कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया केवल एक बाजार संकेतक है, और सी.सी.आई. की दरें कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की दरों के साथ तुलनीय नहीं हैं।

उत्तर को इस तथ्य पर विचार करते हुए देखा जा सकता है कि कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की दरें प्रचलित दरों (बाजार संकेतक) को दर्शाती हैं और ऐसे कई उदाहरण हैं जहां कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान की गई दरों से ₹500 प्रति कैंडी में अधिक दरों पर कपास खरीदा गया था। इसलिए, एनटीसी ने खुले बाजार में आवश्यक

¹²¹ पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय: ₹9.88 करोड़ और दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय: ₹28.60 करोड़।

गुणवत्ता वाले पास की उपलब्धता की जांच और नियत दर का पता लगाए बिना सीसीआई से कपास खरीदा।

अनुशंसा क्रमांक 4:

एनटीसी उचित/प्रतिस्पर्धी दरों पर कच्चा माल खरीदे जिससे उत्पादन लागत कम हो जाएगी।

(ii) उच्च श्रम लागत

दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान संघ (एसआईटीआरए) के अनुसार, वेतन और मजदूरी लागत मूल्य¹²², जिसे बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, 10 प्रतिशत या उससे अधिक को चिंता के साथ देखा जाना चाहिए और श्रम और मशीन की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह की योजना बनाने का आह्वान किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एनटीसी की सभी 23 प्रचालनरत मिलों में वेतन और मजदूरी लागत मूल्य 2016-17 से 2019-20 के दौरान एसआईटीआरए द्वारा सुझाई गई 10 प्रतिशत की सीमा से अधिक था। इसके अलावा, एनटीसी बंद मिलों के मामले में भी निष्क्रिय मजदूरी के भुगतान से बचने के लिए कोई ठोस निर्णय नहीं ले सका। लेखापरीक्षा में पाया गया कि एनटीसी ने मिलों¹²³ के संचालन न होने के कारण 50 प्रतिशत की दर से 6,140 श्रमिकों को निष्क्रिय मजदूरी के लिए मई 2020 से मार्च 2022 तक ₹112.75 करोड़ का भुगतान किया था। इसके अलावा, एनटीसी ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया, न ही मिलों के संचालन न होने को दृष्टिगत रखते हुए अधिशेष श्रमिकों की पुनर्नियुक्ति के संबंध में मंत्रालय को कोई प्रस्ताव भेजा। इसी तरह, 2016-17 से 2021-22 के दौरान, एनटीसी ने 49 बंद मिलों के संबंध में कर्मचारियों की लागत के रूप में ₹ 47.27 करोड़ खर्च किए।

¹²² वेतन और मजदूरी लागत मूल्य = कुल वेतन और मजदूरी लागत * 100 / कुल अनुमानित यार्न बिक्री मूल्य।

¹²³ कोविड-19 महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के कारण 25 मार्च, 2020 से सभी 23 मिलों का संचालन स्थगित कर दिया गया था। इसके अलावा, जून 2020 में, एनटीसी ने स्टॉक के 15 दिनों की आवश्यकता तक कम होने तक संचालन को स्थगित रखने का निर्णय लिया। कुछ मिलों का संचालन 28 दिसंबर, 2020 से चरणबद्ध तरीके से फिर से शुरू किया गया।

प्रबंधन ने बताया (जून 2022) कि बंद मिलों में बड़ा खर्च एनटीसी की संपत्ति की सुरक्षा और अतिक्रमण से बचाव के लिए तैनात आवश्यक कार्यबल को वेतन/मजदूरी के भुगतान के कारण हुआ। इसके अलावा, कार्यबल को यथासंभव युक्तियुक्त बनाया गया और अधिशेष कार्यबल को संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (एमवीआरएस) की पेशकश की गई।

प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि 2016-17 से 2020-21 के दौरान केवल 85 कर्मचारियों¹²⁴ ने एमवीआरएस का विकल्प चुना था। इसके अलावा, मिलों के संचालन न होने के कारण निष्क्रिय वेतन और मजदूरी लागत मूल्य को कम करने के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदमों पर कोई उत्तर नहीं दिया गया।

अनुशंसा क्रमांक 5:

एनटीसी को मिलों के अधिशेष/निष्क्रिय श्रमिकों को लाभकारी रोजगार प्रदान करने के लिए उनकी पुनर्नियुक्ति की आवश्यकता का आकलन करने की आवश्यकता है।

(iii) उच्च ऊर्जा लागत

फरवरी 2016 में एनटीसी ने 2018-19 तक बिजली और ईंधन की लागत को उत्पादन मूल्य के 10 प्रतिशत तक लाने का फैसला किया था। हालांकि, उत्पादन मूल्य के प्रतिशत के संदर्भ में एनटीसी की बिजली और ईंधन लागत 2016-17 से 2021-22 की अवधि के दौरान 19.82 प्रतिशत (2017-18) और 40.77 प्रतिशत (2021-22) के बीच रही, जो कंपनी द्वारा निर्धारित 10 प्रतिशत के लक्ष्य से काफी अधिक थी।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि वस्त्र मंत्रालय ने भारत सरकार के 'राष्ट्रीय सौर मिशन' के अंतर्गत एनटीसी को 7.37 मेगावाट की कुल क्षमता के साथ 23 ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना का लक्ष्य सौंपा था (अगस्त 2016)। तदनुसार, एनटीसी को सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा सूचीबद्ध एजेंसियों के माध्यम से रूफटॉप सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना करनी थी, जो राष्ट्रीय सौर मिशन के अनुसरण में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप योजना के अंतर्गत रूफटॉप सौर प्रतिष्ठानों के लिए नोडल एजेंसी थी।

¹²⁴ एक मिल में चार कर्मचारी (2016-17 में), पांच मिलों में 72 कर्मचारी (2017-18 में), तीन मिलों में नौ कर्मचारी (2018-19 में) तथा 2019-20 और 2020-21 में शून्य कर्मचारी

रूफटॉप सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना अक्टूबर 2018 तक पूरी होनी थी।

₹4.30 करोड़ की लागत से 0.78 मेगावाट की कुल क्षमता वाली दो रूफटॉप सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के बाद, एनटीसी ने अनुमान लगाया (दिसंबर 2016) कि ₹43 करोड़ के व्यय से 6.59 मेगावाट की शेष क्षमता स्थापित की जाएगी। एनटीसी ने पूंजीगत व्यय¹²⁵ मॉडल पर सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए ₹40 करोड़ का बजट स्वीकृत किया (जनवरी 2018), लेकिन बाद में एनटीसी की वित्तीय स्थिति को देखते हुए रेस्को¹²⁶ मॉडल को अपनाने का फैसला किया (सितंबर 2018)। हालांकि, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एनटीसी को सूचित किया (09 अक्टूबर, 2018) कि रूफटॉप सौर परियोजनाओं को पूरा करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर, 2018 थी, और इस प्रकार, नई परियोजनाएं शुरू नहीं की जा सकतीं।

इस प्रकार, एनटीसी द्वारा सौर संयंत्रों की स्थापना के तौर-तरीकों पर निर्णय लेने में विलंब के परिणामस्वरूप ऊर्जा लागत में बचत प्राप्त करने के अवसर की अपरिहार्य हानि हुई।

प्रबंधन ने बताया (जून 2022) कि ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप योजना के बंद होने के बाद, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 04 मार्च, 2020 तक सूचीबद्ध एजेंसियों की सूची जारी नहीं की थी। इसके बाद, 25 मार्च, 2020 को कोविड-19 महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के कारण सभी एनटीसी मिलों का संचालन निलंबित कर दिया गया था।

उत्तर को इस बात पर विचार करते हुए देखा जा सकता है कि योजना को अक्टूबर 2018 तक पुनर्निर्धारित किया गया था और एनटीसी के पास रूफ टॉप सौर संयंत्रों की स्थापना के बारे में निर्णय लेने के लिए पर्याप्त समय था। इसलिए, रूफ टॉप सौर संयंत्रों के तरीके (यानी, पूंजीगत या रेस्को) के बारे में निर्णय लेने में विलंब के कारण रूफ टॉप सौर संयंत्रों की स्थापना नहीं हो पाई। परिणामस्वरूप, एनटीसी ने बिजली की लागत में बचत करने का अवसर खो दिया, जिसके कारण बिजली और ईंधन एवं उत्पादन की लागत बढ़ गई।

¹²⁵ पूंजीगत मोड में, रूफटॉप प्रणाली का स्वामित्व स्वयं उपभोक्ता के पास होता है तथा वह प्रणाली की लागत वहन करता है।

¹²⁶ रेस्को मोड में, विक्रेता रूफटॉप प्रणाली की लागत वहन करता है और उपभोक्ता प्रणाली द्वारा उत्पन्न बिजली खरीदता है।

अनुशंसा क्रमांक 6:

एनटीसी बिजली की लागत कम करने के लिए कदम उठाए एवं रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने की दिशा में कार्रवाई में तेजी लाए।

(iv) मिलों के आधुनिकीकरण में विलंब

संशोधित योजना-08 (एमएस-08) के अंतर्गत, एनटीसी ने मार्च 2022 तक 23 मिलों के आधुनिकीकरण पर ₹1,542.62 करोड़ खर्च किए। 23 मिलों के आधुनिकीकरण की स्थिति और एनटीसी द्वारा वहन की गई लागत **अनुलग्नक-XLII** में दी गई है। अन्य सभी संशोधित योजनाएँ (एमडीआरएस-10, एमडीआरएस-12, एमडीआरएस-14, आधुनिकीकरण योजना-2015 और सीट्रा द्वारा 2017 का आधुनिकीकरण प्रस्ताव) एनटीसीबोर्ड द्वारा इन योजनाओं को मंजूरी न दिए जाने और एनटीसीकी विनिवेश प्रक्रिया शुरू होने के कारण लागू नहीं की जा सकीं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 31 मार्च 2022 तक एनटीसी मिलों का औसत आधुनिकीकरण प्रतिशत 41.2 प्रतिशत था। आधुनिकीकरण के मिल-वार विश्लेषण से पता चला कि सात मिलों में आधुनिकीकरण की सीमा 50 प्रतिशत या उससे अधिक, 12 मिलों में 31 प्रतिशत से 50 प्रतिशत से कम और चार मिलों में 30 प्रतिशत तक थी।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अवलोकन से सहमति जताई (जून 2022) कि आधुनिकीकरण सूचकांक कम होने के कारण उत्पादकता कम हुई। हालांकि, आधुनिकीकरण के लिए रोडमैप, यदि कोई हो, के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

(v) स्थापित क्षमता का कम उपयोग :

एनटीसी ने अपनी सभी मिलों के लिए 96 प्रतिशत क्षमता उपयोग का मानदंड तय किया था। हालांकि, 2016-17 से 2021-22 के दौरान कुल क्षमता उपयोग 90 प्रतिशत से कम रहा, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है:

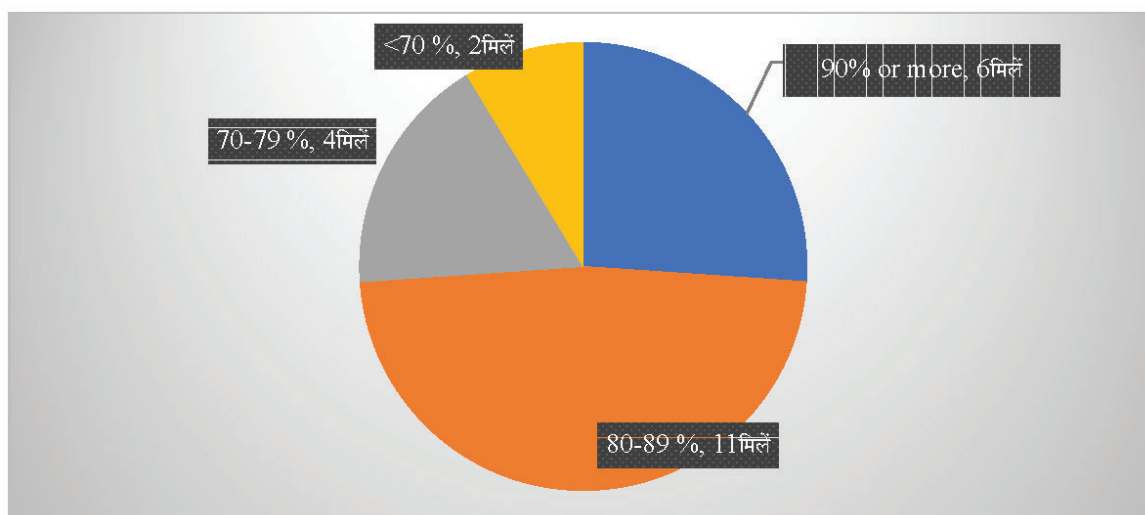
तालिका 6.10: 2016-22 की अवधि के दौरान बुनाई और कटाई की क्षमता उपयोग

(प्रतिशत में)

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कटाई	85.35	88.24	85.95	76.43	52.64	28.99
बुनाई	81.76	84.31	80.84	46.53	42.27	10.10

वर्षवार एवं मिलवार कताई का विवरण वर्ष 2016-17 से 2019-20 की अवधि¹²⁷ के दौरान कताई क्षमता उपयोग के आंकड़े *अनुलग्नक-XLIII* में दिए गए हैं। मिल-वार कताई क्षमता उपयोग का सारांश चार्ट 6.1 में दिया गया है।

चार्ट 6.1: परिचालन मिलों की औसत कताई क्षमता उपयोग



प्रबंधन ने बताया (जून 2022) कि मिलों की स्थापित क्षमता के उपयोग को बढ़ाने के लिए ग्रुप कैप्टिव पावर प्रणाली, ओपन एक्सेस प्राइवेट पावर और सौर ऊर्जा को अपनाने, नई भर्तियां, ब्रेकडाउन रखरखाव के बजाय निवारक रखरखाव, मशीनरी में उन्नयन, रात्रि दौरे, मशीन लेखापरीक्षा, श्रमिकों के साथ समझौता और स्टॉक के संचय और कार्यशील पूंजी को अवरुद्ध करने से बचने के लिए गतिविधियों में कटौती जैसे कदम उठाए गए हैं।

तथ्य यह है कि क्षमता उपयोग बेंचमार्क से नीचे रहा और वास्तव में वर्ष 2017-18 के बाद से यह और भी खराब हो गया।

6.7.4.2 वित्तीय प्रबंधन

(i) भारत सरकार को देय बकाया

वर्ष 2006-07 से 2008-09 के दौरान, भारत सरकार ने वेतन सहायता¹²⁸ के लिए एनटीसी को 14.5-15.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दरों पर ₹270 करोड़ का ऋण दिया। एक

¹²⁷ वर्ष 2020-21 और 2021-22 पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि कोविड-19 महामारी और कच्चे माल की खरीद के लिए कार्यशील पूंजी की कमी के कारण सभी मिलें चालू नहीं थीं।

¹²⁸ 2006-07 में ₹62.50 करोड़, 2007-08 में ₹62.50 करोड़ तथा 2008-09 में ₹145 करोड़।

वर्ष की स्थगन अवधि के बाद ऋण चार समान वार्षिक किस्तों में चुकाने योग्य थे। एनटीसी ने 2011 से 2014 के दौरान ऋण और उस पर ब्याज की छूट के लिए वस्त्र मंत्रालय से अनुरोध किया, जिसके उत्तर में मंत्रालय ने (जून और अगस्त 2015) एनटीसी को एक पुनर्गठन योजना प्रस्तुत करने के लिए कहा। हालाँकि, एनटीसी ने मंत्रालय को पुनर्गठन योजना प्रस्तुत नहीं की। इसलिए, 31 मार्च, 2022 तक कुल मूल ऋण ₹270 करोड़ और उस पर अर्जित ब्याज की राशि ₹631.19 करोड़ बकाया थी।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अवलोकन में उल्लिखित तथ्यों को दोहराया (जून 2022)।

अनुशंसा संख्या 7:

एनटीसी ऋण पर ब्याज के संचय से बचने के लिए यथाशीघ्र मंत्रालय को पुनर्गठन योजना प्रस्तुत करे ।

(ii) अन्य संस्थाओं से वसूल की जाने वाली बकाया राशि

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित मामले पाए गए जहां एनटीसी को अन्य संस्थाओं से अभी तक बकाया राशि प्राप्त नहीं हुई थी:

(क) ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन को दिए गए ऋण की वसूली न होना

वस्त्र मंत्रालय की सलाह पर, एनटीसी ने समझौता¹²⁹ जापन पर हस्ताक्षर करके ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन (बीआईसी) को ₹56.10 करोड़ और ₹9.91 करोड़ के ब्रिज लोन जारी किए थे। इसके बाद, एनटीसी ने (जनवरी 2014) बीआईसी को ₹4.70 करोड़ का एक और लोन जारी किया। बीआईसी ने (सितंबर 2015) बिना ब्याज के ₹9.91 करोड़ और ₹4.70 करोड़ के लोन चुकाए। हालाँकि, 31 मार्च 2022 तक ₹122.49 करोड़ (तीनों लोन पर) के बकाया ब्याज के साथ ₹56.10 करोड़ का लोन आज तक वसूल नहीं हुआ है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि भले ही ₹56.10 करोड़ का ऋण परिसंपत्तियों की पर्याप्त सुरक्षा सशर्त था, एनटीसी ने प्रतिभूति/बंधक प्राप्त किए बिना ऋण जारी कर दिया। इसके अलावा, बीआईसी की कमजोर वित्तीय स्थिति और बीआईसी से पहले से ही लंबित बकाया के बारे में पता होने के बावजूद, एनटीसी ने वेतन और मजदूरी के भुगतान के लिए बीआईसी को फिर से ₹10 करोड़ का अंतर-कॉर्पोरेट ऋण/वित्तीय सहायता जारी की (अक्टूबर 2019)।

¹²⁹ जनवरी 2012 और जून 2013.

31 मार्च, 2022 तक इस ऋण पर ₹2.86 करोड़ का ब्याज भी जमा हो गया था।

इस प्रकार 31 मार्च, 2022 तक ₹66.10 करोड़ की मूल राशि और ₹125.35 करोड़ के ब्याज सहित ₹191.45 करोड़ की धनराशि बीआईसी के पास अवरुद्ध रही।

प्रबंधन ने कहा (जून 2022) कि बीआईसी को अंतर-कॉर्पोरेट ऋण देने के प्रस्ताव पर निदेशक मंडल ने पहले ऋण में चूक और ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन की वित्तीय स्थिति को देखते हुए शुरू में सहमति नहीं दी थी। हालांकि, बीआईसी को ऋण देने के लिए वस्त्र मंत्रालय से विभिन्न पत्र प्राप्त करने के बाद बोर्ड ने अपनी 387 वीं बैठक में इसे मंजूरी दे दी। हालांकि, बीआईसी से शेष राशि की साल-दर-साल नियमित रूप से पुष्टि की गई थी।

हालांकि तथ्य यही है कि, वस्त्र मंत्रालय ने एनटीसी की कमजोर वित्तीय स्थिति के बावजूद एनटीसी को बीआईसी को ऋण देने का निर्देश दिया, जो कि विवेकपूर्ण नहीं था। इसके अलावा, 31 मार्च, 2020 के बाद बीआईसी से कोई शेष राशि की पुष्टि नहीं हुई थी।

अनुशंसा संख्या 8:

एनटीसी किसी भी ऋण को जारी करने से पहले पर्याप्त संपार्श्विक सुरक्षा लेकर और ऋण देते समय उधारकर्ता की विश्वसनीयता पर उचित विचार करके अपने हितों की रक्षा करे।

(ब) पुडुचेरी सरकार से बिक्री प्रतिफल प्राप्त न होना

एनटीसी ने पुडुचेरी में स्थित दो मिलों¹³⁰ को पुडुचेरी सरकार को सौंप दिया। उनके मध्य समझौता जापन के अनुसार, यह सहमति हुई थी कि पुडुचेरी सरकार दो मिलों के हस्तांतरण के लिए एनटीसी को ₹39.37 करोड़ की राशि का भुगतान करेगी, हालांकि, भुगतान की तारीखें निर्दिष्ट नहीं की गई थीं। 31 मार्च, 2022 तक ब्याज सहित ₹39.37 करोड़ की राशि पुडुचेरी सरकार से वसूल की जानी बाकी थी।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अवलोकन में उल्लिखित तथ्यों को दोहराया (जून 2022)। इन बकाया राशियों की वसूली के लिए उठाए गए कदमों के बारे में विशेष रूप से कोई उत्तर नहीं दिया गया।

¹³⁰ स्वदेशी कॉटन मिल्स और श्री भारती मिल्स।

6.7.4.3 परिसंपत्ति प्रबंधन

परिसंपत्तियों का इष्टतम प्रबंधन सुचारू संचालन और कुशल तरीके से तैयार उत्पादों के प्रभावी उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। लेखापरीक्षा ने परिसंपत्तियों के प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित बातें देखीं:

(i) तैयार उत्पाद, कच्चा माल और अन्य भण्डारण वस्तुओं का संचय

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 31 मार्च, 2022 तक एनटीसी के पास क्रमशः ₹8.28 करोड़¹³¹ और ₹32.29 करोड़¹³² मूल्य के धागे और कपड़े का स्टॉक एक साल से भी ज्यादा समय से पड़ा हुआ था। एनटीसी के रिकॉर्ड के अनुसार, तैयार स्टॉक का निपटान न होने का कारण बिक्री मूल्य का मौजूदा बाजार मूल्य से ज्यादा होना था। समय बीतने के साथ, धागे और कपड़े की गुणवत्ता खराब होती जाएगी और प्राप्त होने वाले मूल्य में कमी होने से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, 31 मार्च, 2022 तक मिलों में ₹8.27 करोड़ मूल्य के कपास की गांठों और पॉलिएस्टर का दो साल से भी ज्यादा पुराना स्टॉक बिना इस्तेमाल के पड़ा हुआ था। इसके अलावा, मिलों में ₹4.39 करोड़ मूल्य के स्टोर और स्पेयर (रसायन, पैकिंग सामग्री और अन्य सामान) पड़े हुए थे, जिनमें से ₹2.74 करोड़ मूल्य के स्टोर और स्पेयर तीन साल से भी ज्यादा समय से स्टॉक में थे।

प्रबंधन ने कहा (जून 2022) कि:

- एनटीसी ने साप्ताहिक आधार पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित फार्मूले के आधार पर यार्न और कपड़े की कीमतें तय कीं। इसके अलावा, पिछले दो वर्षों में महामारी की स्थिति के कारण, पूरा वस्त्र बाजार जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन एनटीसी फिर भी यार्न और कपड़े को बेचने में कामयाब रहा।
- मार्च 2020 में लॉकडाउन के बाद, एनटीसी ने संगठन की वित्तीय स्थिति और परिचालन व्यवहार्यता पर विचार करते हुए चरणबद्ध तरीके से कुछ मिलों में परिचालन फिर से शुरू किया। कुछ मिलों के परिचालन को फिर से शुरू करने के बाद, 31 मार्च, 2022 तक स्टॉक में कच्चे माल का मूल्य पिछले वर्ष की इन्वेंट्री के मूल्य की तुलना में घटकर ₹9.27 करोड़ रह गया।

¹³¹ यार्न = पश्चिमी क्षेत्र कार्यालय: ₹0.86 करोड़ और दक्षिणी क्षेत्र कार्यालय: ₹7.42 करोड़

¹³² फैब्रिक = पश्चिमी क्षेत्र कार्यालय: ₹3.60 करोड़ और दक्षिणी क्षेत्र कार्यालय: ₹28.69 करोड़

- स्टोर और स्पेयर्स की सूची का प्रबंधन और योजना संचालनरत मिलों की "तत्कालीन आवश्यकता" के अनुसार की गई थी, लेकिन कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के कारण मिलों के संचालन के निलंबन ने स्थिति को और खराब कर दिया। तीन साल से अधिक समय से स्टॉक में पड़े स्टोर और स्पेयर्स पहले नियमित उपयोग के थे, लेकिन बाजार के कार्यादेशों के अनुसार निर्मित किए जा रहे उत्पादों और उपयोग की जा रही मशीनरी की गतिशील आवश्यकताओं के कारण उनका उपयोग नहीं किया जा सका।

उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि बिक्री मूल्य एनटीसी के उत्पादन की लागत को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं थे और बाजार की कीमतों से भी अधिक थे, जिसके कारण तैयार स्टॉक जमा हो गया। एनटीसी के आंतरिक संचार ने भी उच्च बिक्री मूल्यों को तैयार स्टॉक के संचय लिए जिम्मेदार ठहराया। इस प्रकार, उत्पादन की लागत को कम करने की आवश्यकता है और कीमतें तय करते समय बाजार की कीमतों पर उचित विचार करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, तथ्य यह है कि पर्याप्त मूल्य के कच्चे माल और स्टोर और स्पेयर स्टॉक में बेकार पड़े रहे, और एनटीसी के पास इन वस्तुओं के उपयोग के लिए कोई रोडमैप नहीं था। यह एक व्यापक इन्वेंट्री प्रबंधन नीति की आवश्यकता को दर्शाता है।

अनुशंसा संख्या 9:

एनटीसी को चाहिए कि वह शीघ्रातिशीघ्र माल (कच्चा माल और तैयार माल) के निपटान के लिए एक प्रणाली विकसित करे, ताकि धन के अवरोध को दूर किया जा सके तथा मिलों के सुचारु संचालन के लिए कार्यशील पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

(ii) अप्रचलित मशीनरी का निपटान न करना

वर्ष 2009 में, एनटीसी ने स्वदेशी कॉटन मिल, इलाहाबाद में अप्रचलित मशीनरी को बेचने की कार्रवाई शुरू की। हालाँकि, 15 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी निपटान पूरा नहीं हुआ। लेखापरीक्षा ने संबंधित अभिलेखों की जाँच की और निम्नलिखित मुद्दे देखे:

- आरक्षित मूल्य से कम बोलियाँ प्राप्त होने के बाद, मई 2011 और मई 2012 में फिर से बिक्री प्रक्रिया की गई, लेकिन खराब प्रतिक्रिया के कारण यह विफल हो गई। उसके बाद, तीन साल से अधिक समय तक कोई महत्वपूर्ण कार्रवाई नहीं की गई, जब तक कि एनटीसी ने (दिसंबर 2015) उत्तर भारत वस्त्र अनुसंधान संघ और दो अन्य सरकारी अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं को अप्रचलित मशीनरी का नया मूल्यांकन नहीं सौंपा।
- इसके बाद, बोर्ड ने तीन और मिलों की पुरानी मशीनों का मूल्यांकन करने का फैसला किया (अप्रैल 2016), और चारों मिलों की पुरानी मशीनों के मूल्यांकन का काम फेरो स्कैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल) को सौंपा गया, जिसने अगस्त 2016 में अपनी रिपोर्ट पेश की। इसके बाद बोर्ड ने फैसला किया (दिसंबर 2016) कि सभी मूल्यांकनों में से सबसे अधिक को आरक्षित मूल्य माना जाएगा। हालाँकि, अगस्त 2018 तक कोई और प्रगति नहीं हुई।
- अगस्त 2018 में, एनटीसी ने अनुमान लगाया कि विभिन्न मिलों के अप्रचलित संयंत्र और मशीनरी से कुल अपेक्षित प्राप्ति मूल्य ₹30.57 करोड़ होगा। अप्रचलित मशीनरी के नए मूल्यांकन के आधार पर, बोर्ड ने 22 मिलों की अप्रचलित मशीनरी के लिए ₹11.08 करोड़ का आरक्षित मूल्य स्वीकृत किया (जनवरी 2019)। लगभग एक वर्ष बीत जाने के बाद, वस्त्र मंत्रालय ने परिसंपत्तियों के सत्यापन के लिए एनबीसीसी को नियुक्त किया (दिसंबर 2019)। इस बीच, निपटान की प्रक्रिया को अगले कार्यादेश तक स्थगित रखा गया।
- दो साल से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद, अप्रचलित संपत्तियों के नए मूल्यांकन को मंजूरी दी गई (अप्रैल 2022) क्योंकि कुछ संपत्तियाँ पहले एनबीसीसी द्वारा कवर नहीं की गई थीं। जून 2022 में, बोर्ड ने फैसला किया कि अप्रचलित मशीनरी की पहचान करने के लिए एक तकनीकी सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। तदनुसार, एनटीसी द्वारा एक समिति का गठन किया गया जिसने अप्रैल 2023 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट को अभी भी अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत किया जाना था।

इस प्रकार, वर्ष 2009 में प्रक्रिया शुरू होने के बाद से 15 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अप्रचलित मशीनरी का निपटान पूरा नहीं हो पाया। लंबी अवधि के कई अंतरालों तक एनटीसी ने इन अप्रचलित मशीनरी के निपटान के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण परिसंपत्तियों का नए सिरे से मूल्यांकन करना पड़ा तथा अतिरिक्त

विलंब हुआ। परिणामस्वरूप, 2018 में एनटीसी के अनुमान के अनुसार ₹30.57 करोड़ का संभावित राजस्व प्राप्त नहीं हो सका। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि एनटीसी ने इन परिसंपत्तियों के बार-बार मूल्यांकन पर ₹16.43 लाख¹³³ का निष्फल व्यय किया था।

अपने उत्तर (जून 2022) में, प्रबंधन ने तथ्यों को दोहराया और कहा कि एनटीसी बिक्री प्रक्रिया को ऑनलाइन निष्पादित करता था, जिसमें मूल्यांकन छह महीने से अधिक पुराना नहीं होता था और चूंकि पुरानी और अप्रचलित मशीनरी की बिक्री का निर्णय प्रत्येक अवसर पर छह महीने के भीतर नहीं हो सकता था, इसलिए समय-समय पर मूल्यांकन करवाना अनिवार्य था।

उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जा सकता है कि इन अप्रचलित मशीनों का प्राप्ति योग्य मूल्य समय बीतने के साथ कम हो जाएगा, जिसके बावजूद एनटीसी ने प्रक्रिया शुरू करने के 15 वर्षों से अधिक समय बाद भी परिसंपत्तियों का निपटान पूरा नहीं किया है।

अनुशंसा संख्या 10:

एनटीसी अप्रचलित वस्तुओं के निपटान के लिए एक व्यापक नीति तैयार करे ताकि ऐसी वस्तुओं का समय पर निपटान किया जा सके एवं उनका इष्टतम मूल्य प्राप्त किया जा सके।

जुलाई 2022 में वस्त्र मंत्रालय को पैरा जारी किया गया, जिसके बाद अक्टूबर 2022, दिसंबर 2023 और जून 2024 में अनुस्मारक भेजे गए। मंत्रालय का उत्तर सितंबर 2024 तक प्रतीक्षित था।

6.8 हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड

6.8.1 परिचय

हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) को एक सरकारी कंपनी के रूप में निगमित किया गया था (12 दिसंबर, 1960) जिसका उद्देश्य रंगों, रंग-मध्यवर्ती, रबर रसायन, कीटनाशकों, दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स, लेमिनेट आदि के उत्पादन के लिए आवश्यक रसायनों / मध्यवर्ती के लिए विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करना था। कंपनी

¹³³ दक्षिणी क्षेत्र कार्यालय: ₹8.74 लाख और पश्चिमी क्षेत्र कार्यालय: ₹7.69 लाख।

ने 1970-71 में रसायनी (महाराष्ट्र) में स्थापित अपनी विनिर्माण सुविधा के माध्यम से अपना परिचालन शुरू किया। इसके बाद, कोच्चि (केरल) में स्थापित एक अन्य इकाई ने 1987-88 में उत्पादन शुरू किया। कोच्चि इकाई में वर्तमान में कंपनी की एकमात्र विनिर्माण सुविधा है, जहाँ फिनोल, एसीटोन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण किया जाता है। 31 मार्च, 2022 तक, भारत सरकार के पास 58.78 प्रतिशत (₹67.27 करोड़) हिस्सेदारी थी एवं शेष हिस्से जनता के पास थे। जनवरी 2008 में कंपनी ने 270 करोड़ रुपये (8 प्रतिशत असंचयी विमोच्य) की वरीयता शेयर पूंजी भी भारत सरकार को जारी की थी। एचओसीएल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी थी।

6.8.2 वित्तीय प्रदर्शन

क) परिचालन परिणाम और वित्तीय स्थिति

वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के लिए कंपनी के परिचालन परिणाम और वित्तीय स्थिति का विवरण क्रमशः *अनुलग्नक-XLIV* और *अनुलग्नक-XLV* में दिया गया है। इनके विश्लेषण से पता चला है कि कंपनी पूरे पाँच साल की अवधि में परिचालन घाटे में रही। इन 2017-18, 2019-20 और 2021-22 वर्षों के दौरान कंपनी को काफी घाटा हुआ। 2017-18, 2019-20 और 2021-22 और इन वर्षों के दौरान कंपनी को काफी घाटा हुआ और शेष दो वर्षों के दौरान लाभ मुख्य रूप से अन्य स्रोतों¹³⁴ से आय के कारण था (2018-19 में ₹115.71 करोड़ तथा 2020-21 में 19.27 करोड़)। इसके अभाव में, कंपनी इन दो वर्षों के दौरान भी घाटे में रही होती। हालाँकि, यह देखा जा सकता है कि 2017-18 के बाद परिचालन घाटा काफी कम हो गया। यह कंपनी के पुनर्गठन (रसायनी इकाई के बंद होने के बाद) के कारण था, जैसा कि बाद के पैराग्राफ में विस्तृत है। 2017-18 के दौरान अकेले वित्त लागत कुल व्यय का 15 प्रतिशत थी, जो 2021-22 में घटकर 11 प्रतिशत हो गई।

वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से पता चला कि 31 मार्च, 2022 तक कंपनी की निवल संपत्ति पूरी तरह से खत्म हो गई (₹(-)901.96 करोड़) और संचित घाटा ₹1,017.62 करोड़ रहा। भारत सरकार को जारी किए गए वरीयता शेयर (₹270 करोड़), भारत सरकार से ऋण (₹375.61 करोड़) और उस पर अर्जित ब्याज (₹321.68 करोड़) 31 मार्च, 2022

¹³⁴ ब्याज आय, अतिरिक्त प्रावधान रिटर्न बैंक, संपत्ति की बिक्री पर लाभ, आदि।

तक चालू देनदारियों का एक बड़ा हिस्सा थे। बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू संपत्ति (₹992.20 करोड़) कंपनी की कुल संपत्ति (₹1,454.13 करोड़) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी।

कंपनी की स्थापना के बाद से इकाईवार लाभप्रदता का सारांश 1970-71 से 1986-87, 1987-88 से 2011-12 और 2012-13 से 2018-19 की अवधि के दौरान निम्नलिखित विवरण दिया गया था:

तालिका 6.11 : कंपनी की इकाईवार लाभप्रदता का सारांश

(₹ करोड़ में)

अवधि	लाभ / नुकसान		लाभांश, रिज़र्व और अन्य समायोजन	भूमि की बिक्री से लाभ	संचित लाभ / हानि
	कोच्चि इकाई ¹³⁵	रसायनी इकाई			
1970-71 से 1986-87	-	65.20	(41.89)	-	23.31
1987-88 से 1993-94	110.48	58.73	(32.57)	-	159.95
1994-95 से 2011-12	692.46	(1,209.67)	(33.59)	-	(390.85)
2012-13 से 2018-19 ¹³⁶	(382.58)	(716.18)	(0.51)	436.65	(1,053.40)

तालिका से यह स्पष्ट है कि कोच्चि इकाई ने वर्ष¹³⁷ 2011-12 तक लगातार लाभ कमाया। हालांकि, रसायनी इकाई ने 1994-95 के बाद उच्च श्रम लागत, ब्याज की उच्च लागत, कार्यशील पूंजी की कमी के कारण संयंत्रों के बंद होने की अधिक घटनाएं, संयंत्र के ब्रेकडाउन आदि और परिणामस्वरूप कम क्षमता उपयोग जैसे कारणों से लगातार नुकसान उठाना शुरू कर दिया। रसायनी इकाई के खराब प्रदर्शन ने पूरी कंपनी के प्रदर्शन को नीचे गिरा दिया और फंड की कमी और कार्यशील पूंजी संकट पैदा कर दिया। नतीजतन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और अन्य जैसे कच्चे माल आपूर्तिकर्ताओं के बकाया के कारण कोच्चि इकाई पूरी तरह से काम नहीं कर सकी और वर्ष 2012-13 से घाटे में जाने लगी। जबकि, रसायनी इकाई को बंद करने सहित कंपनी के पुनर्गठन का प्रस्ताव वर्ष 2017 में ही तैयार किया गया था।

¹³⁵ कोच्चि इकाई ने 1987-88 में परिचालन शुरू किया।

¹³⁶ तालिका तुलना के उद्देश्य से है। चूंकि रसायनी इकाई 2018-19 में बंद हो गई थी, इसलिए 2018-19 तक इकाई-वार लाभप्रदता तैयार की गई है।

¹³⁷ 2001-02 को छोड़कर।

6.8.3 कंपनी का पुनर्गठन

डीपीई द्वारा जारी किए दिशा निर्देश के पैरा नं. 4.5.2 (d) अनुसार रुग्ण/प्रारंभिकरुग्ण और कमजोर सीपीएसई के पुनरुद्धार और पुनर्गठन के लिए तंत्र को सुव्यवस्थित करने" के लिए रुग्ण सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ (पीएसयू)¹³⁸ जो रणनीतिक, राष्ट्रीय / रक्षा हितों के लिए उपयोगी नहीं थीं, को ध्यान में रखते हुए अ-प्राथमिकता वाली सीपीएसई की श्रेणी में रखा जाना था और अल्पावधि या मध्यम अवधि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए एक व्यवहार्य व्यवसाय योजना बनाई जानी थी। योजना को प्रदर्शन दक्षता बेंचमार्क, आर्थिक संचालन के व्यवहार्य पैमाने और प्रौद्योगिकी अपनाने / उन्नयन के लिए रोड मैप पर आधारित होना था और इसे वांछित बाजार हिस्सेदारी के समर्थन वाला होना चाहिए। उनके संबंध में व्यवसाय योजना में अंतर्निहित धारणाएँ कारोबारी माहौल, आर्थिक व्यवहार्यता और वित्तपोषण की व्यवस्था बाजार में मान्य और विश्वसनीय रूप से स्थापित होना चाहिए। दिशा-निर्देशों में यह भी सुझाव दिया गया है कि प्रशासनिक मंत्रालय / विभाग ऐसे व्यवसाय, परिचालन और वित्तीय पुनर्गठन योजनाओं को तैयार करने के लिए विश्वसनीय विशेषज्ञ संगठन को शामिल कर सकते हैं ।

नीति आयोग के साथ सचिव स्तर पर हुई बैठकों¹³⁹ में लिए गए निर्णयों के आधार पर, कंपनी ने पुनर्गठन के लिए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए (01 मार्च, 2017) और रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग ने (25 मई, 2017) आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की मंजूरी से अवगत कराया कि:

- (i) रसायनी इकाई के सभी संयंत्रों का परिचालन बंद किया जाना।
- (ii) सांद्र नाइट्रिक अम्ल (सीएनए) संयंत्र / नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N_2O_4 संयंत्र को 20 एकड़ भूमि, संयंत्र और मशीनरी और संबंधित कर्मचारियों के साथ-साथ संयंत्र से जुड़ी पिछली, वर्तमान और भविष्य की देनदारियों के साथ अंतरिक्ष विभाग / भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को हस्तांतरित किया जाना।
- (iii) रसायनी में 442 एकड़ भूमि बीपीसीएल को 1.40 करोड़ रुपये प्रति एकड़ की दर से बिक्री जिसका कुल प्रतिफल 618.80 करोड़ रुपये का होगा। रसायनी में शेष ऋणभार

¹³⁸ एक पीएसयू को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है यदि इसकी निवल संपत्ति नकारात्मक है।

¹³⁹ 01 नवम्बर 2016 एवं 07 नवम्बर 2016।

मुक्त भूमि के निपटान में सुविधा के लिए नेशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन को भूमि प्रबंधन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया जाना।

- (iv) मेटल स्क्रेप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ई - नीलामी के माध्यम से सांद्र नाइट्रिक एसिड प्लांट / नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड प्लांट और रसायनी इकाई की चल संपत्तियों के अलावा संयंत्र और मशीनरी का निपटान।
- (v) रसायनी इकाई में संयंत्रों के बंद होने के कारण अधिशेष हुए कर्मचारियों (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) को वीआरएस देना, सिवाय उन कर्मचारियों के जो इसरो द्वारा अधिग्रहित किए जा रहे सांद्रित नाइट्रिक एसिड संयंत्र/नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड संयंत्र के संचालन से जुड़े हैं।

इस बीच, नीति आयोग ने विभाग द्वारा प्रस्तुत पुनरुद्धार योजना का विश्लेषण किया और सूचित किया (17 मार्च, 2017) कि एचओसीएल, कोच्चि इकाई निम्नलिखित कारणों से सार्वजनिक स्वामित्व में व्यवहार्य नहीं है :

- (i) कोच्चि इकाई में मुख्य उत्पादों के लिए बाजार में मूल्य अस्थिरता का स्तर बहुत अधिक था, जो काफी हद तक अंतरराष्ट्रीय कीमतों से निर्धारित होता था। एक पीएसयू के रूप में, इकाई के पास इसका प्रतिक्रिया देने के लिए लचीलापन नहीं था।
- (ii) नकदी संकट के इतिहास के कारण, इकाई अक्सर अपनी क्षमता से कम काम करती थी।
- (iii) निजी क्षेत्र की कम्पनियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा थी, जो दो लाख मीट्रिक टन फिनोल उत्पादन की क्षमता स्थापित करना चाहती थीं, जबकि इकाई के पास 40,000 मीट्रिक टन फिनोल उत्पादन की क्षमता थी।
- (iv) एंटी-डंपिंग शुल्क के बिना एचओसीएल, कोच्चि इकाई आयात के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ है।

नीति आयोग ने अनुशंसा की कि रसायनी इकाई में भूमि और अन्य ऋणभारमुक्त परिसंपत्तियों के निपटान की प्रक्रिया पूरी होने पर, कंपनी को रणनीतिक बिक्री के लिए रखा जा सकता है और यदि कोई खरीदार नहीं मिला, तो कंपनी को बंद करने पर विचार किया जाए।

इस संदर्भ में, लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी द्वारा प्रस्तुत पुनर्गठन प्रस्ताव

(01 मार्च, 2017) या जो मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया था (25 मई, 2017) में डीपीई दिशानिर्देश (2015) में निर्धारित किसी भी व्यवसाय योजना को शामिल नहीं किया गया था। प्रस्ताव में केवल कंपनी की घाटे में चल रही इकाई को बंद करने, संबंधित परिसंपत्तियों की बिक्री और उससे प्राप्त आय के उपयोग की परिकल्पना की गई थी। इसके अलावा, हालांकि नीति आयोग ने कोच्चि इकाई की अंतर्निहित कमियों को देखते हुए अनुशंसा की थी कि रसायनी इकाई में भूमि और अन्य ऋणभारमुक्त परिसंपत्तियों के निपटान की प्रक्रिया पूरी होने पर कंपनी को रणनीतिक बिक्री के लिए रखा जा सकता है, पुनर्गठन योजना में पुनर्गठन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कोच्चि इकाई के संबंध में किसी भी भविष्य की कार्रवाई के बारे में कुछ नहीं कहा गया।

6.8.4 पुनर्गठन योजना का कार्यान्वयन

सीसीईए द्वारा अनुमोदित पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन की समय सीमा और तरीके (*अनुलग्नक-XLVI*) के अनुसार, रसायनी इकाई में परिसंपत्तियों की संपूर्ण निपटान प्रक्रिया मई 2018 तक पूरा किया जाना था। मई 2023 तक पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन की स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

6.8.4.1 रसायनी इकाई में संयंत्र बंद करना

रसायनी इकाई के सभी संयंत्र और मशीनरी, कंसन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लांट/नाइट्रोजन टेट्राक्साइड प्लांट को छोड़कर, जो पहले से ही बंद¹⁴⁰ थे, 2017-19 के दौरान निपटा दिए गए। कंसन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लांट/नाइट्रोजन टेट्राक्साइड प्लांट को अक्टूबर 2017 में 20 एकड़ जमीन के साथ इसरो को सौंप दिया गया था। इसके अलावा, प्लांट के 150 कर्मचारियों को भी इसरो ने अपने अधीन ले लिया। शेष 366 कर्मचारियों में से 336 कर्मचारियों को वीआरएस¹⁴¹ पर कार्यमुक्त कर दिया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सितम्बर 2017 की लक्ष्य तिथि के मुकाबले फरवरी - मार्च 2018 के दौरान लगभग 94 प्रतिशत कर्मचारियों को वीआरएस पर भेज दिया गया। छह

¹⁴⁰ तीन संयंत्र मई 2013 से तथा एक जून 2016 से बंद हैं।

¹⁴¹ शेष 23 कर्मचारियों को कोच्चि इकाई और सात को कॉर्पोरेट कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया।

महीने का विलंब भूमि के निपटान में विलंब के कारण हुआ, जैसा कि अगले पैरा में चर्चा की गई है।

6.8.4.2 भूमि एवं अन्य परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण

पुनर्गठन में कंपनी के कुल भूमि क्षेत्र (1,139.35 एकड़¹⁴²) का लगभग 89 प्रतिशत और अन्य परिसंपत्तियों के कुल मूल्य का 16.3 प्रतिशत का निपटान शामिल था। स्वीकृत पुनर्गठन योजना के अनुसार, रसायनी इकाई में परिसंपत्तियों की संपूर्ण निपटान प्रक्रिया को मई 2018 तक पूरा किया जाना था। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि भूमि सहित इसकी परिसंपत्तियों के निपटान में काफी विलंब हुई, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(ए) रसायनी इकाई में भूमि का निपटान

रसायनी इकाई में उपलब्ध भूमि के क्षेत्रफल का विवरण और इसके निपटान की स्थिति *अनुलग्नक-XLVII* में दी गई है। इससे यह देखा जा सकता है कि निपटान प्रक्रिया की शुरुआत में उपलब्ध कुल 937.09 एकड़¹⁴³ बिक्री योग्य भूमि में से, कंपनी मई 2023 तक बताए गए विभिन्न कारणों से केवल 40 प्रतिशत (374.96 एकड़¹⁴⁴) भूमि का ही मुद्रीकरण कर पाई थी। यहां तक कि बीपीसीएल को बेची गई भूमि भी अतिक्रमण और उससे संबंधित विरोधों के कारण पूरी तरह से उनके द्वारा नहीं ली गई है। इस प्रकार, कंपनी द्वारा अपनी भू-संपत्ति की सुरक्षा करने में विफलता के कारण अवैध अतिक्रमण, वैकल्पिक उपयोगों के लिए कब्जा और अवैध बसावट हुई है। नतीजतन, ₹ 958.70 करोड़¹⁴⁵ की अपेक्षित धनराशि रसायनी इकाई में भूमि के मुद्रीकरण के माध्यम से अवरुद्ध रह गई।

(ब) पुनर्गठन योजना में शामिल नहीं की गई परिसंपत्तियों का निपटान

रसायनी इकाई में भूमि और चल संपत्तियों के अलावा, कंपनी ने मुंबई में स्थित अपने फ्लैट (₹ 29.48 करोड़), खारघर में 0.25 एकड़ प्लॉट भूमि (₹ 12.97 करोड़) और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से लीज पर ली गई टैंक फार्म संपत्ति (₹ 16.24 करोड़) जैसी

¹⁴² रसायनी: 1012.35 एकड़, पनवेल - आठ एकड़ और कोच्चि - 119 एकड़।

¹⁴³ $442+242+0.386+252.70=937.09$ एकड़

¹⁴⁴ भूमि रसायनी से संबंधित है जिसे बीपीसीएल को बेचा गया है, अर्थात् 289.69 एकड़ + 85.27 एकड़।

¹⁴⁵ बेची गई भूमि से, लेकिन जो बीपीसीएल द्वारा अधिग्रहित नहीं की गई- ₹465 करोड़, अतिक्रमण भूमि- ₹36.58 करोड़, सरकारी एजेंसियों द्वारा कब्जा कर ली गई - ₹50.27 करोड़, बेची जाने वाली भारमुक्त भूमि- ₹406.85 करोड़।

विभिन्न संपत्तियों का निपटान ₹ 58.69 करोड़ की कुल राशि के लिए किया। पनवेल में लगभग ₹158 करोड़¹⁴⁶ मूल्य की सात एकड़ भूमि के निपटान के प्रयासों से अभी तक अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं।

अनुशंसा संख्या 11 :

भूमि मुद्रीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता है ताकि कंपनी की वित्तीय देनदारियों को कम किया जा सके और इस प्रकार इसकी वित्तीय लागत में कमी लाई जा सके;

6.8.4.3 परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त धन का उपयोग

पुनरुद्धार प्रस्ताव (01 मार्च, 2017) में अनुमानित) ₹1,027.05 करोड़ की राशि के मुकाबले, कंपनी को परिसंपत्तियों की बिक्री से ₹635.41 करोड़ और भारत सरकार से ब्रिज लोन के रूप में ₹384.87 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। इस राशि का उपयोग वेतन और वैधानिक बकाया, लेनदारों, बांडों के पुनर्भुगतान, कॉर्पोरेट ऋण पुनर्भुगतान, एसबीआई ओवरड्राफ्ट और वीआरएस भुगतान के लिए किया गया। इस फंड प्रवाह ने कोच्चि इकाई की कार्यशील पूंजी की स्थिति में काफी सुधार किया और बाद की अवधि में इसके प्रदर्शन में सकारात्मक रूप से परिलक्षित हुआ, जैसा कि पैरा 6.8.6 में चर्चा की गई है।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि :

- रसायनी इकाई और पनवेल में निपटान हेतु लंबित भूमि का अनुमानित मूल्य (₹1,116.70 करोड़) मई 2023 के अंत में, ₹1,135.02 करोड़¹⁴⁷ के अपने सुरक्षित और असुरक्षित ऋण देयताओं को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इस प्रकार, भूमि की बिक्री को पूरा करने में विलंब के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहाँ कंपनी पुनर्गठन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी अपनी देनदारियों का निपटान करने और अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में सक्षम नहीं हो सकती है। ऐसा इस तथ्य के कारण हुआ कि बिक्री के लिए तय भूमि की कीमत स्थिर है जबकि ऋण पर ब्याज दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है।

¹⁴⁶ फरवरी 2020 में निदेशक मंडल द्वारा आरक्षित मूल्य निर्धारित किया गया।

¹⁴⁷ वरीयता शेयर पूंजी (₹270 करोड़), वरीयता शेयरों पर ब्याज (₹55.35 करोड़), भारत सरकार का ऋण (₹452.56 करोड़), भारत सरकार के ऋण पर ब्याज (₹348.61 करोड़), गारंटी शुल्क विलंबित भुगतान पर जुर्माना (₹8.50 करोड़)।

- भूमि के निपटान में विलंब के कारण, कंपनी को हर साल ब्याज व्यय वहन करना पड़ा, जो कि भारत सरकार के बकाया ऋणों पर वर्ष 2021-22 के दौरान ₹50.98 करोड़ था (ब्रिज लोन सहित ₹452.56 करोड़)। वर्ष 2021-22 तक संचित ब्याज की राशि ₹348.61 करोड़ थी।
- ऋण में से भारत सरकार से ₹384.87 करोड़ के ब्रिज लोन में से प्राप्त हुए, जिस पर ब्याज दर 11 प्रतिशत वार्षिक थी, ₹274.49 करोड़ का उपयोग बांड की पुनर्खरीद या शोधन के लिए किया गया, जिस पर 9.36 से 10.57 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर थी। वर्तमान बेंचमार्क उधार दर¹⁴⁸ की तुलना में (2022-23 में 7.75 प्रतिशत¹⁴⁹), ब्रिज लोन पर ब्याज दर अधिक है।
- भूमि के निपटान में विलंब के कारण, कंपनी वरीयता शेयर (कुल राशि ₹270 करोड़) पर ₹6.75 करोड़ प्रति वर्ष की दर से ब्याज व्यय वहन करती रही जो मोचन के लिए अतिदेय¹⁵⁰ था। वर्ष 2021-22 तक इस प्रकार जमा हुआ ब्याज ₹55.35 करोड़ हो गया।
- इसके अलावा, कंपनी को बिना बिकी संपत्ति (रसायनी इकाई में) पर ग्राम पंचायत कर और गैर - कृषि कर का भुगतान करने के लिए भी मजबूर किया गया था, भले ही उसे इससे कोई राजस्व प्राप्त नहीं हुआ। 2021-22 की अवधि के दौरान, ऐसे करों की कुल राशि ₹3.92 करोड़ थी।

अनुशंसा संख्या 12:

सरकार ब्रिज लोन पर लगाई जाने वाली दरों की समीक्षा करे।

¹⁴⁸ यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी धन आधारित उधार दर (एमसीएलआर) की औसत सीमांत लागत है। एमसीएलआर का उपयोग बैंकों द्वारा न्यूनतम ब्याज दर निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जिस पर वे उधारकर्ताओं को पैसा उधार दे सकते हैं।

¹⁴⁹ स्रोत: आरबीआई की वेबसाइट।

¹⁵⁰ भारत सरकार को आबंटित 8% वरीयता शेयरों (28 जनवरी, 2008) को 2015-16 तक पूरी तरह से भुनाया जाना था। भारत सरकार की दर से ब्याज के भुगतान तथा पुनर्भुगतान में चूक होने पर 1% की दर से ब्याज देय होने की शर्त पर, मोयन हेतु आगे विस्तार प्रदान किया।

6.8.5 विनिवेश के बाद का प्रदर्शन

रसायनी इकाई में उत्पादन सुविधाओं के विनिवेश के बाद, कोच्चि इकाई कंपनी की एकमात्र उत्पादन इकाई बन गई थी। फिनोल और एसीटोन इकाई के प्रमुख उत्पाद थे। बेंजीन और प्रोपलीन (एलपीजी से निकाले गए) जो इन उत्पादों के लिए प्रमुख कच्चे माल हैं, का उपयोग पहले क्यूमीन का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, जिसे क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में ऑक्सीकृत किया जाता है, और फिर फिनोल और इसके सह - उत्पाद, एसीटोन में विभाजित किया जाता है। इकाई में 40,000 मीट्रिक टन फिनोल, 24,640 मीट्रिक टन एसीटोन और 10,450 मीट्रिक टन हाइड्रोजन पेरोक्साइड (H₂O₂) के उत्पादन की स्थापित क्षमता थी।

6.8.6 अनुपात विश्लेषण

रसायनी इकाई के विनिवेश की शुरुआत से पहले और बाद में कंपनी के प्रदर्शन का तुलनात्मक विश्लेषण निम्नानुसार था:

तालिका 6.12: विनिवेश से पहले और बाद में कंपनी के प्रदर्शन का तुलनात्मक विश्लेषण

अनुपात	2017-18 तक		2017-18 के बाद			
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
वर्तमान अनुपात	0.13	1.43	1.49	1.25	1.17	1.06
परिचालन लाभ (%)	(178.06)	(109.67)	(9.52)	(38.88)	(0.93)	(12.61)
ऋण इक्विटी अनुपात	5.13	19.44	7.73	34.43	17.28	20.35
ऋण सेवा कवरेज अनुपात	(0.23)	(0.22)	0.21	(0.04)	0.08	0.03
क्षमता उपयोग (%)	29.58	49.02	78.45	64.90	82.36	65.08

उपरोक्त अनुपात से पता चलता है:

- तरलता की स्थिति सुधरी हालांकि वर्तमान अनुपात में 1.5 से 2 के इष्टतम स्तर तक पहुंचना अभी बाकी है।
- परिचालन लाभ अनुपात में पर्याप्त सुधार हुआ, जो मुख्य रूप से रसायनी इकाई के विनिवेश के बाद कर्मचारी लागत में बचत के कारण हुआ। हालांकि, परिचालन घाटे

के कारण अनुपात ऋणात्मक बना हुआ है।

- भारत सरकार से लिए गए ब्रिज लोन के कारण कंपनी पर बहुत अधिक कर्ज था। नतीजतन, वह मुश्किल से अपना कर्ज चुका पा रही थी।
- क्षमता उपयोग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिसका मुख्य कारण विनिवेश के माध्यम से जुटाई गई धनराशि के कारण कार्यशील पूंजी की स्थिति में सुधार है।

6.8.7 बाजार प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण

6.8.7.1 बाजार हिस्सेदारी

2017-18 की अवधि के दौरान आयात में कमी आई थी और इसकी जगह स्थानीय उत्पादन ने ले ली थी। इससे पता चला कि देश में फिनोल और एसीटोन की पर्याप्त मांग थी जिसे प्रतिस्पर्धी मूल्य वाले स्थानीय विकल्पों की कमी के कारण आयात के माध्यम से पूरा किया जा रहा था। 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान, इसके प्रमुख उत्पादों के लिए कंपनी की बाजार हिस्सेदारी नगण्य थी जो 6 से 11 प्रतिशत के बीच थी।

6.8.7.2 कंपनी का प्रदर्शन

2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान के प्रदर्शन के विश्लेषण से निम्नलिखित पता चला:

(i) परिचालन का निम्न स्तर और स्थिर लागत का उच्च स्तर :

चूंकि प्रमुख कच्चे माल (बेंजीन और एलपीजी) की कीमत पेट्रोलियम कीमतों के उतार-चढ़ाव से निकटता से जुड़ी हुई थी, इसलिए कंपनी का उस पर न्यूनतम प्रभाव था। उच्च कर्मचारी लागत और वित्त लागत के कारण एचओसीएल का स्थिर लागत अनुपात (कर्मचारी लागत, वित्त लागत और मूल्यवार) अधिक था। एचओसीएल के द्वारा वहन की गई वित्त लागत मुख्य रूप से भारत सरकार से लिए गए ब्रिज ऋण पर ब्याज के कारण थे।

उच्च स्तर की निश्चित लागत को अवशोषित करने के लिए, एचओसीएल को उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता थी ताकि पूर्ण क्षमता उपयोग सुनिश्चित हो सके और साथ ही उच्च उत्पादन क्षमता भी हो। हालांकि, उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ, स्थिर लागत भी बढ़ेगी, बिक्री/उत्पादन में परिणामी वृद्धि कुल निश्चित लागत को अवशोषित लेगी।

हालांकि, कंपनी के अनुसार, कच्चे माल की कमी के कारण क्षमता विस्तार संभव नहीं था क्योंकि बीपीसीएल कोच्चि ने मुख्य कच्चे माल अर्थात् बेंजीन की आपूर्ति (2,200 मीट्रिक टन प्रति माह) सीमित कर दी थी। शेष कच्चे माल को ओएनजीसी मैंगलोर पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पानीपत जैसे अन्य स्रोतों से प्राप्त करना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं था। इसके अलावा, दक्षिणी क्षेत्र में फिनोल के लिए सीमित बाजार था और इसलिए भारत के बाकी हिस्सों में अतिरिक्त क्षमता बेचनी होती जिसके कारण विपणन उत्पादन में वृद्धि से संभारतंत्रीय नुकसान थी।

(ii) मूल्य निर्धारण

कंपनी द्वारा अपने उत्पादों के लिए अपनाई गई मूल्य निर्धारण पद्धति बाजार मूल्यों पर आधारित थी, जोकि आयात की लागत और अपने प्रतिस्पर्धियों द्वारा पेश की गई कीमत से प्रभावित थी। चूंकि कंपनी को मूल्य अनुयायी बनने के लिए मजबूर किया गया था, इसलिए कंपनी के मूल्य निर्धारण निर्णयों में उत्पादन की कुल लागत पर विचार नहीं किया गया। नतीजतन, 2021-22 तक चार वर्षों के दौरान, कंपनी को 26 महीनों के दौरान फेनोल को और एसीटोन को 33 महीनों के दौरान उत्पादन लागत से कम पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रतिकूल बाजार स्थितियों के दौरान, कंपनी को अपने दैनिक उत्पादन को प्रतिबंधित / कम करना पड़ा। इसके अलावा, उत्पादन की परिवर्तनीय लागत से नीचे बाजार की कीमतों में भारी गिरावट के कारण, कंपनी को पिछले चार वर्षों में दो बार अपने संयंत्र बंद करने के लिए मजबूर¹⁵¹ होना पड़ा।

इस तथ्य के बावजूद कि कंपनी ने हमेशा अपने मुख्य उत्पादों फिनोल और एसीटोन के लिए प्रचलित बाजार मूल्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया, यह देखा गया कि हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के कुल उत्पादन के प्रति मीट्रिक टन औसत बिक्री प्राप्ति की तुलना में कम थी। यह पुरानी तकनीक को लगातार अपनाए जाने और किसी भी मूल्य वर्धित उत्पादों की अनुपस्थिति के कारण कम बाजार मूल्य के उप-उत्पादों (यानी, हेवी एन्ड्स ऑफ क्यूमीन) के उत्पादन के कारण हुआ।

¹⁵¹ 03 जून, 2019 से 30 जून, 2019 (28 दिन) और 15 नवंबर, 2021 से 26 दिसंबर, 2021 तक (42 दिन)।

(iii) पुरानी तकनीक के कारण कम उत्पादकता

कंपनी ने मध्यवर्ती उत्पाद क्यूमीन के निर्माण के लिए सॉलिड फॉस्फोरिक एसिड (एसपीए) आधारित प्रक्रिया का इस्तेमाल किया। 1940 के दशक में विकसित इस तकनीक को 1990 के दशक में जिओलाइट आधारित तकनीक द्वारा बदल दिया गया था। जिओलाइट उत्प्रेरक पुनः उत्पन्न करने योग्य था और एसपीए उत्प्रेरक के 6 से 18 महीने के एकल चक्र के मुकाबले कई चक्रों (अधिकतम छह वर्ष) में इस्तेमाल किया जा सकता था। इसके अलावा, एसपीए आधारित तकनीक के इस्तेमाल के परिणामस्वरूप अधिक मात्रा में हैवी एंड्स ऑफ क्यूमीन (एचईसी) का उत्पादन हुआ, जिसका या तो बिक्री मूल्य कम था या अतिरिक्त रीसाइक्लिंग लागत की आवश्यकता थी। हैवी एंड्स ऑफ क्यूमीन के अधिक होने से फिनोल और एसीटोन के उत्पादन में कमी आई। हैवी एंड्स ऑफ क्यूमीन की अधिक मात्रा और परिणामस्वरूप फिनोल और एसीटोन के कम उत्पादन के कारण, कंपनी को उत्पादकता का नुकसान हुआ जो 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान ₹44.46 करोड़ था जैसा कि *अनुलग्नक-XLVIII* में दिया गया है।

(iv) उत्पाद विविधीकरण या डाउनस्ट्रीम मूल्य संवर्धन का अभाव

जबकि फिनोल की बाजार में मांग स्थिर थी, एसीटोन की मांग और कीमत में लगातार उतार-चढ़ाव बना रहा। इसलिए, जब भी एसीटोन की कीमत में भारी कमी होती थी, तो कंपनी को फिनोल के उत्पादन को नियंत्रित करना पड़ता था या एसीटोन को उपलब्ध दर पर बेचना पड़ता था। इस स्थिति से केवल एसीटोन के डाउनस्ट्रीम व्युत्पन्न के उत्पादन के माध्यम से ही बचा जा सकता था। हालाँकि, कंपनी के उत्पाद पोर्टफोलियो में कोई मूल्य-वर्धित डाउनस्ट्रीम उत्पाद नहीं था। कंपनी के अनुसार, कोई विविधीकरण योजना तैयार नहीं की गई थी क्योंकि नीति आयोग ने अनुशंसा की थी कि पुनर्गठन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद कंपनी को बेच दिया जाना चाहिए।

अनुशंसा संख्या 13:

सरकार तकनीकी/वाणिज्यिक अध्ययन और बाजार विश्लेषण के आलोक में कंपनी के परिचालन की स्थिरता की समीक्षा कर सकती है, गैर रणनीतिक क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश हेतु अपनी वर्तमान नीति¹⁵² को लागू करे ताकि कंपनी के संचालन से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।

¹⁵² भारत सरकार द्वारा 04 फरवरी, 2021 को अधिसूचित नई पीएसई नीति ने सीपीएसई को रणनीतिक

इस अध्याय में मंत्रालय के उत्तर (अगस्त 2024) के संज्ञान ले लिया गया है।

6.9 एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलुरु

6.9.1 परिचय

हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1953 में डीएचआई के अंतर्गत देश के लिए औद्योगिक संरचना के निर्माण के लिए आवश्यक मशीन टूल्स की एक सीमित रेंज का उत्पादन करने के उद्देश्य से की गई थी। सितंबर 1978 में इसका नाम बदलकर एचएमटी लिमिटेड कर दिया गया। इसके बाद, विभिन्न विविध व्यवसायों के साथ, एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड (एचएमटी एमटी/कंपनी) को एचएमटी लिमिटेड (होलडिंग कंपनी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में (01 अप्रैल, 2000) बनाया गया, जिसकी अधिकृत शेयर पूंजी ₹355 करोड़ और समादत्त शेयर पूंजी ₹276.60 करोड़ थी। वर्तमान में, कंपनी की देश भर में छह मशीन टूल्स विनिर्माण इकाइयां हैं, अर्थात्, अजमेर, बंगलुरु, हैदराबाद, कलमस्सेरी, पिंजौर और हैदराबाद¹⁵³ में प्रागा टूल्स। इसका एक केंद्रीय विपणन प्रभाग और बंगलुरु में एक निदेशालय कार्यालय भी है। कंपनी के पास विभिन्न प्रकार के मशीन टूल्स¹⁵⁴ के विनिर्माण की सुविधाएं हैं।

6.9.2 लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

लेखापरीक्षा द्वारा की गई टिप्पणियां इस प्रकार थीं:

6.9.2.1 भारत सरकार और होलडिंग कंपनी से सहायता के बावजूद खराब वित्तीय प्रदर्शन

1991 में उदारीकरण से पहले, भारतीय मशीन टूल्स उद्योग में मांग का एक बड़ा हिस्सा सरकार से आता था, जो एक प्रमुख उपभोक्ता था, जिसमें 30 प्रतिशत मांग रक्षा और

और गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है। गैर-रणनीतिक क्षेत्र के उपक्रमों का विलय, सब्सिडी किसी अन्य सीपीएसई के साथ लिया जाना था अथवा नई नीति के तहत उन्हें बंद करने/निजीकरण के लिए विचार किया जाना था। नतीजतन, डीपीई द्वारा 13 दिसंबर, 2021 को संशोधित क्लोजर पॉलिसी सहित नई नीति के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए थे। रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग में सीपीएसई को नई पीएसई नीति के तहत गैर-रणनीतिक क्षेत्र के तहत वर्गीकृत किया गया है।

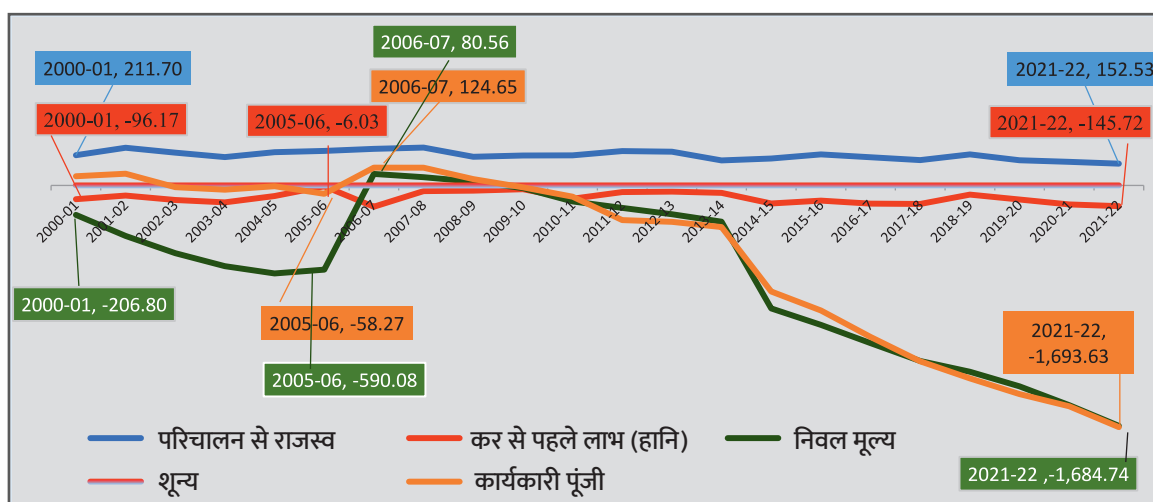
¹⁵³ मेसर्स प्रागा टूल्स लिमिटेड का 2008 में कंपनी में विलय कर दिया गया।

¹⁵⁴ कम्प्यूटरीकृत संख्यात्मक नियंत्रण मशीनें, सामान्य प्रयोजन मशीनें, विशेष प्रयोजन मशीनें, हाइड्रोलिक/मैकेनिकल प्रेस, प्रिंटिंग मशीनें और डाई कास्टिंग मशीनें इंजीनियरिंग के लिए आवश्यक हैं और ऑटोमोबाइल, रेलवे और रक्षा क्षेत्रों के लिए भी उपयोगी हैं।

रेलवे से थी। 1997 तक, मशीन टूल्स की सरकारी खरीद घटकर 10 प्रतिशत¹⁵⁵ रह गई। सरकारी नीति में बदलाव और छोटे पैमाने के निर्माताओं से कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण, एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड का प्रदर्शन खराब रहा है और अप्रैल 2000 में अपनी स्थापना के बाद से ही यह घाटे में था, जैसा कि चार्ट 6.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 6.2: अप्रैल 2000 से मार्च 2022 तक एचएमटी एमटी का प्रदर्शन

(₹ करोड़ में)



31 मार्च 2001 तक, यानी नवगठित सहायक कंपनी के संचालन के पहले वर्ष में कंपनी की संचित हानि कंपनी की निवल संपत्ति से अधिक हो गई। सीसीईए ने कंपनी के लिए ₹880.80 करोड़ के पुनर्गठन/पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी (फरवरी 2007)। पैकेज प्राप्त होने पर, निवल संपत्ति और कार्यशील पूंजी वर्ष 2006-07 से 2008-09 में धनात्मक हो गई। उपरोक्त पुनर्गठन/पुनरुद्धार पैकेज और भारत सरकार और होल्डिंग कंपनी से ₹1,377.47 करोड़¹⁵⁶ (2007 से 2022 के दौरान) की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त होने के बावजूद, कंपनी अपने वित्तीय प्रदर्शन में सुधार नहीं कर सकी और 31 मार्च, 2022 तक, कंपनी का संचित घाटा ₹1,932.26 करोड़ था, (-) ₹1,693.63 करोड़ की कार्यशील पूंजी और निवल संपत्ति (-) ₹1,684.74 करोड़ तक घट गई।

लेखापरीक्षा द्वारा उल्लेखित कम निष्पादन के मुख्य कारण, उच्च विनिर्माण लागत और

¹⁵⁵ स्रोत: इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट स्टडीज द्वारा भारतीय मशीन टूल उद्योग में उत्पादन रुझानों पर रिपोर्ट (6(6): 33-41 (2017))।

¹⁵⁶ भारत सरकार (₹1,119.97 करोड़) और होल्डिंग कंपनी (₹257.50 करोड़)।

पुरानी प्रौद्योगिकी के कारण निजी निर्माताओं के लिए व्यावसायिक अवसरों का नुकसान तथा मुख्य कार्य क्षेत्रों में कुशल कार्यबल की कमी थे, जैसा कि आगे के पैराओं में चर्चा की गई है।

खराब वित्तीय प्रदर्शन के कारण, उत्पन्न राजस्व के अतिरिक्त वैधानिक बकाया के भुगतान के लिए ₹168.28 करोड़¹⁵⁷ का ऋण लेने के बावजूद, कंपनी 2016-17 से 2021-22 की अवधि के दौरान कुल ₹321.82 करोड़ की देय वैधानिक बकाया राशि के मुकाबले केवल ₹195.65 करोड़ का भुगतान कर सकी। यह कमी बिक्री में कमी (2016-17 में ₹197.52 करोड़ से 2021-22 में ₹152.53 करोड़) और गैर-परिचालन (सभी जगह) परिसंपत्तियों से राजस्व का सृजन न होने के कारण हुई। कंपनी ने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम और कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अनुसार देय ब्याज का भुगतान भी नहीं किया था और यहां तक कि अचल संपत्ति की कुर्की के लिए प्राधिकारियों से नोटिस (अक्टूबर 2019/दिसंबर 2019) भी प्राप्त किए थे। वैधानिक बकाया का भुगतान करने में विफलता के परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2022 तक ₹91.72 करोड़ की परिहार्य ब्याज देयता हुई।

6.9.2.2 एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड की कॉर्पोरेट/रणनीतिक योजना, जोखिम प्रबंधन समिति का अभाव और होल्डिंग कंपनी के समझौता ज्ञापन के लक्ष्यों को प्राप्त न करना

बोर्ड द्वारा अनुमोदित कॉर्पोरेट/रणनीतिक योजना के अभाव में, कंपनी के पास दीर्घकालिक दृष्टि और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोई योजना/दृष्टिकोण नहीं था। इसके अलावा, चूंकि शीर्ष स्तर पर कॉर्पोरेट योजना प्रत्येक स्तर से नीचे तक जाती है, इसलिए वार्षिक बजट किसी रणनीति या फोकस द्वारा संचालित नहीं होता है।

पिछले वर्षों के प्रदर्शन के आधार पर होल्डिंग कंपनी द्वारा समझौता ज्ञापन के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों का विवरण नीचे दिया गया है -

¹⁵⁷ होल्डिंग कंपनी से ₹162.66 करोड़ और बैंकों से ₹5.62 करोड़।

तालिका 6.13: बिक्री टर्नोवर के संबंध में उपलब्धि बनाम समझौता ज्ञापन लक्ष्य

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
लक्ष्य (करोड़ रुपए में)	257.00	260.00	220.00	250.00	180.00	200.00
उपलब्धि (करोड़ रुपये में)	197.52	177.08	217.41	176.23	165.82	152.53
उपलब्धि का %	77%	68%	99%	70%	92%	76%

इस संबंध में, यह देखा गया कि तय किए गए समझौता ज्ञापन लक्ष्य बीआईएफआर की पुनर्गठन/पुनरुद्धार योजना के अनुसार अनुमानित लक्ष्यों से बहुत कम थे। उदाहरण के लिए, 2016-17 में बिक्री टर्नोवर का लक्ष्य समझौता ज्ञापन के अनुसार ₹257 करोड़ तय किया गया था, जबकि बीआईएफआर की पुनर्गठन/पुनरुद्धार योजना के अंतर्गत लक्ष्य 2013-14 तक दोगुने से भी अधिक ₹635.06 करोड़ था और कंपनी इन कम लक्ष्यों को भी हासिल करने में असमर्थ रही। लक्ष्यों के इतने कम निर्धारण के कारणों में कम ऑर्डर बुक की स्थिति को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है क्योंकि विपणन प्रणाली प्रभावी नहीं थी और साथ ही कार्यशील पूंजी की कमी, मुख्य क्षेत्रों में कुशल कार्यबल का अभाव और उत्पादों/मशीनों के विकास के लिए प्रौद्योगिकी को उन्नत करने में विफलता भी शामिल है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि हालांकि जोखिम प्रबंधन नीति को कार्यान्वयन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित (मई 2019) किया गया था, लेकिन बोर्ड की मंजूरी के साथ जोखिमों की शीघ्र पहचान और उचित शमन के लिए जोखिम प्रबंधन समिति का गठन नहीं किया गया था। जोखिम प्रबंधन समिति की अनुपस्थिति के कारण, बोर्ड को चिंता के प्रमुख क्षेत्रों के संबंध में अपने कार्यों का निर्वहन करने में उचित समर्थन नहीं मिला, जैसे बाजार से बाहर होने के जोखिम से बचने के लिए प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विविधीकरण, वितरण कार्यक्रमों का पालन, लक्ष्यों को पूरा करना, बाजार की गतिशीलता पर कड़ी नजर रखना, प्रतिस्पर्धी की ताकत और कमजोरियों पर कड़ी नजर रखना आदि। इसके परिणामस्वरूप लागत और प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित करके निरंतर आधार पर उत्पादन की लागत को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए उचित मार्गदर्शन का अभाव था।

मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2022) कि कंपनी जोखिम प्रबंधन समिति के गठन के संबंध में जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाएगी। रणनीतिक योजना के मामले में, यह कहा गया कि होल्डिंग कंपनी के बोर्ड ने 30 मई 2016 को आयोजित अपनी बैठक में आईआईएम बंगलुरु द्वारा तैयार रणनीतिक योजना को मंजूरी दे दी है। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि इसे एचएमटी एमटी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था और प्रत्येक

वर्ष के लिए एचएमटी एमटी की वार्षिक परिचालन योजना उपर्युक्त रणनीतिक योजना से प्रवाहित नहीं होती है।

अपने बाद के उत्तर (जुलाई 2024) में मंत्रालय ने कॉर्पोरेट रणनीतिक योजना तैयार करने की अनुशंसा को स्वीकार कर लिया।

अनुशंसा संख्या 14:

कंपनी दीर्घकालिक दृष्टि और लक्ष्यों के लिए कॉर्पोरेट रणनीतिक योजना तैयार करे एवं निदेशक मंडल से अनुमोदन प्राप्त करे। कंपनी को जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार जोखिम प्रबंधन समिति का गठन भी करना चाहिए और उसे क्रियान्वित करना चाहिए।

6.9.2.3 प्रौद्योगिकी उन्नयन और प्रशिक्षण के लिए निर्धारित निधियों के विचलन के कारण नवीनतम प्रौद्योगिकी प्राप्त करने/उन्नयन करने में विफलता और उत्पादन प्रभागों के बंद होने के कारण व्यवसाय के अवसरों का नुकसान हुआ।

बीआईएफआर की पुनरुद्धार योजना के अंतर्गत कंपनी की प्रौद्योगिकी अधिग्रहण योजना के आधार पर, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इक्विटी शेयर पूंजी के रूप में ₹90 करोड़¹⁵⁸ की राशि के निधि के निवेश को मंजूरी दी (फरवरी 2007)। भारत सरकार ने प्रौद्योगिकी अधिग्रहण/उन्नयन के लिए ₹20 करोड़ और प्रशिक्षण/पुनः प्रशिक्षण के लिए ₹10 करोड़ की राशि जारी की (मार्च 2007) जिसका तुरंत उपयोग किया जाना था। उत्पादों के प्रौद्योगिकी अधिग्रहण/उन्नयन पर प्राप्त ₹20 करोड़ में से, कंपनी ने 2009 से 2018 के दौरान प्रौद्योगिकी अधिग्रहण¹⁵⁹ के लिए केवल ₹9.01 करोड़ और कानूनी/परामर्श शुल्क आदि के लिए ₹1.23 करोड़ का उपयोग किया। प्रशिक्षण/पुनः प्रशिक्षण के लिए प्राप्त ₹10 करोड़ में से, कंपनी ने ₹7.40 करोड़ का उपयोग किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी ने कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए ₹12.36 करोड़¹⁶⁰ की धनराशि

¹⁵⁸ प्रशिक्षण/पुनःप्रशिक्षण के लिए ₹10 करोड़ तथा प्रौद्योगिकी अधिग्रहण/उन्नयन के लिए ₹80 करोड़ चार वर्षों में ₹20-20 करोड़ की चार किस्तों में जारी किए जाएंगे।

¹⁵⁹ मेसर्स फ्रॉनहोफर, जर्मनी से फोर गाइडवे सीएनसी लेथ का विकास (₹0.19 करोड़), मेसर्स एफटी मशीन्स, जर्मनी से फ्लो फॉर्मिंग लेथ (₹5.51 करोड़) और मेसर्स एनयूएम एजी, स्विट्जरलैंड से सीएनसी कंट्रोल सिस्टम (₹3.31 करोड़)।

¹⁶⁰ ₹12.36 करोड़ = ₹9.76 करोड़ (₹20 करोड़ घटाव ₹10.24 करोड़ (₹9.01 करोड़ प्लस ₹1.23 करोड़) + ₹2.60 करोड़ (₹10 करोड़ घटाव ₹7.40 करोड़)।

डायवर्ट की, जबकि भारत सरकार के स्वीकृति कार्यादेश में स्पष्ट निर्देश था कि किसी भी धनराशि को इच्छित उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए डायवर्ट नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद, डीएचआई ने आगे के हिस्से की ₹60 करोड़ की राशि जारी नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप मौजूदा प्रौद्योगिकियों का अधिग्रहण/उन्नयन नहीं हो सका।

डीएचआई की प्रौद्योगिकी अधिग्रहण निधि योजना के अंतर्गत धन जुटाने और मशीनरी की बिक्री आय के माध्यम से मेसर्स पेगार्ड प्रोडक्टिक्स एसए, बेल्जियम से “रैम”¹⁶¹ प्रकार की क्षैतिज बोरिंग और मिलिंग मशीनों के लिए प्रौद्योगिकी प्राप्त करने का प्रस्ताव (जनवरी 2018) रखा गया था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कंपनी सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में थी (जनवरी 2022)। रैम प्रकार की क्षैतिज बोरिंग और मिलिंग मशीनों की अनुपलब्धता के कारण, हैदराबाद में मशीन टूल्स यूनिट ने वर्ष 2014-2020 के दौरान ₹127.82 करोड़ मूल्य के ऑर्डर खो दिए।

कंपनी की बेंगलूर इकाई ने कम्प्यूटरीकृत संख्यात्मक नियंत्रण प्रणाली के विनिर्माण के लिए दिसंबर 2014 में मेसर्स एनयूएम एजी, स्विट्जरलैंड के साथ तकनीकी सहयोग समझौता किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि फंड के डायवर्जन के कारण, कंपनी इस समझौते के अंतर्गत मेसर्स एनयूएम एजी, स्विट्जरलैंड को प्रतिबद्ध व्यय के लिए ₹8.24 करोड़ का भुगतान करने में विफल रही और परिणामस्वरूप, मेसर्स एनयूएम एजी परियोजना से बाहर हो गई। चूंकि पारंपरिक मशीनों की कोई मांग नहीं थी और कम्प्यूटरीकृत संख्यात्मक नियंत्रण प्रणाली को नवीनतम तकनीक के साथ निरंतर उन्नयन की आवश्यकता थी, कम्प्यूटरीकृत संख्यात्मक नियंत्रण प्रणाली तकनीक को अपग्रेड करने में विफलता के परिणामस्वरूप न केवल बेंगलूर में कम्प्यूटरीकृत संख्यात्मक नियंत्रण प्रणाली प्रभाग को बंद करना पड़ा (2018-19) बल्कि व्यापार के अवसरों का भी नुकसान हुआ।

मंत्रालय ने बताया (अगस्त 2022) कि कंपनी ने भविष्य की व्यापार वृद्धि के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बीएचयू), वाराणसी के सहयोग से रैम प्रकार की क्षैतिज बोरिंग और मिलिंग मशीनों के डिजाइन और विकास का प्रस्ताव रखा है।

अपने बाद के उत्तर (जुलाई 2024) में मंत्रालय ने अनुशंसा पर सहमति जताते हुए कहा

¹⁶¹ रैम उस मशीन घटक को संदर्भित करता है जो धुरी को सहारा देने वाले स्तंभ के शीर्ष पर स्थित और चिपका होता है। यह घटक मिलिंग ऑपरेशन के दौरान विभिन्न पदों को समायोजित करने के लिए समायोज्य है।

कि कंपनी ने एनपीए के मुद्रीकरण से उत्पन्न धन से संयंत्र और मशीनरी को उन्नत और आधुनिक बनाने की योजना पहले ही बना ली थी, लेकिन इसका कार्यान्वयन लंबित था क्योंकि भूमि मुद्रीकरण प्रक्रिया में था।

अनुशंसा संख्या 15:

यदि मंत्रालय एचएमटी एमटी का परिचालन जारी रखने का इरादा रखता है, तो कंपनी नवीनतम प्रौद्योगिकियों को उन्नत करने/अधिग्रहण करने की प्रक्रिया में तेजी ला सकती है, ताकि कंपनी का बाजार हिस्सा बढ़ सके और कंपनी का परिचालन व्यवहार्य हो सके।

6.9.2.4 संयंत्रों का क्षमता उपयोग

चयनित इकाइयों में क्षमता उपयोग का विश्लेषण तालिका 6.14 में उल्लिखित है।

तालिका 6.14: 2016-17 से 2021-22 के दौरान चयनित इकाइयों में क्षमता उपयोग

इकाई	स्थापित क्षमता (मशीनों की संख्या)	उत्पादित मशीनों की संख्या					
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
मशीन टूल्स, बेंगलुरु	1,206	115	229	229	125	77	60
मशीन टूल्स, कलमस्सेरी	262	132	92	151	121	106	130
प्रागा टूल्स, हैदराबाद	720	50	56	83	67	50	36
मशीन टूल्स, हैदराबाद	उपलब्ध नहीं है ¹⁶²	19	14	21	20	9	2

¹⁶² मशीन टूल्स, हैदराबाद ने कहा कि निर्मित मशीनों/उपकरणों की प्रक्रियाएं/परिचालन अलग-अलग हैं, इसलिए इन्हें सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता तथा उत्पाद की स्थापित क्षमता का परिमाणन नहीं किया जा सकता।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मशीन टूल्स, बेंगलुरु इकाई ने ऑर्डरों की कमी और प्रौद्योगिकी को उन्नत करने में विफलता के कारण प्रेसिजन मशीनों (2014-15), डाई कास्टिंग और प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों (2017-18) और कम्प्यूटरीकृत संख्यात्मक नियंत्रण प्रणाली सुविधा (2018-19) का उत्पादन बंद कर दिया।

इसके अलावा, मशीन टूल्स, बेंगलुरु इकाई में 74 मशीनें बेकार पड़ी थीं, जबकि हैदराबाद इकाई में 169 मशीनें थीं, जिनमें 43 सुविधा मशीनें शामिल थीं, जिनका बहुत कम इस्तेमाल किया गया था और शेष 126 मशीनों को कुशल कार्यबल की कमी के कारण केवल 21 प्रत्यक्ष कर्मचारियों द्वारा संचालित किया जा रहा था। कलमस्सेरी और प्रागा टूल्स इकाइयों में भी यही स्थिति थी, जहाँ ऑर्डर के अभाव/ऑपरेटरों की अनुपस्थिति के कारण मशीनें बेकार पड़ी थीं।

31 मार्च, 2022 को समाप्त पिछले छह वर्षों के दौरान, कलमस्सेरी को छोड़कर सभी उत्पादन इकाइयों ने हानि दर्ज की, जैसा कि तालिका 6.15 में दर्शाया गया है।

तालिका 6.15: 2016-17 से 2021-22 के दौरान एचएमटी एमटी की सभी उत्पादन इकाइयों में दर्ज कर-पूर्व लाभ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बेंगलुरु	पिंजौर	कलमस्सेरी	हैदराबाद	अजमेर	प्रागा उपकरण
2016-17	-45.94	- 36.08	1.52	-31.02	-14.16	-17.99
2017-18	-28.83	- 41.10	-8.47	-33.71	-15.95	-14.69
2018-19	-25.40	-31.89	4.86	-8.58	-4.57	-13.72
2019-20	-34.07	-39.68	1.93	- 16.55	- 8.09	-17.10
2020-21	-41.29	-43.29	1.90	-39.66	-10.62	-15.74
2021-22	-35.36	-41.81	0.81	-49.74	-15.76	-17.99
कुल	-210.89	-233.85	2.55	-179.26	-69.15	-97.23

एचएमटी एमटी की कलमस्सेरी इकाई ने लाभ दर्ज किया है, क्योंकि यह वर्तमान में भारतीय नौसेना और म्यांमार नौसेना के लिए विभिन्न जहाजों के लिए 18 प्रकार की मशीनें और रेलवे के लिए सतही व्हील लेथ का उत्पादन करती है।

6.9.2.5 अप्रभावी विपणन प्रणाली के कारण ₹2,020.90 करोड़ के व्यापार अवसर का नुकसान हुआ

वर्ष 2016-17 to 2021-22 के दौरान विपणन प्रभाग द्वारा पूर्वानुमानित 60 प्रतिशत से अधिक ऑर्डर 'ऑर्डर के पूरा होने की सबसे कम संभावना' की श्रेणी में आ रहे थे। इसके बावजूद, कॉर्पोरेट विपणन प्रभाग ने उपभोक्ताओं की आवश्यकता और मशीन टूल्स निर्माण में नवीनतम रुझानों को जानने के लिए कोई उद्योग विश्लेषण या कोई स्वतंत्र बाजार सर्वेक्षण नहीं किया है, जिसके कारण लक्षित ऑर्डर बुक स्थिति हासिल नहीं की जा सकी।

मशीन टूल्स के उत्पादन में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी 2016-17 में 5.55 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 1.25 प्रतिशत हो गई और मशीन टूल्स की खपत में इसकी संगत हिस्सेदारी 1.51 प्रतिशत से घटकर 0.97 प्रतिशत हो गई। विशाल बाजार क्षमता (भारत में 2021-22 के लिए ₹15,791 करोड़ और एचएमटी एमटी की हिस्सेदारी ₹152.53 करोड़) होने के बावजूद, उदासीन विपणन दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप कंपनी के लिए व्यावसायिक अवसरों की कमी हुई। कंपनी ने 31 मार्च 2022 को समाप्त पिछले छह वर्षों के दौरान ₹ 2,020.90 करोड़ मूल्य के 2,259 ऑर्डर (जिन ऑर्डर पर बोली लगाई गई थी उनका 43 प्रतिशत) खो दिए। खो दिए गए इन 2,259 ऑर्डर में से कंपनी ने 2,059 ऑर्डर (91 प्रतिशत) एचएमटी एमटी द्वारा उद्धृत उंची कीमतों के कारण खो दिए। एचएमटी एमटी द्वारा उच्च मूल्य निर्धारण के संदर्भ में, सभी इकाइयों द्वारा लागत अनुमानों की समीक्षा करने तथा प्रतिस्पर्धियों की कीमत से मेल खाने के लिए मूल्य निर्धारण तंत्र को समायोजित करने के लिए निदेशक मंडल के निर्देश (अप्रैल 2013) का पालन नहीं किया गया तथा कंपनी ने बाद में इसकी समीक्षा नहीं की। निदेशक मंडल ने भी बाद में इस मुद्दे की समीक्षा नहीं की।

कम ऑर्डर बुक स्थिति और बाजार हिस्सेदारी के बावजूद, विपणन प्रभाग, जिसे देश भर में फैले चार क्षेत्रीय कार्यालयों और छह जोनल कार्यालयों का समर्थन प्राप्त था, ने न तो मूल्य निर्धारण प्रणाली/उत्पाद मिश्रण/उत्पाद डिजाइन की समीक्षा की और न ही अपनी ऑर्डर बुक स्थिति/ बाजार हिस्सेदारी में सुधार के लिए उद्योग विशेषज्ञों से राय ली।

पुराने मामलों सहित प्राप्यों का संग्रह कंपनी और उसके विपणन प्रभाग के बीच समझौता ज्ञापन में स्थिर वित्तीय मापदंडों में से एक था। हालाँकि, विपणन प्रभाग ने, बदले में,

प्राप्यों के संग्रह के लिए क्षेत्रीय/ज़ोनल विपणन कार्यालयों को लक्ष्य नहीं सौंपे थे, जिसके परिणामस्वरूप 2016-17 में बकाया प्राप्यों में ₹130.06 करोड़ (₹52.95 करोड़ के संदिग्ध ऋण¹⁶³ सहित) से 2021-22 में ₹215.54 करोड़ (₹73.86 करोड़¹⁶⁴ के संदिग्ध ऋण सहित) की वृद्धि हुई। विपणन प्रभाग और उत्पादन इकाइयों द्वारा प्रभावी अनुपालन और अनुवर्ती कार्रवाई की कमी के कारण, व्यापार प्राप्यों की वसूली नहीं हो सकी, जो अन्यथा कार्यशील पूंजी की स्थिति में सुधार कर सकती थी।

मंत्रालय ने अनुशंसा पर सहमति जताते हुए (जुलाई 2024) कहा कि कंपनी ने अपने विपणन नेटवर्क को मजबूत करने हेतु चैनल भागीदारों को नियुक्त किया, भविष्य में व्यापार विकास और आयात प्रतिस्थापन के लिए उत्पादों की पहचान की और आईआईटी, बीएचयू जैसे शिक्षण संस्थानों के सहयोग से इसे इन-हाउस विकसित करवा रहा था। आगे यह भी कहा गया कि कंपनी व्यापार प्राप्यों को प्राप्त करने के लिए अपने आपूर्तिकर्ताओं के साथ प्रभावी रूप से संपर्क कर रही थी।

अनुशंसा संख्या 16:

कंपनी को अपने विपणन प्रभाव को मजबूत करना चाहिए और बाज़ार की मांग और ग्राहक विनिर्देशों को जानने के लिए उद्योग विश्लेषण और आवधिक सर्वेक्षण करना चाहिए ताकि नवीनतम मूल्य निर्धारण/उत्पाद मिश्रण/उत्पाद डिज़ाइन को अपनाया जा सके और बाज़ार में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सके। कंपनी आपूर्तिकर्ताओं के साथ सख्ती से अनुवर्ती कार्रवाई भी करे एवं समय पर व्यापार प्राप्यों को वसूल करे।

6.9.2.6 नॉन मूविंग इन्वेंट्री का संचय

कम ऑर्डर बुक स्थिति के कारण, कंपनी के पास 31 मार्च, 2022 तक ₹150.40 करोड़ की इन्वेंट्री जमा थी। 5 वर्षों से अधिक समय से ₹15.74 करोड़ मूल्य की विशाल नॉन-मूविंग इन्वेंट्री पड़े रहने और कार्यशील पूंजी की भारी कमी के बावजूद, कंपनी ने इसकी

¹⁶³ एचएमटी एमटी की लेखा नीति के अनुसार, 5 वर्ष से अधिक समय से बकाया व्यापार प्राप्य को संदेहजनक माना जाएगा।

¹⁶⁴ इसमें उन ग्राहकों से प्राप्त ₹16.57 करोड़ शामिल हैं जिनकी कंपनी बंद हो गई है या जिनकी मशीनें काम नहीं कर रही हैं, तथा उपकरणों की विलम्बित आपूर्ति और स्थापना के लिए परिसमाप्त क्षतिपूर्ति के रूप में ₹15.25 करोड़ शामिल हैं।

उपयोगिता या निपटान का आकलन करने के लिए नॉन-मूविंग इन्वेंट्री की समीक्षा करने हेतु कोई तकनीकी समिति नहीं बनाई थी।

मंत्रालय ने नॉन मूविंग इन्वेंट्री की समीक्षा और परिसमापन के लिए तीन महीने के भीतर सभी इकाइयों में तकनीकी समिति के गठन पर सहमति व्यक्त की (जुलाई 2024)।

अनुशंसा संख्या 17:

कंपनी नॉन मूविंग इन्वेंट्री की समीक्षा और परिसमापन के लिए समय-समय पर तकनीकी समितियों का गठन करे।

6.9.2.7 प्रभावी भूमि प्रबंधन प्रणाली का अभाव

एचएमटी एमटी के कब्जे में जमीन मूल रूप से एचएमटी लिमिटेड (होल्टिंग कंपनी) के नाम पर आवंटित/असाइन की गई थी। 31 मार्च 2022 तक, मार्च 2001 में व्यवस्था योजना (स्कीम ऑफ अरेंजमेंट) के जरिए आवंटित की गई जमीन की तुलना में एचएमटी एमटी के पास 1,957.023 एकड़¹⁶⁵ जमीन के मुकाबले 1,933.573 एकड़¹⁶⁶ जमीन का कब्जा बताया गया। 23.450 एकड़¹⁶⁷ की विसंगति का समाधान नहीं किया गया। इसके अलावा, 679.698 एकड़ तक का स्वामित्व¹⁶⁸ होल्टिंग कंपनी के नाम पर था और शेष 1,253.875 एकड़¹⁶⁹ के लिए, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा एचएमटी एमटी लिमिटेड/एचएमटी लिमिटेड के पक्ष में स्वामित्व हस्तांतरित किया जाना बाकी था।

¹⁶⁵ इसमें मार्च 2001 में व्यवस्था योजना के तहत एचएमटी लिमिटेड को आवंटित 660.750 एकड़ भूमि शामिल है।

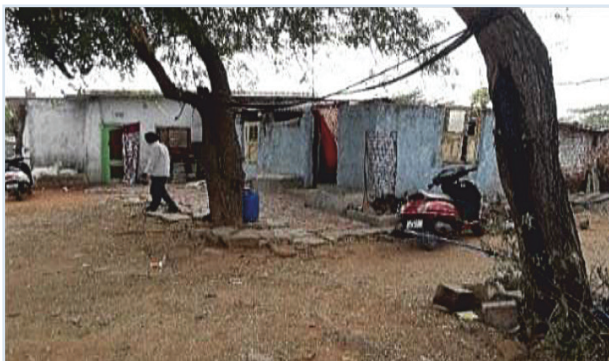
¹⁶⁶ व्यवस्था योजना के अनुसार 1188.658 एकड़ भूमि आवंटित की गई, प्लस प्रागा टूल्स के लिए खरीदी गई 196.395 एकड़ भूमि (बालानगर में 195.825 एकड़ और कवाडीगुडा में 0.57 एकड़) घटाव सरकारी संगठनों (65.238 एकड़) और निजी पार्टियों (23.542 एकड़) को हस्तांतरित 88.780 एकड़ भूमि प्लस एचएमटी लिमिटेड को आवंटित 660.750 एकड़ भूमि।

¹⁶⁷ अजमेर में लगभग 8 एकड़, कलमस्सेरी में 10.580 एकड़ तथा बेंगलुरु इकाई में 4.869 एकड़ भूमि।

¹⁶⁸ बेंगलुरु -330.279 एकड़ प्लस कलमस्सेरी - 348.849 एकड़ प्लस प्रागा टूल्स - 0.57 एकड़।

¹⁶⁹ हैदराबाद इकाई में 888.050 एकड़ भूमि हस्तांतरण विलेख के माध्यम से है तथा इसका स्वामित्व अभी हस्तांतरित होना बाकी है। प्रागा टूल्स में 195.825 एकड़ भूमि तेलंगाना सरकार से खरीदी गई है तथा इसका स्वामित्व अभी हस्तांतरित होना बाकी है। अजमेर में 170.000 एकड़ भूमि राजस्थान सरकार द्वारा हस्तांतरित की जानी है तथा दरों को अंतिम रूप दिए जाने का मामला लंबित है।

चित्र 6.4: प्रागा टूल्स की भूमि पर अतिक्रमण



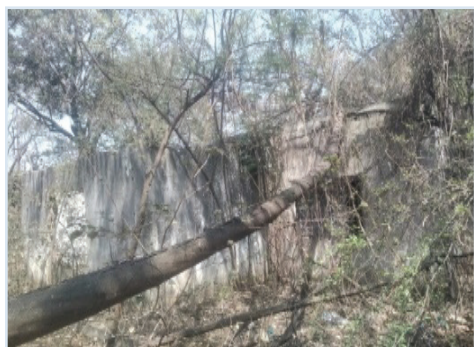
मशीन टूल्स हैदराबाद के कब्जे में भूमि के संबंध में किए गए सर्वेक्षण (फरवरी 2020) के परिणामस्वरूप, यह पाया गया कि आवंटित 888.050 एकड़ के मुकाबले 1,017.375 एकड़ भूमि हैदराबाद में एचएमटी एमटी के कब्जे में थी। क्षेत्र में अंतर को कंपनी और तेलंगाना सरकार के बीच सुलझाया जाना था। प्रागा टूल्स हैदराबाद का भूमि सर्वेक्षण मई 2020 में, यानी आवंटन के 57 साल बाद किया गया था।

हालांकि, एचएमटी एमटी अपने कब्जे वाली संपत्ति की सुरक्षा के लिए कोई कार्रवाई करने में विफल रही, जैसे कि परिसर की दीवारों/बाड़ लगाने आदि का निर्माण, जिसके परिणामस्वरूप 28.05 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण हो गया, जिसकी कीमत लगभग ₹81.46 करोड़¹⁷⁰ रुपये है। कंपनी ने अतिक्रमित भूमि को वापस पाने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। बेंगलुरु और कलमस्सेरी में भूमि सर्वेक्षण अभी तक नहीं हुआ है।

चयनित चार इकाइयों में 2,360 स्टाफ क्वार्टरों में से 446 क्वार्टर खाली थे और 31 मार्च, 2022 तक 962 क्वार्टर उपयोग की स्थिति में नहीं थे।

¹⁷⁰ राज्य सरकार की बाजार दर (जनवरी 2021) के अनुसार 28.05 एकड़ (यानी, 4840 यार्ड x ₹6,000 x 28.05 एकड़) के लिए ₹6,000/- प्रति वर्ग गज की दर से गणना की गई।

**चित्र 6.5: प्रागा टूल्स में खाली पड़े
अनुपयोगी क्वार्टर**



**चित्र 6.6: कलमस्सेरी में खाली पड़े
अनुपयोगी क्वार्टर**



एचएमटी लिमिटेड को तत्कालीन राज्य सरकार (आंध्र प्रदेश - अब तेलंगाना) द्वारा हस्तांतरण विलेख के माध्यम से निःशुल्क 888.05 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी (जनवरी 1972)। कंपनी के पास उपलब्ध खाली/अनुपयोगी भूमि के बारे में चर्चा करने के लिए राज्य सरकार के साथ आयोजित बैठक (जुलाई 2002) के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि कंपनी द्वारा 300 एकड़ भूमि आंध्र प्रदेश औद्योगिक अवसंरचना निगम द्वारा एक औद्योगिक एस्टेट के विकास के लिए अभ्यर्पित की जाएगी। भूमि की बिक्री से प्राप्त 50 प्रतिशत राशि कंपनी को दी जा सकती है, बशर्ते कंपनी तीन वर्षों के भीतर हैदराबाद में अपने परिसर में निवेश करे। इसके अलावा, एक बार 300 एकड़ भूमि सौंप दिए जाने के बाद, राज्य सरकार एचएमटी लिमिटेड के कब्जे में शेष 588.05 एकड़ भूमि के लिए एचएमटी लिमिटेड के पक्ष में स्पष्ट स्वामित्व हस्तांतरित कर देगी। जुलाई 2002 में लिए गए निर्णय को राज्य सरकार के साथ उच्च स्तरीय बैठक में दोहराया गया (अप्रैल 2005) और रंगा रेड्डी जिले के कलेक्टर से कंपनी और राज्य सरकार के बीच औपचारिक समझौते के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य सरकार और होल्डिंग कंपनी के बोर्ड के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, कंपनी ने लगन से काम नहीं किया और अभ्यर्पण के लिए पहचान की गई खाली जमीन का सीमांकन नहीं किया और राज्य सरकार के साथ औपचारिक समझौता भी नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप इस मुद्दे पर गतिरोध पैदा हो गया। क्योंकि कंपनी ने समय पर सक्रिय रूप से कार्रवाई नहीं की थी, इसलिए कंपनी प्रस्ताव से 20 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अपने कब्जे में जमीन का स्पष्ट मालिकाना हक प्राप्त नहीं कर सकी, जिसके परिणामस्वरूप हैदराबाद में मशीन टूल्स यूनिट द्वारा रखी गई गैर-निष्पादन परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण में बाधा उत्पन्न हुई।

बैंगलुरु इकाई के पास डाई कास्टिंग मशीनों, प्रेसिजन मशीनों और कम्प्यूटरीकृत न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीनों के लिए बंद उत्पादन इकाइयों के रूप में अप्रयुक्त बुनियादी ढांचा था, जो 2018 से अप्रयुक्त पड़ा हुआ था। 2007 की पुनरुद्धार योजना के अनुसार, अधिमान शेयर पूंजी के रूप में मंजूर किए गए ₹443 करोड़ रुपये को पहचान की गई अधिशेष संपत्तियों की बिक्री आय से तीन वर्षों में भुनाया जाना था। हालांकि, बैंगलुरु में 46 एकड़ जमीन बेचने का प्रस्ताव, जिसे कैबिनेट की मंजूरी (अप्रैल 2013) भी मिली थी और यहां तक कि सीसीईए ने भी मंजूरी दे दी थी, फलीभूत नहीं हुआ और बिक्री आय से प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता 31 मार्च, 2022 तक नौ साल की अवधि के बाद भी प्राप्त नहीं हो सकी। एचएमटी एमटी को पुनरुद्धार करने के लिए अतिरिक्त अप्रयुक्त भूमि/परिसंपत्तियों की पहचान के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए।

उपरोक्त की पुष्टि करते हुए, प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2022) कि नीतिगत मानदंडों और निर्णय लेने की लंबी प्रक्रिया के कारण इकाइयां मुद्रीकरण और धन उत्पन्न करने में सक्षम नहीं थीं। एचएमटी लिमिटेड हर संभव प्रयास कर रहा था और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने, वैधानिक बकाया का भुगतान करने और बैंक ऋण का भुगतान आदि के लिए बैंगलुरु में 46 एकड़ भूमि की पहचान की, जिसके लिए प्रस्ताव सरकार को मंजूरी के लिए भेजा गया है। मंत्रालय ने आश्वासन दिया (अगस्त 2022) कि कंपनी सभी प्रयास करना जारी रखेगी और अपने नाम पर टाइटल डीड बदलवाने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई जारी रखेगी। मंत्रालय ने यह भी आश्वासन दिया कि कंपनी अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्य करेगी। आगे कहा गया कि कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी के साथ समन्वय में भूमि संबंधी विसंगतियों को हल करने के लिए आवश्यक कार्य करेगी।

अपने बाद के उत्तर (जुलाई 2024) में मंत्रालय ने अनुशंसा पर सहमति जताते हुए कहा कि कंपनी ने भूमि स्वामित्व के मुद्दों के बारे में राज्य सरकारों के साथ पहले ही बात कर ली है और अतिक्रमण हटाने के लिए कदम उठाए हैं। आगे कहा गया कि कंपनी ने मुद्रीकरण के लिए बैंगलुरु में 70 एकड़ भूमि की पहचान की है और वैधानिक बकाया, कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं, संयंत्र के आधुनिकीकरण और भूमि सीमाओं की बाड़ लगाने के लिए आय का उपयोग करने की योजना बनाई है।

अनुशंसा संख्या 18:

कंपनी अपने पक्ष में टाइटल डीड को हस्तांतरित करवाने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ प्रभावी रूप से संपर्क करे एवं अतिक्रमण हटाने के लिए आवश्यक कदम उठाए। कंपनी गैर परिचालन परिसंपत्तियों की पहचान करने और कार्यशील पूंजी के लिए धन जुटाने और वैधानिक बकाया के भुगतान के लिए जल्द से जल्द उनका मुद्रीकरण करने के अपने प्रयासों को तेज करे। कंपनी अपनी अजमेर, कलमस्सेरी और बेंगलुरु इकाइयों में भू स्वामित्व में विसंगति को भी दूर करे।

6.9.2.8 घाटे में चल रही इकाइयों के विलय/आधुनिकीकरण/बंद करने पर अनिर्णय की स्थिति

सीसीईए ने (अप्रैल 2013) डीएचआई को एचएमटी एमटी की कलमस्सेरी इकाई को एक अलग कंपनी बनाने की व्यवहार्यता का पता लगाने का निर्देश दिया। डीएचआई ने मेसर्स आईसीआरए मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड (आईएमएसीएस) को एचएमटी एमटी की सभी छह इकाइयों का व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया ताकि इनमें से प्रत्येक इकाई को अलग-अलग कंपनियों में परिवर्तित किया जा सके। आईएमएसीएस ने कुछ इकाइयों के विलय/बंद करने के साथ-साथ पूरी कंपनी को बंद करने के विकल्प के साथ साथ डीएचआई को सिफारिशें प्रस्तुत कीं (मार्च 2014)।

आईएमएसीएस की सिफारिशों पर डीएचआई के संयुक्त सचिव, निदेशकों और डीएचआई के अन्य अधिकारियों ने एचएमटी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और एचएमटी एमटी के प्रबंध निदेशक के साथ चर्चा की (22 अप्रैल, 2014)। आगे के विचार-विमर्श के बाद, परिचालन घाटे को कम करने और इस तरह एचएमटी एमटी की लाभप्रदता में सुधार करने के लिए पिंजौर इकाई का अजमेर इकाई के साथ और प्रागा टूल्स इकाई का हैदराबाद इकाई के साथ विलय करने पर विचार करने का निर्णय लिया गया। हालांकि, एचएमटी एमटी के निदेशक मंडल द्वारा विषय एजेंडा आइटम को स्थगित कर दिया गया (अगस्त 2015)।

आईएमएसीएस की अनुशंसा के पांच साल बाद एचएमटी एमटी के निदेशक मंडल के बीच चर्चा के लिए एक एजेंडा आइटम प्रस्तावित किया गया (अक्टूबर 2020), जिसमें कंपनी की अव्यवहार्य इकाइयों को बंद करने के बारे में बताया गया और यह पाया गया कि विनिर्माण इकाइयों, जैसे कि पिंजौर और प्रागा टूल्स ने कंपनी में सकारात्मक योगदान नहीं दिया है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के टर्नओवर में भारी नुकसान हुआ है और कंपनी के उपरिव्यय में वृद्धि हो रही है। हालांकि, बोर्ड में चर्चा से पहले ही पिंजौर और

प्रागा टूल्स जैसी अव्यवहार्य उत्पादन इकाइयों को बंद करने के लिए बोर्ड को दिया गया प्रस्ताव वापस ले लिया गया।

इस बीच, भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलुरु ने “एचएमटी लिमिटेड के समेकन और पुनर्गठन योजना” की वित्तीय और रणनीतिक समीक्षा पर रिपोर्ट (जून 2016) प्रस्तुत की, जिसमें एचएमटी लिमिटेड के साथ एचएमटी एमटी का विलय करके मशीन टूल्स पर मुख्य ध्यान देने के साथ एचएमटी लिमिटेड के विनिर्माण कार्यों को एक मजबूत इकाई के अंतर्गत समेकित और पुनर्गठित करने का प्रस्ताव था और अनुशंसा की कि एचएमटी की मुख्य गतिविधि रक्षा सहित प्रमुख ग्राहकों के लिए अनुकूलित मशीन टूल्स और संबद्ध उपकरणों की डिजाइन इंजीनियरिंग और संयोजन होगी। भले ही एचएमटी एमटी को जून 2016 में इस रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया गया इसके बावजूद, जनवरी 2017 में एचएमटी एमटी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित 'आधुनिकीकरण योजना' तैयार करते समय इस पर विचार नहीं किया गया था। हालांकि, इस रिपोर्ट के इनपुट पर देर से विचार किया गया (अक्टूबर 2017) और अंतिम "पुनर्गठन और प्रतिस्पर्धात्मकता संवर्धन योजना" तैयार की गई और जुलाई 2021 में अनुमोदन के लिए डीएचआई को भेज दी गई और प्रस्ताव अभी भी डीएचआई के पास लंबित है।

इस प्रकार, कंपनी की ओर से गैर-निष्पादित इकाइयों को विलय करने/बंद करने में अनिर्णय की स्थिति के परिणामस्वरूप न केवल वित्तीय बोझ बढ़ा, बल्कि कंपनी का निष्पादन भी प्रभावित हुआ।

6.9.2.9 होल्डिंग कंपनी और मंत्रालय द्वारा प्रभावी निगरानी का अभाव

निम्न निष्पादन के बावजूद, प्रबंधन समिति की बैठकों के दौरान होल्डिंग कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के निर्देशों पर की गई कार्रवाई की जानकारी अनुवर्ती कार्रवाई के लिए होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल की आगामी बैठकों में नहीं दी गई।

डीपीई ने 29 अक्टूबर, 2015 के अपने कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से रुग्ण/प्रारंभिक रुग्ण और कमजोर सीपीएसई के पुनरुद्धार और पुनर्गठन के लिए तंत्र को सुव्यवस्थित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए। हालांकि, कंपनी एक रुग्ण कंपनी थी क्योंकि अक्टूबर 2015 तक इसकी निवल संपत्ति ऋणात्मक थी, प्रशासनिक मंत्रालय ने अक्टूबर 2015 में जारी डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार कोई कार्रवाई नहीं की थी। एचएमटी एमटी की तिमाही समीक्षा, बोर्ड में स्वतंत्र सदस्य का नामांकन, प्रदर्शन में गिरावट या गैर-प्रदर्शन

या किसी अन्य सुधारात्मक कदम के लिए जिम्मेदारी तय करना जो उचित और आवश्यक हो सकता है, निर्धारित समय के अनुसार पुनर्गठन/पुनरुद्धार योजना तैयार करना आदि जैसी कोई भी कार्रवाई प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा नहीं की गई।

एचएमटी एमटी के वरिष्ठ प्रबंधन में रिक्तियां थीं (मार्च 2014 से कोई पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक नहीं था और नवंबर 2017 से पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशकों का अभाव था) जिससे कंपनी के निर्णय लेने पर गंभीर प्रभाव पड़ा।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (जुलाई 2024) कि कंपनी की घाटे में चल रही इकाइयों के पुनर्गठन/पुनरुद्धार या बंद करने/विलय का कोई प्रस्ताव नहीं था।

अनुशंसा संख्या 19:

घाटे में चल रही इकाइयों के पुनर्गठन/पुनरुद्धार या बंद करने/विलय के लिए भारी उद्योग विभाग समय पर निर्णय ले, ताकि कंपनी पर और अधिक घाटे का बोझ न पड़े।

यह अध्याय दिसंबर 2023 में डीपीई को भी जारी किया गया था और डीपीई ने अपने उत्तर (मई 2024) में कहा कि उनके पास इस अध्याय पर कोई टिप्पणी नहीं है।



(आनंद मोहन बजाज)

नई दिल्ली

दिनांक : 25 मार्च 2025

उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

(वाणिज्यिक) और अध्यक्ष, लेखा परीक्षा बोर्ड

प्रतिहस्ताक्षरित



(के. संजय मूर्ति)

नई दिल्ली

दिनांक : 25 मार्च 2025

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

अनुलग्नक

अनुलग्नक-1 (पैरा संख्या 1.1.3 देखें)

सरकारी कंपनियों/सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों/सांविधिक निगमों की सूची

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
	सरकारी कंपनियाँ
1.	एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड
2.	एग्रीनोवेटिव इंडिया लिमिटेड
3.	एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड
4.	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड
5.	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड
6.	एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड
7.	अनंतपुरम कुनुल ट्रांसमिशन लिमिटेड
8.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह वन और वृक्षारोपण विकास निगम लिमिटेड
9.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड
10.	अंडमान मत्स्य पालन लिमिटेड
11.	आंध्र प्रदेश सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड
12.	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड
13.	अंगुल सिकिंडा रेलवे लिमिटेड
14.	एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
15.	अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड
16.	अपोलो डिजाइन अपैरल पाकर्स लिमिटेड
17.	आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड
18.	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
19.	औरंगाबाद टेक्सटाइल्स एंड अपैरल पाकर्स लिमिटेड
20.	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड
21.	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड
22.	बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
23.	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड
24.	बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड
25.	बीईएल थालेस सिस्टम लिमिटेड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
26.	बीईएमएल लैंड एसेट्स लिमिटेड
27.	बीईएमएल लिमिटेड
28.	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
29.	बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड
30.	बंगाल इम्यूनिटी लिमिटेड
31.	भादला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड
32.	भारत ब्रेक्स और वाल्व्स लिमिटेड

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
33.	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड
34.	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
35.	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड
36.	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
37.	भारत गैस रिसोर्सेज लिमिटेड
38.	भारत गोल्ड माइन लिमिटेड
39.	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
40.	भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
41.	भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड
42.	भारत ऑप्थेलमिक ग्लास लिमिटेड भारत ऑप्थेलमिक ग्लास लिमिटेड
43.	भारत पेट्रो रिसोर्सेज जेपीडीए लिमिटेड
44.	भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड
45.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
46.	भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड
47.	भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड
48.	भारत संचार निगम लिमिटेड
49.	भारत यंत्र निगम लिमिटेड
50.	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड
51.	भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड
52.	बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड
53.	बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड
54.	बीको लॉरी लिमिटेड
55.	बिहार ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
56.	बिहार इंफ्रा पावर लिमिटेड
57.	बिहार मेगा पावर लिमिटेड
58.	बिजावर विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड
59.	बीकानेर-II भिवाड़ी ट्रांसको लिमिटेड
60.	जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद
61.	बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
62.	बीपीसीएल-केआईएएल फ्यूल फार्म प्राइवेट लिमिटेड
63.	ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड
64.	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
65.	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड
66.	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
67.	ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
68.	ब्रशवेयर लिमिटेड
69.	बीएसएनएल टावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
70.	बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड
71.	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड
72.	कानपुर टेक्सटाइल्स लिमिटेड
73.	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
74.	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
75.	सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड
76.	सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
77.	केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड
78.	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड
79.	भारत के प्रतिभूतिकरण, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित की केंद्रीय रजिस्ट्री
80.	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
81.	सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड
82.	चंडीगढ़ बाल एवं महिला विकास निगम लिमिटेड
83.	चंडीगढ़ औद्योगिक एवं पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
84.	चंडीगढ़ अनुसूचित जाति वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड
85.	चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड
86.	चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड
87.	चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड
88.	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
89.	चेन्नुर इन्फ्रा लिमिटेड
90.	छतरपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड
91.	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड
92.	छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड
93.	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड
94.	छत्तीसगढ़ पूर्व पश्चिम रेलवे लिमिटेड
95.	छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड
96.	सीआईएल नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड
97.	सीआईएल सोलर पीवी लिमिटेड
98.	कोल इंडिया लिमिटेड
99.	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड
100.	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड
101.	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड
102.	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
103.	कॉनकॉर एयर लिमिटेड
104.	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
105.	क्रिएटिव म्यूजियम डिजाइनर
106.	क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
107.	साइकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
108.	दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव एससी/एसटी वित्तीय और विकास निगम लिमिटेड
109.	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
110.	रक्षा नवाचार संगठन
111.	दिल्ली मेट्रो लास्ट माइल सर्विसेज लिमिटेड
112.	दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
113.	दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
114.	देवघर इंफ्रा लिमिटेड
115.	देवघर मेगा पावर लिमिटेड
116.	डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन
117.	दीव स्मार्ट सिटी लिमिटेड
118.	डीएनएच पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
119.	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड
120.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
121.	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
122.	ईसीजीसी लिमिटेड
123.	एडसिल (इंडिया) लिमिटेड
124.	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
125.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
126.	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
127.	ईपीआई अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड
128.	ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड
129.	एफएसीटी आरसीएफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड
130.	फतेहगढ़ भइला ट्रांसमिशन लिमिटेड
131.	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड
132.	फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
133.	फ्रेश एंड हेल्दी एंटरप्राइजेज लिमिटेड
134.	गेल (इंडिया) लिमिटेड
135.	गेल गैस लिमिटेड
136.	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड
137.	जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
138.	घोगरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड
139.	ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड
140.	गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
141.	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
142.	गोल्डमोहर डिज़ाइन एंड अपैरल पार्क्स लिमिटेड
143.	सरकारी ई-मार्केट प्लेस
144.	हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड
145.	हरिद्वार नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड
146.	हसन मैंगलोर रेल विकास कंपनी लिमिटेड
147.	हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड
148.	हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
149.	हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड
150.	हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
151.	उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी
152.	हिमाचल रिन्यूएबल्स लिमिटेड
153.	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
154.	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड
155.	हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड
156.	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड
157.	हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
158.	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बोन्स लिमिटेड
159.	हिंदुस्तान कीटनाशक लिमिटेड
160.	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
161.	हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
162.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
163.	हिंदुस्तान फोटो फिल्मस (मैन्युफैक्चरिंग) कंपनी लिमिटेड
164.	हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड
165.	हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड
166.	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड
167.	हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड
168.	हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड
169.	हिंदुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
170.	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड
171.	एचएलएल इंफ्राटेक सर्विसेज लिमिटेड
172.	एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
173.	एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड
174.	एचएलएल मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल्स लिमिटेड
175.	एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड
176.	एचएमटी चिनार वॉचेस लिमिटेड
177.	एचएमटी लिमिटेड
178.	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड
179.	एचएमटी वॉचेस लिमिटेड
180.	हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
181.	हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड
182.	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड
183.	होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
184.	आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड
185.	एचपीसीएल बायो फ्यूल्स लिमिटेड
186.	एचपीसीएल एलएनजी लिमिटेड
187.	एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड
188.	एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड
189.	आईटीआई लिमिटेड
190.	आईडीपीएल तमिलनाडु (प्राइवेट) लिमिटेड
191.	आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड
192.	आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
193.	आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड
194.	आईएफसीआई लिमिटेड
195.	आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड
196.	आईएफआईएन कमोडिटीज लिमिटेड
197.	आईएफआईएन क्रेडिट लिमिटेड
198.	आईएफआईएन सिक्योरिटीज फाइनेंस लिमिटेड
199.	आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
200.	आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
201.	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
202.	इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड
203.	भारत ऑप्टेल लिमिटेड
204.	इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड
205.	इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड
206.	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
207.	भारत व्यापार संवर्धन संगठन

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
208.	इंडिया यूनाइटेड टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड
209.	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
210.	इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
211.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
212.	आईआरसीटीसी
213.	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड
214.	इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड
215.	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड
216.	भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड
217.	इंडियन वैक्सीन्स कंपनी लिमिटेड
218.	इंडो-रूसी हेलिकॉप्टर्स लिमिटेड
219.	इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड
220.	इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड
221.	इनलैंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड
222.	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड
223.	इरकॉन अक्लोली-शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड
224.	इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड
225.	इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड
226.	इरकॉन गुडगांव रेवारी हाईवे लिमिटेड
227.	इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड
228.	इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
229.	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
230.	इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड
231.	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड
232.	इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड
233.	इरकॉन शिव पुरी गुना लिमिटेड
234.	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड
235.	आईआरईएल आईडीसीओएल लिमिटेड
236.	आईटीपीओ सर्विसेज लिमिटेड
237.	जम्मू एवं कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड
238.	जम्मू एवं कश्मीर खनिज विकास निगम लिमिटेड
239.	जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड
240.	जल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
241.	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड
242.	झारखंड इन्फ्रा पावर लिमिटेड

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
243.	झारखंड राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड
244.	जोगीघोपा लॉजिस्टिक्स पार्क लिमिटेड
245.	कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड
246.	कर्मयोगी भारत
247.	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
248.	कर्नाटक सौर ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड
249.	कर्नाटक व्यापार संवर्धन संगठन
250.	कर्नाटक विजयनगर स्टील लिमिटेड
251.	कवरत्ती स्मार्ट सिटी लिमिटेड
252.	खेतड़ी नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड
253.	केआईओसीएल लिमिटेड
254.	किश्तवाड़ ट्रांसमिशन लिमिटेड
255.	कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड
256.	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड
257.	कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
258.	कोलकाता रिवरफ्रंट डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
259.	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड
260.	कुमारकृपा फ्रंटियर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
261.	लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड
262.	लक्षद्वीप पर्यटन विकास निगम
263.	लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड
264.	लोकटक डाउन स्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड
265.	लखनऊ सौर ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड
266.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
267.	महानदी बेसिन पावर लिमिटेड
268.	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड
269.	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
270.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
271.	महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
272.	महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
273.	महाराष्ट्र रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड
274.	मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड
275.	मांड्या नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड
276.	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
277.	मणिपुर स्टेट ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
278.	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड
279.	मेकॉन लिमिटेड
280.	मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड
281.	मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
282.	माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड
283.	मिश्र धातु निगम लिमिटेड
284.	एमजेएसजे कोल लिमिटेड
285.	एमएमटीसी लिमिटेड
286.	एमएनएच शक्ति लिमिटेड
287.	मोहनलाल गंज ट्रांसमिशन लिमिटेड
288.	एमओआईएल लिमिटेड
289.	एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-1 लिमिटेड
290.	एमएसटीसी लिमिटेड
291.	मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
292.	मुंबई रेल विकास निगम लिमिटेड
293.	म्युनिशंस इंडिया लिमिटेड
294.	नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
295.	नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड
296.	नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड
297.	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
298.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
299.	भारतीय राष्ट्रीय साइकिल निगम लिमिटेड
300.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड
301.	राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र
302.	नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड
303.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
304.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड
305.	नेशनल फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड
306.	राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम
307.	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
308.	नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
309.	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड
310.	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक.
311.	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
312.	राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना निधि ट्रस्टी लिमिटेड

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
313.	राष्ट्रीय जूट निर्माता निगम लिमिटेड
314.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम
315.	नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
316.	भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम लिमिटेड
317.	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम
318.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम
319.	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम
320.	राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
321.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड
322.	राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड
323.	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
324.	एनबीसीसी इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड
325.	एनबीसीसी पर्यावरण इंजीनियरिंग लिमिटेड
326.	एनबीसीसी इंटरनेशनल लिमिटेड
327.	एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड
328.	एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड
329.	नेपा लिमिटेड
330.	न्यू सिटी ऑफ बॉम्बे मैनुफैक्चरिंग मिल्स लिमिटेड
331.	नई दिल्ली नगर पालिका परिषद स्मार्ट सिटी लिमिटेड
332.	न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड
333.	नेयवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड
334.	एनएचडीसी लिमिटेड
335.	एनएचपीसी लिमिटेड
336.	एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड
337.	एनएलसी इंडिया लिमिटेड
338.	एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड
339.	एनएमडीसी सीएसआर फाउंडेशन लिमिटेड
340.	एनएमडीसी लिमिटेड
341.	एनएमडीसी स्टील लिमिटेड
342.	एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड
343.	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड
344.	पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
345.	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड
346.	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
347.	एनपीसीआईएल इंडियन ऑयल न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
348.	एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड
349.	एनटीपीसी ईडीएमसी वेस्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
350.	एनटीपीसी इलेक्ट्रिक सप्लाय कंपनी लिमिटेड
351.	एनटीपीसी लिमिटेड
352.	एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड
353.	एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड
354.	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड
355.	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
356.	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड
357.	ओडिशा इंध्र पावर लिमिटेड
358.	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड
359.	ऑयल इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड
360.	ऑयल इंडिया लिमिटेड
361.	ओमनीबस औद्योगिक विकास निगम दमन, दीव और दादरा और नगर हवेली लिमिटेड
362.	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड
363.	ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड
364.	उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड
365.	उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड
366.	पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
367.	पवन हंस लिमिटेड
368.	पीईसी लिमिटेड
369.	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड
370.	पांडिचेरी अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
371.	पोर्ट ब्लेयर स्मार्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर
372.	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
373.	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
374.	पावर ग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड
375.	पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
376.	पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसको लिमिटेड
377.	पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड
378.	पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड
379.	पावरग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड
380.	पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड
381.	पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड
382.	पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
383.	पावरग्रिड मेदिनीपुर जिरात ट्रांसमिशन लिमिटेड
384.	पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड
385.	पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड
386.	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड
387.	पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड
388.	पावरग्रिड साउदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड
389.	पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड
390.	पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड
391.	पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड
392.	प्राइज पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड
393.	प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड
394.	पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड
395.	पंजाब लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
396.	रेल विकास निगम लिमिटेड
397.	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
398.	रेलटेल एंटरप्राइजेज लिमिटेड
399.	राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
400.	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड
401.	राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड
402.	रामगढ़ न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड
403.	रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
404.	राष्ट्रीय केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
405.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
406.	रैटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
407.	रियल एस्टेट विकास एवं निर्माण निगम राजस्थान लिमिटेड
408.	आरईसी लिमिटेड
409.	आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड
410.	पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड
411.	आरईएमसी लिमिटेड
412.	रिन्यूएबल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड
413.	रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड
414.	रेरोल बर्न लिमिटेड
415.	रिचर्डसन और क्रुडास (1972) लिमिटेड
416.	राइट्स लिमिटेड
417.	रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
418.	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड
419.	सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्रीज लिमिटेड
420.	सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड
421.	सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड
422.	सांभर साल्ट्स लिमिटेड
423.	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड
424.	सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
425.	सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
426.	एसएचसीआईएल सर्विसेज लिमिटेड
427.	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स लिमिटेड
428.	शोंगटोंग करछम वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड
429.	सिडकुल कॉनकॉर इफ्रा कंपनी लिमिटेड
430.	सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड
431.	सीकर-॥ अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड
432.	सिलवासा स्मार्ट सिटी लिमिटेड
433.	एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड
434.	एसजेवीएन लिमिटेड
435.	एसजेवीएन थर्मल प्राइवेट लिमिटेड
436.	स्मिथ स्टैनिस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
437.	भारतीय सौर ऊर्जा निगम
438.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
439.	एसटीसीएल लिमिटेड
440.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
441.	स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
442.	स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड
443.	स्टॉक होल्डिंग सिक्वोरिटीज आईएफएससी लिमिटेड
444.	सूरत इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट लिमिटेड
445.	एसयूटीआई टेक ऑप्शंस लिमिटेड
446.	तालचेर फर्टिलाइजर लिमिटेड
447.	तमिलनाडु व्यापार संवर्धन संगठन
448.	टांडा ट्रांसमिशन लिमिटेड
449.	तातिया आंध्र मेगा पावर लिमिटेड
450.	टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड
451.	टीसीआईएल एलटीआर लिमिटेड
452.	टी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
453.	टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड
454.	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
455.	बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड
456.	ब्रेथवेट बर्न और जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
457.	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड
458.	भारतीय कपास निगम लिमिटेड
459.	एल्गिन मिल्स कंपनी लिमिटेड
460.	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड
461.	द फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड
462.	भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड
463.	इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड
464.	भारतीय जूट निगम लिमिटेड
465.	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
466.	ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
467.	उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड
468.	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
469.	दक्षिणी कीटनाशक निगम लिमिटेड
470.	भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड
471.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड
472.	डूप कम्फर्ट्स लिमिटेड
473.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड
474.	टुस्को लिमिटेड
475.	टायर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
476.	उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
477.	यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
478.	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
479.	उर्वारक विदेश लिमिटेड
480.	उत्कल अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
481.	उत्कर्ष एल्युमीनियम धातु निगम लिमिटेड
482.	विज्ञान इंडस्ट्रीज लिमिटेड
483.	विशाखापत्तनम पोर्ट लॉजिस्टिक्स पार्क लिमिटेड
484.	वाप्कोस लिमिटेड
485.	वेइबर्ड (इंडिया) लिमिटेड
486.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
487.	यंत्र इंडिया लिमिटेड

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
488.	यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड
489.	यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड
490.	जेनिथ सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
	वैधानिक निगम
1.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
2.	केंद्रीय भंडारण निगम
3.	दामोदर घाटी निगम
4.	भारतीय खाद्य निगम
5.	भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
6.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
	सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ
1.	एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड
2.	आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
3.	एक्यूमेज़र्स (पंजाब) लिमिटेड
4.	नबकिसान फाइनेंस लिमिटेड
5.	एएफसी इंडिया लिमिटेड
6.	नबसमृद्धि फाइनेंस लिमिटेड
7.	भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड
8.	एलाइड इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड
9.	अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
10.	एपीआईटीसीओ लिमिटेड
11.	एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड
12.	अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे कंपनी लिमिटेड
13.	अवंतिका गैस लिमिटेड
14.	भरुच दाहेज रेलवे कंपनी लिमिटेड
15.	बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड
16.	भाग्यनगर गैस लिमिटेड
17.	बिहार औद्योगिक एवं तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड
18.	बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
19.	बीओबी कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड
20.	बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड
21.	बीओआई एक्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड
22.	बैंक ऑफ इंडिया ट्रस्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
23.	बीओआई मर्चेन्ट बैंकर्स लिमिटेड
24.	बीओआई शेयरहोल्डिंग लिमिटेड

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
25.	बोकारो पावर सप्लाई कंपनी (प्रा.) लिमिटेड
26.	भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड
27.	भोर सागर पोर्ट लिमिटेड
28.	बड़ौदा सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
29.	केनरा बैंक सिन्डिकेटीज लिमिटेड
30.	कैनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड
31.	कैनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड
32.	कैनबैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
33.	केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
34.	कैनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड
35.	सेंटबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
36.	चेन्नई-एन्नोर पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड
37.	केनरा एचएसबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
38.	कलकत्ता हल्दिया पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड
39.	चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड
40.	सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड
41.	कोल लिग्नाइट ऊर्जा विकास प्राइवेट लिमिटेड
42.	कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
43.	देवघर एयरपोर्ट लिमिटेड
44.	धालभूमगढ़ एयरपोर्ट लिमिटेड
45.	धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड
46.	पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड
47.	राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड
48.	सेंट्रल रेलसाइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड
49.	यूबीआई सर्विसेज लिमिटेड
50.	सीएससी ग्रामीण ईस्टोर प्राइवेट लिमिटेड
51.	सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड
52.	सीएससी वाईफाई चौपाल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
53.	सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड
54.	दिल्ली एविएशन फ्यूल फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड
55.	डीएमई डेवलपमेंट लिमिटेड
56.	राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड
57.	एनआईसीडीसी नीमराना सोलर पावर लिमिटेड
58.	ट्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
59.	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
60.	कामराजर पोर्ट लिमिटेड
61.	ईएसजी जोखिम आकलन और अंतर्दृष्टि लिमिटेड
62.	एक्सेलसियर प्लांट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
63.	फ्लेवरिट स्पाइसेज ट्रेडिंग लिमिटेड
64.	गंगावती शुगर्स लिमिटेड
65.	ग्रीन गैस लिमिटेड
66.	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड
67.	गोवा नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड
68.	गैस और पावर इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड
69.	माल एवं सेवा कर नेटवर्क
70.	हार्डिकॉन लिमिटेड
71.	एचपीओआईएल गैस प्राइवेट लिमिटेड
72.	आईडीबीआई एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड
73.	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लिमिटेड
74.	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड
75.	आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड
76.	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड
77.	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
78.	आईएचबी प्राइवेट लिमिटेड
79.	आईआईडीएल रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड
80.	इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
81.	इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड
82.	इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड
83.	इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
84.	इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
85.	भारतीय पोर्ट रेल और रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड
86.	भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड
87.	इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड
88.	पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड
89.	जम्मू एवं कश्मीर औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड
90.	एनएबीएफआईएनएस लिमिटेड
91.	कन्याकुमारी पोर्ट लिमिटेड
92.	खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड
93.	केरल औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड
94.	किटको लिमिटेड

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
95.	कोंकण एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड
96.	कोलकाता पोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड
97.	कृष्णापट्टनम रेल कंपनी लिमिटेड
98.	कोच्चि सेलम पाइपलाइन्स प्राइवेट लिमिटेड
99.	कच्छ रेलवे कंपनी लिमिटेड
100.	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड
101.	एलआईसी कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड
102.	लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड
103.	एमएमसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड
104.	महाराष्ट्र एक्जीक्यूटिव एंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
105.	मुंबई फ्यूल फार्म फैसिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड
106.	मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड
107.	मिलेनियम इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स लिमिटेड
108.	मुंबई जेएनपीटी पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड
109.	महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड
110.	एमपीकॉन लिमिटेड
111.	मोरमुगाओ पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड
112.	माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनंस एजेंसी लिमिटेड
113.	नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
114.	एनएबी फाउंडेशन
115.	नबसंरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड
116.	नबवैचर्स लिमिटेड
117.	नालंदा सेरामिक्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
118.	नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
119.	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
120.	राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड
121.	नेडफी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड
122.	नेडफी वैचर कैपिटल लिमिटेड
123.	उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड
124.	नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड
125.	पूर्वोत्तर औद्योगिक एवं तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड
126.	एनईएसएल-एसेट डेटा लिमिटेड
127.	एनईएसएल ई-इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
128.	नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
129.	नेशनल हाईवेज इन्फ्रा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
130.	नेशनल हाईवेज इन्विट प्रोजेक्ट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड
131.	नेशनल हाईवेज इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
132.	नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
133.	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड
134.	निकॉन सोशल फाउंडेशन
135.	न्यू मेंगलोर पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड
136.	नॉर्थ इंडिया टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड
137.	एनपीसीआई भारत बिलपे लिमिटेड
138.	एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड
139.	एनआरटीयू फाउंडेशन
140.	एनटीपीसी बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड
141.	एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड
142.	उड़ीसा औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड
143.	ओएनजीसी पेट्रो एडिशन लिमिटेड
144.	पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड
145.	पेट्रोनेट वीके लिमिटेड
146.	पिपावाव रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड
147.	पीएनबी कार्ड और सेवाएं
148.	पीएनबी गिल्ड्स लिमिटेड
149.	पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड
150.	पारादीप पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड
151.	रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड
152.	रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड
153.	रत्ना गिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड
154.	आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी लिमिटेड
155.	रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
156.	मीनाचिल ट्रीटेड रबरवुड (पी) लिमिटेड
157.	पंजा रबर्स लिमिटेड
158.	रबर पार्क इंडिया (पी) लिमिटेड
159.	पजास्सी रबर्स (पी) लिमिटेड
160.	पोनमुडी रबर्स (पी) लिमिटेड
161.	रबरवुड इंडिया (पी) लिमिटेड
162.	एनटीपीसी-सेल पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
163.	सुरक्षा और वैज्ञानिक तकनीकी अनुसंधान एसोसिएशन
164.	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
165.	एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड
166.	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
167.	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
168.	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
169.	एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्योरिटीज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
170.	एसबीआईकैप सिक्योरिटीज लिमिटेड
171.	एसबीआईकैप ट्रस्टी लिमिटेड
172.	एसबीआईकैप वेंचर्स लिमिटेड
173.	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड
174.	एसबीआई फाउंडेशन
175.	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
176.	एसबीआई इंप्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
177.	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
178.	एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
179.	स्मेरा ग्रेडिंग्स एंड रेटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
180.	सिडबी ट्रस्टीज़ कंपनी लिमिटेड
181.	सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड
182.	एक्यूइट रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड
183.	एसटीसीआई कमोडिटीज
184.	एसटीसीआई फाइनेंस लिमिटेड
185.	एसटीसीआई प्राइमरी डीलर्स लिमिटेड
186.	स्टार यूनिन दार्-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
187.	सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड
188.	टेक्सटाइल प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
189.	आईटीसीओटी कंसल्टेंसीज़ एंड सर्विसेज लिमिटेड
190.	तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड
191.	तूतीकोरिन पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड
192.	यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
193.	यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
194.	उज्ज्वल प्लस फाउंडेशन
195.	यूपी इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल कंसल्टेंट्स लिमिटेड
196.	सीआईएल एनटीपीसी ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड
197.	यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड
198.	यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड
199.	वधवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
200.	विशाखापत्तनम पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड
201.	वैगन इंडिया लिमिटेड
202.	पश्चिम बंगाल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड

अनुलग्नक -II (पैरा संख्या 1.1.3 देखें)

सीपीएसई जो 2021-22 के दौरान सीएजी लेखापरीक्षा के दायरे में आए/दायरे से बाहर हुए

सीएजी लेखापरीक्षा के दायरे में आने वाली सरकारी कंपनियां

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1.	इरकॉन अक्लोली-शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड
2.	इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड
3.	इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड
4.	इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड
5.	एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड
6.	कर्मयोगी भारत
7.	इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड
8.	पावरग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड
9.	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स लिमिटेड
10.	छतरपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड
11.	एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड

सीएजी लेखापरीक्षा के दायरे से बाहर जाने वाली सरकारी कंपनियां

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1.	पावरग्रिड परली ट्रांसमिशन लिमिटेड
2.	पावरग्रिड वारोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड
3.	पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड
4.	पावरग्रिड काला अंब ट्रांसमिशन लिमिटेड
5.	इंडियन कैटेलिस्ट प्राइवेट लिमिटेड
6.	एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड
7.	कॉनकॉर लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड
8.	पीएनबी इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड
9.	पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड
10.	एनएमडीसी पावर लिमिटेड
11.	एचएमटी (बियरिंग्स) लिमिटेड
12.	एनपीसीआईएल-नाल्को पावर कंपनी लिमिटेड

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
13.	भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड
14.	बड़ौदा ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
15.	बड़ौदा एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड
16.	गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड
17.	कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड
18.	करूर ट्रांसमिशन लिमिटेड
19.	कोप्पल नरेंद्र ट्रांसमिशन लिमिटेड
20.	एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-II लिमिटेड
21.	नांगलबीबरा बोंगाईगांव ट्रांसमिशन लिमिटेड
22.	खावड़ा भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड
23.	टैनरी एंड फुटवियर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
24.	हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड ¹
25.	एयर इंडिया लिमिटेड
26.	भारतीय सड़क निर्माण निगम लिमिटेड ²
27.	ओएनजीसी मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ³
28.	केरल गेल गैस लिमिटेड

सीएजी लेखापरीक्षा के दायरे से बाहर जाने वाली अन्य सरकार नियंत्रित कंपनियां

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1.	बेकर ग्रे एंड कंपनी (1930) लिमिटेड ⁴
2.	भारत क्लियरिंग और डिपॉजिटरी सेवाएं ⁵

¹ कंपनी का दर्जा बदलकर राज्य सरकार की कंपनी कर दिया गया है। हालांकि, इसका सीएजी द्वारा ऑडिट जारी है।

² कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार कंपनी की स्थिति 'विघटित' है।

³ ओएनजीसी मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के साथ विलय को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 14 अप्रैल, 2022 के अंतिम आदेश के माध्यम से 01 अप्रैल, 2021 को नियत तिथि के रूप में अनुमोदित किया गया था।

⁴ कंपनी अ-संचालनशील प्रतीत होती है क्योंकि ऑडिट के पास कंपनी की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार कंपनी "नाम हटाने" या 'स्ट्राइक ऑफ' की स्थिति में है।

⁵ कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार कंपनी की स्थिति 'परिसमाप्त' है।

अनुलग्नक- III क (पैरा संख्या 1.1.3 और पैरा संख्या 2.3.2 देखें)
बकाया लेखाओं या देय न होने वाले लेखाओं या परिसमापनाधीन कंपनी का विवरण

क. सरकारी कंपनियाँ

क्रम सं.	क्षेत्र/सीपीएसई का नाम	उन वर्षों का विवरण, जिनमें 29 फरवरी, 2024 तक लेखे प्राप्त नहीं हुए
रसायन और उर्वरक		
1**	बंगाल इम्युनिटी लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
2	बिहार ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	2020-21, 2021-22
3**	आईडीपीएल तमिलनाडु (प्राइवेट) लिमिटेड	2010-11 से 2021-22
4**	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	2018-19 से 2021-22
5**	उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
6**	स्मिथ स्टैनिस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
7**	दक्षिणी कीटनाशक निगम लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
वाणिज्य और उद्योग		
8**	राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र	परिसमापन के अंतर्गत
9 **	टी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण		
10	हिंदुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22
वित्त		
11**	इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		
12	एचएलएल मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल्स लिमिटेड	2021-22
भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम		
13**	भारत ब्रेक्स एंड वाल्व्स लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
14**	भारत ऑप्टोथाल्मिक ग्लास लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
15**	भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
16**	भारत यंत्र निगम लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
17**	साइकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
18**	हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
19**	एचएमटी चिनार वॉचेस लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
20**	जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड	2017-18 से 2021-22
21**	मांड्या नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
22**	माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत

क्रम सं.	क्षेत्र/सीपीएसई का नाम	उन वर्षों का विवरण, जिनमें 29 फरवरी, 2024 तक लेखे प्राप्त नहीं हुए
23**	नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड	2017-18 से 2021-22
24**	पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
25**	रेरोल बर्न लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
26**	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड	2013-14 से 2021-22
27**	टायर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
28**	वेइबर्ड (इंडिया) लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन		
29**	कर्मयोगी भारत	प्रथम खाते बकाया नहीं
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस		
30**	ऑयल इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
विद्युत		
31	बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड	2021-22
32**	छतरपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	प्रथम खाते बकाया नहीं
33	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	2021-22
34**	एनएचपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड	प्रथम खाते बकाया नहीं
35**	पावरग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड	प्रथम खाते बकाया नहीं
36	शॉगटोंग करछम वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड	2021-22
37**	एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	प्रथम खाते बकाया नहीं
38	तातिया आंध्र मेगा पावर लिमिटेड	2021-22
रेलवे		
39	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड	2021-22
40**	इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	प्रथम खाते बकाया नहीं
41**	इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	प्रथम खाते बकाया नहीं
42**	इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	प्रथम खाते बकाया नहीं
जहाजरानी		
43**	कोलकाता रिवरफ्रंट डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड	2017-18 से 2021-22
वस्त्र		
44	अपोलो डिज़ाइन अपैरल पार्क्स लिमिटेड	2021-22
45	औरंगाबाद टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क्स लिमिटेड	2021-22
46**	ब्रशवेयर लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
47**	कानपुर टेक्सटाइल्स लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
48	गोल्डमोहुर डिज़ाइन एंड अपैरल पार्क्स लिमिटेड	2021-22
49	इंडिया यूनाइटेड टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड	2021-22

क्रम सं.	क्षेत्र/सीपीएसई का नाम	उन वर्षों का विवरण, जिनमें 29 फरवरी, 2024 तक लेखे प्राप्त नहीं हुए
50	राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड	2021-22
51	न्यू सिटी ऑफ बॉम्बे मैन्युफैक्चरिंग मिल्स लिमिटेड	2021-22
52**	एल्लिगन मिल्स कंपनी लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
पर्यटन		
53	लक्षद्वीप पर्यटन विकास निगम	2020-21, 2021-22
संघ शासित प्रदेश प्रशासन		
54**	चंडीगढ़ बाल एवं महिला विकास निगम लिमिटेड	2017-18 से 2021-22
55**	चंडीगढ़ अनुसूचित जाति वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड	2018-19 से 2021-22
शहरी विकास		
56**	ईपीआई अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
57**	एनबीसीसी इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
58	पोर्ट ब्लेयर स्मार्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर	2020-21, 2021-22
59	सिलवासा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22

****ऐसे सीपीएसई जिनके खाते तीन वर्ष या उससे अधिक समय से बकाया थे या परिसमापन के अधीन थे या जिनके पहले खाते बकाया नहीं थे।**

अनुलग्नक- III ब (पैरा सं.1.1.3 और पैरा सं.2.3.2 देखें)

बकाया लेखों या परिसमापनाधीन कंपनी का विवरण

ब. सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	29 फरवरी, 2024 तक अप्राप्त लेखों का विवरण
1**	एक्यूमेज़र्स (पंजाब) लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
2**	एलाइड इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
3**	बिहार औद्योगिक एवं तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
4**	एक्सेलसियर प्लांट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
5**	गंगावती शुगर लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
6	गैस और पावर इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड	2020-21, 2021-22
7 **	इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
8**	मिलेनियम इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
9**	नालंदा सेरामिक्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
10	नेशनल हाईवेज़ इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	2021-22
11**	पूर्वोत्तर औद्योगिक एवं तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड	2012-13 से 2021-22
12**	उड़ीसा औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड	1997-98 से 2021-22 ⁶
13**	पजास्सी रबर्स (पी) लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
14**	पोनमुडी रबर्स (पी) लिमिटेड	2016-17 से 2021-22
15	एसबीआई इन्फ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	2021-22
16**	टेक्सटाइल प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
17**	वैगन इंडिया लिमिटेड	परिसमापन के अंतर्गत
18	लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड	2021-22

**ऐसे सीपीएसई जिनके खाते तीन वर्ष या उससे अधिक समय से बकाया हैं या परिसमापन के अधीन हैं।

⁶कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के मास्टर डेटा (अगस्त 2024) के अनुसार कंपनी की स्थिति 'सक्रिय' है।

अनुलग्नक -IV (पैरा संख्या 1.2.2.2 देखें)

उन सरकारी कंपनियों की सूची जिनकी कुल परिसंपत्तियों का मूल्य 31.03.2022 तक बकाया दीर्घकालिक ऋणों से कम था

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड
2	अंडमान फिशरीज लिमिटेड
3	उत्कल अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
4	भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड
5	बिहार ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
6	बिंको लॉरी लिमिटेड
7	बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
8	भारत पेट्रो रिसोर्सेज जेपीडीए लिमिटेड
9	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
10	तथ्य आरसीएफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड
11	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड
12	एचएमटी वॉचेस लिमिटेड
13	होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
14	हिंदुस्तान फोटो फिल्मस (मैन्युफैक्चरिंग) कंपनी लिमिटेड
15	हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड
16	इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड
17	इरकॉन शिव पुरी गुना लिमिटेड
18	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड
19	कर्नाटक विजयनगर स्टील लिमिटेड
20	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
21	भारतीय राष्ट्रीय साइकिल निगम लिमिटेड
22	पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
23	राष्ट्रीय जूट निर्माता निगम लिमिटेड
24	ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड
25	राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
26	टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड
27	टीसीआईएल एलटीआर लिमिटेड
28	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड

अनुलग्नक-V (पैरा संख्या 1.2.4 देखें)

65 सूचीबद्ध सीपीएसई के बाजार पूंजीकरण में वृद्धि और कमी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	बाजार पूंजीकरण 2021-22	बाजार पूंजीकरण 2020-21	अंतर
1	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	2,06,190.78	1,28,507.55	77,683.23
2	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1,51,262.7	1,12,819.23	38,443.47
3	भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड	61,968	28,099.2	33,868.8
4	कोल इंडिया लिमिटेड	1,12,777.93	80,361.98	32,415.95
5	एनटीपीसी लिमिटेड	1,30,856.51	1,03,221.01	27,635.5
6	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,11,981.42	86,421.98	25,559.44
7	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	51,375.56	30,481.78	20,893.78
8	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	49,726.77	33,266.54	16,460.23
9	ऑयल इंडिया लिमिटेड	25,835.95	13,300.23	12,535.72
10	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	22,360.99	9,917.81	12,443.18
11	गेल (इंडिया) लिमिटेड	69,136.8	60,189.42	8,947.38
12	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	40,706.33	32,568.32	8,138.01
13	एनएमडीसी लिमिटेड	47,622.35	39,636.44	7,985.91
14	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	40,968.95	36,390.1	4,578.85
15	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	38,208.6	34,146.86	4,061.74
16	केआईओसीएल लिमिटेड	12,653.38	8,730.34	3,923.04
17	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	10,018.15	6,095.93	3,922.22
18	एनएचपीसी लिमिटेड	27,925.2	24,560.11	3,365.09
19	बीईएमएल लिमिटेड	7,567.43	5,227.84	2,339.59
20	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	8,673.41	6,995.58	1,677.83
21	द फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	8,479.88	7,279.56	1,200.32
22	रेल विकास निगम लिमिटेड	6,818.02	6,067.41	750.61
23	राष्ट्रीय केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	4,943.13	4,275.58	667.55
24	एसजेवीएन लिमिटेड	10,787.29	10,237.12	550.17
25	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	4,832.49	4,287.93	544.56
26	राइट्स लिमिटेड	6,315.13	5,782.86	532.27
27	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	2,592.88	2,119.21	473.67
28	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	7,273.28	6,800.08	473.2

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	बाजार पूंजीकरण 2021-22	बाजार पूंजीकरण 2020-21	अंतर
29	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,901.6	1,490.6	411
30	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	798.26	407.59	390.67
31	एमएमटीसी लिमिटेड	6,622.5	6,360	262.5
32	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	1,420.65	1,185.03	235.62
33	उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	1,709.79	1,477.44	232.35
34	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	17,183.98	16,975.06	208.92
35	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	5,363.68	5,158.72	204.96
36	मोइल लिमिटेड	3,753.28	3,568.22	185.06
37	भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड	582.6	445.8	136.8
38	एमएसटीसी लिमिटेड	2,156.35	2,101.09	55.26
39	आईएफसीआई लिमिटेड	2,334.32	2,280.88	53.44
40	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	987.68	965.68	22
41	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड	18.76	14.78	3.98
42	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	3,251.09	3,293.97	-42.88
43	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	274.47	317.67	-43.2
44	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	10,990.23	11,056.36	-66.13
45	भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	121.34	196.47	-75.13
46	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	187.75	266.34	-78.59
47	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	2,602.52	2,761.96	-159.44
48	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	3,098.6	3,310.3	-211.7
49	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड	819.97	1,038.39	-218.42
50	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	1,928.07	2,205.09	-277.02
51	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	29,687.72	30,004.53	-316.81
52	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	3,738.55	4,154.73	-416.18
53	एचएमटी लिमिटेड	3,124.62	3,696.56	-571.94
54	हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड	3,258.98	3,910.2	-651.22
55	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	3,597.07	4,330.54	-733.47
56	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	3,866.63	4,936.71	-1,070.08
57	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2,699.09	4,069.5	-1,370.41
58	आरईसी लिमिटेड	24,291.49	25,920.8	-1,629.31
59	आईटीआई लिमिटेड	9,027.17	10,744.85	-1,717.68
60	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	6,534	8,388	-1,854
61	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	28,031.95	29,992.22	-1,960.27

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	बाजार पूंजीकरण 2021-22	बाजार पूंजीकरण 2020-21	अंतर
62	आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड	6,546.21	8,788.34	-2,242.13
63	न्यू इंडिया एश्योरेस कंपनी लिमिटेड	18,391.68	25,436.88	-7,045.2
64	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	77,919.56	92,833.17	-14,913.61
65	भारतीय साधारण बीमा निगम	19,982.62	35,009.05	-15,026.43

अनुलग्नक-VI (पैरा संख्या 1.3.1 देखें)

सरकारी कंपनियों और निगमों की सूची जिन्हें 2020-21 में घाटे की तुलना में 2021-22 के दौरान लाभ कमाने वाले सीपीएसई में जोड़ा गया

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	क्या परिचालन लाभ 2021-22 में अर्जित लाभ कमाने का कारण है
1.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	हाँ
2.	एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	हाँ
3.	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड	हाँ
4.	पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसको लिमिटेड	हाँ
5.	पांडिचेरी अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ
6.	बख्तरबंद वाहन निगम लिमिटेड*	हाँ
7.	एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड*	हाँ
8.	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	हाँ
9.	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	हाँ
10.	भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड	नहीं
11.	चंडीगढ़ औद्योगिक एवं पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	नहीं
12.	चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	नहीं
13.	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ
14.	पावरग्रिड भड़ला ट्रांसमिशन लिमिटेड	हाँ
15.	पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	हाँ
16.	सरकारी ई-मार्केट प्लेस	हाँ
17.	ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड*	हाँ
18.	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड	हाँ
19.	एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड	नहीं
20.	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	हाँ
21.	हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ
22.	आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	नहीं
23.	आईएफआईएन क्रेडिट लिमिटेड	नहीं
24.	इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड*	हाँ
25.	इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड	नहीं

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	क्या परिचालन लाभ 2021-22 में अर्जित लाभ कमाने का कारण है
26.	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	नहीं
27.	पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	हाँ
28.	कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	नहीं
29.	एमजेएसजे कोल लिमिटेड	नहीं
30.	डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन	नहीं
31.	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	हाँ
32.	म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड*	हाँ
33.	एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड	नहीं
34.	नई दिल्ली नगर पालिका परिषद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	नहीं
35.	एनएमडीसी सीएसआर फाउंडेशन लिमिटेड	नहीं
36.	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	हाँ
37.	एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड	हाँ
38.	एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड	नहीं
39.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	हाँ
40.	सिडकुल कॉनकॉर इंफ्रा कंपनी लिमिटेड	हाँ
41.	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	नहीं
42.	स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड	हाँ
43.	पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	हाँ
44.	डूप कम्फर्ट्स लिमिटेड*	हाँ
45.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड	नहीं

* क्रमांक 6, 7, 17, 24, 32 और 44 पर स्थित छह कंपनियां नई थीं और उन्होंने 2021-22 के दौरान अपने परिचालन के पहले वर्ष में लाभ दर्ज किया।

अनुलग्नक-VII (पैरा संख्या 1.3.1 देखें)

2021-22 में लाभ अर्जित करने वाली कंपनियों की सूची से बाहर रखी गई सरकारी कंपनियों की सूची

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	क्या 2021-22 में हानि का कारण परिचालन हानि है?
1.	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	हाँ
2.	एंड्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	हाँ
3.	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	हाँ
4.	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड	हाँ
5.	भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड	नहीं
6.	बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	हाँ
7.	बिहार मेगा पावर लिमिटेड	शून्य लाभ
8.	भारत पेट्रो रिसोर्सज जेपीडीए लिमिटेड	हाँ
9.	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	नहीं
10.	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	शून्य लाभ
11.	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	नहीं
12.	हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड	नहीं
13.	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	हाँ
14.	हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड	हाँ
15.	आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड	नहीं
16.	इरकॉन गुडगांव रेवारी हाईवे लिमिटेड	हाँ
17.	भारतीय जूट निगम लिमिटेड	नहीं
18.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड	हाँ
19.	उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड	शून्य लाभ
20.	ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड	हाँ
21.	प्राइज पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड	हाँ
22.	पावरग्रिड साउदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	नहीं
23.	राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	हाँ
24.	सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ
25.	एसजेवीएन थर्मल प्राइवेट लिमिटेड	हाँ
26.	तालचेर फर्टिलाइजर लिमिटेड	हाँ

अनुलग्नक-VIII (पैरा संख्या 1.3.3 देखें)

31 मार्च 2022 तक शून्य या ऋणात्मक निवल संपत्ति वाली सरकारी कंपनियों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	कर पश्चात लाभ	निवल संपत्ति	प्रदत्त पूंजी
1.	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	-1,057.47	-6,266.13	62,365.45
2.	एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड	-447.76	-3,098.55	402.25
3.	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड	837.12	-1,381.51	166.67
4.	अंडमान फिशरीज लिमिटेड	-7.22	-47.78	1
5.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह वन एवं वृक्षारोपण विकास निगम लिमिटेड	-2.61	-24.52	3.59
6.	पांडिचेरी अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.16	-1.71	1.6
7.	रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-0.75	-15.63	4.9
8.	उत्कल अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-0.88	-27.31	1.3
9.	भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड	-68.88	-1,982.54	51.06
10.	भारत पम्प्स एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड	-53.69	-90.42	53.53
11.	बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड	-4.41	-25.07	10.5
12.	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-79.05	-1,304.44	31.71
13.	बिहार ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	-0.49	-45.69	7.77
14.	बिंको लॉरी लिमिटेड	0.89	-114.11	74.76
15.	बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	-5.40	-147.36	0.39
16.	बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड	7.81	-141.1	87.29
17.	बीपीसीएल-केआईएएल फ्यूल फार्म प्राइवेट लिमिटेड	-3.85	-4.65	9
18.	भारत पेट्रो रिसोर्सज जेपीडीए लिमिटेड	-0.31	-56.52	60
19.	बीएसएनएल टावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.00	-2.79	0
20.	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-97.64	-348.92	365.83
21.	चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00	-2.15	0.05
22.	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	-0.01	-0.01	0.05
23.	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	0.00	0	0.05

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	कर पश्चात लाभ	निवल संपत्ति	प्रदत्त पूंजी
24.	छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड	-0.01	0	0.05
25.	सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-24.38	-68.66	10.85
26.	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	0.00	0	0.05
27.	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00	-2.1	0.05
28.	पावरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.31	-0.26	0.05
29.	तथ्य आरसीएफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड	-8.58	-137.71	70.45
30.	गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	-6.67	-11.38	19.02
31.	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड	-16.21	-623.45	71.72
32.	हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-256.07	-844.07	606.08
33.	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड	-6.13	-78.81	19.61
34.	एचएलएल मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल्स लिमिटेड	-0.01	0	0.1
35.	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	-145.73	-1,684.73	276.6
36.	एचएमटी वॉचेस लिमिटेड	1.05	-2,682.28	6.49
37.	हृगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड	-0.04	-5.82	1.03
38.	होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-84.81	-613.86	137.6
39.	हिंदुस्तान फोटो फिल्मस (मैन्युफैक्चरिंग) कंपनी लिमिटेड	-1.88	-23,738.9	206.87
40.	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	50.78	-547.31	301.99
41.	इनलैंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड	-0.89	-0.19	1.05
42.	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	22.26	-367.63	146.05
43.	इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड	0.00	-0.05	0.05
44.	झारखंड राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड	-0.01	-0.08	0.01
45.	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00	-1.92	0.05
46.	कर्नाटक विजयनगर स्टील लिमिटेड	-0.70	-1.91	0.1
47.	लक्षद्वीप पर्यटन विकास निगम	-0.29	-0.25	0.05
48.	लखनऊ सौर ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	1.28	-0.18	1
49.	मणिपुर स्टेट ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	-250.31	-470.99	0.85

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	कर पश्चात लाभ	निवल संपत्ति	प्रदत्त पूंजी
50.	महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	-625.87	-757.51	1.24
51.	महानदी बेसिन पावर लिमिटेड	-0.02	-5.99	0.05
52.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	162.05	-505.39	162.14
53.	एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-1 लिमिटेड	-0.80	-1.62	0.05
54.	मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00	-1.87	0.05
55.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	-2,602.59	-18,656.5	630
56.	नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड	-12.82	-8.26	50
57.	भारतीय राष्ट्रीय साइकिल निगम लिमिटेड	-21.26	-671.48	5.65
58.	पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	-28.33	-40.77	8.5
59.	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड	-4.63	-21.98	35.85
60.	राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना निधि ट्रस्टी लिमिटेड	0.03	-0.1	0.02
61.	राष्ट्रीय जूट निर्माता निगम लिमिटेड	-8.13	-228.52	55.8
62.	एनटीपीसी ईडीएमसी वेस्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	-2.05	-2.76	0.2
63.	उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड	0.00	-0.07	0.05
64.	पीईसी लिमिटेड	-314.29	-2,223.98	60
65.	राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	-2.13	-101.4	4.99
66.	राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.20	-0.1	0.05
67.	रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड	0.00	-0.02	0.01
68.	सांभर साल्ट्स लिमिटेड	10.85	-30.52	1
69.	सिलवासा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	-0.16	-1.9	0.05
70.	शौंगटोंग करछम वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00	0	0.01
71.	भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड	-93.97	-197.57	60
72.	एसटीसीएल लिमिटेड	7.12	-4,557.11	1.5
73.	सूटी टेक ऑप्शंस लिमिटेड	-0.01	-0.32	0.5
74.	तातिया आंध्र मेगा पावर लिमिटेड	0.00	0	0.05
	टांडा ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00	0	0

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	कर पश्चात लाभ	निवल संपत्ति	प्रदत्त पूंजी
75.	टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड	0.08	-40.65	19.57
76.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड	9.57	-98.81	8.44
77.	पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	-0.01	-19.42	0.05
78.	यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	-0.01	-0.08	0.05
79.	यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड	-0.01	-0.04	0.05
	कुल	-5,239.69	-75,186.19	66,682.49

अनुलग्नक- IX (पैरा संख्या 1.3.4 देखें)
सरकारी कंपनियों द्वारा घोषित लाभांश में कमी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	निवल संपत्ति	कर के बाद लाभ	लाभांश घोषित	निवल संपत्ति का 5%	कर पश्चात लाभ का 30%	घोषित किया जाने वाला न्यूनतम लाभांश	कमी
सूचीबद्ध सरकारी कंपनियाँ								
1.	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2,790.14	1,342.42	29.78	139.51	402.73	402.73	372.94
2.	एचएमटी लिमिटेड	426.66	38.36	0.00	21.33	11.51	21.33	21.33
3.	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	40,996.34	6,089.84	1,829.60	2,049.82	1,826.95	2,049.82	220.22
4.	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	1,190.72	176.31	58.08	59.54	52.89	59.54	1.46
5.	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	7,196.34	2,955.27	0.00	359.82	886.58	886.58	886.58
6.	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	13,806.64	1,236.78	416.00	690.33	371.03	690.33	274.33
7.	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	8,820.58	794.79	15.51	441.03	238.44	441.03	425.52
असूचीबद्ध सरकारी कंपनियाँ								
8.	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड	209.14	23.93	7.15	10.46	7.18	10.46	3.30
9.	आंध्र प्रदेश सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड	286.58	71.98	0.00	14.33	21.59	21.59	21.59
10.	ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग	21.14	11.09	1.67	1.06	3.33	3.33	1.66

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	निवल संपत्ति	कर के बाद लाभ	लाभांश घोषित	निवल संपत्ति का 5%	कर पश्चात लाभ का 30%	घोषित किया जाने वाला न्यूनतम लाभांश	कमी
	कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड							
11.	बीईएल-थेल्स सिस्टम्स लिमिटेड	62.85	5.21	1.56	3.14	1.56	3.14	1.58
12.	भारत गैस रिसोर्सेज लिमिटेड	1,799.94	149.84	0.00	90.00	44.95	90.00	90.00
13.	भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड	4,435.73	892.17	0.00	221.79	267.65	267.65	267.65
14.	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड	395.84	21.28	6.43	19.79	6.38	19.79	13.36
15.	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	150.55	42.42	0.00	7.53	12.73	12.73	12.73
16.	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	819.62	62.33	0.00	40.98	18.70	40.98	40.98
17.	चंडीगढ़ औद्योगिक एवं पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	60.82	4.61	0.00	3.04	1.38	3.04	3.04
18.	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	40.05	40.03	0.00	2.00	12.01	12.01	12.01
19.	डीएनएच पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	877.43	105.84	0.00	43.87	31.75	43.87	43.87
20.	दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव एससी/एसटी वितीय और	15.16	4.47	0.00	0.76	1.34	1.34	1.34

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	निवल संपत्ति	कर के बाद लाभ	लाभांश घोषित	निवल संपत्ति का 5%	कर पश्चात लाभ का 30%	घोषित किया जाने वाला न्यूनतम लाभांश	कमी
	विकास निगम लिमिटेड							
21.	ईसीजीसी लिमिटेड	15,375.28	875.16	276.50	768.76	262.55	768.76	492.26
22.	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1,255.73	220.78	33.12	62.79	66.24	66.24	33.12
23.	गेल गैस लिमिटेड	2,430.75	283.36	0.00	121.54	85.01	121.54	121.54
24.	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड	636.42	547.34	0.00	31.82	164.20	164.20	164.20
25.	एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड	143.61	25.18	6.18	7.18	7.55	7.55	1.37
26.	आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	27.14	2.16	0.00	1.36	0.65	1.36	1.36
27.	आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	22.93	3.74	0.00	1.15	1.12	1.15	1.15
28.	इस्कॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	239.90	60.16	0.00	12.00	18.05	18.05	18.05
29.	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	239.09	24.66	4.05	11.95	7.40	11.95	7.91
30.	कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड	1,865.75	131.84	25.06	93.29	39.55	93.29	68.23
31.	कुमारकृष्णा फ्रंटियर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड	27.29	4.16	0.97	1.36	1.25	1.36	0.39
32.	लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड	388.64	23.56	0.00	19.43	7.07	19.43	19.43

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	निवल संपत्ति	कर के बाद लाभ	लाभांश घोषित	निवल संपत्ति का 5%	कर पश्चात लाभ का 30%	घोषित किया जाने वाला न्यूनतम लाभांश	कमी
33.	नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	24.39	7.49	0.00	1.22	2.25	2.25	2.25
34.	एनएमडीसी सीएसआर फाउंडेशन लिमिटेड	6.04	1.02	0.00	0.30	0.31	0.31	0.31
35.	न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड	1,441.77	342.99	0.00	72.09	102.90	102.90	102.90
36.	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड	562.57	150.26	30.00	28.13	45.08	45.08	15.08
37.	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	46,147.08	6,394.78	1,897.00	2,307.35	1,918.43	2,307.35	410.35
38.	ओमनीबस औद्योगिक विकास निगम दमन, दीव और दादरा और नगर हवेली लिमिटेड	232.93	24.50	0.00	11.65	7.35	11.65	11.65
39.	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	35,681.78	3,247.53	480.00	1,784.09	974.26	1,784.09	1,304.09
40.	प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड	167.40	10.81	3.24	8.37	3.24	8.37	5.13
41.	रेलटेल एंटरप्राइजेज लिमिटेड	21.39	1.30	0.00	1.07	0.39	1.07	1.07
42.	रिचर्डसन और क्रुडास (1972) लिमिटेड	247.31	19.35	0.00	12.37	5.80	12.37	12.37

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	निवल संपत्ति	कर के बाद लाभ	लाभांश घोषित	निवल संपत्ति का 5%	कर पश्चात लाभ का 30%	घोषित किया जाने वाला न्यूनतम लाभांश	कमी
43.	रिन्यूएबल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड	5.74	1.99	0.00	0.29	0.60	0.60	0.60
44.	टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड	612.79	30.33	12.13	30.64	9.10	30.64	18.51
45.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	1,505.82	942.41	0.00	75.29	282.72	282.72	282.72
	कुल	1,93,711.79	27,445.81	5,134.03	9,685.59	8,233.74	10,945.54	5,811.51

अनुलग्नक- X (पैरा संख्या 1.3.4 देखें)

सीपीएसई का विवरण जिन्हें लाभांश घोषित करना आवश्यक नहीं

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	कर पश्चात लाभ
1	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम	64.15
2	जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद	9.00
3	भारत के प्रतिभूतिकरण, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित की केंद्रीय रजिस्ट्री	65.57
4	क्रिएटिव म्यूजियम डिजाइनर	4.16
5	रक्षा नवाचार संगठन	0.00
6	डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन	1.43
7	सरकारी ई-मार्केट प्लेस	104.07
8	उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी	447.52
9	इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड	0.94
10	भारत व्यापार संवर्धन संगठन	-52.83
11	कर्नाटक व्यापार संवर्धन संगठन	1.32
12	कर्मयोगी भारत	प्रथम खाते बकाया नहीं
13	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	30.56
14	राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम	6.20
15	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक.	46.17
16	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम	67.64
17	भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम लिमिटेड	0.05
18	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम	15.92
19	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम	48.78
20	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	24.45
21	तमिलनाडु व्यापार संवर्धन संगठन	3.89

अनुलग्नक-XI (पैरा संख्या 1.4.1 देखें)
सरकारी कंपनियों और निगमों द्वारा नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
1	एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड							2,573.47	6.16	0.24
2	एगीनोवेटिव इंडिया लिमिटेड	69.68	3.76	5.40	71.07	1.86	2.62	72.61	2.06	2.84
3	एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	403.18	133.86	33.20	184.40	-223.09	-120.98	361.65	-1.94	-0.54
4	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड	-2,178.67	107.20	-4.92	-2,218.34	-9.58	-0.43	776.78	575.28	74.06
5	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	22,119.07	3,808.64	17.22	22,162.77	2,327.83	10.50	8,718.88	1,974.15	22.64
6	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	15,544.36	3,817.08	24.56	14,747.17	-2,726.42	-18.49	15,379.24	97.16	0.63

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
7	एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड	-2,256.66	-56.01	-2.48	-2,651.16	-198.69	-7.49	-3,098.55	-262.71	-8.48
8	अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड				0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
9	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह वन एवं वृक्षारोपण विकास निगम लिमिटेड	-21.02	-1.03	-4.90	-21.91	-0.89	-4.06	-24.52	-2.61	-10.64
10	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड	180.03	46.71	25.95	192.35	26.41	13.73	209.14	32.77	15.67
11	अंडमान फिशरीज लिमिटेड	-0.04	-0.02	-50.00	-0.06	-0.02	-33.33	-0.09	-0.02	-22.22

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
12	आंध्र प्रदेश सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड	159.18	88.03	55.30	215.12	83.06	38.61	286.58	97.59	34.05
13	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	168.28	-13.81	-8.21	190.68	22.80	11.96	189.97	17.02	8.96
14	अंगुल सुकिंदा रेलवे लिमिटेड	1,160.30	-0.08	-0.01	1,649.81	0.00	0.00	2,240.49	0.64	0.03
15	एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,596.57	297.04	18.60	1,567.31	77.22	4.93	1,513.87	36.24	2.39
16	अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
17	अपोलो डिज़ाइन अपैरल पार्क्स लिमिटेड	123.49	13.59	11.00	122.50	-0.99	-0.81	122.50	-0.99	-0.81
18	बख्तरबंद वाहन निगम लिमिटेड							12,302.08	73.65	0.60
19	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम	483.29	85.68	17.73	533.64	52.26	9.79	599.26	64.15	10.70

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
20	औरंगाबाद टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क्स लिमिटेड	14.05	-0.79	-5.62	13.30	-0.78	-5.86	13.30	-0.78	-5.86
21	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	1,328.21	229.71	17.29	1,310.66	159.57	12.17	1,319.86	171.98	13.03
22	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड	176.31	85.80	48.66	167.16	86.13	51.53	159.96	67.80	42.39
23	बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	26,274.39	-486.70	-1.85	30,693.07	-797.12	-2.60	34,473.66	-519.32	-1.51
24	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	294.06	1.44	0.49	294.60	0.73	0.25	293.71	-1.18	-0.40
25	बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड	236.27	4.45	1.88	240.52	7.57	3.15	244.32	7.91	3.24

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
26	बीईएल-थेल्स सिस्टम्स लिमिटेड	54.50	4.64	8.51	57.65	3.98	6.90	62.85	5.60	8.91
27	बीईएमएल लैंड एसेट्स लिमिटेड							0.00	-0.01	0.00
28	बीईएमएल लिमिटेड	2,382.59	33.18	1.39	2,273.39	105.22	4.63	2,280.73	233.90	10.26
29	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	139.99	15.04	10.74	146.08	7.74	5.30	76.96	9.24	12.01
30	बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड	48.91	-1.09	-2.23	71.82	-2.09	-2.91	250.31	-5.78	-2.31
31	भड़ला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड				0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
32	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड	85.96	3.21	3.73	87.41	2.17	2.48	84.92	-2.49	-2.93
33	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	4,297.66	1,180.59	27.47	3,088.81	-1,512.16	-48.96	3,273.77	191.31	5.84

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
34	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	2,606.83	742.45	28.48	2,684.75	340.88	12.70	3,030.56	709.91	23.43
35	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	9,852.94	2,479.17	25.16	10,761.20	2,934.81	27.27	11,984.26	3,157.80	26.35
36	भारत गैस रिसोर्सेज लिमिटेड	299.74	2.94	0.98	900.10	0.35	0.04	1,799.94	205.25	11.40
37	भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड	-102.76	30.52	-29.70	-120.16	217.63	-181.12	-123.04	1.02	-0.83
38	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	29,221.40	-590.52	-2.02	26,448.87	-3,571.49	-13.50	2,6971.16	484.34	1.80
39	भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	20.47	-10.15	-49.58	41.04	-19.85	-48.37	50.18	-4.59	-9.15

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
40	भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड				11,272.86	405.93	3.60	11,240.31	2,766.18	24.61
41	भारत पेट्रो रिसोर्सेज जेपीडीए लिमिटेड	-68.44	-4.10	-5.99	-1.67	12.24	-732.93	-1.97	-0.31	-15.74
42	भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड	5,771.80	-798.95	-13.84	4380.12	-1,600.31	-36.54	5,582.33	131.14	2.35
43	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	58,431.48	3,221.76	5.51	70,333.31	22,393.64	31.84	63,837.42	12,176.00	19.07
44	भारत पम्प्स एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड	-188.84	-0.26	-0.14	-202.49	-70.77	-34.95	-90.42	-46.84	-51.80
45	भारत संचार निगम लिमिटेड	48,306.21	-13,985.50	-28.95	46,012.06	-5,372.42	-11.68	34,441.88	-4,825.16	-14.01
46	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड	5,891.95	0.10	0.00	5,518.93	0.29	0.01	5,869.04	0.24	0.00

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
47	भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड	8,191.89	667.18	8.14	6,309.35	757.24	12.00	7,681.85	820.15	10.68
48	बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड	-20.65	-5.42	-26.25	-25.07	-2.79	-11.13	-25.07	-2.79	-11.13
49	बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड				0.07	0.03	42.86	0.07	-0.01	-14.29
50	बिंको लॉरी लिमिटेड	-3.26	-3.34	-102.45	10.66	11.59	108.72	11.55	0.89	7.71
51	बिहार ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	-30.16	-0.49	-1.62	-30.16	-0.49	-1.62	-30.16	-0.49	-1.62
52	बिहार इंफ्रा पावर लिमिटेड	0.06	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00
53	बिहार मेगा पावर लिमिटेड	48.63	0.00	0.00	49.48	0.00	0.00	50.27	0.00	0.00

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
54	बिजावर विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
55	जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद	112.53	7.95	7.06	120.65	6.79	5.63	130.13	9.00	6.92
56	बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	-11.13	0.19	-1.71	-11.92	-0.71	-5.96	-12.16	-0.60	-4.93
57	बीपीसीएल-केआईएएल फ्यूल फार्म प्राइवेट लिमिटेड	13.35	-0.89	-6.67	9.72	-5.05	-51.95	5.32	-2.90	-54.51
58	ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड	4,424.17	2,097.87	47.42	4,747.07	1,244.12	26.21	3,390.03	994.53	29.34
59	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	459.22	-129.70	-28.24	321.47	-137.75	-42.85	223.83	-97.64	-43.62

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
60	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	93.81	24.13	25.72	118.13	31.23	26.44	150.55	46.70	31.02
61	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड	377.75	85.07	22.52	376.67	44.70	11.87	395.84	62.99	15.91
62	ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	7.58	3.13	41.29	11.32	9.60	84.81	111.85	25.86	23.12
63	बीएसएनएल टावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-2.80	-0.03	-1.07	-2.79	0.01	-0.36	-2.79	-0.01	-0.36
64	उंडेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड	9.41	-0.01	-0.11	48.67	-0.18	-0.37	155.03	-0.88	-0.57
65	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड	184.63	0.47	0.25	184.63	-0.05	-0.03	184.63	-0.05	-0.03
66	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	128.81	-50.94	-39.55	121.10	13.15	10.86	162.34	40.20	24.76

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
67	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	6,391.53	2,932.72	45.88	7,548.53	1,913.18	25.35	8,411.98	2,094.73	24.90
68	सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-13.58	-9.27	-68.26	-44.33	-29.81	-67.25	-68.66	-23.96	-34.90
69	सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	84.39	10.55	12.50	107.71	36.57	33.95	122.34	36.62	29.93
70	केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड	42.42	2.85	6.72	56.17	14.85	26.44	56.50	1.32	2.34
71	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड	570.31	312.62	54.82	784.47	414.49	52.84	995.62	366.04	36.77
72	भारत के प्रतिभूतिकरण,	825.33	114.90	13.92	869.95	62.56	7.19	935.51	88.66	9.48

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
	परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित की केंद्रीय रजिस्ट्री									
73	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड				0.02	-0.03	-150.00	40.05	53.49	133.56
74	केंद्रीय भंडारण निगम	2,789.26	409.67	14.69	2,868.61	565.54	19.71	3,088.15	589.73	19.10
75	सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड	78.60	13.98	17.79	80.67	15.02	18.62	79.30	11.25	14.19
76	चंडीगढ़ औद्योगिक एवं पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	58.23	0.57	0.98	56.53	3.97	7.02	60.82	0.84	1.38
77	चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.10	-1.59	-1590.00	200.00	-0.55	-0.28	203.44	1.78	0.87

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
78	चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	-2.14	-0.44	-20.56	-2.15	-0.01	-0.47	-2.15	0.00	0.00
79	चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड	17,576.46	-396.93	-2.26	17,195.61	-477.99	-2.78	18,705.29	-539.73	-2.89
80	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4,144.96	-2,664.84	-64.29	4,442.43	1,651.58	37.18	5181.69	2,244.08	43.31
81	चेन्नई इन्फ्रा लिमिटेड	0.08	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00
82	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83	छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड	-0.04	-0.04	-100.00	0.06	-0.11	-183.33	0.05	-0.10	-200.00
84	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	2,299.31	8.79	0.38	2,675.20	21.59	0.81	3,084.81	5.98	0.19
85	छत्तीसगढ़ पूर्व पश्चिम रेलवे लिमिटेड	671.92	-0.11	-0.02	1,029.87	-0.27	-0.03	1,500.41	-0.28	-0.02

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
86	छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड	0.01	-0.01	-100.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00
87	सीआईएल नवकरणीय ऊर्जा लिमिटेड							0.05	0.00	0.00
88	सीआईएल सोलर पीवी लिमिटेड							0.05	0.00	0.00
89	कोल इंडिया लिमिटेड	16,813.30	11,299.26	67.20	1,6751.71	7,673.98	45.81	16,357.95	11,358.34	69.44
90	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-100.00
91	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	141.39	0.00	0.00	149.29	0.00	0.00	157.58	0.00	0.00
93	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	3,835.48	863.43	22.51	4,081.25	810.59	19.86	4,462.86	794.39	17.80

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
94	कॉनकॉर एयर लिमिटेड	36.84	11.81	32.06	33.91	-2.07	-6.10	24.24	-9.21	-38.00
95	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	10,064.74	530.14	5.27	10,203.74	679.10	6.66	10,777.30	1,407.02	13.06
96	क्रिएटिव म्यूजियम डिजाइनर	17.78	2.94	16.54	20.91	3.41	16.31	10.19	4.16	40.82
97	क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	244.33	36.37	14.89	236.53	28.80	12.18	235.66	29.63	12.57
98	दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव एससी/एसटी वित्तीय और विकास निगम लिमिटेड	10.37	1.33	12.83	11.60	0.33	2.84	15.16	4.47	29.49
99	दामोदर घाटी निगम	22,072.80	3,192.79	14.46	21,621.75	2,821.45	13.05	23,413.91	2,552.13	10.90

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
100	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	36,713.51	978.93	2.67	41,109.34	1,369.35	3.33	48,416.84	1,521.39	3.14
101	रक्षा नवाचार संगठन	61.82	0.00	0.00	85.81	0.00	0.00	123.77	0.00	0.00
102	दिल्ली मेट्रो लास्ट माइल सर्विसेज लिमिटेड	-0.01	-0.01	100.00	0.08	-0.01	-12.50	0.07	-0.01	-14.29
103	दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	71,277.51	-193.90	-0.27	69,613.92	-3,117.90	-4.48	67,461.06	-4,288.10	-6.36
104	दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	12.33	0.80	6.49	12.82	0.67	5.23	12.98	0.22	1.69
105	देवघर इंफ्रा लिमिटेड	0.32	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
106	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	20.32	0.00	0.00	23.16	0.00	0.00	23.85	0.00	0.00
107	डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन	42.24	0.00	0.00	36.27	0.00	0.00	33.35	1.43	4.29
108	दीव स्मार्ट सिटी लिमिटेड	1.96	0.00	0.00	1.99	0.03	1.51	2.02	0.03	1.49
109	डीएनएच पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	541.68	18.50	3.42	771.58	270.19	35.02	877.43	118.45	13.50
110	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	-2.08	-0.19	9.13	-2.09	-0.01	0.48	-2.10	0.00	0.00
111	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	3,842.69	1,501.35	39.07	2,980.50	-907.26	-30.44	1,964.75	-1,437.37	-73.16
112	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	269.64	-0.72	-0.27	270.43	0.46	0.17	269.99	0.27	0.10

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
113	ईसीजीसी लिमिटेड	12,687.73	399.97	3.15	13,765.91	582.65	4.23	15,375.28	1,131.02	7.36
114	एडसिल (इंडिया) लिमिटेड	148.73	56.19	37.78	173.00	49.44	28.58	211.79	71.33	33.68
115	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1,011.88	89.86	8.88	1,078.42	156.42	14.50	1,255.73	301.66	24.02
116	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड	198.54	14.05	7.08	148.52	-35.77	-24.08	83.46	-59.83	-71.69
117	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	2,345.46	675.51	28.80	1,701.01	350.57	20.61	1,925.05	447.84	23.26
118	तथ्य आरसीएफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड	-76.61	-66.67	-87.03	-77.23	-0.61	-0.79	-79.87	-2.58	-3.23
119	फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड	216.92	47.28	21.80	226.68	32.32	14.26	212.00	54.18	25.56

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
120	फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	580.81	53.89	9.28	631.86	61.46	9.73	666.50	42.97	6.45
121	भारतीय खाद्य निगम	2,88,068.65	19,615.34	6.81	42,500.33	29,067.72	68.39	45,004.55	3,715.06	8.25
122	फ्रेश एंड हेल्दी एंटरप्राइजेज लिमिटेड	36.39	-5.95	-16.35	31.56	-4.84	-15.34	33.29	-3.73	-11.20
123	गेल (इंडिया) लिमिटेड	47,493.40	8,048.96	16.95	51,333.45	6,656.33	12.97	60,416.88	13,895.52	23.00
124	गेल गैस लिमिटेड	1,863.69	212.84	11.42	2,511.28	233.52	9.30	3,065.96	416.42	13.58
125	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	1,040.23	225.15	21.64	1,137.12	207.12	18.21	1,248.60	257.24	20.60
126	जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1,09,624.35	-445.97	-0.41	1,27,917.40	3163.38	2.47	1,39,087.47	3,560.14	2.56

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
127	घोगरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	15.01	0.00	0.00	15.01	0.00	0.00	15.01	0.00	0.00
128	ग्लाडर्स इंडिया लिमिटेड							529.96	0.96	0.18
129	गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	8.50	-6.11	-71.88	-3.80	-10.88	286.32	-10.06	-5.69	56.56
130	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	1,025.24	282.51	27.56	1,098.26	172.33	15.69	1,148.40	135.43	11.79
131	गोल्डमोहर डिज़ाइन एंड अपैरल पार्क्स लिमिटेड	117.55	11.60	9.87	116.03	-1.63	-1.40	116.03	-1.63	-1.40
132	सरकारी ई-मार्केट प्लेस	0.01	-3.14	-31,400.00	0.01	-4.76	-47,600.00	98.83	140.24	141.90
133	ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड	451.79	74.72	16.54	468.36	26.92	5.75	508.19	60.13	11.83

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
134	हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड	2,370.78	0.20	0.01	2,664.53	98.60	3.70	2,558.30	164.37	6.42
135	हरिद्वार नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड	107.94	-2.62	-2.43	169.16	1.24	0.73	155.99	5.77	3.70
136	हसन मैंगलोर रेल विकास कंपनी लिमिटेड	379.63	23.27	6.13	347.60	-26.00	-7.48	307.60	-34.79	-11.31
137	हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड	97.18	4.45	4.58	116.19	26.38	22.70	100.29	-12.19	-12.15
138	हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-400.73	-381.13	-95.11	-582.25	-165.01	-28.34	-844.07	-245.31	-29.06
139	हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड	285.08	-0.79	-0.28	417.63	-8.77	-2.10	440.25	-12.82	-2.91

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
140	हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.13	0.06	46.15	2.42	-0.19	-7.85	46.71	2.50	5.35
141	उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी	6,465.87	321.46	4.97	8,043.15	551.05	6.85	7,861.84	551.06	7.01
142	हिमाचल रिन्यूएबल्स लिमिटेड	4.40	0.06	1.36	4.52	0.13	2.88	4.59	0.10	2.18
143	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	13,189.93	3,928.35	29.78	15,356.55	4,270.89	27.81	19,264.00	5,289.29	27.46
144	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड	-178.83	-0.01	-0.01	-217.08	-24.96	-11.50	-91.63	-2.91	-3.18
145	हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड	-300.79	13.88	-4.61	-31.23	269.56	-863.14	57.16	88.39	154.64
146	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	949.38	-477.56	-50.30	1297.92	149.60	11.53	998.73	410.70	41.12

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
147	हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	138.23	12.64	9.14	147.65	11.01	7.46	150.16	3.20	2.13
148	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड	-47.32	-2.38	-5.03	-72.64	-24.07	-33.14	-78.81	-5.49	-6.97
149	हिंदुस्तान कीटनाशक लिमिटेड	104.43	19.80	18.96	185.41	22.70	12.24	172.52	28.50	16.52
150	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	511.18	-38.42	-7.52	526.46	68.74	13.06	505.80	27.83	5.50
151	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	52,719.30	2,289.78	4.34	62,630.83	15,082.64	24.08	73,028.96	8,991.03	12.31

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
152	हिंदुस्तान फोटो फिल्मस (मैन्युफैक्चरिंग) कंपनी लिमिटेड	-23,499.17	-2.35	-0.01	-23,499.54	-0.37	0.00	-23,501.42	-1.88	-0.01
153	हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड	19.20	-15.45	-80.47	20.88	1.08	5.17	8.63	-12.25	-141.95
154	हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड	48.39	2.18	4.51	50.64	8.81	17.40	52.06	4.14	7.95
155	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	-26.41	14.52	-54.98	-53.95	-79.45	147.27	-6.10	68.15	-1117.21
156	हिंदुस्तान स्टील्स वर्क्स लिमिटेड	115.22	39.01	33.86	125.61	32.57	25.93	146.06	37.65	25.78
157	हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड	6,660.10	0.07	0.00	13,598.89	-15.93	-0.12	17,697.59	-18.83	-0.11
158	हिंदुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स	9.88	1.02	10.32	10.14	0.41	4.04	10.14	0.41	4.04

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
	कॉर्पोरेशन लिमिटेड									
159	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड	433.86	-59.01	-13.60	397.03	7.14	1.80	636.42	671.72	105.55
160	एचएलएल इंफ्राटेक सर्विसेज लिमिटेड	19.05	42.20	221.52	19.81	15.41	77.79	30.70	24.04	78.31
161	एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड	616.96	155.68	25.23	408.58	172.84	42.30	768.91	572.10	74.40
162	एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड	4.37	-0.77	-17.62	3.52	-0.76	-21.59	3.19	1.64	51.41
163	एचएलएल मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल्स लिमिटेड	-1.90	-2.79	-146.84	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00
164	एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड	36.33	3.88	10.68	37.17	1.20	3.23	36.78	0.28	0.76

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
165	एचएमटी लिमिटेड	977.06	248.18	25.40	1,020.42	48.80	4.78	1,068.27	46.82	4.38
166	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	-1,408.05	-19.10	-1.36	-1,539.84	-49.67	-3.23	-1,684.73	-61.49	-3.65
167	एचएमटी वॉचेस लिमिटेड	7.76	1.85	23.84	10.46	2.70	25.81	11.50	1.05	9.13
168	हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	61.81	-2.52	-4.08	142.65	-4.08	-2.86	170.82	-3.82	-2.24
169	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड	-2.52	162.75	-6,458.33	0.28	3.90	1,392.86	2.82	6.58	233.33
170	हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड	-5.05	-1.48	-29.31	-5.78	-0.73	-12.63	-5.82	-0.04	-0.69
171	होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-432.99	-29.47	-6.81	-529.61	-62.18	-11.74	-110.90	-36.53	-32.94
172	आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड	63,588.64	7,022.34	11.04	64,153.67	6,993.46	10.90	58,986.01	6,878.47	11.66

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
173	एचपीसीएल बायो फ्यूल्स लिमिटेड	250.25	-38.67	-15.45	400.89	-40.98	-10.22	310.18	-44.04	-14.20
174	एचपीसीएल एलएनजी लिमिटेड							1,522.53	-14.03	-0.92
175	एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड	3,269.63	30.74	0.94	6,724.37	178.96	2.66	15,505.44	514.58	3.32
176	एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड	109.78	64.24	58.52	117.74	13.61	11.56	143.61	33.21	23.13
177	आईटीआई लिमिटेड	1,105.12	277.25	25.09	1,233.52	155.42	12.60	1,232.92	286.78	23.26
178	आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड	283.80	21.93	7.73	273.97	5.81	2.12	264.35	6.22	2.35
179	आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	69.57	-1.17	-1.68	68.39	-1.59	-2.32	69.74	1.08	1.55

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
180	आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड	513.74	16.15	3.14	505.04	8.66	1.71	506.80	10.15	2.00
181	आईएफसीआई लिमिटेड	13,827.87	1,275.44	9.22	8,895.01	-1,028.26	-11.56	6,540.74	-862.22	-13.18
182	आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड	268.72	7.64	2.84	242.03	12.17	5.03	179.79	1.83	1.02
183	आईएफआईएन कमोडिटीज लिमिटेड	5.15	-0.27	-5.24	4.74	-0.38	-8.02	4.13	-0.66	-15.98
184	आईएफआईएन क्रेडिट लिमिटेड	1.98	0.04	2.02	1.97	-0.01	-0.51	1.98	0.00	0.00
185	आईएफआईएन सिक्योरिटीज फाइनेंस लिमिटेड	28.59	-0.22	-0.77	28.66	0.23	0.80	28.96	0.43	1.48

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
186	आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	23.24	1.09	4.69	24.74	1.98	8.00	27.14	2.89	10.65
187	आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	16.22	2.10	12.95	18.55	3.32	17.90	22.93	5.14	22.42
188	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	46,477.54	1,897.30	4.08	49,700.55	2544.61	5.12	51,537.78	2,935.32	5.70
189	इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड	1,920.32	8.14	0.42	2,353.21	0.82	0.03	3,051.17	1.33	0.04
190	भारत ऑप्टेल लिमिटेड							5,778.55	84.80	1.47

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
191	इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड	10.00	-1.16	-11.60	10.00	-0.99	-9.90	10.00	6.51	65.10
192	इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड	574.01	-446.47	-77.78	461.61	-326.89	-70.82	473.06	-169.47	-35.82
193	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	346.49	42.68	12.32	319.87	-23.79	-7.44	319.26	10.43	3.27
194	भारत व्यापार संवर्धन संगठन	2,346.34	92.00	3.92	2,367.04	-81.37	-3.44	2,371.44	-52.83	-2.23
195	इंडिया यूनाइटेड टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड	163.25	13.27	8.13	173.54	13.74	7.92	173.54	13.74	7.92
196	इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	74.98	0.46	0.61	85.90	15.71	18.29	117.89	45.41	38.52

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
197	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,43,492.05	2,285.34	1.59	1,56,130.19	32,175.58	20.61	1,92,637.33	34,200.93	17.75
198	भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड	1,327.82	745.35	56.13	1,466.95	269.04	18.34	1,883.88	889.51	47.22
199	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	2,59,213.85	17,803.46	6.87	3,51,407.03	21,953.71	6.25	4,12,985.23	14,654.16	3.55
200	इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड	957.10	402.93	42.10	1,167.47	415.08	35.55	1,548.15	746.63	48.23
201	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड	24,115.76	1,590.02	6.59	26,275.93	2,008.72	7.64	32,374.35	2,360.64	7.29
202	भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड	3,441.03	-100.46	-2.92	3,340.52	-100.51	-3.01	3,255.38	-99.31	-3.05

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
203	इंडियन वैक्सीन्स कंपनी लिमिटेड	8.28	-0.45	-5.43	8.24	-0.04	-0.49	4.54	-2.42	-53.30
204	इंडो-रूसी हेलिकॉप्टर्स लिमिटेड	8.71	-0.34	-3.90	7.92	-0.80	-10.10	7.59	-0.33	-4.35
205	इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड	42.57	-7.18	-16.87	289.60	2.82	0.97	577.55	2.45	0.42
206	इनलैंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड	-0.05	0.00	0.00	0.70	-0.25	-35.71	0.31	-0.89	-287.10
207	इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड	159.92	45.72	28.59	194.68	34.79	17.87	204.43	26.75	13.09
208	इरकॉन अक्लोली-शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड							0.05	0.00	0.00
209	इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	436.82	18.64	4.27	506.80	26.15	5.16	560.97	35.45	6.32

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
210	इरकाँन गुडगांव रेवारी हाईवे लिमिटेड				0.06	0.00	0.00	18.40	0.00	0.00
211	इरकाँन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	153.89	14.86	9.66	159.64	14.11	8.84	164.94	13.39	8.12
212	इरकाँन इंटरनेशनल लिमिटेड	6,007.05	690.98	11.50	4,406.48	574.02	13.03	4,620.96	610.50	13.21
213	इरकाँन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड							0.05	0.00	0.00
214	इरकाँन पीबी टोलवे लिमिटेड	528.91	2.78	0.53	425.28	-13.10	-3.08	410.07	-9.18	-2.24
215	इरकाँन शिव पुरी गुना लिमिटेड	628.68	22.08	3.51	599.75	27.44	4.58	554.76	29.46	5.31
216	इरकाँन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	317.06	6.62	2.09	707.52	18.15	2.57	760.44	122.31	16.08

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
217	आईआरईएल आईडीसीओएल लिमिटेड	0.08	-0.01	-12.50	1.01	-0.03	-2.97	1.87	-0.05	-2.67
218	आईटीपीओ सर्विसेज लिमिटेड				0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
219	जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड	161.09	8.53	5.30	163.11	3.90	2.39	165.42	3.81	2.30
220	जम्मू और कश्मीर खनिज विकास निगम लिमिटेड	10.08	-3.65	-36.21	8.74	-1.35	-15.45	7.83	-0.90	-11.49
221	जल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड				0.00	-1120.36		281.49	-0.35	-0.12
222	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	56.94	1.77	3.11	90.86	2.16	2.38	448.77	3.03	0.68

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
223	झारखंड इंफ्रा पावर लिमिटेड	0.06	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00
224	झारखंड राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड	-0.07	-0.01	-14.29	-0.07	-0.01	-14.29	-0.08	-0.01	-12.50
225	जोगीघोषा लॉजिस्टिक्स पार्क लिमिटेड							0.01	0.00	0.00
226	कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड	3,697.85	392.19	10.61	3,719.96	407.77	10.96	3,477.90	367.59	10.57
227	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	205.62	32.65	15.88	222.72	31.48	14.13	239.84	33.16	13.83
228	कर्नाटक सौर ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	97.41	60.54	62.15	178.90	61.04	34.12	210.36	67.15	31.92

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
229	कर्नाटक व्यापार संवर्धन संगठन	140.06	6.79	4.85	143.14	3.08	2.15	144.46	1.32	0.91
230	कर्नाटक विजयनगर स्टील लिमिटेड	641.24	-0.49	-0.08	640.77	-0.68	-0.11	640.42	-0.70	-0.11
231	कावारती स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
232	केआईओसीएल लिमिटेड	1,915.93	63.68	3.32	1,985.99	410.23	20.66	2,152.64	412.75	19.17
233	किशतवाड़ ट्रांसमिशन लिमिटेड							0.01	0.00	0.00
234	कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड	5,554.47	-153.84	-2.77	6,442.58	-147.69	-2.29	6,701.44	-152.57	-2.28
235	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	-1.91	-0.41	-21.47	-1.92	-0.01	-0.52	-1.92	0.00	0.00

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
236	कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5,605.13	-236.89	-4.23	7,446.57	0.00	0.00	8,298.10	0.06	0.00
237	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4,243.26	161.47	3.81	4,250.91	-161.94	-3.81	4,609.97	102.34	2.22
238	कुमारकृष्णा फ्रंटियर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड	26.55	12.41	46.74	24.70	6.87	27.81	27.29	5.84	21.40
239	लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड	335.94	42.50	12.65	365.08	34.34	9.41	388.64	28.61	7.36
240	लक्षद्वीप पर्यटन विकास निगम	4.70	-0.28	-5.96	4.70	-0.28	-5.96	4.70	-0.28	-5.96
241	लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड	921.76	-2,818.13	-305.73	997.16	-0.21	-0.02	1,440.50	-0.20	-0.01
242	लोकतक डाउन स्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक	143.27	0.13	0.09	151.88	0.01	0.01	160.21	0.01	0.01

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
	कॉर्पोरेशन लिमिटेड									
243	लखनऊ सौर ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	-3.11	1.91	-61.41	-1.46	2.28	-156.16	-0.18	1.78	-988.89
244	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	-76.65	-62.89	-82.05	-139.93	79.18	-56.59	49.92	235.12	470.99
245	महानदी बेसिन पावर लिमिटेड	-5.94	-0.03	-0.51	-5.97	-0.03	-0.50	-5.99	-0.02	-0.33
246	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	-0.81	-0.83	-102.47	-0.87	-0.06	-6.90	89.07	-0.02	-0.02
247	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	3,884.30	8,646.24	222.59	5,538.07	9,328.56	168.44	8,216.86	11,462.43	139.50
248	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	-1,031.50	- 1,810.30	-175.50	2,132.30	-460.63	-21.60	-2,090.91	-598.55	-28.63
249	महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड	-131.37	-0.03	--0.02	-131.40	-0.03	0.02	-757.51	-523.77	-69.14

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
	फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड									
250	महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	9,890.01	-61.96	-0.63	12,986.25	-164.72	-1.27	14,206.69	-260.27	-1.83
251	महाराष्ट्र रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	92.86	0.31	0.33	101.43	1.81	1.78	614.18	5.69	0.93
252	मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड	-1.86	-0.40	-21.51	-1.87	-0.01	-0.53	-1.87	0.00	0.00
253	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	15,751.05	-3,212.84	-20.40	17,450.61	-345.10	-1.98	21,411.84	3,573.81	16.69
254	मणिपुर स्टेट ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	-183.77	-30.86	-16.79	-220.68	0.00	0.00	-470.99	-172.01	-36.52

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
255	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	2,590.88	766.69	29.59	2,919.01	629.92	21.58	3,321.31	772.69	23.26
256	मेकॉन लिमिटेड	398.24	87.49	21.97	371.09	19.63	5.29	382.93	20.16	5.26
257	मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड	5.37	0.35	6.52	5.50	0.19	3.45	5.69	0.27	4.75
258	मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	567.04	198.61	35.03	674.06	201.07	29.83	679.06	28.49	4.20
259	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	958.57	202.40	21.11	1072.63	238.09	22.20	1,190.72	243.75	20.47
260	एमजेएसजे कोल लिमिटेड	74.48	-19.61	-26.33	74.04	-0.44	-0.59	74.13	0.09	0.12
261	एमएमटीसी लिमिटेड	1,350.84	-88.55	-6.56	422.46	-896.23	-212.15	193.40	326.43	168.78
262	एमएनएच शक्ति लिमिटेड	89.41	2.86	3.20	90.69	1.71	1.89	41.55	1.15	2.77

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
263	मोहनलाल गंज ट्रांसमिशन लिमिटेड							0.01	0.00	0.00
264	मोडल लिमिटेड	2,763.38	340.49	12.32	2,819.90	240.11	8.51	2,141.51	523.29	24.44
265	एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज- I लिमिटेड				-0.82	-0.87	106.10	-1.62	-0.80	49.38
266	एमएसटीसी लिमिटेड	283.22	156.95	55.42	359.28	115.52	32.15	471.36	222.69	47.24
267	मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	13,296.01	-28.09	-0.21	15,051.22	-20.11	-0.13	17,746.05	-24.37	-0.14
268	मुंबई रेल विकास निगम लिमिटेड	244.34	19.60	8.02	240.30	23.25	9.68	235.19	7.57	3.22
269	म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड							6,549.75	25.40	0.39
270	नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	14,597.07	384.28	2.63	15,382.27	1,278.51	8.31	16,323.38	1,675.33	10.26

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
271	नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड	15.34	-9.08	-59.19	4.76	-11.04	-231.93	-8.26	-12.82	155.21
272	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	9,988.07	226.24	2.27	10,680.70	1,316.52	12.33	12,184.34	3,954.87	32.46
273	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	1,947.75	26.45	1.36	2,036.30	34.21	1.68	2,068.65	30.56	1.48
274	भारतीय राष्ट्रीय साइकिल निगम लिमिटेड	3.90	-0.29	-7.44	3.85	0.14	3.64	3.52	-0.33	-9.38
275	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड	1,993.41	34.49	1.73	4,983.18	74.87	1.50	8,999.05	136.00	1.51
276	नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	13.98	0.94	6.72	16.89	3.87	22.91	24.39	10.00	41.00

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
277	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	2,687.27	139.40	5.19	2,921.34	612.96	20.98	3,013.16	268.48	8.91
278	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड	27.86	-8.15	-29.25	28.50	0.64	2.25	21.76	-6.74	-30.97
279	नेशनल फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड	1.17	0.04	3.42	1.20	0.04	3.33	1.21	0.03	2.48
280	राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम	478.90	11.99	2.50	490.06	9.21	1.88	496.22	6.20	1.25
281	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	88.42	-11.13	-12.59	78.59	-9.81	-12.48	76.76	-2.64	-3.44
282	नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	7,700.74	70.41	0.91	10,721.35	25.40	0.24	13,351.85	105.14	0.79

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
283	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	265.11	117.73	44.41	323.09	113.53	35.14	410.39	152.21	37.09
284	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक.	592.14	132.99	22.46	695.69	131.52	18.90	741.86	61.80	8.33
285	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	-1,272.80	- 4,033.61	-316.91	1484.78	-488.28	-32.89	3,661.32	-1,599.95	-43.70
286	राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना निधि ट्रस्टी लिमिटेड	-0.19	0.04	-21.05	-0.13	0.06	-46.15	-0.10	0.03	-30.00
287	राष्ट्रीय जूट निर्माता निगम लिमिटेड	8.26	-0.29	-3.51	6.27	-2.03	-32.38	-9.99	-7.77	77.78
288	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम	2,686.50	64.18	2.39	2,870.68	65.66	2.29	3,039.34	67.64	2.23

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
289	नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	189.66	45.49	23.99	216.05	34.10	15.78	241.48	50.45	20.89
290	भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम लिमिटेड	9.27	-0.04	-0.43	9.45	0.31	3.28	9.50	0.20	2.11
291	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम	798.32	6.41	0.80	854.25	23.62	2.76	875.22	15.92	1.82
292	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम	2,088.66	60.98	2.92	2,136.24	47.82	2.24	2,185.31	48.78	2.23
293	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	1,077.55	37.52	3.48	1,103.82	26.35	2.39	1,128.22	24.45	2.17
294	राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड	672.69	68.28	10.15	660.84	8.41	1.27	668.26	17.57	2.63

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
295	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	1,040.54	256.94	24.69	1,108.53	216.72	19.55	1,180.06	208.03	17.63
296	राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड	1,547.99	-299.66	-19.36	1,204.12	-297.79	-24.73	1,204.12	-297.79	-24.73
297	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	1,523.61	241.28	15.84	1,691.50	244.45	14.45	1,774.75	236.73	13.34
298	एनबीसीसी पर्यावरण इंजीनियरिंग लिमिटेड	1.01	0.03	2.97	1.02	0.01	0.98	1.03	0.01	0.97
299	एनबीसीसी इंटरनेशनल लिमिटेड	1.01	0.04	3.96	1.03	0.03	2.91	1.04	0.02	1.92
300	एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड	23.30	6.69	28.71	31.45	12.20	38.79	32.97	6.12	18.56
301	एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड				0.96	-0.05	-5.21	0.98	0.03	3.06

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
302	नेपा लिमिटेड	103.85	-42.36	-40.79	202.78	-16.87	-8.32	238.95	-16.05	-6.72
303	न्यू सिटी ऑफ बॉम्बे मैनुफैक्चरिंग मिल्स लिमिटेड	63.27	-1.34	-2.12	61.94	-1.39	-2.24	61.94	-1.39	-2.24
304	नई दिल्ली नगर पालिका परिषद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	276.51	-53.24	-19.25	100.35	-176.03	-175.42	135.96	2.35	1.73
305	न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड	61.29	68.57	111.88	167.74	163.33	97.37	1,441.77	459.15	31.85
306	नेयवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड	8,225.41	443.63	5.39	10,573.84	-0.96	-0.01	12,450.56	-0.33	0.00
307	एनएचडीसी लिमिटेड	5,563.59	496.01	8.92	5,692.53	862.11	15.14	5,644.67	725.95	12.86
308	एनएचपीसी लिमिटेड	48,925.17	4,944.41	10.11	51,246.58	5,364.54	10.47	55,286.46	3,305.69	5.98

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
309	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	24,009.67	3,016.15	12.56	23,272.58	2,730.29	11.73	22,632.70	3,390.20	14.98
310	एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड	4,886.49	678.04	13.88	4,693.67	908.45	19.35	4,063.94	538.58	13.25
311	एनएमडीसी सीएसआर फाउंडेशन लिमिटेड	8.91	-2.92	-32.77	5.02	-3.90	-77.69	6.04	1.02	16.89
312	एनएमडीसी लिमिटेड	27,533.95	6,132.31	22.27	30,302.57	8,911.23	29.41	36,512.19	13,013.67	35.64
313	एनएमडीसी स्टील लिमिटेड	0.01	-0.01	-100.00	0.00	-0.01		0.04	-0.01	-25.00
314	एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड	186.75	-3.34	-1.79	184.49	-3.60	-1.95	181.66	-4.03	-2.22
315	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड	12,982.45	332.90	2.56	12,396.63	220.94	1.78	13,096.80	490.46	3.74

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
316	पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	3.69	-4.39	-118.97	5.37	-1.16	-21.60	3.85	-28.18	-731.95
317	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड	-27.92	-4.14	-14.83	-30.70	-2.32	-7.56	-19.98	-2.38	-11.91
318	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	4,382.57	6,985.45	159.39	6,616.08	6,267.78	94.74	7,871.34	6,937.64	88.14
319	एनपीसीआईएल इंडियन ऑयल न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1.35	0.08	5.93	1.41	0.08	5.67	1.45	0.05	3.45
320	एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड				5.39	-0.58	-10.76	7.29	2.31	31.69

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
321	एनटीपीसी ईडीएमसी वेस्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड				-0.71	-0.91	-128.17	-2.76	-2.05	-74.28
322	एनटीपीसी इलेक्ट्रिक सप्लाइ कंपनी लिमिटेड	49.76	10.17	20.44	55.28	6.27	11.34	55.58	-0.25	-0.45
323	एनटीपीसी लिमिटेड	2,60,340.57	28,682.00	11.02	2,70,165.03	23,013.70	8.52	2,94,382.14	30,489.82	10.36
324	एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
325	एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड				291.54	-3.47	-1.19	767.78	0.17	0.02
326	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड	370.29	25.97	7.01	442.31	128.20	28.98	562.57	201.08	35.74

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
327	न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	84,238.79	9,111.89	10.82	97,366.67	8,837.09	9.08	1,08,783.01	11,533.23	10.60
328	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	5,204.38	1,735.93	33.36	5,496.03	4,091.43	74.44	9,237.72	4,849.68	52.50
329	ओडिशा इंफ्रा पावर लिमिटेड	0.31	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00
330	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	1,96,567.24	20,888.14	10.63	2,10,870.13	16,709.40	7.92	2,435,29.03	41,344.74	16.98
331	ऑयल इंडिया लिमिटेड	32,739.82	2,560.17	7.82	37,096.68	1,160.71	3.13	40,994.16	5,558.83	13.56
332	ओमनीबस औद्योगिक विकास निगम दमन, दीव और दादरा और नगर हवेली लिमिटेड	183.52	39.10	21.31	209.08	35.57	17.01	232.93	32.92	14.13

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
333	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	52,183.74	-2,584.25	-4.95	55,710.31	3,294.77	5.91	65,365.11	6,177.21	9.45
334	ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड	17,746.36	-801.69	-4.52	19,776.43	51.23	0.26	22,067.20	-419.58	-1.90
335	उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड	130.63	0.00	0.00	145.69	0.00	0.00	153.17	0.00	0.00
336	पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2,572.72	159.51	6.20	3,934.80	205.59	5.22	5,750.81	278.78	4.85
337	पवन हंस लिमिटेड	979.07	-95.54	-9.76	982.23	-17.94	-1.83	970.01	-3.94	-0.41
338	पीईसी लिमिटेड	-1,780.12	-30.57	-1.72	-1,909.21	-15.28	-0.80	-2,223.98	-5.27	-0.24
339	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	59.97	78.45	130.82	87.18	36.96	42.40	120.83	51.11	42.30
340	पांडिचेरी अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-0.48	-1.59	-331.25	-1.83	-1.35	-73.77	-1.71	0.16	-9.36

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
341	पोर्ट ब्लेयर स्मार्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर	212.85	0.00	0.00	212.85	0.00	0.00	212.85	0.00	0.00
342	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3,53,400.41	29,839.10	8.44	3,90,567.53	33,401.80	8.55	3,91,999.26	34,898.95	8.90
343	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1,99,860.83	24,079.66	12.05	1,98,658.91	23,677.43	11.92	2,08,298.61	27,649.90	13.27
344	पावर ग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	60.76	17.23	28.36	57.67	14.07	24.40	59.61	21.34	35.80
345	पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसको लिमिटेड	162.42	-0.46	-0.28	543.98	-0.02	0.00	582.36	32.96	5.66
346	पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड				0.01	0.00	0.00	633.59	-0.02	0.00

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
347	पावरग्रिड भड़ला ट्रांसमिशन लिमिटेड				-0.67	-0.72	107.46	299.47	8.86	2.96
348	पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	47.45	0.25	0.53	291.31	0.00	0.00	456.08	20.86	4.57
349	पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	83.02	0.00	0.00	429.23	0.00	0.00	945.72	-0.04	0.00
350	पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड				0.01	0.00	0.00	448.82	-0.03	-0.01
351	पावरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड							-0.26	-0.31	-119.23
352	पावरग्रिड फतेहगढ़	146.80	0.00	0.00	572.43	21.40	3.74	660.32	36.85	5.58

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
	ट्रांसमिशन लिमिटेड									
353	पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	211.39	0.00	0.00	403.89	21.61	5.35	447.26	46.86	10.48
354	पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	212.19	2.76	1.30	794.00	-0.05	-0.01	994.58	57.40	5.77
355	पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड	2,371.58	0.00	0.00	2,941.79	188.65	6.41	3,215.88	430.54	13.39
356	पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	30.99	0.00	0.00	194.00	0.00	0.00	751.45	-0.02	0.00

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
357	पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	767.96	0.00	0.00	1,096.93	55.85	5.09	1,181.91	113.62	9.61
358	पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड				0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
359	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	1,172.18	47.96	4.09	1,144.22	86.23	7.54	1,155.63	80.60	6.97
360	पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड				5.36	-0.66	-12.31	92.86	-0.01	-0.01
361	पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	14.31	-1.24	-8.67	126.02	2.84	2.25	551.40	-0.01	0.00
362	पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड				-0.54	-0.59	109.26	525.86	16.37	3.11

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
363	पावरग्रिड साउदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	3,496.76	230.06	6.58	3,570.06	356.43	9.98	3,291.11	141.21	4.29
364	पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड							8.67	-0.44	-5.07
365	पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	661.30	0.00	0.00	826.11	0.02	0.00	934.60	75.85	8.12
366	पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	-19.40	-0.01	-0.05	-19.41	-0.01	-0.05	-19.42	-0.01	-0.05
367	प्राइज पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड	111.68	-16.96	-15.19	115.30	3.59	3.11	109.53	-5.79	-5.29

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
368	प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड	154.95	45.86	29.60	157.54	26.25	16.66	167.40	14.84	8.86
369	पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड	2.28	-0.01	-0.44	2.27	-0.01	-0.44	2.26	-0.01	-0.44
370	पंजाब लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	239.42	-1.79	-0.75	233.55	-7.07	-3.03	221.25	-3.89	-1.76
371	रेल विकास निगम लिमिटेड	8,756.42	1,013.18	11.57	10,637.09	1,155.67	10.86	11,946.84	1,935.82	16.20
372	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1,361.28	181.14	13.31	1,402.73	196.44	14.00	1,516.02	282.77	18.65
373	रेलटेल एंटरप्राइजेज लिमिटेड	18.04	6.75	37.42	20.09	4.81	23.94	21.39	1.76	8.23

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
374	राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	-39.23	-26.21	-66.81	-46.17	-9.34	-20.23	-27.30	-2.06	-7.55
375	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड	94.54	-28.60	-30.25	81.09	-18.20	-22.44	72.94	-7.49	-10.27
376	राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड				0.10	0.06	60.00	-0.10	-0.20	200.00
377	रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-11.84	-1.75	-14.78	-14.88	-2.75	-18.48	-15.63	-0.53	-3.39
378	राष्ट्रीय केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	3,932.42	406.29	10.33	4,585.74	682.59	14.89	5,250.46	1,049.52	19.99

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
379	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	13,031.56	-2,865.92	-21.99	12,580.24	414.88	3.30	11,947.06	2,363.94	19.79
380	रैटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड							186.27	-0.53	-0.28
381	रियल एस्टेट विकास एवं निर्माण निगम राजस्थान लिमिटेड	3.59	0.21	5.85	3.74	0.20	5.35	3.82	0.10	2.62
382	आरईसी लिमिटेड	3,18,666.12	25,980.34	8.15	3,72,650.28	32,245.21	8.65	3,83,528.83	34,477.81	8.99
383	आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड	168.20	20.34	12.09	297.98	32.62	10.95	328.58	68.87	20.96
384	आरईएमसी लिमिटेड	198.87	53.53	26.92	204.56	37.55	18.36	233.22	66.43	28.48

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
385	रिन्यूएबल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड	3.39	1.48	43.66	5.31	2.41	45.39	5.74	2.45	42.68
386	रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड	127.38	28.55	22.41	141.00	27.05	19.18	185.04	28.37	15.33
387	रिचर्डसन और क्रुडास (1972) लिमिटेड	214.56	24.07	11.22	227.97	18.42	8.08	247.31	25.44	10.29
388	राइट्स लिमिटेड	2,576.62	822.61	31.93	2,321.93	562.35	24.22	2,399.26	674.56	28.12
389	रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड	-0.02	-0.01	-50.00	-0.02	-0.03	-150.00	-0.02	-0.01	-50.00
390	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	556.78	8.95	1.61	687.99	1.22	0.18	794.77	9.38	1.18
391	सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्रीज लिमिटेड	87.28	23.51	26.94	79.82	18.50	23.18	68.98	5.99	8.68
392	सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड	94.98	20.34	21.42	105.71	16.31	15.43	120.38	27.75	23.05

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
393	सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	16.39	0.00	0.00	16.39	0.00	0.00	16.39	0.00	0.00
394	सांभर साल्ट्स लिमिटेड	-10.92	5.13	-46.98	-5.59	10.98	-196.42	5.25	15.15	288.57
395	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	66.02	-15.73	-23.83	57.50	-48.65	-84.61	65.08	13.16	20.22
396	सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	3,971.39	1,057.80	26.64	4,469.97	858.44	19.20	4,854.23	923.09	19.02
397	सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	799.99	2.60	0.33	800.80	1.23	0.15	800.70	-0.10	-0.01
398	एसएचसीआईएल सर्विसेज लिमिटेड	69.35	6.46	9.32	79.22	23.09	29.15	91.73	28.60	31.18
399	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड							0.01	0.00	0.00

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
	एंड एसेट्स लिमिटेड									
400	शौंगटोंग करछम वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00	-0.01		0.00	0.00		0.00	0.00	
401	सिडकुल कॉनकॉर इंफ्रा कंपनी लिमिटेड	90.49	-2.22	-2.45	90.08	-0.59	-0.65	90.29	0.02	0.02
402	सिलवासा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	6.07	7.71	127.02	-1.90	-0.16	8.42	-1.90	-0.16	8.42
403	एसजेवीएन लिमिटेड	13,731.50	2,028.40	14.77	14,617.52	2,165.82	14.82	17,925.56	1,460.96	8.15
404	एसजेवीएन थर्मल प्राइवेट लिमिटेड	996.29	-0.31	-0.03	2,147.43	1.18	0.05	3,689.50	-0.81	-0.02
405	भारतीय सौर ऊर्जा निगम	695.72	232.80	33.46	873.58	237.59	27.20	2,060.46	320.00	15.53
406	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	3,064.35	2524.01	82.37	4,308.00	2,044.50	47.46	5,442.08	2,137.34	39.27

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
407	एसटीसीएल लिमिटेड	-4,565.09	-0.47	-0.01	-4,564.22	0.97	-0.02	- 4,557.11	7.16	-0.16
408	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	72,960.64	6,657.42	9.12	60,315.55	9,696.17	16.08	59,620.23	17,736.60	29.75
409	स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2,235.62	44.86	2.01	2,684.20	86.41	3.22	4,552.99	161.70	3.55
410	स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड	63.49	-35.18	-55.41	65.70	-11.95	-18.19	66.33	6.82	10.28
411	स्टॉक होल्डिंग सिक्योरिटीज आईएफएससी लिमिटेड	14.19	-1.57	-11.06	12.00	-1.85	-15.42	12.93	-2.30	-17.79
412	सूरत इंडीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन	7.28	0.41	5.63	7.48	0.42	5.61	7.73	0.33	4.27

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
	डेवलपमेंट लिमिटेड									
413	सूटी टेक ऑप्शंस लिमिटेड	0.00	-0.01	0.00	-0.31	-0.01	-3.23	-0.32	-0.01	-3.13
414	तालचेर फर्टिलाइजर लिमिटेड	456.79	-3.04	-0.67	1,591.29	7.85	0.49	2,394.30	-5.87	-0.25
415	तमिलनाडु व्यापार संवर्धन संगठन	325.29	36.02	11.07	306.87	6.33	2.06	310.20	3.89	1.25
416	टांडा ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
417	तातिया आंध्र मेगा पावर लिमिटेड	0.00	-0.05		0.00	0.00		0.00	0.00	
418	टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड	56.49	1.54	2.73	45.83	9.71	21.19	42.31	8.02	18.96
419	टीसीआईएल एलटीआर लिमिटेड	81.50	3.73	4.58	78.31	2.67	3.41	76.66	0.82	1.07

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
420	टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड	585.88	94.79	16.18	611.19	74.06	12.12	612.79	47.75	7.79
421	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	13,450.43	1,411.53	10.49	15,558.49	1,572.42	10.11	16,832.13	1,586.44	9.43
422	बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड	-152.71	-9.34	-6.12	-146.72	7.55	-5.15	-141.10	8.44	-5.98
423	ब्रेथवेट बर्न और जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	208.31	2.54	1.22	209.49	16.03	7.65	211.99	5.12	2.42
424	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-1,050.42	-38.01	-3.62	-1,155.47	-24.26	-2.10	- 1,234.52	-3.21	-0.26
425	भारतीय कपास निगम लिमिटेड	367.45	557.75	151.79	372.64	1371.37	368.01	363.38	491.37	135.22
426	एफसीआई अरावली जिप्सम	250.20	21.06	8.42	251.61	18.22	7.24	250.82	15.57	6.21

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
	एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड									
427	द फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	1,304.56	1,263.36	96.84	1,615.90	594.79	36.81	1,975.16	595.21	30.13
428	भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड	23.79	-8.78	-36.91	20.82	-8.49	-40.78	87.03	-18.05	-20.74
429	इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड	-0.04	0.00	0.00	-0.05	0.00	0.00	-0.05	0.00	0.00
430	भारतीय जूट निगम लिमिटेड	147.70	21.36	14.46	155.24	15.99	10.30	133.69	-13.78	-10.31
431	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	25,971.51	1,638.83	6.31	36,450.64	2,036.72	5.59	38,191.19	159.91	0.42

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
432	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	4,399.66	- 1,498.70	-34.06	8,552.36	-1,512.06	-17.68	7,533.32	-3,146.87	-41.77
433	उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	57.08	-29.02	-50.84	296.15	-20.96	-7.08	131.47	16.42	12.49
434	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	8,823.51	543.46	6.16	10,413.75	728.32	6.99	10,966.77	899.90	8.21
435	भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड	-61.51	-113.63	-184.73	-109.20	-51.23	-46.91	-197.57	-48.60	-24.60
436	डूप कम्फर्ट्स लिमिटेड							4,573.67	23.04	0.50
437	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड	-45.37	-4.69	-10.34	-54.46	-0.30	-0.55	-44.89	-0.18	-0.40
438	टुस्को लिमिटेड				9.74	-0.35	-3.59	18.71	-1.46	-7.80
439	उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड				141.53	-1.31	-0.93	139.32	-17.52	-12.58

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
440	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2,341.66	- 1,411.30	-60.27	7,674.79	-910.61	-11.86	6,047.69	-2,061.30	-34.08
441	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	3,208.27	607.43	18.93	3,557.25	623.21	17.52	3,944.70	777.48	19.71
442	उर्वारक विदेश लिमिटेड	0.07	-0.01	-14.29	0.06	-0.01	-16.67	0.06	-0.01	-16.67
443	उत्कल अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-22.23	-0.12	-0.54	-22.93	-0.12	-0.52	-23.81	-0.18	-0.76
444	उत्कर्ष एल्युमीनियम धातु निगम लिमिटेड	36.75	-3.64	-9.90	37.01	0.38	1.03	37.63	0.65	1.73
445	विज्ञान इंडस्ट्रीज लिमिटेड	-0.01	-4.49	-44,900.00	-5.90	-5.48	-92.88	53.85	-4.95	-9.19

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसीई % में	नियोजित पूंजी	ईबीआईटी	आरओसी ई % में
446	विशाखापतनम पोर्ट लॉजिस्टिक्स पार्क लिमिटेड	189.29	-9.23	-4.88	186.60	-5.79	-3.10	180.24	-0.49	-0.27
447	वाप्कोस लिमिटेड	626.04	212.53	33.95	617.14	58.30	9.45	659.28	65.36	9.91
448	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	381.29	12.12	3.18	548.88	383.53	69.88	1,505.82	1259.73	83.66
449	यंत्र इंडिया लिमिटेड							2,577.89	-123.12	-4.78
450	यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	-0.06	0.00	0.00	-0.07	0.00	0.00	-0.08	-0.01	12.50
451	यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड	-0.03	0.00	0.00	-0.03	-0.01	33.33	-0.04	-0.01	25.00
452	जेनिथ सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	14.73	-2.02	-13.71	17.85	3.35	18.77	22.65	43.70	192.94
		35,35,015.6 9	2,70,219.3 6	7.64	36,62,023.72	3,63,926.72	9.94	40,09,375.79	4,19,293.9 7	10.46

अनुलग्नक-XII (पैरा संख्या 1.4.2 देखें)
सरकारी कंपनियों और निगमों के इक्विटी पर रिटर्न

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
1	एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड							4.71	2,573.47	0.18
2	एग्रीनोवेटिव इंडिया लिमिटेड	2.81	69.68	4.03	1.39	71.07	1.96	1.54	72.61	2.12
3	एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	66.21	403.18	16.42	-203.66	184.40	-110.44	15.33	361.65	4.24
4	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड	107.19	-2,178.67	-4.92	-9.58	-2,218.34	0.43	837.12	-1,381.51	-60.59
5	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	134.02	134.07	99.96	43.70	177.77	24.58	-1,057.47	-6,266.13	16.88
6	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	1,985.09	15,452.80	12.85	-1,962.06	12,849.96	-15.27	8.76	12,227.30	0.07

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
7	एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड	-200.63	-2,256.66	-8.89	-360.09	-2651.16	-13.58	-447.76	-3,098.55	-14.45
8	अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड				0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
9	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह वन एवं वृक्षारोपण विकास निगम लिमिटेड	-1.03	-21.02	-4.90	-0.89	-21.91	-4.06	-2.61	-24.52	-10.64
10	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड	33.77	180.03	18.76	19.30	192.35	10.03	23.93	209.14	11.44
11	अंडमान फिशरीज लिमिटेड	-4.28	-35.66	-12.00	-4.91	-40.56	-12.11	-7.22	-47.78	-15.11
12	आंध्र प्रदेश सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड	73.70	159.18	46.30	56.74	215.12	26.38	71.98	286.58	25.12

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
13	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	-20.52	168.28	-12.19	21.20	190.14	11.15	-0.90	183.14	-0.49
14	अंगुल सुकिंदा रेलवे लिमिटेड	0.28	714.69	0.04	0.70	851.41	0.08	0.53	867.07	0.06
15	एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	220.69	1,596.57	13.82	55.71	1,567.31	3.55	24.96	1,513.87	1.65
16	अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00
17	अपोलो डिज़ाइन अपैरल पार्क्स लिमिटेड	10.39	123.49	8.41	-1.03	122.50	-0.84	-1.03	122.50	-0.84
18	बख्तरबंद वाहन निगम लिमिटेड							54.19	12,302.08	0.44
19	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम	85.68	483.29	17.73	52.26	533.64	9.79	64.15	599.26	10.70

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभान्श के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभान्श के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभान्श के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
20	औरंगाबाद टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क्स लिमिटेड	-0.76	14.05	-5.41	-0.76	13.30	-5.71	-0.76	13.30	-5.71
21	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	170.65	1,319.67	12.93	116.45	1,307.73	8.90	122.81	1,319.86	9.30
22	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड	83.58	176.31	47.41	84.62	167.16	50.62	66.62	159.96	41.65
23	बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-595.67	6,276.61	-9.49	-902.54	7,545.44	-11.96	-476.92	11,147.71	-4.28
24	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	1.19	294.06	0.40	0.54	294.60	0.18	-0.89	293.71	-0.30
25	बीईएल ऑप्टॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड	3.01	235.28	1.28	4.90	240.52	2.04	5.16	244.32	2.11
26	बीईएल-थैल्स सिस्टम्स लिमिटेड	3.34	54.50	6.13	3.15	57.65	5.46	5.21	62.85	8.29

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभों के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभों के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभों के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
27	बीईएमएल लैंड एसेट्स लिमिटेड							-0.01	0.00	0.00
28	बीईएमएल लिमिटेड	68.38	2,181.09	3.14	74.80	2,173.39	3.44	134.59	2,280.73	5.90
29	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	13.07	-53.71	-24.33	6.08	-47.63	-12.77	7.47	76.96	9.71
30	बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड	-1.09	48.91	-2.23	-2.09	71.82	-2.91	-3.82	250.31	-1.53
31	भड़ला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड				0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
32	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड	3.24	85.96	3.77	1.45	87.41	1.66	-2.49	84.92	-2.93
33	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	918.68	4,297.66	21.38	-1202.48	3,088.81	-38.93	111.62	3,273.77	3.41
34	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	534.90	2,606.83	20.52	257.77	2,684.75	9.60	499.92	3,030.56	16.50

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
35	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	1,793.83	9,852.94	18.21	2,065.42	10,761.20	19.19	2,348.93	11,984.26	19.60
36	भारत गैस रिसोर्सेज लिमिटेड	1.51	299.74	0.50	0.36	900.10	0.04	149.84	1,799.94	8.32
37	भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड	-79.42	-2,061.05	-3.85	147.39	-1,913.66	-7.70	-68.88	-1,982.54	-3.47
38	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	-1,472.97	29,146.03	-5.05	-2,717.14	26,448.87	-10.27	410.24	26,971.16	1.52
39	भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-10.21	20.47	-49.88	-18.11	34.04	-53.20	-8.75	43.18	-20.26
40	भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड				-76.35	3,543.07	-2.15	892.17	4,435.73	20.11
41	भारत पेट्रो रिसोर्सेज जेपीडीए लिमिटेड	-4.10	-68.44	-5.99	12.24	-56.21	-21.78	-0.31	-56.52	-0.55

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
42	भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड	-915.03	3,209.39	-28.51	-1,796.85	2,290.12	-78.46	-22.81	3,392.33	-0.67
43	भारत पेट्रोलीयम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2,683.19	32,158.78	8.34	19,041.67	53,300.47	35.73	8,788.73	48,355.45	18.18
44	भारत पम्प्स एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड	-26.99	-213.61	-12.64	-83.89	-204.95	-40.93	-53.69	-90.42	-59.38
45	भारत संचार निगम लिमिटेड	-15,499.58	18,931.47	-81.87	-7,441.12	11,478.46	-64.83	-6,981.62	5,000.00	-139.63
46	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड	0.07	4,766.17	0.00	0.22	4,806.39	0.00	0.19	4,806.58	0.00
47	भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड	258.46	2,742.79	9.42	282.48	2,770.13	10.20	328.70	2,921.98	11.25
48	बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड	-6.92	-20.65	-33.51	-4.41	-25.07	-17.59	-4.41	-25.07	-17.59
49	बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड				0.02	0.07	28.57	-0.01	0.07	-14.29

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभों के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभों के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभों के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
50	बिहारी लॉरी लिमिटेड	-3.36	-126.84	-2.65	11.84	-115.00	-10.30	0.89	-114.11	-0.78
51	बिहार ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	-0.49	-45.69	-1.07	-0.49	-45.69	-1.07	-0.49	-45.69	-1.07
52	बिहार इंफ्रा पावर लिमिटेड	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00
53	बिहार मेगा पावर लिमिटेड	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00
54	बिजावर विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00
55	जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद	7.95	112.53	7.06	6.72	120.65	5.57	9.00	130.13	6.92
56	बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	-4.71	-136.53	-3.45	-5.43	-141.96	-3.83	-5.40	-147.36	-3.66

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
57	बीपीसीएल-केआईएएल फ्यूल फार्म प्राइवेट लिमिटेड	-1.97	5.26	-37.45	-6.06	-0.80	757.50	-3.85	-4.65	82.80
58	ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड	1507.60	2073.05	72.72	739.89	2811.26	26.32	690.53	3280.79	21.05
59	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-129.70	-113.53	-114.24	-137.75	-251.28	-54.82	-97.64	-348.92	-27.98
60	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	19.78	83.42	23.71	24.72	108.13	22.86	42.42	150.55	28.18
61	ब्रिज एंड रुफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड	31.42	377.75	8.32	7.80	376.67	2.07	21.28	395.84	5.38
62	ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	-4.85	7.58	-63.98	2.55	10.17	25.07	11.09	21.14	52.46

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
63	बीएसएनएल टावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-0.03	-2.80	-1.07	0.01	-2.79	-0.36	0.00	-2.79	0.00
64	बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड	-0.17	9.41	-1.81	-0.13	48.67	-0.27	-0.70	95.03	-0.74
65	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड	0.47	184.63	0.25	-0.14	184.63	-0.08	-0.14	184.63	-0.08
66	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-50.94	-22.09	-230.60	13.15	-29.80	-44.13	40.20	11.44	351.40
67	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	1,847.75	6,391.53	28.91	1221.28	7,548.53	16.18	1,696.92	8,411.98	20.17
68	सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-9.25	-14.38	-64.33	-29.92	-44.33	-67.49	-24.38	-68.66	-35.51
69	सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	3.13	80.76	3.88	23.26	105.82	21.98	23.78	122.34	19.44

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
70	केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड	2.48	42.42	5.85	13.75	56.17	24.48	0.34	56.50	0.60
71	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड	193.39	570.31	33.91	316.96	784.47	40.40	282.12	995.62	28.34
72	भारत के प्रतिभूतिकरण, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित की केंद्रीय रजिस्ट्री	85.76	825.33	10.39	44.62	869.95	5.13	65.57	935.51	7.01
73	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड				-0.03	0.02	-150.00	40.03	40.05	99.95
74	केंद्रीय भंडारण निगम	372.32	2,789.26	13.35	438.17	2,868.61	15.27	450.56	3,088.15	14.59
75	सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड	10.08	78.60	12.82	11.23	80.67	13.92	8.11	79.30	10.23

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभान्श के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभान्श के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभान्श के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
76	चंडीगढ़ औद्योगिक एवं पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	-1.68	58.23	-2.89	-1.33	56.53	-2.35	4.61	60.82	7.58
77	चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	-1.83	0.10	-1,830.00	-2.92	200.00	-1.46	1.29	203.44	0.63
78	चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.44	-2.14	-20.56	-0.01	-2.15	-0.47	0.00	-2.15	0.00
79	चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड	-525.20	5,100.08	-10.30	-613.37	4,487.07	-13.67	-722.98	5,967.43	-12.12
80	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-2,077.58	1,192.19	-174.27	237.56	1,424.48	16.68	1,342.42	2,790.14	48.11
81	चेन्नुर इन्फ्रा लिमिटेड	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00
82	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83	छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड	-0.04	-0.04	-100.00	-0.11	0.06	-183.33	-0.10	0.05	-200.00

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
84	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	-22.48	539.27	-4.17	7.76	656.03	1.18	62.33	819.62	7.60
85	छत्तीसगढ़ पूर्व पश्चिम रेलवे लिमिटेड	-0.11	503.36	-0.02	-0.27	503.09	-0.05	-0.28	592.81	-0.05
86	छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड	-0.01	0.01	-100.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
87	सीआईएल नवकरणीय ऊर्जा लिमिटेड							0.00	0.05	0.00
88	सीआईएल सोलर पीवी लिमिटेड							0.00	0.05	0.00
89	कोल इंडिया लिमिटेड	11,280.88	16,813.30	67.09	7,640.10	16,751.71	45.61	11,201.57	16,357.95	68.48
90	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	100.00
91	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
92	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	0.00	0.08	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.08	0.00
93	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	637.69	3,712.48	17.18	610.10	3,958.25	15.41	586.57	4,339.86	13.52
94	कॉनकॉर एयर लिमिटेड	7.20	36.84	19.54	-2.93	33.91	-8.64	-9.65	24.24	-39.81
95	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	375.78	10,064.74	3.73	503.33	10,203.74	4.93	1,062.34	10,777.30	9.86
96	क्रिएटिव म्यूजियम डिजाइनर	2.94	17.78	16.54	3.41	20.91	16.31	4.16	10.19	40.82
97	क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	21.47	109.97	19.52	15.19	114.97	13.21	17.26	126.90	13.60
98	दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव एससी/एसटी वितीय और विकास निगम लिमिटेड	1.33	10.37	12.83	0.33	11.60	2.84	4.47	15.16	29.49

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभान्श के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभान्श के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभान्श के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
99	दामोदर घाटी निगम	185.32	5,269.45	3.52	301.96	5,817.69	5.19	634.89	6,738.82	9.42
100	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-90.52	14,256.29	-0.63	112.45	14,370.56	0.78	-16.15	15,994.76	-0.10
101	रक्षा नवाचार संगठन	0.00	61.82	0.00	0.00	85.81	0.00	0.00	123.77	0.00
102	दिल्ली मेट्रो लास्ट माइल सर्विसेज लिमिटेड	-0.01	-0.01	100.00	-0.01	0.08	-12.50	-0.01	0.07	-14.29
103	दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-468.27	28,118.43	-1.67	-2,368.74	26,735.32	-8.86	-3,815.11	24,130.39	-15.81
104	दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.60	12.33	4.87	0.48	12.82	3.74	0.17	12.98	1.31
105	देवघर इंधन लिमिटेड	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00
106	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00
107	डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन	0.00	42.24	0.00	0.00	36.27	0.00	1.43	33.35	4.29

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
108	दीव स्मार्ट सिटी लिमिटेड	-0.09	1.96	-4.59	0.03	1.99	1.51	0.03	2.02	1.49
109	डीएनएच पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	11.40	541.68	2.10	229.91	771.58	29.80	105.84	877.43	12.06
110	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.43	-2.08	-20.67	-0.01	-2.09	-0.48	0.00	-2.10	0.00
111	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	997.65	1,882.88	52.99	-759.58	888.82	-85.46	-1,060.66	1,813.71	-58.48
112	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	-0.56	269.64	-0.21	0.79	270.43	0.29	-0.44	269.99	-0.16
113	ईसीजीसी लिमिटेड	323.84	12,687.73	2.55	460.30	13,765.91	3.34	875.16	15,375.28	5.69
114	एडसिल (इंडिया) लिमिटेड	40.92	148.73	27.51	36.89	173.00	21.32	50.41	211.79	23.80
115	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	50.43	1,011.88	4.98	112.17	1,078.42	10.40	220.78	1,255.73	17.58

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
116	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड	0.92	198.54	0.46	-49.74	148.52	-33.49	-65.06	83.46	-77.95
117	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	430.24	2,345.46	18.34	259.50	1,701.01	15.26	344.41	1,925.05	17.89
118	तथ्य आरसीएफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड	-71.49	-123.08	-58.08	-5.99	-129.07	-4.64	-8.58	-137.71	-6.23
119	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड	30.58	216.92	14.10	22.75	226.68	10.04	40.36	212.00	19.04
120	फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	52.77	580.81	9.09	51.05	631.86	8.08	35.74	666.50	5.36
121	भारतीय खाद्य निगम	0.00	4,468.65	0.00	0.00	5,500.33	0.00	0.00	8,004.55	0.00
122	फ्रेश एंड हेल्दी एंटरप्राइजेज लिमिटेड	-6.45	36.39	-17.72	-4.84	31.56	-15.34	-3.73	33.29	-11.20
123	गेल (इंडिया) लिमिटेड	6,620.63	43,881.28	15.09	4,890.18	46,506.37	10.52	10,363.97	55,586.79	18.64
124	गेल गैस लिमिटेड	156.25	1,707.85	9.15	157.70	2,100.96	7.51	283.36	2,430.75	11.66

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभों के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभों के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभों के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
125	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	163.48	1,040.23	15.72	153.47	1,137.12	13.50	189.53	1,248.60	15.18
126	जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-359.09	1,09,624.35	-0.33	1,920.44	1,27,917.40	1.50	2,005.74	1,39,087.47	1.44
127	घोगरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00
128	ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड							0.71	529.96	0.13
129	गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	-5.43	7.09	-76.59	-11.55	-5.39	214.29	-6.67	-11.38	58.61
130	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	197.77	1,025.24	19.29	127.91	1,098.26	11.65	101.09	1,148.40	8.80
131	गोल्डमोहर डिजाइन एंड अपैरल पार्क्स लिमिटेड	8.59	117.55	7.31	-1.59	116.03	-1.37	-1.59	116.03	-1.37
132	सरकारी ई-मार्केट प्लेस	-2.37	0.01	-23,700.00	-4.02	0.01	-40,200.00	104.07	98.83	105.30

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
133	ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड	57.55	451.79	12.74	20.50	468.36	4.38	44.39	508.19	8.73
134	हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड	0.49	1,064.58	0.05	38.84	1,227.43	3.16	31.20	1,358.27	2.30
135	हरिद्वार नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड	-1.99	39.37	-5.05	0.67	40.04	1.67	3.34	43.14	7.74
136	हसन मैंगलोर रेल विकास कंपनी लिमिटेड	21.46	379.63	5.65	-32.04	347.60	-9.22	-40.00	307.60	-13.00
137	हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड	3.29	97.18	3.39	19.00	116.19	16.35	-12.19	100.29	-12.15
138	हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-405.37	-400.73	-101.16	-175.78	-582.25	-30.19	-256.07	-844.07	-30.34
139	हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड	-0.76	284.08	-0.27	-7.45	376.63	-1.98	-14.86	372.33	-3.99
140	हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.04	0.13	30.77	-0.21	2.42	-8.68	1.91	46.71	4.09

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
141	उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी	315.82	5,470.16	5.77	441.59	6,131.75	7.20	447.52	6,579.27	6.80
142	हिमाचल रिन्यूएबल्स लिमिटेड	0.06	4.40	1.36	0.11	4.52	2.43	0.07	4.59	1.53
143	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	2,832.36	13,189.93	21.47	3,232.96	15,356.55	21.05	5,086.50	19,264.00	26.40
144	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड	-0.01	-568.99	0.00	-38.26	-607.24	-6.30	-16.21	-623.45	-2.60
145	हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड	13.88	-300.79	-4.61	269.56	-31.23	-863.14	88.39	57.16	154.64
146	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	-569.35	313.21	-181.78	109.98	528.04	20.83	373.78	805.61	46.40
147	हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	10.43	126.47	8.25	9.42	135.89	6.93	2.52	138.40	1.82
148	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड	-3.63	-47.32	-7.67	-24.83	-72.64	-34.18	-6.13	-78.81	-7.78

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभों के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभों के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभों के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
149	हिंदुस्तान कीटनाशक लिमिटेड	0.59	104.43	0.56	1.15	105.58	1.09	2.21	107.80	2.05
150	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	-94.68	29.02	-326.26	15.47	59.85	25.85	-23.24	53.23	-43.66
151	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2,637.26	28,337.36	9.31	10,663.88	35,561.11	29.99	6,382.63	38,052.04	16.77
152	हिंदुस्तान फोटो फिल्मस (मैन्युफैक्चरिंग) कंपनी लिमिटेड	-2.35	-23,736.69	-0.01	-0.37	-23,737.06	0.00	-1.88	-23,738.94	-0.01
153	हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड	-14.98	19.20	-78.02	1.67	20.88	8.00	-12.25	8.63	-141.95
154	हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड	-1.85	47.19	-3.92	5.80	50.04	11.59	1.52	52.06	2.92
155	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	13.03	-567.62	-2.30	-14.01	-595.16	2.35	50.78	-547.31	-9.28

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभों के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभों के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभों के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
156	हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	44.20	115.22	38.36	29.48	125.61	23.47	27.77	146.06	19.01
157	हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड	0.05	2,540.70	0.00	-16.32	3,807.43	-0.43	-19.84	5,356.35	-0.37
158	हिंदुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.72	9.88	7.29	0.25	10.14	2.47	0.25	10.14	2.47
159	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड	-58.32	121.22	-48.11	-31.99	89.09	-35.91	547.34	636.42	86.00
160	एचएलएल इंफ्राटेक सर्विसेज लिमिटेड	31.63	19.05	166.04	10.86	19.81	54.82	17.60	30.70	57.33
161	एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड	109.80	572.96	19.16	112.33	385.74	29.12	408.23	768.91	53.09
162	एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड	-0.77	4.37	-17.62	-0.85	3.52	-24.15	1.37	3.19	42.95

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभों के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभों के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभों के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
163	एचएलएल मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल्स लिमिटेड	-2.79	-3.00	-93.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
164	एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड	2.71	36.33	7.46	0.97	37.17	2.61	0.21	36.78	0.57
165	एचएमटी लिमिटेड	248.18	361.00	68.75	27.49	387.14	7.10	38.36	426.66	8.99
166	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	-98.72	-1,408.05	-7.01	-132.79	-1,539.84	-8.62	-145.73	-1,684.73	-8.65
167	एचएमटी वॉचेस लिमिटेड	0.96	-2,686.03	-0.04	2.70	-2,683.33	-0.10	1.05	-2,682.28	-0.04
168	हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	-2.49	17.81	-13.98	-3.16	42.65	-7.41	-2.84	39.82	-7.13
169	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड	117.58	-2.52	-4,665.87	2.80	0.28	1,000.00	2.50	2.82	88.65
170	हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड	-1.16	-5.05	-22.97	-0.73	-5.78	-12.63	-0.04	-5.82	-0.69

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभों के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभों के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभों के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
171	होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-55.55	-432.99	-12.83	-97.37	-529.61	-18.39	-84.81	-613.86	-13.82
172	आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड	1,708.42	8,906.45	19.18	1,578.58	9,312.17	16.95	1,716.60	11,343.13	15.13
173	एचपीसीएल बायो फ्यूल्स लिमिटेड	-85.55	-34.50	-247.97	-80.07	265.86	-30.12	-66.95	206.92	-32.36
174	एचपीसीएल एलएनजी लिमिटेड							-14.09	1,230.54	-1.15
175	एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड	1.81	1,742.87	0.10	-33.41	2,334.12	-1.43	-22.37	5,646.75	-0.40
176	एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड	37.63	109.78	34.28	9.82	117.74	8.34	25.18	143.61	17.53
177	आईटीआई लिमिटेड	150.86	925.12	16.31	11.20	933.52	1.20	121.06	933.52	12.97
178	आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड	-5.38	126.20	-4.26	-9.80	116.22	-8.43	-9.67	106.44	-9.08

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
179	आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	-1.17	69.57	-1.68	-1.32	68.39	-1.93	1.07	69.74	1.53
180	आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड	13.11	513.74	2.55	6.14	505.04	1.22	8.32	506.80	1.64
181	आईएफसीआई लिमिटेड	-277.88	3,859.84	-7.20	-1,957.81	2,124.17	-92.17	-1,991.33	445.45	-447.04
182	आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड	0.60	166.99	0.36	2.47	169.57	1.46	-2.97	166.74	-1.78
183	आईएफआईएन कमोडिटीज लिमिटेड	-0.27	5.15	-5.24	-0.38	4.74	-8.02	-0.66	4.13	-15.98
184	आईएफआईएन क्रेडिट लिमिटेड	0.04	1.98	2.02	-0.01	1.97	-0.51	0.00	1.98	0.00
185	आईएफआईएन सिक्क्योरिटीज फाइनेंस लिमिटेड	-0.22	28.59	-0.77	0.20	28.66	0.70	0.31	28.96	1.07

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
186	आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	0.82	23.24	3.53	1.46	24.74	5.90	2.16	27.14	7.96
187	आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	1.56	16.22	9.62	2.46	18.55	13.26	3.74	22.93	16.31
188	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	50.92	9,999.92	0.51	285.27	9,999.92	2.85	514.26	10,731.19	4.79
189	इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड	5.91	1,859.44	0.32	0.49	2,207.34	0.02	0.94	2,453.86	0.04
190	भारत ऑप्टेल लिमिटेड							60.11	5,778.55	1.04
191	इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड	-1.25	10.00	-12.50	-1.16	10.00	-11.60	6.38	10.00	63.80
192	इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड	-334.01	574.01	-58.19	-320.54	444.61	-72.09	-159.62	473.06	-33.74

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
193	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	22.48	346.49	6.49	-27.20	319.87	-8.50	6.86	319.26	2.15
194	भारत व्यापार संवर्धन संगठन	92.00	2,114.12	4.35	-81.37	2,030.78	-4.01	-52.83	1,971.87	-2.68
195	इंडिया यूनाइटेड टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड	10.08	163.25	6.17	10.29	173.54	5.93	10.29	173.54	5.93
196	इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.45	74.98	0.60	11.05	85.90	12.86	33.76	117.89	28.64
197	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,313.23	90,433.15	1.45	21,836.04	1,07,164.32	20.38	24,184.10	1,29,321.49	18.70
198	भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड	528.57	1327.82	39.81	189.90	1466.95	12.95	663.69	1883.88	35.23

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
199	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	3,692.42	30,962.43	11.93	4,416.13	35,913.38	12.30	6,089.84	40,996.34	14.85
200	इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड	291.74	957.10	30.48	315.66	1,167.47	27.04	555.51	1,548.15	35.88
201	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड	214.55	2,262.22	9.48	346.41	2,736.08	12.66	633.53	4,962.72	12.77
202	भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड	-101.60	3,441.03	-2.95	-100.51	3,340.52	-3.01	-99.31	3,255.38	-3.05
203	इंडियन वैक्सीन्स कंपनी लिमिटेड	-0.45	8.28	-5.43	-0.04	8.24	-0.49	-3.70	4.54	-81.50
204	इंडो-रूसी हेलिकॉप्टर्स लिमिटेड	-0.34	8.71	-3.90	-0.80	7.92	-10.10	-0.33	7.59	-4.35
205	इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड	-5.31	42.57	-12.47	2.03	289.60	0.70	1.95	577.55	0.34

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
206	इनलैंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड	0.00	-0.05	0.00	-0.25	0.70	-35.71	-0.89	-0.19	468.42
207	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	35.58	-424.65	-8.38	34.76	-389.89	-8.92	22.26	-367.63	-6.06
208	इरकॉन अक्लोली-शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड							0.00	0.05	0.00
209	इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	0.77	167.60	0.46	0.65	168.25	0.39	5.87	196.92	2.98
210	इरकॉन गुडगांव रेवारी हाईवे लिमिटेड				0.01	0.06	16.67	-0.01	18.40	-0.05
211	इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	11.51	153.89	7.48	5.75	159.64	3.60	5.30	164.94	3.21
212	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	489.79	4,161.13	11.77	404.56	4,406.48	9.18	544.32	4,620.96	11.78
213	इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड							0.00	0.05	0.00

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
214	इस्कॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	-17.18	149.62	-11.48	-21.39	128.24	-16.68	-24.62	169.41	-14.53
215	इस्कॉन शिव पुरी गुना लिमिटेड	-30.83	87.81	-35.11	-14.06	73.75	-19.06	-12.05	61.70	-19.53
216	इस्कॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	0.24	136.06	0.18	0.28	136.34	0.21	60.16	239.90	25.08
217	आईआरईएल आईडीसीओएल लिमिटेड	-0.02	0.08	-25.00	-0.03	1.01	-2.97	-0.05	1.87	-2.67
218	आईटीपीओ सर्विसेज लिमिटेड				0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00
219	जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड	6.13	161.09	3.81	2.02	163.11	1.24	2.31	165.42	1.40
220	जम्मू और कश्मीर खनिज विकास निगम लिमिटेड	-3.80	10.08	-37.70	-1.35	8.74	-15.45	-0.90	7.83	-11.49

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभों के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभों के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभों के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
221	जल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड				-1,120.36	0.00	0.00	-0.48	281.49	-0.17
222	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	1.33	56.94	2.34	1.28	90.86	1.41	2.02	92.87	2.18
223	झारखंड इंधन पावर लिमिटेड	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00
224	झारखंड राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड	-0.01	-0.07	-14.29	-0.01	-0.07	-14.29	-0.01	-0.08	-12.50
225	जोगीघोषा लॉजिस्टिक्स पार्क लिमिटेड							0.00	0.01	0.00
226	कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड	103.98	1,561.01	6.66	134.53	1,755.60	7.66	131.84	1,865.75	7.07
227	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	22.99	198.87	11.56	23.18	218.97	10.59	24.66	239.09	10.31

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभों के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभों के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभों के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
228	कर्नाटक सौर ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	44.16	97.41	45.33	45.43	178.90	25.39	49.92	210.36	23.73
229	कर्नाटक व्यापार संवर्धन संगठन	2.68	140.06	1.91	3.08	143.14	2.15	1.32	144.46	0.91
230	कर्नाटक विजयनगर स्टील लिमिटेड	-0.49	-0.54	-90.74	-0.68	-1.21	-56.20	-0.70	-1.91	-36.65
231	कवरत्ती स्मार्ट सिटी लिमिटेड	-0.01	0.05	-20.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.04	0.00
232	केआईओसीएल लिमिटेड	43.48	1,915.93	2.27	301.17	1,985.99	15.16	313.41	2,143.64	14.62
233	किश्तवाड़ ट्रांसमिशन लिमिटेड							0.00	0.01	0.00
234	कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड	-309.80	2,325.60	-13.32	-334.18	2,541.87	-13.15	-339.73	2,551.88	-13.31
235	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.41	-1.91	-21.47	-0.01	-1.92	-0.52	0.00	-1.92	0.00

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
236	कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-236.92	1,185.08	-19.99	0.00	1,402.92	0.00	0.06	3,758.62	0.00
237	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5.96	1,911.32	0.31	-366.41	1,570.18	-23.34	-135.08	1,458.68	-9.26
238	कुमारकृष्णा फ्रंटियर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड	9.23	26.55	34.76	5.17	24.70	20.93	4.16	27.29	15.24
239	लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड	37.78	335.94	11.25	29.14	365.08	7.98	23.56	388.64	6.06
240	लक्षद्वीप पर्यटन विकास निगम	-0.29	-0.25	-116.00	-0.29	-0.25	-116.00	-0.29	-0.25	-116.00
241	लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड	-2,955.75	920.50	-321.10	-0.21	995.50	-0.02	-0.20	1,440.50	-0.01
242	लोकतक डाउन स्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.10	143.27	0.07	0.00	151.88	0.00	0.01	160.21	0.01

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
243	लखनऊ सौर ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	-3.76	-3.11	-120.90	1.65	-1.46	-113.01	1.28	-0.18	-711.11
244	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	-134.88	-630.89	-21.38	2.87	-695.23	-0.41	162.05	-505.39	-32.06
245	महानदी बेसिन पावर लिमिटेड	-0.03	-5.94	-0.51	-0.03	-5.97	-0.50	-0.02	-5.99	-0.33
246	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	-0.83	-0.81	-102.47	-0.06	-0.87	-6.90	-0.02	89.07	-0.02
247	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	6,427.39	3,878.82	165.70	6,872.35	5,533.04	124.21	8,480.51	8,212.55	103.26
248	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	-3,695.68	-13,585.65	-27.20	-2,461.79	-16,039.88	-15.35	-2,602.59	-18,656.46	-13.95
249	महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	-0.03	-131.61	-0.02	-0.03	-131.64	-0.02	-625.87	-757.51	-82.62

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
250	महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-62.56	4,151.13	-1.51	-161.78	4,626.35	-3.50	-237.42	4,868.78	-4.88
251	महाराष्ट्र रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	-0.38	92.86	-0.41	1.28	101.43	1.26	3.41	514.13	0.66
252	मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.40	-1.86	21.51	-0.01	-1.87	0.53	0.00	-1.87	0.00
253	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	-2,707.64	7,799.53	-34.72	-240.46	7,528.37	-3.19	2,955.27	7,196.34	41.07
254	मणिपुर स्टेट ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	-30.86	-183.77	-16.79	-36.91	-220.68	-16.73	-250.31	-470.99	-53.15
255	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	415.02	2,590.88	16.02	479.57	2,919.01	16.43	586.47	3,321.31	17.66
256	मेकॉन लिमिटेड	69.00	398.24	17.33	6.24	371.09	1.68	13.70	382.93	3.58
257	मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड	0.26	5.37	4.84	0.14	5.50	2.55	0.20	5.69	3.51

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
258	मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	146.13	567.04	25.77	149.79	674.06	22.22	20.21	679.06	2.98
259	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	159.73	958.39	16.67	166.29	1,072.63	15.50	1,76.31	1,190.72	14.81
260	एमजेएसजे कोल लिमिटेड	-19.61	74.48	-26.33	-0.44	74.04	-0.59	0.09	74.13	0.12
261	एमएमटीसी लिमिटेड	-227.11	1,184.14	-19.18	-769.69	422.46	-182.19	-241.93	193.40	-125.09
262	एमएनएच शक्ति लिमिटेड	1.41	89.41	1.58	1.28	90.69	1.41	0.86	41.55	2.07
263	मोहनलाल गंज ट्रांसमिशन लिमिटेड							0.00	0.01	0.00
264	मोइल लिमिटेड	248.22	2,763.38	8.98	176.63	2,819.90	6.26	376.98	2,141.51	17.60
265	एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-1 लिमिटेड				-0.87	-0.82	106.10	-0.80	-1.62	49.38
266	एमएसटीसी लिमिटेड	75.20	279.83	26.87	101.07	354.96	28.47	200.09	465.48	42.99

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
267	मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-20.19	3,362.89	-0.60	-21.39	3,741.37	-0.57	-19.49	4,313.71	-0.45
268	मुंबई रेल विकास निगम लिमिटेड	19.60	244.34	8.02	23.25	240.30	9.68	7.57	235.19	3.22
269	म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड							18.10	6,549.75	0.28
270	नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	111.33	4,575.00	2.43	182.57	5,035.77	3.63	436.99	5,188.10	8.42
271	नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड	-9.08	15.34	-59.19	-11.04	4.76	-231.93	-12.82	-8.26	155.21
272	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	138.23	9,988.07	1.38	1,299.53	10,680.70	12.17	2,951.97	12,184.34	24.23
273	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	26.29	1,947.75	1.35	34.21	2,036.30	1.68	30.56	2,068.65	1.48

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
274	भारतीय राष्ट्रीय साइकिल निगम लिमिटेड	-21.37	-629.26	-3.40	-20.96	-650.22	-3.22	-21.26	-671.48	-3.17
275	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड	26.85	805.41	3.33	43.41	1,490.31	2.91	47.04	1,829.50	2.57
276	नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	0.68	13.98	4.86	2.91	16.89	17.23	7.49	24.39	30.71
277	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	-171.01	1,918.43	-8.91	249.63	2,168.93	11.51	108.20	2,279.03	4.75
278	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड	-8.15	27.86	-29.25	0.64	28.50	2.25	-6.74	21.76	-30.97
279	नेशनल फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड	0.03	1.17	2.56	0.03	1.20	2.50	0.02	1.21	1.65
280	राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम	11.99	478.90	2.50	9.21	490.06	1.88	6.20	496.22	1.25

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभान्श के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभान्श के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभान्श के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
281	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	-11.19	88.42	-12.66	-9.63	78.59	-12.25	-1.57	76.76	-2.05
282	नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	55.92	7,700.74	0.73	22.43	10,721.35	0.21	83.93	13,351.85	0.63
283	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	87.62	265.11	33.05	84.35	323.09	26.11	113.29	410.39	27.61
284	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक.	90.76	592.14	15.33	98.23	695.69	14.12	46.17	741.86	6.22
285	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	-4,108.34	-2,167.80	-189.52	-561.87	589.78	-95.27	-1,674.72	2,766.32	-60.54
286	राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना निधि ट्रस्टी लिमिटेड	0.04	-0.19	-21.05	0.06	-0.13	-46.15	0.03	-0.10	-30.00
287	राष्ट्रीय जूट निर्माता निगम लिमिटेड	-0.62	-222.59	-0.28	-2.39	-224.98	-1.06	-8.13	-228.52	-3.56

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
288	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम	64.18	2,686.50	2.39	65.66	2,870.68	2.29	67.64	3,039.34	2.23
289	नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	19.29	189.66	10.17	24.51	216.05	11.34	35.10	241.48	14.54
290	भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम लिमिटेड	-0.17	9.27	-1.83	0.19	9.45	2.01	0.05	9.50	0.53
291	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम	6.41	798.32	0.80	23.62	854.25	2.76	15.92	875.22	1.82
292	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम	60.98	2,088.66	2.92	47.82	2,136.24	2.24	48.78	2,185.31	2.23
293	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	37.52	1,077.55	3.48	26.35	1,103.82	2.39	24.45	1,128.22	2.17

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभों के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभों के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभों के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
294	राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड	29.92	671.83	4.45	2.44	659.90	0.37	10.76	668.26	1.61
295	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	99.19	987.13	10.05	101.59	1,056.33	9.62	108.23	1,131.70	9.56
296	राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड	-346.55	1,547.99	-22.39	-344.66	1,204.12	-28.62	-344.66	1,204.12	-28.62
297	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	79.87	1,523.61	5.24	201.74	1,691.50	11.93	182.86	1,774.75	10.30
298	एनबीसीसी पर्यावरण इंजीनियरिंग लिमिटेड	0.02	1.01	1.98	0.01	1.02	0.98	0.01	1.03	0.97
299	एनबीसीसी इंटरनेशनल लिमिटेड	0.03	1.01	2.97	0.02	1.03	1.94	0.02	1.04	1.92
300	एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड	4.13	23.30	17.73	9.55	31.45	30.37	4.26	32.97	12.92
301	एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड				-0.04	0.96	-4.17	0.02	0.98	2.04

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
302	नेपा लिमिटेड	-71.26	62.16	-114.64	-53.90	101.21	-53.26	-59.90	119.72	-50.03
303	न्यू सिटी ऑफ बॉम्बे मैन्युफैक्चरिंग मिल्स लिमिटेड	-1.29	63.27	-2.04	-1.33	61.94	-2.15	-1.33	61.94	-2.15
304	नई दिल्ली नगर पालिका परिषद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	-53.36	276.51	-19.30	-176.17	100.35	-175.56	2.36	135.96	1.74
305	न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड	51.29	61.29	83.68	121.84	167.74	72.64	342.99	1,441.77	23.79
306	नेयवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड	-1.28	3,047.63	-0.04	-0.97	3,245.89	-0.03	-0.33	3,870.14	-0.01
307	एनएचडीसी लिमिटेड	919.97	5,562.79	16.54	664.63	5,692.53	11.68	512.96	5,644.67	9.09
308	एनएचपीसी लिमिटेड	3,007.17	28,035.43	10.73	3,233.37	30,005.36	10.78	3,537.71	32,119.85	11.01
309	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	1,413.85	12,639.51	11.19	1,041.79	13,574.68	7.67	1,236.78	13,806.64	8.96

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
310	एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड	143.15	2,491.24	5.75	363.00	2,785.08	13.03	211.28	2,625.16	8.05
311	एनएमडीसी सीएसआर फाउंडेशन लिमिटेड	-2.92	8.91	-32.77	-3.90	5.02	-77.69	1.02	6.04	16.89
312	एनएमडीसी लिमिटेड	3,610.12	27,533.95	13.11	6,253.05	29,756.14	21.01	9,398.48	34,843.97	26.97
313	एनएमडीसी स्टील लिमिटेड	-0.01	0.01	-100.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.04	-25.00
314	एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड	-3.31	186.75	-1.77	-2.80	184.49	-1.52	-2.52	181.66	-1.39
315	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड	165.84	5,754.31	2.88	47.91	5,802.98	0.83	148.89	5,908.70	2.52
316	पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	-4.39	-12.31	-35.66	-1.16	-12.63	-9.18	-28.33	-40.77	-69.49
317	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड	-7.75	-45.15	-17.17	-6.54	-47.93	-13.64	-4.63	-21.98	-21.06

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
318	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	4,971.43	4,382.57	113.44	4,398.39	6,616.08	66.48	4,857.05	7,871.34	61.71
319	एनपीसीआईएल इंडियन ऑयल न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.06	1.35	4.44	0.06	1.41	4.26	0.04	1.45	2.76
320	एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड				-0.61	5.39	-11.32	1.90	7.29	26.06
321	एनटीपीसी ईडीएमसी वेस्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड				-0.91	-0.71	-128.17	-2.05	-2.76	-74.28
322	एनटीपीसी इलेक्ट्रिक सप्लाइ कंपनी लिमिटेड	7.38	49.76	14.83	5.52	55.28	9.99	0.29	55.58	0.52
323	एनटीपीसी लिमिटेड	10,112.81	1,06,507.93	9.49	13,769.52	1,18,935.41	11.58	16,111.42	1,28,000.99	12.59
324	एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.04	0.00

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
325	एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड				-3.51	291.54	-1.20	0.11	727.78	0.02
326	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड	17.53	370.29	4.73	92.02	442.31	20.80	150.26	562.57	26.71
327	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	4,458.98	39,031.99	11.42	4,370.73	42,933.90	10.18	6,394.78	46,147.08	13.86
328	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	1,381.32	5,204.38	26.54	3,036.10	5,496.03	55.24	3,561.56	8,288.08	42.97
329	ओडिशा इंफ्रा पावर लिमिटेड	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00
330	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	13,444.54	1,94,322.15	6.92	11,246.44	2,04,542.61	5.50	40,305.74	2,37,132.13	17.00
331	ऑयल इंडिया लिमिटेड	2,584.06	23,854.68	10.83	1,741.59	25,678.65	6.78	3,887.31	29,358.52	13.24
332	ओमनीबस औद्योगिक विकास निगम दमन,	24.24	183.52	13.21	26.16	209.08	12.51	24.50	232.93	10.52

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
	दीव और दादरा और नगर हवेली लिमिटेड									
333	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	-7,264.48	27,268.87	-26.64	1,826.95	30,561.36	5.98	3,247.53	35,681.78	9.10
334	ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड	-790.74	-103.04	-767.41	151.31	2,948.80	5.13	-610.63	5,402.20	-11.30
335	उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड	0.00	-0.08	0.00	0.00	-0.07	0.00	0.00	-0.07	0.00
336	पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	-0.41	671.31	-0.06	-0.21	1,197.45	-0.02	-0.03	1,670.39	0.00
337	पवन हंस लिमिटेड	-23.08	970.54	-2.38	-8.87	981.56	-0.90	-13.13	970.01	-1.35
338	पीईसी लिमिटेड	-147.27	-1,780.12	-8.27	-129.62	-1,909.21	-6.79	-314.29	-2,223.98	-14.13
339	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	58.15	59.97	96.97	27.10	87.18	31.09	37.68	111.31	33.85
340	पांडिचेरी अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-1.52	-0.48	316.67	-1.37	-1.83	74.86	0.16	-1.71	-9.36

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
341	पोर्ट ब्लेयर स्मार्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर	0.00	212.85	0.00	0.00	212.85	0.00	0.00	212.85	0.00
342	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5,655.14	45,164.11	12.52	8,444.01	52,393.12	16.12	10,021.90	59,350.28	16.89
343	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	10,811.18	64,439.72	16.78	11,935.78	69,578.84	17.15	17,093.76	7,6151.57	22.45
344	पावर ग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	9.64	24.45	39.43	4.94	21.61	22.86	16.76	25.02	66.99
345	पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसको लिमिटेड	-0.33	-0.28	-117.86	-0.01	111.66	-0.01	0.91	115.57	0.79
346	पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड				0.00	0.01	0.00	-0.01	62.34	-0.02
347	पावरग्रिड भडला ट्रांसमिशन लिमिटेड				-0.72	-0.67	-107.46	0.15	19.75	0.76

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
348	पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.12	-0.60	-20.00	0.00	49.40	0.00	-0.07	89.43	-0.08
349	पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00	0.01	0.00	0.00	97.71	0.00	-0.03	179.97	-0.02
350	पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड				0.00	0.01	0.00	-0.02	22.19	-0.09
351	पावरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड							-0.31	-0.26	-119.23
352	पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00	0.01	0.00	0.00	113.41	0.00	2.26	143.26	1.58
353	पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00	0.05	0.00	1.04	78.24	1.33	17.12	101.60	16.85

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
354	पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	-0.33	-0.28	-117.86	-0.04	161.03	-0.02	5.96	203.84	2.92
355	पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00	289.33	0.00	19.15	568.78	3.37	191.62	692.24	27.68
356	पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00	0.01	0.00	0.00	32.01	0.00	-0.02	129.69	-0.02
357	पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00	119.99	0.00	0.95	214.44	0.44	38.09	254.51	14.97
358	पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड				0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
359	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	-29.48	83.27	-35.40	-37.05	252.87	-14.65	7.50	264.27	2.84

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
360	पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड				-0.51	-0.46	-110.87	-0.01	0.58	-1.72
361	पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.88	-0.83	-106.02	0.00	20.64	0.00	-0.06	108.06	-0.06
362	पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड				-0.59	-0.54	109.26	0.12	46.88	0.26
363	पावरग्रिड साउदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	8.68	716.10	1.21	108.68	824.77	13.18	-37.51	639.79	-5.86
364	पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड							-0.33	8.67	-3.81
365	पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	0.00	125.04	0.00	0.01	168.06	0.01	20.16	195.00	10.34

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
366	पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	-0.01	-19.40	-0.05	-0.01	-19.41	-0.05	-0.01	-19.42	-0.05
367	प्राइज पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड	-16.96	111.68	-15.19	3.59	115.30	3.11	-5.79	109.53	-5.29
368	प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड	31.83	154.95	20.54	19.07	157.54	12.10	10.81	167.40	6.46
369	पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड	-0.01	2.28	-0.44	-0.01	2.27	-0.44	-0.01	2.26	-0.44
370	पंजाब लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	0.95	175.79	0.54	-9.13	166.65	-5.48	-5.93	160.69	-3.69
371	रेल विकास निगम लिमिटेड	753.32	4,499.77	16.74	940.55	4,965.57	18.94	1,087.21	5,631.41	19.31
372	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	138.35	1,361.28	10.16	140.41	1,402.73	10.01	208.34	1,516.02	13.74

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
373	रेलटेल एंटरप्राइजेज लिमिटेड	2.70	18.04	14.97	2.05	20.09	10.20	1.30	21.39	6.08
374	राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	-26.21	-89.93	-29.14	-9.34	-99.27	-9.41	-2.13	-101.40	-2.10
375	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड	-17.07	93.93	-18.17	-12.78	81.09	-15.76	-8.46	72.94	-11.60
376	राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड				0.05	0.10	50.00	-0.20	-0.10	200.00
377	रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-2.15	-11.84	-18.16	-3.02	-14.88	-20.30	-0.75	-15.63	-4.80
378	राष्ट्रीय केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	208.15	3,186.27	6.53	373.11	3,338.47	11.18	704.36	3,889.23	18.11
379	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	-3,910.17	3,271.79	-119.51	-789.10	2,464.25	-32.02	913.19	3,174.55	28.77

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभों के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभों के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभों के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
380	रैटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड							-0.43	186.27	-0.23
381	रियल एस्टेट विकास एवं निर्माण निगम राजस्थान लिमिटेड	0.18	3.59	5.01	0.15	3.74	4.01	0.08	3.82	2.09
382	आरईसी लिमिटेड	4,886.16	35,076.56	13.93	8,361.78	42,867.97	19.51	10,045.92	50,427.20	19.92
383	आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड	12.47	168.20	7.41	25.62	297.98	8.60	53.03	328.58	16.14
384	आरईएमसी लिमिटेड	35.02	166.28	21.06	24.13	179.91	13.41	45.32	216.24	20.96
385	रिन्यूएबल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड	1.14	3.39	33.63	1.92	5.31	36.16	1.99	5.74	34.67
386	रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड	16.16	27.72	58.30	13.45	40.88	32.90	12.75	49.93	25.54

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
387	रिचर्डसन और क्रुडास (1972) लिमिटेड	29.47	214.56	13.74	13.41	227.97	5.88	19.35	247.31	7.82
388	राइट्स लिमिटेड	596.39	2,576.62	23.15	424.35	2,321.93	18.28	497.10	2,399.26	20.72
389	रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड	-0.01	-0.02	-50.00	-0.02	-0.02	-100.00	0.00	-0.02	0.00
390	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	6.67	556.78	1.20	0.88	687.99	0.13	6.98	794.77	0.88
391	सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्रीज लिमिटेड	15.53	57.54	26.99	2.48	60.02	4.13	1.62	61.63	2.63
392	सेल रिफ्रेक्टरी कंपनी लिमिटेड	14.22	94.98	14.97	11.88	105.71	11.24	19.66	120.38	16.33
393	सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00
394	सांभर साल्ट्स लिमिटेड	-2.59	-46.69	-5.55	5.35	-41.36	-12.94	10.85	-30.52	-35.55
395	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	-15.73	50.02	-31.45	-48.65	0.50	-9730.00	7.58	8.08	93.81

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
396	सिक्नोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	527.60	3,971.39	13.29	423.81	4,469.97	9.48	689.19	4,854.23	14.20
397	सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1.65	799.99	0.21	0.81	800.80	0.10	-0.10	800.70	-0.01
398	एसएचसीआईएल सर्विसेज लिमिटेड	6.00	69.35	8.65	17.16	79.22	21.66	21.35	91.73	23.27
399	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स लिमिटेड							0.00	0.01	0.00
400	शॉगटोंग करछम वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	सिडकुल कॉनकॉर इंफ्रा कंपनी लिमिटेड	6.60	90.37	7.30	-0.29	90.08	-0.32	0.21	90.28	0.23
402	सिलवासा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	5.35	6.07	88.14	-0.16	-1.90	8.42	-0.16	-1.90	8.42

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभों के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभों के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभों के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
403	एसजेवीएन लिमिटेड	1,651.89	11,759.31	14.05	1,633.04	12,761.84	12.80	977.52	13,128.61	7.45
404	एसजेवीएन थर्मल प्राइवेट लिमिटेड	-0.37	996.29	-0.04	1.14	2147.43	0.05	-1.14	2,511.29	-0.05
405	भारतीय सौर ऊर्जा निगम	178.94	695.72	25.72	177.71	873.58	20.34	240.32	2,060.46	11.66
406	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	1,734.92	3,064.35	56.62	1439.95	4,308.00	33.43	1,544.87	5,442.08	28.39
407	एसटीसीएल लिमिटेड	-0.47	-4,565.09	0.01	0.77	-4,564.22	-0.02	7.12	-4,557.11	-0.16
408	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	2,021.54	38,400.61	5.26	3,850.02	42,408.98	9.08	12,015.04	51,484.42	23.34
409	स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	40.85	2,235.62	1.83	68.84	2,684.20	2.56	136.55	4,552.99	3.00
410	स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड	-29.62	48.02	-61.68	-13.00	35.03	-37.11	1.57	36.63	4.29

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभों के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभों के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभों के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
411	स्टॉक होल्डिंग सिन्डिकेटीज आईएफएससी लिमिटेड	-1.57	13.92	-11.28	-1.85	11.74	-15.76	-2.30	12.93	-17.79
412	सूरत इंडीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट लिमिटेड	0.41	7.28	5.63	0.20	7.48	2.67	0.24	7.73	3.10
413	सूटी टेक ऑप्शंस लिमिटेड	-0.01	-0.30	3.33	-0.01	-0.31	3.23	-0.01	-0.32	3.13
414	तालचेर फर्टिलाइजर लिमिटेड	-3.02	456.79	-0.66	6.57	1,591.29	0.41	-5.94	2,394.30	-0.25
415	तमिलनाडु व्यापार संवर्धन संगठन	36.02	325.29	11.07	6.33	306.87	2.06	3.89	310.20	1.25
416	टांडा ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
417	तातिया आंध्र मेगा पावर लिमिटेड	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभों के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभों के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभों के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
418	टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड	-21.04	-42.11	-49.96	1.39	-40.73	-3.41	0.08	-40.65	-0.20
419	टीसीआईएल एलटीआर लिमिटेड	-7.56	9.01	-83.91	-3.00	6.02	-49.83	-5.20	0.82	-634.15
420	टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड	44.43	585.88	7.58	52.77	611.19	8.63	30.33	612.79	4.95
421	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	920.25	9,493.47	9.69	1,092.41	9,837.93	11.10	894.78	10,178.15	8.79
422	बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड	-10.28	-155.72	6.60	6.91	-148.23	-4.66	7.81	-141.10	-5.54
423	ब्रेथवेट बर्न और जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	1.96	203.48	0.96	11.68	204.84	5.70	3.15	209.37	1.50
424	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-113.23	-1,120.34	-10.11	-105.06	-1,225.39	-8.57	-79.05	-1,304.44	-6.06

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
425	भारतीय कपास निगम लिमिटेड	38.07	367.45	10.36	26.12	372.64	7.01	13.29	363.38	3.66
426	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनेरल्स इंडिया लिमिटेड	14.91	250.20	5.96	13.48	251.61	5.36	11.59	250.82	4.62
427	द फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	975.52	-491.43	-198.51	351.98	-174.98	-201.15	353.28	189.37	186.56
428	भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड	-10.27	13.82	-74.31	-10.21	13.82	-73.88	-19.37	13.82	-140.16
429	इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड	0.00	-0.04	0.00	0.00	-0.05	0.00	0.00	-0.05	0.00
430	भारतीय जूट निगम लिमिटेड	15.40	147.70	10.43	12.15	155.24	7.83	-13.78	133.69	-10.31

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
431	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,417.75	25,971.51	5.46	1604.69	36,450.64	4.40	164.27	38,191.19	0.43
432	ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	-1,524.11	3,649.66	-41.76	-1,525.44	7,802.36	-19.55	-3,115.16	6,783.32	-45.92
433	उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	-76.69	57.08	-134.36	-39.65	18.07	-219.42	-14.49	3.53	-410.48
434	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	302.35	7,146.13	4.23	618.10	7,749.97	7.98	794.79	8,820.58	9.01
435	भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड	-113.63	-61.51	-184.73	-51.23	-109.20	-46.91	-93.97	-197.57	-47.56
436	हूप कम्फर्ट्स लिमिटेड							16.38	4,573.67	0.36
437	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड	-1.69	-100.60	1.68	-7.78	-108.38	7.18	9.57	-98.81	-9.69
438	टुस्को लिमिटेड				-0.26	9.74	-2.67	-1.03	18.71	-5.51

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभों के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभों के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभों के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
439	उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड				-1.36	136.53	-1.00	-12.94	124.32	-10.41
440	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	-1,485.85	1,441.66	-103.07	-984.68	6,774.79	-14.53	-2,135.55	5,147.69	-41.49
441	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	482.05	3,208.27	15.03	470.74	3,557.25	13.23	576.72	3,944.70	14.62
442	उर्वारक विदेश लिमिटेड	-0.01	0.07	-14.29	-0.01	0.06	-16.67	-0.01	0.06	-16.67
443	उत्कल अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-0.81	-25.73	3.15	-0.64	-26.43	2.42	-0.88	-27.31	3.22
444	उत्कर्ष एल्युमीनियम धातु निगम लिमिटेड	-3.26	36.75	-8.87	0.26	37.01	0.70	0.62	37.63	1.65
445	विज्ञान इंडस्ट्रीज लिमिटेड	-4.70	-0.01	-47,000.00	-6.12	-5.90	-103.73	-6.00	53.85	-11.14
446	विशाखापत्तनम पोर्ट लॉजिस्टिक्स पार्क लिमिटेड	-16.05	110.42	-14.54	-12.59	97.83	-12.87	-8.21	89.62	-9.16

क्रम सं.	सीपीएसई	2019-20			2020-21			2021-22		
		कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात शुद्ध लाभ	इक्विटी	आरओई (में %)	कर एवं वरीयता लाभांश के पश्चात निवल लाभ	इक्विटी	आरओई (% में)
447	वाष्कोस लिमिटेड	143.43	626.04	22.91	40.52	617.14	6.57	40.85	619.45	6.59
448	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	-528.28	381.29	-138.55	234.29	548.88	42.69	942.41	1,505.82	62.58
449	यंत्र इंडिया लिमिटेड							-123.12	2,577.89	-4.78
450	यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	0.00	-0.06	0.00	0.00	-0.07	0.00	-0.01	-0.08	12.50
451	यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड	0.00	-0.03	0.00	-0.01	-0.03	33.33	-0.01	-0.04	25.00
452	जेनिथ सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	-2.02	14.73	-13.71	3.15	17.85	17.65	41.20	22.65	181.90
	कुल योग	82,746.63	14,22,646.39	5.82	1,59,537.80	15,98,295.45	9.98	2,37,960.84	18,25,434.09	13.04

अनुलग्नक-XIII (पैरा संख्या 2.5.1.1 देखें)

उन सीपीएसई की सूची जिन्होंने अपने वित्तीय विवरण में संशोधन किया

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी) / सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)
1	महाराष्ट्र एक्जीक्यूटिव एंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	जीसीओसी
2	नेशनल फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड	जीसी
3	आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी लिमिटेड	जीसी
4	एसयूटीआई टेक ऑप्शंस लिमिटेड	जीसी
5	यूबीआई सर्विसेज लिमिटेड	जीसीओसी
6	यूल इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	जीसी
7	यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड	जीसी

अनुलग्नक-XIV (पैरा संख्या 2.5.1.2 देखें)

उन सीपीएसई की सूची जहां सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट संशोधित की

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी) / सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)
1	आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	जीसीओसी
2	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	जीसी
3	अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	जीसीओसी
4	बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	जीसीओसी
5	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	जीसी
6	बीईएमएल लैंड एसेट्स लिमिटेड	जीसी
7	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	जीसी
8	भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड	जीसी
9	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड	जीसी
10	भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड	जीसी
11	भोर सागर पोर्ट लिमिटेड	जीसीओसी
12	बोकारो पावर सप्लाई कंपनी (प्रा.) लिमिटेड	जीसीओसी
13	कैनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड	जीसीओसी
14	कैनबैंक वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड	जीसीओसी
15	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	जीसी
16	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड	जीसी
17	चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड	जीसीओसी
18	छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड	जीसी
19	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	जीसी
20	कोल इंडिया लिमिटेड	जीसी
21	कॉनकॉर एयर लिमिटेड	जीसी
22	क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	जीसीओसी
23	ट्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	जीसी
24	घोगरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	जीसी
25	सरकारी ई-बाज़ार	जीसी
26	हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड	जीसीओसी
27	एचएमटी इंटरनेशनल लिमिटेड	जीसी
28	एचएमटी लिमिटेड	जीसी
29	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	जीसी

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी) / सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)
30	एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड	जीसी
31	एचएसआरसी इंफ्रा कंपनी लिमिटेड	जीसी
32	आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड	जीसी
33	आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड	जीसी
34	आईएफआईएन क्रेडिट लिमिटेड	जीसी
35	इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड	जीसीओसी
36	भारत पर्यटन विकास निगम	जीसी
37	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	जीसी
38	भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड	जीसी
39	इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	जीसी
40	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	जीसी
41	आईटीपीओ सर्विसेज लिमिटेड	जीसी
42	जम्मू और कश्मीर खनिज विकास निगम लिमिटेड	जीसी
43	जल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जीसी
44	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	जीसी
45	कर्नाटक विजयनगर स्टील लिमिटेड	जीसी
46	कोलकाता पोर्ट एक्सीरशन लिमिटेड	जीसीओसी
47	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	जीसी
48	महाराष्ट्र एक्जीक्यूटिव एंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	जीसीओसी
49	महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड	जीसीओसी
50	मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड	जीसीओसी
51	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	जीसी
52	एनएबीएफआईएनएस लिमिटेड	जीसीओसी
53	नबसमृद्धि फाइनेंस लिमिटेड	जीसीओसी
54	नेशनल फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड	जीसी
55	नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	जीसीओसी
56	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	जीसी
57	एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड	जीसी
58	निकॉन लिमिटेड	जीसी
59	एनएमडीसी लिमिटेड	जीसी
60	एनएमडीसी स्टील लिमिटेड	जीसी
61	एनआरटीयू फाउंडेशन	जीसी
62	एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड	जीसीओसी

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी) / सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)
63	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड	जीसी
64	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	जीसी
65	ओएनजीसी पेट्रो एडिशन लिमिटेड	जीसी
66	पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड	जीसी
67	पांडिचेरी अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जीसी
68	पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	जीसी
69	पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड	जीसी
70	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	जीसी
71	रैटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जीसी
72	रिन्यूएबल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड	जीसी
73	आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी लिमिटेड	जीसी
74	सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड	जीसी
75	सेल-राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	जीसीओसी
76	एसजेवीएन लिमिटेड	जीसी
77	भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड (सीएफएस)	जीसी
78	एसयूयूटीआई टेक ऑप्शंस लिमिटेड	जीसी
79	सिंड बैंक सर्विसेज लिमिटेड	जीसीओसी
80	तमिलनाडु व्यापार संवर्धन संगठन	जीसी
81	बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड	जीसी
82	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड	जीसी
83	टुस्को लिमिटेड	जीसी
84	उज्ज्वला प्लस फाउंडेशन	जीसीओसी
85	उत्कर्ष धातु निगम लिमिटेड	जीसी
86	विज्ञान इंडस्ट्रीज लिमिटेड	जीसी
87	विशाखापत्तनम पोर्ट लॉजिस्टिक्स पार्क लिमिटेड	जीसी
88	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	जीसी

अनुलग्नक-XV (पैरा संख्या 2.5.1.3 देखें)

उन सीपीएसई की सूची जहां सीएजी द्वारा टिप्पणियां जारी की गईं

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी) /सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)
1	एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (वित्त वर्ष 2020-21)	जीसी
2	एयर इंडिया लिमिटेड (वित्त वर्ष 2020-21)	जीसी
3	एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड (वित्त वर्ष 2020-21)	जीसी
4	आंध्र प्रदेश सौर ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड	जीसी
5	अंगुल सुकिंदा रेलवे लिमिटेड	जीसीओसी
6	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	जीसी
7	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	जीसी
8	बैंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जीसी
9	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	जीसी
10	भारत संचार निगम लिमिटेड	जीसी
11	भोर सागर पोर्ट लिमिटेड	जीसीओसी
12	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	जीसी
13	ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	जीसी
14	कलकत्ता हल्दिया पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड (वित्त वर्ष 2020-21)	जीसीओसी
15	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	जीसी
16	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड	जीसी
17	कोल इंडिया लिमिटेड	जीसी
18	कॉनकॉर एयर लिमिटेड	जीसी
19	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	जीसी
20	क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	जीसीओसी
21	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	जीसी
22	देवगढ़ एयरपोर्ट लिमिटेड (वित्त वर्ष 2020-21)	जीसी
23	धालभूमगढ़ एयरपोर्ट लिमिटेड (वित्तीय वर्ष 2019-2020)	जीसी
24	धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड (वित्त वर्ष 2020-21)	जीसी
25	दीव स्मार्ट सिटी लिमिटेड (वित्त वर्ष 2020-21)	जीसी
26	डीएमई डेवलपमेंट लिमिटेड (वित्त वर्ष 2020-21)	जीसीओसी
27	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	जीसी
28	फेक्ट आरसीएफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड	जीसी
29	सरकारी ई-बाज़ार	जीसी

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी) /सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)
30	भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड (वित्त वर्ष 2020-21)	जीसी
31	हसन मँगलोर रेल विकास कंपनी लिमिटेड	जीसी
32	हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड	जीसी
33	उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी	जीसी
34	आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड	जीसी
35	आईएफसीआई लिमिटेड	जीसी
36	आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड	जीसी
37	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	जीसी
38	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	जीसी
39	इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड (वित्त वर्ष 2020-21)	जीसी
40	आईटीआई लिमिटेड	जीसी
41	कर्नाटक विजयनगर स्टील लिमिटेड	जीसी
42	कन्याकुमारी पोर्ट लिमिटेड	जीसीओसी
43	कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड	जीसी
44	कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जीसी
45	कृष्णापट्टनम रेलवे कंपनी लिमिटेड	जीसीओसी
46	कच्छ रेलवे कंपनी लिमिटेड	जीसीओसी
47	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	जीसी
48	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	जीसी
49	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	जीसी
50	मेकॉन लिमिटेड	जीसी
51	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	जीसी
52	एमपीकॉन लिमिटेड	जीसी
53	मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जीसी
54	नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड	जीसी
55	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	जीसी
56	नेशनल हाई स्पीड रेलवे कंपनी लिमिटेड	जीसी
57	नेशनल हाईवे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (वित्त वर्ष 2020-21)	जीसीओसी
58	राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड	जीसीओसी
59	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक	जीसी
60	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	जीसी
61	एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड	जीसी

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी) /सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)
62	नेपा लिमिटेड	जीसी
63	न्यू मेंगलोर पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड	जीसीओसी
64	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	जीसी
65	एनएमडीसी लिमिटेड	जीसी
66	नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	जीसीओसी
67	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	जीसी
68	एनआरटीयू फाउंडेशन	जीसी
69	एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड	जीसी
70	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	जीसी
71	ऑयल इंडिया लिमिटेड	जीसी
72	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	जीसी
73	पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड	जीसी
74	पीएनबी गिल्ड्स लिमिटेड	जीसीओसी
75	पांडिचेरी अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जीसी
76	पंजाब लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	जीसी
77	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	जीसी
78	रेलटेल एंटरप्राइजेज लिमिटेड	जीसी
79	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	जीसी
80	रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड (वित्त वर्ष 2020-21)	जीसी
81	सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	जीसीओसी
82	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	जीसीओसी
83	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	जीसी
84	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	जीसी
85	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	जीसी
86	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	जीसी
87	उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	जीसी
88	टुस्को लिमिटेड	जीसी
89	तूतीकोरिन पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड	जीसीओसी
90	उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	जीसी
91	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	जीसी
92	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	जीसी

अनुलग्नक-XVI (पैरा संख्या 2.6 देखें)

उन सीपीएसई का विवरण जहां सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखांकन मानक/इंड एस का अनुपालन न किए जाने की सूचना दी गई

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	श्रेणी (सूचीबद्ध/असूचीबद्ध)	सरकारी कंपनी (जीसी) / सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	लेखांकन मानक (एस)/इंड एस की संख्या
1	आंध्र बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	गैर-सूचीबद्ध	जीसीओसी	एस 29
2	एपीआईटीसीओ लिमिटेड	गैर-सूचीबद्ध	जीसीओसी	एस 29
3	बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	गैर-सूचीबद्ध	जीसी	इंड एस 20 और इंड एस 21
4	भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सूचीबद्ध	जीसी	इंड एस 16, इंड एस 20 और इंड एस 36
5	भारत संचार निगम लिमिटेड	गैर-सूचीबद्ध	जीसी	इंड एस 16, इंड एस 109, इंड एस 115 और इंड एस 116
6	कैनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड	गैर-सूचीबद्ध	जीसीओसी	एस 5
7	तथ्य आरसीएफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड	गैर-सूचीबद्ध	जीसी	इंड एस 36
8	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड	सूचीबद्ध	जीसी	इंड एस 37 और इंड एस 105
9	एचएमटी बियरिंग्स लिमिटेड	गैर-सूचीबद्ध	जीसी	इंड एस 37
10	एचएमटी लिमिटेड	सूचीबद्ध	जीसी	इंड एस 2, इंड एस 16, इंड एस 19, इंड एस 36 और इंड एस 109

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	श्रेणी (सूचीबद्ध/असूचीबद्ध)	सरकारी कंपनी (जीसी) / सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	लेखांकन मानक (एएस)/इंड एएस की संख्या
	एचएमटी लिमिटेड (समेकित वित्तीय विवरण)	सूचीबद्ध	जीसी	इंड एएस 2, इंड एएस 16, इंड एएस 19, इंड एएस 36, इंड एएस 37, इंड एएस 40 और इंड एएस 109
11	एचएमटी वॉचेस लिमिटेड	गैर-सूचीबद्ध	जीसी	इंड एएस 37
12	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी	गैर-सूचीबद्ध	जीसी	इंड एएस 20, इंड एएस 37 और इंड एएस 109
13	कर्नाटक व्यापार संवर्धन संगठन	गैर-सूचीबद्ध	जीसी	एएस 29
14	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	सूचीबद्ध	जीसी	इंड एएस 16 और इंड एएस 36
15	मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड	गैर-सूचीबद्ध	जीसीओसी	इंड एएस 16 और इंड एएस 36
16	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक	गैर-सूचीबद्ध	जीसी	इंड एएस 8 और इंड एएस 115
17	एनटीपीसी बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	गैर-सूचीबद्ध	जीसीओसी	इंड एएस 36 और इंड एएस 37
18	तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड	सूचीबद्ध	जीसीओसी	इंड एएस 109
19	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	सूचीबद्ध	जीसी	इंड एएस 16

अनुलग्नक-XVII (पैरा संख्या 2.7 देखें)

उन सीपीएसई का विवरण जहां सीएजी द्वारा जारी प्रबंधन पत्रों के आधार पर महत्वपूर्ण सुधार किया गया

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी) / सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	प्रबंधन पत्र में उजागर की गई खामियां	सुधार किया गया
1.	बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जीसी	- कंपनी के पास एक वर्ष से अधिक उपयोगी जीवन वाले पुर्जों के पूंजीकरण और मूल्यहास के लिए कोई लेखा नीति नहीं थी। साथ ही, कंपनी के पास इंड एस 16 के प्रावधानों के अनुसार पीपीई के घटकीकरण और मूल्यहास की गणना के लिए कोई लेखा नीति नहीं थी। - जहां कंपनी पट्टादाता है, वहां वित्तीय पट्टों के लेखांकन के लिए कंपनी के पास कोई लेखांकन नीति नहीं थी।	- कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान पुर्जों के घटकीकरण सहित मूल्यहास/परिशोधन पर अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीति को संशोधित किया। - कंपनी ने लेखांकन नीति तैयार की और खुलासा किया।
2.	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	जीसी	कंपनी ने एमसीपी गतिविधि के लिए ऐसे व्यय को प्राप्य के रूप में दर्ज किया, जिसे खदान बंद करने की गतिविधि नहीं माना गया।	कंपनी ने मार्च 2022 तक नौ परियोजनाओं की खदान बंद करने की योजना को संशोधित किया।

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी) / सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	प्रबंधन पत्र में उजागर की गई खामियां	सुधार किया गया
3.	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	जीसी	• इंड एस 24 के पैरा 17 के अंतर्गत "संबद्ध पक्ष प्रकटीकरण" पर अपेक्षित प्रकटीकरण की पूर्णता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। • नकदी प्रवाह विवरण इंड एस 7 के प्रावधानों के अनुरूप होना सुनिश्चित किया गया, विशेष रूप से अप्राप्य विदेशी मुद्रा लाभ और हानि पर विचार करते हुए परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह की गणना के संबंध में। • मूल्यहास/परिशोधन की गणना इंड एस -2 के अनुरूप सुनिश्चित की जानी चाहिए। • इंड एस 108 - परिचालन खंडों के अंतर्गत अपेक्षित विस्तृत प्रकटीकरण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।	• कंपनी द्वारा पर्याप्त प्रकटीकरण दिया गया। • कंपनी ने लेखापरीक्षा द्वारा सुझाए गए सुधार का अनुपालन किया। • कंपनी ने लेखापरीक्षा द्वारा सुझाए गए सुधार का अनुपालन किया। • कंपनी द्वारा विस्तृत खुलासा किया गया।
4.	भारत संचार निगम लिमिटेड	जीसी	• आकस्मिक देयताओं से संबंधित इंड एस 37 के प्रावधानों का अनुपालन न करना। • विशिष्ट परियोजनाओं के लिए प्राप्त निधियों का विशिष्ट उपयोग।	• आवश्यक सुधार किये गये। • प्रत्येक परियोजना के लिए अलग खाते खोले गए और सुधार किया गया।

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी) / सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	प्रबंधन पत्र में उजागर की गई खामियां	सुधार किया गया
5.	सेंटबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	जीसीओसी	संयंत्र, संपत्ति और उपकरण को अचल परिसंपत्तियों के रूप में उल्लेखित किया गया था, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III की आवश्यकता के अनुरूप नहीं था।	कंपनी ने 2021-22 में इसमें सुधार किया।
6.	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	जीसी	सीएस-23 के विचलन में, डकरा ओसीपी के स्ट्रिपिंग अनुपात को संशोधित नहीं किया गया था और ओआर का लेखा-जोखा पुराने स्ट्रिपिंग अनुपात के आधार पर किया गया था।	कंपनी ने डकरा ओसीपी के औसत स्ट्रिपिंग अनुपात का तकनीकी मूल्यांकन किया। मानक अनुपात में संशोधन के परिणामस्वरूप, वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी का लाभ ₹23 करोड़ कम हो गया।
7.	कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	जीसी	आकस्मिक देयताओं के विवरण और प्रकृति के संबंध में अपूर्ण प्रकटीकरण।	कंपनी ने वित्तीय विवरणों के नोट्स में आकस्मिक देयताओं के प्रासंगिक विवरण और प्रकृति को शामिल किया।
8.	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	जीसी	कंपनी द्वारा घोषित लाभांश/अंतरिम लाभांश के लेखांकन के संबंध में कंपनी ने कोई लेखांकन नीति तैयार नहीं की है।	कंपनी ने भुगतान/घोषित किए जाने वाले लाभांश/अंतरिम लाभांश के लेखांकन के लिए लेखांकन नीति तैयार की और वित्तीय विवरणों के नोट में उसका समुचित रूप से खुलासा किया।

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी) / सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	प्रबंधन पत्र में उजागर की गई खामियां	सुधार किया गया
9.	ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	जीसी	कंपनी ने आयातित पुर्जों के विदेशी मुद्रा जोखिम का खुलासा नहीं किया।	वर्ष 2021-22 के वित्तीय विवरणों में आवश्यक प्रकटीकरण किया गया है।
10.	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	जीसी	इंड एस 116, इंड एस 19 और इंड एस 107 के अनुसार प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाना आवश्यक था।	इंड एस 116, इंड एस 19 और इंड एस 107 में अपेक्षित प्रकटीकरण का अनुपालन किया गया।
11.	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	जीसी	आकस्मिक परिसंपत्तियों के संबंध में महत्वपूर्ण लेखांकन नीति को इंड एस 37 के अनुसार उपयुक्त रूप से संशोधित करने की आवश्यकता है।	कंपनी ने लेखापरीक्षा सुझाव का अनुपालन किया।
12.	जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	जीसी	जीआईसी रे दुबई शाखा के सॉल्वेंसी घाटे के बारे में गैर-प्रकटीकरण।	कंपनी ने नोट्स में आवश्यक खुलासे किये।
13.	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड	जीसी	कंपनी ने बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों का उचित मूल्य प्राप्त नहीं किया तथा इन परिसंपत्तियों का मूल्यांकन इंड एस 105 के पैरा 15 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, वहन मूल्य पर किया।	निपटान के लिए रखी गई परिसंपत्तियों का उचित मूल्य प्राप्त किया गया और वित्तीय वर्ष 2021-22 के वित्तीय विवरणों में इसका खुलासा किया गया।

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी) / सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	प्रबंधन पत्र में उजागर की गई खामियां	सुधार किया गया
14.	एचपी ऑयल गैस लिमिटेड	जीसी	कंपनी की राजस्व मान्यता नीति की समीक्षा की जानी चाहिए तथा उसे इंड एस 115 के अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए। प्रवर्तक कंपनियों अर्थात् एचपीसीएल और ओआईएल की उधार लागत लेखांकन नीति की समीक्षा की जानी चाहिए तथा वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स में उचित नीति प्रकटीकरण के साथ उसे तदनुसार अपनाया जाना चाहिए।	कंपनी ने राजस्व मान्यता और उधार लागत पर लेखांकन नीतियों को उपयुक्त रूप से संशोधित किया।
15.	आईएचबी लिमिटेड	जीसीओसी	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह की गणना के लिए गैर-नकद मदों अर्थात् अप्राप्त विदेशी मुद्रा पूंजी का समायोजन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।	कंपनी ने परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह की गणना के लिए गैर-नकद मदों अर्थात् अप्राप्त विदेशी मुद्रा पूंजी का समायोजन किया।
16.	भारत व्यापार संवर्धन संगठन	जीसी	कंपनी ने कुछ अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन उनके पांच वर्ष के कानूनी अधिकार को ध्यान में रखते हुए किया, जो उसकी लेखांकन नीति के अनुरूप नहीं था।	वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी ने अपनी लेखा नीति को संशोधित किया, 'अमूर्त संपत्तियों को उपयोग के कानूनी अधिकार की अवधि में समान रूप से पूरी तरह से परिशोधित किया जाता है। जहां उपयोग के कानूनी अधिकार की अवधि उपलब्ध नहीं है, वहां परिसंपत्तियों को तीन वित्तीय वर्षों में

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी) / सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	प्रबंधन पत्र में उजागर की गई खामियां	सुधार किया गया
				परिशोधित किया जाता है, जिस वर्ष से परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है।'
17.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जीसी	आनुपातिक आधार पर मूल्यहास वसूलने के संबंध में इंड एस 16 के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम की अनुसूची II पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार परिसंपत्तियों का मूल्यहास/परिशोधन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।	कंपनी ने वर्ष 2021-22 के वित्तीय विवरणों में लाभ और हानि के विवरण पर प्रभाव के प्रकटीकरण के साथ मासिक समूहीकरण की समयावधि को क्रमबद्ध करने के लिए मूल्यहास के प्रभार में संशोधन किया।
18.	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी	जीसी	विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व को शामिल करने के लिए लेखांकन नीति में उपयुक्त परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है।	कंपनी ने इसे लेखांकन नीति में सम्मिलित कर लिया।
19.	कोंकण एलएनजी लिमिटेड	जीसीओसी	- प्रति शेयर आय की गणना की समीक्षा की जानी चाहिए तथा इंड एस 33 के अनुसार अनिवार्य संचयी परिवर्तनीय वरीयता शेयरों पर दिए जाने वाले लाभांश पर विचार करते हुए उसे सही किया जाना चाहिए। - नकदी और नकदी समकक्षों के लेखांकन को इंड एस 7 की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की आवश्यकता है।	कंपनी ने लेखापरीक्षा सुझाव का अनुपालन किया।

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी) / सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	प्रबंधन पत्र में उजागर की गई खामियां	सुधार किया गया
				कंपनी ने लेखापरीक्षा सुझाव का अनुपालन किया।
20.	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जीसी	कंपनी को अपनी विविध परिचालन गतिविधियों जैसे यात्री सेवाएं, परियोजना राजस्व, माल परिवहन आदि के लिए अपने परिचालन चक्र की समीक्षा करने की आवश्यकता थी।	कंपनी ने अपने परिचालन चक्र की समीक्षा की है और परिचालन से प्राप्त राजस्व का लेखा इंड एस 115 के अनुसार किया गया है।
21.	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	जीसी	कंपनी ने कोल इंडिया लिमिटेड के निर्देशों के अनुसार नमूना परिणाम पर विचार नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप 2020-21 के दौरान कोयला गुणवत्ता भिन्नता का गलत लेखा-जोखा हुआ।	कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रसारित कोयला गुणवत्ता भिन्नता की गणना की एक समान पद्धति का कंपनी द्वारा वर्ष 2021-2022 के लिए वार्षिक खाते तैयार करते समय विधिवत पालन किया गया।
22.	मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जीसी	इंड एस-1 के पैरा संख्या 135(बी) के अनुसार 100 करोड़ रुपये तक के सब-ऑर्डिनेट ऋण जारी करने का खुलासा न करना।	वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आवश्यक खुलासे किए गए।

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी) / सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	प्रबंधन पत्र में उजागर की गई खामियां	सुधार किया गया
			• ₹1 करोड़ से कम के सभी पट्टा समझौतों के लिए पट्टा देयता की मान्यता न देना तथा इंड एस 116 के अनुसार पट्टा देयता का खुलासा न करना। • आरे डिपो कार्य की वर्तमान स्थिति से संबंधित गैर-प्रकटीकरण।	
23.	नबसमृद्धि फाइनेंस लिमिटेड	जीसीओसी	• कंपनी के पास (i) पास-थ्रू सर्टिफिकेट में किए गए निवेश, (ii) पूर्व भुगतान प्रभारों के माध्यम से मान्यता प्राप्त आय और (iii) गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की वसूली के विनियोग आदेश के संबंध में कोई विशिष्ट लेखांकन नीति नहीं थी। • कंपनी ने प्रतिभूतिकरण में निवेश का मूल्यांकन प्राप्त नहीं किया - पास-थ्रू प्रमाणपत्र, जिसका उचित मूल्य नहीं किया गया था, जो कंपनी की लेखांकन नीति और एस - 13 के प्रावधानों का उल्लंघन है।	• निवेशों पर विशिष्ट लेखांकन नीतियों, पूर्वभुगतान प्रभारों के माध्यम से मान्यता प्राप्त आय और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की वसूली के विनियोग के आदेश का खुलासा नोट 1 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अंतर्गत किया गया। • वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय विवरण तैयार करते समय पास-थ्रू सर्टिफिकेट में निवेश के प्रकटीकरण में सुधार किया गया।
24.	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक	जीसी	एलडी से संबंधित जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न करना।	प्रावधानों का अनुपालन किया गया।

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी) / सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	प्रबंधन पत्र में उजागर की गई खामियां	सुधार किया गया
25.	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	जीसी	पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि का आयु-वार विश्लेषण आईआरडीआई द्वारा दिए गए प्रारूप के अनुरूप नहीं था।	कंपनी ने आईआरडीआई की आवश्यकताओं के अनुसार 2021-22 के दौरान अपने प्रारूप में परिवर्तन किया।
26.	राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम	जीसी	अमूर्त परिसंपत्तियों से संबंधित लेखांकन नीति की समीक्षा और अद्यतनीकरण की आवश्यकता है।	कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों से संबंधित लेखांकन नीति की समीक्षा की और उसे अद्यतन किया।
27.	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम	जीसी	लेखा-नोट में सीएसआर निधि की अप्रयुक्त राशि का खुलासा नहीं किया गया।	वर्ष 2021-22 के वित्तीय विवरणों में इसका अनुपालन किया गया।
28.	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम	जीसी	- फलेक्सी जमा राशि की कुल राशि को बैंक शेष में नकदी और नकदी समतुल्य के रूप में माना गया, जो कि इंड एस 7 में दिए गए नकदी और नकदी समतुल्य के स्पष्टीकरण के विपरीत है। - कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-III के अनुसार आकस्मिक देयताओं और पूंजी प्रतिबद्धताओं का खुलासा नहीं किया गया।	- वर्ष 2021-22 के वित्तीय विवरण में फ्लेक्सी जमा को सामान्य एफडीआर के बराबर माना जाएगा। - वर्ष 2021-22 के वित्तीय विवरण में प्रत्येक शीर्षक के अंतर्गत विवरण का खुलासा किया गया है।

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी) / सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	प्रबंधन पत्र में उजागर की गई खामियां	सुधार किया गया
29.	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	जीसी	कंपनी के पट्टों पर लेखा नीति संख्या 1.10 में कहा गया है कि पट्टा समझौते में जहां कंपनी पट्टादाता है और कंपनी किसी परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित नहीं करती है, उसे परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तदनुसार, कुछ स्थानों पर रियल एस्टेट परियोजनाओं को परिचालन पट्टों के तहत पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए और पूंजीकृत किया जाना चाहिए।	इंड एस 116 के पैरा 88 के अनुसार लेखांकन नीति में संशोधन किया गया है, 'ऐसे पट्टे जिनमें कंपनी किसी परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित नहीं करती है, उन्हें परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टे के तहत पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों को अंतर्निहित परिसंपत्ति की प्रकृति के अनुसार पहचाना और प्रस्तुत किया जाता है।'
30.	एनएचडीसी लिमिटेड	जीसी	धारा 135(5) के प्रावधान के अनुपालन में सीएसआर व्यय के लेखांकन और प्रकटीकरण की समीक्षा की जानी चाहिए और उचित रूप से सुधार किया जाना चाहिए।	कंपनी ने लेखापरीक्षा सुझाव का अनुपालन किया।
31.	एनएमडीसी लिमिटेड	जीसी	कंपनी के पास पूंजीगत स्पेयर पार्ट्स, स्टैंडबाय उपकरण और सेवा उपकरणों के लिए कोई विशिष्ट लेखांकन नीति नहीं थी, जो वर्ष के दौरान पूंजीकृत पीपीई की परिभाषा को पूरा करती हो।	कंपनी ने पीपीई के अंतर्गत निम्नलिखित लेखांकन नीति को शामिल किया है "पीपीई की परिभाषा को पूरा करने वाले और प्रत्येक मामले में 20 लाख रुपये से अधिक मूल्य वाले स्पेयर

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी) / सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	प्रबंधन पत्र में उजागर की गई खामियां	सुधार किया गया
				पार्ट्स, स्टैंडबाय उपकरण और सेवा उपकरण को उपयोग के लिए उपलब्ध होने पर पूंजीकृत किया जाता है।"
32.	नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	जीसीओसी	प्रति शेयर आय को इंड एस 33 की अपेक्षाओं के अनुरूप मान्यता प्रदान करने और मापने की आवश्यकता है।	प्रति शेयर आय को इंड एस 33 की आवश्यकताओं के अनुपालन में मान्यता दी गई है और मापा गया है
33.	ऑयल इंडिया लिमिटेड	जीसी	कंपनी के पास परित्यक्त कुओं के उद्धार के लेखांकन के लिए कोई परिभाषित नीति नहीं थी।	कंपनी ने परित्यक्त कुओं के उद्धार के लेखांकन के लिए अपनी नीति में परिवर्तन किया तथा लेखांकन नीति में यह जोड़ा कि "उत्पादन कुओं और उत्पादन सुविधाओं की लागत, उद्धार मूल्य के बाद, सिद्ध विकसित भंडारों पर समाप्त हो जाती है"।

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी) / सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	प्रबंधन पत्र में उजागर की गई खामियां	सुधार किया गया
34.	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	जीसी	- नकदी प्रवाह विवरण में नकदी के अंतर्वाह और बहिर्वाह के संबंध में सही जानकारी इंड एस-7 के अनुरूप सुनिश्चित की जानी चाहिए। - नोट 61 के अंतर्गत दर्शाए गए मुद्रा जोखिम को संदर्भ तिथि पर संदर्भ विनिमय दर के अनुसार भारतीय रुपये में विदेशी मुद्रा का मूल्य अपनाकर सही ढंग से प्रकट किया जाना आवश्यक है। - इंड एस -8 के अनुरूप पूर्व अवधि की मदों के लिए पर्याप्त प्रकटीकरण सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।	- लेखापरीक्षा की टिप्पणियों पर विचार करने के बाद नकदी प्रवाह का विवरण तैयार किया गया। - वित्तीय विवरण लेखापरीक्षा की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। - वित्तीय विवरण लेखापरीक्षा की टिप्पणियों पर विचार करते हुए तैयार किया गया है।
35.	पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जीसी	इंड एस 12 के अनुसार एकचुरियल लाभ पर कर प्रभाव के लेखांकन में उचित सावधानी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।	वर्ष 2021-22 के वित्तीय विवरणों में भारतीय लेखा मानक 12 के अनुसार बीमांकिक लाभ पर कर प्रभाव का लेखा-जोखा किया गया है।

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी) / सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	प्रबंधन पत्र में उजागर की गई खामियां	सुधार किया गया
36.	आरईसी लिमिटेड	जीसी	• कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) नियम, 2014 की आवश्यकताओं के अनुपालन में कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व व्यय का सही ढंग से खुलासा करना आवश्यक था। • भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की कॉर्पोरेट प्रशासन आवश्यकताओं के संबंध में पर्याप्त प्रकटीकरण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।	• कंपनी ने वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स में आवश्यक परिवर्तन किए। • कंपनी ने आवश्यक खुलासा किया।
37.	राइट्स लिमिटेड	जीसी	इन्वेंटरी से संबंधित लेखांकन नीति में कच्चे माल, भंडार और पुर्जों तथा प्रगतिरत कार्यों के मूल्यांकन को शामिल नहीं किया गया।	इन्वेंटरी से संबंधित लेखांकन नीति को उचित रूप से संशोधित/पुनर्शब्दांकित किया गया है तथा आवश्यक प्रकटीकरण को भी संशोधित/पुनर्शब्दांकित किया गया है।
38.	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड	जीसीओसी	कंपनी ने इंड एस - अमूर्त आस्तियों के पैरा 118 के अंतर्गत निर्धारित आवश्यकताओं का खुलासा नहीं किया।	कंपनी ने वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोटों में इंड एस 38 के पैरा 118 की प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन किया।

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी) / सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	प्रबंधन पत्र में उजागर की गई खामियां	सुधार किया गया
39.	भारतीय प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड	जीसी	आकस्मिक देयताओं से संबंधित इंड एस 37 के प्रावधानों का अनुपालन न करना।	आवश्यक सुधार किये गये।
40.	सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	जीसी	- यह सुनिश्चित करना कि पवन ऊर्जा परियोजना के लिए बीजी नकदीकरण हेतु अलग लेखांकन नीति तैयार की जाए। - यह सुनिश्चित करना कि मार्च माह के लिए बिना बिल वाली बिक्री/खरीद से संबंधित मामले की समीक्षा की जा सके तथा संबंधित लेखांकन नीति को तदनुसार संशोधित किया जा सके। - यह सुनिश्चित करना कि मार्च माह के लिए बिल न किए गए ट्रांसमिशन प्रभारों से संबंधित मामले की समीक्षा की जा सके तथा संबंधित लेखा नीति को तदनुसार संशोधित किया जा सके।	कंपनी ने उठाए गए मुद्दों के लिए अलग लेखांकन नीतियां बनाईं और उनका खुलासा किया।

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी) / सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	प्रबंधन पत्र में उजागर की गई खामियां	सुधार किया गया
41.	स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	जीसी	- इंड एस 1 के पैरा संख्या 66(सी) का अनुपालन न करते हुए, सावधि जमा में निवेश को चालू परिसंपत्तियों के बजाय गैर-चालू परिसंपत्तियों के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया। - कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति में कहा गया है कि अतिरिक्त के मामले में अधिग्रहण के महीने से आनुपातिक आधार पर मूल्यहास लगाया जाता है, हालांकि, इसमें यह उल्लेख नहीं किया गया है कि यह स्थापना की तारीख है या चालान की तारीख है।	- उन जमाराशियों का वर्गीकरण जो निःशुल्क हैं तथा रिपोर्टिंग तिथि के अंत से 12 महीनों के भीतर परिपक्व होती हैं, उन्हें गैर-चालू परिसंपत्तियों के स्थान पर चालू परिसंपत्तियों में शामिल किया गया है। - इसे महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में शामिल किया गया है।

अनुलग्नक-XVIII (पैरा संख्या 2.7 देखें)

उन सीपीएसई का विवरण जहां सीएजी द्वारा प्रबंधन पत्र जारी किए गए

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1	आवंतिका गैस लिमिटेड
2	एक्यूआईटीई रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड
3	कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड
4	आंध्र प्रदेश सौर ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड
5	एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
6	एसआरआईसी (इंडिया) लिमिटेड
7	बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
8	बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड
9	बैंक ऑफ इंडिया ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड
10	बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड
11	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड
12	भाग्यनगर गैस लिमिटेड
13	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
14	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
15	भारत गैस रिसोर्सज लिमिटेड
16	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
17	भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड
18	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
19	भारत पेट्रोरिसोर्सज लिमिटेड
20	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड
21	भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड
22	बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड
23	बिहार इंफ्रा पावर लिमिटेड
24	जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद
25	बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड
26	बीओबी कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड
27	बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड
28	बीओआई मर्चेन्ट बैंकर्स लिमिटेड
29	बीओआई शेयरहोल्डिंग लिमिटेड

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
30	बोकारो पावर सप्लाई कंपनी (प्रा.) लिमिटेड
31	ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड
32	केनरा बैंक सिक्योरिटीज लिमिटेड
33	केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
34	कैनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड
35	कैनबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
36	सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड
37	सेंटबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
38	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
39	भारत के प्रतिभूतिकरण, आस्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित की केंद्रीय रजिस्ट्री
40	चेन्नई एन्नोर रोड कंपनी लिमिटेड
41	चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड
42	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
43	चेय्युर इन्फ्रा लिमिटेड
44	कोल इंडिया लिमिटेड
45	कॉनकॉर एयर लिमिटेड
46	क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
47	दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
48	डीएनएच पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
49	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
50	ईसीजीसी लिमिटेड
51	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
52	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड
53	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
54	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
55	ईएसजी जोखिम मूल्यांकन और अंतर्दृष्टि लिमिटेड
56	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड
57	फ्रेश एंड हेल्दी एंटरप्राइजेज लिमिटेड
58	गेल (इंडिया) लिमिटेड
59	गेल गैस लिमिटेड
60	जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
61	सरकारी ई-बाज़ार

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
62	हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड (वित्त वर्ष 2020-21)
63	हार्डिकॉन लिमिटेड
64	हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड
65	हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
66	हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड
67	उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी
68	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
69	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
70	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड
71	हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड
72	हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड
73	एचएमटी इंटरनेशनल लिमिटेड
74	एचएमटी लिमिटेड
75	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड
76	एचपी एलएनजी लिमिटेड
77	एचपी ऑयल गैस प्राइवेट लिमिटेड
78	एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड
79	एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड
80	आईडीबीआई एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड
81	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड
82	आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड
83	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड
84	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड
85	आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड
86	आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड
87	आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड
88	आईएफसीआई लिमिटेड
89	आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड
90	आईएफआईएन क्रेडिट लिमिटेड
91	आईएफआईएन सिक्योरिटीज फाइनेंस लिमिटेड
92	आईएचबी लिमिटेड
93	आईआईडीएल रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड
94	इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
95	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
96	इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
97	भारत पर्यटन विकास निगम
98	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
99	भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड
100	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड
101	भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड
102	इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड
103	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी
104	भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड
105	इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड
106	इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड
107	जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड
108	जल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
109	कर्नाटक सौर ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड
110	कर्नाटक विजयनगर स्टील लिमिटेड
111	केआईओसीएल लिमिटेड
112	कॉकण एलएनजी लिमिटेड
113	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड
114	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
115	महाराष्ट्र एक्जीक्यूटिव एंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
116	महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
117	महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड
118	मैंगलोर रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
119	मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड
120	माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनमेंस एजेंसी लिमिटेड
121	मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
122	एमएमटीसी लिमिटेड
123	मोइल लिमिटेड
124	एमपीकॉन लिमिटेड
125	मुंबई एविएशन फ्यूल फार्म फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड
126	मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
127	एनएबीसंरक्षण

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
128	नबवेंचर्स लिमिटेड.
129	नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
130	नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड
131	नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड
132	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
133	नेशनल फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड
134	नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
135	राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड
136	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
137	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
138	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम
139	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
140	एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड
141	नेपा लिमिटेड
142	एनईएसएल एसेट डेटा लिमिटेड
143	एनईएसएल ई-इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
144	न्यू मैंगलोर पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड
145	न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड
146	नेयवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड
147	एनएचडीसी लिमिटेड
148	एनएचपीसी लिमिटेड
149	निकॉन लिमिटेड
150	निकॉन सोशल फाउंडेशन
151	एनएलसी इंडिया लिमिटेड
152	एनएमडीसी लिमिटेड
153	नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
154	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
155	एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड
156	एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड
157	एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड
158	एनटीपीसी इलेक्ट्रिक सप्लाय कंपनी लिमिटेड
159	एनटीपीसी लिमिटेड
160	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
161	एनटीपीएल तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड
162	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
163	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड
164	ऑयल इंडिया लिमिटेड
165	ओएनजीसी पेट्रो एडिंशंस लिमिटेड
166	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड
167	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
168	पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
169	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड
170	पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड
171	पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड
172	पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड
173	पांडिचेरी अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
174	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
175	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
176	पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
177	पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड
178	पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड
179	पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड
180	पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड
181	पावरग्रिड साउदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड
182	पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड
183	रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
184	रेल विकास निगम लिमिटेड
185	रेलटेल एंटरप्राइजेज लिमिटेड
186	रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड
187	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
188	रैटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
189	रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड
190	आरईसी लिमिटेड
191	रिन्यूएबल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड
192	रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड
193	रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
194	राइट्स लिमिटेड
195	सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्रीज लिमिटेड
196	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड
197	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड
198	एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड
199	एसबीआई फाउंडेशन
200	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट इंडिया लिमिटेड
201	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
202	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड
203	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
204	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
205	एसबीआई पेमेंट्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
206	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
207	एसबीआईकैप सिक्योरिटीज लिमिटेड
208	एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड
209	एसबीआईकैप वेंचर्स लिमिटेड
210	एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्योरिटीज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
211	सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
212	एसएचसीआईएल सर्विसेज लिमिटेड
213	सिडबी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड
214	सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड
215	एसजेवीएन लिमिटेड
216	एसएमईआरए रेटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
217	सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
218	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
219	स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
220	एसटीसीआई फाइनेंस लिमिटेड
221	एसटीसीआई प्राइमरी डीलर लिमिटेड
222	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
223	स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
224	स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड
225	स्टॉकहोल्डिंग सिक्योरिटीज आईएफएससी लिमिटेड
226	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
227	भारतीय कपास निगम लिमिटेड
228	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
229	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
230	भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड
231	टुस्को लिमिटेड
232	तूतीकोरिन पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड
233	यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
234	यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
235	यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड
236	यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
237	यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड
238	वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड
239	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
240	जेनिथ सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड

अनुलग्नक-XIX (पैरा संख्या 3.1.2 देखें)

71 सीपीएसई की सूची जिनके शेयर/बांड स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थे और ऑडिट में शामिल हैं

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1	भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2	कोल इंडिया लिमिटेड
3	ऑयल इंडिया लिमिटेड
4	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
5	आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड
6	हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड
7	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
8	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
9	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड
10	न्यू इंडिया एश्योरेंस लिमिटेड
11	जनरल इश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
12	एसबीआई लाइफ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
13	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
14	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
15	आईटीआई लिमिटेड
16	तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड
17	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड
18	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
19	बीईएमएल लिमिटेड
20	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड
21	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
22	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड
23	मिश्र धातु निगम लिमिटेड
24	एनएलसी इंडिया लिमिटेड
25	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
26	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
27	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
28	इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड
29	इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
30	एचएमटी लिमिटेड
31	ट्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
32	केआईओसीएल लिमिटेड
33	एनएमडीसी लिमिटेड
34	द फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड
35	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
36	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
37	राष्ट्रीय केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
38	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
39	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
40	गेल (इंडिया) लिमिटेड
41	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
42	एनएचपीसी लिमिटेड
43	सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड
44	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
45	एनटीपीसी लिमिटेड
46	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
47	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड
48	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
49	मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड
50	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड
51	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
52	एमएमटीसी लिमिटेड
53	भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड
54	पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड
55	आईएफसीआई लिमिटेड
56	रेल विकास निगम लिमिटेड
57	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
58	राइट्स लिमिटेड
59	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड
60	भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड
61	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
62	इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
63	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
64	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
65	बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड
66	मेटल स्क्रेप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएसटीसी)
67	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड
68	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
69	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड
70	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड
71	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड

अनुलग्नक-XX (पैरा संख्या 3.1.2 देखें)

35 सीपीएसई/सांविधिक निगमों की सूची जिनके बांड/डिबेंचर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थे

क्रम सं.	सीपीएसई/सांविधिक निगम का नाम
1	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड
2	भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (सांविधिक निगम)
3	आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड
4	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड
5	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सांविधिक निगम)
6	डीएमई डेवलपमेंट लिमिटेड
7	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
8	एनटीपीसी- सेल (संयुक्त उद्यम)
9	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड
10	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
11	भारत संचार निगम लिमिटेड
12	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड
13	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
14	एनटीपीसी लिमिटेड
15	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
16	इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
17	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
18	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड
19	सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड
20	एनएचपीसी लिमिटेड
21	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड
22	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
23	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
24	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
25	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
26	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
27	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड
28	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड
29	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

क्रम सं.	सीपीएसई/सांविधिक निगम का नाम
30	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
31	भारतीय खाद्य निगम (सांविधिक निगम)
32	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड
33	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
34	भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड
35	ओएनजीसी पेट्रो एडिशन लिमिटेड

अनुलग्नक- XXI (पैरा संख्या 3.1.2 देखें)

उन 18 सीपीएसई की सूची जिनके शेयर और बांड दोनों स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थे

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड
2	आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड
3	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
4	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड
5	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
6	एनटीपीसी लिमिटेड
7	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
8	इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
9	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
10	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड
11	सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड
12	एनएचपीसी लिमिटेड
13	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
14	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड
15	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड
16	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड
17	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड
18	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

अनुलग्नक- XXII (पैरा संख्या 4.10 देखें)

रणनीतिक विनिवेश की स्थिति

रणनीतिक विनिवेश की स्थिति	सीपीएसई का नाम
दीपम द्वारा संसाधित किए जा रहे चालू लेनदेन जिनमें ईओआई जारी किया गया है	1. बीईएमएल लिमिटेड
	2. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
	3. एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड
	4. प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड
	5. फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एमएसटीसी लिमिटेड की सहायक कंपनी)
	6. इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
	7. एनएमडीसी स्टील लिमिटेड
	8. आईडीबीआई बैंक
ऐसे लेनदेन जिनमें ईओआई जारी नहीं किया गया है या ऐसे लेनदेन ईओआई/आरएफपी जारी होने के बाद रद्द कर दिए गए	1. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को छोड़कर)
	2. पवन हंस लिमिटेड
	3. सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
	4. मिश्र धातु इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर; सलेम इस्पात संयंत्र; भद्रावती इस्पात संयंत्र - स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की इकाइयां
	5. कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
	6. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा लेनदेन की प्रक्रिया की जा रही है	1. हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड
	2. बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
	3. भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की विभिन्न इकाइयाँ
मुकदमेबाजी के कारण लेन-देन रुका	1. हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कंपनी)
	2. कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

सीपीएसई द्वारा बंद करने की सिफारिश/अनुमोदन के कारण या किसी अन्य कारण से लेन-देन रोक दिया गया	1. हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स केमिकल्स लिमिटेड)*(हिंदुस्तान केमिकल ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की सहायक कंपनी)
	2. स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड*
	3. भारत पम्प्स एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड*
	4. हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड (सीपीएसई बंद होने की स्थिति में है)
	5. सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नयागांव इकाई) की इकाइयां (लेनदेन व्यवहार्य नहीं है और इकाइयां राज्य सरकारों को वापस की जा रही हैं)।
लेन-देन संभव नहीं	1. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड
	2. ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
लेन-देन पूर्ण हो गया	1. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
	2. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड
	3. एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड
	4. नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
	5. ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
	6. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
	7. नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
	8. कामराजर पोर्ट लिमिटेड
	9. एयर इंडिया लिमिटेड, एआईएक्सएल और एआईएसएटीएस में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी^
	10. नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड

* इसके बाद सरकार ने इन सीपीएसई को बंद करने की मंजूरी दे दी।

^ जो सहायक कंपनियाँ अभी एआईएचएल के पास हैं, उनका विनिवेश होना अभी बाकी है

अनुलग्नक- XXIII (पैरा संख्या 5.3 देखें)
लेखापरीक्षा के लिए चयनित सीपीएसई की सूची

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	लाभ (₹ लाख में)	समीक्षा के लिए चुना गया है या नहीं
₹500 करोड़ से अधिक			
1	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	21,83,604	हाँ
2	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	19,04,167	हाँ
3	एनटीपीसी लिमिटेड	13,76,952	हाँ
4	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	11,93,578	हाँ
5	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	11,24,644	हाँ
6	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	10,66,388	हाँ
7	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8,44,401	हाँ
8	आरईसी लिमिटेड	8,36,178	हाँ
9	कोल इंडिया लिमिटेड	7,64,010	हाँ
10	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	6,87,235	हाँ
11	एनएमडीसी लिमिटेड	6,25,305	हाँ
12	गेल (इंडिया) लिमिटेड	4,89,019	हाँ
13	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन	4,41,613	हाँ
14	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	4,39,839	हाँ
15	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	4,37,067	हाँ
16	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	3,85,002	हाँ
17	एनएचपीसी लिमिटेड	3,23,337	हाँ
18	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	3,23,296	हाँ
19	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	303610	हाँ
20	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	2,06,542	हाँ
21	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	1,88,588	हाँ
22	ऑयल इंडिया लिमिटेड	1,74,159	हाँ

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	लाभ (₹ लाख में)	समीक्षा के लिए चुना गया है या नहीं
23	एसजेवीएन लिमिटेड	1,63,304	हाँ
24	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,57,858	हाँ
25	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	1,43,995	हाँ
26	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	1,29,953	हाँ
27	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	1,22,128	हाँ
28	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	1,09,241	हाँ
29	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	1,04,179	हाँ
30	रेल विकास निगम लिमिटेड	94,055	हाँ
31	ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलीमर लिमिटेड	73,990	हाँ
32	एनएचडीसी लिमिटेड	66,463	हाँ
33	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	61,810	हाँ
34	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	61,010	हाँ
35	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	50,333	हाँ
₹100 करोड़ से अधिक - ₹500 करोड़			
36	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	47,958	हाँ
37	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	47,074	नहीं
38	ईसीजीसी लिमिटेड	46,030	नहीं
39	केंद्रीय भंडारण निगम	43,817	नहीं
40	राइट्स लिमिटेड	42,435	हाँ
41	भारतीय प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड	42,381	हाँ
42	इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	40,456	नहीं
43	राष्ट्रीय केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	37,311	नहीं

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	लाभ (₹ लाख में)	समीक्षा के लिए चुना गया है या नहीं
44	एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड	36,300	हाँ
45	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल ट्रावनकोर लिमिटेड	35,198	हाँ
46	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड	34,641	हाँ
47	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड	31,696	नहीं
48	आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड	31,569	नहीं
49	केआईओसीएल लिमिटेड	30,117	हाँ
50	इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	28,527	हाँ
51	भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड	28,248	नहीं
52	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	25,950	नहीं
53	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	25,777	हाँ
54	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	24,963	हाँ
55	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	23,756	नहीं
56	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	23,429	नहीं
57	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	20,174	हाँ
58	भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड	18,990	नहीं
59	नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड	18,257	हाँ
60	सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	17,771	हाँ
61	मोइल लिमिटेड	17,663	नहीं
62	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	16,629	नहीं
63	गेल गैस लिमिटेड	15,770	हाँ
64	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	15,347	हाँ

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	लाभ (₹ लाख में)	समीक्षा के लिए चुना गया है या नहीं
65	मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	14,979	नहीं
66	रेलटेल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड	14,041	नहीं
67	पावर ग्रिड वारोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	14,028	नहीं
68	पावर ग्रिड परली ट्रांसमिशन लिमिटेड	13,653	नहीं
69	कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड	13,453	नहीं
70	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	12,791	हाँ
71	न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड	12,184	नहीं
72	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	11,645	हाँ
73	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	11,245	हाँ
74	एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड	11,233	हाँ
75	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	10,998	हाँ
76	पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड	10,920	नहीं
77	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	10,915	नहीं
78	पावर ग्रिड साउदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	10,868	हाँ
79	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	10,159	हाँ
80	एमएसटीसी लिमिटेड	10,107	हाँ
81	एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड	10,010	नहीं
₹50 करोड़ से अधिक - ₹100 करोड़			
82	नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकॉर्पोरेटेड	9,823	हाँ
83	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड	9,202	नहीं

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	लाभ (₹ लाख में)	समीक्षा के लिए चुना गया है या नहीं
84	पावर ग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	8,970	नहीं
85	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	8,462	नहीं
86	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	8,435	नहीं
87	बीईएमएल लिमिटेड	7,480	नहीं
88	एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड	7,226	नहीं
89	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम	6,547	नहीं
90	एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5,571	हाँ
91	दूरसंचार कंसल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड	5,277	नहीं
92	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम	5,226	हाँ
93	भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड	5,105	नहीं
₹10 करोड़ - ₹50 करोड़			
94	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4,790	नहीं
95	नेशनल शेड्यूलड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	4,782	नहीं
96	भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री	4,462	नहीं
97	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	4,369	नहीं
98	वाप्कोस लिमिटेड	4,053	नहीं
99	ईडीसीआईएल(इंडिया) लिमिटेड	3,689	नहीं
100	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	3,424	नहीं
101	पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	3,000	नहीं

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	लाभ (₹ लाख में)	समीक्षा के लिए चुना गया है या नहीं
102	हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	2,948	नहीं
103	रिचर्डसन एंड क्रुडास (1972) लिमिटेड	2,947	नहीं
104	पावरग्रिड काला अंब ट्रांसमिशन लिमिटेड	2,947	नहीं
105	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	2,856	नहीं
106	एचएमटी लिमिटेड	2,749	नहीं
107	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	2,634	नहीं
108	भारतीय कपास निगम लिमिटेड	2,612	नहीं
109	आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड	2,561	नहीं
110	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	2,472	नहीं
111	नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2,451	नहीं
112	रेलवे ऊर्जा प्रबंधन कंपनी लिमिटेड	2,413	नहीं
113	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम	2,359	नहीं
114	सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	2,326	नहीं
115	मुंबई रेलवे विकास निगम लिमिटेड	2,325	नहीं
116	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	2,318	नहीं
117	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड	2,275	नहीं
118	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	2,120	नहीं
119	पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2,050	नहीं
120	सेंट्रल रेलसाइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड	1,936	नहीं
121	पावर ग्रिड मेदिनीपुर जीरात ट्रांसमिशन लिमिटेड	1,915	नहीं

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	लाभ (₹ लाख में)	समीक्षा के लिए चुना गया है या नहीं
122	प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड	1,907	नहीं
123	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	1,547	नहीं
124	चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड	1,476	हाँ
125	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	1,384	नहीं
126	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स (इंडिया) लिमिटेड	1,348	हाँ
127	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1,315	नहीं
128	भारतीय जूट निगम लिमिटेड	1,215	नहीं
129	सेल रिफ्रेक्टरी कंपनी लिमिटेड	1,188	हाँ
130	ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	1,168	नहीं
131	सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड	1,123	नहीं
132	आईटीआई लिमिटेड	1,120	हाँ
133	इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,105	नहीं
134	एचएलएल इंफ्रा टेक सर्विसेज लिमिटेड	1,086	नहीं
135	हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,043	नहीं
136	इंडिया यूनाइटेड टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड	1,028	नहीं
₹10 करोड़ से कम			
137	एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड	982	नहीं
138	एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड	955	नहीं
139	कुमारकृष्णा फ्रंटियर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड	923	नहीं

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	लाभ (₹ लाख में)	समीक्षा के लिए चुना गया है या नहीं
140	राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम	921	नहीं
141	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड	780	नहीं
142	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	776	नहीं
143	बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड	690	नहीं
144	जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद	672	नहीं
145	तमिलनाडु व्यापार संवर्धन संगठन	633	नहीं
146	मेकॉन लिमिटेड	624	नहीं
147	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	608	नहीं
148	हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड	580	नहीं
149	इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	575	नहीं
150	एनटीपीसी इलेक्ट्रिक सप्लाय कंपनी लिमिटेड	552	नहीं
151	सांभर साल्ट्स लिमिटेड	535	नहीं
152	पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	494	नहीं
153	बीईएल ऑप्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लिमिटेड	490	नहीं
154	प्राइज पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड	359	नहीं
155	बीईएल-थेल्स सिस्टम्स लिमिटेड	315	नहीं
156	कर्नाटक व्यापार संवर्धन संगठन	308	नहीं
157	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	287	नहीं
158	ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	255	नहीं
159	आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	246	नहीं
160	राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड	244	नहीं

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	लाभ (₹ लाख में)	समीक्षा के लिए चुना गया है या नहीं
161	रेलटेल एंटरप्राइजेज लिमिटेड	205	नहीं
162	जम्मू और कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड	202	नहीं
163	आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	146	नहीं
164	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड	145	नहीं
165	एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड	139	नहीं
166	टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड	139	नहीं
167	एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड	115	नहीं
168	पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	104	नहीं
169	एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड	97	नहीं
170	पावर ग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	95	नहीं
171	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	79	नहीं
172	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड	69	नहीं
173	इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	65	नहीं
174	दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	49	नहीं
175	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	28	नहीं
176	राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम	19	नहीं
177	मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड	14	नहीं

अनुलग्नक-XXIV (पैरा संख्या 5.5.1.1 देखें)

स्वतंत्र निदेशक वाले 38 सूचीबद्ध सीपीएसई की सूची

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1	भारत डायनेमिक लिमिटेड
2	भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड
3	बामर लॉरी कंपनी लिमिटेड
4	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
5	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
6	कोल इंडिया लिमिटेड
7	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
8	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल ट्रावनकोर लिमिटेड
9	गेल (इंडिया) लिमिटेड
10	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड
11	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
12	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड
13	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
14	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
15	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
16	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन
17	आईटीआई लिमिटेड
18	केआईओसीएल लिमिटेड
19	मज़गांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड
20	एमएसटीसी लिमिटेड
21	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
22	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
23	नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड
24	एनएचपीसी लिमिटेड
25	एनएलसी इंडिया लिमिटेड
26	एनएमडीसी लिमिटेड
27	एनटीपीसी लिमिटेड
28	ऑयल इंडिया लिमिटेड
29	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड
30	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
32	आरईसी लिमिटेड
33	राइट्स लिमिटेड
34	रेल विकास निगम लिमिटेड
35	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
36	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
37	एसजेवीएन लिमिटेड
38	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

स्रोत: सीपीएसई से प्राप्त और सीपीएसई की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़े।

अनुलग्नक-XXV (पैरा संख्या 5.5.2.1 और 5.7 देखें)

सीपीएसई वार कुल सीएसआर व्यय

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	2% व्यय किया जाना है (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	कंपनी के प्रकार	क्षेत्र	क्या कंपनी एक सूचीबद्ध कंपनी है	निदेशकों की कुल संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	व्यवस्थापक ओवरहेड (₹ लाख में)
1	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	16,673	13,778	महारत्न	पेट्रोलियम	हाँ	5	2	328
2	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	45,031.70	45,799.00	महारत्न	पेट्रोलियम	हाँ	5	3	2,180.90
3	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	16,186.00	12,606.00	महारत्न	पेट्रोलियम	हाँ	4	1	305
4	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	7,884.00	7,827.00	नवरत्न	रक्षा	हाँ	4	1	373
5	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	5,329.19	3,072.87	नवरत्न	रक्षा	हाँ	5	2	253.77
6	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	1,413.00	1,111.00	लघु रत्न	रक्षा	हाँ	5	3	52

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	2% व्यय किया जाना है (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	कंपनी के प्रकार	क्षेत्र	क्या कंपनी एक सूचीबद्ध कंपनी है	निदेशकों की कुल संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	व्यवस्थापक ओवरहेड (₹ लाख में)
7	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	1169.8	1812.61	लघु रत्न	रक्षा	हाँ	6	5	45.25
8	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	431.8	447.33	लघु रत्न	रक्षा	नहीं	5	2	20.40
9	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	405.5	410	लघु रत्न	रक्षा	हाँ	3	1	0
10	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	4,080.00	4,080.00	नवरत्न	शक्ति	हाँ	2	2	204
11	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	1,616.93	1,619.47	लघु रत्न	शिपिंग	हाँ	4	2	79.32
12	एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड	808.65	254.21	अन्य	शक्ति	नहीं	4	0	40.43
13	एनएमडीसी लिमिटेड	14,815.00	28,733.00	नवरत्न	खनन	हाँ	3	1	358
14	केआईओसीएल लिमिटेड	438.7	1,341.47	लघु रत्न	खनन	हाँ	5	3	0
15	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	5,905.00	7,415.00	लघु रत्न	पेट्रोलियम	नहीं	6	4	164

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	2% व्यय किया जाना है (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	कंपनी के प्रकार	क्षेत्र	क्या कंपनी एक सूचीबद्ध कंपनी है	निदेशकों की कुल संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	व्यवस्थापक ओवरहेड (₹ लाख में)
16	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	2,860.00	3,691.38	नवरत्न	खनन	हाँ	5	3	134.99
17	ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलीमर लिमिटेड	1,910.00	1,454.82	अन्य	पेट्रोलियम	नहीं	4	1	0
18	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	0	77.19	लघु रत्न	खनन	हाँ	4	3	0
19	एमएसटीसी लिमिटेड	0	17.83	लघु रत्न	अन्य	हाँ	4	2	0
20	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	441	1,048.16	लघु रत्न	पेट्रोलियम	हाँ	6	3	26
21	कोल इंडिया लिमिटेड	681	7,764.33	महारत्न	खनन	हाँ	4	3	0
22	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	18,162.22	25,175.81	लघु रत्न	खनन	नहीं	6	1	0
23	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	13,275.00	12,352.00	लघु रत्न	खनन	नहीं	6	3	587
24	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	6,758.00	6,933.69	लघु रत्न	खनन	नहीं	5	3	269.55
25	ऑयल इंडिया लिमिटेड	2,591.00	16,374.00	नवरत्न	पेट्रोलियम	हाँ	6	4	0

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	2% व्यय किया जाना है (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	कंपनी के प्रकार	क्षेत्र	क्या कंपनी एक सूचीबद्ध कंपनी है	निदेशकों की कुल संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	व्यवस्थापक ओवरहेड (₹ लाख में)
26	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	5,025.00	2,481.68	लघु रत्न	खनन	नहीं	6	2	80.84
27	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	7,006.00	4,501.79	लघु रत्न	रेलवे	हाँ	3	1	0
28	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2,571.00	1,517.16	नवरत्न	रेलवे	हाँ	5	3	0
29	रेल विकास निगम लिमिटेड	1,936.55	1,315.28	लघु रत्न	रेलवे	हाँ	4	1	0
30	राइट्स लिमिटेड	1,387.00	982.75	लघु रत्न	रेलवे	हाँ	3	1	66.18
31	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	0	85.75	अन्य	रेलवे	नहीं	3	2	0
32	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4,199.00	2,947.07	लघु रत्न	अन्य	हाँ	6	4	0
33	एनबीसीसी (भारत) लिमिटेड	580.17	255.53	नवरत्न	अन्य	हाँ	4	2	29

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	2% व्यय किया जाना है (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	कंपनी के प्रकार	क्षेत्र	क्या कंपनी एक सूचीबद्ध कंपनी है	निदेशकों की कुल संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	व्यवस्थापक ओवरहेड (₹ लाख में)
34	चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड	62.92	63.13	अन्य	विमानन	नहीं	3	0	0
35	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	32,314.00	29,829.00	महारत्न	पेट्रोलियम	हाँ	6	2	1420
36	एनटीपीसी लिमिटेड	28,180.00	35,672.00	महारत्न	शक्ति	हाँ	5	3	0
37	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	25,707.00	27,113.88	महारत्न	शक्ति	हाँ	5	3	1036
38	पावर फाइनैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	17,043.00	7,618.00	महारत्न	शक्ति	हाँ	4	2	441
39	गेल (इंडिया) लिमिटेड	13,646.00	20,497.00	महारत्न	पेट्रोलियम	हाँ	4	2	826
40	आरईसी लिमिटेड	17,067.00	16,762.00	महारत्न	शक्ति	हाँ	3	2	524
41	एनएचपीसी लिमिटेड	6,545.00	10,529.00	लघु रत्न	शक्ति	हाँ	6	4	385.71
42	एसजेवीएन लिमिटेड	3,944.00	5,167.00	लघु रत्न	शक्ति	हाँ	2	2	8.85
43	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	2,623.32	2,720.55	लघु रत्न	शक्ति	हाँ	3	1	73.95
44	एनएचडीसी लिमिटेड	1,855.00	1,991.00	अन्य	शक्ति	नहीं	4	0	94
45	गेल गैस लिमिटेड	362	146.84	अन्य	पेट्रोलियम	नहीं	3	0	0

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	2% व्यय किया जाना है (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	कंपनी के प्रकार	क्षेत्र	क्या कंपनी एक सूचीबद्ध कंपनी है	निदेशकों की कुल संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	व्यवस्थापक ओवरहेड (₹ लाख में)
46	पावर ग्रिड साउदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	103.15	103.15	अन्य	शक्ति	नहीं	3	0	0
47	नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड	345.21	216.44	लघु रत्न	उर्वरक	हाँ	5	4	0
48	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स (इंडिया) लिमिटेड	46.12	46.14	लघु रत्न	उर्वरक	नहीं	5	2	0
49	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल ट्रावनकोर लिमिटेड	56.07	106.28	अन्य	उर्वरक	हाँ	3	1	0
50	नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकॉर्पोरेटेड	112	0	अन्य	अन्य	नहीं	4	0	0
51	आईटीआई लिमिटेड	110.55	99.09	अन्य	अन्य	हाँ	4	1	0

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	2% व्यय किया जाना है (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	कंपनी के प्रकार	क्षेत्र	क्या कंपनी एक सूचीबद्ध कंपनी है	निदेशकों की कुल संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	व्यवस्थापक ओवरहेड (₹ लाख में)
52	भारतीय प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड	1,754.47	133.35	लघु रत्न	अन्य	नहीं	3	1	6
53	एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड	164.7	153.6	लघु रत्न	अन्य	नहीं	4	1	0
54	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम	142.05	113.21	लघु रत्न	अन्य	नहीं	4	2	0
55	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	10,190.00	10,196.00	अन्य	शक्ति	नहीं	5	2	0
56	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्थालिमिटेड	685.34	872.93	लघु रत्न	शक्ति	नहीं	3	1	1.23
57	सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	424.86	447.04	अन्य	शक्ति	नहीं	3	1	0
58	एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	549	574.86	लघु रत्न	अन्य	नहीं	2	1	0.04

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	2% व्यय किया जाना है (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	कंपनी के प्रकार	क्षेत्र	क्या कंपनी एक सूचीबद्ध कंपनी है	निदेशकों की कुल संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	व्यवस्थापक ओवरहेड (₹ लाख में)
59	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	285.78	15.93	अन्य	अन्य	नहीं	5	0	0.12
60	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	223.53	224.1	लघु रत्न	अन्य	नहीं	4	1	0
61	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	604.95	398.13	नवरत्न	शिपिंग	हाँ	5	3	0
62	सेल रिफ़ैक्टरी कंपनी लिमिटेड	45.2	13.25	अन्य	अन्य	नहीं	6	2	0
63	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	8,821	9,424.00	महारत्न	खनन	हाँ	4	3	31
	कुल	3,65,584.43	4,00,530.08						10,445.53

स्रोत: सीपीएसई से प्राप्त आंकड़े और सीपीएसई की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़े।

अनुलग्नक-XXVI (पैरा संख्या 5.5.2.2 और 5.5.2.3 देखें)

अधिनियम द्वारा सीपीएसई वार अनिवार्य सीएसआर व्यय बनाम वास्तविक आवंटन

(₹ लाख में)

क्रम संख्या (1)	सीपीएसई का नाम (2)	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार शुद्ध लाभ	2% व्यय किया जाना है (3)	2% से आवंटित (4)	वास्तविक व्यय (5)	वास्तविक व्यय 2%(+) से अधिक/2%(-) से कम (6)=(5)-(3) (अव्ययित राशि)	2% से अधिक और 2% से कम आवंटित
1	एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	27,463.88	549	574.86	574.86	25.86	25.86
2	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम	7,102.64	142.05	142.1	113.21	-28.84	0.05
3	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	22,049.96	441	डेटा उपलब्ध नहीं	1,048.16	607.16	डेटा उपलब्ध नहीं
4	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	58,489.99	1,169.80	डेटा उपलब्ध नहीं	1,812.61	642.81	डेटा उपलब्ध नहीं
5	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	2,66,459.69	5,329.19	5,329.20	3072.87	-2,256.32	0.01
6	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8,33,649	16,673.00	16,673.00	13778	-2895	0
7	ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलीमर लिमिटेड	95,473.00	1,910.00	1,910.00	1,454.82	-455.18	0
8	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	2,51,270	5,025.00	5,025.40	2,481.68	-2,543.32	0.40

क्रम संख्या (1)	सीपीएसई का नाम (2)	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार शुद्ध लाभ	2% व्यय किया जाना है (3)	2% से आवंटित (4)	वास्तविक व्यय (5)	वास्तविक व्यय 2%(+) से अधिक/2%(-) से कम (6)=(5)-(3) (अव्ययित राशि)	2% से अधिक और 2% से कम आवंटित
9	चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड	3,146.23	62.92	62.9	63.13	0.21	-0.02
10	कोल इंडिया लिमिटेड	34,042.00	681	10,531.00	7,764.33	7,083.33	9,850
11	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	80,846.25	1,616.93	1,616.90	1,619.47	2.54	-0.03
12	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1,28,564	2,571.00	2,571.00	1,517.16	-1,053.84	0
13	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	0	0	0	85.75	85.75	0
14	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स (इंडिया) लिमिटेड	2,305.78	46.12	46.10	46.14	0.02	-46.12
15	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल ट्रावनकोर लिमिटेड	2803	56.07	56.00	106.28	50.21	-0.07
16	गेल (इंडिया) लिमिटेड	6,82,302	13,646.00	20,496.90	20,497	6,851	6,850.90
17	गेल गैस लिमिटेड	18,095.00	362	320.4	146.84	-215.16	-41.60
18	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	20,275.00	405.5	410	410	4.50	4.50
19	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	21,590.33	431.8	431.8	447.33	15.53	0

क्रम संख्या (1)	सीपीएसई का नाम (2)	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार शुद्ध लाभ	2% व्यय किया जाना है (3)	2% से आवंटित (4)	वास्तविक व्यय (5)	वास्तविक व्यय 2%(+) से अधिक/2%(-) से कम (6)=(5)-(3) (अव्ययित राशि)	2% से अधिक और 2% से कम आवंटित
20	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	3,94,208	7,884.00	7,884	7,827	-57	0
21	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	0	0	0	77.19	77.19	0
22	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8,09,317	16,186.00	16,186	12,606	-3,580	0
23	एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड	8,234.89	164.70	164.70	153.6	-11.10	0
24	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2,09,957	4,199	2,500.00	2,947.07	-1,251.93	-1,699
25	आईटीआई लिमिटेड	5,527.26	110.55	110.5	99.09	-11.46	-0.05
26	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	14,288.99	285.78	285.8	15.93	-269.85	0.02
27	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	16,15,705	32,314.00	32,314.00	29,829	-2,485	0
28	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन	3,50,282	7,006.00	7,006.00	4,501.79	-2,504.21	0
29	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्थालिमिटेड	34,267.13	685.34	685.3	872.93	187.59	-0.04
30	केआईओसीएल लिमिटेड	21,934.41	438.7	1,438.7	1,341.47	902.77	1,000
31	एमएसटीसी लिमिटेड	0	0	0	17.83	17.83	0

क्रम संख्या (1)	सीपीएसई का नाम (2)	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार शुद्ध लाभ	2% व्यय किया जाना है (3)	2% से आवंटित (4)	वास्तविक व्यय (5)	वास्तविक व्यय 2%(+) से अधिक/2%(-) से कम (6)=(5)-(3) (अव्ययित राशि)	2% से अधिक और 2% से कम आवंटित
32	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	9,08,111	18,162.22	18,162.20	25,175.81	7,013.59	-0.02
33	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	70,629.00	1,413.00	1,413.00	1,111	-302	0
34	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	1,42,987	2,860.00	4,672.60	3,691.38	831.38	1,812.6
35	नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड	17,260.54	345.21	345.21	216.44	-128.77	0
36	नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकॉर्पोरेटेड	5,556.00	112	112	0	-112	0
37	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	11,176.72	223.53	223.5	224.1	0.57	-0.03
38	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	29,008.65	580.17	705.8	255.53	-324.64	125.63
39	एनएचडीसी लिमिटेड	92,735.00	1,855.00	1,991.60	1,991	136	136.6
40	एनएचपीसी लिमिटेड	3,27,230	6,545.00	6,544.60	10,529	3,984	-0.4
41	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	2,04,023	4,080.00	4,080.00	4,080	0	0
42	एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड	40,432.38	808.65	808.60	254.21	-554.44	-0.05
43	एनएमडीसी लिमिटेड	7,40,749	14,815.00	24,412.00	28,733	13,918	9,597

क्रम संख्या (1)	सीपीएसई का नाम (2)	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार शुद्ध लाभ	2% व्यय किया जाना है (3)	2% से आवंटित (4)	वास्तविक व्यय (5)	वास्तविक व्यय 2%(+) से अधिक/2%(-) से कम (6)=(5)-(3) (अव्ययित राशि)	2% से अधिक और 2% से कम आवंटित
44	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	6,63,746	13,275.00	13,275.00	12,352	-923	0
45	एनटीपीसी लिमिटेड	14,08,980	28,180.00	28,180.00	35,672	7,492	0
46	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	5,09,487	10,190.00	10,057.00	10,196	6	-133
47	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	2,95,264	5,905.00	5,905.30	7,415	1,510	0.3
48	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	22,51,583	45,031.70	45,032	45,799	767.3	0.3
49	ऑयल इंडिया लिमिटेड	1,29,556	2,591.00	16,374.00	16,374	13,783	13,783
50	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8,52,150	17,043.00	17,044.00	7,618	-9425	1
51	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	12,85,350	25,707.00	25,706.40	27,113.88	1,406.88	-0.6
52	पावर ग्रिड साउदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	5,157.43	103.15	103.2	103.15	0	0.05
53	रेल विकास निगम लिमिटेड	96,827.58	1,936.55	1,958.70	1,315.28	-621.27	22.15
54	आरईसी लिमिटेड	8,53,362	17,067.00	17,067.00	16,762	-305	0
55	राइट्स लिमिटेड	69,340.00	1,387.00	1,387.00	982.75	-404.25	0

क्रम संख्या (1)	सीपीएसई का नाम (2)	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के अनुसार शुद्ध लाभ	2% व्यय किया जाना है (3)	2% से आवंटित (4)	वास्तविक व्यय (5)	वास्तविक व्यय 2%(+) से अधिक/2%(-) से कम (6)=(5)-(3) (अव्ययित राशि)	2% से अधिक और 2% से कम आवंटित
56	सेल रिफ्रेक्टरी कंपनी लिमिटेड	2,261.00	45.2	47.4	13.25	-31.95	2.2
57	भारतीय प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड	87,723.67	1,754.47	2,100.50	133.35	-1621.12	346.03
58	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	30,248.00	604.95	605	398.13	-206.82	0.05
59	एसजेवीएन लिमिटेड	1,97,222	3,944.00	3,944.40	5,167	1,223	0.4
60	सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड.	21,243.11	424.86	424.9	447.04	22.18	0.04
61	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	3,37,888	6,758.00	6,758.00	6,933.69	175.69	0
62	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	4,41,037	8,821.00	8,047.00	9,424	603	-774
63	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	1,31,166	2,623.32	2,720.60	2,720.55	97.23	97.28
	कुल	18,279,139.51	365,584.43	404,934.97	400,530.08		40,961.34
	निर्धारित व्यय से 2% अधिक वास्तविक व्यय (₹ 4,005.30 करोड़ - ₹ 3,655.84 करोड़)						₹ 349.46 करोड़

स्रोत: क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त आंकड़े तथा सीपीएसई की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़े।

अनुलग्नक- XXVII (पैरा संख्या 5.5.2.5 देखें)

अतिरिक्त सीएसआर व्यय को समायोजित करने का दावा करने वाले सीपीएसई की सूची

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	क्या सीएसआर पर खर्च की गई अतिरिक्त राशि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (5) की आवश्यकता के अनुसार है	क्या कंपनी के बोर्ड ने इस आशय का कोई प्रस्ताव पारित किया है
1	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	हाँ	हाँ
2	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ	हाँ
3	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	हाँ	हाँ
4	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	हाँ	हाँ
5	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ	हाँ
6	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ	हाँ
7	रेल विकास निगम लिमिटेड	हाँ	हाँ
8	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ	हाँ
9	गेल (इंडिया) लिमिटेड	हाँ	हाँ
10	आरईसी लिमिटेड	हाँ	हाँ
11	एनएचपीसी लिमिटेड	हाँ	हाँ
12	भारतीय प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड	हाँ	हाँ
13	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ	हाँ
14	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ	हाँ
15	एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ	नहीं
16	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ	नहीं
17	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	हाँ	उपलब्ध नहीं है
18	एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड	हाँ	उपलब्ध नहीं है
19	गेल गैस लिमिटेड	हाँ	नहीं

स्रोत: सीपीएसई से प्राप्त आंकड़े तथा सीपीएसई की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़े।

अनुलग्नक-XXVIII (पैरा संख्या 5.5.2.6 देखें)

सीपीएसईवार व्यय न की गई सीएसआर राशि

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय न की गई राशि (लाख रुपए में)	चालू परियोजना से संबंधित व्यय न की गई सीएसआर राशि 30 दिनों के भीतर अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित की जाएगी	क्या चालू परियोजना से संबंधित व्यय न की गई सीएसआर राशि 30 दिनों के भीतर अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित की गई है?
1	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम	28.84	28.84	हाँ
2	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	2,256.32	2,256.32	हाँ
3	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4,596	3,940	हाँ
4	ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलीमर लिमिटेड	455.18	455.18	हाँ
5	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	1,529.32	1,818.67	हाँ
6	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2,404.84	1,778.00	हाँ
7	गेल गैस लिमिटेड	216.36	173.58	हाँ
8	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	273.00	300.00	हाँ
9	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	-	18.07*	हाँ
10	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	942.00	951.00	हाँ
11	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	269.85	269.85	हाँ
12	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन	2,504.21	2,504.21	हाँ
13	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	456	456	हाँ
14	नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड	128.77	125.21	हाँ

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय न की गई राशि (लाख रुपए में)	चालू परियोजना से संबंधित व्यय न की गई सीएसआर राशि 30 दिनों के भीतर अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित की जाएगी	क्या चालू परियोजना से संबंधित व्यय न की गई सीएसआर राशि 30 दिनों के भीतर अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित की गई है?
15	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	324.64	443.52	हाँ
16	एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड	554.44	554.44	हाँ
17	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	-	1307.3*	हाँ
18	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5,487.00	5,487.00	हाँ
19	राइट्स लिमिटेड	404.25	427.40	हाँ
20	भारतीय प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड	1,523.46	1,967.11	हाँ
21	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	206.82	206.82	हाँ
22	सेल रिफ़ैक्टरी कंपनी लिमिटेड	31.95	34.19	हाँ
23	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,251.93	0	—
24	आईटीआई लिमिटेड	11.46	0.00	हाँ
25	नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकॉर्पोरेटड	112	0	हाँ
26	एमएसटीसी लिमिटेड	--	6.15*	हाँ
	कुल	25,968.64	25,523.93	

स्रोत: सीपीएसई से प्राप्त आंकड़े और सीपीएसई की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़े।

* राशि पिछले वित्तीय वर्ष से संबंधित है।

अनुलग्नक-XXIX (पैरा संख्या 5.6.2 देखें)

सामान्य विषय-वस्तु पर सीएसआर व्यय

सामान्य विषय-वस्तु पर सीएसआर व्यय 60% से अधिक (सीपीएसई द्वारा रिपोर्ट के अनुसार)		
क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	सामान्य विषय-वस्तु पर किया गया व्यय (%)
1	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	82.25
2	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	79.38
3	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	67.00
4	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	70.79
5	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	92.38
6	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	61.00
7	एनएमडीसी लिमिटेड	72.00
8	केआईओसीएल लिमिटेड	91.80
9	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	76.17
10	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	97.53
11	ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलीमर लिमिटेड	76.18
12	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	77.99
13	कोल इंडिया लिमिटेड	77.98
14	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	82.19
15	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	60.24
16	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	61.00
17	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन	85.97
18	राइट्स लिमिटेड	63.91
19	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	100.00
20	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	61.00
21	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	69.28
22	गेल (इंडिया) लिमिटेड	70.07
23	आरईसी लिमिटेड	62.00
24	एसजेवीएन लिमिटेड	60.03
25	एनएचडीसी लिमिटेड	76.67
26	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	74.31
27	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल ट्रावनकोर लिमिटेड	86.56
28	नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकॉर्पोरेटेड	100.00
29	आईटीआई लिमिटेड	69.65
30	एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड	81.00

सामान्य विषय-वस्तु पर सीएसआर व्यय 60% से अधिक (सीपीएसई द्वारा रिपोर्ट के अनुसार)		
क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	सामान्य विषय-वस्तु पर किया गया व्यय (%)
31	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम	73.92
32	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड	80.72
33	एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	73.13
34	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	75.00
35	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	63.27
36	एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड	83.97
37	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	93.00
38	ऑयल इंडिया लिमिटेड	75.00
39	पावर ग्रिड साउदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	100.00
सामान्य विषय पर सीएसआर व्यय 60% से कम (सीपीएसई द्वारा रिपोर्ट के अनुसार)		
क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	सामान्य विषय पर किया गया व्यय (%)
1	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	49.45
2	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	37.82
3	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	40.00
4	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	53.00
5	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	57.67
6	चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड	20.00
7	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	51.86
8	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	35.00
9	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	48.25
10	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	32.33
11	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	22.53
12	गेल गैस लिमिटेड	20.27
13	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स (इंडिया) लिमिटेड	52.84
14	सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	52.57
15	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	40.16
16	सेल रिफ़ैक्टरी कंपनी लिमिटेड	27.93
17	रेल विकास निगम लिमिटेड	24.63
18	एनएचपीसी लिमिटेड	56.00
19	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	50.00
20	भारतीय प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड	20.51
21	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	उपलब्ध नहीं है

स्रोत: सीपीएसई से प्राप्त आंकड़े और सीपीएसई की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़े।

अनुलग्नक-XXX (पैरा संख्या 5.7 देखें)

प्रभाव आकलन पर सीएसआर व्यय

(₹ लाख में)

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि
1	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	0.68
2	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	0.70
3	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	1.65
4	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2.78
5	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	4
6	कोल इंडिया लिमिटेड	4.59
7	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	6
8	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	6
9	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	12
10	एनएचडीसी लिमिटेड	12
11	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	14.26
12	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	17
13	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	17.91
14	आरईसी लिमिटेड	23
15	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	23
16	गेल (इंडिया) लिमिटेड	26
	कुल	171.57

स्रोत: सीपीएसई से प्राप्त आंकड़े तथा सीपीएसई की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़े।

अनुलग्नक- XXXI (पैरा संख्या 5.8.1 देखें)

आधारभूत/आवश्यकता मूल्यांकन सर्वेक्षण आयोजित करने की स्थिति

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	आधारभूत/आवश्यकता मूल्यांकन सर्वेक्षण आयोजित किया गया (2021-22)	क्रम सं.	सीपीएसई जहां आधारभूत/आवश्यकता मूल्यांकन सर्वेक्षण नहीं किया गया (2021-22)
1	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	76	1	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
2	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	564	2	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड
3	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	87	3	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
4	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	29	4	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड
5	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	2	5	एनएलसी इंडिया लिमिटेड
6	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	48	6	एनएमडीसी लिमिटेड
7	केआईओसीएल लिमिटेड	28	7	ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलीमर लिमिटेड
8	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	45	8	कोल इंडिया लिमिटेड
9	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	25	9	ऑयल इंडिया लिमिटेड
10	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	14	10	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन
11	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	217	11	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
12	नॉर्थ कोलफील्ड्स लिमिटेड	52	12	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
13	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	53	13	चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड
14	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	135	14	गेल गैस लिमिटेड

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	आधारभूत/आवश्यकता मूल्यांकन सर्वेक्षण आयोजित किया गया (2021-22)
15	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	35
16	रेल विकास निगम लिमिटेड	5
17	राइट्स लिमिटेड	31
18	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	8
19	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	362
20	एनटीपीसी लिमिटेड	699
21	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	162
22	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	29
23	आरईसी लिमिटेड	40
24	एनएचपीसी लिमिटेड	106
25	एसजेवीएन लिमिटेड	12
26	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	113
27	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	2
28	भारतीय प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड	15
29	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनेरल्स (इंडिया) लिमिटेड	6
30	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड	12

क्रम सं.	सीपीएसई जहां आधारभूत/आवश्यकता मूल्यांकन सर्वेक्षण नहीं किया गया (2021-22)
15	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल ट्रावनकोर लिमिटेड
16	नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंफॉर्मेटिक्स
17	आईटीआई लिमिटेड
18	एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड
19	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
20	सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
21	एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
22	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
23	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड
24	एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड
25	पावर ग्रिड साउदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड
डेटा उपलब्ध नहीं	
क्रम सं.	सीपीएसई
1	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड
2	सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड
3	एमएसटीसी लिमिटेड

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	आधारभूत/आवश्यकता मूल्यांकन सर्वेक्षण आयोजित किया गया (2021-22)
31	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	7
32	गेल (इंडिया) लिमिटेड	25
33	एनएचडीसी लिमिटेड	17
कुल		3,055

क्रम सं.	सीपीएसई जहां आधारभूत/आवश्यकता मूल्यांकन सर्वेक्षण नहीं किया गया (2021-22)
4	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
5	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

स्रोत: सीपीएसई से प्राप्त आंकड़े तथा सीपीएसई की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़े।

अनुलग्नक-XXXII (पैरा संख्या 5.11 देखें)
सीएसआर गतिविधियों की निगरानी की स्थिति

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
मासिक निगरानी	
1	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड
2	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
3	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड
4	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
5	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
6	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
7	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
8	एनटीपीसी लिमिटेड
9	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
10	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
11	एनएचडीसी लिमिटेड
12	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
13	आईटीआई लिमिटेड
14	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
द्विमासिक/त्रैमासिक निगरानी	
1	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
2	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड
3	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
4	भारत डायनामिक्स लिमिटेड
5	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
6	एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड
7	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
8	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
9	रेल विकास निगम लिमिटेड
10	एसजेवीएन लिमिटेड
11	गेल गैस लिमिटेड
12	नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकॉर्पोरेटेड
13	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
14	सेल रिफ़ैक्टरी कंपनी लिमिटेड
15	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
16	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
17	एनएचपीसी लिमिटेड
अर्धवार्षिक निगरानी	
1	एनएमडीसी लिमिटेड
2	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड
3	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
4	एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड
वार्षिक निगरानी	
1	चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड
2	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल ट्रावनकोर लिमिटेड
परियोजना / एमओयू आधार निगरानी के अनुसार	
1	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2	एमएसटीसी लिमिटेड
3	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
4	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन
5	राइट्स लिमिटेड
6	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
7	आरईसी लिमिटेड
8	ऑयल इंडिया लिमिटेड
नियमित/आवधिक निगरानी	
1	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड
3	एनएलसी इंडिया लिमिटेड
4	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
5	कोल इंडिया लिमिटेड
6	गेल (इंडिया) लिमिटेड
7	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड
8	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम
9	सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
10	केआईओसीएल लिमिटेड
कोई निर्दिष्ट आवधिकता नहीं	
1	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
2	एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
3	पावर ग्रिड साउदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
4	ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलीमर लिमिटेड
डेटा उपलब्ध नहीं कराया गया	
1	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड
2	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स (इंडिया) लिमिटेड
3	भारतीय प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड
4	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

स्रोत: सीपीएसई से प्राप्त आंकड़े।

अनुलग्नक- XXXIII (पैरा सं.5.11 देखें)

प्रभाव आकलन की स्थिति

33 सीपीएसई की सूची - प्रभाव आकलन (₹ 10 करोड़ से अधिक का दायित्व)			
क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	₹ 10 करोड़ से अधिक है?	क्या कंपनी ने एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से अपने सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव आकलन कराया है, जिनका परिव्यय ₹ 1 करोड़ या उससे अधिक है और जो प्रभाव अध्ययन शुरू करने से कम से कम एक वर्ष पहले पूरी हो चुकी हैं।
1	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ	हाँ
2	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	हाँ	हाँ
3	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ	नहीं
4	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	हाँ	हाँ
5	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	हाँ	हाँ
6	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	हाँ	हाँ
7	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	हाँ	हाँ
8	एनएमडीसी लिमिटेड	हाँ	नहीं
9	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	हाँ	हाँ
10	ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलीमर लिमिटेड	हाँ	नहीं
11	कोल इंडिया लिमिटेड	हाँ	हाँ
12	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ	हाँ
13	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ	नहीं

14	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ	हाँ
15	ऑयल इंडिया लिमिटेड	हाँ	नहीं
16	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ	हाँ
17	रेल विकास निगम लिमिटेड	हाँ	हाँ
18	राइट्स लिमिटेड	हाँ	हाँ
19	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ	हाँ
20	एनटीपीसी लिमिटेड	हाँ	नहीं
21	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ	हाँ
22	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ	नहीं
23	गेल (इंडिया) लिमिटेड	हाँ	हाँ
24	आरईसी लिमिटेड	हाँ	हाँ
25	एनएमपीसी लिमिटेड	हाँ	हाँ
26	एसजेवीएन लिमिटेड	हाँ	नहीं
27	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	हाँ	नहीं
28	एनएचडीसी लिमिटेड	हाँ	हाँ
29	भारतीय प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड	हाँ	हाँ
30	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ	हाँ
31	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ	नहीं
32	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	हाँ	नहीं
33	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	हाँ	ना
34	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ	हाँ
35	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	हाँ	नहीं

36	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ	नहीं
37	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन	हाँ	नहीं

22 सीपीएसई की सूची - प्रभाव आकलन (₹ 1 करोड़ के परिव्यय वाली सीएसआर परियोजनाएं)

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	₹10 करोड़ से अधिक है?	क्या कंपनी ने एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से अपने सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव आकलन कराया है, जिनका परिव्यय ₹ 1 करोड़ या उससे अधिक है और जो प्रभाव अध्ययन शुरू करने से कम से कम एक वर्ष पहले पूरी हो चुकी हैं।
1	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ	हाँ
2	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	हाँ	हाँ
3	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	हाँ	हाँ
4	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	हाँ	हाँ
5	कोल इंडिया लिमिटेड	हाँ	हाँ
6	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ	हाँ
7	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ	हाँ
8	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ	हाँ
9	रेल विकास निगम लिमिटेड	हाँ	हाँ
10	राइट्स लिमिटेड	हाँ	हाँ
11	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ	हाँ
12	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ	हाँ
13	गेल (इंडिया) लिमिटेड	हाँ	हाँ

14	आरईसी लिमिटेड	हाँ	हाँ
15	एनएचपीसी लिमिटेड	हाँ	हाँ
16	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ	हाँ
17	एनएचडीसी लिमिटेड	हाँ	हाँ
18	भारतीय प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड	हाँ	हाँ
19	न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ	हाँ
20	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	हाँ	हाँ
21	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	हाँ	हाँ
22	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	हाँ	हाँ

15 सीपीएसई की सूची - प्रभाव आकलन (सीपीएसई ने प्रभाव आकलन नहीं किया था)

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	₹ 10 करोड़ से अधिक है?	क्या कंपनी ने एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से अपने सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव आकलन कराया है, जिनका परिव्यय ₹1 करोड़ या उससे अधिक है और जो प्रभाव अध्ययन शुरू करने से कम से कम एक वर्ष पहले पूरी हो चुकी हैं।
1	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ	नहीं
2	एनएमडीसी लिमिटेड	हाँ	नहीं
3	ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलीमर लिमिटेड	हाँ	नहीं
4	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ	नहीं
5	ऑयल इंडिया लिमिटेड	हाँ	नहीं
6	एनटीपीसी लिमिटेड	हाँ	नहीं
7	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ	नहीं
8	एसजेवीएन लिमिटेड	हाँ	नहीं

9	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ	नहीं
10	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	हाँ	नहीं
11	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	हाँ	ना
12	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	हाँ	नहीं
13	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	हाँ	नहीं
14	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ	नहीं
15	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन	हाँ	नहीं

स्रोत: सीपीएसई से प्राप्त आंकड़े।

अनुलग्नक-XXXIV (पैरा संख्या 5.12 देखें)

सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से निर्मित/अर्जित पूंजीगत परिसंपत्तियों की स्थिति

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	क्या सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से कोई पूंजीगत परिसंपत्ति बनाई/अर्जित की गई है?
1	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ
2	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	हाँ
3	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	हाँ
4	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	हाँ
5	कोल इंडिया लिमिटेड	हाँ
6	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ
7	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ
8	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ
9	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ
10	राइट्स लिमिटेड	हाँ
11	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	हाँ
12	एनएचपीसी लिमिटेड	हाँ
13	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	हाँ
14	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ
15	सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ
16	एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ
17	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ
18	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ
19	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	हाँ
20	भारतीय प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड	हाँ
21	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	हाँ

स्रोत: सीपीएसई की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़े।

अनुलग्नक-XXXV (पैरा संख्या 6.5.2.3 देखें)

वर्ष 2016-17 से 2020-21 की अवधि के लिए हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचईसी)
के लिए उत्पादन हेतु समझौता ज़ापन लक्ष्य और उपलब्धियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
उत्पादन के लिए समझौता ज़ापन	610.01	704.15	628.20	559.32	440.80
वास्तविक उत्पादन	364.84	393.38	340.21	158.29	252.44
उपलब्धि (%)	59.81	55.87	54.16	28.30	57.27

*2021-22 के लिए समझौता ज़ापन का लक्ष्य और उपलब्धि उपलब्ध नहीं थी क्योंकि समझौता ज़ापन का प्रारूप संशोधित किया गया था।

अनुलग्नक-XXXVI (पैरा संख्या 6.5.2.3 देखें)

एचईसी के संयंत्रों और मशीनरी की स्थापित क्षमता और उपयोग

(मात्रा टन में)

वर्ष	फाउंड्री फोर्ज प्लांट		भारी मशीन निर्माण संयंत्र		भारी मशीन उपकरण संयंत्र		एचईसी के लिए कुल	
	स्थापित क्षमता 28,956 टन		स्थापित क्षमता 17,658 टन		स्थापित क्षमता 1,335 टन		स्थापित क्षमता- 47,949 टन	
	वास्तविक उत्पादन	उपयोग (में %)	वास्तविक उत्पादन	उपयोग (में %)	वास्तविक उत्पादन	उपयोग (में %)	वास्तविक उत्पादन	उपयोग (% में)
2016-17	2,444	8.44	6,718	38.05	456	34.16	9,618	20.06
2017-18	3,559	12.29	3,813	21.59	106	7.94	7,478	15.60
2018-19	4,260	14.71	3,248	18.39	162	12.13	7,670	16.00
2019-20	3,716	12.83	1,942	11.00	200	14.98	5,858	12.22
2020-21	2,322	8.02	3,346	18.95	333	24.94	6,001	12.52
2021-22	864	2.98	1,031	5.84	12	0.93	1,907	3.98

अनुलग्नक-XXXVII (पैरा संख्या 6.5.2.4 देखें)

एचईसी के संबंध में आदेशों और निष्पादन की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्राप्त ऑर्डर का मूल्य	निष्पादित आदेशों का मूल्य	31 मार्च तक लंबित ऑर्डरों का संचयी मूल्य
2016-17	245.83	390.11	1,114.52
2017-18	159.01	399.02	900.66
2018-19	175.08	356.21	642.43
2019-20	1,013.46	132.68	1,166.70
2020-21	1,421.17	202.76	2,142.38
2021-22	188.18	184.69	1,451.40
कुल	3,202.73	1,665.47	

अनुलग्नक-XXXVIII (पैरा संख्या 6.5.2.4 देखें)

वर्ष 2016-17 से 2021-22 की अवधि के दौरान एचईसी द्वारा निर्धारित समय में एवं निर्धारित समय से परे निष्पादित आदेशों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कुल निष्पादित ऑर्डर	16,966.03	9,919.45	10,802.07	6,319.02	3,811.43	10,128.38
समय पर निष्पादित आदेश	2,122.46 (12.51%)	4,598.89 (46.36%)	5,511.24 (51.02%)	3,026.78 (47.90%)	3,104.01 (81.44%)	6,418.57 (63.37)
समय सीमा से अधिक समय में निष्पादित आदेश	6,110.39 (95.49%)	3,665.70 (66.95%)	3,382.43 (94.93%)	600.65 (38.16%)	287.78 (26.58%)	148.80 (2.90%)

अनुलग्नक-XXXIX (पैरा संख्या 6.5.2.5 देखें)

2016-17 से 2021-22 के दौरान एचईसी की कार्यशील पूंजी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्तमान संपत्ति	वर्तमान देनदारियां	कार्यशील पूंजी (कॉलम 2-कॉलम 3)
(1)	(2)	(3)	(4)
2016-17	455.36	994.87	-539.51
2017-18	607.41	674.81	-67.40
2018-19	519.31	653.76	-134.45
2019-20	371.42	882.07	-510.65
2020-21	428.51	1,095.95	-667.44
2021-22	392.48	1,330.17	-937.69

अनुलग्नक-XL (पैरा संख्या 6.6.3 देखें)

अगस्त 2019 की बैठक में लिए गए निर्णय और पीईसी लिमिटेड द्वारा उस पर की गई कार्रवाई

क्रम सं.	बैठक में लिया गया निर्णय	कंपनी/वाणिज्य विभाग द्वारा दी गई सूचना (अप्रैल 2022) के अनुसार की गई कार्रवाई
1.	पीईसी तुरन्त समापन प्रक्रिया शुरू करेगी।	विभाग के निर्देशानुसार, पीईसी ने सितंबर 2019 से नया कारोबार शुरू करना बंद कर दिया और चरणों में वीआरएस शुरू किया, जिसमें वीआरएस के तहत 20 कर्मचारियों को सेवामुक्त किया गया। इसके अलावा, निदेशक मंडल ने वीआरएस के अगले चरण (चरण- IV) को मंजूरी दी (अक्टूबर 2021)। चूंकि पीईसी घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी थी, इसलिए डीपीई दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप वीआरएस शुरू करने के लिए निदेशक मंडल के साथ-साथ प्रशासनिक विभाग की मंजूरी की आवश्यकता थी। तदनुसार, पीईसी ने 12 नवंबर, 2021 के पत्र के माध्यम से वाणिज्य विभाग से अनुमोदन मांगा। कंपनी द्वारा वीआरएस के कार्यान्वयन के लिए अनुमोदन के अनुरोध के साथ वाणिज्य विभाग को 06 अप्रैल, 2022 और 13 अप्रैल, 2022 के पत्र भेजे गए। हालांकि, 04 मई, 2023 तक कोई जवाब नहीं मिला था। अनुमोदन प्राप्त होने के बाद वीआरएस लागू किया जाएगा।
2.	वाणिज्य विभाग एक निश्चित समय सीमा के भीतर पीईसी को बंद करने की सिफारिश करते हुए मंत्रिमंडल के लिए एक व्यापक नोट तैयार करेगा और प्रस्तुत करेगा।	पीईसी को बंद करने के लिए कैबिनेट सचिवालय को 26 अक्टूबर, 2021 को एक कैबिनेट नोट भेजा गया था। हालांकि, कैबिनेट सचिवालय ने इसे 13 दिसंबर, 2021 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से डीपीई द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रक्रिया करने की सलाह के साथ वापस कर दिया था। इस संबंध में अद्यतन स्थिति पैरा 6.6.3 में दी गई है।
3.	पीईसी द्वारा एनबीसीसी परियोजना में बुक किए गए स्थान को सरेंडर करने के बाद उपलब्ध धनराशि और संभावित धनराशि (लगभग ₹45 करोड़) के माध्यम से स्वैच्छिक पृथक्करण योजना	एनबीसीसी से रिफंड 01 मई, 2020 को प्राप्त हो गया था और आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग स्वैच्छिक पृथक्करण योजना के लिए किया जाएगा।

क्रम सं.	बैठक में लिया गया निर्णय	कंपनी/वाणिज्य विभाग द्वारा दी गई सूचना (अप्रैल 2022) के अनुसार की गई कार्रवाई
	प्रक्रिया आरंभ की जा सकती है। पीईसी अधिकारियों को एनबीसीसी के साथ प्राथमिकता के आधार पर अनुवर्ती कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।	
4.	पीईसी प्रबंधन को लंबित अनुबंधों/व्यवसाय, यदि कोई हो, को भारत सरकार के अन्य सार्वजनिक उपक्रमों या संगठनों को हस्तांतरित करने पर विचार करना चाहिए, जो ऐसे कार्यों को कर सकते हैं।	अगस्त 2019 में कोई भी ऐसा बड़ा अनुलग्नक नहीं था जिसे अन्य सार्वजनिक उपक्रमों को हस्तांतरित किया जा सके। 2019-20 में पीईसी द्वारा आंशिक रूप से निष्पादित अनुबंधों में केवल शेष शिपमेंट किए गए, जिसमें ₹8 करोड़ का कारोबार दर्ज किया गया। बाद के वर्षों में कारोबार शून्य रहा।
5.	पीईसी प्रबंधन को सभी चल रहे वसूली और भुगतान मामलों, चल रही आपराधिक जांच और कानूनी और मध्यस्थता मामलों पर आक्रामक रूप से कार्रवाई करने को कहा गया है।	पीईसी की बकाया राशि वसूलने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं और साथ ही सभी कानूनी, आपराधिक, सिविल, मध्यस्थता मामलों का पालन किया जा रहा है। 2021-22 के दौरान ₹5.34 करोड़ की वसूली की गई। हालांकि, कोविड प्रतिबंधों के कारण कानूनी मामलों में प्रगति सीमित रही क्योंकि अदालतें वर्चुअल तरीके से काम कर रही थीं।
6.	पीईसी प्रबंधन सभी संवेदनशील फाइलों/दस्तावेजों/कागजातों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा ताकि आपराधिक जांच या वसूली के मामलों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। उन्हें इस संबंध में सभी उचित उपाय करने के निर्देश दिए गए।	पीईसी ने आसानी से प्राप्त करने के लिए आवश्यक रिकॉर्ड (लगभग 37.41 लाख पृष्ठ) को डिजिटल कर दिया है। डिजिटल डेटा वाली हार्ड ड्राइव को अग्निरोधी लॉकर में रखा गया है।
7.	सेवानिवृत्त/वीआरएस विकल्प चुनने वालों के लिए चिकित्सा योजना के संबंध में, पीईसी प्रबंधन को उपलब्ध धनराशि से अग्रिम भुगतान करके किसी भी राष्ट्रीय बीमा कंपनी से उपयुक्त स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लेने पर विचार करने का निर्देश दिया गया।	29 अगस्त, 2019 की बैठक के बाद, वाणिज्य विभाग ने पीईसी को सीजीएचएस, ईएसआईसी, रेलवे और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के माध्यम से चिकित्सा सुविधा की संभावना तलाशने का निर्देश दिया। पीईसी ने वाणिज्य विभाग के माध्यम से उपरोक्त संगठनों को अपना विवरण पहले ही प्रस्तुत कर दिया है। इसके अलावा, पीईसी ने मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए एक टेंडर भी जारी किया (दिसंबर 2021)। हालांकि, कोई बोली प्राप्त नहीं हुई। इसलिए, टेंडर नोटिस को कंपनी की वेबसाइट पर फिर से (मार्च 2022) होस्ट किया गया। कंपनी के उत्तर (04 मई,

क्रम सं.	बैठक में लिया गया निर्णय	कंपनी/वाणिज्य विभाग द्वारा दी गई सूचना (अप्रैल 2022) के अनुसार की गई कार्रवाई
		2023) के अनुसार, मेडिकल टेंडर दो बार जारी किया गया था, लेकिन पीईसी को कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।
8.	वाणिज्य विभाग एक मजबूत और प्रभावी तंत्र की जांच करेगा तथा उसका प्रस्ताव करेगा, जिसमें प्रतिष्ठित व्यक्तियों और सीवीसी/बैंकों आदि से लिए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों की एक समिति गठित करने का प्रस्ताव भी शामिल होगा, जो पीईसी के बंद होने के बाद भविष्य की वसूली और भुगतान की निगरानी करेगी।	पीईसी लिमिटेड को बंद करने की मंजूरी के बाद इस संबंध में कदम उठाए जाने की आवश्यकता थी, किसी भी मामले में वसूली के मामलों को पीईसी लिमिटेड द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा, 13 दिसंबर 2021 को डीपीई दिशानिर्देश जारी होने के बाद, मामले को इन दिशानिर्देशों के अनुसार संसाधित किया जाना था।
9.	तमिलनाडु नागरिक आपूर्ति निगम को पीईसी की बकाया राशि का मुद्दा राज्य सरकार के समक्ष उठाया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या बकाया राशि को कम करने की कोई गुंजाइश है। राज्य सरकार को देय मूल राशि का भुगतान एसटीसी/पीईसी की शेष संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि से किया जाना होगा और किसी भी कमी का भुगतान वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाना होगा।	तमिलनाडु नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किए गए ₹154.52 करोड़ के दावे के विरुद्ध, पीईसी ने वाणिज्य विभाग के माध्यम से सीपीएसई विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र के तहत ₹63 करोड़ का प्रति दावा किया था। 14 जून 2021 को निर्धारित सीपीएसई विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र की अंतिम बैठक स्थगित कर दी गई थी। नई तिथि अभी अधिसूचित की जानी है (मई 2023)।
10.	पीईसी को बंद करने की पूरी प्रक्रिया शीघ्रता से पूरी की जानी चाहिए तथा इसमें सभी प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए।	बंद करने की प्रक्रिया वाणिज्य विभाग द्वारा संचालित की जा रही थी। जब भी विभाग को किसी डेटा/इनपुट की आवश्यकता होती थी तो वह पीईसी द्वारा उपलब्ध कराया जाता था।
11.	वाणिज्य विभाग बैठक में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की नियमित समीक्षा करेगा तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के कार्यालय को नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की बैठकों में बैंकों के साथ पीईसी के एकमुश्त निपटान, लंबित अदालती मामलों, पीईसी को बंद करने आदि के संबंध में लिए गए निर्णयों की नियमित समीक्षा की गई।

अनुलग्नक- XLI (पैरा संख्या 6.7.1 देखें)
राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड (एनटीसी) की 23 संचालित मिलों की सूची

क्रम सं.	मिल/राज्य का नाम	जगह
आंध्र प्रदेश		
1	तिरुपति कॉटन मिल्स	रेनिगुंटा
गुजरात		
2	राजनगर टेक्सटाइल मिल नं. 1	अहमदाबाद
कर्नाटक		
3	न्यू मिनर्वा मिल्स	हसन
केरल		
4	अलगप्पा टेक्सटाइल मिल्स	अलगप्पानगर
5	कन्नानोर स्पिनिंग और वीविंग मिल्स	कैन्नानोर
6	केरल लक्ष्मी मिल्स	त्रिचूर
7	विजयमोहिनी मिल्स	तिरुवनंतपुरम
मध्य प्रदेश		
8	बुरहानपुर ताप्ती मिल्स	बुरहानपुर
9	न्यू भोपाल टेक्सटाइल मिल्स	भोपाल
महाराष्ट्र		
10	पोद्दार मिल्स	मुंबई
11	टाटा मिल्स	मुंबई
12	इंडिया यूनाइटेड मिल नं. 5	मुंबई
13	बारशी टेक्सटाइल मिल्स	बारशी
14	फिनले मिल्स	अचलपुर
पुदुचेरी		
15	कन्नानोर स्पिनिंग और वीविंग मिल्स	माहे
तमिलनाडु		
16	पायनियर स्पिनर्स मिल्स	कामुदाकुडी
17	कालीश्वर मिल्स 'बी' यूनिट	कलयारकोइल
18	कंबोडिया मिल्स	कोयंबटूर
19	कोयंबटूर मुरुगन मिल्स	कोयंबटूर
20	पंकजा मिल्स	कोयंबटूर
21	श्री रंगविलास जिनिंग, स्पिनिंग और वीविंग मिल्स	कोयंबटूर
22	कोयंबटूर स्पिनिंग और वीविंग मिल्स	कोयंबटूर
पश्चिम बंगाल		
23	आरती कॉटन मिल्स	दास नगर

अनुलग्नक- XLII { पैरा संख्या 6.7.4.1(iv) देखें }

एनटीसी की 23 मिलों के आधुनिकीकरण की स्थिति और आधुनिकीकरण पर आने वाली लागत
(31 मार्च, 2022 तक)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मिल का नाम	आधुनिकीकरण का अनुमानित प्रतिशत	आधुनिकीकरण के लिए परिकल्पित लागत	*प्राप्त आधुनिकीकरण का प्रतिशत	आधुनिकीकरण पर व्यय
1	तिरूपति कॉटन मिल्स, आंध्र प्रदेश	19%	-	शून्य	3.85
2	राजनगर टेक्सटाइल मिल नंबर 1, गुजरात	100%	119.47	55%	142.41
3	न्यू मिनर्वा मिल्स, कर्नाटक	100%	152.92	55%	177.95
4	अल्गप्पा टेक्सटाइल मिल्स, केरल	51%	19.59	35%	25.34
5	कन्नानोर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, केरल	100%	71.22	55%	130.00
6	केरल लक्ष्मी मिल्स, केरल	45%	25.00	35%	26.83
7	विजयमोहिनी मिल्स, केरल	63%	22.85	30%	26.09
8	बुरहानपुर ताप्ती मिल्स, मध्य प्रदेश	100%	54.47	50%	125.59
9	न्यू भोपाल टेक्सटाइल मिल्स, मध्य प्रदेश	100%	47.43	35%	100.46
10	पोद्दार मिल्स, महाराष्ट्र	47%	45.85	35%	40.45
11	टाटा मिल्स, महाराष्ट्र	43%	68.63	35%	81.17

क्रम सं.	मिल का नाम	आधुनिकीकरण का अनुमानित प्रतिशत	आधुनिकीकरण के लिए परिकल्पित लागत	*प्राप्त आधुनिकीकरण का प्रतिशत	आधुनिकीकरण पर व्यय
12	इंडिया यूनाइटेड मिल नं. 5, महाराष्ट्र	66%	37.01	35%	32.29
13	बार्शी टेक्सटाइल मिल्स, महाराष्ट्र	49%	48.75	35%	25.27
14	फिनले मिल्स, महाराष्ट्र	100%	188.95	55%	257.45
15	कन्नानोर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, पुडुचेरी	79%	21.10	35%	37.21
16	पायनियर स्पिनर्स मिल्स, तमिलनाडु	51%	26.22	48%	78.67
17	कलेश्वर मिल्स 'बी' यूनिट, तमिलनाडु	58%	16.94	48%	71.64
18	कंबोडिया मिल्स, तमिलनाडु	19%	10.72	10%	14.06
19	कोयंबटूर मुरुगन मिल्स, तमिलनाडु	58%	14.44	50%	16.88
20	पंकजा मिल्स, तमिलनाडु	40%	16.61	35%	22.59
21	श्री रंगविलास जिनिंग, स्पिनिंग एवं वीविंग मिल्स, तमिलनाडु	54%	25.21	50%	56.77
22	कोयंबटूर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, तमिलनाडु	4%	-	शून्य	0.96
23	आरती कॉटन मिल्स, पश्चिम बंगाल	100%	57.13	45%	48.69
	कुल		1,090.51		1,542.62

स्रोत: एनटीसी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

* मशीनरी के जीवन के आधार पर आधुनिकीकरण प्रतिशत की गणना की गई (अवधि मशीन निर्माण के वर्ष से मार्च 2020 तक)

अनुलग्नक-XLIII {पैरा संख्या 6.7.4.1(v) देखें}

2016-17 से 2019-20 के दौरान एनटीसी की 23 मिलों की कताई क्षमता का उपयोग

(प्रतिशत में)

क्रम सं.	मिल का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	औसत
1	तिरुपति कॉटन मिल्स, आंध्र प्रदेश	81.83	89.30	90.01	74.66	84
2	राजनगर टेक्सटाइल मिल नंबर 1, गुजरात	93.54	87.17	90.16	83.40	89
3	न्यू मिनर्वा मिल्स, कर्नाटक	91.83	91.81	83.09	10.33	69
4	अल्गप्पा टेक्सटाइल मिल्स, केरल	76.13	75.18	74.35	81.42	77
5	कन्नानोर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, केरल	87.02	90.57	89.40	89.93	89
6	केरल लक्ष्मी मिल्स, केरल	83.20	87.06	80.03	81.08	83
7	विजयमोहिनी मिल्स, केरल	87.80	90.84	88.20	76.36	86
8	बुरहानपुर ताप्ती मिल्स, मध्य प्रदेश	95.19	93.80	96.03	91.82	94
9	न्यू भोपाल टेक्सटाइल मिल्स, मध्य प्रदेश	87.27	90.24	93.53	89.44	90
10	पोद्दार मिल्स, महाराष्ट्र	97.43	95.92	96.36	75.54	91
11	टाटा मिल्स, महाराष्ट्र	87.25	87.10	88.10	71.38	83
12	इंडिया यूनाइटेड मिल नं. 5, महाराष्ट्र	89.49	94.60	94.37	80.07	90
13	बार्शी टेक्सटाइल मिल्स, महाराष्ट्र	90.70	95.90	95.74	82.23	91
14	फिनले मिल्स, महाराष्ट्र	94.02	91.72	93.97	95.61	94
15	कन्नानोर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, पुडुचेरी	81.35	82.74	84.45	74.91	81
16	पायनियर स्पिनर्स मिल्स, तमिलनाडु	79.26	85.86	82.43	76.63	81
17	कलेश्वर मिल्स 'बी' यूनिट, तमिलनाडु	84.64	90.40	87.83	80.49	86
18	कंबोडिया मिल्स, तमिलनाडु	81.87	86.44	80.32	70.92	80

क्रम सं.	मिल का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	औसत
19	कोयंबटूर मुरुगन मिल्स, तमिलनाडु	77.27	87.13	76.29	76.92	79
20	पंकजा मिल्स, तमिलनाडु	79.66	83.79	79.58	72.42	79
21	श्री रंगविलास जिनिंग, स्पिनिंग एवं वीविंग मिल्स, तमिलनाडु	89.12	93.43	82.26	92.06	89
22	कोयंबटूर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, तमिलनाडु	58.80	87.96	80.73	72.65	75
23	आरती कॉटन मिल्स, पश्चिम बंगाल	69.28	67.93	68.07	38.14	61

अनुलग्नक-XLIV (पैरा संख्या 6.8.2 देखें)

हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) के परिचालन परिणाम

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
आय					
बिक्री कारोबार	242.33	471.99	300.01	411.58	433.67
अन्य कमाई	66.30	115.71	21.95	19.27	31.43
कुल आय	308.63	587.70	321.96	430.85	465.10
खर्च					
प्रयुक्त सामग्री की लागत	132.18	255.18	196.82	201.05	278.80
इन्वेंटरी में परिवर्तन, - तैयार माल और कार्य- प्रगति	(8.36)	9.44	(0.25)	0.55	(14.31)
कर्मचारी लाभ व्यय	175.97	55.13	52.66	45.70	45.20
वित्त लागत	74.61	65.74	56.36	53.36	51.34
मूल्यहास	4.30	1.76	1.29	1.21	1.16
एफए पर हानि क्षति के लिए प्रावधान	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य खर्च					
स्टोर और स्पेयर्स	6.37	9.77	8.86	9.85	11.67
उपयोगिताएँ (बिजली, ईंधन और पानी)	55.55	82.89	62.94	71.44	78.79
मरम्मत	4.02	3.50	6.89	4.65	6.57
प्रशासनिक व्यय	18.91	16.42	16.05	11.32	12.84
पूर्व अवधि व्यय .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विक्रय व्यय (सीडी आदि)	3.84	8.07	6.06	7.87	7.53
प्रावधानों	38.21	9.01	9.07	8.39	8.75
कुल व्यय	508.11	516.91	416.65	415.39	488.34
कर से पहले लाभ / (हानि)	(199.48)	70.79	(94.69)	15.46	(23.24)
परिचालन घाटा ⁷	(265.78)	(44.92)	(116.64)	(3.81)	(54.67)

⁷ मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन में उल्लिखित वित्तीय प्रदर्शन मानदंडों के आधार पर, परिचालन हानि की गणना प्रत्येक वर्ष के कर-पूर्व लाभ/हानि से पूर्व अवधि के व्यय और अन्य आय को घटाकर की जाती है ।

अनुलग्नक पुनः-XLV (पैरा संख्या 6.8.2 देखें)

एचओसीएल की वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
संपत्ति					
1. गैर- वर्तमान परिसंपत्तियां					
क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	102.40	118.72	124.52	134.47	153.48
ख) निवेश संपत्ति	0.05	0.95	0.88	0.88	0.89
ग) अमूर्त संपत्ति	0.00	0.00	0.19	0.23	0.27
घ) वित्तीय परिसंपत्तियां	37.52	15.13	3.29	8.39	10.63
इ) अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	1.46	2.17	6.24	4.98	4.98
कुल गैर- मौजूदा संपत्तियां	141.43	136.97	135.12	148.95	170.25
2. वर्तमान परिसंपत्तियाँ					
क) इन्वेंटरी	57.31	47.35	46.20	50.81	75.11
ख) वित्तीय परिसंपत्तियां					
i) व्यापार प्राप्त्य	4.39	17.71	7.86	2.40	7.35
ii) नकदी और बैंक शेष	109.04	70.35	103.65	148.20	135.11
iii) ऋण	5.40	12.57	20.42	20.66	32.18
iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	11.43	11.94	2.66	3.93	13.34
ग) बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ ⁸	1,257. 11	1,178.46	987.51	992.20	992.20
d) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	58.67	42.36	34.13	25.97	28.59
कुल मौजूदा संपत्तियां	1,503.35	1,380. 74	1,202. 43	1,244. 17	1,283. 88
कुल संपत्ति	1,644.78	1,517.71	1,337.55	1,393. 12	1,454.13
इक्विटी और देयता					
1. इक्विटी					
क) इक्विटी शेयर पूंजी	67.27	67.27	67.27	67.27	67.27
ख) अन्य इक्विटी					

⁸ इसमें रसायनी में भूमि, भवन, संयंत्र और उपकरण, फर्नीचर, फिक्सचर और उपकरण शामिल हैं, जिन्हें पुनर्गठन के हिस्से के रूप में निपटाया जाना है।

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
i) प्रतिभूति प्रीमियम	48.39	48.39	48.39	48.39	48.39
ii) प्रतिधारित आय	(1,177.11)	(1,073.72)	(1,010.97)	(994.97)	(1,017.62)
iii) अन्य व्यापक आय ⁹	1,113.11	1,063.96	924.33	939.17	955.19
कुल	51.66	105.90	29.02	59.86	53.23
2. देयताएं					
गैर मौजूदा देनदारियां :					
क) वित्तीय देयताएं (शुद्ध)					
i) उधार	245.57	245.62	158.82	76.95	0.00
ख) प्रावधान (कर्मचारी लाभ देयताओं सहित)	56.84	33.14	32.47	33.34	29.81
ग) आस्थगित कर देयताएं	199.86	209.00	151.95	157.62	164.02
कुल	502.27	487.76	343.24	267.91	193.83
वर्तमान देनदारियां:					
क) वित्तीय देनदारियां					
i) वरीयता शेयर धारकों को देय राशि	270.00	270.00	270.00	270.00	270.00
ii) व्यापार देयताएं	175.58	98.00	36.13	22.51	41.52
iii) अन्य चालू वित्तीय देनदारियाँ	86.82	86.79	86.79	81.87	76.95
ख) प्रावधान (कर्मचारी लाभ देयताओं सहित)	64.31	49.61	57.48	61.30	68.01
ग) अन्य चालू देयताएं	494.14	419.65	514.89	629.67	750.59
वर्तमान देनदारियां	1,090.85	924.05	965.29	1,065.35	1,207.07
कुल शेयर और देनदारियां	1,644.78	1,517.71	1,337.55	1,393.12	1,454.13
कार्यशील पूंजी (सीए-सीएल)	412.50	456.69	237.14	178.82	76.81
निवल संपत्ति (शेयर पूंजी + सुरक्षा प्रीमियम + रिजर्व और अधिशेष)	(1,061.45)	(958.06)	(895.31)	(879.31)	(901.96)

⁹ इसमें संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का पुनर्मूल्यांकन, कर्मचारियों की परिभाषित लाभ योजना में परिवर्तन आदि शामिल हैं।

अनुलग्नक-X LVI (पैरा संख्या 6.8.4 देखें)

सीसीईए अनुमोदन के अनुसार एचओसीएल की पुनर्गठन योजना

लेना तारीख का रसीद का सीसीईए अनुमोदन जैसा 'टी' (22.05.2017)		नियत तारीख
बीपीसीएल को भूमि की बिक्री से संबंधित औपचारिकताओं को पूरा करना जैसे पंजीकरण आदि	टी + 45 दिन	06.07.2017
20 एकड़ भूमि और संबंधित जनशक्ति के साथ एन ₂ ओ ₄ संयंत्र का इसरो को हस्तांतरण	टी + 3 महीने	22.08.2017
कर्मचारियों के वेतन/मजदूरी और वैधानिक बकाया का निपटान और वीआरएस के माध्यम से कर्मचारियों को अलग करना (अस्थिर कर्मचारियों और वीआरएस का विकल्प नहीं चुनने वालों को छोड़कर)	टी + 3 महीने	22.08.2017
वीआरएस का विकल्प न चुनने वाले कर्मचारियों की छंटनी	टी + 4 महीने	22.09.2017
एनबीसीसी के माध्यम से केंद्र सरकार के विभागों/निकायों/सीपीएसई, राज्य सरकार के विभागों/निकायों/एसपीएसई को लीजहोल्ड/फ्रीहोल्ड भाररहित भूमि की बिक्री	टी + 6 महीने	22.11.2017
उपरोक्त (v) में दिए गए विकल्प समाप्त होने के बाद किसी भी इकाई को भूमि की नीलामी :	टी + 12 महीने	22.5.2018
एमएसटीसी द्वारा ई - नीलामी के माध्यम से चल संपत्तियों / संयंत्र और मशीनरी का निपटान	टी + 3 महीने	22.08.2017
अगस्त-सितंबर 2017 में भारत सरकार के गारंटीकृत बांड के लिए ₹250 करोड़ का भुगतान किया जाएगा जब बांडों का मोचन देय था।		

अनुलग्नक-XLVII (पैरा संख्या 6.8.4.2 देखें)

एचओसीएल की रसायनी इकाइयों में भूमि बिक्री की स्थिति

क्रम सं.	भूमि का विवरण	भूमि निपटान विवरण	टिप्पणी	क्षेत्रफल एकड़ में
1	आवंटित/हस्तांतरित भूमि			704.39
ए	पुनर्गठन योजना के अनुसार बीपीसीएल को भूमि आवंटित की गई (442 एकड़)	दो किस्तों में बेचा गया: (i) फरवरी 2018 में 251 एकड़ (मूल्य: ₹351.40 करोड़)। (ii) मार्च 2019 में 38.68 एकड़ (मूल्य: ₹54.16 करोड़)। (कुल: 289.69 एकड़ मूल्य ₹405.56 करोड़)	442 एकड़ का यह क्षेत्र संपूर्ण फैक्ट्री क्षेत्र को चिह्नित करता है। सर्वेक्षण और भूमि के सीमांकन को पूरा करने में लगने वाले समय के कारण इस पहले हिस्से की बिक्री में सात महीने की देरी हुई। अधिग्रहण से पहले बीपीसीएल द्वारा संपत्ति के भौतिक सत्यापन में लगने वाले समय के कारण दूसरे हिस्से की बिक्री में एक साल की और देरी हुई। 152.32 एकड़ का शेष क्षेत्र, बीपीसीएल के नाम पर पहले से आवंटित भूमि पर बाड़ लगाने के खिलाफ ग्रामीणों के विरोध के कारण बिक्री के लिए लंबित है। बीपीसीएल ने स्थानीय ग्रामीणों के प्रतिरोध और अतिक्रमण को हटाए बिना क्षेत्र को अपने अधीन करने से इनकार कर दिया।	
बी	एनबीसीसी के माध्यम से नीलामी द्वारा बीपीसीएल को ₹1.61 करोड़ प्रति एकड़ की दर से भूमि आवंटित की गई (242 एकड़)	मई 2019 में 85.27 एकड़ (मूल्य: ₹137.19 करोड़) बेची गई	बीपीसीएल की बोली नवंबर 2017 में लगी थी। 242 एकड़ में से 85.27 एकड़ जमीन 1.5 साल की देरी से बेची जा सकी, क्योंकि जीओएम से एनओसी मिलने में देरी हुई। 156.73 एकड़ का शेष क्षेत्र जिसकी कीमत ₹252.33 करोड़ है, अभी भी बिक्री के लिए लंबित है, क्योंकि पहले से पंजीकृत भूमि पर बाड़ लगाने के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध जारी है। बीपीसीएल ने	

			अतिक्रमण और स्थानीय ग्रामीणों के प्रतिरोध को हटाए बिना इस क्षेत्र को अपने अधीन लेने से इनकार कर दिया।	
सी	इसरो को हस्तांतरित क्षेत्र (20 एकड़)			
डी	पेट्रोल पंप के लिए आईओसीएल को बेचा गया (0.386 एकड़)			
2	कंपनी द्वारा अतिक्रमित के रूप में पहचाना गया	उन्हें स्थानांतरित करने के प्रयास अभी तक सफल नहीं हुए हैं ।		22 . 72
3	महात्मा एजुकेशन सोसाइटी के नियंत्रण में क्षेत्र	अवैध कब्ज़ा - मामला न्यायालय में विचाराधीन		13 . 75
4	सरकारी एजेंसियों द्वारा कब्जाया गया क्षेत्र	कब्जे वाली संपत्तियों का सर्वेक्षण करने और एजेंसियों को सर्किल दरों पर इसे खरीदने के लिए राजी करने के प्रयास जारी		17.48
5	सुविधाओं के लिए आबंटित			1.32
6	बिक्री के लिए भारमुक्त भूमि उपलब्ध	एनबीसीसी इसका निपटान नहीं कर सका। कंपनी के अनुसार (23 मई), सरकारी एजेंसियां अतिक्रमणकारियों को मुआवजा देने के मामले के निपटारे के बाद ही इस जमीन को खरीदेंगी ।		252.70
रसायनी इकाई में कुल भूमि				1012.36

अनुलग्नक-XLVIII {(पैरा संख्या 6.8.7.2(iii) देखें)}

एचओसीएल के क्यूमीन के भारी सिरों के अधिक उत्पादन के कारण उत्पादन हानि

वर्ष	एचईसी उत्पादन (एमटी)	दर (₹/मीट्रिक टन)	मूल्य (करोड़ रूपये में)	फिनोल का समतुल्य उत्पादन ¹⁰ (एमटी)	दर (₹/मीट्रिक टन)	मूल्य (करोड़ रूपये में)	एसीटोन का समतुल्य उत्पादन ¹¹ (एमटी)	दर (₹/मीट्रिक टन)	मूल्य (करोड़ रूपये में)	हानि (करोड़ रूपये में)
क	ख	ग	घ (ख*ग)	ङ (ख*62.50%)	च	छ (ङ*च)	ज (ख*37.5%)	झ	ट (एच*आई)	ड (जी+जेडी)
2017-18	1,314	36,019	4.73	821	81,091	6.66	493	53,100	2.62	4.54
2018-19	2,449	34,192	8.37	1531	1,02,772	15.73	918	46,064	4.23	11.59
2019-20	2,901	41,574	12.06	1813	72,541	13.15	1088	43,425	4.72	5.82
2020-21	3,648	31,545	11.51	2280	59,223	13.50	1368	74,927	10.25	12.25
2021-22	1917	45372	8.70	1198	1,20,806	14.47	719	62,416	4.49	10.26
कुल	12,229		45.37	7,643		63.52	4,586		26.31	44.46

¹⁰ 62.50 प्रतिशत क्यूमीन फिनोल रूपांतरण अनुपात लागू करके प्राप्त किया गया¹¹ 37.50 प्रतिशत क्यूमीन एसीटोन रूपांतरण अनुपात लागू करके प्राप्त किया गया

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in